रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1987/पौष 5, 1909
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1987/PAUSA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than The Ministry of Defence

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3520.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, अर्थात् :—

(क) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (1939 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 10) की धारा 32 और धारा 55 के अधीन दंडनीय अपराध ;

(ख) खंड (क) में वर्णित अपराधों में से किसी एक या अधिक अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र ।

[सं. 228/34/87-ए. वी. डी. (II)]

जी. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 4th December, 1987

S.O. 3520.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) offence punishable under the U.P. Indian Medicines Act, 1939 (U.P. Act No. X of 1939);

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transactions arising out of the same facts.

[No. 228/34/87-AVD II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

(आयकर)

का. आ. 3521.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (IV) मद (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "10% आरक्षित विमोच्य एन. टी. पी. सी. बन्धपत्र, 1986—प्रथम श्रृंखला" को विनिर्दिष्ट करती है।

बशर्ते कि उक्त मद के अंतर्गत लाभ केवल तब स्वीकार्य होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम और सीधन उक्त कॉर्पोरेशन में पंजीकृत कराता है।

[सं. 7439/फा. सं.—178/19/87—आ. क. (नि.-1)]
के. के. त्रिपाठी, उपसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd July, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 3521.—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "10% Secured Redeemable NTPC Bonds 1986—First Series" issued by the National Thermal Power Corporation Ltd., New Delhi for the purpose of the said item :

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his name and the holding with the said Corporation.

[No. 7439 F. No. 178/19/87-IT (A-1)]
K. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1987

(आयकर)

का. आ. 3522.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (IV) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए "10% आरक्षित विमोच्य असंपरिवर्तनीय, 1000 रुपए प्रति बन्ध पत्र" को विनिर्दिष्ट करती है।

बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत लाभ केवल तब स्वीकार्य होगा यदि ऐसे बन्ध-पत्रों का धारक अपना नाम और सीधन उक्त कॉर्पोरेशन में पंजीकृत कराता है।

[सं. 7520/फा. सं. 178/53/87—आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 11th September, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 3522.—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of Clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "10% Secured Redeemable Non-convertible Bonds of Rs. 1,000 each" issued by the Indian Railway Finance Corporation Limited for the purpose of the said item.

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his name and the holding with the said Corporation.

[No. 7520/F. No. 178/53/87-IT(AI)]

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1987

(आयकर)

का. आ. 3523.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "हजरत पीर मोहम्मद शाह दरगाह शरीफ, ट्रस्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7581/फा. सं. 197/130/87—आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 13th October, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 3523.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Hazarat Pir Mohammed Shah Darga Sharif Trust" for the purpose of the said clause for the assessment year 1988-89.

[No. 7581/F. No. 197/130/87-IT (A-1)]

का. आ. 3524.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "हिज होलीनैस द दलाईलामास चैरिटेबल ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7583/फा. सं. 197/53/86—आ. क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3524.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "His Holiness The Dalai Lama's Charitable Trust" for the purpose of the said clause for the assessment years 1987-88 and 1988-89.

[No. 7583/F. No. 197/43/86-IT (A-1)]

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1987

(आयकर)

का. आ. 3525—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ, दक्षिणेश्वर" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7580/फा. सं. 197/178/87-आ. क. (नि-1)]

New Delhi, the 13th October, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 3525.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dakshineswar Ramkrishna Sangha, Dakshninswar", Calcutta for the purpose of the said clause for the assessment year 1988-89.

[No. 7580/F. No. 197/178/87-IT (A-1)]

(आयकर)

का. आ. 3526.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री मलाडी सत्यलिंगम, नायकर चरिटीज, काकीनाड़ा" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7582/फा. सं. 197क/90/82-आ. क. (नि.-1)]

रोशन सहाय, अवर सचिव,

(Income-tax)

S.O. 3526.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Malladi Satyalingam Naicker Charities, Kakinada", for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1988-90.

[No. 7582|F. No. 197A|90|82-IT (A-1)]
ROSHAN SAHAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1987

(आयकर)

का. आ. 3527.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "द सोसायटी आंफ द फ्रांसिस्कन सर्वेन्टस ऑफ मेरी सलेम" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7587/फा. सं. 197/40/85-आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 15th October, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 3527.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of the Franciscan Servants of Mary, Salem" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1988-89.

[No. 7587|F. No. 197|40|85-IT (A-1)]

(आयकर)

का. आ. 3528.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कलकत्ता डायोसीज (उत्तरी भारत का चर्च)" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7588/फा. सं. 197/8/86 आ. क. (नि.-1)]

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

(INCOME-TAX)

S.O. 3528.—In exercise of the powers conferred by clause (V) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Diocese of Calcutta (Church of North India)" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1988-89.

[No. 7588|F. No. 197|8|86-IT (A-1)]
DALIP SING, Officer on Special Duty

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3529.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस०सी० मेहरोत्रा को प्रथमा बैंक, मुरादाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-10-87 से प्रारम्भ होकर 31-10-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री मेहरोत्रा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 2/35/87-आर० आर० बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 1st December, 1987

S.O. 3529.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. C. Mehrotra as the Chairman of the Prathama Bank, Moradabad and specifies the period commencing on the 29th October, 1987 and ending with the 31st October, 1990 as the period for which the said Shri Mehrotra shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-35/87-RRB]

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3530.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर० के० मिश्र को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-4-87 को समाप्त हो गयी है, 1-5-87 से प्रारम्भ होकर 31-12-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 2-6/87-आर०आर०बी०]

New Delhi, the 4th December, 1987

S.O. 3530.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri R. K. Mishra whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of Section 11 had expired on 30th April, 1987 as the Chairman of Bareilly Kshetriya Gramin Bank, Bareilly for a further period commencing from 1st May, 1987 to 31st December, 1987.

[No. F. 2-6/87-RRB]

का०आ० 3531.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम०पी० पाटनी को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 31-3-87 को समाप्त हो गयी है, 1-4-87 से प्रारम्भ

होकर 31-12-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 2-6/87-आर०आर० बी०]

S.O. 3531.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri M. P. Patni whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31st March, 1981 as the Chairman of Dungarpur Banswara Kshetriya Gramin Bank, Dungarpur (Rajasthan) for a further period commencing from 1st April, 1987 and ending with 31st December, 1987.

[No. F. 2-6/87-RRB]

का०आ० 3532.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० एल० जैन को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 31-3-87 को समाप्त हो गयी है, 1-4-87 से प्रारम्भ होकर 31-12-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ 2-6/87-आर० आर० बी०]

S.O. 3532.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri M. L. Jain whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31st March, 1987 as the Chairman of Bhilwara Ajmer Kshetriya Gramin Bank, Bhilwara for a further period commencing from 1st April, 1987 and ending with 31st December, 1987.

[No. F. 2-6/87-RRB]

का. आ. 3533—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 4 जून 1977 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 382 (ई) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में "हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक" शब्दों के स्थान पर "अवध ग्रामीण बैंक" शब्द रखे जाएं।

[एफ. संख्या 1-27/84 आर. आर. बी.]

प्रवीण कुमार तेजयान, अवर सचिव

S.O. 3533.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Department of Revenue and Banking notification No. S.O. 382(E), dated the 4th June, 1977, namely:—

In the said notification for the words "Hardoi Unnao Grameen Bank", the words "Avadh Grameen Bank" shall be substituted.

[F. No. 1-27/84-RRB]
P. K. TEJYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3534—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री अवतार सिंह बग्गा को 13 दिसम्बर, 1987 से प्रारंभ होने वाली और 12 जनवरी, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/38/87—बी ओ—1 (1)]

New Delhi, the 11th December, 1987

S.O. 3534.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri Autar Singh Bagga as the Managing Director of the Punjab and Sind Bank for a period commencing on December 13, 1987 and ending with January 12, 1988.

[No. F. 9/38/87-BO.I(1)]

का. आ. 3535—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री अवतार सिंह बग्गा को जिन्हें 13 दिसम्बर 1987 से पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ 9/38/87 – बीओ – 1(2)]
एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 3535.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks, (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Autar Singh Bagga who has been re-appointed as Managing Director of the Punjab and Sind Bank with effect from December 13, 1987 to be the Chairman of the Board of Directors of the Punjab and Sind Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/38/87-BO.I(2)]
S. S. HASURKAR, Director

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

आदेश

का.आ. 3536:—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के केन्द्रीय बोर्ड को उनकी नीमच और गाजीपुर में सरकारी ओपियम एवं अलकालायड वर्क्स उपक्रम यूनिटों द्वारा उपयोग में लाने के लिए अफीम के बदले में कोडायन फास्फेट 1000 कि०ग्रा० और नासकापाइन बी०पी० 400 कि०ग्रा० का आयात करने के लिए 38,00,000 रुपये (अठतीस लाख रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० जी/पी/1106484, दिनांक 19-10-87 दिया गया था।

2. वित्त मंत्रालय ने इस आधार पर अनुलिपि लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस न तो उन्हें और न ही उनकी नीमच और गाजीपुर में यूनिटों को प्राप्त हुआ है। अनुलिपि लाइसेंस मूल लाइसेंस के पूरे मूल्य अर्थात् 38,00,000/—रु० के लिए अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र सं० ए० 66012/42/86-सी०एम., दिनांक 18-11-87 में अनुलिपि लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

3. मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं० जी/पी/1106484 दिनांक 19-10-87 पारगमन में कहीं खो गया है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9(घ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा आयात लाइसेंस जी/पी/1106484, दिनांक 19-10-87 को रद्द करता हूं। इस रद्द किए गए मूल लाइसेंस के बदले में पार्टी को 38,00,000/—रुपये के लिए एक अनुलिपि लाइसेंस अलग से जारी किया जा रहा है।

[फाइल सं० 3-गवर्ट/एम/एफ/87-88/ए०एल०एस०]

एन०एस० कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 8th December, 1987

ORDER

S.O. 3536.—Ministry of Finance, Department of Revenue Central Board of Excise & Customs, New Delhi were granted an Import Licence No. G/P/1106484 dated 19th October, 1987 for Rs. 38,00,000 (Rupees Thirty Eight Lakhs only) for import of 1000 Kg of Codine Phosphate and 400 kg of Noscapine B.P. in exchange for opium for use by their units—Government Opium & Alkaloid Works Undertakings at Neemuch and Gazipur.

The Ministry of Finance has applied for issue of duplicate licence on the ground that the Original licence has not been received by them or their Units at Neemuch and Gazipur. The duplicate licence is required for the entire amount of the original licence viz. Rs. 38,00,000. The Ministry of Finance have requested in their letter No. A-66012/42/86-CM dated 18th November, 1987 for issue of a duplicate licence.

3. I am satisfied that the original licence No. G/P/1106484 dated 19th October, 1987 has been lost in transit. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(d) of Import Control Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended, I hereby cancel the Import Licence G/P/1106484 dated 19th October, 1987. I duplicate Import Licence for Rs. 38,00,000 is being issued to the party in lieu of the original licence cancelled hereby.

[F. No. 3-Govt./M/F/87-88/ALS]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 3537—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/2/87, तारीख 15 सितम्बर, 1987 का निरीक्षण नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सिंगरौली के कार्यालय में या कलक्टर, सिधी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अनुभाग, नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली को भेजेंगे।

अनुसूची

गोर्वी ब्लाक विस्तार

नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड

सिंगरोली (जिला सिन्धी) मध्य प्रदेश

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्र.सं.	ग्राम	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	गोर्वी	चितरंगी	सीधी	39.00 (लगभग)	भाग
2.	नोरडिया	,,	,,	54.00 (लगभग)	,,
3.	महदयया	,,	,,	292.00 (लगभग)	,,
4.	फुलझर	,,	,,	32.00 (लगभग)	,,
5.	कसर	,,	,,	10.00 (लगभग)	,,
			कुल क्षेत्र :	427.00 एकड़ (लगभग)	
			या	172.80 हेक्टर (लगभग)	

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा नोरडिया और महदयया ग्राम से होकर जाती है।

ख—ग रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है।

ग—घ रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है।

घ—ङ रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है।

ङ—च रेखा महदयाय और कसर ग्राम से होकर जाती है।

च—छ रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है।

छ—ज रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है।

ज—झ रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है।

झ—ञ रेखा कसर ग्राम से होकर जाती है।

ञ—ट रेखा कसर और महदयया ग्राम से होकर जाती है।

ट—ठ रेखा महदयया ग्राम से होकर जाती है।

ठ—ड रेखा महदयया और फुलझर ग्राम से होकर जाती है।

ड—ढ रेखा फुलझर और गोर्वी ग्राम से होकर जाती है और गोर्वी ग्राम में बिन्दु "ढ" पर मिलती है जो गोर्वी ब्लाक के साथ साथ सामान्य सीमा बनाती है।

ढ—ण रेखा गोर्वी और नोरहिया ग्राम में से गुजरती है, जो गोर्वी ब्लाक की सामान्य सीमा बनाता है।

ण—क रेखा नोरहिया ग्राम में से गुजरती है, जो गोर्वी ब्लाक की सामान्य सीमा बनाता है।

[सं. 43015/19/87-सी.ए./एल.एस. डब्ल्यू.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 23rd November, 1987

S.O. 3527.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (28 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for Coal therein.

The plan No. Rev/2/87 dt 15-9-87 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Northern Coalfields Limited (Revenue Section), Singrauli or at the office of the Collector, Sidhi (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in Sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Section, Northern Coalfields Limited, Singrauli within 90 days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE
GORBI BLOCK EXTENSION
NORTHER COAL FIELDS LIMITED
SINGRAULI
Distt Sidhi (M.P.)

Lands notified for prospecting :—

Sl No.	Village	Tahsil	District	Area		Remarks
1.	Gorbi	Chitrangi	Sindhi	39.00	(approx.)	Part
2.	Naurbia	,,	,,	54.00	,,	,,
3	Mahdaiya	,,	,,	292.00	,,	,,
4	Fuljhar	,,	,,	32.00	,,	,,
5.	Kasar	,,	,,	10.00	,,	,,
			Total :	427.00	Acres (approx.)	
			or	172.60	Hectares (approx)	

A-B Line passes through village Naurbia and Mahdeiya.
B-C Line passes through village Mahdeiya.
C-D Line passes through village Mahdeiya.
D-E Line passes through village Mahdeiya.
E-F Line passes through village Mahdeiya and Kasar
F-G Line passes through village Kasar.
G-H Line passes through village Kasar
H-I Line passes through village Kasar.
I-J Line passes through village Kasar.
J-K Line passes through village Kasar and Mahdeiya.
K-L Line passes through village Mahdeiya.
L-M Line passes through village Mahdeiya and Fuljhar.
M-N Line passes through village Fuljhar and Gorbi and meets at point 'N' in village Gorbi which forms common boundary with Gorbi Block.
N-O Line passes in village Gorbi and Naurbia which forms common boundary of Gorbi Block.
O-A Line passes in village Naurbia which forms common boundary of Gorbi Block.

[No 43015/19/87-CA/I(SW)]

का.आ. 3538.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 सितम्बर, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 4267, तारीख 21 अगस्त, 1985 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 894.05 हेक्टर (लगभग) या 2209.24 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और उक्त भूमि की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 सितम्बर, 1987 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

आई.बी. घाटी कोयला क्षेत्र में ओरीएंट खान संख्यांक 1, 2 और 3 का वेस्टर्न ब्लाक जिला सम्बलपुर (उड़ीसा राज्य)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	गन्डधोरा	झारसुगुडा	सम्बलपुर	200.00	भाग
2.	चिगरीगुडा	यथोक्त	यथोक्त	300.00	भाग
3.	जामकानि	लखनपुर	यथोक्त	400.00	भाग
4.	छुआलिबेरना	झारसुगुडा	यथोक्त	1100.00	भाग
5.	आमदरहा	यथोक्त	यथोक्त	169.24	भाग
6.	लाजकुरा	यथोक्त	यथोक्त	40.00	भाग
			कुल क्षेत्र :	2209.24 एकड़ (लगभग)	
			या	894.05 हैक्टर (लगभग)	

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा, बिन्दु "क" से आरंभ होती है और आमदरहा ग्राम से होकर जाती है और आमदरहा और छुआलिबेरना ग्रामों की सम्मिलित सीमा के बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ग रेखा, जमींदारी वन और छुआलिबेरना ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ जाती है और जमींदारी वन, समडा और छुआलिबेरना ग्राम के दिशांगम बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—घ रेखा, छुआलिबेरना और समडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है, फिर जामकानि और समडा ग्रामों से होकर जाती है और समडा और जामकानि ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर, बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ—ङ रेखा, जामकानि, चिरीगुडा और लाजकूरा ग्रामों से होकर जाती है, और लाजकूरा ग्राम में बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ—क रेखा, लालकूरा, छुआलिबेरना, गन्धधोरा ग्रामों से होकर जाती है, फिर आमदरहा ग्राम की दक्षिण पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

(43015/16/86—सी.ए./एल.एस. डब्ल्यू.)

S.O. 3538.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) number S.O. 4267, dated the 21st August 1, 1985 under sub-section (1) o fsection 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 14th September, 1985, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 894.05 hectares (approximately) or 2209.24 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, in respect of the said lands, no notice under-section (1) of Section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 14th September, 1987 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

THE SCHEDULE

WESTERN BLOCK OF ORIENT MINE NOS. 1, 2 AND 3

IB VALLEY COALFIELD

DISTRICT SAMBALPUR (ORISSA STATE)

Serial number	Name of the village	Tahsil	District	Area in acres	Remarks
1.	Gandghara	Jharsuguda	Sambalpur	200.00	Part
2.	Chingriguda	Jharsuguda	Sambalpur	300.00	Part
3.	Jamkani	Lakhanpur	Sambalpur	400 00	Part
4.	Chhualiberna	Jharsuguda	Sambalpur	1100.00	Part
5.	Amadarha	Jharsguda	Sambalpur	169.24	Part
6.	Lajkura	Jharsuguda	Sambalpur	40.00	Part
		Grand total area :		2209.24 acres (approximately)	
			or	894.05 hectares (approximately)	

Boundary description :

A-B Line starts from point 'A' and passes through village Amadarha and meets on the common boundary of village Amadarha and Chhualiberna at point 'B'.

B-C Line passes along the common boundary of zamindari forest and village Chhualiberna and meets on tri-junction point of zamindari forest, village Samda and Chhualiberna at point 'C'.

C-D Line passes along the common boundary of villages Chhualiberna and Samda, then Jamkani and Samda and meets on the common boundary of villages Samda and Jamkani at point 'D'.

D-E Line passes through villages Jamkani, Chingriguda and Lajkura and meets in the village Lajkura at point 'E'.

E-A Line passes through villages Lajkura, Chhualiberna, Gandghara, then proceeds along the south-eastern boundary of village Amadarha and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/16/85-CA/LSW]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1987

का.आ. 3539.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/27/87 तारीख 8 जुलाई, 1987 का निरीक्षण केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लि., राजस्व अनुभाग, दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) के कार्यालय में या उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लि., दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) को भेजेंगे।

अनुसूची

ब्लाक "डी" (दामोदर और नकोरी नदी तल में) दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र जिला हजारी बाग (बिहार)
पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित करते हुए

क्र.सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	प्लाट सं.	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	गिढी	मांडू	36	हजारीबाग	863	2.50	भाग
2.	सौदा	रामगढ़	24	,,	4	6.20	,,
3.	दियोरिया	,,	48	,,	1	5.27	,,
					23	15.30	,,
					कुल क्षेत्र	29.27 एकड़ (लगभग)	
					या	11.84 हैक्टर (लगभग)	

सीमा-वर्णन :

क—ख रेखा ग्राम सांदा और दियोरिया बरगंवा में नकारी नदी से होकर जाती है।

ख—ग रेखा ग्राम, दियोरिया बरगंवा में नकारी नदी के दाहिने किनारे के साथ साथ जाती है।

ग—घ रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है (जो दियोरिया बरगंवा और ढंढवा की सामान्य सीमा बनाती है और ग्राम गिदी में दामोदर नदी से होकर भी जाती है।)

घ—ङ रेखा ग्राम गिदी में दामोदर नदी के भाग बाएं किनारे के साथ साथ जाती है।

ङ—च—छ रेखा ग्राम गिदी और दियोरिया बरगंवा में दामोदर नदी में से होकर जाती है।

छ—ज रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है। जो सोदा और दियोरिया बरगंवा की सामान्य सीमा बनाती है।

ज—झ रेखा नकारी नदी की भाग केन्द्रीय रेखा के साथ साथ जाती है (जो ग्राम सौंटा और दियोरिया बरगंवा की भाग सामान्य सीमा बनाती है।

झ—ञ रेखा ग्राम सोदा में नकारी नदी में से होकर जाती है।

ञ—क रेखा ग्राम सौंदा में नकारी नदी के भाग बाएं किनारे के साथ साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/16/87-सी ए]
बी. बी. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 12th November, 1987

S.O. 3539.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Cenrral Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/27/87 dated the 8th July, 1987 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) or in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, chars and other documents referred to in sub-section 7 of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

BLOCK 'D' (in Damodar & Nakari River Bed)
SOUTH KARANPURA COALFIELD
DISTRICT HAZARIBAGH (BIHAR)

Serial number	Village	Thana	Showing land notified for prospecting				
			Thana number	District	Plot No.	Area in acre	Remarks
1.	Gidi	Mandu	36	Hazaribagh	863	2.50	Part
2.	Saunda	Ramgarh	24	"	4	6.20	"
3.	Deoria Barganwa	"	48	"	1	5.27	"
					23	15.30	"
			Total area :			29.27 acres (approximately)	
					or	11.84 Hectare (approximately)	

Boundary description :—

A-B Line passes through Nakari River in villages Saunda and Deoria Barganwa.

B-C Line passes along right bank of Nakari River in village Deoria Barganwa.

C-D Line passes through Damoder River (which forms common boundary with Deoria Barganwa and Dundwa and also through Demodar River in village Gidi).

D-E Line pos es along the part left bank of Rivver Damodar in village Gidi.

E-F Line passes through Damodar River in village Gidi
-G and Deoria Barganwa.

G-H Line passes through Damodar River (which forms common boundary with Saunda and Deoria Barganwa).

H-I Line passes along the part Central line of Nakari River (which forms part common boundary of villages Saunda and Deoria Barganwa).

I-J Line passes through Nakari River in village Saunda.

J-A Line passes along the part left bank of Nakari River in village Saunda and meets at starting point 'A'.

B. B. RAO, Under Secy.

[No. 43015/16/87-CA]

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1987

का. आ. 3540.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम, 1976 के अंतर्गत नियम 8 के उप-नियम (4) के अनुसरण में विद्युत् विभाग के प्रशासन—दो अनुभाग, प्रशासन—तीन अनुभाग, पुस्तकालय और रोकड़ अनुभाग के निम्नलिखित कार्य केवल हिन्दी में करने के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :—

प्रशासन—दो अनुभाग

(1) अर्जित छुट्टी व अन्य प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के आदेश।

(2) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति से संबंधी आदेश।

(3) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में सभी प्रकार की प्रविष्टियां

(4) लघु अवधि वाले अग्रिम (जैसा कि त्यौहार अग्रिम राशि, साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम राशि, पंखा खरीदने के लिए अग्रिम राशि आदि से संबंधी आदेश)।

(5) सभी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि/निकासी (विदड्राल से संबंधी कार्य)

प्रशासन—तीन अनुभाग

(1) स्थायी/अस्थायी पास जारी करने संबंधी कार्य।

(2) टेलीफोन बिलों के भुगतान करने संबंधी सभी नोटिंग।

(3) सफाई का सामान और फर्नीचर की मदें की खरीद से संबंधी नोटिंग।

(4) स्टाफ कार की लाग-बुक में सभी प्रविष्टियां।

पुस्तकालय

(1) सदस्यता टिकट जारी करने संबंधी सभी कार्य।

(2) हिन्दी पुस्तकों की सूची एवं संबंधित कार्य हिन्दी करना।

रोकड़ अनुभाग :

वेतन बिल (पे बिल)/निस्तारण पंजी (एक्विटेंस रोल) में सभी नाम हिन्दी में लिखना।

[सं. ई-11017/10/87—हिन्दी]

दीवान चन्द, उप सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 25th November, 1987

S.O. 3540.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 8 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies Administration-II, Administration-III, Library and Cash Sections of the Department of Power for using Hindi alone for the following business :—

I. Administration-II Section

1. Orders for sanctioning of Earned Leave and other kinds of Leave.
2. Orders for appointment, posting, transfer, promotion and reversion in respect of Class-IV employees.
3. All entries in the Service Book of Class-IV employees.
4. Orders for sanctioning of short-term advance, (like Festival Advance, Cycle Advance, Fan Advance etc.)
5. Work relating to sanctioning of G.P.F. advances/ withdrawals in respect of all categories of staff.

II. Administration III Section

1. Work relating to the issue of permanent/temporary passes.
2. Noting in respect of payment of telephone bills.
3. Noting in respect of purchase of sanitary and furniture items.
4. Entries in log books of staff cars.

III. Library

1. Work relating to the issue of Membership Cards.
2. Preparation of catalogue and accession of Hindi books in Hindi.

IV. Cash Section

All names in Pay Roll/Acquittance Roll in Hindi.

[No. E-11017/10/87-Hindi]

DIWAN CHAND, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल

म0प्र0 परिमंडल,)

भोपाल, 25 नवम्बर, 1987

का०आ० 3541 :—यतः, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि श्री एम० जी० शेंडे, छटाई सहायक, रेल डाक सेवा रायपुर संभाग, अभिलेख कार्यालय नागपुर के विरुद्ध विभागीय जांच के प्रयोजन से निम्नलिखित व्यक्तियों को साक्षियों के बतौर समन किया जाना आवश्यक है :—

(i) श्री एन०के० नायक, सेवा निवृत्त अधीक्षक डाकघर, द्वारा-उप डाकपाल करेली जिला नरसिंहपुर (म० प्र०) ।

(ii) श्री एच० एन० सेन गुप्ता, सेवा निवृत्त मुख्य छटाई सहायक (एल० एस० जी०) क्वार्टर नं० जनता-30 म०प्र० गृह निर्माण मण्डल कालोनी, शंकर नगर, रायपुर (म० प्र०) ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विभागीय जांच साक्षियों की उपस्थिति तथा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण को प्रवर्तन अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एतद्द्वारा उक्त श्री एम०जी० शेंडे, छटाई सहायक, रेलडाक सेवा रायपुर संभाग अभिलेख कार्यालय नागपुर के विरुद्ध सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियमावली 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिये श्री बी०एस० पटेल, उप संभागीय निरीक्षक (डाक) छिन्दवाड़ा (म० प्र०) को जांच प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[संख्या डिस्क/53/आर०एम०एस० आर०पी०/86]

जी०व्ही०एस० राव, पोस्टमास्टर जनरल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(Office of the Postmaster-General, M.P. Circle)

Bhopal, the 25th November, 1987

S.O. 3541.—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purpose of the departmental inquiry relating to Shri M. G. Shende, Sorting Asstt., Railway Mail Service, 'RP' RMS Division, Record Office, Nagpur, it is necessary to summon as witnesses the following persons :—

(i) Shri N. K. Nayak, Retired Superintendent of Post Offices, C/o Sub Postmaster, Kareli, District Narsinghpur (M.P.).

(ii) Shri H. N. Sengupta, Retired L.S.G. HSA, Quarter No. Janata-30, M.P. Housing Board, Colony, Shankar Nagar, Raipur (M.P.).

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of attendance of witnesses and production of documents) Act, 1972 (XVIII of 1972) the Central Government hereby authorises Shri B. S. Patil, Sub Divisional Inspector (Postal), Chhindwara as the inquiring authority to exercise powers specified in Section 5 of the said Act in relation to the departmental enquiry under rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 against the said Shri M. G. Shende, Sorting Assistant, RMS 'RP' Division, Record Office Nagpur.

[No. DISC/53/RMS RP/86]

G. V. S. RAO, Postmaster-General

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3542.—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 671(अ), तारीख 16 सितंबर, 1985 की सारणी में,—

(क) क्रम सं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबन्धित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

1	2	3
"8 क.	जम्मू-कश्मीर कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार, जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर राज्य"

(ख) क्रम सं. 29 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3
"29क	सहकारी लेखा परीक्षा निदेशक, मद्रास	तमिलनाडु राज्य"

[सं. एल—11012/2/85—एल एण्ड एम]
अलोक भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt. of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 9th December, 1987

S.O. 3542.—In exercise of the powers confered by sub-section (2) of section 4 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984(51 of 1984), the Central Government hereby directs that in the Notification of the Govt. of India inthe Ministry of Agriculture & Rural Development, Deptt. of Agriculture & Cooperation No. S.O. 671(E) dated the 16th September, 1985, in the Table,—

(a) after serial number 8, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :

1	2	3
8A	The Registrar of Cooperative Societies, J&K appointed udder section 3 of the Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act, 1960	The State of Jammu and Kashmir

(b) after serial number 29, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

1	2	3
29A	The Director of Cooperative Audit, Madras.	The State of Tamil Nadu.

[No. L-11012/2/85-L&M]
ALOK BHATNAGAR, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

का.आ. 3543—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले इंडियन एयर-लाइन्स के निम्नलिखित स्टेशनों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. इंडियन एयरलाइन्स स्टेशन, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
2. इंडियन एयरलाइन्स स्टेशन, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

[संख्या ई – 11011/4/85 – हिन्दी]
एस. गणेशपाण्डियन, निदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 8th December, 1987

S.O. 3543.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for the official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following stations of the Indian Airlines (under the administrative control of the Ministry of Civil Aviation), the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi namely :—

1. Indian Airlines Station at Kanpur (U.P.)
2. Indian Airlines Station at Gwalior (M.P.)

[No. E. 11011/4/85-Hindi]
S. GANESPANDIAN, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1987

का. आ. 3544अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1965 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री अनिल बोर्डिया, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग को श्री आनन्द सरूप के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक सदस्य के रूप में नामोदिष्ट करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2959, दिनांक 6 जुलाई, 1983 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"श्री अनिल बोर्डिया, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ।	— मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि ।"

[संख्या वी. 16011/1/87—एम. ई (पी. जी.)]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th November, 1987

S.O. 3544.—In pursuance of clause (d) of section 4 read with sub-section (3) of section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Anil Bordia, Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Education, to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, vice Shri Anand Sarup resigned, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 2959 dated the 6th July, 1983, namely :—

In the said notification, for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely :—

"Shri Anil Bordia, Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Education.	—Representative of the Ministry of Human Resource Development Department of Education.

[No. V. 16011/1/87-ME(PG)]

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3545.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध के अनुसरण में डा. अवध किशोर नारायन सिन्हा को बिहार राज्य से इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम. आई. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

10. डा. अवध किशोर नारायन सिन्हा,
अहियापुर हाउस,
कादम कुआं,
पटना-800003

[सं. वी. 11013/60/87-एम. ई. (पी)]
आर. के. अहूजा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 17th December, 1987

S.O. 3545.—Whereas in pursuance of the provision of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Awadh Kishore Narain Sinha has been elected from the Bihar State to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, tn pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No.5-13|59 MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (c) of sub-section (1) of sectton 3" for serial number 10 and enjry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

10. Dr. Awadh Kishore Narain Sinha,
Ahiyapur House, Sahitya Sammelan Road,
Kadam Kaun, Patna-800003.

[No. V. 11013|60|87-ME(P)]
R. K. AHOOJA, Jt. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्त्री और बाल विकास विभाग)
धमार्थ दान अधिनियम, 1890 (1890 की 6) के संबंध में
और
राष्ट्रीय, बाल कोष, नई दिल्ली के संबंध में

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3546.—धमार्थ दान अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के खंड 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबन्ध बोर्ड के निवेदन पर तथा उसकी सहमति से एतद्द्वारा आदेश जारी करती है कि पांच वर्षीय सावधि जमा लेखा में निवेश की गई रु. 10,00,000.00 (केवल दस लाख रुपए) की धनराशि भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की दिनांक 2 मार्च, 1979 की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या एल. ओ.-120(ई) के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए योजना के अनुसार विनियोग किए जाने के लिए भारतीय धमार्थ निधि के कोषाध्यक्ष के अधीन होगी।

[फा. सं. 2-3/85-टी. आर.]
सुमन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

In the matter of the Charitable Endowments

Act, 1890 (6 of 1890)

In the matter of the National Children's Fund, New Delhi

New Delhi, the 15th December, 1987

S.O. 3546.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi, as in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government both hereby order that the sum of Rs. 10,00,000.00 (Rupees ten lakhs only) invested in 5 year Post Office Time Deposite Account shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi, published with the notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120(E) dated the 2nd March, 1979, as amended from time to time.

[F. No. 2-3/85-TR]

SUMAN NAYAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3547.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 दिसम्बर, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला सबरकांथा में तालुक हिम्मत नगर के हिम्मत नगर नगर पालिका और राजस्व बीमा तथा जी०आई०डी०सी० हिम्मत नगर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

[सं० एस०-38013/33/87-एस०एस०-I]

ए०के० भट्टाराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th December, 1987

S.O. 3547.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th December, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

"The areas within the Municipal and revenue limit of Himat-Nagar and GIDC Himatnagar of Taluka Himatnagar District Sabarkantha."

[No. S. 38013/33/87-SS. I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3548.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-11-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th December, 1987

S.O. 3548.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of National Insurance Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
Case No. CGIT/LC(R)(69) of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of National Insurance Company Ltd., Firdos Chambers, Jawaharlal Nehru Marg, Nagpur (M.S.).

AND

Their workman Shri Rajendra Manohar Deshmukh, Near Benoda Pumpong Station, Chhatri Talao Road, Amravati.

APPEARANCES :

For workman—Shri V. R. Deshpande.

For management—Shri S. K. Mishra, Advocate.

INDUSTRY : Insurance. DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated, the November 23, 1987

By Notification No. L-17012/73/85-D.IV(A) dated 22nd August, 1986 the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Amravati Branch in terminating the services of Shri Rajendra Manohar Deshmukh sub-staff w.e.f. 13th July, 1985 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. Facts which are no longer in dispute are that the workman, Shri Rajendra Manohar Deshmukh, was employed by the Insurance Company at Nagpur as casual daily rated basis from 6th June, 1983 at the rate of Rs. 8 per day. Thereafter wages were increased from time to time and ultimately raised to Rs. 14 per day till the date he was discontinued in service with effect from 13th July, 1985.

3. It is not disputed by the management that the workman, Shri Rajendra Manohar Deshmukh, worked as under :—

1983 — 171
1984 — 293
1985 — 149

His services were terminated without notice or pay in lieu of notice without any retrenchment compensation or without issuing him charge sheet. On the basis of actual working days

on the principle of no work no pay, he was discontinued with effect from 13th July, 1985 but again appointed as a sub-staff after complying with the norms of recruitment with effect from 26th May, 1986 and he is continuing in that capacity.

4. The case of the workman further is that he was appointed in a clear vacancy in the clerical capacity as sub-staff. His services were terminated though his juniors were retained and fresh persons were taken in employment and absorbed in regular service. He had worked continuously from 6th May, 1983 to 13th July, 1985.

5. The case of the management is one of denial of the allegations of the workman.

6. Fresh appointment of workman is not the subject matter of reference. I, therefore, need not go into it.

7. First question that arises for consideration is whether the workman worked continuously for near 240 days. In tnsi regard he has filed the certificate (Ex. W/2) of Branch Manager, Amravati that he worked from 6th May, 1983 to 13th July, 1985 full time as casual daily peon and his work was satisfactory. This proves that he worked continuously for the purpose of Sec. 25B and S. 25F of the I. D. Act. However, since the authority of the Branch Manager has been challenged to grant such a certificate I propose to consider the case from another angle. I have already pointed that in their pleading the management has admitted that the workman worked with them 171 days in 1983, 293 days in 1984 and 149 days in 1985. The workman in support of his case has relied on a list of his working days with the management (Ex. W/1) and payment authorities Ex. W/3 to Ex.W/120 which is not rebutted by the management. This goes to show that the workman worked with the management with certain breaks with effect from 6-6-1983 to 13-7-1985 and he was paid for his working days weekly. For no fault of the workman he was given artificial breaks by the management. On this artificial breaks the management has contended that in the last year under reference he had not worked for 240 days in a year. Therefore he cannot be deemed to be in continuous service. I am unable to agree. This interpretation is fallacious.

8. In his book "The Law of Industrial Disputes" Fourth Edn. Vol. 2 learned Author, Shri O. P. Malhotra, relying on various authorities at pages 1311-1312 has commented as under :—

> "Sub-section (2) provides for a fiction to treat a workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered an uninterrupted service for a period of one year but he has rendered service for a period of 240 days during the period of 12 calender months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in sub-section 2(a). It is necessary to determine first the service which is complained of as 'retrenchment'. After that date is ascertained, move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the period of 12 months, the workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively answered in favour of the workman, pursuant to the deeming fiction enacted in sub-section (2), it will have to be assumed that the workman is in "continuous service for a period of one year", and he will satisfy the eligibility qualifications enacted in Section 25B".

9. Another learned Author, Shri Vithalbhai B. Patel in his book 'Law on Industrial Disputes' 3rd Edn. Vol. 1 has reiterated the above at page 757 in the following words :—

> "Continuity of service does not necessarily mean that a workman must have one completed year of service in every year. It is sufficient that continuity of service exists and arises even if a workman works for the number of days specified in the section during a period of twelve calender months preceding the date with reference to which calculation is to be made, because the fiction converts service of specified number of days into continuous service for one complete year."

10. Neither the management has pointed out any reason nor I see so to differ from the views of the learned Authors. In any case the wordings of the Sec. 25F also go to show that this interpretation is the only plausible interpretation.

11. For the reasons discussed above, it is proved that the workman had put in continuous service of more than 240 days preceding the date with reference to which the calculation is to be made.

12. Further contention of the management is that in any case taking the broken period of his service into account it cannot be said during any year that he had uninterrupted service for a period of one year in any of those years. This contentions to my mind is also fallacious. Sub-section (1) of Sec. 25B of the I.D. Act lays down that if the cessation of work is not on account of any fault on the part of the workman then he will be deemed to be in continuous service for the said period.

13. I have already pointed out that it is an admitted position that the workmnn was neither given notice nor pay in lieu of notice nor any retrenchment compensation though he had put in more than 240 days service in the preceding 12 calendar months under reference.

14. It is now well settled that once a workman sails into the harbour of Section 25B of the I.D. Act his termination for whatsoever reasons amounts to retrenchment. In the case of Mohan Lal Vs. Manager of M/s. Bharat Electronics Ltd. (AIR 1981 SC 1253) the Hon'ble Supreme Court held as under :—

> "Niceties and semantics apart, termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever would constitute retrenchment except in cases exempted in the section itself."

Thus discontinuance of service of the workman amounts to retrenchment and as normal rule he is liable to be reinstated with all ancillary reliefs, but admittedly the workman has been appointed as a fresh candidate with effect from 25th May, 1986. In the circumstances, I answer the reference as under :—

> That the action of the management of National Insurance Co. Ltd. Amravati Branch in terminating the services of Shri Rajendra Manohar Deshmukh, Substaff w.e.f. 13th July, 1985 is illegal and unjustified. It is, therefore, ordered that the workman be reinstated with effect from 13th July, 1985 with full back wages and all ancillary reliefs i.e. his seniority and wages accordingly and further the management is directed to pay the difference of wages which were already paid to him with effect from 26th May, 1986 and pay and allowances admissible to him with effect from 13th July, 1985 taking his seniority from the date of his termination. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-17012/73/85-D.IV(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3549.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सीनियर सुप्रिन्टेन्डेंट पोस्ट आफिस के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 7th December, 1987

S.O. 3549.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Senior Superintendent of Post Office and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st December, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(21)/1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Senior Superintendent of Post Offices, Girlpeth, Nagpur-10

AND

Their workman Shri Deorao S/o Tukaram Patre, R/o Pardi, Post Bhandewadi, Nagpur-8 (M.S.).

APPEARANCES :

For workman—Shri Bagale, Advocate.

For management—S/Shri S. V. Natu, Advocate and V. V. Vidwans, Advocate.

INDUSTRY : Post & Telegraphs DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : November 20, 1987

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-40012/85-D.II(B) dated 23rd January, 1986 for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of Senior Superintendent of Post Offices, Nagpur City Division, Nagpur in not giving an opportunity for re-employment to Shri Deorao Tukaram subsequent to his termination with effect from 13th July, 1983 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. Facts which are no longer in dispute are that the workman was employed on daily wages as a Postman which is a post in Group C Cadre as against the casual labour in Group D Cadre. The workman worked as such in broken period from 15th April, 1981 to 13th July, 1983 as and when his services were required as a Postman on account of absence of leave of a regular Postman. The workman worked for 190 days in 1981, 110 days in 1982 and 138 days in 1983 as per Annexure A attached. The workman was discontinued from service on the recruitment of postman by selection through the prescribed test held on 7th October, 1982 and 83 candidates were recruited as per list B. It is further admitted that at the time of discontinuance of his service workman was not paid any retrenchment compensation.

3. The case of the management is that he was not a regular workman. Therefore he was not entitled to any retrenchment compensation. The letter concerning regularisation of the workers in the department related to only those workers who had worked 240 days or more in two consecutive years after passing the necessary prescribed test.

4. The case of the workman is that he was employed as a casual labour (Postman) in the office of the Assistant Postmaster in Delivery Section, Nagpur City, with effect from 15th April, 1981 to 13th July, 1983. His services were terminated with effect from 13th July, 1983 without complying with the provision of Sec. 25F of the I.D. Act. He is, therefore, entitled to be re-employed.

5. As already pointed out above, from the admitted facts the position is, as has been admitted by Shri M. B. Vijayker, Asstt. Superintendent of Post Offices, Sub-Division No. 2 of City Nagpur, that the workman was employed in broken period on daily wages as Postman from 15th April, 1981 to 13th July, 1983. The plea of the management as also stated by Shri Vijayker is that workman was working as Class C employee, therefore, He could not be absorbed as Class D employee which is a lower grade as per the instructions dated 21st February, 1983 Annexure A. This said the least is nothing but a lame excuse. If he could not be employed as Postman in Group C at least he could have been employed in a lower grade of Group D.

6. As for the plea that the workman had not qualified in the literary test, it will suffice to say as has been admitted by Shri Vijayker that he had no knowledge whether the applicant was called for the said test. The statement of the workman is that he was not given any information to appear in such a test. In fact, Shri Vijayker, had admitted that as per the practice 50 per cent of the workers of Class D are regularised in Class C post after the necessary literary test.

7. Next objection for re-employing the workman stated to be is that looking to broken period his service he cannot be deemed to be in continuous service as per the provision of S. 25B of the I.D. Act. In other words, it is argued that the workman had not put in 240 days service since in the year 1983 he had not actually worked during a period of 12 calendar months preceding the date of his termination. Therefore he cannot said to be in continuous service for the purpose of Sub-section (2) of Section 25B of the I.D. Act I am unable to agree.

8. Management has not correctly interpreted the relevant provision of Section 25B of the I.D. Act. in the case of Mohan Lal Vs Bharat Electronic Ltd. (reported in 1981 Lab. I.C. 806) Supreme Court laid down that "Sub-section (2) provides for a fiction to treat a workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he had not rendered uninterrupted service for a period of one year, but he had rendered service for a period of 240 days during the period of 12 calendar months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in Sub-section 2(a), it is necessary to determine first the relevant date i.e. the date of termination of service which is complained of as 'retrenchment'. After that date is ascertained, move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the period of 12 months, the workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively answered in favour of the workman, pursuant to the deeming fiction enacted in sub-section 2(a), it will have to be assumed that the workman is in "continuous service or a period of one year", and he will satisfy the eligibility qualification enacted in Section 25F".

9. As a last resort on behalf of the management it has been contended that there are so many broken spells and that if the same are left out the applicant would not be deemed to have completed 240 days service in the last preceding year. This contention is also fallacious and devoid of any substance. Sub-section (1) of Section 25B of the I.D. Act defines continuous service for the purpose of the said chapter. It says, the workman shall be deemed to be in continuous service if the cessation of work is not due to any fault on the part of the workman. The broken spell of service of the workman were no fault of his. Therefore that part of broken period of service will be taken account while counting the period of his service backward from the date of his retrenchment. It is now well settled that the termination of service of the workman for whatsoever reason amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D. Act.

10. For the reasons discussed above, I am of the opinion that firstly termination of the workman was illegal. Secondly as the workman has also stated that after his repeated request orally and in writing he was not re-employed on flimsy grounds. I, therefore, answer the reference as under :—

That the action of the management of Senior Superintendent of Post Offices, Nagpur City Division, Nagpur in not giving an opportunity for re-employment to Shri Deorao Tukaram subsequent to his termination with effect from 13th July, 1983 is illegal

and unjustified. He is, therefore, entitled to be re-employed on the same post with continuity of service with effect from 13th July, 1983, with full back wages and all ancillary reliefs. I make no order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-40012/12/85-D.II(B)]

का. आ. 3550.—औद्योक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, जनरल मैनेजर पश्चिम रेलवे बम्बई, सीनियर डी. एम. ई. (लोको) बड़ोदा डी आर एम. पश्चिम रेलवे बड़ोदा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण न. 1, बम्बई के पंचापट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 3550.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Gove n-ment Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Disputes between the employers in relation to the management of General Manage", Western Railway, Bombay, Sr. D.M.E. (Loco) Baroda, D.R.M. Western Railway, Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Mr. Justice M. S. Jamdar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-15 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of G.M. Western Railway, Bombay, Sr. DME (Loco) Ba oda, DRM Western Railway, Baroda.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management—Mr. P. R. Pai, Advocate.

For the Workman—Mr. Anil Gupta, Advocate holding for Mr. Jha, Advocate.

INDUSTRY : Railway STATES : Maharashtra and Gujarat.

Bombay, the 18th day of November, 1987

AWARD

By an order passed in October, 1985, the Central Government, in exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Railway Administration in not paying the wages to Shri Husen Miya Call Boy for the period from 3rd May, 1984 to 7th November, 1984 is justified ? If not, to what relief Shri Husen Miya is entitled ?"

2. The workman, Husen Miya was placed under suspension with effect from 15th April, 1984 by an order of even date. This suspension was revoked on 28th April, 1984. Thereafter, he resumed duty and remained present for work on 30th April and 1st May, 1984. 2nd May was a rest day for him and from 3rd May, 1984, he remained absent till 7th November, 1984.

3. It is the case of the workman that he was prevented from working and was put off duty with effect from 3rd May, 1984 without assigning any reason and without giving him anything in writing. According to the management, the workman voluntarily remained absent from 3rd May, 1984.

4. Shri Purushottam Sadashiv Bhagwat, who is working as Chief Power Controller at Divisional Head-Quarters of the Western Railway has categorically stated in his affidavit of evidence that on revocation of his suspension on 28th April, 1984, Shri Husen Miya did not turn up for work immediately, but came for duty only on 30th April, 1984 and worked only upto 2nd May, 1984. He also categorically stated that thereafter, Husen Miya did not turn up for work, nor did he send any intimation about his absence. He has further asserted that Husen Miya came back to work only on 8th November, 1984. Shri Bhagwat was not subjected to any cross-examination. Apart from that, his evidence that Shri Husen Miya turned up for work only from 30th April, 1984 to 2nd May, 1984, then remained absent till 7th November, 1984, and came back to work only on 8th November, 1984 is completely borne out by the entries in the muster rolls of class-III and Class-IV of the Power Control Department of the Baroda Divisional Office for the period from April, 1984 to June, 1985. The relevant entries in the muster rolls which are marked Exhibit M-1 and M-2 clearly show that the workman was absent from 3rd May, 1984 till 7th November 1984. The workman has not led any evidence to show that he was prevented from attending duty during this period. Moreover, there was absolutely no reason for the Railway Administration to indulge in such unfair practice. As mentioned above, he was allowed to join duty after revocation of suspension order and also on 8th November, 1984 even after such a long unauthorised absence. The workman has not led any evidence to support his allegation which prima-facie appears to be a want on allegation.

5. Workman therefore would not be entitled to any wages for the period 3rd May, 1984, to 7th November, 1984 and the action of the Railway Administration in not paying wages for the period was perfectly justified. But as stated by Shri Bhagwat in his affidavit, in the conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner at Ahmedabad, the Railway Administration had agreed to treat the period from 3rd May, 1984 to 7th November, 1984 as leave without pay. Under the circumstances, this would be the only relief which the workman would be entitled. I, therefore, direct the Railway Administration to treat the absence of the workman Shri Husen Miya from 3rd May, 1984 to 7th November, 1984 as Leave without Pay.

6. Award accordingly.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer
[No. L-41012/5/85-D.II(B)]

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3551.—औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इन्डिया, बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, बम्बई के पंचापट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 8th December, 1987

S.O. 3551.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of International Air-

port Authority of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Mr. Justice M. S. Jamdar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-21 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of International Airports Authority of India, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Mr. Patil Advocate and Mr. Diwakar Goyal, Personnel Officer.

For the Workman—Mr. S. B. Joshi, Branch Secretary of the International Airport Authoity of India Workers' Union.

INDUSTRY : Airlines STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 20th day of November, 1987

AWARD

The dispute which is referred to this Tribunal for adjudication relates to non-confirmation of Miss Jayashree Snivraj Senior Lady Assistant in that grade with effect from 26-6-1979 and not granting her regular annual increments from 25-6-1980 onwards.

2. Miss Jayashree Shivraj was originally appointed as Assistant Lady Announcer with effect from 17-8-1977 and was confirmed in that post on 17-8-1978. She was appointed as Lady Announcer, which post was redesignated subsequently as Senior Lady Assistant, as a direct recruit w.e.f. 26-6-1979 by virtue of appointment order dated 15-6-1979, initially on probation for a period of one year. She was however, not confirmed in the said post and on the contrary as a result of a departmental enquiry she was reverted to the post of Assistant Lady Announcer wef 6-7-1984 for a period of two years, and at the time when this reference was made, she was working in the said post of Assistant Lady Announcer. This period of reversion was reduced to one year on her appeal with the condition that she was to be restored to the original post of Lady Announcer only if her work and performance was found 'above average'. In the meantime, Miss Jayashreet Shivraj raised the present industrial dispute. At the hearing of this reference, parties filed a joint memorandum of settlement, incorporating therein the terms on which International Airports Authority of India Workers Union settled the dispute with the management of IATI and stating that these terms have already been implemented by the management. As mentioned in this memorandum of settlement, the dispute is settled on the following terms.

"1. Miss Jayashree Shivraj is to be restored on her original post of Lady Announcer (redesignated as Senior Airport Hostess).

2. The salary of Miss Jayashree Shivraj is to be fixed as per the Rules."

3. I find that the settlement is reasonable and is in the interests of the workman concerned. Further as stated in the memorandum of settlement, the terms have been implemented by the management and hence the union wants to withdraw this industrial dispute with the condition that the settlement will be treated as final and irrevocable and that, no further Industrial Dispute on the above issues will be raised by the Union as well as by the workman before any Authority or Court of Law. The settlement is therefore accepted and award passed accordingly in terms of the settlement.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer

[No. L-11012/9/85-D.II(B)]

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

In the matter of Industrial Dispute CGIT (IDA) No 21 of 1986

BETWEEN

Miss Jayshree Shivaraj (represented through IAAIWU)

...Workman

AND

International Airports Authority of India, Bombay Airport, Bombay 400099.

Employers

SHORT RECITAL OF THE CASE

Miss Jayshree Shivaraj was appointed as Assistant Lady Announcer with effect from 17-8-1977 and was confirmed on 17-8-1978. Lateron, she was appointed as Lady Announcer with effect from 26-6-1979. Due to a departmental enquiry conducted by the IAAI Hqrs. against her, she was reverted back to the post of Assistant Lady Announcer with effect from 6-7-1984 for a period of 2 years. This period was reduced to one year on her appeal, with a condition that she will be restored to her post, i.e. Lady Announcer, only if her work and performance is found 'above average'. In the meantime, Miss Jaysree Shivaraj raised an Industrial Dispute before the Regional Labour Commissioner (Central), Bombay, who referred the matter to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, for adjudication.

However, the Union has settled the Dispute with the Management of I.A.A.I. on the following terms & conditions:—

1. Miss Jayshree Shivaraj is to be restored on her original post of Lady Announcer (redesignated as Senior Airport Hostess).

2. The salary of Miss Jayshree Shivaraj is to be fixed as per the Rules.

As the above demands have been implemented by the Management, the Union hereby withdraws the said Industrial Dispute with the conditions that the settlement will be reated as final and irrevocable and, that, no further Industrail Dispute on the above issues will be raised by the Union as well as by the workman before any Authority or Court of Law.

The above settlement has been signed by both the parties on this 20th day of November, 1987, in presence of the following witnesses.

Sd/-
(Jayashree Shivraj),
Workman

Sd/-
(A. V. Anand),
Airport Director

Sd/-
(Diwakar Goel)
Ir. Manager, IAAI

Sd/-
(S. B. Joshi),
Branch Secretary,
IAAI Workers' Union

Sd/-
(J. T. Palande)
AG-II (Com)

का. आ. 3552.—औद्योगक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य नियगम लुधियाना के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच. अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चन्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 3552.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India Ludhiana and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th November, 1987.

BEFORE SHRI M. K. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 18/86

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their workman—Vijay Kumar Nishal.

APPEARANCES :

For the workman—Shri Manohar Lal Sharma.

For the management—Shri N. K. Zakhmi.

INDUSTRY : FCI STATE : Punjab.

AWARD

Dated 20-11-1987

Vide Central Government, gazette notification No. L-42012(15)/85-D.(V) dated 14th January, 1986 issued under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947, Ministry of Labour referred the following Industrial Dispute for decision:

"Whether the action of the mangement of Food Corporation of India in refusing promotion to Shri Vijay Kumar Nishal as Asst. Grade II with effect from 2.1.1979 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the workman is that he joined FCI on 1-10-1971 as Asstt. Grade III (Depot). That vide order dated 30-12-1978 Ex. M-2 he was promoted from the said post of Asstt. Grade II. That many workers were promoted at that time. That name of the workman was at serial No. 54. That promotion orders were not served on the workman. That workman came to know of the orders when his colleagus were promoted. That action of the D.M. FCI Ludhiana in withholding the promotion of the workman is void. So he prayed for his promotion from the date 2-1-1979. It is the date when the promotion orders were received by D. M. Ludhiana.

3. The management in their reply did not dispute the factual position but alleged that promotion was subject to the condition that employee is not undergoing any penaly. That on that date i.e. 30-12-1978 workman was undergoing punishment imposed vide order dated 7-12-1977 so orders were not served on him and he was not promoted. That workman has been promoted on 15-10-1983 so present reference has become infractuous.

4. In support of their respective allegations parties placed on the file affidavits and documents. The claim of the workman is being resisted by the FCI on two grounds. First ground raised before me is that order of promotion could not be served on the workman till 2-1-1979 as they were received only on 2-1-1979. That as per M2 the promotion was to take effect latest by 30-12-1978. That as orders could not be served up to 30-12-1978 so workman has no right to claim promotion. This arguments is liable to be rejected forthwith being not raised in written reply. Even otherwise it is admitted by the FCI District Manager Shri Manmohan Singh who appeared as MW1 that in persuance of the above order Rajinder Singh and Bnag Singh have been promoted. If orders could be served on any employee till 30-12-1978 due to its non receipt by D.M. Ludhiana up the said date, there was no occasion for the FCI to serve these orders to Rajinder Singh and Bhag Singh. The above two employees could also not have been promoted under the above orders but case is otherwise. So I am of the view that this argument that orders for promotion can not be given effect due to its non receipt up to 2-1-1979 is devoid of any force and is rejected.

. The next contention of the management is that workman could not be given promotion as he was undergoing punishment imposed on him vide order dated 7-12-1977. Copy of the said order has been placed on the file by the FCI and is Ex. M-3. It is a letter copy of which was sent to the workman and is dated 7-12-1977. In the same it is specified that vide order dated 21-11-1977 one increment of the workman has been withheld without cumulative effect. The date from which the order was to take effect is not specified. So this order M-3 will take effect either from the date when it was passed i.e. 21-11-1977 or from the date when it was communicated to the workman i.e. 7-12-1977 and will expire much before 30-12-1978. So question of the workman undergoing any penalty due to corruption case at that time does not arise. So it will be held that in December, 1978 workman was not undergoing any penalty. The reason given by the FCI for withholding the promotion of the workman in pursuance of the order M-2 dated 30-12-1978 is not proved to be justified.

5. The second ground urged before me is that workman was involved in a corruption case in the March, 1979. So he could not be given promotion later on. This argument cannot be accepted being not so raised in the pleadings. Even otherwise promotion once granted cannot be denied due to involvement of the employees in any departmental case subsequently. For the lapses committed by the employee after grant of promotion he can be punished for the lapses which have been done in the present case i.e. for the lapses committed in March 1979 the workman has already been punished and his two increements were ordered to be forfeited.

6. For the reasons detailed above I am of the view that workman is entitled to promotion from 2-1-1979 from Asstt. Grade III to the post of Asstt. Grade II. The workman will also be entitled to arrear of his pay as fixed in the post of Asstt. Grade II on 2-1-1979. This order will not absolve the workman from the penalty imposed upon him vide order dated 29/30-12-1980 i.e. above order vide which two increments of the workman were stopped cumulative effect will take effect in the grade in which workman will stand promoted from 2-1-1979. Management will also pay arrears so worked out to the workman within one month failing which workman will entitled to recover the arrear together with interest @12 per cent from today. In a way reference is answered in favour of the workman and against the mangement.

Chandigarh,

Dated : 20-11-1987.

M. K. BANSAL, Presiding Officer

[L-42012/15/85-D.VID.II (B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3553:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ईस्ट बासुरिया कॉलयरी, मैसर्स भारत कोकिंग कॉल लिमिटिड के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 9th December, 1987

S.O. 3553.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cenral Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Bassuriya Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 29 of 1983

PARTIES:

Employers in relation to the management of East Bassuriya Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers: Shri B. Joshi, Advocate.
For the Workmen: Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 24th November, 1987

AWARD

By Order No. L-20012(464)/82-D.III(A) dated, the 12th/19th April, 1983, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Messrs. Bharat Coking Coal Limited in terminating the services of Sri Bishnu Parsad Pramanik, Assistant Surveyor in August/September, 1982 after regularising him as Assistant Surveyor, vide the management's Order dated the 5th May, 1981, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the management, stripped of unnecessary details, is as follows:

The defence of the management is two folds—technical and on merits. The management has asserted that the present reference is not legally maintainable. The management has further asserted that it has formulated certain procedure under which certain persons are given chance to take practical trainings as mining and surveying apprentices. Apprentices are required to undergo stipulated periods of training on different types of job as prescribed by the Board of Mining Examination held by the Chief Inspector of Mines in India. The Board of Mining holds regular examiations of mining ad surveying Appretices and grant certificate to the candidates who pass the written, oral and practical tests conducted by the Board. Those persons who become successful in obtaining the certificates qualify for appointment for the posts of Asstt. Manager, Asstt. Surveyor, Manager and Surveyor etc. But the management has no obligation to give employment to the successful candidates. The candidates who fail to get through the examination can have no claim for employment on any job. They also cannot claim for continuance in training beyond the stipulated period. The concerned workman was given chance to take training as Survey Appretice with effect from 26-6-79 by letter dated 22/26-6-79. The apprenticeship of the concerned workman was to be terminated after completion of two years of training subject to further extension of six months. After completion of training he was not required to undergo further training and he was to concentrate on his studies and pass the examination. He could not pass the examination and could not get the Surveyorship certificate. He was not fit to be appointed as Surveyor or Asstt. Surveyor and his apprenticeship was to be terminated as per terms and conditions under which he was given training as Apprentice. But he managed to get himself appointed as Asstt. Surveyor (Un-qualified) by letter dated 5-5-81 at the local level by influencing the Agent of the colliery. He got some note-sheet prepared and managed to get him regularised. The Agent was not empowered to appoint any mining and surveying apprentice as workman of the colliery. The power of new recruitment and posting etc. are vested with the Head-quarter under the control of the Director. All recruitments are to be made according to rules of recruitment. There was no provision for regularisation of mining and surveying apprentices as workmen. No post of Asstt. Surveyor (Unqualified) was sanctioned or existed in the colliery. In the circumstance, the concerned workman was deemed to have never been appointed Asstt. Surveyor (Un-qualified) by the management of M/s. B.C.C. Ltd. It is alleged that the concerned workman found to have procured employment by fradulent means and when irregularity and illegality were detected necessary order was issued. The illegal appointment of the concerned workman was cancelled. In the context of the facts and circumstances it has been prayed for by the management that the present reference be rejected.

3. The concerned workman has disputed the action of the management by filing written statement in support of his defence. He has stated that he was originally appointed Survey Apprentice for one year by letter No. BCCL/PA-II/5/2/45/74/79/652/7-19, dated 3/19-12-1979. He joined on 4-1-82 and was posted to Basseriya Colliery. During the period of his apprenticeship he worked to the satisfaction of the management. His period of apprenticeship expired on 3-1-81. Thereafter he started working as regular employee. In the meantime he got an opportunity for appointment as Civil Surveyor in M/s. C.C. Ltd. and so on 15-4-81 he applied for issuance of 'no-objection certificate'. Thereupon the Agent of the Colliery raised a note-sheet being Ref. No. EBC/788/81 dated 18/20-4-81 for his regularisation as Asstt. Surveyor (Unqualified) and did not issue 'no objection certificate' as claimed by him. The management regularised him as Asstt. Surveyor (Unqualified) in Grade 'E' by order dated 5-5-81 and since then he had been working continuously as Asstt. Surveyor with unblemished record of service. The management came to know of his trade union association and started threatening him. Since he was a member of Bihar Colliery Kamgar Union to which the management was strongly biased and prejudiced, the union, in apprehention of the intention of the managemet raised an industrial dispute soliciting intervention of the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, on 30-8-82. The Asstt. Labour Commissioner (C) fixed the first date of conciliation on 8-9-82, but on that date the representative of the management did not attend the conciliation proceeding with some ulterior motive. Appretending the malafide intention of the management the union prayed for issuance of notice for maintenance of status quo at the instance of Conciliation Officer. Acting upon that the Conciliation Officer issued a notice being No. 1/218/82-E4 dated 8-9-82 directing the management to maintain status quo. On the next date of hearing for conciliation on 18-9-82 the representative of the manage-

ment attended the conciliation and assured the Conciliation Officer for maintenance of status quo. But the management reneged from the position and issued letter of termination of the service of the concerned workman on 23-9-82, but the letter was allegedly signed on 7/8th September, 1982. By the letter of termination the management dis-continued the apprenticeship of the concerned workman with effect from 7/8-9-82. But the concerned workman from the date of his regularisation on 5-5-81 till the date of his alleged termination had put in more than 190/240 days attedance in the preceding twelve months. The management terminated his service without paying any retrenchment compensation, without complying with the mandatory provision of Section 25F of the I.D. Act and without issuing any chargesheet, without conducting any enquiry and without assigning any reason even. Furthermore, the management by the letter of termination allegedly dis-continued the apprenticeship of the concerned workman even though at that time he was working as Asstt. Surveyor (Unqualified) and not as an Apprentice. Being dis-satisfied and aggrieved by the order of the management the concerned workman has raised the present industrial dispute. The action of the management in terminating his service is an act of victimisation and smacks of anti-labour policy of the management. The action of the management is also indicative of the fact that it has got scanty respect for the law of the land when the entire matter of dispute was before the Conciliation Officer for adjudication. In this context of facts and circumstances the concerned union has prayed that the concerned workman be reinstated in service with full back wages.

4. Both the parties have adduce evidence, both oral and documentary in support of their respective contentions. The management has examined only one witness and the union also has examined an equal number of witness. The management has introduced in evidence a mass of documents which have been marked Exts. M-1 to M-8. The union also has introduced a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-7.

5. Mr. B. Joshi, Advocate, appearing for the management has submitted before me that this is a simple case of termination of Apprenticeship of the concerned workman after expiry of the stipulated period and hence the concerned workman has got no relief in this case. He has further contended that the concerned workman managed to get regularisation in service as Asstt. Surveyor (Unqualified), which post is non-existent, in collusion with some officials of the management and that this appointment is illegal, irregular and invalid and hence the concerned workman is not entitled to claim any benefit under it. In order to support his contention Mr. Joshi has referred to the provisions of 11, 12 and 17 of Coal Mines Regulations.

6. Mr. D. Mukherjee, appearing for the concerned workman has submitted that initially the concerned workman was appointed Surveying apprentice for a stipulated period. But he was subsequently regularised in the service as Asstt. Surveyor (Unqualified) and this post is envisaged by the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry which has got statutory force of its own. He has further submitted that the period of apprenticeship was dis-continued at a time when he was no longer in apprentice, but was regularised as Asstt. Surveyor (Un-qualified) and hence the termination of his service is illegal. He has also contended that the concerned workman had rendered service for a period of 240 days within a period of twelve months and termination of his service is 'retrenchment' within the meaning of Section 25F read with Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act (hereinafter referred to as Act) and since prerequisite for valid retrenchment has not been complied with retrenchment bringing about the termination of service of the concerned workman is void-abinitio. He has submitted also that the management has manifested its malafide intention in terminating the service of the concerned workman during the pendency of the conciliation proceeding over the matter.

7. Admittedly the concerned workman was appointed Apprentice in the Survey trade for a period of two years on monthly stipend under the Apprenticeship Act, 1961 by letter dated 3/10-12-79 (Ext. M-1). This letter also bears out that after satisfactory completion of apprenticeship training and on obtaining Surveyor's Certificate of competency from the Director General of Mines Safety, the concerned workman was to be placed in appropriate grade of Asstt. Surveyor (Qualified) as per Wage Board recommendations, but in case he failed to obtain aforesaid certificate of competency he might be given an extension of six months to enable him to obtain the above statutory certificate of Surveyorship. But should be failed to do so the period of Apprenticeship/training would be terminated by the management. Mr. Joshi, armed with the letter of appointment (Ext. M-1) has contended that there was no scope for regularisation of the service of the concerned workman as Asstt. Surveyor (Unqualified) which post did not exist at all and that after expiry of the period of Apprenticeship the service of the concerned was terminated because he could not get Surveyor's Certificate of competency from the Board of Mining Examination. The concerned workman has stated in his testimony that while he was undergoing training as Surveying Apprentice he got a better offer from M/s. C.C. Ltd. in the post of Surveyor (Civil) and that he applied to the management to favour him with 'no objection certificate'. According to his testimony the management declined him to give certificate and that the Agent, Mr. J. C. Sen, addressed a letter to the Headquarter dated 20-4-81 (Ext. W-6) stating that since one person had retired from service the Surveyman for 'no objection certificate' be regularised and that by Order dated 5-5-81 (Ext. W-1) the management regularised him in the post of Asstt Surveyor (Unqualified). It is his emphatic statement in his cross-examination that he did not now possess the letter of appointment from M/s. C.C. Ltd. since that was submitted to M/s. B.C.C. Ltd. along with his application for 'no objection certificate'. He has denied the suggestion of the management that the letter of Mr. J. C. Sen, Agent of Bassuria Colliery is false and fabricated. The management could well have examined Mr. Sen to prove the point, but they have not done so. However, it appears from Office Order of Personnel Manager of Kusunda Area dated 5-5-81 (Ext. W-1) and Office Order of the Manager of East Bassuria Colliery dated 12-5-81 (Ext. W-3) that the concerned workman was regularised as Asstt. Surveyor (Unqualified) with effect from 12-5-81. In terms of the original letter of appointment as Surveying Apprentice, the concerned workman was to undergo training with effect from 10-12-79 and a further extension of six months in case of his failure to obtain Surveyor's Certificate of Competency within two years. Admittedly the concerned workman could not obtain Surveyor's Certificate of Competency by passing the Board of Mining Examination. Thus it appears that the Apprenticeship of the concerned workman was to expire on 9-6-82. It appears that he was regularised in service as Asstt. Surveyor (Un-quailfied) even before the expiry of the aforesaid period. He was regularised in service as Asstt. Surveyor (Un-qualified) with effect from 12-5-81. The management noticed alleged irregularity in the matter and Mr. A. A. Jafri. Dy. Chief Perspnel Manager (R) of M/s. B.C.C. Ltd. by letter dated 19-12-81 (Ext. M-2) directed General Manager, Kusunda Area, for discontinuance of the Apprenticeship of the concerned workman. Mr. Jafri took exception to appointment of the concerned workman, as Asstt. Surveyor (Un-quailfied) without obtaining D.G.M.S.'s certificate which is contrary to the clause of his appointment letter. Mr. Jafri informed the General Manager, Kusunda Area, by letter dated 7/9-2-82 (Ext. M-4) to confirm the termination order of regularisation of the concerned workman as Asstt. Surveyor (Un-qualified) and dis-continuance of his Apprenticeship. Mr. Jafri again wrote to the Agent, East Basuria Colliery, Kusunda Area on 5-7-82 (Ext. M-5) that the regularisation of the concerned workman was most irregular and that the management never approved of such regularisation and that the General Manager was requested to terminate the Apprenticeship of the concerned workman and that the order of termination should be issued immediately. Ultimately the Apprenticeship of the concerned workman was dis-continued by the Agent of the East Basuria Colliery by letter dated 7/8-7-82 (Ext. W-2) with immediate effect and this was communicated to Mr. Jafri by the Personnel Manager, Kusunda Area by letter dated 21-9-82 (Ext. M-6).

8. Thus it is evident that during the period of his apprenticeship the concerned workman was regularised as Asstt. Surveyor (Un-qualified), but his apprenticeship was dis-continued by the management while he was no longer acting as an apprentice but was regularised in service as Asstt. Surveyor (Un-qualified).

9. Mr. Joshi has taken exception to the appointment of the concerned workman in the post of Asstt. Surveyor (Un-qualified) which was non-existent. He has also asserted that the Agent, East Basuria Colliery had no authority to issue such appointment of the concerned workman to non-existent post. He has cited provisions 11, 12 and 17 of Coal Mines Regulations in support of the fact that no such post as Asstt. Surveyor (Un-qualified) exists.

Mr. D. Mukherjee has submitted that the contention of Mr. Joshi is without any basis for the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry envisages such post. This is really so; there is provision for the post of Asstt. Surveyor (Un-qualified) in Grade 'E' in the new consolidated basic scale of pay of Rs. 180—273. Needless to say that this post recommended by the Wage Board has a statutory force. That being so, it can be concluded that the concerned workman was not appointed to a non-existent post and hence the contention of Mr. Joshi to the contrary must founder on the ground.

10. The management terminated the Apprentice.hip of the concerned workman while he was holding the post of Asstt. Surveyor (Un-qualified) as the evidence reveals and gleaned above. The evidence on record firmly establishes the position that the concerned workman had rendered service for a period of 240 days within a period of twelve months and the management did not comply with the pre-requisite for valid retrenchment as laid down in Section 25F read with Section 2(oo) of the Act. A new provision has been added to Section 2(oo) of the Act with effect from 18-8-84 envisaging termination of service of the workman as a result of non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein beyond the pale of retrenchment. Even from this view of the matter the case of the concerned workman cannot be considered as not termination of his service because that was not done on account of non-renewal of the contract of employment after expiry of the stipulated period. After expiry of Apprenticeship period of two years and a half the concerned workman was continuing in service and looked at from this point of view his Apprenticeship was considered to be extended for a further period of six months during which his Apprenticeship was dis-continued by the management. The management are not within their rights to do so. In this view of the matter the action taken by the management shall be construed to be a retrenchment without pre-requisite for valid retrenchment as laid down in Section 25F of the Act and hence this retrenchment bringing about the termination of the service of the concerned workman must be held abnitio void (AIR 1981 SC. 1253). That apart it appears that the management discontinued the service of the concerned workman during the pendency of the conciliation proceeding over the matter without taking any leave from the Conciliation Officer (Ext. W-5 series).

11. It appears that after dis-continuance of his Apprenticeship with effect from 7/8-9-82 the management have again reinstated the concerned workman as Amin (Trainee) with effect from 10-12-85 on certain terms and conditions (Ext. M-8). Thus it is obvious that the concerned workman is again in the service of the management. But that does not indicate that the earlier action of the management in discontinuance of Apprenticeship of the concerned workman which in fact meant termination of his service as Asstt. Surveyor (Un-qualified) in which post he was then regularised and working is justified.

12. It is needless to mention that the order of the Tribunal must be fashioned and adapted according to realities of circumstances. Since the action of the management in terminating the service of the concerned workman is not justified, he is not automatically entitled to get reinstatement in the said post because now he has been holding the post of Amin (Trainee) under the management. In the context of the circumstance, he is entitled to get back wages from 8-9-1982 to 9-12-1985 as admissible to him in the capacity of Asstt. Surveyor (Un-qualified).

Hence, it is ordered—

that the action of the management of M/s. B.C.C. Ltd. in terminating the service of the concerned workman as Asstt. Surveyor (Un-qualified) after regularising him as Asstt. Surveyor (Un-qualified) is not justified. The concerned workman is entitled to get back wages from 8-9-1982 to 9-12-85 as admissible to him as Asstt. Surveyor (Un-qualified).

In the circumstance of the case the parties to bear their own costs.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012(464)/82-D.III(A)]

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3554—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैनीदीह कालयरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटिड के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संख्या–1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th December, 1987

S.O. 3554.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSRIAL TRIBUNAL NO 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 84 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 27th November, 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012 (201)/84-D.III(A) dated, the 23rd October, 1984 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the demand of Coalfield Labour Union for regularisation of the workmen of Benedih Colliery

of Messrs Bharat Coking Coal Limited, whose names are given in the Annexure below, in the jobs shown against them each is justified? If so, to what relief these workmen are entitled?"

ANNEXURE

1 Shri Dhaneshwar Nonia.
2. Shri Ganpat Nonia.
3. Shri Chanarik Nonia.
4. Shri Brahmdeo Nonia.
5. Shri Surdhan Rajwar.
6. Shri Surajdeo Rajwar.
7.Shri Harihar Nonia.
8. Shri Ram Prasad Nonia.
9. Smt. Dhani Kamin.
10. Shri Sarju Nonia.
11. Shri Lakhan Mahato.
12. Shri Bijali Beldar.
13. Shri Suren Manjhi.

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/201/84-D.III(A)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II

DHANBAD

Notification No. L-20012(201)/84-D-III(A) Dated 21-10-84
Ref. 84/84

Employers in relation to the management of Benidih Colliery

AND

Their workmen.

PETITION OF THE SETTLEMENT

The humble petition on behalf of the parties above named most respectfully shewith :—

1. That, the Central Government by notification No. L-20012(201)/84-D-III(A), dated 21-10-84 has been pleased to refer the present dispute to this Hon'ble Tribunal for adjudication of the issue contained in the schedule of notification which is reproduced below :—

SCHEDULE

"Whether the demand of Coal Feld Labour Union for regularisation of the workmen of Benidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, whose names are given in the Annexure below, in the jobs show nagainst them each, is justified? If so, to what relief these workmen are entitled?"

ANNEXURE 'A'

1 Shri Dhaneshwar Nonia.
2. Shri Ganpat Nonia.
3. Shri Chanarik Nonia.
4. Shri Brahmdeo Nonia.
5. Shri Surdhan Rajwar.
6. Shri Surajdeo Rajwar.
7.Shri Harihar Nonia.
8. Shri Ram Prasad Nonia.
9. Smt. Dhani Kamin.
10. Shri Sarju Nonia.
11. Shri Lakhan Mahato.
12. Shri Bijali Beldar.
13. Shri Suren Manjhi.

2. That the above dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That the following concerned workmen will be regularised on the posts mentioned against their names in Annexure 'B' from 1-1-1984 and will be put in the initial starting of the basic wages of the category plus nos. of increment as shown in Annexure 'B' against each of their names.

(b) That, the concerned workmen will have no other or further claims.

(c) That, in view of the settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen.

(R. A. Singh),
General Secretary,
Coal Field Labour Union.

For the Employers :
(G. Rai), General Manager,
Block-II Area.,
(R. B. Kidder),
Personnel Manager,
Block-II Area
(P. P. Singh),
Dy. CME, Benidih Colliery

ANNEXURE—'B'

Sl. No.	Name	Designation on regularisation	Category	No. of increment to be given	Basic wages on regularisation	Date of next increment
1.	Shri Dhaneshwar Nonia	Mason Mazdoor	Cat. I	3	Rs. 22.45	1.1.1985
2.	Shri Ganpat Nonia	Mason Mazdoor	Cat. I	3	Rs. 22.45	1.1.1915
3.	Shri Chanarik Nonia	Mason Madoor	Cat. I	3	Rs. 22.45	1.1.1985
4.	Shri Brahmdeo Nonia	Mason Mazdoor	Cat. I	3	Rs. 22.45	1.1.1985
5.	Shri Surdhan Rajwar	Prop Mazdoor	Cat II	2	Rs. 22.71	1.1.1985
6.	Shri Surajdeo Rajwar	Prop Mazdoor	Cat. II	2	Rs. 22.71	1.1.1985
7.	Shri Harihar Nonia	Prop Mazdoor	Cat. II	2	Rs. 22.71	1.1.1985
8.	Shri Ram Prasad Nonia	Prop Mazdoor	Cat. II	2	Rs. 22.71	1.1.1985

1	2	3	4	5	6	7
9.	Smt. Dhani Kamin	General Mazdoor Working as Coal Supplier	Cat. I			
10.	Smt. Sarju Nonia	General Mazdoor Working as S.B. Attendant	Cat. III	2	Rs. 24.00	1-1-1985
11.	Shri Lakhan Mahato	General Mazdoor Working as Clay Cartridge Mazdoor	Cat. I	2	Rs. 22.02	1-1-1985
12.	Shri Bijali Beldar	General Mazdoor Working as Shale Picker.				
13.	Shri Suren Manjhi	Explosive Carrier.	Cat. II	2	Rs. 22.71	1-1-1985

Sd./illegible	Sd./illegible
(R.A. Singh)	(P.P. Singh)
General Secretary	Dy. CME
Coal Field Labour Union	Benidih Colliery.

Sd-/illegible	Sd,/illegible
(R.B. Kidda)	(G. Rai)
Personnel Manager	General Manager
Block II Area	Block II Area

का. आ. 3555—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भातदी कॉलयरी, मैसर्स भारत कोकिंग कॉल लिमिटिड के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संख्या-1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3555.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhatdee Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 48 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhatdee Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Mohuda, Dist. Dhanbad,

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Collieryd Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 25th November, 1987

AWARD

By Order No. L-20012(442)/81-D.III (A), dated the 23rd April, 1982, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of the workmen of Bhatdee Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad for reinstatement of Shrimati Sanjoti Kamin and Shrimati Hemi Kamin as Wagon Loaders in the Colliery is justified ? If so, to what relief are the workers concerned entitled ?"

2. The fascicle of facts as appearing in the written statement of the concerned workmen Smt. Hemi Kamin and Smt. Sanjoti Kamin are as follows :

Both S/Smt. Hemi Kamin and Sanjoti Kamin had been working as permanent wagon loaders of Bhatdih Colliery since long with unblemished record of service. They have put in 240 days attendance in each calendar year. They are active members of Bihar Colliery Kamgar Union. The local management is very much biased and prejudiced against the members of Bihar Colliery Kamgar Union of M/s. B.C.C. Ltd. has taken a policy decision to remove all female workmen. The management formulated a Voluntary Retirement Scheme under which a female workman can voluntarily retire for employment of her male dependant only. While the Voluntary Retirement Scheme as formulated by the management was in force. Smt. Sonjati Kamin expressed her willingness to retire voluntarily from service by submitting an application on 8-3-77 with a pre-condition for employment of her son. Likewise Smt. Hemi Kamin submitted an application for voluntary retirement on 7-1-77 with a pre-condition for employment of her son. But the management stopped Sonjati Kamin from performing her duties with effect from 9-4-78 and Hemi Kamin from 19-3-78. They were not paid any retrenchment compensation. The concerned workmen and their union protested against the illegal and arbitrary termination of their service but without any effect. The union raised an industrial dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, against the anti-labour policy of the management. The management took the position in the conciliation proceeding that Hemi Kamin submitted voluntary resignation for employment of her son and Soniati Kamin submitted her voluntary retirement. The conciliation proceeding ended in failure due to the adamant attitude of the management. It has been alleged that the action of the management in terminating the service of the concerned workmen was illegal, arbitrary, unjustified and against the principles of natural justice.

3. In opposition the management has stated in its written statement that the concerned workmen were employed as permanent wagon loaders in Bhatdih colliery. Smt. Hemi Kamin submitted her resignation on 1-7-77 voluntarily unconditionally and in an unequivocal term mentioning inter-alia that she submitted her resignation and even if in case her resignation was not accepted she would not attend her duty from 30-1-77. She also requested therein that her dues be paid and that her son be provided with a job. In view of her unconditional and unequivocal voluntary resignation on

the ground of her ill health the employer had no other alternative than to accept her resignation. The Manager of the colliery forwarded her resignation to the General Manager by letter dated 14-1-77 and the General Manager accepted her resignation with immediate effect by letter dated 22-1-77 and the same was duly communicated to her. She accordingly relieved of her duties. Smt. Sanjoti Kamin also voluntarily has tendered her resignation on 8-7-77. Her resignation was accepted and she was paid her dues for her voluntary resignation. It has been submitted that after the acceptance of the resignation there was no employer-employee relationship between the concerned workman and the employer of Bhatdih Colliery.

In the rejoinder to the written statement of the workmen the management has denied the contentions of the workmen as appearing in the written statement and asserted that Volunary Retirement Scheme which was introduced were applicable both to male and female employees but since the scheme was mis-used by the workmen themselves, the same was withdrawn.

4. Both the parties have led, both oral and documentary evidence in support of their respective cases. The workmen have examined themselves and B. Mohanty, Area Secretary of Bihar Colliery Kamgar Union in support of their cases. They have adduced documentary evidence in support of their claims which have been marked Exts. W-1 to W-8. The management have examined as many as six witnesses and introduced in evidence a mass of documents which have been marked Exts. M-1 to M-3.

5. Mr. D. Mukherjee appearing for the workmen on behalf of the union has contended that the concerned workmen signified their intention to retire from service voluntarily with a pre-condition for employment of their sons in terms of Voluntary Retirement Scheme obtaining in M/s. B.C.C. Ltd. at the relevant time. In otherwords, the contention of Mr. Mukherjee is that the intention of the concerned workmen to retire from service voluntarily was conditional and that condition not being complied with the management had no right to accept their resignation from service voluntarily. He has further contended that by the action of the management the concerned workmen were suffered to loose their employment. Mr. Mukherjee has further contended that the acceptance of the resignations of the concerned workmen from services was not communicated to them and as such the offers of the concerned workmen for resignation from service were never accepted by the management and hence the management was not justified in refusing them to perform their duties as permanent wagon loader.

6. Mr. G. Prasad, Advocate, appearing for the management has submitted that the applications of the concerned workmen offering resignation from services were not hedged in with any condition and so it is pointless to suggest that their offers for resignations from services were conditional. He has further submitted that the resignations of the concerned workmen from service were rightly accepted by the management and in doing so the management has paid off their dues. According to him the concerned workmen are not entitled to get any relief in the present reference.

7. Admittedly both the concerned workmen were employed as permanent wagon loaders in Bhatdih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. It is the case of the concerned workmen that they submitted applications for voluntary retirement from their services with the pre-condition for employment of their sons in terms of Voluntary Retirement Scheme formulated by the management and was in force at the relevant time. According to the written statement of the concerned workman Smt. Hemi Kamin submitted her application for voluntary retirement from service on 7-1-77 and Smt. Sonjoti Kamin on 8-3-77. It appears from the evidence of MW-1, H. K. Choudhury who was promoted to the post of Personnel Officer of Bhatdih Colliery on 7-6-77 that a Voluntary Retirement Scheme was in force in 1977 in that colliery and that the resignations submitted by the concerned workmen were conditional. None of the parties arrayed has spared any pain to produce before me the Voluntary Retirement Scheme framed by M/s. B.C.C. Ltd. Anyway it is spelt out from the pleadings of the parties that Voluntary Retirement Scheme was applicable both to male and female employees and according to the workmen it envisaged employment of male dependant of female workman returning from service voluntarily. If that be so, evidently the scheme for voluntary retirement is contrary to the provision of the Constitution of India. Indeed, it has been stated in the written statement of the concerned workmen that Hon'ble Supreme Cour has stayed the operation of the Voluntary Retirement Scheme framed by M/s. B.C.C. Ltd. on the ground of constitutional validity. This being the position, the Voluntary Retirement Scheme cannot be considered to be a shot in the arms of the concerned workmen and will hardly bring grist to their mill. Even if it is assumed for the sake of argument that the concerned workmen submitted their applications for voluntary retirement from service on the basis of Voluntary Retirement Scheme, their retirement from service voluntarily cannot be considered to be on the basis of Voluntary Retirement Scheme which is unconstitutional and has got no legal force at all. It remains now to be considered whether the concerned workmen submitted the applications for voluntary retirement with pre-condition for employment of their sons. It has been admitted by the concerned workmen in the written statement that Hemi Kamin submitted application for voluntary retirement on 7-1-77 and that Sonjoti Kamin submitted her application on 8-3-77. The management has produced the application of Hemi Kamin dated 7-1-77 which has been marked 'Y' for identification on the disclaimer of the concerned workmen that the letter was written by her. But she has admitted in the written statement that she submitted application on 7-1-77 for voluntary retirement from service. Hence in spite of her disclaimer I have every reason to believe that this letter was sent by her to the management. In this letter she has stated that she was unable to work properly and therefore, she submitted her resignation and that she would not report for work from 30-1-77. She has prayed for her dues like bonus, compulsory deposit, gratuity be paid earlier, she also prayed for employment of her one son. Thus, this letter by itself shows that she retired from service voluntarily with a prayer for employment of her son. The Superintendent, Bhatdih Colliery by his letter dated 14-1-77 forwarded the letter to the General Manager, Mohuda Area No. II, for acceptance of the resignation (M-3). General Manager, Mohuda Area No. II by his letter dated 22-1-77 (76 ?) accepted the resignation of Hemi Kamin and directed her to collect all her dues from the colliery office after vacating the Quarter of the company. This letter has been marked 'Y-2' for identification. Hemi Kamin submitted another letter to the management dated 5-4-78 (Ext. W-3) wherein she has stated that she submitted voluntary resignation on 17-2-78 after duly filling in form for giving employment to her son. This letter of hers seems to be an afterthought because in her original application for voluntary retirement she attached no condition suggesting for employment of her son upon her retirement from service voluntarily.

8. The original application for voluntary retirement submitted by the other workman Sonjoti Kamin has not been produced by the management but it has been admitted in the written statement that the said application was submitted on 8-3-77. I have come across one copy of her application in the file of the A.L.C. (C), Dhanbad. In that application she has stated that her resignation be accepted in accordance with the Voluntary Retirement Scheme and her dues like gratuity, bonus, provident fund etc. be paid to her immediately. It appears that on 1-2-78 she submitted another application to the management signifying her intention to retire from service provided her son was given employment (Ext. W-1). By another letter dated 2-2-78 she has stated that if her son was not given employment she would not retire from service (Ext. W-2). These two letters Exts. W-1 and W-2 seem to be a product of after thought for in the letter dated 9-7-78 (Ext. W-4) B. Mohanty, Asstt. Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union Branch, Bhatdih complaining that although Sonjoti Kamin submitted her resignation on 8-3-77 under Voluntary Retirement Scheme, she was not paid her dues. Again on 10-2-78 (Ext. W-5) Mohanty wrote to the management that Sonjoti Kamin submitted her resignation on 8-3-77 and that she was not paid her gratuity. This being the position, I come to the conclusion that Sonjoti Kamin retired voluntarily from service by submitting an application on 8-3-77. It appears that the management raised a note

Sanjoti Kamin in 1978,—an inaccurate position—under Sanjoti Kamin in 1978,—an inaccurate position—under Voluntary Retirement Scheme and that their sons be considered for appointment as loaders. But the General Manager did not approve of the course suggested and the entire matter fell apart (Ext. W-8). This being so I cannot hold that the management agreed to the employment of the sons of the concerned workmen on their voluntary retirement from service. Even if it is considered that they submitted their applications for voluntary retirement from service with pre-condition for appointment of their respective sons under Voluntary Retirement Scheme, that does not automatically mature into an abiding and durable agreement between the parties concerned because Voluntary Retirement Scheme itself is unconstitutional and no agreement on the basis of such unconstitutional scheme can be given effect to.

9. From the documentary evidence on record it has not been proved that the concerned workmen resigned from their service voluntarily with a condition for appointment of their sons. The evidence of MW-1, H. K. Choudhry contrary to this position is bristle with inaccuracies and cannot be accepted at all.

10. Considering all these facts and circumstances I come to the inescapable conclusion that the concerned workmen have voluntary retired from service. They have not made any complaint at the time of hearing that they were not paid their dues, such as, bonus, provident fund, gratuity etc. by the management. It is an admitted fact that the management has refused performance of duties by them. These circumstances indicate that the management accepted offer of their voluntary retirement from service.

11. It is a well settled position that Voluntary Retirement Scheme does not amount to dismissal or discharge and the concerned workmen are not entitled to any relief on termination of their services as they have voluntarily resigned.

12. The voluntary retirement of the concerned workmen from service is not a 'retrenchment' within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947.

13. In view of the facts and circumstances of the case I come to the conclusion that the concerned workmen have got no relief in this reference.

Hence, it is ordered—

that the demand of the workmen of Bhatdee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited for reinstatement of Shrimati Sanjoti Kamin and Shrimati Hemi Kamin as Wagon Loaders is not justified.

In the circumstances of the case the parties are to bear their own costs.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/442/81-D.III(A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3556.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इंडिया सिमेन्टस् लिमिटेड, संकरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-11-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th December, 1987

S.O. 3556.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of India Cements Limted, Sankari and their workmen which was received by the Central Government on the 27th November, 1987.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 19th day of November, 1987

PRESENT :

Thiru Fyzee Mahmood, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 19 of 1982

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of India Cements Limited, Sankari West, Salem District.)

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary,
India Cements Employees Union,
Sankari West-637303.

AND

The General Manager,
India Cements Limited,
Sankari West-637303.

REFERENCE :

Order No. L-29011/40/81-D.III (B), dated 27-2-1982 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 7th day of October, 1987 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N. G. R. Prasad for Thiruvalargal Row and Reddy, Advocates appearing for the workmen and of Thiru S. Jayaraman, Advocate for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This dispute between the workmen and the Management of India Cements Limited, Sankari West, Salem District arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-29011/40/81-D.III (B), dated 27-2-1982 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issues :

"Whether the demands of the workmen of Lime Stone Quarry of Messrs India Cements Limited, Sankari West given in the Annexure are justified, if so, to what relief are the workmen entitled ?"

ANNEXURE

1. Provision of quarters to all the workmen.

2. Supply of uniform to Breakers, Loaders, Earth Loaders and Jolly Workers.

3. Provision of free transport from the quarry to residence and back.

4. Supply of water at the dwelling place of workmen.

2. In the claim statement filed by the Petitioner-Union, it is stated that the workmen had put forth four demands as detailed in the reference. The Respondent-Management employs about 2100 quarry workers. Most of them are living 5 to 15 miles away from the quarries. The house rent in the Panchayats are increasing year by year. Hence the claim for provision of quarters to all the workmen. The workers find it difficult to travel to the workspot and therefore free transport from their residence to the quarry is demanded. Similarly, another demand has been put forth that all the workmen employed in the quarries should be provided with uniforms. The last demand relate to supply of water by the Management at the dwelling place of all the workmen. As the charter of demands in relation to the above resulted in failure at the conciliation stage, the present dispute has come into-existence.

3. In the counter statement filed on behalf of the Respondent-Management, it is stated that the Management had

provided quarters for about 30 employees after consultation with the Union. Those who are not provided with quarters have been paid House Rent Allowance as per the Arbitration Award for Cement Industry which came into effect on 1-10-1978 and which had been implemented by the Respondent-Management. The demand for provision of quarters for all workmen is totally unjustified. Regarding the demand for supply of uniforms this was one of the demands put forward before the Arbitration Board and as per the Award, the Respondent-Management had supplied uniforms to the workmen. The Management had even extended this benefit to the workers who are not required to be supplied with uniforms as per the Arbitration Award. In respect of the demand for free transport to all the workmen, it is impracticable to comply with. The Respondent-Management had provided bus facility for some of the workmen in consultation with the Petitioner-Union. The workmen are also receiving conveyance allowance. Hence this demand has to be dismissed. The demand for supply of water at the dwelling place of each workman for about 2100 workers is not only unjustified, but impossible to implement. This obligation cast on the employer to provide drinking water to every dwelling place of every workman cannot be sustained. Demand Nos. 1 to 3 in the claim statement were already the subject matter of the Arbitration and an Award had been passed prior to the reference. In these circumstances the present reference made by the Government is not maintainable. Moreover, the Second Arbitration Board for Cement Industry has already been constituted and the Demands 1 to 3 in this reference are pending adjudication before the Board.

4. In the additional counter statement, it is contended that the issues which have been referred for adjudication do not come under the purview of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act and hence it has to be rejected. It is further submitted that the reference itself is bad in law and incompetent.

5. Thiru P. R. Narayanan, the President of the Union had been examined as WW-1 and Exs. W-1 to W-5 relied upon by the Petitioners. Thiru V. Paramasivam employed as Chief Time Keeper in the Respondent-Management had been examined as MW-1 and Exs. M-1 to M-4 filed in support of the Respondent's case.

6. The point for consideration is as contained in the reference.

7. The first demand made by the employees is for provision of quarters to all the employees of the Respondent-Management. It is in evidence that there are about 2100 workmen. Of these, 700 are employed in the factory and the rest are engaged in the mines which is situated about 3 kms. away from the Factory. According to WW-1, the residential quarters are provided by the Management only for some of the workers and that all the workmen of the Respondent-Management should be provided with residential quarters. MW-1 had testified that about 300 quarters in the factory colony were allotted to the workers in consultation with the Union. As far as the other workmen are concerned, they were given house-building loan facility. Ex. M-3 is a Scheme adopted by the Respondent-Management for granting house loans to all permanent employees who had put in more than 10 years of service. According to the Scheme, the maximum amount of loan that may be sanctioned is 60 times of the salary which includes Basic Pay and Dearness Allowance. MW-1 had further testified that Housing Committee had been formed consisting of Management and workmen representatives to help the workmen to construct houses with their own funds under the supervision of technical personnel belonging to the Company's Civil Department. It has also to be noted that in the Arbitration Award Ex. M-1 which came into effect from 1-10-1978, the demand had been made for increase in House Rent Allowance for the different categories of workmen and in the final Award passed, the existing House Rent Allowance had been increased by Rs. 25 per month subject to the deduction of house rent from this allowance for employees who are provided with Company's quarters. In the later Arbitration Award Ex. M-2 dated 11-7-1983 which was subsequent to the reference of this dispute made on 27-2-1982, enhancement of House Rent Allowance had been made and it had been raised for different Grades ranging from Rs. 50 to Rs. 75 per month. Hence this demand stands rejected.

8. In respect of the second demand, this was one of the demands raised before the Arbitration Board and by the Award marked as Ex. M-1, the employees in certain categories were directed to be given three sets of uniforms every year. It has been represented on behalf of the Management apart from complying with the directions of the Award, all the other categories of workmen had also been supplied with uniforms. As a matter of fact, WW-1 in his deposition admitted this fact and categorically stated that the Union is not pressing this demand. Accordingly it is rejected.

9. A demand has been made for free transport to quarry from the residence of the employees employed by the Respondent-Management. MW-1 had deposed that two buses have been provided by the Management to transport workmen free of cost and that it makes five trips every day. In addition to this, lorry facility is also given to some of the workmen. WW-1 had also admitted that town buses are plying upto the factory entrance. In this connection, it may be pointed out that a demand for Conveyance Allowance had been made and is subject matter of the Arbitration Award marked as Ex. M-2. According to it, Cycle Allowance of Rs. 10 per month was directed to be paid to all workmen who had not been provided wtih quarters or with free or subsidised transport. In the circumstances, the demand made is devoid of merits and stands rejected.

10. The last demand is for supply of water to all the workmen at their dwelling place. It is strange that this issue should have been referred for adjudication when such a demand is impossible of implementation by any employer. It is not disputed that for workmen who had been provided with quarters, water facility has been given and there is also adequate water supply to the Factory and Mines. The peculiar demand raised by the Union is that the workmen are residing in surrounding village to an extent of about 15 kms. away from the work spot and they should all be provided with water facility at the places where they reside. Admittedly, it is not the case of the Petitioner that the workmen to whom water supply is asked for are residing in the Company quarters or within the Company campus. The evidence adduced discloses that the Management had already provided water supply to the places covered in between the factory to quarry road by providing brick masonry water tubs in consultation with the Union and these water tubs are at regular intervals filled with water by means of lorry. This is being done to benefit the workmen and their families living in surrounding areas. The demand of the Union is that the water must be tapped from the main line proceeding from the factory to the mines at different spots to enable the workmen to draw water from the main line. As rightly urged by the Respondent-Management this demand cannot be acceded to as it would not only affect the working of the mines where drinking water supply has to be provided as per Mines Act, but also result in large scale of pilfering and misuse of water by members of the general public who are residing in the vicinity. It is an impossibility or performance for any Management to arrange water supply to each and every dwelling place of its employees nor they legally bound to do so. It is the responsibility of the local Panchayats to Municipalities to meet the basic needs of water amenities to the residents and this responsibility cannot be shifted on a private Management. Hence this demand in totally unjustified and impossible of implementation. Accordingly it stands rejected.

11. In the result, an award is passed rejecting all the four demands raised by the workmen and holding that they are not entitled to any relief. There will be no order as to costs.

Dated, this 19th day of November, 1987.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For Workmen :

WW-1—Thiru P. R. Narayanan.

For Management :

MW-1—Thiru V. Paramasivam.

DOCUMENTS MARKED

For Workmen :

Ex. W-1—Plan drawn by the Union.

Ex. W-2/28-11-79—Copy of letter from the Union to the Management regarding allotment of quarters.

Ex. W-3/7-5-80—Copy of demands from the Union to the Management.

Ex. W-4/17-1-81—Copy of letter from the Union to the Regional Labour Commissioner.

Ex. W-5/18-8-81—Copy of report submitted by the Assistant Labour Commissioner, Central to the Government of India.

For Management :

Ex. M-1—Arbitration Award for Cement Industry, 1978.

Ex. M-2—Arbitration award for Cement Industry, 1983.

Ex. M-3—Rules for grant of Housing Loan to the employees of India Cements Limited.

Ex. M-4/28-7-84—Copy of Circular issued by the Management regarding provision of Water Tanks.

[No. L-29011/40/81-D.III (B)]

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal

का.आ. 3557.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, न्यू इंडिया माइनिंग कारपोरेशन (प्रा.) लि., सिंधुदुर्ग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्री एफ. एच. लाला, जिला और सैशन जज और औद्योगिक अधिकरण (रिटायर्ड) और मध्यस्थ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-12-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3557.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of Shri F. H. Lala, District and Session Judge and Industrial Tribunal, (Retd.) and Arbitrator, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Mining Corporation (P) Ltd. Sindhu Durg and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-12-1987.

VOLUNTARY REFERENCE BEFORE SHRI F. H. LALA.

ARBITRATOR

(Under Section 10-A, I.D. Act, 1947)

Re: Industrial Dispute

BETWEEN

Shri Dilip Kumar Srivastava, Director, M/s. New India Mining Corporation, Pvt. Ltd., Redi Iron Ore Mines, P.O. Sindhudurg.

AND

Their workmen.

(Rep. by 1. Shri S. R. Kulkarni, President, All India Port & Dock Workers' Federation, Bombay, Rep. Redi Kamgar Sanghatana, Redi, P.O. Redi, Sindhudurg District. 2. Shri B. Mohan Rao, Secretary, A.I.P. & D.W. Federation Rep. Redi Kamgar Sanghatana, Redi & Shri K. L. Rane, President Redi Kamgar Sanghatana, Redi, Sindhudurg)

AWARD

1. The Industrial Dispute existing between the above Employers and their workmen has, by their Agreement under Section 10A, I.D. Act, 1947, been referred to me for Arbitration. The said agreement has been published in the Gazette of India before 8th March 1986 and I have, therefore, to arbitrate on the dispute as per Government of India, (Ministry of Labour), Order No. L-26011/23/85-D. III(B)(ii) dated 26th February, 1986.

2. In pursuance of the said order, I issued Notice to the Union to file its statement of claim and another to the Employers to file their Written Statement and to display a Notice in the language known to the workmen, not wishing to be represented by the said Union, to file their say in the matter, if any.

3. The President, All India Port & Dock Workers' Federation representing Redi Kamgar Sanghatana has filed the written Statement dated 24th June, 1986 in reply to my Notice of 11th March, 1986. Inter alia, he has raised the following contentions in support of the workmen's Demands.

4. By the Agreement between the parties dated 30th January, 1986, the Demand referred for arbitration is, whether the workmen's Demand, that their wages should be increased by 30 per cent w.e.f. 1st October, 1984 is justified and, if not, what should be the increase in wages from 1st October, 1984 having regard to the wages and service conditions in the similar industries in the nearby region, in addition to the interim relief granted under the Settlement of 16th February, 1985. The further Demand for arbitration is, what should be their classification, pay scales, various D.A., variable D.A., H.R.A. of the workmen and other conditions of service.

5. The Employers have employed as many as 507 workmen who could be covered under the present reference. The service conditions of the workmen are governed by the settlement of 17th January, 1984 between the above Employers and Deccan Mineral Pvt. Ltd. in respect of the interim allowance of Rs. 200 per month and other demands of mine workers of D. Minerals Pvt. Ltd. A copy of the said settlement has been annexed as Exh. A. A Charter of Demands was served on the Employers demanding Monsoon payment and other 18 facilities. Since the final determination of the dispute was impossible, a settlement dated 16th February, 1985 was arrived at, by which an interim arrangement to pay additional interim relief was agreed to and the Dispute has been, by agreement, referred for arbitration.

6. The principles of wage fixation laid down by the Supreme Court show that the wages paid to them are not proper as the oldest workman employed drew Rs. 847 as total salary on 1st January, 1984 and the wages paid to them are very low as compared to those of the employees in similar business at Redi, Goa and other places. The mining operation involves physical, manual and hazardous work and requires skill. Therefore, the demand for 30 per cent rise in total wages received by the workers is just and fair and will not cast a monthly burden of more than Rs. 300 per worker from 1st October, 1984. The statement of wages etc. of different comparable concerns filed and to be filed, will show that the demand is most fair and proper. The concerns at Goa, viz., P. T. Industries, Durga M. Co., Sesa Goa Ltd., V. S., Dempo & Co., Chougule & Co. and Salitho Ores Ltd., which are comparable to the NIMCO, pay wages higher than those paid by NIMCO and the Demands made are proper and should be granted.

7. The Employers have filed their written statement and contended, inter alia, that the Demands made are not fair and justified. They stated that the Company was incorporated in 1940 and the present management came into picture in 1973. They added that the Mines are in a remote corner and backward area of Maharashtra adjoining border of Goa and the Lump Ore deposits are nearly exhausted. They raised the following contentions also.

8. Mining and export is possible in fair weather through the minor port, Redi, and is canalised through S.T.C. which came into existence in 1956. The canalisation was made to maintaining the existing interest of mine owners and exporters and for systematic development of production and export. From 1957 the S.T.C. became the exporter and was responsible for marketing of Iron Ore in the world market and enhanced its charges unilaterally to Rs. 3 per Tonne. It kept on enhancing its service charges every year. M.M.T.C. came into existence in 1963 and continued the old practice and the charges were enhanced to Rs. 12 per Tonne unilaterally and without any justification.

9. In 1967 the M.M.T.C. was unable to sell the Lump Ore and inspite of their best efforts, the M.M.T.C. could not find out market for fine ore. The Employers, therefore, made a number of visits abroad and ultimately concluded a 5 year contract with Japan at the rate of 3,50,000 Tonnes per shipping season as a distress sale. They put more rigid conditions on them as compared to those put on Goa mine owners. The M.M.T.C. took responsibility for marketing the iron ore in the world market for suitable price and lost the Japan market inspite of the owners' repeated requests not to do so. Japan is not lifting a single tonne of ore from Redi from the fifth year of contract. They invested Crores of rupees in planning systematic development for increase of production at the suggestion of M.M.T.C. to replace the old equipments. M.M.T.C. found it difficult to sell Lump Ore in the world market, with the result, that the Company suffered loss of lakhs of rupees. The export also suffered set back from 1980-81 due to non-fulfilment of its promise by M.M.T.C. From October, 1982 to December, 1982 no ore was despatched from Redi, with the result, that the Company suffered great financial losses.

10. Canalisation of Ore India is only from Redi Sector and owners only get 95 percent of the due from M. M. T. C., which never....lifts the quantity available and so the inflow of funds is affected and there is a financial crisis every month. It does not fix the price in advance and so nothing is known about the inflow of funds, which is not the case with the minor owners relied upon for comparison by the Sanghatana. The future of the industry. Mine at Redi is not bright and it cannot be compared to manufacturing industries and it is not a direct exporter. The Goa Mine Owners are direct exporters and they get 100 FOBT) value paid by foreign buyers. The production cost of the Company at Redi is 25 percent more than that of Goa owners and even the production of ore per c. Ft. is more in Goa mines than Redi mines.

11. The Company's neighbours, Gogte Minerals Ltd., have got vast reserves and so they can continue to work for longer period as compared to NIMCO. Fore the last 15 years, NIMCO has been paying to its workers more than what Gogtes are paying NIMCO's mines are at lower level. The Mines being in a remote corner, more money has to be spent on procuring spare parts, diesel and other commodities and hence Goa mines and their wages scales etc. are not relevant for comparison. The employees have exploited the NIMCO by frequent strike and shattered the Company's economy. It employs 281 permanent confirmed workmen and 209 temporary workmen.

12. The present Chairman of the Company, who came in the picture in 1968-69, implemented the recommendations of the Central Wage Board for the I. Ore Mining Industry at Redi in 1969, with retrospective effect from 1-1-1967 even when the other Mine owners in Goa had not implemented them. Even Gogtes and Deccan Minerals Pvt. Ltd. had not implemented the said recommendations. Gogtes have brought their workers on par with this Company only in 1984.

13. The workers have been changing from Union to Union and in December 1980 a new settlement was signed casting a burden of lakhs of rupees on the Company. The Contractor's jetty workers resorted to illegal strike and forced the Company to sign a settlement as per agreement with A. I. P. D. W. Federation on 2-3-82, though the old settlement of 20-9-77 was in force. Even then the workmen went on illegal strikes from 1980-81 to 1985-86, which have resulted in losses of Rs. 8,50,82,535/15. The Company is thus unable to take additional burden by way of revision of wages etc. The Sanghatana has not served a charter of Demands on the Company and given details of their demands and the capacity of the industry and its working for a season has to be considered and having to all these contentions the Demand may be rejected.

14. The point for consideration and finding before me is, whether the Demands made by the workmen are just and fair. FINDING on the point is, that they are JUST and PROPER to the extent stated in the settlement between the Employers, (NIMCO), and their workmen dated 20th November 1987, which forms PART of this AWARD.

REASONS

15. This is a Reference made to me by the Government of India as per the Agreement between the Employers and the Union Representatives of their workmen dated 30th January 1986. The workmen have raised several Demands regarding their wage scales etc. against their Employers, who have and own, Iron Ore Mines at Redi, Sindhudurg District of Maharashtra State. I am to arbitrate on the workers' Demands referred to me as per their mutual agreement. At the request of the parties and their representatives I visited the Mines at Redi and inspected their working on site in the company of the parties and their representatives.

16. After inspection of the working in the mines at Redi, I fixed the Arbitration for hearing at Panjim, (Goa), and Bombay on several days. The parties appeared before me at the hearings with their representatives and Advocates. Both the parties have filed several documents including settlements of other mining companies in support, and justification, of their claims and contentions. Each party has admitted correctness of some of the documents and papers filed by the opposite party.

17. The reference was last fixed for hearing before me in the Employers' Office at Bombay, on 20th inst., by consent of the concerned parties. The Employers' Managing Director, Shri. Shyamkumar Shrivastavji, and the Union representatives, Shri Mohan Rao of A. I. P. & D. W. Federation, Bombay-38, and Shri. K. L. Rane, President, Redi, Kamgar Sanghatana, submitted before me, that by mutual negotiations they had arrived at a settlement of the dispute referred to me for arbitration. I went through the settlement and explained its terms to the Union representatives and Shri. S. Shirvastavji, Man. Director of NIMCO PVT. LTD. I asked, and inquired of them if they had understood the terms and impact of the settlement and if they found it to be fair, just and proper. They added that they had read and studied the terms of the settlement and they found and thought that it was just and fair and in their interest and, therefore, they had voluntarily signed and executed it. As an Arbitrator I also find that the Management, the Federation and Sanghatana representatives have cooperated with each other and had negotiations in a sporting manner with a view to have good industrial relations now and in the future. I find that they have arrived at a reasonable and fair settlement of the dispute. I am firmly of the opinion, that the settlement is fair and just to the Employers and their workmen and hope and wish, that this very approach should be used in case of any dispute in future, small or big. I have, therefore, taken on record, the said settlement, which was executed and signed by, and explained to, the parties on 20th inst. and 26th inst. and which is fair, just, proper, voluntary and legal. I, therefore make an Award in terms of the legal settlement and make the following order.

ORDER.

I hereby make an award in terms of the settlement between the above parties, which consists of 5 pages and Annexures, A & B, dated 20th inst. and signed on that day and to-day by the parties and which forms PART of this AWARD I direct that both the parties shall implement it in letter and spirit I thus dispose of the reference.

F. H. LALA, Arbitrator.

[No. L.-26011/23/85-D. III(B)]

10/2. Sunflower,
C. Parade Reclamation,
Bombay-400005,
Dated 26th November, 1987.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Under Section 2(p) read with Section 18(1) of the

Industrial Disputes Act, 1947

NAMES OF THE PARTIES.

Representing Employer :

Shri Shyamkumar Shrivastava,
Chairman,
New India Mining Corpn. Pvt. Ltd.,

'Mittal Tower', 'A' Wing,
14th Floor, Nariman Point,
Bombay-400021.

Representing Workmen :

Shri S. R. Kulkarni,
President,
All India Port & Dock Workers' Federation,
Bombay.

Shri B. Mohan Rao,
Secretary,
All India Port & Dock Workers' Federation,
Bombay.

Shri K. L. Rane, President
Shri T. A. Mathew, Treasurer
Redi Kamgar Sanghatana, At & Post- Redi District Sindhudurg.

Shri Bhagat B. N.—Committee Member.

Shri Sharad A. Sawant—Secretary, Mauli Kamgar Sanghatana, Redi.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas the Redi Kamgar Sanghatana, Redi, (hereinafter referred to as the 'Union') representing the workmen working in New India Mining Corporation Pvt. Ltd., At & Post—Redi, and affiliated to All India Port & Dock Workers' Federation, Bombay submitted a Charter of Demands to New India Mining Corporation Pvt. Ltd., At & Post—Redi (hereinafter referred to as 'Employer') and desired to have discussions with the employer for amicable settlement of those demands ;

Whereas the employer and the Union could not amicably settle the demands in the discussions held between them;

Whereas the Union and employer failed to reach an amicable settlement on all the demands, agreed to grant interim relief and referred the Charter of Demands to the Sole Arbitration of Shri P. H. Lala, vide the settlement, dated 30th January, 1986 ;

Whereas the said Settlement stipulated that the Award shall be binding for a period of 3 years effective from 1st October, 1984 to 30th September, 1987.

Whereas the Arbitration proceedings could not commence till 11th March, 1986, as the Government of India's order in this respect was issued vide Ministry of Labour's Order No. L-26011/23/85-D. II(B)(P) dated 16th January, 1986.

Whereas during the course of discussions Shri B. Mohan Rao on behalf of the RKS pleaded that NIMCO and Chitragupta Agencies to follow the similar memorandum of settlement as M/s. Gogte Minerals giving ad hoc payment as per Annexure 'A' and increments as per Annexure 'B' of the settlement.

And whereas Mr. Shyamkumar Shrivastava, Chairman of NIMCO argued that he has been paying higher wages and better amenities to his workmen since earlier year 1979 and that he also maintained larger number of workmen both on mines and at jetty establishments. The number of permanent workmen at mines being 290 as on date. He further argued that the settlement similar to Gogte's would put on him tremendous financial burden. Shri Shyamkumar Shrivastava pointed out that there have been stoppages of work during the period of dispute causing productive and financial losses. Shri Shyamkumar Shrivastava insisted that in these circumstances he deserves concession in the settlement as that of M/s. Gogte Minerals.

Both Mr. S. R. Kulkarni and Mr. Mohan Rao appreciated the good gesture of Shri Shyamkumar Shrivastava in keeping more permanent workmen and providing better welfare amenities.

However, Shri S. R. Kulkarni and Shri Shyamkumar Shrivastava left the issue of giving the benefit of quantum of reduction in Ad hoc payments to workers to the final decision of Hon'ble Arbitrator Shri P. H. Lala.

Hon'ble Shri Lala after hearing Shri Shyamkumar Shrivastava, he was convinced that there was merit for reduction in ad hoc payment as compared to Gogte Minerals, but requested as a gesture of goodwill to consider to pay the same like Gogte Minerals and drawn the attention of the workmen and reciprocate the same by best performance and productivity and Shri Shyamkumar Shrivastava agreed, so that the industry could be developed on sound footing. Shri Shyamkumar agreed to the proposal of Shri Lala to pay the same like Gogte Minerals.

Whereas at the pursuasion for amicable settlement, the parties entered into a settlement on the following terms and conditions under Section 2(p) read with Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 and also decided to seek award from the Arbitrator in terms of the Settlement.

Terms of Settlement

1. The existing pay-scales, Dearness Allowance Scheme, other allowances, shall continue to remain unchanged. Workmen whose pay has reached the maximum of the pay-scale shall be given increment every year which will be equivalent to the last drawn increment given based on Wage Board recommendations by RMMS.

2. The workmen covered by the reference shall be paid the following ad hoc amount as per Annexure 'A' in full and final settlement of their claims under Charter of Demands for the period from 1st October, 1984 to 30th September, 1986.

3. The workmen covered by the reference shall further be paid increased wages with effect from 1st October, 1986 on the basis of their normal wages for the month of October, 1986 as stipulated in Annexure 'B' to this Settlement. Increased wages shall be termed as additional pay which shall include the Interim Relief granted under Settlement, dated 30th January, 1986 and interim relief will not be paid separately. The additional pay shall be treated as pay for all purposes.

4. Those workmen who have been recruited after 1st October, 1984 and covered under this reference and have not been placed in the grade shall be paid on ad hoc amount on pro rata basis and from 1st October, 1987 they shall be given D.A. and other allowances, per month shall not be less than Rs 800 and the pay will be fixed accordingly.

5. It is agreed by the employer that the amount due to workmen as per Clause 2 above shall be paid in three instalments each after shipment of two lakhs tonnes by NIMCO and also the arrears as per Clause 3 will also be paid in three instalments along with the ad hoc payment as said above.

6. It is agreed between the parties that merely as a consequence of this settlement any facility, privilege, amenity, benefit monetary including payment of one month's salary as ex-gratia every year/season or concession to which a workmen or category of workmen might be entitled to by way of any award, settlement, practice, or usage, shall not be withdrawn, reduced or curtailed except subject to such modifications/alterations/additions/deletions etc., affected by the Award of the Hon'ble Arbitrator Shri V. Sinha, Regional Labour Commissioner (C), Bombay, referred to him on 6th June, 1986 particularly in respect of Clause Nos. 7 and 22 of the Agreement dated 20th December, 1980.

7. As agreed in the Settlement dated 30th January, 1986, this Settlement shall be binding on the parties till 30th September, 1987 and thereafter workmen are free to raise the demands and seek settlement to

those demands with the employer. It is further agreed that the workmen shall not resort to any illegal strike/abrupt stoppage of work and they shall try to settle the disputes and differences with the Management by direct negotiations and further unresolved disputes shall be taken by the Federation with the Management for settlement.

8. Both the parties hereby agree to seek the consent award from the Arbitrator, Shri F. H. Lala, in the dispute referred to him by the Government of India's Order L-26011/23/85-D.III(B)(P) dated 16th January, 1986.

9. Should there be any problem in implementation of the terms of the settlement, such disputes shall be resolved through mutual discussion between the Union and the Management at Redi, failing which, such unresolved issue shall be jointly referred to Shri S. R. Kulkarni, President, All India Port & Dock Workers' Federation, and Shri Shyamkumar Shrivastava, Chairman, New India Mining Corporation Pvt. Ltd., for discussions and settlement. Their decisions in the matter shall be final and binding on the parties.

Bombay :
Dated : 20-11-1987.
On behalf of the
Employer :
Sd/-

(SHYAMKUMAR SHRIVASTAVA)
Chairman
New India Mining Corporation
Pvt. Ltd.

WITNESS :

Sd/-
1. (D. S. RAO)
Sd/-
2.

On behalf of the Workmen :
Sd/-
(S. R. KULKARNI)
President,
All India Port & Dock Workers' Federation.

Sd/-
(B. MOHAN RAO)
Secretary,
All India Port & Dock Workers' Federation.

Sd/-
(K. L. RANE),
President,
Redi Kamgar Sanghatana.

Sd/-
(T. A. MATHEW)
Treasurer,
Redi Kamgar Sanghatana.

Sd/-
(B. N. BHAGAT)
Committee Member,
Redi Kamgar Sanghatana.

Sd/-
(SHARAD SAWANT)
Secretary,
Mauli Kamgar Sanghatana

WITNESS :

Annexure, 'A' to Settlement.

Ad-hoc payment admissible to the workmen for the period of 1-10-1984 to 31-9-1986

Eligibility	Ad-hoc amount payable to a permanent workman	Ad-hoc amount payable to a seasonal workman
1. Workmen who were in receipt of Interim Relief of Rs. 60/- p.m. during the period 1-10-1984 to 30-9-1986	Rs. 1650/- each	Rs.100/-each
2. Workmen who were in receipt of Interim Relief of Rs. 70/- pm. during the period 1-10-1984 to 30-9-1986	Rs. 2250/- each	Rs. 1500/-each
3. Workmen who were in receipt of Interim Relief of Rs. 80/- p.m. during the period 1-10-1984 to 30-9-1986	Rs. 3,000/- each	Rs. 2,000/- each

N.B. (a) Above ad hoc amount will be paid in full to those workmen who are on the Muster Roll of the Company on 1-10-1984 and 31-9-1986. Those workmen who were on leave without pay for a month, the amount will be reduced to that extent on pro rata basis.

(b) The workmen who have resigned, retired, discharged or died etc. after 1-10-1984 or those who have joined the service after 1-10-1984 shall be eligible for ad hoc payment for the period they were in service on pro rata basis.

Annexure 'B' to Settlement.

Statement showing the Wage Increase granted to the workmen a per Clause 3 of the Settlement and with effect from 1-10-1986

Wage range for wage increase on the basis of workmen's wages for a month as on 1-10-1986 (excluding OT wages)		Wage increase per month
Wage Rs.	Range Rs.	Rs.
801	850	125
851	900	132
901	950	140
951	1000	147
1001	1050	155
1051	1100	162
1101	1150	170
1150	1200	177
1201	1250	185
1251	1300	192
1301	1350	200
1351	1400	207

1401	1450	215
1451	1500	222
1501	1550	230
1551	1600	237
1601	1650	245
1651	1700	252
1701	1750	260
1751	1800	267
1801	1850	275
1851	1900	282
1901	1950	290
1951	2000	297
2001	2050	305
2051	2100	312

N.B. (a) Wages for the above purpose will mean monthly gross emoluments excluding OT wages.

(b) The payment of Interim Relief separately will be discountinued from 1-10-1986 as the same will be adjusted in the wage increase.

The above settlement of pages 1 to 5 with annexures, A &B, arrived at by negotiations by the Employers and their workmen's Union Representatives and, which is attested by Shri D.S. Rao and is dated 20th Novembet 1987, was filed at the hearing before me today (20th Nov.'87). The settlement was read over, and explained by me, to the Parties and Office bearers of the Federation and kam. Sanghatana. All of them admitted the correctness of the settlement and said that they had understood its impact etc. They added that it has been signed and executed by them all for the benefit of workers and industry voluntarily and that it will be binding on them.

I also find, that they have arrived at the settlement after giving careful thought to all the aspects of the Demands and their implications etc. I think and find that the settlement is just,fair, proper and legal. I, therefore, have taken it on record as it is fair, valid and legal.

Bombay-21, (F.H. Lala)
20th Nov., '87. Arbitrator.

Shri Sharad Sawant, Secretary, Mauli Kamgar Sanghatana, was shown the settlement, and it was read over and explained to him and the implications were also explained to him. He agreed to the term and admitted that the terms are fair and, just. He has, therefore, signed and executed the settlement on behalf of his Sanghatana and the workers. I have, therfore admitted the settlement as fair and shall pass an AWARD on basis of the Settlement, which shall form part of my AWARD.

(F.H. Lala)

Bombay, 26 Nov. '87 Arbitrator.

का.आ. 3558—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैलडिला आयरन और परियोजना–14 किरन्दुल, जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-12-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3558.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Bailadila Iron Ore Project 14 Kirandul, Distt. Bastar (M.P.), and their workmen, which was received by the Central Government on 2-2-87.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR.(M.P.)

1. Case No. CGIT|LC(R)(84)|1986.

2. Case No. CGIT|LC(R)(12)|1987.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14, Kirandul, Distt. Bastar (M.P.) and their workmen represented through Metal Mines Workers Union and Samykta Khadan Mazdoor Sangh, P. O. Kirandul, Distt. Bastar (M.P.).

APPEARANCES :

For Workmen :

1. Shri A. B. Khan, Jt. Secy., M. M. Workers Union.

2. Shri Arvind Shrivastava, Advocate for S. K. Mazdoor Sangh.

For Management : Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Iron Ore Mine. DISTT. : Bastar (M.P.)

AWARD

Dated the 26th November, 1987

Exercising powers under Sec. 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute vide Notification No. L-26011|8|85-D. III(B), dated the 29th September, 1986 (Registered as Case No. CGIT/LC(R)/(84)|86) :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14, Kirandul in not regularising the 64 ex-wagon Levelling workmen (as per list attached) is justified ? If not, to what relief the concerned workmen entitled ?"

By another notification No. L-26011/12/85-D. III(D), dated the 27th January, 1987 (Registered as Case No. CGIT|LC(R)(12)|87) another dispute has been referred the schedule of which is as under :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14, Kirandul in not regularising the 34 Ex-Wagon Levelling Workmen (As per list enclosed) is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

(List not received)

From the above two references, it appears that the disputes are for regularisation of 64 (represened by INTUC) Ex-wagon Levelling workmen and 34 Ex-wagon Levelling workmen (represened by AITUC). Therefore, it will be convenient to dispose off both the references by one order.

After the references were received parties contested the disputes by filing their pleadings and documents in both the

references separately, but at the stage of evidence, parties settled the dispute mutually in respect of 98 Ex-wagon Levelling workmen (covered by two references) and filed compromise petitions, duly verified.

I have persued the terms of the settlement duly incorporated in the compromise petitions (Annexed with this award as Annexure 'A' and 'B') and I am satisfied that the terms of the settlement are fair, just, reasonable, in the interest of the workmen concerned as well as the two Unions representing the workmen i.e. Metal Mines Workers Union (INTUC) and Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC). I, therefore, record my award in terms of the settlement.

No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. L-26011|8|85-D. III(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE 'A'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT REACHED UNDER SECTION 18(1) OF THE I.D. ACT BETWEEN THE MANAGEMENT OF NMDC LTD. BIOP, DEPOSIT NO. 14 AND THE WORKMEN REPRESENTED BY

METAL MINES WORKERS UNION.

Representing Management :

1. Shri C. Ramachandran, General Manager
2. Shri G. S. Purohit, Dy. General Manager (P)
3. Shri T. Ranganathan, Chief Engineer (M&S)
4. Shri P. V. Rathnam, Financial Adviser
5. Shri S. Guruswami, Sr. Personnel Manager

Representing M.M.W.U. :

1. Shri J. A. Siddique, Secretary,
2. Shri S. R. Kashyap, Office Secretary
3. Shri A. B. Khan, Jt. Secretary
4. Shri Arvind Lal, Jt. Secretary
5. Shri P. P. R. Pillai, Jt. Secretary

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas in the Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14 of NMDC Ltd. there were 98 labourers who had been engaged by different contractors in the contract work of levelling of iron ore loaded into the Railway wagons as the levelling of railway wagons was insisted upon by the SE Railways for safety of the railway rolling stock as uneven loading could cause derailment of wagons. Subsequently, it was decided by the Railway authorities that in case loading of iron ore was evenly done into railway wagons the work of levelling need not be done. Accordingly, the levelling work was discontinued with effect from 9-4-81 even before such operation was prohibited under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act.

Whereas on discontinuance of the aforesaid wagon levelling work, based on mutual discussions with the Union, it was agreed to provide alternate employment to those contract labourers in minor petty civil works through any agency. Accordingly, since then these labourers have been engaged by the contractors under minor civil works from time to time.

87/1861 GI—5

And whereas the Metal Mines Workers Union raised an industrial dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Jagdalpur vide their letter dated 20-1-1985 demanding regularisation of these ex-wagon levelling labourers who have been working under different contractors. The ALC(C), Jagdalpur, seized the matter into conciliation and proceedings were held on 7-4-85 which ended in failure.

And whereas the Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi upon receipt of failure of conciliation report vide their Order dated 29th September, 1986 referred the case to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for adjudication.

And whereas notwithstanding the fact that the issue has been referred to the CIGT for adjudication, the MMWU which raised the dispute, discussed the demand with the Management and during the discussion, it was agreed to resolve the matter mutually and to submit the terms of Settlement to the CGIT for passing a consent award, in the dispute referred for adjudication.

Now, therefore, after series of protracted discussions, the Management and the Union have finally arrived at the following Settlement, mutually acceptable to them, in a spirit of co-operation and goodwill and reaffirming their faith in bilateral discussions in the larger interest of the workmen :—

TERMS OF SETTLEMENT

The parties hereby agree that :—

1. In view of historical reasons, the 98 Ex-wagon levelling labourers whose names are indicated in Annexure I forming part of this Settlement, will be considered for employment by the Management of NMDC Ltd. Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14 as per the following terms and conditions taking into account the restrictions imposed under the Mines Act for employment of female members in the Mines in the night shift :—

(a) (i) Out of the aforesaid 98 persons, there are 27 female members whose names are indicated in Annexure II forming part of this Settlement. They have agreed to leave the services of their Contractor Employer on resignation subject to the condition that their husbands are offered employment in any capacity by the Management of BIOP, Deposit No. 14. Accordingly, these 27 persons will submit their resignation from the services with their contractors and they shall leave the services after payment of usual benefits admissible to them on resignation. After resignation and relief, they shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concession|rights in BIOP, Deposit No. 14.

(ii) The 27 male members (husbands) whose names are indicated in Annexure-III forming part of this Settlement in whose favour female members (wives) are resigning will also have an option to resign from the services of their contractor employer in favour of their legitimate sons provided such husbands (male members) are aged 55 years or above. Those who are below the age of 55 years shall not be eligible for such option. Such persons who are resigning in favour of their legitimate sons, after resignation and relief shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concession|rights in BIOP, Deposit No. 14.

(b) Similarly, 10 more female members whose names are indicated in Annexure-IV forming part of this Settlement out of the remaining 44 persons have agreed to leave the services on resignation subject to the condition that their male members as their substitutes are offered employment in any capacity by the Management of BIOP, Dep. 14. Accordingly, these 10 persons will submit their resignation from the services with their contractors and they shall

leave the services after payment of usual benefits admissible to them on resignation. After resignation and relief, they shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concesion/rights in BIOP, Dep. 14.

(c) On fulfilment of the conditions specified in Clause 1(a) and (b) above, such of those who possess minimum qualification of Middle class passed shall be interviewed by a Selection Committee, duly constituted by the Management to adjudge their suitability for appointment to the post of Khalasi subject to fulfilling all conditions for recruitment to such posts and those who are thus found suitable shall be offered the post of Khalasi in the regular scale of pay of Rs. 550-11-704 with the starting basic pay of the said scale with all other attendant benefits/allowances. Their employment for all purposes and intents shall reckon only from the date from which they join in the regular scale of pay on their appointment.

(d) On completion of recruitment action as contemplated in Clause (c) supra, in the first instance, such of those out of 27 persons who are governed by Clause (a) supra and who are not considered for appointment to the regular post of Khalasi will be engaged as 'Muck Cleaning piece-rated labour' for muck cleaning operations, as a fresh entrant with effect from the first of the succeeding month from the date of implementation of this Settlement. On their employment as 'Muck Cleaning Piece-rated labour', they shall be eligible for a maximum earning of Rs. 29/- per day per head, based on actual attendance, based on price rate basis subject to completion of the quantum of work as fixed by the Management. If however, they do not complete the quantum of work prescribed making them eligible for earning under piece-rated system, they will be eligible for payment of fall back wages only, subject to the full attendance, for each day, which will be equivalent to the minimum wages, as may be prescribed from time to time, under the Notification issued by the Governemnt of India for 'Iron Ore Industry'. Their daily maximum piece rate earning of Rs. 29/- initially fixed shall also be increased every year by three and half precent subject to a maximum of Re. 1/- (Rupee One only) per day from 1988 to 1993. The first such increase shall be due in the year 1988, on completion of one year service from the date of their present engagement and thereafter on completion of every year of service. They shall, on completion of 6 years service from the date of their proposed engagement as 'Muck Cleaning Piece-rated Labour' viz. in the year 1994, be offered and fixed at the bottom of the lowest scale of pay with all other allowances, as may be in force in BIOP, Deposit No. 14 at that time, for muck cleaning operations.

(e) The remaining left out persons shall be interviewed by a Selection Committee duly constituted by the Management to adjudge their suitability for engagement as Muck cleaning piece-rated labour for muck cleaning operations. Based on the panel of selection so drawn, if there is any requirement of muck cleaning piece-rated labourers as per the assessment made by the Management, persons out of this panel only shall be engaged as Muck Cleaning Piece-rated labour and they shall be governed by the provisions of Clause(d) of this Settlement. The initial minimum piece-rated wages, subsequent increase in wages every year and grant of the lowest scale on completion of 6 years service shall however, reckon only from the date of their employment as 'Muck Cleaning Piece-rated Labour' for grant of such benefits.

(f) Such of those who are not offered the post of Muck Cleaning piece-rated labour for muck cleaning operations for any reason whatsoever shall be engaged on daily wages by BIOP, Dep. No. 14 for works in Civil Department as fresh entrant with effect from the first of the succeeding month from the date of implementation of this Settlement, after their resignation and relief from the services of their contractor. On their employment, they shall be paid daily wages prescribed under the Minimum Wages Act for civil construction work as may be in force from time to time.

(g) As a special case, if any vacancies for the post of Khalasis arise in future, the workmen who are engaged as 'Muck Cleaning Piece-rated Labours' shall only be given preference for appointment to such posts, subject to fulfilling all other conditions for recruitment to such posts. However, in respect of persons who are covered under Clause (d) supra only, the educational qualifications prescribed for appointment to the post of Khalasi, shall not be insisted upon. This concession shall be applicable only for their initial appointment and shall not be applicable for future promotions.

2. This Settlement shall be in force for a period of six years from the date of its implementation. During the currency of this Settlement :—

(a) If the fall back minimum wage is increased by the relevant statute or if any higher wages are fixed for the daily rated workmen at the Corporate level by any other Settlement, the Muck Cleaning Piece-rated labourers shall not be deprived of such higher wages towards fall back wages.

Similarly if any higher wages are fixed for the daily rated workmen at the Corporate level by any other Settlement, the daily rated workmen engaged for civil construction work shall not be deprived of such higher wages as their minimum wages.

(b) No dispute whatsoever shall be raised by the Union regarding ex-wagon levelling labourers.

(c) The provisions of the Settlement shall not be quoted nor shall be treated as precedent for any other category and in particular for the labourers engaged by the contractors in BIOP, Dep. No. 14.

3. The parties have reached this Memorandum of Settlement on their own volition, in the interest of industrial peace and for mutual beefit. The parties feel that the provisions of this Settlement are fair and reasonable.

4. The parties shall make an application jointly before the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for passing consent award, in terms of the provisions of this Settlement, to answer the terms of reference referred for adjudication by the Government of India to the Tribunal.

5. The provisions of this Memorandum of Settlement shall be implemented only after the orders are passed by the Central Government Industrial Tribunal for the dispute referred to the Tribunal for adjudication and the date of implementation of this Settlement shall be the date on which the orders are passed by the Central Government Industrial Tribunal.

Signed at Kirandul on 31st day of October 1987.

Representing Management :

Sd./-

(C. Ramachandran)
General Manager

Sd./-

(G. S. Purohit)
Dy. General Manager (P)

Sd./-

(T. Ranganathan)
Chief Engineer (M&S)

Sd./-

(P. V. Rathnam)
Financial Adviser

Sd./-

(S. Guruswami)
Sr. Personnel Manager

Representing Union :

Sd.|-
(J. A. Siddique)
Secretary

Sd.|-
(S. R. Kashyap)
Office Secretary

Sd.|-
(A. B. Khan)
Jt. Secretary

Sd.|-
(Arvind Lal)
Jt. Secretary

Sd.|-
(P. P. R. Pillai)
Jt. Secretary

Witness :

Sd.|- Sd.|-
(M. K. Chatterjee) (T. P. Gopalakrishnan)
Personnel Officer Sr. Stenographer

Verified today at Jabalpur.

Sd|- Sd|-
(M. K. Chatterjee) (A. B. Khan)
P.O. It. Secretary
Management Representative MMWU

[No. L-26011|8|85-D. III(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer.

ANNEXURE I

Names of Ex-Wagon Levelling Labourers (98 Nos.)

(Ref.: Clause 1 of the Settlement)

S. No.	Token No.	Name of labour	Father's (Husband's) Name
1	2	3	4
		S/Shri	S/Shri
1.	21000	Barsan	Bhagwani
2.	21001	Konal Ram	Ramlain
3	21002	Smt. Sumitra Bai	Nirbhai Ram
4.	21003	Phagni Bai	Dev Singh
5.	21004	Dhani Ram	Pushao
6.	21005	Smt. Shanti Bai	Dhanesh
7.	21012	Smt. Jamuna Bai	Dhana Ram
8.	21013	Bisahoo Ram	Chaitu Ram
9.	21014	Smt. Dhan Bai	Bishai Ram
10.	21015	Bhagat Ram	Kegu Ram
11.	21016	Smt. Ramotia Bai	Bhagat Ram
12.	21017	Smt. Mahadev	Pardeshi
13.	21018	Smt. Birja Bai	Mahadev
14.	21019	Smt. Shanti Bai	Agat Ram
15.	21020	Shanta Ram	Firangi
16.	21021	Smt. Niresha Bai	Shanta Ram
17.	21022	Bhelu Ram	Dukhu
18.	21023	Smt. Rohini Bai	Kamal Singh
19.	21024	Barma	Jhadu
20.	21025	Qwal	Barma
21.	21026	Smt. Debati Bai	Qwal
22.	21027	Balaram	Bisharu
23.	21028	Smt. Bisahin Bai	Balaram
24.	21029	Sankar	Darbari
25.	21031	Smt. Khotbaharin Bai	Tatfi Ram
26.	21032	Mangal Mala	Chhannu
27.	21033	Smt. Sone Bai	Mangal Mali
28.	21034	Manoranjan	Harikrishna
29.	21035	Arjun	Jatu Ram
30.	21036	Biknatin Bai	Arjun
31.	21037	Raghunath	Dasarath
32.	21038	Sahadev	Jatu ram
33.	21039	Mallaiya	Narsaiya
34.	21040	Smt. Ram Bai	Malaiya
35.	21042	K. Sanyasi	Neelaiya
36.	21043	Pannu Ram	Motilal
37.	21044	Smt. Kausalya Bai	Pannu Ram
38.	21045	Lokesh	Lakhan
39.	21046	Asha Ram	Anand Ram
40.	21047	Smt Sukhiva Bai	Asha Ram
41.	21048	Komal Singh	Ramjee
42.	21049	Gurao Ram	Manilal
43.	21050	Smt. Sundar Bai	Komal
44.	21051	GK Murthy	Kistamma
45.	21052	G. Simachalam	G. Kistamma
46.	21053	Bhikari Ram	Rameshwar
47.	21054	Smt. Kunti Bai	Bhikari Ram
48.	21055	Maniram	Ramjee
49.	21056	Smt. Kausalya Bai	Maniram
50.	21057	Debu Ram	Banau
51.	21058	Ram Singh	Durjan
52.	21059	Smt. Birwa Bai	Ram Singh
53.	21060	Itwari	Samaru
54.	21061	Udai Ram	Bisali Ram
55.	21062	Smt. Chaitu Bai	Puranik
56.	21063	Jagau	Tilak
57.	21064	Smt. Kamala Bai	Jagau
58.	21065	Dattu	Peera
59	21066	Thani Bai	Raisingh
60.	21067	Budhwar Singh	Mandhar
61.	21068	Gariba Ram	Mukund
62.	21069	Amar Singh	Channu
63.	21070	Smt. Suraj Bai	Amar Singh
64.	21071	Smt. Keja Bai	Ram Singh
65.	21072	Smt. Milapa Bai	Santram
66.	21073	Maadhir	Asha Ram
67.	21074	Smt. Dev Kumari	Manohar
68.	21075	Smt. Sundar Bai	Pardeshi
69.	21076	Smt. Dasaree Bai	Dhiraj
70.	21077	Kasinath	Pandurang
71.	21078	Dhanesh	Keshav
72.	21079	Smt. Hemin Bai	Mahesh
73.	21080	Bisahu Ram	Pitamber
74.	21081	Poshaiya	Ramiaya
75.	21082	Smt. Champa Bai	Poshaiya
76.	21083	Sukhi Ram	Mehtar Ram
77.	21084	Radheshyam	Kartik Ram
78.	21085	Rama	Bali
79.	21086	Smt. Surja Bai	Ramam
80.	21087	Bhagwan	Gayanoba
81.	21088	Smt. Gigya Bai	Bhagwan
82.	21089	Dukhu Ram	Gangdeo
83.	21090	Smt. Sonbatiay Bai	Dhukhu Ram

Shri Rudresh, Tumkur Taluk, Honnudike Post, Honudike-57212.

V/s.

SECOND PARTY :

The Chairman & Managing Director State Bank of Mysore, Head Office, Bangalore

APPEARANCES :

For the first party—Shri N. Sampathkumar, Advocate.

For the second party—Sri C. M. Magabushan, Advocate.

Industrial Dispute between Shri H. S. Rudresh (Temporary peon, Honnudike Branch) and State Bank of Mysore-C.R. No. 29/87 (Old No. 16/85).

With reference to the above, Shri H. S. Rudresh, who appeared for the interview for considering absorption has been found suitable by the committee. Accordingly, we have authorised the Zonal Manager, Bangalore Zone, to offer the appointment of subordinate staff on full wages to Shri H. S. Rudresh, early. The same may be advised to the Tribunal.

Yours faithfully,

Sd/-
Personnel Manager.

1	2	3	4
		S/Shree	S/Shree
84.	21091	Adinarayan	Mallanna
85.	21092	M. Prakash Rao	Sayanna
86.	21093	Subu Ram	Mangloo
87.	21094	Kamal	Bhagwani
88.	21095	Sant Ram	Manbodhi
89.	21096	Udai Ram	Manbodhi
90.	21097	Pardeshi	Bishal
91.	21041	P.K. Rao	Kesanna
92.	22242	Puranik	Anand
93.	22631	Sukumar	Radhanath
94.	22633	Smt. Hirondi Bai	Hobit Ram
95.	22635	Smt. Sukbati Bai	Mitru Das
96.	22239	J.V.R.B. Sastry	J.V.S. Sastri
97.	22238	B.G. Naidu	B.A. Suraiya
98.	22241	D. Mohan Rao	Ramchandra

Annexure–II

Name of 27 Female (Couple) Members
[Ref. : Clause 1(a)(i) of the Settlment]

S. No.	Token No.	Name of female labour	Name of Hasband
1.	21006	Smt. Shanti Bai	Shri Dhanesh
2.	21014	Smt. Dhan Bai	Shri Bisahu Ram
3.	21016	Smt. Ramotin Bai	Sri Bhagat Ram
4.	21018	Smt. Birja Bai	Sri Mahadev
5.	21021	Smt. Nirasha Bai	Sri Sant Ram
6.	21023	Smt. Rohini Bai	Sri Komal Singh
7.	21026	Smt. Debati Bai	Sri Gawal
8.	21028	Smt. Bishahin Bai	Sri Balaram
9.	21033	Smt. Sona Bai	Sri Mangal Mali
10.	21040	Smt. Ram Bai	Sri Mallaiya
11.	21044	Smt. Kausalya Bai	Sri Pannu Ram
12.	21047	Smt. Sukhiya Bai	Sri Asha Ram
13.	21050	Smt. Sundar Bai	Sri Kamal
14.	21054	Smt. Kunti Bai	Sri Bhikari Ram
15.	21056	Smt. Kausalya Bai	Sri Mani Ram
16.	21059	Smt. Biswa Bai	Sri Ram Singh
17.	21062	Smt. Chaiti Bai	Sri Puranik
18.	21064	Smt. Kamla Bai	Sri Jagao
19.	21070	Smt. Suraj Bai	Sri Amar Singh
20.	21072	Smt. Milapa Bai	Sri Sant Ram
21.	21074	Smt. Deb Kumari	Sri Manteen
22.	21075	Smt. Sunder Bai	Sri Pardeshi
23.	21082	Smt. Champa Bai	Sri Poshaiya
24.	21086	Smt. Surja Bai	Sri Rama
25.	21088	Smt. Jijiya Bai	Sri Bhagwan
26.	21090	Smt. Sonbatniya Bai	Sri Dukhu Ram
27.	21036	Smt. Bikantin Bai	Sri Arjun

Annexure–III

Name of 27 male labourers
[Ref. : Clause I (a)(ii) of the Settlement]

S. No.	Token No.	Name of labour	Father's name
1	2	3	4
		S/Shri	S/Shri
1.	21070	Dhanesh	Keshav
2.	21013	Bisahu Ram	Chaitu Ram
3.	21015	Bhagat Ram	Keju Ram
4.	21017	Mahadev	Pardeshi
5.	21020	Sant Ram	Firangi
6.	21048	Kamal Singh	Ramjee
7.	21025	Gawal	Barma
8.	21027	Balaram	Bisru
9.	21032	Mengal Mali	Channu
10.	21035	Arjun	Jetu Ram
11.	21039	Ballaiya	Narsingh
12.	21043	Panna Ram	Motilal
13.	21046	Asha Ram	Anandram
14.	21094	Kamal	Bhagwani
15.	21053	Bhikari Ram	Rameshwar
16.	21055	Mani Ram	Ramjee
17.	21058	Ram Singh	Durjan
18.	22242	Puranik	Anand
19.	21063	Jagao	Tilak
20.	21069	Amar Singh	Channu
21.	21095	Sant Ram	Manbodhi
22.	21073	Manteen	Asha Ram
23.	21097	Pardeshi	Bishal
24.	21081	Poshaiya	Ramiya
25.	21085	Rama	Bali
26.	21087	Bhagwan	Gayanoba
27.	21089	Dukhu Ram	Gong Dev

Annexure-IV

Name of 10 Female Labourers
(Ref. : Clause 1(b) of the Settlement)

S. No.	Token No.	Name of labour	Father's/Husband's name
			S/Shri
1.	21002	Smt. Sumitra Bai	Nirbhai Ram
2.	21003	Smt. Phagni Bai	Dev Singh
3.	21019	Smt. Shanti Bai	Agat Ram
4.	21031	Smt. Khorbaharin Bai	Tatu Ram
5.	21066	Smt. Thani Bai	Rai Singh
6.	21071	Smt. Keja Bai	Ram Singh
7.	21076	Smt. Deshari Bai	Dheeraj
8.	21079	Smt. Hemin Bai	Mahesh
9.	22633	Smt. HirenJi Bai	Hobit Ram
10.	22635	Smt. Sukbati Bai	Mitru Das

ANNEXURE 'B'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT REACHED UNDER SECTION 18(1 OF THE ID ACT BETWEEN THE MANAGEMENT OF NMDC LTD., BIOP, DEP, 14 AND THE WORKMEN REPRESENTED BY SKMS.

Representing Management	Representing S.K.M.S.
1. Shri C. Ramachandran, General Manager.	1. Shri Barsadula Ram, President
2. Shri G.S. Purohit, Dy. General Manager(P)	2. Shri M.K. Biswas, Vice President
3. Shri T. Ranganathan, Chief Engineer (M&S)	3. Shri P.N. Bhagwat, Secretary.
4. Shri PV Rathnam, Financial Adviser	4. Shri R.D.C.P. Rao, Org. Secretary
5. Shri S. Guruswami, Sr. Personnel Manager	5. Shri L. Subramanian, Treasurer.

SHORT RECITAL OF THE CASE

WHEREAS in the Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 14 of NMDC Ltd. there were 98 labourers who had been engaged by different contractors in the contract work of levelling of iron ore loaded into the Railway wagons as the levelling of railway wagons was insisted upon by the S.E. Railways for safety of

the railway rolling stock as uneven loading could cause derailment of wagons. Subsequently, it was decided by the Railway authorities that in case loading of iron ore was evenly done into railway wagons the work of levelling need not be done. Accordingly, the levelling work was discontinued with effect from 9-4-81 even before such operation was prohibited under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act.

WHEREAS on discontinuance of the aforesaid wagon levelling work based on mutual discussions with the Union, it was agreed to provide alternate employment to those contract labourers in minor petty civil works through any agency. Accordingly, since then these labourers have been engaged by the contractors under minor civil works from time to time.

AND WHEREAS the SKMS Union raised an Industrial Dispute before the Assittant Labour Commissioner(Central), Jagdalpur vide their letter dated 29-1-1985 demanding regularisation of these ex-wagon levelling labourers who have been working under different contractors. The Asstt. Labour Commissioner(C), Jagdalpur seized the matter into conciliation and proceedings were held on 15-3-1985, 6-4-1985, 24-5-1985, 6-6-1985 and 24-6-1985 which ended in failure.

And whereas the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi upon receipt of failure of conciliation report vide their Order dated 27-1-87 referred the case to Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for adjudication.

And whereas notwithstanding the fact that the issue has been referred to the Central Government Industrial Tribunal for adjudication, the SKMS which raised the dispute, discussed the demand with the Managemnt and during the discussion, it was agreed to resolve the matter mutually and to submit the terms of Settlement to the Central Government Industrial Tribunal for passing a consent award, in the dispute referred for adjudication.

Now, therefore, after series of protracted discussions, the Management and the Union have finally arrived at the following Settlement, mutually acceptable to them, in a spirit of co-operation and goodwill and reaffirming their faith in bilateral discussions in the larger interest of the workmen :—

TERMS OF SETTLEMENT

The parties hereby agree that :—

1. In view of historical reasons, the 98 ex-wagon levelling labourers whose names are indicated in Annexure I forming part of this Settlement, will be considered for employment by the Management of NMDC Limited, BIOP, Deposit No. 14 as per the following terms and conditions taking into account the restrictions imposed under the Mines Act for employment of female members in the Mines in the night shift :—

(a) (i) Out of the aforesaid 98 persons, there are 27 female members whose names are indicated in Annexure II forming part of this Settlement. They have agreed to leave the services of their Contractor Employer on resignation subject to the condition that their husbands are offered employment in any capacity by the Management of BIOP, Deposit No. 14. Accordingly, these 27 persons will submit their resignation from the services with their contractors and they shall leave the services after payment of usual benefits admissible to them on resignation. After resignation and relief, they shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concession/rights in BIOP, Deposit No. 14.

(ii) The 27 male members (husbands whose names are indicated in Annexure III forming part of this Settlement in whose favour female members (wives) are resigning will also have an option to resign from the services of their contracor employer in favour of their legitimate sons provided such husbands (male members) are aged 55 years or above. Those who are below the age of 55 years shall not be eligible for such option. Such persons who are resigning in favour of their legitimate sons, after resignation and relief shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concession/rights in BIOP, Deposit-14.

(b) Similarly 10 more female members whose names are indicated in Annexure IV forming part of this Settlement out of the remaining 44 persons have agreed to leave the services on resignation subject to the condition that their male members as their substitutes are offered employment in any capacity by the Management of BIOP, Deposit No. 14. Accordingly, these 10 persons will submit their resignation from the services with their contractors and they shall leave the services after payment of usual benefits admissible to them on resignation. After resignation and relief, they shall have no claim whatsoever for any further employment in any capacity whatsoever or for any concession/rights in BIOP, Deposit No. 14.

(c) On fulfilment of the conditions specified in Clauses (a) and (b) above, such of those who possess minimum qualification of Middle class passed shall be interviewed by a Selection Committee, duly constituted by he Management to adjudge their suitability for appointment to the post of Khalasi subject to fulfilling all conditions for recruitment to such posts and those who are thus found suitable shall be offered the post of Khalasi in the regular scale of pay of Rs. 550-11-704 with the starting basic pay of the said scale with all other attendant benefits/allowances. Their employment for all purposes and intents shall reckon only from the date from which they join in the regular scale of pay on their appointment.

(d) On completion of recruitment action as contemplated in Clause (c) supra, in the first instance, such of those out of 27 persons who are governed by Clause (a) supra and who are not considered for appointment to the regular post of Khalasi will be engaged as 'Muck Cleaning Piece-rated Labour' for muck cleaning operations, as a fresh entrant with effect from the first of the succeeding month from the date of implementation of this Settlement. On their employment as 'Muck Cleaning Piece-rated Labour', they shall be eligible for a maximum earning of Rs. 29 per day per head, based on actual attendance, based on piece-rate basis subject to completion of the quantum of work as fixed by the Management. If, however, they do not complete the quantum of work prescribed making them eligible for earnings under piece-rated system, they will be eligible for payment of fall back wages only, subject to the full attendance, for each day, which will be equivalent to the minimum wages, as may be prescribed from time to time, under the Notification issued by the Government of India for 'Iron Ore Industry'. Their daily maximum piece-rate earning of Rs. 29 initially fixed shall also be increased every year by three and half per cent subject to a maximum of Re. 1 (Rupee One only) per day from 1988 to 1993. The first such increase shall be due in the year 1988, on completion of one year service from the date of their present engagement and thereafter on completion of every year of service. They shall, on completion of 6 years service from the date of their proposed engagement as 'Muck Cleaning piece-rated labour' viz. in the year 1994, be offered and fixed at the bottom of the lowest scale of pay with all other allowances, as may be in force in BIOP, Deposit No. 14 at that time, for muck cleaning operations.

(e) The remaining left out persons shall be interviewed by a Selection Committee duly constituted by the Management to adjudge their suitability for engagement as Muck Cleaning piece-rated labour for muck cleaning operations. Based on the panel of selection so drawn, if there is any requirement of much cleaning piece-rated labourers as per the assessment made by the Management, persons out of this panel only shall be engaged as Muck Cleaning piece-rated labour and they shall be Governed by the provisions of Clause (d) of this Settlement. The initial minimum piece-rated wages, subsequent increase in wages every year and grant of the lowest scale on completion of 6 years service shall, however, reckon only from the date of their employment as 'Muck Cleaning piece-rated labour' for grant of such benefits.

(f) Such of those who are not offered the post of Muck cleaning piece-rated labour for muck cleaning operations for any reason whatsoever, shall be engaged on daily wages by BIOP, Dep. 14 for works in Civil Department as fresh entrant with effect from the first of the succeeding month from the date of implementation of this Settlement, after their resignation and relief from the services of their contractor. On their employment, they shall be paid daily wages prescribed under the Minimum Wages Act for civil construction work as may be in force from time to time.

(g) As a special case, if any vacancies for the post of Khalasis arise in future, the workmen who are engaged as 'Muck cleaning piece-rated labours' shall only be given preference for appointment to such posts, subject to fulfilling all other conditions for recruitment to such posts. However, in respect of persons who are covered under Clause (d) supra only, the educational qualifications prescribed for appointment to the post of Khalasi, shall not be insisted upon. This concession shall be applicable only for their initial appointment and shall not be applicable for future promotions.

2. This Settlement shall be in force for a period of six years from the date of its implementation. During the currency of this Settlement :—

(a) If the fall back minimum wage is increased by the relevant statute or if any higher wages are fixed for the daily rated workmen at the Corporate level by any other Settlement, the Muck Cleaning Piece-rated labourers shall not be deprived of such higher wages towards full back wages. Similarly if any higher wages are fixed for the daily rated workmen at the Corporate level by any other Settlement, the daily rated workmen engaged for civil construction work shall not be deprived of such higher wages as their minimum wages.

(b) No dispute whatsoever shall be raised by the Union regarding ex-wagon levelling labourers.

(c) The provisions of the Settlement shall not be quoted nor shall be treated as precedent for any other category and in particular for the labourers engaged by the contractors in BIOP, Deposit No. 14.

3. The parties have reached this Memorandum of Settlement on their own volition, in the interest of industrial peace and for mutual benefit. The parties feel that the provisions of this Settlement are fair and reasonable.

4. The parties shall make an application jointly before the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for passing consent award, in terms of the provisions of this Settlement, to answer the terms of reference referred for adjudication by the Government of India to the Tribunal.

5. The provisions of this Memorandum of Settlement shall be implemented only after the orders are passed by the Central Government Industrial Tribunal for the dispute referred to the Tribunal for adjudication and the date of implementation of this Settlement shall be the date on which the orders are passed by the Central Government Industrial Tribunal.

Signed at Kirandul on 31st day of October 1987.

Representing Management	Representing Union
(C. Ramachandran) General Manager	(Barsadula Ram) President
(G.C. Purohit) Dy. General Manager (P)	(M.K Biswas) Vice President
(T. Ranganathan) Chief Engineer (M&S)	(P.N. Bhagwat) Secretary
(P.V. Rathnam) Financial Adviser	(R.D.C.P. Rao) Org. Secretary
(S. Guruswami) Sr. Personnel Manager	(L. Subramanian) Treasurer

WITNESS

(MK Chatterjee) Personnel Officer	(T.P. Gopalakrishnan) Sr. Stenographer

Annexure—I

Names of Ex-Wagon Levelling Labourers (98 Nos.)

(Ref: Clause 1 of the Settlement).

Sl. No.	Token No.	Name of labour	Father's/Husband's Name
1	2	3	4
			S/Shri
1.	21000	Shri Barsan	Bhagwani
2.	21001	,, Komal Ram	Ramjee
3.	21002	Smt. Sumitra Bai	Nirbhai Ram
4.	21003	,, Phagni Bai	Dev Singh
5.	21004	Shri Dhani Ram	Pusahoo
6.	21006	Smt. Shanti Bai	Dhanesh
7.	21012	,, Jamuna Bai	Dhana Ram
8.	21013	Shri Bisahu Ram	Chaitu Ram
9.	21014	Smt. Dhan Bai	Bishal Ram
10.	21015	Shri Bhagat Ram	Keju Ram
11.	21016	Smt. Ramodin Bai	Bhagat Ram
12.	21017	Shri Mahadev	Pardeshi
13.	21018	Smt. Dirja Bai	Mahadev
14.	21019	,, Shanti Bai	Agat Ram
15.	21020	Shri Shanta Ram	Firangi
16.	21021	Smt. Nirasha Bai	Santa Ram
17.	21022	Shri Bhedu Ram	Dukhu
18.	21023	Smt. Rohini Bai	Kamal Singh
19.	21024	Shri Barma	Jhadu
22.	21025	Shri Gwal	Barma
21.	21026	Smt. Debati Bai	Gwal
22.	22027	Shri Bala Ram	Bisru
23.	21028	Smt. Bisahin Bai	Bala Ram
24.	21029	Shri Shankar	Darbari
25.	21031	Smt. Khorbaharin Bai	Tatu Ram
26.	21032	Shri Mangal Mali	Chhannu
27.	21033	Smt. Sona Bai	Mangal Mali

1	2	3	4
28.	21034	Shri Manoranjan	Harikrishna
29.	21035	Shri Arjun	Jatu Ram
30.	21036	Smt. Bikantin Bai	Arjun
31.	21037	Shri Raghunath	Dasrath
32.	21038	Shri Sahadev	Jatu Ram
33.	21039	Shri Mallaiya	Narasaiah
34.	21040	Smt. Ram Bai	Mallaiah
35.	21042	Shri K. Sanyasi	Neelaiah
36.	21043	Shri Pannu Ram	Motilal
37.	21044	Smt. Kausalya Bai	Pannu Ram
38.	21045	Shri Lokesh	Lakhan
39.	21046	Shri Asha Ram	Anand Ram
40.	21047	Smt. Sukhiya Bai	Asha Ram
41.	21048	Shri Komal Singh	Ramjee
42.	21049	Shri Gurao Ram	Manilal
43.	21050	Smt. Sundar Bai	Komal
44.	21051	Shri G.K. Murthy	Kisthamma
45.	21052	Shri G. Simhachalam	G. Kisthamma
46.	21053	Shri Bhikari Ram	Ramsewar
47.	21054	Smt. Kunti Bai	Bhikari Ram
48.	21055	Shri Mani Ram	Ramjee
49.	21056	Smt. Kaushalya Bai	Mani Ram
50.	21057	Shri Debu Ram	Banau
51.	21058	Shri Ram Singh	Durjan
52.	21059	Smt. Biswa Bai	Ram Singh
53.	21060	Shri Itwari	Samaru
54.	21061	Shri Udai Ram	Bisali Ram
55.	21062	Smt. Cheiti Bai	Puranik
56.	21063	Shri Jagao	Tilak
57.	21064	Smt. Kamla Bai	Jagao
58.	21065	Shri Dattu	Peera
59.	21066	Smt. Dhani Bai	Rai Singh
60.	21067	Shri Budhwar Singh	Mandhar
61.	21068	Shri Gareeba Ram	Mukund
62.	21069	Shri Amar Singh	Channu
63.	21070	Smt. Suraj Bai	Amar Singh
64.	21071	Smt. Keja Bai	Ram Singh
65.	21072	Smt. Milapa Bai	Sant Ram
66	21073	Shri Mandhir	Asha Ram
67.	21074	Smt. Deo Kumari	Mandhir
68.	21075	Smt. Sundar Bai	Pardeshi
69.	21076	Smt. Dasree Bai	Dneeraj
70.	21077	Shri Kashinath	Pandurang
71.	21078	Shri Dhanesh	Keshav
72.	21079	Smt. Hemin Bai	Mahesh
73.	21080	Shri Bisahu Ram	Peethamber
74.	21081	Shri Poshaiya	Ramaiya
75.	21082	Smt. Champa Bai	Poshaiya
76.	21083	Shri Sukhi Ram	Mehtar Ram
77.	21084	Shri Radheshyam	Karthik Ram
78.	21085	Shri Rama	Bali
79.	21086	Smt. Surja Bai	Rama
80.	21087	Shri Bhagwan	Gayanoba
81.	21088	Smt. Jijiya Bai	Bhagwan
82.	21089	Shri Dukhu Ram	Genj Dev
83.	21090	Smt. Sonbatiya Bai	Dukhu Ram
84.	21091	Shri Adinarayan	Malanna
85.	21092	Shri M. Prakash Rao	Sayanna
86.	21093	Shri Subu Ram	Mangalu
87.	21094	Shri Kamal	Bhagwani
88.	21095	Shri Sant Ram	Manbodhi
89.	21096	Shri Udai Ram	Manbodhi
90.	21097	Shri Pardeshi	Bishal
91.	21041	Shri PK Rao	Kasanna
92.	22242	Shri Puranik	Anand
93.	22631	Shr. Sukumar	Radhanath
94.	22633	Smt. Hira[illegible] Bai	[illegible] Ram
95.	22635	Smt. Sukhbati Bai	Mitru Das
96.	22239	Shri JVRB Sastri	JVS Sastri
97.	22238	Shsi B.G. Naidu	BA Suraiya
98.	22241	Shri D. Mohan Rao	Ramachandra

Annexure-II

(Ref: Clause 1(a)(i) of the Settlement)

Name of 27 female (couple) members.

Sl. No.	TokenNo.	Name of female labour	Name of husband
1.	21006	Smt. Shanti Bai	S/Shri Dhanesh
2.	21014	Smt. Dhan Bai	Bisahu Ram
3.	21016	Smt. Ramotin Bai	Bhagat Ram
4.	21018	Smt. Dirja Bai	Mahadev
5.	21021	Smt. Nirasha Bai	Sant Ram
6.	21023	Smt. Rohini Bai	Komal Singh
7.	21026	Smt. Debati Bai	Gawal
8.	21028	Smt. Bishahin Bai	Balaram
9.	21033	Smt. Sona Bai	Mangal Mali
10.	21040	Smt. Ram Bai	Mallaiya
11.	21044	Smt. Kausalya Bai	Pannu Ram
12.	21047	Smt. Sukhiya Bai	Asha Ram
13.	21050	Smt. Sundar Bai	Kamal
14.	21054	Smt. Kunti Bai	Bhikari Ram
15.	21056	Smt. Kausalya Bai	Mani Ram
16.	21059	Smt. Biswa Bai	Ram Singh
17.	21062	Smt. Chaiti Bai	Puranik
18.	21064	Smt. Kamla Bai	Jagao
19.	21070	Smt. Suraj Bai	Amar Singh
20.	21072	Smt. Milapa Bai	Sant Ram
21.	21074	Smt. Deb Kumari	Manteen
22.	21075	Smt. Sundar Bai	Pardeshi
23.	21082	Smt. Champa Bai	Poshaiya
24.	21086	Smt. Surja Bai	Rama
25.	21088	Smt. Jijiya Bai	Bhagwan
26.	21090	Smt. Sonbatiya Bai	Dukhu Ram
27.	21036	Smt. Bikantin Bai	Arjun.

Annexure-III

(Ref: Clause 1(a)(ii) of the Settlement)

Name of 27 Male Labourers.

S. No.	Token No.	Name of labour	Father s name
1	2	3	4
		S/Shri	S/Shri
1.	21078	Dhanesh	Keshav
2.	21013	Bisahu Ram	Chaitu Ram
3.	21015	Bhagat Ram	Keju Ram
4.	21017	Mahadev	Pardeshi
5.	21020	Sant Ram	Firangi
6.	21048	Komal Singh	Ramjee
7.	21025	Gawal	Barma
8.	21027	Balaram	Bisru
9.	21032	Mangal Mali	Channu
10.	21035	Arjun	Jetu Ram
11.	21039	Mallaiya	Narsingh
12.	21043	Pannu Ram	Motilal
13.	21046	Asha Ram	Anandram
14.	21094	Kamal	Bhagwani
15.	21053	Bhikari Ram	Rameshwar
16.	21055	Mani Ram	Ramjee

17.	21058	Ram Singh	Durjan
18.	22243	Puranik	Anand
19.	21063	Jagao	Tilak
20.	21069	Amar Singh	Channu
21.	21095	Sant Ram	Manbodhi
22.	21073	Manteen	Asha Ram
23.	21097	Pardeshi	Bishal
24.	21081	Poshaiya	Ramaiya
25.	21085	Rama	Bali
26.	21087	Bhagwan	Gayanoba
27.	21089	Dukhu Ram	Gong Dev.

Annexure-IV

(Ref: Clause 1(b) of the Settlement)

Name of 10 Female labourers.

S. No.	Token No.	Name of labour	Father's/Husband's Name
1	2	3	4
			S/Shri
1.	21002	Smt. Sumitra Bai	Nirbai Ram
2.	21003	Smt. Phagni Bai	Dev Singh
3.	21019	Smt. Shanti Bai	Agat Ram
4.	21031	Smt. Khorbaharin Bai	Tatu Tam
5.	21066	Smt. Thani Bai	Rai Sihgh
6.	21071	Smt. Keja Bai	Ram Singh
7.	21076	Smt. Deshari Bai	Dheeraj
8.	21079	Smt. Hemin Bai	Mahesh
9.	22633	Smt. Hirondi Bai	Hobit Ram
10.	22635	Smt. Sukbati Bai	Mitru Das

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3559.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2811 तारीख 3 अगस्त, 1984 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम कल्याण संगठन, करमा बिहार के प्रशासकीय एवं लेखाधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और यह भी निदेश देती है कि उक्त अधिकारी तालिका के कालम 2 में निर्दिष्ट सरकारी परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्दर उक्त अधिनियम के द्वारा सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों को करेगा ।

तालिका

अधिकारी का नाम	सरकारी परिसर के वर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं ।
1	2
प्रशासकीय एवं लेखाधिकारी श्रम कल्याण संगठन, करमा, बिहार।	अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर, जो बिहार राज्य में हजारीबाग, गया, गिरीडीह और मुंगेर जिलों में स्थित हैं।

[सं. जैड-20025/28/87-डब्ल्यू. 1]

एस. एस. भल्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 1987

S.O. 3559.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the public premises (Eviction of unauhorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2811 dated the 3rd August, 1984 the Central Government hereby appoints the Administrative-cum-Accounts Officer, Labour Welfare Organisation, Karma, Bihar, being a gazetted Officer of Government to be estate officer for the purpose of the said Act and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act within the limits of his respectve jurisdiction in respect of the public premises specified in column 2 of the Table :

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Administrative-cum-Accounts Officer, Labour Welfare Organisation, Karma, Bihar.	Premises under the administratve control of the Mica Mines Labour Welfare Organisation situated in the Districts of Hazaribagh, Gaya, Giridih, and Monghyr in the State of Bihar.

[File No. Z-20025/28/87-WII]

S. S. BHALLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3560.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1652 दिनांक 15 जून, 1987 द्वारा सीमेन्ट उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 जून, 1987 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 दिसम्बर, 1987 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फाइल संख्या एस-11017/13/85-डी-1(ए)]

नन्द लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 1987

S.O. 3560.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1652 dated the 15th June, 1987 the Cement Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 19th June, 1987;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility servtce for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 19th December, 1987.

[No. S-11017/13/85-D.I(A)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1987

शुद्धि-पत्र

का. आ. 3561.—श्रम मंत्रालय की दिनांक 27-10-87 की अधिसूचना सं. एल-12012/35/76-डी-II(ए) (खंड) में संलग्न पंचाट के पैरा 25 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाए:

"25. इसके परिणामस्वरूप यहां यह पंचाट इस प्रकार पास किया जाता है कि दूसरी पार्टी बैंक के लिपिक श्री के. चन्द्रहास को 6-11-75 से पदच्युत करने में बैंक की कार्रवाई को न्यायोचित न होना नहीं कहा जा सकता और कि वह किसी अनुतोष का हकदार नहीं है ?"

[संख्या-एल-12012/85/76-डी-II(ए) खंड]

एन. के. वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th December, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 3561.—Para 25 of the award annexed to the Ministry of Labour Notification No. L-12012|85|76-D.II(A)(Pt) dated 27-10-87, may be substituted by the following part :—

"25. In the result, an award is hereby passed to the effect that the management cannot be said be not justified in dismissing Shri K. Chandrahara, a clerk of the second party Bank with effect from 6-11-1975 and that he is not entitled to any relief".

[No. L-12012|85|76-D.II.A]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1987

का. आ. 3562.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th December, 1987

S.O. 3562.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-12-87.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No.2) AT DHANBAD.

Reference No. 167 of 1986

In the matter of industrial dtspute under Ssection 10(1) (d) of the I. D. Act., 1947.

Parties :

Employers in relation to the management of Ctate Bank of India, Patna and their workmen.

Appearances :

On behalf of the workmen : Shri K. K. Samajdar, Regional Secretary, SBISA, Patna.

On behalf of the employers : Shri B. N. P. Verma, Authorised Respresentative.

STATE : BIHAR :

INDUSTRY : Banking.

Dated, Dhanbad the 20th November, 1987

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to their Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012|174|83-D.II(A) dated, the 21st April, 1986.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Patna Main Branch in terminating the services of Shri Rajender Kumar Arya, Ex-Cashier with effcet form 7th April, 1968 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman R. K. Arya was appointed as temporary cashier in the State Bank of India, Patna Main branch on 16-7-67 and he worked as such till 6th April, 1968. He had thus worked for 260 days continuously within a period of one year. According to the Bank's Circular No. 105 dated 4th September, 1982 was decided to include Sundays and paid festival holidays also while counting 240 days of service in a continuous period of 12 calendar months or less. The concerned workman although was appointed as a temporary cashier was fully protected under Section 25(b) of the I.D. Act as he was in service for 266 days within 12 calendar months and salary and allowances were paid for those days including Sundays and holidays. The services of the concerned workman were terminated without any rhyme or reason or any fault on his part. As he had worked for more than 240 days within 12 calendar months and fulfilled the criteria of continuous service as mentioned in Section 25(b) of he I.D. Act, his termination of service from the Bank without adopting the procedure as laid down under Section 25F of the I.D. Act was bad in law. The management had not given any notice to the concerned workman before terminating his services. He was not paid any notice pay nor retrenchment compensation @ 15 days salary for each completed year. There was no agreement for the termination of services. The management of the Bank did not give any intimation in the prescribed proforma to this effect to the Govt. authorities as provided in the industrial disputes act. Thus there was no legal termination of service by the concerned workman and the relation of employer and employee continued between the management and the concerned workman. As the termination of the concerned workman was illegal and bad in law he is entitled to reinstatement with retrospective effect along with full back wages. The Bank has appointed thousands of new persons as cashiers after termination of services of the concerned workman but no opportunity was given to him to which he was entitled under Section 25C and 25H of the I.D. Act. The State Bank of India Staff Association had raised the dispute before the ALC(C) Patna and the conciliation failed on 26-11-82. On the receipt of the failure report, Govt. of India, referred the present dispute for adjudication to this Tribunal.

The case of the management is that the reference is without jurisdiction and is not maintainable under the law. Initially the Labour Ministry found that the action of the management was not unjustified and was not in violation of Section 25(b) read with Section 25F of the I.D. Act and as such the dispute was not referred for adjudication and the Bank was accordingly informed by the Labour Ministry vide letter dt. 11-8-83. The State Bank of India Staff Association had never raised the industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad but had raised the dispute before the ALC(C) Patna. The case of the management further is that the concerned workman had not completed 240 days service if Sundays and holidays are excluded from the attendance of 266 days being claimed by the union. As the concerned workman had not completed 240 days service in a year at the time of termination when his terms of appointment expired, he was not found eligible for benefits provided under Section 25F of the I.D. Act having put in an aggregate of 210 days of service. According to the management the law as then stood and was understood, the termination was in order to exclude Sundays and holidays for computing days actually worked for the purpose of Section 25B(2) of the I.D. Act. Bank's circular No. 105 dt. 4-9-82 was issued by Hyderabad Local Head office and the said instructions contained therein was based in incorrect interpretation of the Bank's Central Office instruction and as soon as the discrepancy came to the notice of the Bank's Central Office the matter was clarified subsequently and the correct position in the matter was isued in Circular No. 43 of 183. Thus the concerned workman could not have been considered for having completed 240 days in a period of 12 calendar months to attract the provision of Section 25(b) as it was understood then and as such Section 25F was not at all applicable.

The case of the concerned workman is also bad on the ground if staleness. The terms of service of the concerned workman expired on 6-4-1968 and no dispute of any nature was raised by the concerned workman or his union soon

after or within a reasonable period of time under the provision of law. They kept silent for a long period of 14 years after the termination of the services of the concerned workman. Now the present belated dispute has been raised when the concerned workman has become otherwise disqualified for banks services. The concerned workman or his union had not taken any step in respect of the termination of the services of the concerned workman prior the decision of the Supreme Court made in No. Sudamini's case. The claim of the union malafide and unjustified. The said judgement of the Supreme Court did not given any benefit to the concerned workman as it has not been made effective retrospectively. The concerned workman after expiry of his service terms was at liberty to seek absorption in the Bank's services by sitting in a number of recruitment tests held after the termination of the services. The concerned workmen and not avail of the said opportunity and now he cannot get an adjudication of the disputes before the industrial Tribunal at this stage after lapses of more than 17 years. On the above facts it has been submitted on behalf of the management that the concerned workman is not entitled to any benefit.

The point for determination in this reference is whether the termination of the services of the concerned workman with effect from 7-4-68 was justified.

The concerned workman examined one witness namely the concerned workman Shri R. K. Arya. The management did not examine any witness. However, both the parties exhibited documents. The documents filed on behalf of the management were marked as Ext. M-1 to M-3. The documents of the workmen are marked Ext. W-1 to W-7.

The facts of the case are almost admitted. The concerned workman Shri R. K. Arya had admittedly worked in the State Bank of India from 16-7-67 to 6-4-68 as Cashier in Patna Main Branch. The concerned workman WW-1 Shri R. K. Arya has stated in his evidence that he was employed by the State Bank of India on 16-7-67 and worked till 6-4-68 as Cashier in the Patna Main Branch. Ext. W-2 to W-2/7 are the memorandum issued by the Agent of the State Bank of India Patna to the concerned workman showing that the termination of his temporary appointment was being continued for a limited period, in some cases for one month and in some cases for even a period shorter than a month. The date when the term of temporary appointment was to end was also stated in those memorandums. It is clear therefore from Ext. W-2 series that the appointment of the concerned workman was being made for a definite period and that there was mention of the fact as to when the services was to end. However, it appears that the concerned workman had received the memorandum to continue in the temporary service at about the time of the termination of the term of his temporary appointment. Ext. W-1 dt. 5-8-68 is a certificate issued by the then Agent of SBI Patna which shows that the concerned workmen Shri R. K. Arya was a temporary Cashier in the Cash department from 16-7-67 to 6th April, 1968. Ext. W-1 is a photo copy and a portion of it cannot clearly be read as the original perhaps was torn and mutilated. However, Ext. W-1 shows that the concerned workman had worked as a temporary cashier in the cash department from 16-7-67 to 6-4-68 which of course is an admitted case. The period from 16-7-67 to 6-4-68 will come to 268 days. The case of the management is that the concerned workman had actually an attendance of 210 days only and he had notactually completed 240 days of service in 12 preceding months as during those period Sundays and Holidays were not taken into consideration in computing the days for the purpose of Section 26(b) of the I. D. Act. The case of the workman on the other hand, is that Sundays and paid holidays were to be included in computing the period of attendance for the purpose of Section 26(b) of the I.D. Act. Under Section 25(b) of the I.D. Act the Sundays and paid holidays are counted for computing the period of 240 days in a year. The management has not adduced any evidence to show that the attendance of 265 days calculated by the workmen included any unpaid holidays. The concerned workman WW-1 has stated that he got salaries and allowances from the Bank for 266 days and this fact asserted by the concerned workman has not been shown to be false in his cross-examination. I hold therefore that the concerned workman had completed 266 days of attendance in one calendar year prior to the termination of services.

Section 25F of the I.D. Act provides that no workman employed in any industry who has been in continuous services for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until the three conditions laid down thereunder is complied. It will appear from Ext. W-2 series that the services of the concerned workman was being extended from time to time for a limited period in which the date of the expiry of the said term was also stated. Admittedly the concerned workman had not been given one months notice in writing indicating the reasons for his retrenchment nor the concerned workmun had been paid in lieu of such notice wages for the period of notice. He was also admittedly not paid any retrenchment compensation equivalent of 15 days average pay for every completed year of continuous service. The two clauses of Section (a) and (b) of Section 25F are imperative and concerns the workmen and it has to be complied with before the services of a workman is retrenched. The case of the concerned workman is covered by the definition of retrenchment in Section (oo) of the I.D. Act as his services were terminated by the management for the reasons other than the exceptions provided under Section 2(oo) of the I.D. Act. The termination of the services of the concerned workman was not unflicted as a punishment by way of disciplinary action, it was not a voluntary retirement by the concerned workman, it was not a case of superannuation and it was also not a termination on the ground of continued ill health. It has been held in the case of State Bank of India Vrs. N. Sundermony (1966-LIC-769) that "termination for any reason whatsoever in Section 2(oo) are the key words. Whatever the reason, every termination spells retrenchment ..... A termination takes place where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated terms. Termination embraces not merely an act of termination by the employer, but the fact of termination howsoever produced. That to write into the order of appointment the date of termination confers no moksh from Section 25F(b) is inferable from the proviso to Section 25F(A)". The said decision completely covers the case of the workmen to show that writing the date of termination in the appointment order of the workmen cannot take out the case of the concerned workman from the arena of retrenchment. I hold, therefore, that the termination of the concerned workman from service would be covered under the definition of retrenchment and it has to be held that the concerned workman had been retrenched without complying with the provisions of Section 25F of the I. D. Act.

The management has next concentrated his case on the point that the dispute raised by the workmen is very stale. Admittedly the services of the concerned workman was terminated on 6-4-68 and no dispute appears to have been raised either by the concerned workman or his union prior to 1982 when for the first time the union SBI Staff Association had raised the dispute before the ALC(C) Patna. Ext. M-2 dt. 11-8-83 is a letter from the Desk Officer of the Ministry of Labour and Rehabilitation of the Government of India addressed to the General Secretary, State Bank of India Staff Association, Patna. The Government of India had refused to refer the dispute raised by the union in respect of the concerned workman for adjudication on the ground that the concerned workman had not completed 240 days of attendance in a calendar year. Prior to the raising of the dispute in which the said order was made by the Government of India, it appears that the union or the concerned workman had not raised the dispute. WW-1 is the concerned workman who had not in his examination-in-chief stated that he had ever raised the dispute either before the management or before the Conciliation Authority. WW-1 has stated in his cross-examination that he was not a member of the union when he was in service and he did not become member of the union after the termination of his service. Towards the close of his cross-examination he has stated that he had never given in writing to the union about his illegal termination of service and to take up the matter with the authorities. He has further stated that he had not given any registered letter to the Bank and that he had not personally delivered any letter to the Bank. He has further stated that he had sent letters under Certificate of posting. But strangely enough he has not filed any of the office copies of the letters which he had sent under certificate of posting to the management. Ext. W-7 series are the photo copies of certificate of posting showing that something was sent to the Agent, SBI, Patna Main Branch under Postal certificate. But

it does not show as to who had sent those letters. It also cannot show the matter which was sent under certificate of posting. It has been submitted on behalf of the management that the stamps on some of the certificate of posting in Ext. W-7 are of a period subsequent to the date of the postal stamp given on the certificates. However, the said matter has not been examined as it was not felt necessary in the absence of the actual letters which are stated to have been given, as stated by the workmen, to the management of the SBI, Patna Main Branch. In my opinion the said certificate of postings cannot show that the concerned workman had sent any letter to the management in respect of his termination of service. The postal receipts therefore have to be completely discarded. I hold therefore that the concerned workman had not represented his case before the management prior to 1982. It is clear therefore that the concerned workman had kekpt quite for a long period of about 14 years. The union has not tried to explain as to why such an inordinate delay was made in presenting the case of the concerned workman. In this connection I would like to refer the case of Inder Singh and sons-vers-the ir workmen reported in SCIJ-I page-104 and Shalimar Works Vrs. Their workmen reported in SCLJ-4 page-2228. It was held in the case of Inder Singh referred to above that "on the question whether retrospective effect can be given to an Award in the Industrial adjudication, no doubt laws of limitation which might bar any Civil Court from giving remedy in respect of lawful right should not be applied by Industrial Tribunal but over state claims should not generally be encouraged or allowed unless there is satisfactory explanation for the delay. It was further held that both the risk to industrial peace from the entertainment of claims after long lapses of time and the unsettling effect which is likely to have on the employers financial arrangement should be taken into account. Where a claim has become too stale or not will denend on the facts of each case". It was held in the case of Shalimar Works Limited referred to above that " it is true that there is no limitation prescribed for reference or dispute to an industial tribunal, even so it is only reasonable that dispute should be referred as soon as possible after they have arised". In the present case, as I have already stated above, no dispute had been raised since 1968 to 1982 and the gap of 14 years remains unexplained. It is clear therefore that the present dispute in respect of the concerned workman has been raised after a great delay and it is an over stale claim in which this Tribunal feels unable to give relief so as to cause unsettling effect in the employees of the management more so when the said long delay has not at all been explained. There appears to be some force in the submission of the management that the concerned workman has raised the dispute after so many years when the effect of Sundarmoni's case was somehow brought to his knowledge and that in fact he had never raised any dispute regarding his termination after his services were terminated on completion of the term of his services.

In the result, I hold that although the State Bank of India, Patna Main Branch was not justified in terminating the services of the concerned workman with effect from 7-4-68, the concerned workman is entitled to no relief as the dispute raised by him is overstale and such overstale claim cannot be encouraged so as to open the flood gate encouraging further litigation by the employees whose services might have been terminated long long ago. In the above view of the matter no relief is being granted to the concerned workman.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-12012/174/83-D.II(A)]

का.आ. 3563.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजन और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-11-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3563.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner & Jaipur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th Nov., 1987.

BEFORE SHRI M. K. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 53|86

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.

AND

Their workmen : Surinder Kumar.

APPEARANCES :

For the workman : Shri B. N. Sehgal.

For the management : Shri P. Suryanarain.

INDUSTRY : Banking STATE : Punjab

AWARD

Dated 24-11-1987

Vide Central Govt. Gazette Notification No. L-12012|187|85-D.II(A) dated the 31st July, 1986 issued under Section 1(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 the following Industrial Disputes was referred to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur in terminating the services of Shri Sunder Kumar, Temporary Cashier|Clerk in heir Madhopuri Chowk, Ludhiana Branch w.e.f. 11-1-1984 while retaining his juniors in the service and not considering him for future employment when subsequently recruiting fresh hands is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. The case of the workman is that on 24-10-1983 he was appointed as cashier on a monthly pay of Rs 996|-. Than his services were terminated on 11-1-1984. That order of termination is void as no notice was served on the workman. That juniors to the workman have been retained in service. That other persons were also recruitted after his termination. That provisions of Section 2-G and H of I.D. Act have been violated. According to workman his termination is void and he is liable to be re-instated with back wages from 11-1-1984 onwards.

3. The Bank in their reply alleged that workman was appointed purely for a temporary period for a specific period as per the appointment letter. That his services came to an end on expiry of the period. That question of passing any termination order does not arise. That workman was never appointed against any permanent post. That workman has no worked for 240 days so he has no right to claim any notice prior to termination or any retrenchment compensation. That the case of the workman does not come within defination of retrenchment so he has no right to maintain the present reference. That provisions of Section 25-G and H do not apply to the case of the workman. That there is a Regional Recruitment Board for making appointment in the Bank on permanent. The recruitment Board staff cannot make any appointment. The recruitment Board is an independent authority and have their own procedure for selecting the candidates. That board allot to the Bank candidate as per Bank requirement and bank offer them appointment. That in order to meet administrative exegencies casual appointments are made at a branch so that interest of cusomer be protected. That any person appointed casually can not

claim benefits of Section 25-G and H of I.D. Act 1947. That persual of the Rule 76 of I. D. (Central Rule 1957 makes it clear that rule 77 regarding maintainance of seniority list and rule 78 regarding re-emplyment of retrenched workman are applicable only in cases of workman who have been referred to in Rule 76 i.e. those workman who completed one year of service.

4. Both the parties produce documents and affidavits in support of their respective allegations. MW1 P. K. Lahri admitted that no offer was given to workman separately for re-employment. That vacancies were displayed on notice board of all branches of the Bank. That three|four persons were employed in the Bank for period not exceeding 80 days To the same effect is the statement of Prem Raj Gupta MW2. The workman placed his affidavit in support of his case. He admitted his application and appointment letter to be correct. He also admitted that when he left service his juniors were there and he can not say whether they have been relieved or not.

5. Ex. M2 is the appointment letter dated 24-10-1983 of the workman. He was appointed on purely temporary basis for a period of 30 days w.e f. 24-10-1983. His services come to an end on 22-11-83. Vide letter dated 23-11-1983 the appointment of the workman was extended up to 22-12-1983 which was later on extended to 11-1-1984 vide letter dated 13-12-1983. On 11-1-1984 workman stood relieved from the job. The above documents genuineness of which have not been disputed, shows that workman remained in service of the Bank from 24-10-1983 to 11-1-1984 i.e. for the period of above 80 days. He has not completed 240 days services in the Bank. So question of workman being entitled to a notice prior to his being relieved from the job or retrenchment compensation does not arise.

6. Now the point to be determined is whether retrenchment is bad under Section 25-G of I. D. Act or not ? Section 25-G provides as under :

> "Procedure for retrenchment. Where any workman in an industrial establishment, who is a citizen of India is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment in that establishment in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workmen who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman."

7. Persual of the above shows that in case of retrenchment juniors is to be retrenched first. It also shows that the above provisions will apply if there is no agreement between employer and workman in this behalf. In the present case the above provisions will not apply because there is an agreement between the Bankk and the workman as contained in the appointment letter and further the extensions letter issued that services will come to an end on expiry of he period i.e. 11-1-1984. The position would have been different if appointment would have been on temporary basis without any period being specified therein. As in the present case the period of the employment of the workman is specified in the appointment letter and workman accepted it by signing on it so the proviso of Section 25-G of the Act as reproduced above will not apply. There can be no dispute with the law that Labour legislation being a social legislation length of service is not required in cases falling under Section 25-G of the I. D. Act 1947. There also can be no dispute that provisions contained in Section 25-F and 25-G I.D. Act are proposition of law that provisions of Section 25-G will apply independent of each other. There is also no dispute with proposision of law that provistons of Section 21-G will apply to the case of temporary workman also. But in the present case they do not apply as there is an agreement between the employer i.e. the Bank and the workman that services of the workman were to come to an end on 11-1-1984.

8. Now next point to be determined is whether termination this void due to violation of principal laid down in Section 25-H. The contention of the management is that as services of the workman came to an end on expiry of the period so it does not come within definition of retrenchment as given in Section 2(oo) (bb) which is as under:

> "termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under stipulation in that behalf contained therein."

9. The above definition was inserted by Act No. 49 of 1984 w.e.f. 18-8-1984. Though the case of the workman is covered under the above definition but point is whether the above definition is retrospective or not. Patna High Court in case Arun Kumar vs. Union of India 1986(1) Labour Law Notes 528 held that amendment is not retrospective. Same appears to be the view of Gujarat High Court in Case Gujrat State Machine Tools Corporation Vs. Deepak 1987 Labour I. C. 1361. No contrary view has been cited before me. So i will be held that the above definition is not retrospective. The case of the Bank is that though definition is not retrospective but it should be deemed to be there as in the object of amended Act it was specified that above amendment is only to clarify the view already existing. I do not agree with the same. If the definition of retrenchment did include the case covered by the amendment made, there was no occasion to make the amendment. As amendmen has been made so it will primafacie shows that it was not there prior to 18-8-1984. So case of the workman is not excluded from the terms of retrenchment.

10. The other point to be determined is whether provisions of Section 25-H of I. D. Act has been followed in the present case or not. Under the above section in case of re-employment of any other workkman notice is required to be given to the retrenched workman. The manner in which notice is to be given is there in Rule 78 which prescribed a notice by regd. post. It is admitted that in the present case Bank recruitted some clerks though for temporary period. It is also admitted thta no notice by Regd. post was given to the workman so there is a violation of the provisions of Section 25-H of I.D. Act. Now question is what is its effects. According to workman he is entitled to be re-instated. He draw support for the same from authority Nawashhr Central Co-operative Bank Vs. Labour Court (1980) 57 F. J. R. 206 of Punjab High Court. In the above case provisions of Section 25-H were not followed. Workman was ordered to be reinstated with back wages by the Industrial Tribunal. In writ his Lordships ordered his re-appointment from the date he reports for duty. In authority Gujarat State Machine & Tools Corporation Ltd. (Supra) workman was in service for period 12-10-1982 to 11-4-1983. His re-employment was ordered because provisions of Section 25-H was not followed. Normally I would have also allowed fresh appointment to the workman as done in the above two authority. But in the present case it can not be done. The allegations of the Bank are that as per policy of the Govt. candidates are to be recruitted in Banks service through the Recruitment Board which has its own procedure. The Banking Board is to select the candidate and recommend. Giving appointment to the workman will amount to bypassing the board which is not permissible. From facts of the case of both the authortty it is not evident whether there was any recruitment policy in those cases or not. The workman could not show how the provisions of the recruitment to service that the Board can be bypassed. Under Section 25-H of I.D. Act workman has only a right to considered for appointment. When appointment is to be made by the Board then workman has a right to be considered for appointment by the Board. So in the present case the only relief which workman can get is that he will be entitled to notice from the Bank for his re-employment and will be given re-employment if found fit by the recruitment Board. Other ise reference is answered against the workman.

Chandigarh.
Dt. : 24-11-1987.

M. K. BANSAL, Presiding Officer
[No. L-12012|87|85-D. II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3564.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1948 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार, ब मालकेरा कोलियरी मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-12-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th December, 1987

S.O. 3564.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Malkera Colliery of M|s Tata Iron & Steel Co. Limited, P.O. Jamadoba (Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th December, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Reference No. 118 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Malkera Colliery of M|s. TISCO. Ltd., and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri Nanka Kamar, the conerned workman himself.

On behalf of the employers : Shri P. Akhaury, Authorised representative.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 2nd Dec., 1987

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(41)| 85 dt. 5th August, 1985.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Malkera Colliery of M|s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P.O. Jamadoba, District Dhanbad, in dismissing the service of Sh. Nanka Kamar, Mechanical Fitter Helper is justified? If not, to whatrelief the workman is entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Nanka Kamar was employed as a Mechanical Fitter Helper since 27-4-43 in Malkera Colliery of M|s. Tisco Ltd. He had completed about 41 years of servtce. He had applied for the employment of his dependent son-in-law Shri Bihari Kamar. The management being satisfied that Bihari Kamar was the dependent son-in-law of the concerned workman enrolled Bihari Kumar for employment in future as Miner| Loader. The concerned workman produced documentary evidence in support of the fact that Bihari Kamar was his son-in-law. The concerned workman had already completed 15 years service without any blame and made a declaration dt. 8-6-79 that Shri Bihari Kamar is his son-in-law and got his name registered for future employment and produced a certificate from the Mukhiya of Garhar Gram Panchayat dt. 1-3-79 to the effect that Bihari Kamar was his son-in-law. In persuance of the Manager Malkera Colliery letter dt. 19|22-3-77 the concerned workman applied for the employment of Shri Bihari Kamar for his enlistment in the company's dependent reetster of employment and enclosed a certificate from the aforesaid Mukhiya as well which was registered in the colliery after the management was satisfied about the correctness of the declaration.

The management issued a false and vague chargesheet dt. 2|3-6-83 that the declaration given by the concerned workman with regard to Bihari Kamar was false. The management falsely charged the concerned workman on the ground of dishonesty in connection with the company's property and business with malafide intention to victimise the concerned workman. The concerned workman replied to the chargesheet on 20-6-83 denying the charge and stated therein that Shri Bihari Kamar is his son-in-law. The management ordered for an enquiry into the chargesheet. The management did not allow the concerned workma to know as to who had informed them that Shri Bihari Kamar was not the son-in-law of the concerned workman. The managemet never disclosed the source of such information to the concerned workma. The enquiry was conducted in gross violation of the principles of natural justice. During the enuqiry Shri C. K. Jha representative of the employer was examined before the enquiry officer. Shri C. K. Jha was biased and prejudiced against the concerned workman from the very beginning. Shri C. K. Jha had earlier recorded statemet of the concerned workman and Shri Bihari Kamar in English but the contents thereof was not explained over to the concerned workman or ShriBihari Kamar. The copy of the said statement as recorded by Shri C. K. Jha was not supplied in advance to the concerned workman and hence the concerned workman could not effectively cross-examine Shri C. K. Jha. The concerned workmkan clearly stated even during the said preliminary enquiry that Shri Bihari Kamar was his son-in-law but Shri C. K. Jha did not record with some ulterior motive to victimise the concerned workman. The enquiry officer fully relied upon the statement recorded during the preliminay enquiry submitted by Shri C. K. Jha but the enquiry officer did not consider the certificate issued by the Mukhiya which stated that Shri Bihari Kamar was son-in-law of Nanka Kamar. The enquiry Officer relied upon the deposttion of Bihari Kamar taken in the preliminary enquiry by Shri C. K. Jha but Shri Bihari Kamar was never cross examined as a witness during the departmental enquiry nor the concerned workman was given ay opportunity to cross-examine Shri Bihari Kamar. The finding of the enquiry officer are perverse not having been based on the evidence on record and the enquiry officer relied upon the statement take in the back of the concerned workman. The charge was not proved by legal evidence and the enquiry officer relied on the cross-examination of the concerned workman. The action of the maagement in dismissing the concerned workman is not iustified and as such he is entitled to reinstatement and full back wages and other benefits for the perod of his forced idleness.

The case of the management is that the concerned workman committed serions misconduct of fraud and dishonesty by making false declaration that Shri Bihari Kamar is his dependent son-in-law for securing his employment under the company's scheme of employment of dependents of employees. On the strength of fraudulent declaration of the concerned workman, he secured the employment of Bihari Kamar worked in the colliery for several years. Subsequently it was discovered that Shri Bihari Kamar was the Brother-in-law of the concerned workman and was not eligible for employment as dependent of the concerned workman. The concerned workman had no issue. A preliminary enquiry was conducted by Shri C. K. Jha, Group Personnel Officer and he recorded the statement of the concerned workman and Bihari Kamar. They confessed before Shri C. K. Jha that the concerned workman had no issue and Shri Bihari Kamar was the brother-in-law of the concerned workman. Thus the fact that the concerned workman made false declaration and got his brother-in-law employed as his son in law was admitted by the concerned workman and Shri Bihari Kamar. A chargesheet dated 2/3-6-84 was issued to the concerned workman for misconduct of fraud and dishonesty under clause 19(2) of the Certified Standing Orders applicable to the establishment. The concerned workman submitted his reply dated 20-6-83 denying the allegation levelled against him in the chargesheet Shri S. N. Pandey, Group. Personnel Officer of Jamadoba Group was appointed as Enquiry Officer to conduct the enquiry relating to the chargesheet issued to the concerned workman. The concerned workman appeared in the departmental enquiry and the enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice. Shri C. K. Jha appeared as a sole management's witness in the departmental enquiry He give his statement that the concerned workman and Shri Bihari Kamar confessed their guilt before him and proved the statement recorded by him at the preliminary enquiry. He

also proved the other document to establish the charges against the concerned workman. Shri C. K. Jha was cross-examined by the concerned workman. The concerned workman was given full opportunity to cross-examine the management's witness and to give his own statement and to produced his defence statement. The concerned workman gave his own statement but did not produce any defence witness. The enquiry officer considered the materials before him and gave his finding holding the concerned workman guilty of the misconduct alleged against him. The enquiry report dated 24-1-84, the enquiry proceeding and all other relevant papers were examined by the competent authorities and finally decision was taken by the competent authority to impose the punishment of discharge from the company's services by letter dated 16/18-5-86 of the Agent of the colliery who is empowered to impose any punishment including discharge and dismissal of a workman as per provision of the certified Standing Order. The misconduct of fraud and dishonesty was considered to be of a serious nature warranting imposition of punishment of dismissal to deter like minded workman from indulging in fraudulent and dishonest activities. It is submitted that the punishment imposed against the concerned workman was proportionate to the misconduct committed by him.

The concerned workman had been dismissed after holding a domestic enquiry into the charges framed against him and as such the management made a prayed for hearing of the preliminary issue whether the enquiry held against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principles of natural justice so that in case the enquiry is held to be not proper and in accordance with the principles of natural justice, the management may adduce evidence before this Tribunal to prove the charge levelled against the concerned workman. The workman also challenged the fairness and propriety of domestic enquiry. Accordingly it was decided that the preliminary issue be first heard. On 15-9-87 an order was passed on the preliminary issue whether the domestic enquiry held against the concerned workman was fair proper and in accordance with the principles of natural justice. It was held that the enquiry held against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principles of natural justice. The case thereafter was fixed for hearing on merit.

Now the point for decision is whether the dismissal of the concerned workman Nanka Kamar from service was justified. In other words it has to be seen whether the management has established the charge that the concerned workman had fraudulently represented before the management that Bihari Kamar was his dependent son-in-law and secured employment on the said false representation.

The management has produced the papers regarding the enquiry proceeding against the concerned workman and the have been marked as Ext. M-1 to M-10.

Ext. M-1 dated 2/3-6-83 is the chargesheet issued to the concerned workman under Clause 19(2) of the Standing Orders of the management. It was alleged that the concerned workman had declared Shri Bihari Kamar as his son-in-law and secured employment for him on the length of service of the concerned workman but subsequently it was detected that Shri Bihari Kamar was not the son-in-law of the concerned workman and that the concerned workman secured employment of Bihari Kamar by fraudulent means declaring him as his dependent. Ext. M-2 dated 20-6-83 is the reply of the concerned workman to the chargesheet in which the concerned workman has completely denied the charge and has reiterated that Shri Bihari Kamar was his son-in-law and that there was no fraud in making the said declaration. The management had produced the abstract of employees depending register before the enquiry officer and the same forms part of enquiry proceeding which shows that the concerned workman Nanka Kamar had got the name of Shri Bihari Kamar recorded in the employees dependent register as his son-in-law. The management also produced the true copy of the declaration of Nanka Kamar dated 8-6-79. The declaration show that Nanka Kamar got the name of his son-in-law Shri Bihari Kamar registered in the employees dependent register in the year 1979 and that in token of the correctness of the said declaration he was putting his LTI on it. There is another copy of letter written by the concerned workman to the Manager, Malkera Colliery by which he had enclosed certificate from the Mukhiya of his Gram Panchayat who had certified that Shri Bihari Kamar is his son-in-law and that he had no son. There is copy of the certificate of the Mukhiya of the Gorhar Gram Panchayat was also filed before the enquiry Officer. The certificate was dated 1-3-79 by Shri Mukhlal Mahato Mukhiya by which he had certified that Shri Bihari Kamar son of late Teju Kamar of Village Amar, District Giridi was son-in-law of Nanka Kamar of Village Godhar and that Shri Nanka Kamar has no son of his own. The fact that the concerned workman made a declaration that Bihari Kamar was his son-in-law and that it was recorded in the employees' dependent register of the management is admitted by the concerned workman. The case of the concerned workman is that Bihari Kamar is his son-in-law and that he got his employment by making such declaration before the management. Even in his reply to the chargesheet the concerned workman had asserted the fact that Bihari Kamar was his son-in-law and he got employment of Bihari Kamar on the strength of his service. The management's case is that the concerned workman had got the appointment of Bihari Kamar on the basis of the strength of service of the concerned workman and on his declaration that Bihari Kamar was his dependent son-in-law. It is thus clear that the concerned workman got employment of Bihari Kamar on the Strength of his services by making a declaration that Bihari Kamar was his dependent son-in-law.

The question which actually is in issue is whether Bihari Kamar is the son-in-law of the concerned workman. As already stated above the concerned workman is asserting that Bihari Kamar is his son-in-law and that he got his employment on his declaration that Bihari Kamar was his dependent son-in-law. The management has examined the only witness Shri C. K. Jha before the Enquiry Officer. It will appear that Shri C. K. Jha had no personal knowledge of the fact whether Bihari Kamar was the son-in-law of the concerned workman or not. C. K. Jha has stated that he came to know that one Shri Bihari Kamar was employed in the company at Malkera Colliery as the son-in-law of the concerned workman Nanka Kamar and that it was subsequently noticed that Shri Bihari Kamar was not the son-in-law of the concerned workman but was the brother-in-law of Nanka Kamar. He had made a preliminary enquiry on 4-5-83 and in that connection he had recorded the statement of S/Shri Nanka Kamar and Bihari Kamar wherein they had stated that Nanka Kamar had no issue and since he did not have any issue he got Bihari Kamar employed as his son-in-law as a Miner in the year 1979 at Malkera Colliery and that they also accepted that Bihari Kamar was the brother-in-law of Nanka Kamar. The said statement was signed by Nanka Kamar and Bihari Kamar. The management has relied on the said statement of Nanka Kamar and Bihari Kamar recorded by Shri C. K. Jha. The copy of the said statement form part of the enquiry proceeding. It will appear from the statement of Nanka Kamar recorded by Shri C. K. Jha that Nanka Kamar had stated that he had no issue and since he has no issue he got Shri Bihari Kamar employed as miner and on his strength of service as son-in-law in the year 1979. He also stated that Shri Bihari Kamar is his brother-in-law. The said statement was recorded in English, and it was signed by Nanka Kamar. The copy of the statement of Bihari Kamar recorded by Shri C. K. Jha also forms part of the enquiry proceeding wherein Bihari Kamar stated that he was appointed as temporary miner since 1979 on the service strength of Nanka Kamar. Biahri Kamar also stated in the said statement that Shri Nanka Kamar had no issue and he was the brother-in-law of Nanka Kamar and since Nanka Kamar had neither son nor daughter he got him employed on his strength of service declaring him as his son-in-law. Nanka Kamar had given his statement before the enquiry officer in the enquiry proceeding on 17-1-84 in which he had stated that Shri Bihari Kamar is his son-in-law and that he got him employed in Malkera Colliery as temporary miner on the strength of his service. He was cross-examined at length on behalf of the management wherein it is stated that his statement and the statement of Bihari Kamar were recorded on 4-5-83 at Malkera P.O.'s Office by Shri C. K. Jha but he stated that Shri Bihari Kamar is his son-in-law and he denied that he had stated before Shri C. K. Jha that Shri Bihari Kamar was not his son-in-law. The concerned workman also admitted in his

statement before the enquiry officer that he and Bihari Kamar put their signature on the statement recorded by Shri C. K. Jha but he has stated that the statement recorded by Shri C. K. Jha was not explained to him Shri Bihari Kamar. Thus the concerned workman admits that Shri C. K. Jha had earlier taken his statement but he has denied that the contents of the statement recorded by Shri C. K. Jha were explained to him. Thus according to the evidence of the concerned workman it appears that the statement recorded by Shri C. K. Jha are not admitted by the concerned workman Bihari Kamar has not been examined in his case to show what he had stated in the statement recorded by Shri C. K. Jha. There is also no evidence to the effect that Bihari Kamar had given his statement before Shri C. K. Jha in presence of the concerned workman. Admittedly, the concerned workman has not been given any chance to cross-examine Shri Bihari Kamar to test the correctness of the statement made before Shri C. K. Jha. The statement were admittedly taken down by Shri C. K. Jha in English and there is no evidence that the concerned workman knew English. Shri C. K. Jha has stated that the statements were explained to the concerned workman whereas the concerned workman has stated that the contents of the statements recorded by Shri C. K. Jha were not explained to him. Thus there is no evidence against the concerned workman except the retracted so called confessional statement of the concerned workman. The said statement of the concerned workman is not corroborated by any oral or documentary evidence.

Admittedly, the concerned workman had got the employment of Bihari Kamar on the strength of his service declaring him as his son-in-law. The concerned workman has also asserted that Bihari Kamar was his son-in-law in his reply to the chargesheet. In his statement before the Enquiry Officer the concerned workman stated that Bihari Kamar is his son-in-law. The management has also produced the certificate of the Mukhiya Hemlal Mahato in which Mukhiya certified that Bihari Kamar is the son-in-law of Nanka Kamar. Thus in the past before the chargesheet and even after the chargesheet the concerned workman has been asserting that Bihari Kamar was his son-in-law. He was also supported by the certificate of the Mukhiya which was relied upon by the management to record the name of Bihari Kamar as son-in-law of Nanka Kamar for giving employment on the strength of service of Nanka Kamar. The only fact which stands against the concerned workman is the so called statement recorded by Shri C. K. Jha which is not being admitted by the concerned workman. I have stated above that Shri C. K. Jha has no personal knowledge about the relationship between the concerned workman and Bihari Kamar. The management has produced no evidence to the effect as to how it came to their notice that the concerned workman was not the father-in-law of Bihari Kamar. I think there could have been some evidence to the effect as to how the management came to know that Bihari Kamar was not the son-in-law of the concerned workman. In the absence of all these facts and circumstances and in the absence of any independent witness I hold that the management has not been able to establish that Bihari Kamar was not the son-in-law of the concerned workman. The evidence produced is not legal evidence to establish the charge against the concerned workman. In view of the discussions made above I hold that the management has not been able to establish the charges against the concerned workman so as to dismiss him from service.

In the result, I hold that the action of the management of Malkera Colliery of M/s. Tisco, in dismissing the service of Shri Nanka Kamar, the concerned workman is not justified. The management is therefore directed to reinstate the concerned workman in service from the date of his dismissal with all back wages and other consequential benefits, within one month from the date of publication of this Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012/41/85-D.IV (B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1987

का०आ० 3565—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-11-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th December, 1987

S.O. 3565.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 63 of 1986

In the matter of industrial dispute under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri K. K. Samajdar, Regional Secretary SBISA.

On behalf of the employers.—Shri B. N. P. Verma, Authorised Representative.

STATE : Bihar INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 23rd November, 1987

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/105/85-D II (A), dated the 17th January, 1986

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Patna in terminating the services of Shri P. C. Jain, Temporary Cashier, State Bank of India, Main Branch, Patna with effect from 29-5-68 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

The case of the workman is that Shri P. C. Jain was appointed as a temporary Cashier in State Bank of India, Patna Main Branch and worked continuously from 4-9-67 to 28-5-68, the total number of working days being 268 days. According to the Bank's circular No. 105 dated 4-9-82 Sundays and said holidays are to be counted in computing the number of days worked by a workman. The concerned workman had been paid wages for all the 268 days worked by him in the Bank within a period of one calendar year. The concerned workman although as appointed as temporary cashier, he was fully protected under Section 25(b) of the I. D. Act as he was in the service of the Bank for 268 days in a calendar year and salary and allowances were paid to him for those days including Sundays and holidays. The concerned workman's services were terminated without any reason. As he had worked for more than 240 days within 12 calendar months and fulfilled the criteria of continuous service as mentioned in Section 25(B) of the I. D. Act, his termination of service from the Bank without adopting the procedure of Section 25-F of the I. D. Act was bad in law. The concerned workman had not been given any notice for the termination of his services. He was not paid for the notice period nor he was paid any retrenchment compensation @ 15 days salary for each completed year. There was also no agreement for the termination of his services. The management did not give any intimation in the prescribed proforma to the Government authorities as

provided under Section 25-F of the I. D. Act. Thus there was no legal termination of the services of the concerned workman and the relationship of employer and employee continued between the management of the concerned workman. It is submitted that as the termination of the services of the concerned workman was illegal and unjust, he is entitled to reinstatement in service with retrospective effect along with full back wages. The Bank has appointed thousands of new persons as cashiers after the termination of his services but the concerned workman was given no opportunity thereby attracting the provisions of Section 25(G) and 25(H) of the I. D. Act. The State Bank of India Staff Association had raised the dispute in respect of the concerned workman before the ALC(C) Patna sometime in February, 1985 and the conciliation before him failed and the ALC(C) sent failure report to the Central Government vide letter dated 28-4-85 and thereafter the present reference was made.

The case of the management is that the reference is not maintainable. The concerned workman was engaged purely on temporary basis as cashier at Patna Main Branch of SBI on 4-9-67, clearly spelling out that his appointment would be deemed to have come to an end at the expiry of the aforesaid period unless in the meantime it is extended at the discretion of the Bank for further period. Accordingly the concerned workman was issued appointment letters each time for specific period clearly mentioning therein that the temporary appointment would be deemed to have come to an end at the expiry of the aforesaid period unless it is extended at the discretion of the Bank for further period. The concerned workman on the basis of the aforesaid several appointment letters worked on purely temporary basis as a temporary cashier against temporary vacancies for the specified period. His last appointment letter was for the period from 1-5-68 to 28-5-68. His services in the absence of any further grant of extension after 28-5-68 resulted into automatic termination and he ceased to be an employee since then. The concerned workman did not raise any industrial dispute for a long period of 15 years and as such his claim is over stale and not maintainable. The concerned workman had actually worked for 210 days only and not 268 days as alleged by him. Within the period between 4-9-67 to 28-5-68 there were only 212 working days excluding Sundays and Holidays and out of that the concerned workman had remained absent for two days. The concerned workman therefore did not complete 240 days in a calendar year preceding the date when his term of temporary appointment for specific period came to an end on 28-5-68. He was therefore not entitled to get the benefits of the provisions of Section 25-F of the I. D. Act. The concerned workman after the termination of his services did not either verbally or in writing made any representation to the Branch Manager or any other authority of the Bank for his reinstatement. The Bank is a statutory body which is required to observe the statutory conditions regarding its rule for permanent appointment in the Bank. The policy of the Bank was within the knowledge of the concerned workman and he knew that the posts in the Bank are filled in after advertisement and inviting notice of the employment exchange. The candidates are required to qualify in the written test followed by an interview and the candidate who qualified in the aforesaid test were given appointment in order of merit depending upon the number of vacancies. The concerned workman did not apply for appointment in the Bank's services whenever applications were invited by the Bank and he did not appear in any such examination for recruitment in the Bank's services after the termination of his services. The claim of the concerned workman therefore for reinstatement is not justified.

The point for consideration in this reference is whether the termination of the services of the concerned workman with effect from 29-5-68 is justified.

The workman examined Shri P. C. Jain himself before this Tribunal as WW-1 and the management did not examine any witness. However, both the parties produced document. The documents of the management have been marked Ext. M-1 to M-7 and the documents of the workmen have been marked as Ext. W-1 to W-10.

From the pleadings of the parties it will appear that some of the facts are admitted. It is admitted that the concerned workman had worked in Patna main branch of SBI as temporary cashier from 4-9-67 to 28-5-68. The concerned workman WW-1 has also stated that he was working in Patna Main Branch as Cashier from 4-9-67 to 28-5-68. Ext. W-3 to W-3/10 are appointment letters given to the concerned workman from 4-9-67 to 28-5-68. It will appear from this appointment letters that the concerned workman was appointed temporarily vide these appointment letters mostly for a period of one month in which the date of the termination of his services is also mentioned and the period was extended from time to time at the time the period of the term was being ended. The management also in his W.S. has admitted that the concerned workman had worked from 4-9-67 to 28-5-68. Thus there is no controversy regarding the period when the concerned workman had worked in the Bank. The case of the management further is that within the said period between 4-9-67 to 28-5-68 the concerned workman had worked only for 210 days and that he had not worked for 268 days in the 12 preceding months as during those period Sundays and holidays were not to be taken into consideration in computing the working days for the purpose of Section 25(b) of the I. D. Act. On the other hand the case of the workmen is that Sundays and paid holidays were to be included in computing the period of attendance for the purpose of Section 25(b) of the I. D. Act. It is now well settled that under Section 25(b) of the I. D. Act Sundays and paid holidays are counted for computing the period of 240 days attendance in a calendar year. The concerned workman WW-1 has stated in his evidence that he had received salary and allowance for 268 days when he had worked in the Bank. The management has not adduced any evidence to show that the concerned workman had not been paid wages of 268 days prior to his termination. The evidence of the concerned workman therefore has to be accepted that he had completed attendance of 268 days in one calendar year prior to the termination of his services.

Section 25-F of the I. D. Act provides that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched untill the three conditions laid under the said provision are complied with by the management. It will appear from the appointment letters Ext. W-3 series that the services of the concerned workman were being extended from time for a limited period and that the said appointment letter itself embodied the date of expiry of the said term of appointment. There is no case of the management that the provision of Section 25-F of the I. D. Act were complied with prior to the termination of the services of the concerned workman. Admittedly the concerned workman had not been given one months notice indicating the reasons for its retrenchment nor he had been paid wages for the period of notice in lieu of it. He was also not paid any retrenchment compensation. It is mandatory on the part of the management to comply with the provision of Clause (a) and (b) of Section 25-F before a workman is terminated. It will appear that the definition of retrenchment in Section 2(oo) of the I. D. Act is applicable in the case of the concerned workman as his services were terminated by the management for the reasons other than the exceptions provided under Section 2(oo) of the I. D. Act. The termination of the services of the concerned workman on the ground that his services were terminated automatically on completion of the term provided in the appointment letter cannot prevail in view of the decision of the different courts on that issue. The most important decision on the point is the decision reported in 1966 LIC Page-769 (SBI-Vrs.-N. Sundermoni) where it has been held that "termination for any reason whatsoever in Section 2(oo) are the key words whatsoever the reason every termination spell retrenchment ..... A termination takes place where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. The termination embraces not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination howsoever produced. That to write into the order of appointment the date of termination confers no moksh from Section 25-F (b) is inferable from the proviso to section 25(F) (a) of the I.D. Act". The said principle of law enunciated by their Lordships in the above quoted decision completely covers the case of the concerned workman to show that writing the date of termination in appointment order of the workmen cannot take out the case of the concerned workman from the arena of retrenchment.

I hold therefore that the termination of services of the concerned workman is fully covered under the definition of retrenchment and I have no hestitation in holding that the concerned workman had been retrenched from service without complying with the provision of Section 25-F of the I. D. Act.

The management has raised in para-6 of his W.S. that the industrial dispute raised on behalf of the concerned workman is overstale as it had not been agitated for a long period of 15 years and as such the concerned workman is not entitled to any relief. It is admitted case of the parties that the services of the concerned workman was terminated on 28-6-68. Admittedly no industrial dispute was raised either by the concerned workman or his union soon after the termination of the services of the concerned workman. The concerned workman WW-1 has stated that he had files several representations before the management for giving his employment and he personally met with the Branch Manager for giving him employment. But the said oral evidence is not supported by any document or any witness in whose presence the concerned workman had represented his case before the management. In cross-examination he has stated that the union had not taken up his cause at the time his services were terminated. He, however, again stated that the union had taken up his case in 1968. But there is no evidence to support that the union had taken up his case in 1968. He has further stated that he had not made any representation to the management for his employment verbally and that he had not applied in the Bank for appointment in response to any advertisement of the Bank. He has stated that he was writing letters for his appointment to the management and had sent representation by post from Aligarh where he resides. The concerned workman has not filed copy of any of the representations which he asserts to have sent by post from Aligarh. He has filed some photo copies of postal certificate of posting. The said certificate of posting are Ext. W-11 series in the case. It only shows that some letters were addressed to the Agent, State Bank of India Patna. It does not show as to who had sent the letters for which the certificate of postings was granted by the post office. It also does not show as to what these letters were for which postal certificates were granted. Unless a copy of the letters is produced it cannot be said that the concerned workman had sent any letter to the Agent representing for his appointment. Had the concerned workman actually sent any letter of representation to the management of State Bank of India regarding giving him employment he must have maintained his copies with him. It has been alleged on behalf of the management that the concerned workman has now maninulated the postal certificate of posting. The concerned workman or his union did not ask for the original of the letters which were sent by the workmen to the Bank by the so called "Certificate of posting." If the concerned workman had really sent the letters to the Bank he must have made a praver for calling of those papers from the Bank . I hold therefore that the said certificate of posting Ext W-1 series cannot show that the concerned workman had sent any letter to the management for his employment after the termination of his services. It will appear on reference to Ext M-1 that the industrial dispute in respect of the concerned workman was raised for the first time sometime in the year 1983. Ext. M-2 M-3, M-4, M-5, W-7, W-8 and W-9 all go to show that the industrial dispute raised on behalf of the concerned workman by the union continued from 1983 to 1984. Ext. W-10 dated 6-6-85 shows that the report of the conciliation officer Patna was received by the Desk Officer, Ministry of Labour on 9-5-85 There is no document to show that the industrial dispute was raised prior to 1983. On the consideration of the above evidence, I hold that no industrial dispute had been raised either by the concerned workman or his union prior to 1983 and that the concerned workman had kept silent since the date of termination of his services on 28-5-68. No explanation has been given to show as to why no step had been taken during the period 1968 to 1982 and the said gap of long period of about 14 years remained un-explained. In this connection decision reported in SCLJ-1 Page 104 (Inder Singh and sons-Vrs-their workman) and SCLJ-4 Page 2228 (Shalimar Works-vrs- their workman) have been cited on behalf of the management to show that the concerned workman cannot be given any relief because of his inordinate delay in raising the industrial dspute. It has been held in the case of Inder Singh referred to above "on the question where retrospective effect can be given to an Award in the industrial adjudication, no doubt laws of limitation which might bar in Civil Court from giving remedy in respect of lawful right should not be applied by the Industrial Tribunal but even stale claims should not generally be encouraged or allowed unless there is satisfactory explanation for the delay". It was further held that "both the risk of indsutrial peace from the entertainment of claims after long lapse of time and unsettling affect when is likely to have on the employers financial arrangement should be taken into account. Where a claim has become too stale or not will depend on the facts of each case." In the case of Shalimar Works Limited it was held that "It is true that there is no limitation prescribed for reference or dispute to an industrial Tribunal, even so it is only reasonable that dispute should be referred as soon as possible after they have arisen." It will appear from the facts of the present case that no dispute was raised by the concerned workman or his union since 1968 to 1982 and the said gap of long 14 years has not been explained by the workman. The present dispute in respect of the concerned workman has been raised after a great delay of 14 years and there is no doubt that the claim of the concerned workman is overstale. In the circumstances I feel unable to give any relief to the concerned workman which would have an unsettling effect in the employees of the management and it will create many problems. The workmen have produced photo copies of letter Ext. W-1 dated 20-11-78 and a certificate Ext. W-2 dated 1-3-82 to show that the Bank had given employment to Shri Deo Kumar Pathak whose services also had been terminated. True it is that Shri Deo Kumar Pathak working as temporary cashier at Chhapra Branch of SBI was given employment by the Bank vide Ext. W-1, but from Ext. W-2 itself it will be clear that Shri Deo Kumar Pathak had worked for about 1538 days during the years, 1970, 1971, 1972, 1973 and upto February, 1974 and 21-11-78 to 8-12-78. It is apparent that the said dispute of Deo Kumar Pathak was raised soon after the termination of his services and it was not a case of delay in raising the dispute. The workmen therefore cannot equate his case with the case of Shri Deo Kumar Pathak.

In the result I hold that although the State Bank of India Patna Main Branch was not justified in terminating the services of the concerned workman Shri P.C. Jain with effect from 29-5-68, the concerned workman is not entitled to any relief as the dispute which has been raised on his behalf is overstale and as such overstale claim cannot be encouraged so as to open flood gate of litigation by the one to see whose services might have been terminated long long ago. In the above view of the matter the concerned workman is entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-12012/105/85-D.II(A)]

का.आ. 3566—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-12-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3566.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 2-12-87.

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 104 of 1987

Reference No. L-12011/60/86-D.II(A) dt. 18-8-87

In the matter of dispute

BETWEEN

The Secretary, Central Bank Staff Association, C/o Central Bank of India, Civil Line, Kanpur.

AND

The Divisional Manager, Central Bank of India, 117/H- 1/240, Pandu Nagar, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12011/60/86-D.II(A) dated 18-8-87, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the demand of Secretary, Central Bank Staff Association that the 2 candidates S/Shri A. K. Seth and R. C. Gupta should be promoted before the promotion of S/Shri Brij Kishore, Baburam and Ram Gopal by the management of Central Bank of India, Divisional Office, Kanpur is justified? If so, to what relief S/Shri A. K. Seth and R. C. Gupta are entitled?"

2. In this case despite issue of various notices, one on 26-8-87, second on 15-9-87, third on 25-9-87 and the last one on 20-10-87, none has appeared to file the claim statement on behalf of the workman.

3. It therefore appears that neither the workman nor Central Bank Staff Association, who raised the dispute is interested any longer in the case.

4. Accordingly a no claim award is given in the case.

Let six copies of this award be sent to the government for its publication.

Dated : 23-11-1987.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-12011/60/86-D.II(A)]

का० आ० 3567— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ मैसूर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण बंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-12-97 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3567.—*In pursuance* of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Mysore and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd December, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated, the 18th November, 1987

Shri B. N. Lalge, B.A (Hons) LL.B., Presiding Officer.

Central Reference No. 29/87

Old Central Reference No. 16/85

FIRST PARTY :

Shri Rudresh, Tumkur Taluk, Honnudike Post, Honudike-57212.

V/s.

SECOND PARTY :

The Chairman & Managing Director State Bank of Mysore, Head Office, Bangalore

APPEARANCES :

For the first party—Shri N. Sampathkumar, Advocate.

For the second party—Sri C. M. Nagabushan, Advocate.

AWARD

The Government of India by its order No. L-12012/223/84-D.II.A dated 16th April, 1985 made the present reference on the following point of dispute.

POINT OF DISPUTE

"Whether the action of the management of State Bank of Mysore in terminating the services of Shri Rudresh, temporary sub-staff in their Hunnudike Branch with effect from May 1984 and not considering him for further employment while recruiting fresh sub-staff is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

2. When evidence was being recorded and the matter was being heard, the first party workman has filed a memo and he prays that the reference may be closed for the reason that he has been offered appointment by the second party on full wages. The second party has been heard in the matter and the counsel agrees for the same,

3. In the result an award is passeed that the matter stands closed as not pressed. The memo. shall form part of the award.

(Dictated the secretary taken down by him and got typed and corrected by me).

B. M. LALGE, Presiding Officer
[No. L-12012/223/84-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer.

BEFORE THE CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT BANGALORE
C.R. No. 29 of 1987

First Party—Rudresh.

V/s.

Second Party—State Bank of Mysore by Managing Director.

First Parties Memo.

In view of second parties' memo. dated 17th November, 1987 bearing No. PER/38/96 by the personnal Manager of the Second Party informing there Advocates Shri R. V. Vasantha Kumar and Sri C. Nagabushanna that the first party H. S. Rudresh has been found suitable by the committee and to offer the appoint of subordinate staff on full wages vide memo. mentioned above, the first party will not press the above petition. Accordingly the petition may be dismissed.

Sd/-

Advocate for the First Party.

Sd/-
First Party.

Bangalore ;

Dated : 18-11-1987.

स्टेट बैंक आफ मैसूर

STATE BANK OF MYSORE

(Personnel Department)

Dated, the 17th November, 1987

Ref. PER/3896.

Shri R. V. Vasanth Kumar &
Shri C. M. Nagabhushana,
Advocates,
Krishna Buildings,
Avenue Road,
BANGALORE-560002.

Dear Sirs,

Industrial Dispute between Shri H. S. Rudresh (Temporary neon. Honnudike Branch) and State Bank of Mysore-C.R. No. 29/87 (Old No. 16/85).

With reference to the above, Shri H. S. Rudresh, who appeared for the interview for considering absorption has been found suitable by the committee. Accordingly, we have authorised the Zonal Manager, Bangalore Zone, to offer the anpointment of subordinate staff on full wages to Shri H. S. Rudresh, early. The same may be advised to the Tribunal.

Yours faithfully,

Sd/-
Personnel Manager.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1987

का. आ. 3568:--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :---

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट
वर्ष पहली जुलाई 1986 से 30 जून 1987 तक
भाग I -- आर्थिक स्थिति

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष 1986-87 के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 4.5 और 5 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है जबकि 1985-86 में यह 5.1 प्रतिशत थी। औद्योगिक वृद्धि दर 7 और 8 प्रतिशत के बीच मानी गयी है जो योजना के पहले वर्ष में प्राप्त 8.7 प्रतिशत की दर से कम होगी। कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष की 1.9 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि के मुकाबले में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। संपूर्ण सातवीं योजना के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर का है। वृद्धि की यह रफ्तार 8 प्रतिशत वार्षिक की औद्योगिक वृद्धि और 4 प्रतिशत वार्षिक की कृषि वृद्धि द्वारा बनाये रखने की आशा की जाती है। पहले दो वर्षों को एक साथ लेने पर वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि की औसत दर 5 प्रतिशत से केवल अंशतः ही कम होगी। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि जहां लक्ष्य के काफी निकट रही है, वहीं कृषि क्षेत्र का कार्य लक्ष्य से काफी कम रहा है। सेवा क्षेत्र, जिसका वजन अब सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत से अधिक है, की समग्र वृद्धि दर काफी रही है यह प्रति वर्ष लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है।

2. 1986-87 में कृषि के खराब कार्य-निष्पादन के कारण अनाजों और रेशेवाली फसलों के उत्पादन में कमी आयी है। केवल तिलहन और चीनी ने सुधार दर्शाया है। उद्योग में हालांकि समग्र वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी, किन्तु बिजली, कोयला और सीमेंट जैसे कुछ मूलभूत उद्योगों का कार्य पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है।

3. बिन्दु-वार आधार पर थोक मूल्य में 1985-86 में 3.8 प्रतिशत की तुलना में 1986-87* में 5.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गयी है। बिन्दु-वार आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 1985-86** की 8.9 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 में कम अर्थात् 7.5 प्रतिशत रही। इस प्रकार पिछले वर्ष की तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा नापने पर मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक द्वारा निर्देशित दर की तुलना में काफी उच्चतर थी। सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में औसत मूल्य वृद्धि बिन्दु-वार आधार पर 4.5 प्रतिशत है और थोक मूल्य के संबंध में औसत आधार पर 5.5 प्रतिशत है जबकि उपभोक्ता मूल्यों के लिए संबंधित आंकड़े 8.2 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत हैं। लगातार दो वर्षों में भारी वृद्धि विशेषकर उपभोक्ता मूल्यों में भारी वृद्धि एक क्षोभकारी प्रवृत्ति है।

4. प्रारंभिक आंकड़े दर्शाते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध घरेलू बचत 1986-87 में 18.2 प्रतिशत थी, जो 1985-86 में हुई 16.8 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी; शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल शुद्ध निवेश भी 1985-86 के 19.3 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

5. बाह्य स्थिति को देखें तो 1986-87 में व्यापार घाटे में कुछ कमी आयी है जिसका कारण हमारे निर्यातों में सुधार और आयात बिल में धीमी गति से वृद्धि है, जिसका मुख्य कारण तेल मूल्य में गिरावट है। यात्रा और पर्यटन के कारण परोक्ष प्राप्तियां 1986-87 में अपेक्षाकृत अधिक रहीं।

6. देश के विदेशी मुद्रा के आरक्षित भंडार जिनमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, स्वर्णधारिता और विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं, में 331 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और ये मार्च 1987 के अंत में 8,151 करोड़ रुपए हो गये; 1985-86 में इनमें 577 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। विशेष आहरण अधिकार के अर्थ में यह आरक्षित भंडार 1986-87 में 6,150 लाख विशेष आहरण अधिकार की गिरावट दर्शाता है, जबकि 1985-86 में 2,760 लाख विशेष आहरण अधिकार की गिरावट हुई थी।

7. समग्र वृद्धि दर की दृष्टि से देखें, तो अर्थ-व्यवस्था में 1986-87 में अच्छा सुधार हुआ है। किन्तु कृषि वृद्धि में लगातार धीमापन चिन्ता का कारण है। हालांकि चालू खाते में कमी हुई थी, फिर भी भुगतान संतुलन की स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन

8. कृषि उत्पादन में 1986-87 में अनुमानतः थोड़ी सी गिरावट होगी, जबकि 1985-86 में इसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और 1984-85 में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। हालांकि पिछले 3 वर्षों में अपेक्षाकृत गत्यवरोध रहा है किन्तु 1981-82 से 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान कृषि की स्थिति 3.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर दर्शाती है।

9. 1986-87 में मानसून लगातार तीसरे वर्ष भी प्रतिकूल रहा है। मौसम विज्ञान के 35 उप प्रभागों में से 14 उप प्रभागों में वर्ष के दौरान वर्षा या तो बहुत कम हुई है या छिटपुट वर्षा हुई है जबकि पिछले वर्ष में केवल 9 उप प्रभागों में और 1984-85 में 8 उप प्रभागों में ऐसी स्थिति थी।

10. खाद्यान्न उत्पादन 1986-87 में अनुमानतः 1,490 और 1,500 लाख टन के बीच हुआ है। जबकि 1985-86 में यह 1,505 लाख टन था। यह 1986-87 के लिए लक्ष्य से 100-110 लाख टन कम है। खरीफ के अनाजों का उत्पादन अनुमानतः 830-840 लाख टन के लगभग था, जबकि रबी का उत्पादन लगभग 660 लाख टन माना गया है। चावल का उत्पादन 1986-87 में कम अर्थात् 600-605 लाख टन माना गया है, जबकि 1985-86 में यह 640 लाख टन था।

11. दूसरी ओर गेहूं का उत्पादन 1986-87 में 480 लाख टन के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था, जो 1985-86 में प्राप्त 469 लाख टन के स्तर से अधिक है। मोटे अनाज का उत्पादन जो 1985-86 में सूखे के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, वह 1986-87 में 280-285 लाख टन का उत्पादन होने से एक अच्छी स्थिति का संकेत देता है, किन्तु यह अभी भी 320 लाख टन के लक्ष्य से कम है। दालों का उत्पादन 1986-87 में 130 लाख टन था, जो 1985-86 के लगभग बराबर है।

12. खाद्यान्न से इतर फसलों में से रूई और पटसन (मेस्ता सहित) का उत्पादन 1985-86 की तुलना में 1986-87 में कम समझा जाता है। रूई का उत्पादन 1986-87 में अनुमानतः 71.8 लाख गांठें हुआ है, जबकि पिछले मौसम में यह 86.1 लाख गांठें था। पटसन और

* किन्तु औसत आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 1986-87 में 5.4 प्रतिशत थी जो 1985-86 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी कम थी।

** किन्तु औसत आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 8.8 प्रतिशत थी जो 1985-86 में हुई 6.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।

मेस्ता का उत्पादन 86.3 लाख गांठों के लगभग था यह भी 1985-86 की 127.3 लाख गांठों के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम था। 1986-87 के मौसम में पटसन और मेस्ता के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह था कि 1985-86 में इस फसल का उत्पादन काफी बड़े क्षेत्र में हुआ था और 1986-87 में इसके क्षेत्र में कमी आयी। कम उत्पादन के बावजूद रूई, पटसन और मेस्ता को मौसम के दौरान कुल उपलब्धता संतोषजनक थी, जिसका कारण पिछले मौसम में बचा हुआ भारी स्टाक था।

13. तिलहन का उत्पादन अनुमानतः 120-123 लाख टन था, जो 1985-86 के 112 लाख टन से अधिक था किन्तु 1986-87 के लिए 148 लाख टन के लक्ष्य से कम था। गन्ने का उत्पादन 1,755 लाख टन था जो पिछले वर्ष के 1,717 लाख टन से थोड़ा ही अधिक है।

14. 1986-87 में खाद्यान्नों की कुल वसूली 199 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष में यह 201 लाख टन थी। चावल के उत्पादन में कमी से चावल की वसूली 1 अक्तूबर 1986 से 26 जून 1987 तक 5.2 प्रतिशत कम हुई और यह 91 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 96 लाख टन थी किन्तु 1986-87 में गेहूं का उत्पादन 469 लाख टन था जो एक रिकार्ड था और इस कारण 1986-87 में गेहूं की वसूली 105 लाख टन थी जो 1985-86 की 103 लाख टन से अधिक थी। गेहूं की वसूली रबी के विपणन के चालू मौसम में 30 जून 1987 तक 78 लाख टन रही जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 104 लाख टन की वसूली से कम थी।

15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी को कम करनेवाले कार्यक्रमों के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न के नियतन के कारण 1986-87 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए 19 लाख टन अनाज उठाया गया जो पिछले वर्ष के 11 लाख टन से अधिक था। वित्तीय वर्ष 1986-87 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें गरीबी कम करने के लिए ये कार्यक्रम शामिल हैं, और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री के लिए कुल 190 लाख टन अनाज (86 लाख टन चावल, 102 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन मोटे अनाज) उठाया गया था जबकि 1985-86 में 193 लाख टन अनाज (74 लाख टन चावल, 117 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन मोटे अनाज) उठाया गया था। गेहूं के उठाने में जो कमी आयी है वह रोलर आटा मिलों को खुले बाजार में गेहूं की खरीद के लिए अनुमति देने की सरकार की नीति को परिलक्षित करती है।

16. पहली जुलाई, 1987 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न का स्टाक 234 लाख टन था जो 1 जुलाई 1986 के 283 लाख टन और पहली जुलाई 1985 के 286 लाख टन के स्टाक से कम था। चूंकि ये स्टाक अतिरिक्त स्टाक नीति संबंधी तकनीकी दल के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित स्टाक से अधिक थे, अतः सरकार इन स्टाकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से अधिक मात्रा में आबंटन जैसे उपायों से कम करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के अंतर्गत लक्ष्य समूहों को वितरण के माध्यम से स्टाक कम करना वर्ष के दौरान भी जारी रहा।

17. पटसन और रूई की वसूली 1985-86 की तुलना में 1986-87 में कम रही। भारतीय जूट निगम द्वारा पटसन की खरीद 1986-87 के मौसम में 12.2 लाख गांठें थी, जब कि पिछले मौसम में यह 28.2 लाख गांठें था। खरीद में गिरावट का कारण फसल के उत्पादन में कमी था जो पिछले वर्ष की 127.3 लाख गांठों की तुलना में लगभग 86.3 लाख गांठें ही था। इस प्रकार रूई की वसूली भी कम रही। भारतीय कपास निगम द्वारा 30 जून 1987 तक 8.2 लाख गांठों की खरीद की गयी थी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 15.2 लाख गांठें खरीदी गयी थीं। महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव काटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा 30 जून 1987 तक 12.1 लाख गांठों की खरीद की गयी थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 27.6 लाख गांठों की खरीद की तुलना में आधे से भी कम थी। इसका कारण इस मौसम में 71.8 लाख गांठों का कम उत्पादन था, जबकि पिछले वर्ष में यह 86.1 लाख गांठें था। रूई के निर्यात के संबंध में अनिश्चितता दूर करने के लिए सरकार ने पहली बार तीन वर्षीय रूई निर्यात नीति घोषित की है, जिसके अन्तर्गत 1986-87 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष 6 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। हां, निर्यात सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन होंगे।

18. 1986-87 के दौरान कृषि उत्पादन में थोड़ी-सी गिरावट का कारण अनुकूल मानसून का न होना था। उर्वरकों एवं निवेश वस्तुओं के अधिक उपयोग से उत्पादन में भारी गिरावट को रोकने में मदद मिली है। 1986-87 में उर्वरकों की खपत अनुमानतः लगभग 92 लाख टन हुई थी, जबकि 1985-86 में यह 87 लाख टन थी। यह 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है, जो पिछले दो वर्ष के दौरान 6.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से कम है। प्रमाणित श्रेष्ठ बीजों की अधिक आपूर्ति से भी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। श्रेष्ठ बीजों का वितरण 1985-86 में 55.0 लाख क्विंटल था, जो बढ़कर 1986-87 में 55.8 लाख क्विंटल हो गया। प्रजनक (बीज उत्पादक) बीजों और प्रमाणित बीजों का उत्पादन भी अनुमानतः 1985-86 के क्रमशः 23.6 हजार क्विंटल और 44.8 लाख क्विंटल से बढ़कर 1986-87 में 24.8 हजार क्विंटल और 56.5 लाख क्विंटल हो गया।

19. कृषि क्षेत्र के कार्य की एक विशेषता पिछले तीन वर्षों में यह रही है कि आपूर्ति और मांग में असंतुलन रहा है, विशेषकर तिलहन, गन्ना और दालों जैसे कुछ पण्यों के मामले में, जिनके कारण उत्पादन में सुधार के बावजूद संबंधित उपभोक्ता वस्तुओं के आयात करने पड़े और काफी विदेशी मुद्रा खर्च हुई। 1986-87 (अप्रैल-मार्च) में खाद्य तेलों के आयात 14.15 लाख टन रहे हैं जिनके लिए 612 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर गयी, जबकि 1985-86 में 769 करोड़ रुपये मूल्य के 10.80 लाख टन के आयात किये गये थे। 1986-87 में 205 करोड़ रुपये की चीनी के आयात पिछले वर्ष के 432 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी कम थे। इसका कारण 1986-87 में चीनी के उत्पादन में सुधार है, जो 84 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 1985-86 में यह 70.0 लाख टन था।

20. तिलहनों का पर्याप्त उत्पादन न होने और खाद्य तेल के आयात में विदेशी मुद्रा की भारी राशि बाहर जाने की बात को ध्यान में रखकर सातवीं योजना के अंत तक तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था और इसने मई 1986 से कार्य प्रारंभ किया था। उक्त मिशन ने तिलहन के उत्पादन में सातवीं योजना के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुमुखी योजना बनायी है। मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं—123 लाख टन तिलहन (पिछले तीन वर्षों के औसत) और 36 लाख टन तेल के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1989-90 तक तिलहन का उत्पादन 180 लाख टन करना और खाद्य तेल की वसूली का स्तर 50 लाख टन तक पहुंचाना।

21. अधिकतर उत्पादन का लक्ष्य अधिकाधिक सिंचित क्षेत्र में तिलहन की खेती करके प्राप्त करने का प्रस्ताव है। 1985-86 में यह क्षेत्र 28 लाख हेक्टेयर था और इसे बढ़ाकर सातवीं योजना के अंत तक 52 लाख हेक्टेयर करना है। वर्तमान में कुल जितने क्षेत्र में तिलहन की खेती की जाती है उसका 14.9 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। सातवीं योजना के अंत तक यह प्रतिशत बढ़ाकर 23.6 किया जायेगा।

22. कार्य-नीति के एक अंग के रूप में उक्त मिशन ने कार्यक्रम के चार लघु मिशन स्थापित किये हैं। पहला लघु मिशन उन पांच तिलहनों के बारे में फसल संबंधी प्रौद्योगिकी में सुधार करने से संबंधित है, जो कुल तिलहन उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान करते हैं। ये तिलहन हैं—मूंगफली तोरिया/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और एरण्ड। इसके अलावा केरल तथा, अंडमान और निकोबार में नारियल और ताड़ के तेल का उत्पादन सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। दूसरा लघु मिशन प्रसंस्करण और फसल कटाई के बाद के कार्यों से संबंधित है, जिसमें उन संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा, जो तिलहन से तेल निकालते हैं, क्योंकि पारंपरिक तकनीक में 7 से 10 प्रतिशत तक तेल खली में रह जाता है। तीसरा लघु मिशन फार्म सहायक प्रणाली से संबंधित है, अर्थात् निवेश सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि विस्तार सेवाएं और उन तिलहन उत्पादकों को उर्वरकों की आपूर्ति भी करना जो आम तौर पर छोटे किसान हैं और प्रायः बहुत थोड़ी जमीन पर खेती करते हैं। वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य सुनिश्चित करना भी यह लघु मिशन देखेगा। अंत में, चौथा लघु मिशन मूल्य समर्थन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा। उक्त प्रौद्योगिकी मिशन ने 17 राज्यों में फैले 180 जिलों में अपनी गतिविधियां केन्द्रित करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास का भूतपूर्व कार्यक्रम उक्त मिशन के कार्य-क्षेत्र में ले आया गया है, ताकि वह तिलहन उत्पादन के बारे में समेकित दृष्टिकोण अपना सके।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियां

23. औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर 1986-87 के पहले दस महीनों (अप्रैल-जनवरी) में 7.7 प्रतिशत रही है (नयी श्रृंखला के अंतर्गत 1980-81=100) जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 9.2 प्रतिशत थी (सारणी 1)। वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र द्वारा की गयी कम वृद्धि है 1986-87 में खनिज और खनन तथा बिजली क्षेत्रों में वृद्धि दरें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही हैं।

सारणी 1—औद्योगिकी उत्पादन की प्रवृत्तियां (आधार 1980-81=100)

क्र० सं०	मद	वजन	अप्रैल-मार्च					अप्रैल-जनवरी	
			1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खनिज और खनन	11.46	117.7 (+17.7)	132.3 (+12.4)	147.8 (+11.7)	160.8 (+8.8)	167.5 (+4.2)	160.1 (+3.2)	171.0 (+6.8)
2.	विनिर्माण	77.11	107.9 (+7.9)	109.4 (+1.4)	115.6 (+5.7)	124.8 (+8.0)	136.9 (+9.7)	134.7 (+10.6)	144.4 (+7.2)
3.	बिजली	11.43	110.2 (+10.2)	116.5 (+5.7)	125.4 (+7.6)	140.4 (+12.0)	152.4 (+8.5)	151.3 (+8.2)	166.9 (+10.3)
	सामान्य सूचकांक	100.00	109.3 (+9.3)	112.8 (+3.2)	120.4 (+6.7)	130.7 (+8.6)	142.1 (+8.7)	139.4 (+9.2)	150.1 (+7.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

नया सूचकांक

24. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, 1970 के आधार वर्ष से हटाकर 1980-81 को आधार वर्ष बनाकर, संशोधित कर दिया गया है। सूचकांक के संशोधन की प्रक्रिया में, उद्योगों का वर्गीकरण, शामिल की जानेवाली मदों और विभिन्न औद्योगिक समूहों में सकल योजित मूल्य के आधार पर दिये जानेवाले वजन को भी बदल दिया गया है।

25. 1970 के आधार वर्ष वाली पहले की श्रृंखलाओं और 1980-81 को आधार वर्ष बनाकर नयी श्रृंखलाओं में सामान्य सूचकांक में शामिल तीन क्षेत्रों की मदों की संख्या और वजन की तालिका की तुलना नीचे की सारणी में की गयी है।

26. हालांकि तीन वर्षों में से प्रत्येक में शामिल मदों की कुल संख्या दोनों श्रृंखलाओं में पूर्ववत बनी हुई है, विनिर्माण क्षेत्र का वजन कम हुआ है और अन्य दो क्षेत्रों का वजन बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में हालांकि मदों की कुल संख्या वही है, उनके गठन में परिवर्तन हुआ है, जिसका कारण पुरानी श्रृंखला में शामिल कुछ मदों को जोड़ना/घटाना और उनका समेकन/उप विभाजन करना है।

सारणी 2—पुरानी श्रृंखला में मदों की संख्या और वजन

क्र. सं.	उद्योग/क्षेत्र	मदों की संख्या		वजन	
		पुरानी श्रृंखला (1970=100)	नयी श्रृंखला (1980-81=100)	पुरानी श्रृंखला	नयी श्रृंखला
1	2	3	4	5	6
1.	खनिज और खनन	61	61	96.90	114.64
2.	विनिर्माण	290	290	810.80	771.07
3.	बिजली	1	1	92.30	114.29
	कुल	352	352	1000.00	1000.00

27. विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख समूहों में से मदों के गठन में सबसे अधिक परिवर्तन "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के मामले में हुआ है; लगभग 25 मदें छोड़ दी गई हैं और 35 नई मदें जोड़ी गई

हैं। इसके परिणामस्वरूप इस समूह का वजन 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। "बिजली की मशीनें" समूह के मामले में लगभग 16 नयी मदें जोड़ी गयी हैं, ताकि तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रानिक्स और दूर संचार उद्योगों जैसे टेलीविजन, मिनी कम्प्यूटर, टेलीफोन और टेलीप्रिंटर आदि को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। दूसरी ओर "अधात्विक खनिज उत्पाद और धातु उत्पादों और पुर्जों (मशीनरी और परिवहन उपकरण छोड़कर) का निर्माण" के मामले में अनेक मदें छोड़ दी गई है। "पेट्रो-रसायन और सम्बद्ध उत्पाद" में कुछ मदें पहले के सूचकांक में शामिल नहीं की गयी थी, उन्हें इस नये सूचकांक में शामिल कर लिया गया है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को और अधिक सही नापने की दृष्टि से लघु क्षेत्र के उत्पादन को भी नये सूचकांक में शामिल कर लिया गया है।

तिमाही प्रवृत्तियां

28. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का तिमाही आधार पर विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 1986-87 की जिन तीन तिमाहियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से दो में सामान्य वृद्धि दर में धीमापन आया है (सारणी 3)। खनिज और खनन के मामले में तीनों तिमाहियों में वृद्धि दर में सुधार हुआ है, जबकि बिजली के मामले में दूसरी तिमाही में थोड़ी सी कमी आयी थी। दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र ने केवल दूसरी तिमाही में उच्चतर वृद्धि दर दर्शायी है, जबकि अन्य दो तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर में काफी धीमापन आया है।

सारणी 3—तिमाही आधार पर औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां

आधार 1980—81=100

अवधि		सामान्य सूचकांक		खनिज और खनन		विनिर्माण		बिजली	
वजन		100.00		11.46		77.11		11.43	
क्र० सं०	वर्ष	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अप्रैल-जून	131.7 (+9.3)	139.7 (+6.1)	152.2 (+0.4)	162.3 (+6.6)	126.6 (+11.3)	133.5 (+5.3)	144.2 (+7.8)	159.2 (+10.4)
2.	जुलाई-सितम्बर	134.7 (+7.3)	146.1 (+8.5)	147.1 (+3.2)	159.0 (+8.1)	130.7 (+7.9)	141.2 (+8.0)	152.0 (+9.8)	166.0 (+9.2)
3.	अक्तूबर-दिसम्बर	147.3 (+11.8)	156.7 (+6.4)	169.7 (+4.9)	182.0 (+7.2)	143.1 (+14.0)	150.7 (+5.3)	154.1 (+7.0)	171.6 (+11.4)
4.	जनवरी-मार्च	154.6 (+6.5)	अनु०	201.0 (+7.6)	अनु०	147.0 (+5.8)	अनु०	159.0 (+9.1)	अनु०

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।
अनु. = अनुपलब्ध

क्षेत्रीय प्रवृत्तियां:

29. अप्रैल-जनवरी 1986-87 में, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में प्राप्त 10.6 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत रह गयी। विनिर्माण क्षेत्र में आनेवाले उद्योगों के इंजीनियरी समूह के अक्तूबर तक आंकड़े उपलब्ध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वृद्धि दर पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की 13.2 प्रतिशत दर की लगभग आधी अर्थात् 6.7 प्रतिशत थी। मूलभूत क्षेत्र का कार्य सुधारने पर बल दिये जाने से अन्य दो क्षेत्रों अर्थात् खनिज और खनन और बिजली उत्पादन ने अप्रैल-जनवरी 1986-87 के दौरान उच्चतर वृद्धि दर दर्शायी है।

मूलभूत उद्योग

30. जिन छः उद्योगों [अर्थात् बिजली, कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर), कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, बिक्री योग्य इस्पात और सीमेंट] का वजन औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक में 28.77 प्रतिशत (पुरानी श्रृंखला में 24.55 प्रतिशत) है, उनके संयुक्त सूचकांक ने पिछले वर्ष की 7.9 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 1986-87 के पूरे वित्तीय वर्ष में 7.4 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्शायी है। इसके अलावा वर्ष के लिए मूलभूत उद्योग की वृद्धि दर का जो 9.5 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया, उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। छः मूलभूत उद्योगों में से बिजली, कोयला और सीमेंट के मामले में 1986-87 में वृद्धि दर, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में प्राप्त दर की तुलना में अधिक थी (सारणी

सारणी 4-मूलभूत उद्योगों की प्रवृत्तियां

क्र० सं०	उद्योग	यूनिट	वजन	उत्पादन (अप्रैल-मार्च)		
				1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिजली	मिलि० कि० वाट घंटा	11.43	1,56,973	1,70,045 (+8.3)	1,87,568 (+10.3)
2.	कोयला	मिलि० टन	6.61	147.41	154.24 (+4.6)	165.79 (+7.5)
3.	विकीर्णीय इस्पात	हजार टन	5.21	6,997.00	7,774.00 (+11.1)	8,219.00 (+5.7)
4.	कच्चा पेट्रोलियम	,,	2.41	28.990	30,168 (+4.1)	30.463 (+1.0)
5.	पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	,,	152	33.236	39.881 (+20.0)	42.490 (+6.5)
6.	सीमेंट	,,	1.60	30.174	33.130 (+9.8)	36.400 (+9.9)
7	कुल मूलभूत उद्योग		28.77		(+7.9)	(+7.4)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

उपयोग के आधार पर और निवेश के आधार पर किये गये वर्गीकरण पर आधारित प्रवृत्तियां

31. चूंकि औद्योगिक उत्पादन के नयी शृंखला (1980-81=100) पर आधारित मदवार आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने जारी नहीं किये हैं, अतः उपयोग के आधार पर और निवेश के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अंतर्गत प्रवृत्तियों का वर्गीकरण पुराने सूचकांक (1970=100) के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक ने अप्रैल-अक्तूबर 1986 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की 5.9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। मदवार सूचकांकों के बारे में अक्तूबर 1986 तक के उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जहां पूंजीगत वस्तु उद्योगों और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों के मामले में वृद्धि दर अप्रैल-अक्तूबर 1986 के दौरान धीमी रही है, वहीं मूल उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग समूहों ने अप्रैल—अक्तूबर 1986 में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की है (सारणी 5)। मूल उद्योग समूह में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की 6.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी, जो खनिज और खनन तथा बिजली की वजह से थी।

32. पूंजीगत वस्तु उद्योग समूह में पिछले वर्ष में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर थी, जिसके मुकाबले अप्रैल—अक्तूबर 1986-87 की 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की थी जो मुख्यतः अनेक उद्योगों अर्थात् वाणिज्यिक वाहनों, बॉल और रोलर बेयरिंग्स, बिजली के ट्रांसफार्मरों, बिजली से चलने वाले पम्पों, कृषि ट्रैक्टरों, रोड रोलरों, जीपों आदि में हुई ऋणात्मक वृद्धि दर में परिलक्षित होती है। किन्तु रेलवे वैगनों (52.6 प्रतिशत) के उत्पादन में अप्रैल—अक्तूबर 1986 में भारी वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में गिरावट (26.2 प्रतिशत) आयी थी। वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में संपूर्ण राजकोषीय वर्ष 1986-87 के लिए अंतिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष के दौरान उत्पादन दर में गिरावट 4.0 प्रतिशत तक ही थी, जिसका कारण वर्ष की पहली छमाही में हुई 19.6 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले दूसरी छमाही में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि थी। 1986-87 के दौरान उनकी बिक्री में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो 1985-86 की केवल 0.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में उच्चतर थी। मझौले और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के मामले में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि दर थी, जो पिछले वर्ष की 5.1 प्रतिशत गिरावट की तुलना में धनात्मक थी। इसके अलावा मार्च 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार उनके स्टॉकों में वर्ष भर में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी थी।

सारणी 5-औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि : उपयोग के आधार पर वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	उद्योग समूह	वजन	अप्रैल-मार्च	(अप्रैल—अक्तूबर)	
			1985-86	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1.	मूल उद्योग	33.23	+7.2	+6.4	+8.5
2.	पूंजीगत वस्तु उद्योग	14.98	+3.4	+4.1	+3.2
3.	मध्यवर्ती वस्तु उद्योग	21.33	+10.1	+10.3	+3.4
4.	उपभोक्ता वस्तु उद्योग	30.16	+3.7	+3.2	+8.2
	(क) टिकाऊ	3.91	+14.3	+18.5	+22.3
	(ख) गैर-टिकाऊ	26.65	+1.6	—0.1	+4.6
	सामान्य सूचकांक (1970=100)	100.0	+6.3	+5.9	+6.4

33. मध्यवर्ती वस्तु उद्योग मे अप्रैल—अक्तूबर 1986-87 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जो 1985-86 की तदनुरूप अवधि में हुई 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम थी। इस समूह के जिन उद्योगों ने अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्शायी उनमें मुख्य रूप से कमी आॅटो-टायर, सूती और मिश्रित धागे तथा पेट्रोलियम और रिफायनरी उत्पादों में थी जबकि चक्की के पाटों, बोल्टों, ढिबरियों, रिवेटों और सूखे सेलों ने ऋणात्मक वृद्धि दर दर्शायी। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग ने 1984-85 से लाइसेंस नीति के उदार होने से पर्याप्त गतिशीलता प्रदर्शित की है। इस समूह ने अप्रैल—अक्तूबर 1986 में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की 18.5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यात्री कारों, बाइसिकलों, घड़ियों और स्कूटरों में वृद्धि है। गैर-टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल—अक्तूबर 1986 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 0.1 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत थी। उक्त अवधि के दौरान चीनी (32.4 प्रतिशत) पेंसिलिन (28.1 प्रतिशत) और वनस्पति उद्योगों (9.5 प्रतिशत) ने उच्चतर वृद्धि दर दर्शायी है।

34. निवेश के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार कृषि पर आधारित और रसायन पर आधारित उद्योग समूहों के उत्पादन में अप्रैल—अक्तूबर 1986 में क्रमश: 4.5 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में केवल क्रमश: 1.7 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। किन्तु धातु पर आधारित उद्योग समूह की वृद्धि 1986-87 में 3.6 प्रतिशत ही थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की 9.6 प्रतिशत की तुलना में काफी धीमी थी।

औद्योगिक रुग्णता

35. छोटे मझौले और बड़े उद्योग यूनिटों में औद्योगिक रुग्णता बढ़ना जारी रहा। संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर के कारण यह चिंताजनक है। जून 1986 के अंत की स्थिति के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा रुग्ण रूप में पहचानी गयी यूनिटों की कुल संख्या 1,30,606 हो गयी और उन पर 4,665 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे, जो कुल बैंक ऋण का 8.4 प्रतिशत अथवा उद्योग (लघु, मझौले और बड़े) को दिये गये बैंक ऋण का 17.1 प्रतिशत बैठते थे।

36. भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर रुग्णता को प्रारंभ में ही पहचानने तथा वाणिज्य बैंकों और मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं के बीच निर्माण कार्यान्वयन और पुनर्वास संबंधी उपाय करने के बारे में उचित समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एक निश्चित समय के भीतर उन रुग्ण इकाइयों को पहचानें जिन्हें पुनः सक्षम बनाया जा सकता है और साथ ही संभावित सक्षमता वाले यूनिटों के लिए उचित पुनर्वास संबंधी उपाय अधिकाधिक तत्परता से तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

37. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अनुसार भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के संबंध में अपेक्षित रोकथाम, सुधारात्मक और निवारक तथा अन्य उपाय तय करने और इस प्रकार तय किये गये उपायों को तत्परता से लागू करने के लिए जनवरी 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है (जिसने 15 मई 1987 से कार्य शुरू कर दिया है) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए पुनर्वास संबंधी उपायों के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड को व्यापक अधिकार दिये गये है। इन उपायों में उनका पुनर्गठन पुनरुज्जीवित करना और साथ ही उनके प्रबंध तंत्र को बदलना या किसी अन्य कंपनी के साथ उसे समामेलित करना अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि के किसी भाग या संपूर्ण प्रतिष्ठान को बेचना या पट्टे पर देना अथवा कंपनी को बंद ही कर देना तक शामिल है। बैंकों ने जिन कंपनियों को सहायता दी है और जिनके मामले में उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे उनके संबंध में बैंकों को क्या कार्रवाई करनी है, यह सूचित करते हुए मार्गदर्शी सिद्धांत 24 फरवरी 1987 को जारी किये गये। संक्षेप में, ये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के बैंकों के पास खातों के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रिपोर्ट देने, जिसकी एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक को भी देनी है, से संबंधित है: (1) वे मामले जिनमें वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, (2) वे मामले, जहां संभाव्य क्षमता के अध्ययन पूरे किये जा चुके हैं और पुनर्वास कार्यक्रम चल रहा है, (3) वे मामले जहां, संभाव्य क्षमता का अध्ययन अभी किया जानेवाला है; और (4) वे मामले, जहां पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गये हैं और यूनिटों को पुनरुज्जीवित न हो सकने वाला मान लिया गया है।

38. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने औद्योगिक रुग्णता को बढ़ने से रोकने और उन्हें पुनरुज्जीवित करने में सहायता देने के लिए विभिन्न कदम उठायें हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने जून, 1986 के अंत तक जिन 333 यूनिटों को सहायता प्रदान की है, उनमें से 136 यूनिटों को पुनरुज्जीवित किया गया था और 131 यूनिट देखरेख (पोषण) कार्यक्रम के अंतर्गत थीं। शेष यूनिटें या तो लगातार हानि उठा रही थीं अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए शुरू किये गये ऋण और अग्रिमों को लौटाने की मांग के साथ अनधिसूचित कर दी गयी थीं।

39. रुग्ण लघु उद्योगों के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में 10 मई 1986 को एक 'लघु उद्योग विकास निधि' स्थापित की गयी है। इसके अलावा कपड़ा और जूट क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करने के प्रयोजन से सरकार ने दो निधियां स्थापित की है। ये निधियां हैं वस्त्र (टेक्सटाइल) आधुनिकीकरण निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि। ये निधियां क्रमश. 1 अगस्त 1986 और 1 नवंबर 1986 से स्थापित की गयी हैं।

राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश

40. उपलब्ध स्थूल निर्देशकों के आधार पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की दर 1986-87 में वास्तविक अर्थ में 4.5 और 5.0 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि 1985-86 में यह 5.1 प्रतिशत थी। 1986-87 में कुल शुद्ध घरेलू बचत, अंतिम रूप से चालू बाजार मूल्यों पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 18.2 प्रतिशत मानी गयी है, जो 1985-86 के 16.8 प्रतिशत से अधिक है; यह 1984-85 में 16.9 प्रतिशत थी। घरेलू क्षेत्र की शुद्ध बचत, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू बाजार मूल्यों पर 1985-86 में 15.6 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही; अनुमान है, 1986-87 में काफी बढ़कर 17.0 प्रतिशत हो गयी है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र की बचत 1986-87 में 0.7 प्रतिशत पर ही बनी रहने का अनुमान है, 1985-86 में भी यही दर थी। घरेलू निजी निगमित क्षेत्र की शुद्ध बचत 1986-87 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 0.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

41. कुल शुद्ध निवेश 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 18.4 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 19.3 प्रतिशत हो गया था। अनुमान है कि 1986-87 में, यह और बढ़कर 20.2 प्रतिशत हो जाएगा। यह सुधार और अधिक हुआ होता, यदि विदेशी संसाधनों की प्राप्ति में तीव्र गिरावट न हुई होती। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध घरेलू बचत और निवेश के अनुमान से संबंधित आंकड़े सारणी 6 में दिये गये हैं।

42. वित्तीय आस्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत, जो 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 9.3 प्रतिशत से गिरकर 1985-86 में 8.7 प्रतिशत हो गयी थी, अनुमान है कि 1986-87 में काफी बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गयी है। भौतिक आस्तियों के रूप में बचत, जो 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 6.9 प्रतिशत हो गयी थी, अनुमान है कि 1986-87 में उसी दर पर बनी रहेगी। वित्तीय आस्तियों (सकल) में घरेलू बचत, अनुमान

है कि 1985-86 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में 12.6 प्रतिशत हो गयी है। किन्तु घरेलू वित्तीय देयताएं 1985-86 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 2.7 प्रतिशत से घटकर 1986-87 में 2.5 प्रतिशत रह गयीं, 1984-85 में ये 2.8 प्रतिशत थीं। मुद्रा के रूप में बचत 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 1.0 प्रतिशत रह गयी थी; यह 1986-87 में बढ़कर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 1.3 प्रतिशत हो गयी है। बैंक जमा राशियों के रूप में बचत, जो 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 5.0 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 4.7 प्रतिशत रह गयी थी, 1986-87 में यह काफी बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गयी, जिसका मुख्य कारण वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में भारी संचय है। उपर्युक्त की दृष्टि से घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों (सकल) में मुद्रा और जमाराशियों का हिस्सा 1985-86 के 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में 53.1 प्रतिशत हो गया। सरकार पर घरेलू क्षेत्र के दावे (मुख्यत: लघु बचत), अनुमान है कि 1985-86 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में 1.7 प्रतिशत हो गये। यह थोड़ी सी वृद्धि अनिवार्य जमा-राशि की अदायगी के कारण काफी राशि के निर्गमन की वजह से है।

सारणी 6—देशी बचत और निवेश के अनुमान

(चालू बाजार मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	क्षेत्र/मद	राजकोषीय वर्ष 1984-85	1985-86 (अनन्तिम)	1986-87 (प्रारंभिक अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू क्षेत्र की शुद्ध बचत जिसमें से वित्तीय आस्तियों में बचत	15.6 9.3	15.6 8.7	17.0* 10.1
2.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी क्षेत्र की शुद्ध बचत	0.8	0.7	0.7*
3.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में देशी निजी निगमित क्षेत्र की शुद्ध बचत	0.5	0.5	0.5*
4.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल शुद्ध देशी बचत (1+2+3)	16.9	16.8	18.2
5.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी संसाधनों का आगम	1.5	2.5	2.0
6.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल शुद्ध निवेश (4+5)	18.4	19.3	20.2

* घरेलू क्षेत्र द्वारा भौतिक आस्तियों में निवेश और सरकारी क्षेत्र की बचत के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमान उपलब्ध न होने के कारण पिछले वर्ष की दर इस वर्ष भी मान ली गई है जिसमें जनवरी 1988 में के. सां. सं. द्वारा त्वरित अनुमान जारी करने पर संशोधित किया जायेगा।

टिप्पणी: 1984-85 और 1985-86 के शुद्ध अनुमान पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये अनुमानों से मेल नहीं खाते, क्योंकि और अधिक आंकड़े प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश के अनुमानों में काफी संशोधन किये गये हैं।

43. विदेशी संसाधनों की शुद्ध प्राप्ति जो 1984-85 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से काफी बढ़कर 1985-86 में 2.5 प्रतिशत हो गयी थी, उसके 1986-87 में घटकर 2.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इस प्रकार विदेशी संसाधनों की शुद्ध प्राप्ति में तीव्र गिरावट के बावजूद कुल शुद्ध निवेश शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 1985-86 के 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में 20.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

ऋण नीति सम्बन्धी गतिविधियां

मुख्य बातें

44. पिछले तीन वर्षों में प्रारक्षित मुद्रा और समग्र चल निधि में भारी वृद्धि की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि 1986-87 के दौरान मुद्रास्फीतिकारी दबाव फिर से न बढ़ने देने के लिए सावधानीपूर्वक ऋण नीति अपनायी जाये।

45. प्रारक्षित निधियां संबंधी अपेक्षाएं, नीति का प्रमुख साधन बनी रहीं, जिसमें दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को कारगर ढंग से बनाये रखने पर विशेष बल दिया गया। चार प्रतिशत छूट सीमा (सांविधिक चल निधि अनुपात के अन्तर्गत रखने के लिए अपेक्षित राशि के संबंध में) धीरे धीरे कम की गयी और अन्तत: उसे समाप्त कर दिया गया। चूंकि 1986-87 में समग्र चलनिधि की वृद्धि विशेषकर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान, उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वृद्धि से अधिक थी, इसलिये मुद्रागत विस्तार की गति को धीमा करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये। सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी अनुपात, दोनों प्रकार की प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं बढ़ा दी गयी और रोकी गयी नकद राशि को मुक्त करने की जो घोषणा पहले की गयी थी उसे अंशत: निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हालांकि एम3 की 1986-87 में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी किन्तु इन उपायों ने मुद्रागत विस्तार की गति को कुछ संयत कर दिया।

46. समीक्षाधीन अवधि में एक प्रमुख गतिविधि ब्याज दरों को कम करने से संबंधित है। मुद्रा की लागत को कम करने और ब्याज दर नीति को लचीला बनाने की दृष्टि से ऋण दरों और जमा दरों तथा जमाराशियों की अवधि पूरी होने संबंधी विन्यास में चयनात्मक परिवर्तन किये गये। यह माना गया कि हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति की दर 1979-81 की उच्च मुद्रास्फीति दरों से काफी नीचे रही है। उस समय इस उच्च दर के कारण ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की गयी थी। ब्याज की वास्तविक दरें, विशेषकर बैंकों की अधिकतम ऋण दर काफी ऊंची थी और तदनुसार अधिकतम ऋण दर में जो कमिक कमी अप्रैल 1983 और अप्रैल 1985 में की गयी थी, उसे आगे अप्रैल 1987 में और कम किया गया। अप्रैल 1987 में पहली बार बचत लिखतों पर ब्याज दरों में समन्वित परिवर्तन कटौती की गयी, जिसमें बैंक जमाराशियां, डाकघर जमाराशियां, राष्ट्रीय बचत पत्र, कम्पनी जमाराशियां, ऋण पत्र (डिबेंचर), सरकारी क्षेत्र के बांड तथा अन्य योजनाएं शामिल हैं। बैंक जमाराशियों के मामले में अधिकतम जमा दर के लिए लागू अवधि समाप्ति (मैच्युरिटी) को कम करने का सजग प्रयास किया गया था। आशा की जाती है कि इससे देश में अर्थव्यवस्था की बदलती हुई स्थिति के संदर्भ में जमाराशियों और ऋणों पर ब्याज दरें बदलने में बैंकिंग तंत्र को कुछ लचीलापन मिल सकेगा।

47. अन्य नीतिगत परिवर्तन मौजूदा उपायों को औचित्यपूर्ण बनाने और उनके कारगर कार्यान्वयन के स्वरूप के थे। चयनात्मक ऋण नियंत्रण को औचित्यपूर्ण बनाने का जो कार्य 1985-86 में किया गया था उसे 1986-87 में एक कदम और आगे बढ़ाया गया। सरकारी ऋण व्यवस्था संबंधी ऋण क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित को लागू किया (i) 91 दिवसीय खजाना बिलों को पुन: प्रचलित करने की योजना, (ii) 91 दिवसीय खजाना बिलों के अवधिपूर्व भाजन पर अतिरिक्त शुल्क, और (iii) 182 दिवसीय खजाना बिल नामक एक नयी लिखत का आरम्भ।

48. मुद्रा बाजार के संबंध में कार्यकारी दल ने मुद्रा बाजार को सक्रिय करने और उसके विकास के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। यद्यपि कुछ सिफारिशों की और विस्तृत जांच आवश्यक है, वहीं रिजर्व बैंक ने अनेक सिफारिशों पर पहले ही विशिष्ट कार्रवाई की है।

49. जुलाई 1986 और जून 1987 के बीच विभिन्न बातों के संबंध में घोषित किये गये ऋण नीति संबंधी उपायों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

नीतिसंबंधी उपाय---अगस्त 1986

50 निर्यातों को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के विन्यास को मार्च 1986 में औचित्यपूर्ण बनाया गया; अगस्त 1986 में इन्हें और कम किया गया। उक्त दोनों संशोधनों से निर्यात ऋण के बाकी भाग के लिए ब्याज दरें काफी कम हो गयीं; यह कमी 2.5 से लेकर 4.5 प्रतिशत अंक तक थी।

51. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों का प्रभावी प्रतिलाभ (ब्याज उपार्जन के लिए समायोधन के बाद) और पुनर्वित्त दर के बीच मार्जिन अक्षुण्ण बना रहे, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक के निर्यात ऋण पुनर्वित्त की ब्याज दर भी 10 प्रतिशत से घटाकर पहली अगस्त 1986 से 9 प्रतिशत कर दी गयी।

नीतिसंबंधी उपाय--सितम्बर 1986

52. विदेशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरों में लगातार गिरावट के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अन्तर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 8 सितम्बर 1986 से एक बार फिर घटाकर संशोधित की गयीं। किन्तु अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं। जमा दरों का विन्यास सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7--अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

क्र. सं.	समाप्त होने की अवधि	एफ सी एन आर दरें लागू होने की तारीख		एन आर ई दरें
		5 मई 1986	8 सितम्बर 1986	27 मई 85 से लागू
1	2	3	4	5
1.	15 दिन से 45 दिन	3.0	3.0	3.0
2.	46 दिन से 90 दिन	4.0	4.0	4.0
3.	91 दिन और अधिक लेकिन 6 माह से कम	6.5	6.5	6.5
4.	6 माह और अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	8.0	7.5	8.0
5	1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	8.5	8.0	10.5
6.	2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	9.0	8.5	11.0
7.	3 वर्ष और अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	10.0*	9.0*	12.0
8.	5 वर्ष से अधिक			13.0

*इस दर पर एफ सी एन आर जमाराशियां केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं।

नीतिसंबंधी उपाय--अक्तूबर 1986

53. 1986-87 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था में हुई गतिविधियों और दूसरी तिमाही में संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति अक्तूबर 1986 में घोषित की गयी थी और उसमें निम्नलिखित उपाय निहित थे।

अवरुद्ध नकदी शेष राशियां जारी करना

54. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे 14 जनवरी 1977 और 31 अक्तूबर 1980 के बीच बनने वाली वृद्धिशील शुद्ध मांग और मियादी देयताओं के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रारक्षित नकदी अनुपात रखेंगे। इस तरह रोकी गयी 1,859 करोड़ रुपये की राशि का पांचवा हिस्सा (372 करोड़ रुपये) अक्तूबर 1984 और दिसम्बर 1984 में 2 किस्तों में जारी कर दिया गया; शेष राशि का एक तिहाई (495 करोड़ रुपये) अक्तूबर 1985 में जारी किया गया था। इस प्रकार 992 करोड़ रुपये की राशि रिजर्व बैंक के पास रोककर रखी गयी थी। अधिक कामकाज के समय में ऋण आवश्यकताओं की संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों के संसाधनों को संपूरित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि शेष राशि का आधा (496 करोड़ रुपये) 22 नवम्बर 1986 और 31 जनवरी 1987 को दो समान किस्तों में जारी किया जाये। किन्तु वास्तव में एक ही किस्त जारी की गयी।

विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा की उपलब्धता

55. बैंक इस सुविधा को आसानी से प्राप्त कर सकें इसके लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे 1985-86 में बैंक की औसत जमा राशियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि तक का पुनर्वित्त अधिक से अधिक 14 दिन के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति लिये बिना अपने विवेकाधिकार से आहरित कर सकते हैं। 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए अथवा ऊपर निर्दिष्ट जमा से अधिक की राशि आहरित करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा जारी रही।

निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं

56. सामान्य परम्परा से हटते हुए यह निर्णय किया गया कि बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं की गणना के लिए आधार वर्ष आगे न बढ़ाया जाये जिसका अर्थ वास्तव में यह था कि बैंकों को निर्यात पुनर्वित्त सुविधा उस राशि से लगभग 200 करोड़ रुपये अधिक उपलब्ध होगी जो उन्हें उस स्थिति में मिलती यदि आधार वर्ष आगे ले आया गया होता।

खजाना बिल

57. खजाना बिलों से संबंधित ऋण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए भी दो उपाय घोषित किये गये थे।

(i) 182 दिवसीय खजाना बिल

58. खजाना बिलों को लचीली दरों वाली लिखत के रूप में विकसित करने के लिए मुद्रा प्रणाली के कार्य की समीक्षा संबंधी सिफारिशों को अपनाते हुए प्रारम्भ में मासिक नीलामी आधार पर 182 दिवसीय खजाना बिलों की योजना लागू की गयी; इसके लिए रिजर्व बैंक से कोई पुनः खरीद व्यवस्था नहीं होगी और इस प्रकार की पहली नीलामी नवम्बर 1986 में हुई थी। उक्त नयी लिखत अल्पावधि निवेशों के लिए एक विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से बनायी गयी थी और यह आशा की गयी थी कि समय बीतने के साथ अलग अलग अवधि समाप्ति वाली लिखतों का एक व्यापक विन्यास (समूह) तैयार हो जायेगा, जिससे द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता मिलेगी।

(ii) 91 दिवसीय खजाना बिलों की समय से पहले पुनर्भुनाई पर अतिरिक्त शुल्क

59. रिजर्व बैंक के खजाना बिल संविभाग (पोर्टफोलियो) में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव न हों, इस दृष्टि से 91 दिवसीय खजाना बिलों की समय से पहले पुनर्भुनाई पर नवम्बर 1986 में अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया। इस शुल्क की दर प्रति एक लाख रुपये के अंकित मूल्य पर पहले दिन 8.11 रुपये से लेकर सातवें दिन 50 रुपये तक अलग अलग रही और 14 दिन तक यह दर कायम रही। 14 दिन के बाद से पहले पुनर्भुनाई के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी रूप से मिलने वाला शुल्क पहले दिन शून्य है और 14 दिन तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 8 अक्तूबर 1986 से रिजर्व बैंक के पास रखे हुए पुनः भुनाए गये जिन खजाना बिलों की अवधि पूरी होने में 30 दिन से अधिक की अवधि शेष थी, उन्हें उसी दर पर निवेशकों को पुनः जारी किया गया, जो दर उसी प्रकार के नये बिलों के लिए लागू थी। समय से पहले पुनः भुनाने पर अतिरिक्त शुल्क रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नए बिलों और साथ ही पुराने बिलों के बदले जारी किये गये नये बिलों दोनों पर लगाया गया है।

1986-87 के पेराई मौसम के लिए चीनी उद्योग को अग्रिम

60. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1986-87 के मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए चीनी बिलों को पिछले मौसम में उपयोग में लायी गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़कर) के 115 प्रतिशत तक आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमाएं रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजूर कर सकते हैं।

नीतिसंबंधी उपाय—जनवरी 1987

61. जैसा कि अक्तूबर 1986 में घोषित किया गया था, वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास अभी भी अवरुद्ध अतिरिक्त नकद राशि की पहली किस्त, जो 248 करोड़ रुपये थी 22 नवम्बर 1986 को जारी की गयी थी। किन्तु 248 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त की अदायगी पहले स्थगित कर दी गयी और बाद में बैंकों की सुविधाजनक चलनिधि स्थिति को देखते हुए मार्च 1987 में रद्द कर दी गयी।

नीतिसंबंधी उपाय—फरवरी 1987

62. दिसम्बर 1986 के अंत और जनवरी 1987 में समग्र चलनिधि में भारी वृद्धि हुई थी। उत्पादन क्षेत्रों को ऋण के मौसमी प्रवाह में कोई रुकावट डाले बिना बैंकिंग तंत्र की चलनिधि को स्थिरता प्रदान करने दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि 28 फरवरी, 1987 से प्रारम्भ पखवाड़े से प्रारक्षित नकदी अनुपात 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत कर दिया जाये।

नीतिसंबंधी उपाय—मार्च 1987

63. ऋण नीति संबंधी उपायों की समीक्षा मार्च 1987 में की गयी थी। यह देखा गया कि 1985-86 और 1986-87 में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने संबंधी अपेक्षा के अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फिर, बैंकों द्वारा धारित खजाना बिलों में सप्ताह-दर-सप्ताह होने वाली अस्थिरता बहुत कम हो गयी। पिछले कुछ वर्षों में प्रारक्षित मुद्रा में भारी वृद्धि अहा चिंता की बात थी, वहीं रिजर्व बैंक की शुद्ध घरेलू आस्तियों* से यह संकेत मिलता है कि देश से उद्भूत प्राथमिक मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण रखा गया है जिससे अनावश्यक द्वितीयक विस्तार रोका जा सका है। रिजर्व बैंक की शुद्ध घरेलू अस्तियों में 1986-87 (अप्रैल मार्च) में 2,192 करोड़ रुपए (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इनमें 2,293 करोड़ रुपये (11.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 1987-88 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति संबंधी उपाय मुद्रागत और ऋण संबंधी गतिविधियों और वास्तविक अर्थ अवस्था में संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 1987 को घोषित किये गये।

64. मूल्य स्थिति और अर्थ व्यवस्था चलनिधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि 1987-88 में समग्र चलनिधि की वृद्धि को, 1986-87 में हुई वृद्धि दर से काफी नीचे रखा जाये। M_3 की वृद्धि को संयत रखने की नीति के अनुसार 1987-88 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि में वृद्धि के लिए कार्यकारी अनुमान 18,500 करोड़ रुपये (18.0 प्रतिशत) रखा गया, जबकि 1986-87 में यह 17,340 करोड़ रुपये (20.3 प्रतिशत था)। वर्ष की दोनों छमाहियों में जमाराशियों की वृद्धि लगभग समान रहने का अनुमान था। इस वृद्धि से बैंक न केवल 1987-88 की पहली छमाही के दौरान ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होंगे, बल्कि अपनी चलनिधि भी बना सकेंगे।

65. चूंकि यह अनुमान था कि बैंक 1987-88 की पहली छमाही में सुविधाजनक चलनिधि की स्थिति में होंगे, अतः यह उचित समझा गया कि समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष की पहली छमाही में ही नीतिगत समायोजन किये गये। इस संदर्भ में ऋण नीति संबंधी निम्नलिखित उपाय घोषित किये गये थे।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण और जमा दरें

66. जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, मुद्रा की लागत और ब्याज-दर नीति को लचीला बनाने की दृष्टि से ऋण और जमा दरों में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की गयी थी। ऋण दरों में कमी से ऐसी अनेक श्रेणियों के कर्जदारों को राहत मिली है जिनके लिए ब्याज दरें पहले बहुत बढ़ा दी गयी थीं। जिन श्रेणियों के लिए ऋण दरों में पहले ही काफी रियायतें मौजूद थीं और जिनमें सितम्बर 1979 और उसके बाद बहुत कम वृद्धि हुई थी, वे अपरिवर्तित रहीं। जमा दरों में इसी के साथ साथ वृद्धि से बैंकों की लाभप्रदता सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी, अन्यथा ऋण दरें कम करने के परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता

(i) ऋण दरें

67. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 15 प्रतिशत से अधिक के सभी स्तरों पर निर्धारित ऋण दरों में एक प्रतिशत अंक की कमी की गयी विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दरों की जो न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं थीं उस प्रणाली को बनाये रखा गया किन्तु 16.5—17.5 प्रतिशत के उच्चतम चरण के लिए 16.5 प्रतिशत की एक नियत दर निर्धारित की गयी। उक्त परिवर्तन 1 अप्रैल 1987 से निम्नलिखित रूप में लागू किये गये : (सारणी 8)।

सारणी 8—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

क्र. सं.	31 मार्च 1987 तक लागू	1 अप्रैल 1987 से लागू
1	2	3
1.	16.50—17.50 और 17.50 की सीमा (नियत)	16.50 (नियत)
2.	16.50 तक की उच्चतम सीमा	15.50 तक की उच्चतम सीमा
3.	16.50 (नियत)	15.50 (नियत)

*प्रारक्षित मुद्रा घटाकर (भा.रि.बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां + रिजर्व बैंक के पास बैंकों की शेष राशियां + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां)

विनिमय बिलों की भुनाई पर अधिकतम प्रभावी ब्याज दर घटाकर 15.5 प्रतिशत अर्थात् नयी अधिकतम ऋण दर से 1 प्रतिशत अंक कम कर दी गयी। इस उपाय से बिलों के उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान प्रणाली को सुधारने में भी सहायता मिलेगी।

(ii) जमा दरें

68 अधिकतम जमा दर 11 प्रतिशत से घटाकर पहली अप्रैल 1987 से 10 प्रतिशत कर दी गयी और यह उच्चतम दर दो वर्ष और उससे अधिक अवधि वाली जमाराशियों पर लागू की गयी। किन्तु वर्तमान जमाराशियों पर 31 मार्च 1987 तक प्रभावी दरें उन राशियों की अवधि पूरी होने तक लागू रहेंगी। मीयादी जमाराशियों की अवधि पूर्णता संबंधी विन्यास में पिछले 15 वर्षों में विन्यासगत रूप का परिवर्तन हुआ है। 1969 में मीयादी जमाराशियों की केवल 27 प्रतिशत राशियां तीन वर्ष से अधिक पूर्णतावाली थीं, जबकि 1982 में तुलनीय अनुपात 73 प्रतिशत है। अपेक्षाकृत लंबी जमाराशियों में ह्रास की अवधि में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज विन्यास में मजबूती आयी है जिससे बैंकों को ब्याज दरों में सामान्य गिरावट को समायोजित करने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि वे लंबी अवधि वाली जमाराशियों पर उच्चतम दरें अदा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अवधि पूर्णतया संबंधी विन्यास को, अब तक की 5 वर्ष की जमाराशियों के बजाए दो वर्ष की जमाराशियों पर अधिकतम जमाराशि दर अदा करते हुए कम करने में बैंक बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसरण में ब्याज दरों को और आसानी से समायोजित कर सकेंगे। जमा दरों में संशोधित विन्यास विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी (बाह्य) (रुपया खातों को छोड़कर) सारणी 9 में दिया गया है।

69. विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की जमा दर का विन्यास और अवधि पूर्णता का स्वरूप अपरिवर्तित रहा। ये दरें घरेलू जमा दरों से पहले ही अलग की जा चुकी थीं और विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों के लिए दरों का अलग विन्यास निर्धारित किया गया था। अनिवासी बाह्य रुपया खातों की एक वर्ष और उससे अधिक की जमा दरों के मामले में घरेलू जमा दर से इनकी सम्बद्धता खत्म कर दी गयी थी और ब्याज दरों तथा पूर्णता अवधि के लिए एक स्वतन्त्र विन्यास 1 अप्रैल 1987 से निर्दिष्ट किया गया था। किन्तु अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों की जमाराशियों के लिए निर्दिष्ट दरें और पूर्णता की अवधि का जो विन्यास 31 मार्च 1987 से पहले प्रचलित था, उसे नहीं बदला गया।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

70. 25 अप्रैल 1987 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से सांविधिक चलनिधि अनुपात शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 37 प्रतिशत बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया। भारतीय खाद्य निगम ने 1986-87 में भारत सरकार से 1,200 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण लिया था जिसमें से 634 करोड़ रुपये का ऋण 31 मार्च 1987 को जारी कर दिया गया, जिसे बैंकों ने खाद्य ऋण की वापसी के रूप में प्राप्त किया। पिछले बकाया उपदान के 550 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम को अप्रैल और मई 1987 में अदा किये गये थे। इसके अलावा उपदान की मासिक "लेखागत" अदायगी की प्रणाली लागू की गयी है। इस प्रकार 25 अप्रैल 1987 से प्रभावी सांविधिक चलनिधि के अनुपात में वृद्धि से बैंकों के सामने कोई समस्या नहीं आई।

सारणी 9—जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों/अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों को छोड़कर

(प्रतिशत वार्षिक)

क्र. सं.	सीमा	31 मार्च 1987 तक लागू	1 अप्रैल 1987 से लागू
1	2	3	4
1.	चालू खाते	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	बचत खाते	5.0	5.0
3.	मीयादी जमाराशियां :		
	(क) 15 दिन से 45 दिन	3.0	3.0
	(ख) 46 दिन से 90 दिन	4.0	4.0
	(ग) 91 दिन और अधिक लेकिन छः माह से कम	6.5	6.5
	(घ) छः माह और अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	8.0	8.0
	(ङ) 1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	8.5	9.0
	(च) 2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	9.0	10.0*
	(छ) 3 वर्ष और अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	10.0	
	(ज) 5 वर्ष से अधिक	11.0	

*2 वर्ष और अधिक के लिए लागू दर।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों के संबंध में प्रारक्षित नकदी संबंधी अपेक्षाएं

71. पिछले दो वर्षों में विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों की जमा दरें क्रमिक रूप से कम करके उन स्तरों पर ले आयी गयीं, जो घरेलू बैंक जमाराशियों पर मिलने वाली दरों से कम थीं। लेकिन तंत्र में समग्र चलनिधि कम करने के उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों की जमाराशि संबंधी देयताओं के संबंध में प्रारक्षित नकदी अनुपात 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 मई, 1987 से 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। किन्तु विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता जमाराशि संबंधी देयताओं में पहले की तरह उस 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात से छूट मिलती रही, जो नवम्बर 1983 में लागू किया गया था।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

72 पिछले दो वर्षों में चयनात्मक ऋण नियंत्रण को काफी औचित्यपूर्ण बनाया गया है और जहां इस प्रकार के नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं रही, वहां इन्हें हटा दिया गया, फिर जहां शेष पण्य और मूल्यों में उतार-चढ़ाव अनुकूल रहे, उन मदों के मामले में नियंत्रण को कम कठोर रखा गया। चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में पहली अप्रैल 1987 से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये।

(i) ऋण की उच्चतम सीमाओं का स्तर

73. जिन पण्यों के मामले में ऋण के स्तर के बारे में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (नवम्बर-अक्तूबर) की तीन वर्ष की अवधि के आधार पर रखने की शर्त लगायी गयी थी, वहां इस आधार को एक वर्ष आगे बढ़ाकर 1982-83, 1983-84 और 1984-85 की अवधि कर दी गयी।

(ii) मार्जिन

74. "अन्य खाद्यान्नों", दालों, चीनी, गुड़ और खांडसारी के जारी किये गये स्टॉक से न्यूनतम मार्जिन में सीधे 15 प्रतिशत अंक की कमी कर दी गयी। तिलहन, वनस्पति तेलों और चीनी के जारी न किये गये स्टॉक के लिए न्यूनतम मार्जिन अपरिवर्तित रखे गये। न्यूनतम मार्जिन का नया विन्यास सारणी 10 में दिया गया है।

(iii) मिल मालिकों/और व्यापारियों को ऋण

75. रबी 1987 में गेहूं की भारी फसल के संदर्भ में बैंकों को सूचित किया गया कि वे आटा मिलों और व्यापारियों को अब तक की अपेक्षा और अधिक मुक्त रूप में ऋण प्रदान करने पर विचार करें, किन्तु यह सामान्य ऋण अनुशासन के अनुपालन की शर्त पर होगा।

विवेकाधीन पुनर्वित्त की उपलब्धता

76. जो बैंक खाद्य संघ के सदस्य नहीं थे और जिनकी विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमाराशियों में बड़ा हिस्सा था और जिन्हें मार्च 1987 के अन्त के लिए समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता था, उनके मामले में रिजर्व बैंक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि बहुत कम समय के लिए अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

रिजर्व बैंक के पास शेष नकदी पर क्रमिक ब्याज दरें

77. प्रारक्षित नकदी के अनुपात में कमियों के लिए पात्र नकदी शेष राशियों पर क्रमिक ब्याज दरों की योजना 1 जनवरी, 1982 से लागू की गयी थी। प्रारक्षित नकदी अनुपात में कम गिरावटों के लिए बैंकों को और राहत देने के लिए क्रमिक ब्याज दरों की अनुसूची संशोधित की गयी थी। पहले की अनुसूची और संशोधित अनुसूची सारणी 11 में दी गयी है।

सारणी 10—चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अन्तर्गत आने वाले पण्यों के स्टॉकों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

(पहली अप्रैल 1987 से लागू)

(प्रतिशत)

पण्य	स्टॉकों पर		गोदाम रसीदों पर
	प्रोसेसिंग इकाइयां/मिलें	अन्य	
1. 'अन्य खाद्यान्न'	30	45	30
2. दालें	30	45	30
3. तिलहन (मूंगफली, तोरिया/सरसों, एरण्ड, अलसी तथा सभी आयातित तिलहन)	30	45	30
4. वनस्पति तेल (मूंगफली का तेल, तोरिया/सरसों का तेल, अलसी का तेल, एरण्ड का तेल, वनस्पति तथा आयातित तेल)	30*	60	45
5. चीनी			
(क) बफर	0	—	—
(ख) जारी न किये गये स्टॉक	17.5	—	—
(ग) जारी किये गये स्टॉक	60	60	45
6. गुड़ तथा खाण्डसारी	30	60	45

*पंजीकृत तेल मिलों तथा वनस्पति विनिर्माताओं पर लागू।

सारणी 11—प्रारक्षित नकदी अनुपात बनाये रखने में कमी—शेषराशियों पर क्रमिक ब्याज दरों की अनुसूची

(31 मार्च 1987 तक लागू)		(पहली अप्रैल 1987 से लागू)	
रखे जाने के लिए अपेक्षित अनुपात की निरपेक्ष राशि के प्रतिशत के रूप में पखवाड़े के दौरान कमी (तक और को शामिल करते हुए)	3 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक अनुपात से अधिक वास्तव में रखी गयी राशि पर देय ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	रखे जाने के लिए अपेक्षित अनुपात की निरपेक्ष राशि के प्रतिशत के रूप में पखवाड़े के दौरान कमी (तक और को शामिल करते हुए)	3 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक अनुपात से अधिक वास्तव में रखी गयी राशि पर देय ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	2	3	4
	10.50	0.0	10.50
0.5	10.00	0.5	10.25
1.0	8.75	1.0	10.00
1.5	5.25	1.5	9.50
2.0	2.50	2.0	8.75
		2.5	7.75
3.0	0.50	3.0	6.50
3.00 से अधिक	0.00	3.5	5.00
		4.0	3.00
		4.5	1.25
		5.0	0.50
		5.0 से अधिक	0.00

मुद्रा बाजार संबंधी कार्यकारी दल

78. मुद्रा बाजार संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत की। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिजर्व बैंक ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय/उपाय घोषित किये।

मांग मुद्रा ब्याज दरें और सहभागी

79. प्रशासित ब्याज दरों के अनुसार मांग मुद्रा बाजार का विन्यास और बाजार के सहभागी फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगे।

बिल भुनाई दर में कमी

80. अल्पावधि अग्रिमों के लिए निर्धारित ब्याज दरें, जो विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों के लिए उनके नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्टों और बिलों के लिए एकसमान थीं, संदत्त की गयीं, उच्चतम ऋण दर 1 अप्रैल, 1987 से 17.5 प्रतिशत से घटाकर 16.5 प्रतिशत करने की दृष्टि से इस प्रकार की श्रेणी के कर्जदारों के लिए बिलों पर ब्याज दर वह निर्धारित की गयी जो नयी उच्चतम ऋण दरों से एक प्रतिशत कम है इस प्रकार से अप्रैल, 1987 से बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे इस प्रकार के कर्जदारों के लिए बिल भुनाई दर उस स्तर पर नियत करेंगे जो 15.5 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर के बराबर हो, जो वास्तव में इस समय मौजूदा स्तर से दो प्रतिशत अंक कम पड़ता है।

पुनर्भुनाई दर में वृद्धि

81. पहली अप्रैल 1987 से पुनर्भुनाई दर की उच्चतम सीमा 11.5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी। हालांकि बिलों के लिए भुनाई और पुनर्भुनाई दरों के बीच अंतर उनके उच्चतम स्तरों पर 2.5 प्रतिशत अंक से कुछ अधिक तक कम किया गया है, लेकिन इस उपाय से, अनुमान है, पुनर्भुनाई बाजार में अतिरिक्त निधियां आयेंगी और इससे जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को मांग बाजार से पुनर्भुनाई बाजार की ओर अधिक रूप से जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

पुनर्भुनाई बाजार में सहभागिता

82. रिजर्व बैंक फिलहाल पुनर्भुनाई बाजार में संस्थाओं के प्रवेश को हरेक मामले के आधार पर नियंत्रित करना जारी रखेगा। हालांकि पुनर्भुनाई बाजार के लिए पहुंच वर्तमान की अपेक्षा कम प्रतिबंधक होगी।

बिल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उपाय

83. भुनाई दर कम करने (बिल प्रणाली को कर्जदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए) और पुनर्भुनाई दर बढ़ाने (पुनर्भुनाई बाजार में निधियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए) के अलावा बिल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये गये।

(1) बिलों के माध्यम से वित्तपोषित प्राप्य माल का अनुपात

84. ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी पार्टियों (निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों) के मामले में 1 अप्रैल 1988 से प्राप्य माल की जमानत पर नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं तय करते समय पात्र प्राप्य माल का केवल 75 प्रतिशत बैंकों द्वारा निर्धारित सामान्य मार्जिन की शर्त पर वित्तपोषण के लिए विचार में लिया जायेगा। शेष ऋण आवश्यकता के लिए मांग/मीयादी बिलों के माध्यम से वित्त प्रदान किया जा सकता है। जिन पार्टियों के मामलों में प्राप्य माल पर वित्तपोषण का अनुपात पहले ही 75 प्रतिशत से कम है, उनके मामले में बैंकों को सूचित किया गया कि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत में प्राप्य माल पर वित्तपोषण के अनुपात को न बढ़ने दें।

(2) तदर्थ बिल सीमाएं मंजूर करने के लिए बैंकों को विवेकाधिकार

85. अप्रैल 1986 में ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आने वाली सभी पार्टियों को अधिक से अधिक 3 महीने तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से वर्तमान कार्यकारी पूंजी सीमा से 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सीमाएं मंजूर करने का बैंकों का विवेकाधिकार 75 लाख रुपये की समग्र उच्चतम सीमा से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। परिचालनों में वृद्धि की स्थिति में बिल सुविधा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन रूप में, अतिरिक्त सीमाओं को अस्थायी रूप से मंजूर करने के लिए वर्तमान अधिकारों के अलावा, एक अलग अतिरिक्त अंतर्देशीय बिल सीमा बैंकों द्वारा प्रदान करने की अनुमति है, जो कि तीन महीनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी और मौजूदा बिल सीमा के 10 प्रतिशत तक के बराबर राशि तक के लिए होगी और यह 1 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के भीतर होगी।

(3) उधार (प्रत्यय) खरीद के लिए बिल स्वीकरण संबंधी शर्त

86. ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली सभी पार्टियों (निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों) से यह अपेक्षा की गयी थी कि ये उधार खरीदारी के बिल स्वीकरण का 25 प्रतिशत का अनुपात 1 अप्रैल 1988 तक प्राप्त कर लें। जिन मामलों में यह अनुपात निर्धारित स्तर से कम था, बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने ग्राहकों को यह सूचित करें कि वे निर्धारित अनुपात प्राप्त करने के लिए क्रमशः वृद्धि करें। जो पार्टियां निर्धारित अनुपात से अधिक पहले ही प्राप्त कर चुकी थीं, उनके मामले में उसे कम न होने देने और वस्तुतः उधार खरीद के लिए बिल स्वीकरण के अनुपात में वृद्धि करने के लिए कहा गया। निर्धारित अनुपात पर दृढ़ रहना इस बात पर विचार करने के लिए एक मुख्य आवश्यकता होगी कि कोई खाता संतोषजनक रूप से परिचालित किया जा रहा है या नहीं और एक प्रारम्भिक अवधि के बाद विशिष्ट प्रोत्साहन/हतोत्साहन करने के उपाय तय किये जायेंगे।

'182–दिवसीय खजाना बिल' पुनर्वित सुविधा लागू करना

87. पहली अप्रैल 1987 से '182-दिवसीय खजाना बिल' पुनर्वित सुविधा लागू की गयी, जिसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, 182-दिवसीय खजाना बिलों की बैंकों की धारिता के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का पुनर्वित प्रदान किया जाता है । यह पुनर्वित्त 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर होता है।

बिल गृह की स्थापना

88. रिजर्व बैंक ने सिद्धांतः यह निर्णय किया है कि अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखतों का व्यवहार करने के लिए एक वित्त गृह स्थापित किया जाये, जिसका प्रमुख उद्देश्य इन लिखतों को जलनिधि प्रदान करना है यह वित्त गृह सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जायेगा।

89. इस प्रकार, 1987 के कम कामकाज के समय के प्रारंभ में घोषित ऋण नीति संबंधी उपायों में एक व्यापक क्षेत्र निहित था और कुछ उपाय मूलभूत विन्यासगत परिवर्तनों को लागू करने के लिए थे।

मौद्रिसंबंधी उपाय-मई 1987 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता जमाराशियों पर ब्याज दरें

90. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, विशेषकर डालर की ब्याज दरों में वृद्धि होने से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के पास विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों की जमाराशियों पर ब्याज दरें 25 मई 1987 से बढ़ा दीं । 3 वर्षों के लिए मीयादी जमाराशियों पर अदा की जानेवाली उच्चतम दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दी गयी। दो वर्षों और उससे अधिक किन्तु 3 वर्षों से कम अवधिवाली जमाराशियों के लिए दर 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी, एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम अवधिवाली जमाराशियों के लिए दरें 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत तथा 6 महीने और उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम वाली राशियों के लिए यह दरें 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी ।

मुद्रा, ऋण और मूल्यों की प्रवृत्तियां

मुद्रा आपूर्ति

91. व्यूल मुद्रा (एम3) के अर्थ में मुद्रागत विस्तार 1986-87 में 18.5 प्रतिशत (1985-86 के 16,381 करोड़ रुपये की तुलना में 21,918 करोड़ रुपये) था, जो कि 1985-86 के 16.1 प्रतिशत से अधिक था। 1983-84 से 1985-86 के दौरान पिछले तीन वर्षों में औसत वृद्धि दर 17.6 प्रतिशत के लगभग थी, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुपात के संदर्भ में उच्च मानी जा सकती है (सारणी 12)। 1986-87 में एम3 में वृद्धि 17.4 प्रतिशत थी जो, महीनों के अंतिम शुक्रवारों के औसत के आधार पर निकाली गयी है। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक से थोड़ी-सी ही अधिक थी।

92. जनता के पास मुद्रा आपूर्ति (एम1) में 1986-87 के दौरान बिन्दु-दर आधार पर 7,307 करोड़ रुपये (17.0 प्रतिशत) की भारी वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह 3,950 करोड़ रुपये (10.0 प्रतिशत) ही थी (सारणी 12)। किन्तु महीनों के अंतिम शुक्रवारों के औसत के अनुसार एम1 में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई और यह 14.5 प्रतिशत थी।

93. एम3 के घटकों में, जनता के पास मुद्रा और जमाराशि दोनों में ही भारी वृद्धि हुई। जनता के पास मुद्रा में वृद्धि 3,371 करोड़ रुपये अथवा 13.4 प्रतिशत थी, जो 1985-86 की वृद्धि से 2.4 प्रतिशत अंक अधिक थी। बैंकों के पास कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष की 14,229 करोड़ रुपये (18.1 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 18,446 करोड़ रुपये (19.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंकों के पास मांग जमाराशियों में वृद्धि 3,925 करोड़ रुपये (21.6 प्रतिशत) थी जो पिछले वर्ष की 1,793 करोड़ रुपये (11.0 प्रतिशत) की तुलना में दुगुनी से भी अधिक थी । बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों में भी भारी वृद्धि हुई और वह 1985-86 की 12,431 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 14,521 करोड़ रुपये थी, किन्तु 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर 0.6 प्रतिशत अंक कम थी ।

94. $एम_3$ में मुद्रा का वृद्धिशील अनुपात 0.15 था, जो पिछले वर्ष की तुलना में कोई घट-बढ़ नहीं दर्शाता है। अलबत्ता, वर्ष के अंत में $एम_3$ में मुद्रा का अनुपात 1983-84 के 0.23 से घटते हुए 1986-87 में 0.20 तक पहुंच गया, जिससे देश में बैंकिंग की आदत में वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 1986-87 में एम3 की तुलना में मांग जमा राशियों के वृद्धिशील अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई और वह 0.11 से बढ़कर 0.18 हो गया (सारणी 13)।

95. 1986-87 के दौरान $एम_3$ के विस्तार में जिन कारणों का योगदान रहा उनमें सरकार को दिये गये शुद्ध बैंक ऋण में 12,825 करोड़ रुपये (21.9 प्रतिशत) की वृद्धि भी थी जो पिछले वर्ष हुई 9,572 करोड़ रुपये (19.6 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकार को अन्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 1985-86 के 445 करोड़ रुपये (2.3 प्रतिशत) की तुलना में 5,958 करोड़ रुपये (30.4 प्रतिशत)। की तीव्र वृद्धि होने के कारण हुई। सरकार को दिये गये रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में पिछले वर्ष के 9,127 करोड़ रुपये (30.7 प्रतिशत) की तुलना में 6,867 करोड़ रुपये (17.7 प्रतिशत) जितनी कम वृद्धि हुई। वर्ष 1986-87 के दौरान बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में जो तीव्र वृद्धि हुई, वह जहां सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में वृद्धि के फलस्वरूप उनके अधिक आकर्षक होने के कारण थी, वहां बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात का दैनिक आधार पर अनुपालन करने के संबंध में रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी का भी इसमें हाथ रहा।

96 वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण में 1986-87 के दौरान 10,878 करोड़ रुपये (13.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 11,051 करोड़ रुपये (15.6 प्रतिशत) जितनी अधिक वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य रूप से कारण यह था कि वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 1985-86 के 10,750 करोड़ रुपये (15.8 प्रतिशत) की तुलना में 10,515 करोड़ रुपये (13.3 प्रतिशत) जितनी कम वृद्धि हुई। यह ह्रास ऋण की राशि में कमी के कारण हुआ जैसा कि अगले पैरा में बताया गया है।

सारणी 12—मुद्रास्टाक ($एम_3$) में घट-बढ़ (करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान परिवर्तन*							
	1985-86		1986-87@		1986-87 (अप्रैल-जून)		1987-88@ (अप्रैल-जून)	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
	1	2	3	1	5	5	7	8
I. $एम_3$ (क + ख + ग)	+16381	+16.1	+21918	+18.5	+8549	+7.2	+6548	+4.7
(क) जनता के पास मुद्रा	+2504	+11.0	+3371	+13.4	+1490	+5.9	+1939	+6.8
(ख) बैंकों के पास कुल जमा-राशियां (i+ii)	+14229	+18.1	+18446	+19.9	+7038	+7.6	+4695	+4.2
i) मांग जमा राशियां	+1798	+11.0	+3925	+21.6	+1694	+9.3	+210	+1.0
ii) मीयादी जमाराशियां	+12431	+20.0	+14521	+19.4	+5344	+7.2	+4485	+5.0
(ग) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	—352	—58.4	+101	+40.2	+21	+8.4	—86	—24.4
II. $एम_1$ [क + ख (i) + ग]	+3950	+10.0	+7397	+17.0	+3205	+7.4	+2063	+4.0
III. मुद्रा स्टॉक ($एम_3$) के स्रोत (1+2+3+4—5)								
1 सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (अ + आ)	+9572	+19.6	+12825	+21.9	+6773	+11.6	+6030	+8.5
(अ) सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण (i—ii)	+9127	+30.7	+6867	+17.7	+4880	+12.5	+1874	+10.6
i) सरकार पर दावे	+3881	+11.0	+6757	+17.3	+4767	+12.2	+4875	+10.6
ii) मा० रि० बैंक के पास सरकारी जमा राशियां	—5246	—96.7	—110	—61.5	—113	—63.1	+1	+1.4
(आ) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	+445	+2.3	+5958	+30.4	+1893	+9.6	+1206	+4.7
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक का ऋण (अ + आ)	+11051	+15.6	+10878	+13.3	+1814	+2.2	+803	+0.9
(अ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण**	+301	+10.9	+363	+11.8	—17	—0.6	—59	—1.7
(आ) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	+10750	+15.8	+10515	+13.3	+1831	+2.3	+862	+1.0
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ + आ)	+195	+5.9	+1231	+36.0	+274	+7.9	—223	—4.7
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	+299	+9.8	+1251	+37.4	+274	+8.2	—223	—4.9
(आ) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	—104	—44.3	—	—	—	—	—	—
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	+163	+21.0	+201	+21.4	+74	+7.9	—	—

**नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को इसका पुनर्वित्त शामिल नहीं है।

*मार्च/माह के अन्तिम आकड़ों पर आधारित।

@अनन्तिम

	1	2	3	4	5	6	7	8
5 मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं								
(अ+आ)	+4600	+21.1	+3237	+12.2	+336	+1.5	+112	+0.4
(अ) भा०रि० बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	+2991	+38.9	+2183	+20.1	+557	+5.2	—253	—2.0
(आ) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	+1609	+11.4	+1054	+6.7	—171	-1.1	+365	+2.2

नोट. 1. चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा।

सारणी 13—मौद्रिक अनुपात

वर्ष	वर्ष के अन्त में अनुपात					वृद्धिशील अनुपात				
	मु०	मु०	कु० ज०	मांज	मी० ज०	मु०	मु०	कु० ज०	मां० ज०	मी० ज०
	एम 1	एम 3	एम 3	$एम_3$	एम3	एम 1	एम 3	एम 3	एम 3	एम 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1982-83	0.58	0.23	0.77	0.16	0.61	0.57	0.21	0.79	0.15	0.64
1983-84	0.59	0.23	0.77	0.15	0.62	0.64	0.22	0.77	0.12	0.65
1984-85	0.57	0.22	0.77	0.16	0.61	0.17	0.19	0.79	0.20	0.59
1985-86	0.58	0.21	0.79	0.16	0.63	0.63	0.13	0.87	0.11	0.76
1986-87	0.56	0.20	0.79	0.15	0.64	0.46	0.15	0.84	0.18	0.66

मु० : मुद्रा   कु०ज० : कुल जमा   मी०ज० : मीयादी जमा   मां० ज० : मांग जमा

97. बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा की शुद्ध आस्तियों में पिछले वर्ष के 195 करोड़ रुपये की तुलना में 1,251 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

98. राजकोषीय वर्ष 1987-88 की पहली छिमाही के दौरान $एम_3$ में 6,548 करोड़ रुपए (4.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इसमें 8,549 करोड़ रुपए (7.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वृद्धि की यह दर राशि और प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से कम थी। एम 1 में भी कम अर्थात् 3,205 करोड़ रुपए (7.4 प्रतिशत) की तुलना में 2,063 करोड़ रुपए (4.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई इसके घटकों में, जनता के पास चलमुद्रा की वृद्धि दर में वृद्धि हुई और बैंकों के पास मांग और मीयादी जमाराशियों में कम वृद्धि हुई जिससे इसकी संचय दर में मात्र कमी हुई। स्रोतवार, सरकार को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई। वाणिज्य क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में हुई वृद्धि भी काफी कम रही बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा की शुद्ध आस्तियों में कमी हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में इसमें वृद्धि हुई थी।

आरक्षित मुद्रा

99. आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 1986-87 के दौरान 18.2 प्रतिशत (6,904 करोड़ रुपए) रही जो पिछले वर्ष के 20.3 प्रतिशत (6,381 करोड़ रुपए) की तुलना में कम थी। महीनों के औसत की दृष्टि से भी आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 17.3 प्रतिशत रही जो 1985-86 की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक कम थी। इसके घटकों में जनता के पास चलमुद्रा में 1985-86 के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 में 13.4 प्रतिशत जितनी तेज वृद्धि हुई और वृद्धिशील आरक्षित मुद्रा में इसका अंश सर्वाधिक रहा (सारणी 11)। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा में वृद्धि की दर कम रहने का कारण यह था कि 1985-86 की तुलना में सरकार को दिए गए रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार को रिजर्व बैंक के ऋण और आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 1985-86 की तुलना में 1986-87 में कम रही, हालांकि 1985-86 की तुलना में 1986-87 में सरकार के बजट का घाटा अधिक था। पिछले वर्षों के विपरीत, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक (नए ऋणों के नकद अभिदानों को हिसाब में लेते हुए) प्रतिभूतियों की शुद्ध बिक्री करने में सफल रहा।

सारणी 14—प्रारक्षित मुद्रा घट-बढ़ : घटक तथा स्रोत

(करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़			
	1985-86 (अप्रैल—जून)	1986-87 (अप्रैल—जून)	1986-87 (अप्रैल—जून)	1987-88 (अप्रैल—जून)
1	2	3	4	5
प्रारक्षित मुद्रा (1+2+3+4)	+6381	+6904	+3919	+4395
	(+20.3)	(+18.2)	(+10.4)	(+9.8)
1. जनता के पास मुद्रा	+2504	+3371	+1490	+1939
	(+11.0)	(+13.4)	(+5.9)	(+6.8)
2. भा०रि० बैंक के पास अन्य जमाराशियां	—352	+101	+21	—86
	(+58.4)	(+40.2)	(+8.4)	(—24.4)
3. बैंकों के पास नकदी	+89	+73	+438	+310
	(+7.4)	(+5.7)	(+33.9)	(+22.7)
4. भा० रिज़र्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशियां	+4140	+3359	+1970	+2232
	(+59.1)	(+30.1)	(+17.7)	(+15.4)
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत (1+2+3+4+5+6)				
1. सरकार को भा० रि० बैं० का शुद्ध ऋण	+9127	+6867	+4830	+4874
	(+30.7)	(17.7)	(+12.5)	(+10.6)
2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक के दावे@	—519	+405	—734	—449
	(—19.5)	(+17.7)	(—32.1)	(+16.7)
3. वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक के ऋण	+301	+363	—17	—59
	(+10.9)	(+11.8)	(—0.6)	(—1.7)
4. भा० रि० बैं० की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	+299	+1251	+274	—223
	(+9.3)	(+37.4)	(+8.2)	(—4.9)
5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	+163	+201	+74	—
	(+21.0)	(+21.4)	(+7.9)	—
6. भा०रि०बैं० की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	+2991	+2183	+557	—253
	(+38.9)	(+20.4)	(+5.2)	(—2.0)

* अंतिम @नाबार्ड सहित

टिप्पणी : 1. चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े घट-बढ़ दर्शाते हैं।

100 राजकोषीय वर्ष 1987-88 की प्रथम तिमाही के दौरान प्रारक्षित मुद्रा में 9.8 प्रतिशत (4,395 करोड़ रुपये) जितनी कम वृद्धि हुई जबकि 1986-87 में इसी अवधि के दौरान इनमें 10.4 प्रतिशत (3,919 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई थी। प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि दर में तिमाही के दौरान जो कमी हुई वह सरकार को दिये गये रिज़र्व बैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि की दर कम होने और इसकी विदेशी मुद्रा की शुद्ध आस्तियों में कमी होने के कारण थी।

बैंकिंग चलराशियों में घट-बढ़

101. वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित प्रमुख बैंकिंग चलराशियों में घट-बढ़ की प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि जमाराशियों और निवेशों में जहां काफी वृद्धि हुई वहां ऋण विस्तार में कमी आई (सारणी 15) वर्ष के दौरान समग्र जमाराशियों में हुई वृद्धि की राशि 17,340 करोड़ रुपए थी। यह पिछले वर्ष के 13,160 करोड़ रुपए के स्तर से काफी अधिक थी। जमाराशियों में वृद्धि की दर भी 1985-86 के 18.2 प्रतिशत की तुलना में अधिक अर्थात 20.3 प्रतिशत थी (सारणी 15)।

102. घटकवार, मांग जमाराशियों में 23.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि 1985-86 में यह दर 10.5 प्रतिशत थी, इसके विपरीत मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 20.1 प्रतिशत की तुलना में कम अर्थात् 19.7 प्रतिशत थी। यह उल्लेखनीय है कि मांग जमाराशियों की वृद्धि में क्रमिक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति बनी रही और वृद्धि दरों में क्रमशः वृद्धि और कमी होती रही।

103. बैंक ऋण में 7,169 करोड़ रुपए की जो वृद्धि हुई वह राशि की दृष्टि से 1985-86 के दौरान 7,114 करोड़ रुपए की हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी, परन्तु वृद्धि की दर 12.8 प्रतिशत रही जो 1.5 प्रतिशत अंक जितनी कम थी। खाद्य ऋण में 1986-87 में 404 करोड़ रुपए जितनी अधिक वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसमें 130 करोड़ रुपए की कमी हुई थी। खाद्य ऋण में यह कमी सरकार के इस निर्णय के कारण हुई कि भारतीय खाद्य निगम को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वह बकाया खाद्य ऋण का आंशिक भुगतान कर सके। परन्तु खाद्येतर ऋण में 7,573 करोड़ रुपए जितनी अधिक वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में इसमें 7,244 करोड़ की वृद्धि हुई थी। खाद्येतर गैर पेट्रोलियम बैंक ऋण में भी 1986-87 में 7,827 करोड़ रुपए जितनी अधिक वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसमें 6,943 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

104. बैंकों के निवेशों में 1986-87 में 8,081 करोड़ रुपए (26.4 प्रतिशत) की अत्यधिक तीव्र वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में

1986-87 में 2,115 करोड़ रुपए (3.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। निवेशों में, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में जो भारी बढ़ोतरी हुई वह मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों की लाभ प्राप्ति दर में परिवर्तन किए जाने और अंशतः सांविधिक चलनिधि अनुपात के व्यतिक्रमों के संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू करने के फलस्वरूप बैंकों द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं का बेहतर अनुपालन किए जाने के कारण थी।

103. बैंकों की हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक के पास उनकी शेष राशियों में 1985-86 के 4,252 करोड़ रुपए की तुलना में 3,372 करोड़ रुपए जितनी कम वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक से लिए गये उधारों में 339 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष इनमें 604 करोड़ रुपए की कमी हुई थी।

106. वित्तीय वर्ष 1987-88 की पहली तिमाही (अर्थात् 27 मार्च, 1987 से 26 जून, 1987 तक) की अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यकलाप निम्न स्तर पर रहे और प्रमुख बैंकिंग चलराशियों में घट-बढ़ अर्थात् समय जमाराशियां, बैंक ऋण और बैंकों के निवेश जैसी बैंकिंग चलराशियों में वृद्धि की दर में कमी आयी। जमाराशि में वृद्धि की दर 4,,601 करोड़ रुपए (4.5 प्रतिशत) रही जो 1986-87 की तदनुरूप तिमाही के 6,424 करोड़ रुपए अथवा 7.5 प्रतिशत की तुलना में राशि और प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से कम थी। बैंक ऋण में 517 करोड़ रुपए (0.8 प्रतिशत) का जो विस्तार हुआ वह 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान में हुए विस्तार अर्थात् 1,162 करोड़ रुपए (2.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था। यह विस्तार पूरी तरह से खाद्य ऋण में अप्रैल-जून, 1986 के दौरान हुई 876 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 174 करोड़ रुपए की कमी

सारणी 15—महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उतार-चढ़ाव

(अनुसूचित वाणिज्य बैंक)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मदें	निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि			निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में घट-बढ़		तिमाही उतार-चढ़ाव	
		28 मार्च 1986	27 मार्च 1987*	26 जून 1987*	1985-86	1986-87	1986 (अप्रैल-जून)	1987 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कुल मांग एवं मीयादी देयताएं (इसमें भा.रि.बैं. भा.औ.वि.बैं/नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं)	97024	114914	120506	+15139	+17890	+6377	+5592
2	कुल जमाराशियां (क+ख)	85404	102744	107345	+13160 (+18.2)	+17340 (+20.3)	+6424 (+7.5)	+4601 (+4.5)
	(क) मांग जमाराशियां	15612	19234	19383	+1481 (+10.5)	+3622 (+23.2)	+1381 (+8.8)	+149 (0.8)
	(ख) मीयादी जमाराशियां	69792	83510	87962	+11679 (+20.1)	+13718 (+19.7)	+5043 (+7.2)	+4452 (+5.3)
3.	रिज़र्व बैंक से उधार	954	1293	1136	—604	+339	—410	—157
4.	बैंक ऋण	56067	63236	63753	+7114 (+14.3)	+7169 (+12.8)	+1162 (+2.1)	+517 (+0.8)
	(क) खाद्य ऋण	5535	5131	4957	—130	—404	+876	—174
	(ख) गैर-खाद्य ऋण	50532	58796	58414	+7244 (+16.7)	+7573 (+15.0)	+286 (+0.6)	+691 (+1.2)
5.	निवेश (क+ख)	30553	38634	40387	+2415 (+8.6)	+8081 (+26.4)	+2526 (+8.3)	+1753 (+4.5)
	(क) सरकारी प्रतिभूतियां	19044	24897	26093	+347 (+1.9)	+5853 (+30.7)	+1852 (+9.7)	+1196 (+4.8)
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	11509	13737	14294	+2068 (+21.9)	+2228 (+19.4)	+674 (+5.9)	+557 (+4.1)
6	हाथ में नकदी	1127	1172	1481	+83	+45	+388	+309
7.	भा.रि.बैं. के पास शेष राशियां	11053	14380	16572	+4169 (+60.6)	+3327 (+30.1)	+1887 (+17.1)	+2192 (+15.2)
8.	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	65.6	61.5	59.4				
9.	निवल ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	59.2	56.6	54.8				

*संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े घट-बढ़ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

सारणी 16—मांग जमाराशियों में वृद्धि (प्रतिशत रूप में)

मांग जमाराशियां	निम्नलिखित के दौरान प्रतिशत रूप में वृद्धि					
	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
बिन्दुवार आधार पर . . .	7.5	19.1	13.3	24.9	10.5	23.2
बारह महीनों के औसत के आधार पर .	19.3	11.6	14.1	17.0	18.9	17.7

होने के कारण हुआ। इसके विपरीतर खाद्येत्तर ऋण में पिछले वर्ष की तुलनात्मक तिमाही के 286 करोड़ रुपए की तुलना में 691 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। बैंकों के निवेशों में 1,753 करोड़ रुपए (4.5 प्रतिशत) की जो वृद्धि हुई वह1986-87 की पहली तिमाही के दौरान हुई वृद्धि अर्थात् 2,526 करोड़ रुपए (8.3 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम थी।

ऋण-जमा अनुपात

107. प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में लागू होने वाले नीति विषयक निर्णयों के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात के समग्र स्तर में हाल ही के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति पायी जा रही है; ऋण-जमा अनुपात जून, 1981 के अन्त के 65.5 प्रतिशत से घटकर जून, 1986 के अन्त तक 62.3 प्रतिशत और जून, 1987 के अन्त तक और भी घटकर 59.4 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में मार्च, 1979 तक ऋण-जमा अनुपात के लिए 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया था; ग्रामीण शाखाओं के संबंध में तो यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है परन्तु अर्ध-शहरी शाखाओं में इसे प्राप्त नहीं किया जा सका है।

108. क्षेत्रवार आंकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के ऋण-जमा अनुपात के संबंध में उल्लेखनीय अन्तर-क्षेत्रीय विभिन्नताएं विद्यमान हैं। जून, 1985 के अन्त के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुपात उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 42.2 प्रतिशत से पश्चिमी क्षेत्र के लिए 81.5 प्रतिशत के बीच रहा। ऋण के उपयोग के आधार पर तदनुरूप, अनुपात 65.9 प्रतिशत और 80.3 प्रतिशत थे। परन्तु यदि ऋण के उपयोग के अलावा, राज्य-स्तरीय प्रतिभूतियों और बांडों में किये गये निवेशों को भी हिसाब में लिया जाए तो कुछ क्षेत्रों के संबंध में इस अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। केवल ऋण मंजूरियों के आधार पर, जून, 1985 के अन्त में ऋण-जमा अनुपात उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 42.2 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र के लिए 53.8 प्रतिशत और मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए 48.5 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत, उपयोग किये गये ऋण और निवेशों की दृष्टि से विचार करने पर, ऋण और निवेश सहित जमा के अनुपात, उन्हीं क्षेत्रों के लिए क्रमश: 89.8 प्रतिशत, 66.8 प्रतिशत और 63.8 प्रतिशत बैठते हैं। दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि इतनी अधिक स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक सांख्यिकीय निर्देशक के रूप में ऋण-जमा अनुपात के अपने उपयोग हैं, फिर भी इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में जमाराशियों का आधार बड़ा है, उनमें कम ऋण-जमा अनुपात से भी प्रति-व्यक्ति ऋण की ऊंची उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है जबकि जिन राज्यों में जमाराशियों का आधार छोटा है उनमें यह आवश्यक नहीं है कि अधिक अनुपात होने पर भी प्रति व्यक्ति-ऋण की मात्रा अधिक हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो, क्योंकि इनके निर्धारण के लिए ऋण-जमा अनुपात केवल एक निर्देशक है।

ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

109. ऋण के क्षेत्रवार वितियोजन* से संबंधित आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सकल बैंक ऋण में 7,330 करोड़ रुपये (13.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 7,257 करोड़ रुपये (15.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। खाद्य वसूली के लिए दिये गये बैंक ऋण में 404 करोड़ रुपये की हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसमें 130 करोड़ रुपये जितनी कम कमी हुई थी। खाद्येतर सकल बैंक ऋण में 7,734 करोड़ रुपये (15.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1985-86 के दौरान इसमें 7,387 करोड़ रुपये (17.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी (सारणी 17)।

110. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण में 1985-86 के 3,157 करोड़ रुपये की तुलना में 1986-87 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक, अर्थात् 3,493 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मार्च, 1987 के अन्त तक शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का अंश 42.3 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पहले इसका अंश 43.8 प्रतिशत था।

111. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में हुई कुल वृद्धि में कृषि और लघु उद्योगों का अंश क्रमश: 1,530 करोड़ रुपये (43.8 प्रतिशत) और 1,287 करोड़ रुपये (36.8 प्रतिशत) था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इनका अंश क्रमश: 1,398 करोड़ रुपये (44.3 प्रतिशत) और 1,204 करोड़ रुपये (38.1 प्रतिशत) था। मार्च, 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 10,588 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में एक वर्ष पहले यह राशि 9,058 करोड़ रुपये थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों में इसका अंश वर्ष के दौरान थोड़ा-सा बढ़कर 42.3 प्रतिशत हो गया। लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की राशि 9,103 करोड़ रुपये थी और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल ऋण में इसका अंश 36.3 प्रतिशत रहा, यह अनुपात एक वर्ष पहले के 36.2 प्रतिशत के निकट रहा। अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को, जिनमें छोटे परिवहनचालक, स्वनियोजित व्यक्ति, ग्रामीण कारीगर, आदि शामिल हैं, दिये गये अग्रिमों की राशि बढ़कर 5,368 करोड़ रुपये हो गयी और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों में मार्च, 1987 में इनका अंश 21.4 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलना में मार्च 1986 में इनकी राशि 4,692 करोड़ रुपये या 21.8 प्रतिशत थी।

112. 1986-87 के दौरान मझोले और बड़े उद्योगों को दिये गये अग्रिमों में 3,017 करोड़ रुपये (15.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़ाकर 22,187 करोड़ रुपये हो गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान इनमें 3,231 करोड़ रुपये (20.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी, और इनकी राशि बढ़कर 19,170 करोड़ रुपये हो गयी थी, पेट्रोलियम को छोड़कर यह वृद्धि क्रमश: 3,271 करोड़ रुपये (17.4 प्रतिशत) और 2,930 करोड़ रुपये (18.5 प्रतिशत) थी।

*आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं (सारणी 17 देखें)

सारणी 17—प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण* (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित महीने के अन्तिम शुक्रवार को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	मार्च 1985	मार्च 1986	मार्च 1987	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
I. सकल बैंक ऋण (1+2)	47956	55213	62543	+7257	+7330
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	5665	5535	5131	—130	—404
2. गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण	42291	49678	57412	+7387 (100.0)	+7734 (100.0)
(अ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	18409	21566	25059	+3157 (42.7)	+3493 (45.2)
(i) कृषि	7660	9058	10588	+1398 (18.9)	+1530 (19.7)
(ii) लघु उद्योग	6612	7816	9103	+1204 (16.3)	+1287 (16.6)
(iii) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	4137	4692	5368	+555 (7.5)	+676 (8.7)
(आ) उद्योग (मझोले और बड़े)	15939	19170	22187	+3231 (43.7)	+3017 (39.0)
(इ) थोक व्यापार (खाद्य वसूली के अलावा)	2649	3066	3072	+417 (5.7)	+6 (0.1)
(i) भारतीय रूई निगम	135	160	109	+25 (0.3)	—51 (—0.7)
(ii) उर्वरक वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम	166	141	149	—25 (—0.3)	+8 (0.1)
(iii) भारतीय जूट निगम	116	127	198	+11 (0.1)	+71 (0.9)
(iv) अन्य व्यापार	2232	2638	2616	+406 (5.5)	—22 (—0.3)
(ई) अन्य क्षेत्र	5294	5876	7094	+582 (7.9)	+1218 (15.7)
II. निर्यात ऋण मद (2) के अन्तर्गत शामिल	2335	2409	3143	+7	7

*अनन्तिम

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं, जिनका हिस्सा सकल बैंक में 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में भारिबैं, भाऔवि, विबैं, निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पुनः भुनाये गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गैर-खाद्य वृद्धिशील ऋण के अनुपात हैं।

113. बैंक ऋण का उद्योगवार (लघु उद्योग सहित) वितरण सारणी 18 में दर्शाया गया है। 1986-87 में ऋण की वृद्धि में जिन उद्योगों का अंश सर्वाधिक था, वे थे—इंजीनियरी समूह (1,177 करोड़ रुपये), रसायन समूह (509 करोड़ रुपये), लोहा और इस्पात (363 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र (290 करोड़ रुपये), अन्य वस्त्र (172 करोड़ रुपये) और अन्य उद्योग (1,267 करोड़ रुपये)। जिन उद्योगों के मामले में काफी कमी हुई, वे थे : पेट्रोलियम (254 करोड़ रुपये) और नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज (44 करोड़ रुपये)।

114. थोक व्यापार (खाद्य वसूली को छोड़कर) को दिये गए अग्रिमों में 1986-87 के दौरान 6 करोड़ रुपये जितनी मामूली वृद्धि हुई, 1985-86 में इसमें 417 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

115. अवशिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले 'अन्य क्षेत्रों' को दिये गये ऋण में, जिनमें वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों, लीजिंग कंपनियों, वैयक्तिक ऋणों, आदि को दिये गये अग्रिम शामिल हैं। पिछले वर्ष हुई 582 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1,218 करोड़ रुपये जितनी अधिक वृद्धि हुई।

116. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित नीति विषयक परिवर्तनों के बारे में, ऋण नीति विषयक गतिविधियों की जानकारी देते समय पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

117. विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के उपयोग संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है :

खाद्य ऋण पुनर्वित्त

118. खाद्य ऋण की बकाया राशियों का स्तर मार्च, 1986 के अन्त में चूंकि 5,800 करोड़ रुपये के न्यूनतम स्तर से कम था, इसलिए बैंक खाद्य पुनर्वित्त के पात्र नहीं थे। जून, 1986 में सूचना देने के अन्तिम शुक्रवार को बैंकों की खाद्य ऋण पुनर्वित्त सीमाएं 736 करोड़ रुपये थी.

थीं, जिसमें 34 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्य ऋण पुनर्वित्त सीमाओं का शिखर स्तर 866 करोड़ रुपये था, यह स्तर 18 जुलाई, 1986 को रहा जबकि इसी तारीख को बकाया राशि 281 करोड़ रुपये (उपयोग अनुपात 32.4 प्रतिशत) थी।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

119. बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं 27 मार्च, 1987 को 894 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गयीं जबकि वर्ष के दौरान सर्वोच्च बकाया राशि उसी तारीख को 778 करोड़ रुपये थी जबकि 87.0 प्रतिशत सीमाओं का उपयोग हुआ था। 19 जून, 1987 को इस सुविधा के अन्तर्गत सीमाओं की राशि 1,372 करोड़ रुपये थी जिसमें से 343 करोड़ रुपये या 25.0 प्रतिशत का उपयोग किया गया।

सहायक पुनर्वित्त सीमाएं

120. बैंकों को मंजूर की गयी सहायक पुनर्वित्त सीमाओं की राशि मार्च, 1996 में सूचना देने के अन्तिम शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये थी जिसमें से 40 करोड़ रुपये या 80.0 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। 1985-86 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी सहायक पुनर्वित्त सीमाओं की अधिकतम राशि 25 अप्रैल, 1986 को 40 करोड़ रुपये थी और इस पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया था। 27 मार्च, 1987 को इस सुविधा के अन्तर्गत सीमाओं की राशि 14 करोड़ रुपये थी जिसका पूर्ण उपयोग किया गया था जबकि 19 जून, 1997 को 50 करोड़ रुपये की सीमाओं का उपयोग नहीं किया गया था।

सारणी 18—संकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण* (अन्तिम शुक्रवार को)

(करोड़ रुपये)

उद्योग	निम्नलिखित महीने के अन्तिम शुक्रवार को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	मार्च 1985	मार्च 1986	मार्च 1987	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु उद्योग, मझोले और बड़े उद्योगों को जोड़)	22531	26986	31290	+4435	+4304
1. कोयला	119	93	160	-26	+67
2. लोहा और इस्पात	1430	1270	1633	-160	+363
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद	801	958	1050	+157	+92
4. सभी इंजीनियरिंग	5560	6760	7937	+1200	+1177
5. बिजली	416	493	532	+78	+39
6. सूती वस्त्र	1869	2169	2459	+300	+290
7. जूट वस्त्र	263	274	298	+11	+24
8. अन्य वस्त्र	1365	1039	1811	+274	+172
9. चीनी	428	536	550	+108	+14
10. चाय	295	320	387	+25	+67
11. वनस्पति तेल (वनस्पति घी सहित)	311	347	386	+36	+39
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	159	184	228	+25	+44
13. कागज और कागज उत्पाद	596	672	798	+76	+126
14. रबड़ और रबड़ उत्पाद	434	460	513	+26	+53
15. रसायन, रंग पेण्ट आदि	2325	3156	3665	+831	+509
जिनमें से: उर्वरक	(361)	(700)	(852)	(+339)	(+152)
16. सीमेंट	282	351	472	+69	+121
17. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	323	376	420	+53	+44
18. निर्माण	265	285	379	+20	+94
19. पेट्रोलियम	72	373	119	+301	-254
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज	376	326	282	-50	-44
21. बाकी उद्योग	4863	5944	7211	+1081	+1267

* अनन्तिम

विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाएं

121. विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा की सुविधा आशयों से उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 30 अक्तूबर, 1986 से सभी लाइसेंस-प्राप्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को विवेकाधीन पुनर्वित्त का आहरण करने की अनुमति दी गयी थी। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक अपनी 1985-86 (अप्रैल-मार्च) की औसत जमा राशियों के 0.5 प्रतिशत जितनी राशि तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से 14 दिन से अनधिक अवधि और उसके बाद 14 दिन की "राहत" अवधि के लिए विवेकाधीन पुनर्वित्त का आहरण कर सकते हैं। अपवादतः, जो बैंक 14 दिन से अधिक अवधि के किसी अवधि खण्ड के लिए अथवा निर्धारित सीमा से अधिक किसी राशि के लिए विवेकाधीन पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस योजना के अन्तर्गत कुल विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 388 करोड़ रुपये थी। विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की 28 मार्च, 1986 को कुल राशि 398 करोड़ रुपये थी जिसमें से 337 करोड़ रुपये अथवा 84.7 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। 27 मार्च, 1987 को विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं का स्तर 458 करोड़ रुपये था; यह 1986-87

की अवधि के दौरान प्राप्त सर्वोच्च स्तर भी था। इसमें से 204 करोड़ रुपये अथवा 44.8 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। 1986-87 के दौरान बैंकों द्वारा विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं का समग्र उपयोग कम रहा। 19 जून, 1987 तक 389 करोड़ रुपये की विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था।

समग्र स्थिति

122. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कुल सीमाओं की राशि (पोतलदान ऋणों और मुल्क वापसी पर दिये जाने वाले विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) जो 28 मार्च, 1986 को 787 करोड़ रुपये थी, 12 सितम्बर, 1986 को घटकर 402 करोड़ रुपये के अपेक्षाकृत कम स्तर पर पहुंच गयी। 28 मार्च, 1986 को सीमाओं का उपयोग 629 करोड़ रुपये या 79.9 प्रतिशत जितना था। 27 मार्च, 1987 को कुल पुनर्वित्त सीमाओं की समग्र राशि 1,363 करोड़ रुपये थी जिसमें से 995 करोड़ रुपये या 73.0 प्रतिशत का उपयोग किया गया था जबकि 19 जून, 1987 को कुल पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 1,847 करोड़ रुपये थी जिसमें से 343 करोड़ रुपये या 18.6 प्रतिशत का उपयोग किया गया था (सारणी 19)।

सारणी 19—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता

(जहाजरानी ऋणों पर विशेष पुनर्वित्त तथा मुल्क वापसी को छोड़कर) (करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार को	खाद्य ऋण पुनर्वित्त		निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आपाती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1986										
मार्च	--	--	339.3	252.7	50.0	40.0	398.0	336.5	787.3	629.2
जून	736.1	33.6	510.4	68.6	--	--	46.0	1.0	1292.5	103.2
सित.	--	--	463.3	89.1	--	--	--	--	463.3	89.1
दिस.	--	--	634.7	111.3	--	--	388.3	--	1023.0	111.3
1987										
मार्च	--	--	894.1	777.5	14.0	14.0	455.0	203.6	1363.1	995.1
जून	--	--	1372.4	343.4	50.0	--	389.4	-	1846.8*	343.4

* इनमें 35.0 करोड़ रुपये की 182 दिवसीय खाद्यान्न वित्त पुनर्वित्त सुविधायें शामिल हैं।

ऋणों के बजट

123. आलोच्य अवधि के दौरान 54 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों के बजटों की जांच की गयी। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों और 9 विदेशी बैंकों के प्रमुख कार्यपालकों के साथ जून-अगस्त 1986 की अवधि के दौरान विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान बैंकों को इस बात के लिए जोर दिया गया कि वे अपनी योजनाएं अग्रिम रूप से बनायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमी के लिए 4 प्रतिशत की छूट सीमा की समाप्ति सरलतापूर्वक हो। बैंकों का ध्यान इस लक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया कि मौद्रिक लक्ष्यों, विशेष रूप से सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण पर अधिक जोर दिए जाने के कारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकदी शेष राशियों में तीव्र उतार-चढ़ाव से बचना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में बैंकों द्वारा नकदी के बेहतर प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपने उधार संबंधी क्रियाकलापों को स्वयं अपने साधनों के आधार पर नियोजित करें और मुद्रा बाजार की अनिश्चित उतार-चढ़ाव वाली निधियों पर ज्यादा निर्भर न रहें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि ऋण का जो बजट बनाया जाये, उसमें वास्तविक कारोबार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

मूल्य स्थिति

124. थोक मूल्यों में 1986-87 में बिन्दुवार आधार पर 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1985-86 में इसमें 3.8 प्रतिशत और 1984-85 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अलबत्ता, साप्ताहिक औसत आधार पर यह वृद्धि 5.4 प्रतिशत थी जो 1985-86 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में मामूली-सी कम थी।

125. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत मूल्यों में बिन्दुवार आधार पर 1986-87 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अलबत्ता, औसत के आधार पर मूल्यों में 1986-87 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1985-86 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।

126. थोक मूल्य सूचकांक का बिन्दुवार आधार पर समूहवार विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि 1986-87 में हुई वृद्धि में सर्वाधिक अंश प्राथमिक वस्तुओं और निर्मित उत्पादों का था। इस प्रकार, प्राथमिक वस्तुओं के समूह में 1985-86 के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्मित उत्पादों के समूह में भी 1985-86 के 3.1 प्रतिशत की तुलना में 6.3 प्रतिशत जितनी अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, ईंधन, बिजली आदि समूह में 1985-86 के 8.9 प्रतिशत की तुलना में 2.8 प्रतिशत जितनी कम वृद्धि हुई (सारणी 20)।

127. थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि में प्रमुख पण्य समूहों के भार की दृष्टि से योगदान के आंकड़े सारणी 21 में दिये गये हैं।

128. निर्मित उत्पाद समूह, जिसका सूचकांक में भार 50.0 प्रतिशत है, का मूल्य वृद्धि में योगदान 56.5 प्रतिशत रहा जबकि 1985-86 के दौरान यह योगदान 38.5 प्रतिशत था। प्राथमिक वस्तु समूह, जिनका सूचकांक में भार 42.0 प्रतिशत रहा, का मूल्य वृद्धि में योगदान 1985-86 के 29.1 प्रतिशत की तुलना में 35.9 प्रतिशत रहा। मूल्य वृद्धि

में सबसे कम योगदान ईंधन, बिजली आदि के समूह का रहा जिसका सूचकांक में भार केवल 8 प्रतिशत है; 1986-87 में हुई वृद्धि में इसका योगदान 7.6 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में इसका योगदान 32.4 प्रतिशत था।

	थोक मूल्य सूचकांक					
	भार	मार्च के अंत में			जून के अंत में	
		1985	1986	1987	1986	1987
1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य	1000.00	346.3	359.3	378.2	374.5	394.6
प्राथमिक वस्तुएं	416.67	321.6	330.7	347.0	344.9	370.3
ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	84.59	559.2	609.2	626.2	618.1	626.2
निर्मित उत्पाद	498.74	330.8	340.9	362.3	357.9	375.6

क्र. सं.	प्रतिशत घट-बढ़				भार की दृष्टि से योगदान			
	राजकोषीय वर्ष		पहली तिमाही		राजकोषीय वर्ष		पहली तिमाही	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1986-87	1987-88
1	8	9	10	11	12	13	14	15
सभी पण्य	+3.8	+5.3	+4.2	+4.3	100.0	100.0	100.0	100.0
प्राथमिक वस्तुएं	+2.8	+4.9	+4.3	+6.7	+29.1	+35.9	+39.0	+59.4
ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	+8.9	+2.8	+1.5	--	+32.4	+7.6	+5.1	--
निर्मित उत्पाद	+3.1	+6.3	+5.0	+3.7	+38.5	+56.5	+55.9	+40.6

129. थोक मूल्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जारी रहे। थोक मूल्य सूचकांक में मूल्यों में वर्ष के शुरू में तेजी से वृद्धि होने से अप्रैल से जुलाई, 1986 के दौरान 5.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में इसी अवधि के दौरान इसमें 5.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी। अगस्त से अक्तूबर, 1986 तक के अगले तीन महीनों में यह वृद्धि 1.4 प्रतिशत अंक जितनी कम रही जबकि इसके विपरीत 1985 में इसी अवधि में इसमें 1.1 प्रतिशत अंक की कमी आयी थी। वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों अर्थात् नवम्बर, 1986 से मार्च, 1987 के दौरान, जो मोटे तौर पर अधिक कामकाज की अवधि का प्रमुख अंश था, मूल्यों में 1985-86 में हुई 0.4 प्रतिशत अंक की कमी की तुलना में 1.7 प्रतिशत अंक की कमी हुई।

130. सारणी 22 में थोक मूल्य सूचकांक की मौसमी प्रवृत्तियां दर्शायी गयी हैं। सारणी में दिये गये प्रमुख समूहों को देखने से यह पता चलता है कि सभी पण्यों में एक जैसी प्रवृत्तियां रहीं। प्राथमिक वस्तुओं के समूह में मौसमी प्रवृत्तियां अधिक स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार, मार्च अन्त से जुलाई अन्त की अवधि के बीच 1986-87 में मूल्यों में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 7.1 प्रतिशत अंक रही जबकि इसकी तुलना में 1985-86 में यह 6.6 प्रतिशत अंक थी। जुलाई अन्त से अक्तूबर अन्त तक की अगली अवधि में इस समूह में 1986-87 में 1.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष के दौरान इसमें 3.3 प्रतिशत अंक की कमी हुई थी। वर्ष के अन्तिम पांच महीनों के दौरान (अक्तूबर अन्त से मार्च अन्त तक) 1986-87 में मूल्यों में हुई कमी काफी तीव्र अर्थात् 3.7 प्रतिशत अंक थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 0.3 प्रतिशत अंक थी। निर्मित उत्पाद समूह में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति भी कमोबेश इसी प्रकार रही।

131. सारणी 23 में मूल्य प्रवृत्तियों का बिन्दुवार आधार पर पण्य-वार विश्लेषण दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि प्राथमिक वस्तु समूह में जिन प्रमुख पण्यों में मौसत वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई, उनमें फल और सब्जियां, दूध और दुग्ध उत्पाद तथा अन्य खाद्य वस्तुएं, रेशे और तिलहन शामिल हैं।

सारणी 21—थोक मूल्य सूचकांक :

मार्च समूहों के भारित योगदान में प्रवृत्तियां

मदें	भार	1985-86	1986-87
1	2	3	4
सभी पण्य	1000.00	100.00	100.00
I. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	+29.1	+35.9
1. अनाज	107.43	+24.0	+07
2 दालें	21.79	+2.8	—4.6
3. फल और सब्जियां	61.32	+31.6	+14.7
4. दूध और दूध से बनी वस्तुएं	61.50	+3.0	+11.4
5. अंडे, मछली और मांस	18.97	+7.1	+6.6
6. अन्य खाद्य पदार्थ	16.04	—11.2	+4.0
7. तिलहन	42.01	—3.8	+15.3
8. रेशे	31.73	—26.8	+8.5
II. ईंधन, पावर, बिजली और चिकनाई वाले पदार्थ	84.59	+32.4	+7.6
9. कोयला खनन	11.47	—7.2	—
10. खनिज तेल	49.12	+6.1	+0.1
11. बिजली	24.00	+19.1	+7.5
III. विनिर्मित वस्तुएं	498.74	+38.5	+56.5
12. डेयरी उत्पाद	3.88	—	+0.3
13. गल्ला मिल उत्पाद	4.61	+0.5	+0.7
14. बेकरी उत्पाद	1.85	+0.2	+0.2
15. चीनी, कन्फेक्शनरी आदि	0.53	+0.1	—
16. चीनी, खाण्डसारी और गुड़	72.41	+18.8	—8.9
17. खाद्य तेल	37.16	—0.3	+21.3
18. तैयार तम्बाकू	19.49	+12.5	+2.5
19. सूती वस्त्र	81.02	—1.0	+5.4
20. जूट, सन तथा मेस्ता वस्त्र	12.14	—16.2	+1.8
21. जूते तथा चमड़े की वस्तुएं	0.90	+0.5	+0.3
22. परिवहन उपकरण	16.73	+6.4	+1.3

टिप्पणी : भारित योगदान 'सभी पण्य' के प्रतिशत के रूप में हैं।

सारणी 22—थोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ावों के तीन चरण

(प्रतिशत रूप में)

	मार्च के अन्त से जुलाई के अन्त तक		जुलाई के अन्त से अक्तूबर के अन्त तक		अक्तूबर के अन्त से मार्च के अन्त तक	
वर्ग	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य	+5.4	+5.6	-1.1	+1.4	—0.4	-1.7
प्राथमिक वस्तुएं	+6.6	+7.1	-3.3	-1.8	—0.3	-3.7
ईंधन, पावर, बिजली तथा चिकनाई के पदार्थ	+1.7	+1.5	+1.4	0.3	+5.6	+1.0
तैयार माल	+5.4	+5.5	0.1	1.4	—2.2	-0.7

सारणी 23—थोक मूल्यों के सूचकांकों में चढ़ाव (1970-71 = 100)

प्रमुख समूह/समूह/उप समूह/पण्य	भार	प्रतिशत घट-बढ़ (बिन्दुवार) निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में			
		1985-86	1986-87	1986-87 (अप्रैल-जून)	1987-88 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	1000.00	+3.8	+5.3	+4.2	+4.3
I. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	+2.8	+4.9	+4.3	+6.7
खाद्य वस्तुएं	297.99	+7.8	+6.5	+4.8	+5.0
(क) अनाज	107.43	+11.9	+0.4	-1.5	+2.8
(i) चावल	51.31	+4.4	+6.7	+5.1	+4.4
(ii) गेहूं	34.17	+16.8	-2.0	-8.6	-2.2
(ख) दालें	21.79	+4.0	-8.8	-9.7	+7.7
(ग) फल और सब्जियां	61.32	+21.8	+12.2	+16.2	+8.8
(घ) दूध और दुग्ध उत्पाद	61.50	+2.4	+12.6	+3.5	+2.3
(ङ) अन्य खाद्य वस्तुएं	16.04	-21.3	+14.1	+20.1	+8.9
चाय	11.49	-23.9	+19.2	+21.5	+7.4

1	2	3	4	5	6
गैर-खाद्य वस्तुएं	106.21	-9.7	+15.5	+4.5	+13.4
(क) रेशे	31.73	-36.9	+27.0	-4.5	+13.4
पटसन	22.46	-25.2	+33.3	-7.8	+17.7
(ख) तिलहन	42.01	-4.1	+24.7	16.0	23.7
खनिज	12.47	+0.6	—30.9	+0.1	+0.1
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6.02	--	+38.4	--	--
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	84.59	+8.9	+2.8	+1.5	--
कोयला	10.39	+13.8	--	--	--
खनिज तेल	49.12	+2.7	+0.1	+0.3	--
बिजली	24.00	+24.2	+11.1	--	--
III. निर्मित उत्पाद	498.74	+3.1	+6.3	+5.0	+3.7
चीनी, खांडसारी और गुड़	72.41	+8.9	-6.2	+14.7	+10.8
(i) चीनी	21.91	+23.2	-0.7	—4.2	+1.6
(ii) गुड़	45.58	+4.8	-7.4	+23.2	+14.4
(iii) खांडसारी	4.92	+21.7	-13.2	-1.0	+9.7
खाद्य तेल	37.16	-0.3	+36.4	+15.1	+17.2
वस्त्र	110.26	-7.9	+8.3	+1.7	+1.1
कागज और कागज उत्पाद	8.51	+3.9	-0.3	-0.1	--
सीमेंट	7.03	-6.0	-0.1	+0.1	-0.8
रसायन और रसायन उत्पाद	55.48	+5.1	+5.4	+1.3	+1.1
लोहा इस्पात और लौहमिश्र धातुएं	34.73	+1.1	+0.7	+0.3	--

132. निर्मित उत्पाद समूह में 1986-87 में जिन प्रमुख मदों में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वृद्धि हुई वे थी : खाद्य तेल (36.4 प्रतिशत) वस्त्र (8.3 प्रतिशत) तथा रसायन और रसायन उत्पाद (5.4 प्रतिशत)।

133. दालें उप-समूह में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। आपूर्ति स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ आयात किये जाने के कारण दालों के मूल्यों में 8.9 प्रतिशत की कमी हुई जबकि पिछले वर्ष इनमें 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

134. तिलहनों और रेशों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसका कारण तिलहनों के आयातों में कमी और रुई के उत्पादन की मात्रा कम होने से आपूर्ति में आयी कमी था। अलबत्ता, रेशों के मूल्यों में वृद्धि को पिछले वर्ष जूट और के मूल्यों में हुई भारी कमी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। हनों और रेशों के मूल्यों में हुई वृद्धि से कृषकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल्य संबंधी प्रोत्साहन मिलने की आशा की जा सकती है।

135. निर्मित उत्पादों के अन्तर्गत खाद्य तेलों और वस्त्रों में हुई मूल्य वृद्धियां तिलहनों और रुई के मूल्यों में तीव्र वृद्धियां होने के फलस्वरूप हुईं, जिनका प उल्लेख किया जा चुका है। इसके विपरीत चीनी, खाण्डसारी और गुड़ के मूल्यों में हुई कमी का कारण उत्पादन की मात्रा अधिक होना था।

136. ईंधन, बिज, आदि के समूह में मूल्यों में इस वर्ष हुई वृद्धि काफी कम थी, मुख्य रूप से इसका कारण यह था कि खनिज तेलों के मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही।

137. 1987-88 की पहली तिमाही के दौरान सामान्य मूल्य स्तर में बिन्दुवार आधार पर 4.3 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही .2 प्रतिशत) के लगभग बराबर थी। हाल ही में जो मूल्य वृद्धि हुई वह प्राथमिक वस्तु समूह के कारण हुई; 1987-88 की पहली तिमाही के दौरान इसमें 6.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ईंधन बिजली, रोशनी और चिकनाई पदार्थ समूह में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई जबकि निर्मित उत्पाद समूह में 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवधि के दौरान हुई वृद्धि में जिन महत्वपूर्ण पण्यों का योगदान रहा वे थे : रेशे, दालें, तिलहन और खाद्य तेल। रेशों और दालों में जहां 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत कमी के विपरीत 13.4 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई, वहां तिलहनों और खाद्य तेलों में क्रमशः 16.0 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत की तुलना में 23.7 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत जितनी अधिक वृद्धि हुई। अलबत्ता, फल और सब्जियां तथा चीनी, खाण्डसारी और गुड़ उप-समूहों में पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही के दौरान हुई क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 8.8 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्देशित मूल्यों में परिवर्तन

138. जो वस्तुएं सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं उनके संबंध में सरकार की मूल्य नीति के उद्देश्य बहुमुखी होते हैं जैसेकि लागत वृद्धि की पूर्ति करना, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य बनाये रखते हुए उत्पादन में वृद्धि करना और आर्थिक सहायता (उपदान) की मात्रा में कमी करना। एक ओर लागतों को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक साधन जुटाने के लिए निर्देशित मूल्यों में वृद्धि करने तथा दूसरी ओर निर्देशित पण्यों की लागत और उनके मूल्यों के बीच की खाई को पाटने के लिए बजटीय संसाधनों से अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थाएं करने के बीच सामान्यतः तालमेल रखा जाता है।

139. कृषि मूल्य नीति में लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था के द्वारा उत्पादन में वृद्धि पर जोर देना जारी रखा गया। सरकार ने 1986-87 और 1987-88 के दौरान अनाजों, दालों, आदि सहित प्रमुख कृषि पण्यों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की।

140. 16 दिसम्बर, 1986 को सरकार ने 1987-88 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के वसूली मूल्य में 4 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा

की जिससे यह बढ़कर 166 रुपये प्रति क्विंटल हो गया । 1987-88 के विपणन मौसम के लिए वसूली मूल्यों में वृद्धि के बाद सरकार ने 9 अप्रैल, 1987 को गेहूं के मध्यवर्ती निर्गम मूल्य में 1 मई, 1987 से 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि घोषित की । तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मध्यवर्ती निर्गम मूल्य विद्यमान 190 रुपये प्रति क्विंटल के बदले 195 रुपये प्रति क्विंटल होगा । समन्वित जनजाति विकास परियोजना क्षेत्रों और जन जाति वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती निर्गम मूल्य 130 रुपये प्रति क्विंटल और उपभोक्ता मूल्य 155 रुपये प्रति क्विंटल होगा जबकि वर्तमान मूल्य क्रमशः 125 रुपये और 150 रुपये प्रति क्विंटल है ।

141. 29, अगस्त, 1986 को 1986-87 के विपणन मौसम के लिए धान के वसूली मूल्य सभी किस्मों—सामान्य, उत्तम और अत्युत्तम के लिए 4 रुपये प्रति क्विंटल की एक-समान वृद्धि की गयी तदनुसार, सामान्य, उत्तम और अत्युत्तम किस्मों के लिए संशोधित मूल्य क्रमशः 146 रुपये, 150 रुपये, और 154 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल के निर्गम मूल्य में भी तीनों किस्मों के लिए 1 अक्तूबर से 8 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी । सामान्य, उत्तम और अत्युत्तम किस्मों के लिए संशोधित दरें क्रमशः 239 रुपये, 251 रुपये और 266 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी । समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम क्षेत्रों और जनजाति राज्यों में वितरण के लिए चावल का मध्यवर्ती निर्गम मूल्य सामान्य किस्म के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तम किस्म के लिए 170 रुपये प्रति क्विंटल और अत्युत्तम किस्म के लिए 185 रुपये प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रखा गया ।

142. मोटे अनाजों का वसूली मूल्य 1986-87 के विपणन मौसम के लिए सितम्बर, 1986 में 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 132 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया ।

143. तूर, मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1986-87 के विपणन मौसम के लिए एक-समान रूप से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये गये । 1987-88 के विपणन मौसम के लिए उपर्युक्त सभी दालों के लिए मूल्यों में एक-समान रूप से 5 रुपये प्रति क्विंटल की और वृद्धि करके उनका मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया । दिसम्बर, 1986 में सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1987-88 के विपणन मौसम के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 280 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया ।

144. तिलहनों के समर्थन मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक सीमा तक वृद्धि की गयी ताकि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके । इस प्रकार मूंगफली (साबुत) के लिए न्यूनतम मूल्य 1986-87 के विपणन मौसम के लिए 22 सितम्बर, 1986 को 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 370 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी बीज के लिए 15 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया । 1987-88 के विपणन मौसम के लिए मूंगफली के मूल्य में दुबारा वृद्धि करके 390 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया । सोयाबीन (पीली और काली किस्में) के मूल्यों में भी 1986-87 के मौसम के लिए क्रमशः 15 रुपये और 5 रुपये की वृद्धि करके 290 रुपये प्रति क्विंटल और 255 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया और उसके बाद 1987-88 के विपणन के मौसम के लिए क्रमशः 300 रुपये और 260 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया ।

145. इसी प्रकार, रुई की एफ-414 और एच-777 किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1986-87 के विपणन मौसम के लिए 5 रुपये बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल और 1987-88 के विपणन मौसम के लिए और बढ़ाकर 440 रुपये प्रति क्विंटल किया गया । गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य जो 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल वसूली से संबद्ध है, उसे बढ़ाकर 1986-87 में 17 रुपये प्रति क्विंटल और 1987-88 के विपणन मौसम के लिए 18 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी के निर्गम मूल्य में 15 दिसम्बर, 1986 से 5 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि करके उसे 4.85 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया । जूट (डब्ल्यू-5 आसाम से) का सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी 1987-88 के विपणन मौसम के लिए 15 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया ।

146. बिजली और रेल की दरों में कुछ वृद्धियां की गयी । कुछ बिजली बोर्डों ने बिजली की दरों में वृद्धियां की जिससे थोक मूल्य सूचकांक में बिजली समूह के मूल्य सूचकांक में 1986-87 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जहां तक रेल दरों का संबंध है, दिसम्बर, 1986 में भाड़ा दरों के सूक्ष्म स्वरूप को इस प्रकार संशोधित किया गया कि उससे माल परिवहन के भाड़ा प्रभारों में वृद्धि हो जाये ।

147. विभिन्न निविष्टियों की लागत में हुई मूल्य वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने दिसम्बर, 1986 में लेवी सीमेंट के प्रतिधारण मूल्य में 24.50 रुपये प्रति टन की वृद्धि करके 399.50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया । चूंकि प्रतिधारण मूल्य की पूर्ति सीमेंट वितियमन लेखे की बचतों से की जानी थी, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए लेवी सीमेंट के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

148. विभिन्न ग्रेडों के एल्यूमिनियम में सरकार ने पहली मार्च, 1987 से वृद्धियां कीं । वाणिज्यिक ग्रेड की धातु का उत्पादन-गुल्क फैक्ट्री मूल्य 21,962 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 26,449 रुपये प्रति टन, विद्युत संवाहक (इलेक्ट्रिक कन्डक्टर) ग्रेड की धातु का मूल्य 22,188 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 27,152 रुपये प्रति टन और विद्युत संवाहक ग्रेड की तार की छड़ों का मूल्य 22,994 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 27,858 रुपये प्रति टन कर दिया । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सरकार ने 2 मार्च, 1987 को एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए नये प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किये ।

149. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के कारण कैप्रोलेक्टम की एकाधिकार आपूर्ति करने वाली, दि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी ने कैप्रोलेक्टम के फैक्टरी मूल्य में पहली फरवरी, 1987 से 1,400 रुपये प्रति टन की वृद्धि करके उसे 30,400 रुपये प्रति टन कर दिया ।

150. संयुक्त संयंत्र समिति ने इस्पात की वस्तुओं, विशेष रूप से गोलों, सलाखों और छड़ों के मूल्यों में 23 अप्रैल, 1987 से 100 रुपये प्रति टन की वृद्धि की । यह वृद्धि पहली अप्रैल, 1987 से "पैकिंग अतिरिक्त प्रभार" के रूप में की गयी 35 रुपये प्रति टन की वृद्धि के अतिरिक्त थी ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की प्रवृत्तियां

151. पिछले वर्ष की तरह, 1986-87 के दौरान पाये गये वृद्धि के दबाव थोक मूल्यों की अपेक्षा फुटकर मूल्यों में अधिक स्पष्ट थे । अतः औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100) में बिन्दुवार आधार पर मूल्य वृद्धि की दर अधिक अर्थात् 7.5 प्रतिशत रही जबकि उसकी तुलना में 1986-87 के थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । बिन्दुवार आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1986-87 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1985-86 में यह वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी । अलबत्ता, औसत के आधार पर 1986-87 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1985-86 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी ।

152. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बिन्दुवार आधार पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष की इसकी तिमाही में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । अलबत्ता, इसी

अवधि के दौरान औसत आधार पर 8.0 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 8.4 प्रतिशत से थोड़ी-सी कम थी ।

153. शहरी, गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100) के आंकड़ों से पता चलता है कि 1986-87 में औसत आधार पर 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वह 1985-86 के 6.8 प्रतिशत की तुलना में कम थी । बिन्दुवार आधार पर इसमें 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के 8.1 प्रतिशत की तुलना में कम थी ।

154. थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दरों में असमानताओं के कारण इस प्रकार हैं : वृद्धि के थोक मूल्यों से खुदरा मूल्यों तक पहुंचने में लगने वाली समय-अंतराल और दोनों समूहों में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में अंतर होना तथा अलग-अलग मदों को अलग-अलग वजन दिया जाना। अलबत्ता, कुछ समय के बाद इन दोनों श्रेणियों के बीच वृद्धि की दरों में अंतर अधिक नहीं रहता ।

सरकारी वित्त

155. राजकोषीय क्षेत्र में, वर्ष 1986-87 के बजट में 1985-86 में शुरू किये गये राजकोषीय सुधारों को जारी रखा गया है । 1986-87 के बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार थीं : उत्पादन शुल्क के ढांचे में पूरी तरह संशोधन के साथ संशोधित मूल्य-योजित कर लागू करना, लघु इकाइयों के लिए उत्पादन शुल्क की रियायतों की एक सरल और अधिक उत्पादन उन्मुख योजना शुरू करना, उपहार और पूंजी लाभों से संबंधित कराधान उपबंधों को युक्तिसंगत बनाना, निवेश छूट के स्थान पर निवेश जमा लेखा योजना आरंभ करना आदि । सार्वजनिक क्षेत्र योजना के परिव्यय में सहायता देने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बांड और इंदिरा विकास पत्र तथा 182 दिवसीय खजाना बिलों जैसी नयी वित्तीय लिखतें जारी कीं । वास्तविक आय/धन के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के प्रति उत्साहजनक रुख मिलने के कारण योजना की अवधि 31 मार्च 1987 तक बढ़ा दी गयी । सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्कों से संबंधित अपराधों को माफ करने और न्यायालय के मामलों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्री ने पहली अगस्त, 1986 को एक अन्य योजना की घोषणा भी की ।

156. केन्द्र सरकार के राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति 1986-87 में भी जारी रही । अलबत्ता, व्यय विशेष रूप से गैर-योजना व्यय में जो तीव्र वृद्धि हुई वह राजस्व में हुई वृद्धि से कहीं अधिक थी । 1986-87 के संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना और गैर-योजना व्ययों में 1986-87 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परिणामस्वरूप, 1986-87 के लिए बजट घाटा 3,703 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) से बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) हो गया । सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घाटा 1985-86 के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 1986-87 में 3.1 प्रतिशत हो गया । राज्यों के वित्त में घाटे की प्रवृत्ति रही और 23 राज्यों का संयुक्त घाटा 1986-87 में 945 करोड़ रुपये रहा जबकि बजट में 291 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था ।

केन्द्र सरकार का बजट, 1987-88

157. करों की 1986-87 की दर पर 1987-88 में बजट घाटा अनुमानतः 6,010 करोड़ रुपये होगा । इस संबंधी प्रस्तावित उपायों और राहतों को हिसाब में लेने के बाद केन्द्र सरकार को 322 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है जिससे अधूरित बजट घाटा 5,688 करोड़ रुपये रह जायेगा । (सारणी 24) । 70 करोड़ रुपये की बजटोपरान्त कर रियायतों की घोषणा किये जाने के बावजूद बजटीय घाटा उतना ही रहेगा क्योंकि राजस्व में कमी वर्ष के दौरान बेहतर वसूलियों के द्वारा पूरी किये जाने की आशा है । प्रधानमंत्री ने संसद को पक्के तौर पर यह आश्वासन दिया कि 1987-88 का घाटा बजट में दी गयी राशि से अधिक नहीं होगा । तदनुसार, इस बात्ते सरकारी व्यय पर निगरानी रखने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया जिससे यह पता चलता है कि सरकार व्यय, विशेष रूप से गैर-योजना व्यय, में वृद्धि के बारे में काफी गंभीर है । हालांकि 1987-88 के योजना परिव्यय में 1986-87 के मुकाबले केवल 3.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है, परंतु 1984-85 के मूल्यों के आधार पर सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल योजना परिव्यय की तुलना में कुल परिव्यय 63 प्रतिशत रहा । गैर-योजना व्यय में तीव्र वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अपेक्षित अंशदान में कमी के होने कारण योजना में निर्धारित की गई मात्रा से अधिक उधार लेने की आवश्यकता पड़ी, ताकि योजना व्यय के इस स्तर को बनाये रखा जा सके ।

सारणी 24—बजट घाटा, बाजार ऋण और केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के लिए रिजर्व बैंक का समर्थन
(1985-86 से 1987-88 तक के राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	मदें	1985-86 (लेखे)	1986-87 (बजट अनुमान)	1986-87 (संशोधित अनुमान)	1987-88* (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्व लेखा				
	(क) प्राप्तियां£	29,206	31 309	35,153	38,202
	(ख) व्यय£	34,771	38,464	42,386	44,944
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा (—)	—5,565	—7,155	—7,233	—6 742
2.	पूंजीगत लेखा				
	(क) प्राप्तियां	16,763	19,236	18,190	20,566
	(ख) संवितरण	16,135**	15,784	19,242	19,512
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा (—)	+628**	+3,452	—1,052	+1,054

1	2	3	4	5	6
3.	कुल प्राप्तियां 1(क)+2(क)	45,969	50,545	53,343	58,768
4.	समग्र अधिशेष (+)/घाटा (—)**	—4,937	—,703	—8,285	—5,683
5.	(3) के प्रतिशत के रूप में (4)	10.7	7.3	15.5	10.0
6.	सकल बाजार ऋण	5,513	6,350	6,350	7,121
7.	(3) के प्रतिशत के रूप में (6)	12.4	12.6	11.9	12.5
8.	रिजर्व बैंक के अधिकार में विनांकित प्रतिभूतियों (वृद्धियां) (+) कमियां (—)$	+367.9	—1,612.1	—1,612.1	

@इनमें वाणिज्य विभाग शामिल हैं।

* इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं लेकिन बजट के बाद की कर रियायतें शामिल नहीं है।

** राज्य सरकारों को, उनके ओवरड्राफ्ट समाप्त करने के लिये दिये गये, दिनांक 29 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार, 1,628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण शामिल नहीं है।

$रिजर्व बैंक के अभिलेखों के आधार पर बही मूल्य पर।

158. गैर-योजना व्यय के अंतर्गत तीन प्रमुख मदों अर्थात् ब्याज अदायगियों, रक्षा व्यय और प्रमुख उपदानों में क्रमशः वृद्धि होती रही है। ब्याज अदायगियों में 1986-87 के दौरान, 1,100 करोड़ रुपये (11.5 प्रतिशत) की वृद्धि होने की संभावना है। कुल गैर-योजना व्यय में ब्याज अदायगियों का अंश 1986-87 में 25.5 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 27.1 प्रतिशत हो जायेगा। ब्याज अदायगियों के बढ़ते हुए भार का इस बात से पता चलता है कि सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान यह 1984-85 के 5,974 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 10,650 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् इसमें 78.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे आंतरिक ऋण शोधन अनुपात (ब्याज और ऋण की अदायगी की तुलना में कुल प्राप्तियों का अनुपात) 1984-85 के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 20.0 प्रतिशत हो गया है। उधारों में वृद्धि होते रहने के कारण आगामी वर्षों में यह अनुपात और अधिक बढ़ जाने की संभावना है। बजटीय साधनों पर दबाव डालने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण गैर-योजना व्यय रक्षा व्यय है। जिसमें 1986-87 के दौरान बजट के अनुसार (संशोधित अनुमान) 2,318 करोड़ रुपये (22.7 प्रतिशत) की और वृद्धि होगी जबकि 1985-86 में पहले ही इसमें 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान रक्षा व्यय 1984-85 के 6,661 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 (बजट अनुमान) में 12,512 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् इसमें 87.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रमुख उपदानों अर्थात् खाद्य वस्तुओं, उर्वरकों और निर्यात संवर्धन संबंधी उपदानों पर होने वाला व्यय 1984-85 के 3,456 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 4,780 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् इसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्याज अदायगियों में तीव्र वृद्धि होने के फलस्वरूप कुल गैर-योजना व्यय में इन तीन मदों का अंश 1986-87 के 67.7 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 73.3 प्रतिशत हो गया है।

159. 1987-88 के बजट में प्रस्तावित कर प्रस्तावों से 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। बजट में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में 595 करोड़ रुपये की रियायतें भी दी गयीं जिनसे कई उद्योगों को राहत मिलेगी और आम आदमी को लाभ होगा। राहतों के कारण राजस्व में होने वाली हानि और नये करों में राज्यों के अंश को हिसाब में लेने के बाद केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व की शुद्ध राशि 322 करोड़ रुपये होगी।

160. दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अनुरूप आय कर का वर्तमान ढांचा अपरिवर्तित रखा गया है। अलबत्ता, गृह निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किसी नयी रिहायशी संपत्ति की लागत के संबंध में किसी एक वर्ष में ऋण की अदायगी और 10,000 रुपये की सीमा तक की गयी ब्याज अदायगी 40,000 रुपये की वर्तमान वार्षिक सीमा के भीतर धारा 80-ग के अंतर्गत छूट के लिए पात्र मानी जायेगी।

161. बजट में महंगे होटलों में किये जाने वाले व्यय पर 10 प्रतिशत के एक नये कर का प्रस्ताव किया गया है परंतु यह कर उन पर्यटकों पर नहीं लगाया जायेगा जो अपने बिलों की अदायगी विदेशी मुद्रा में करेंगे; इससे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

162. विदेशों में अध्ययन और डाक्टरी इलाज करवाने के लिए की जाने वाली विदेश यात्राओं को छोड़कर, विदेश यात्रा के लिए जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत का एक कर लगाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है।

163. हालांकि पूंजीगत लाभों पर कराधान की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये। लेकिन उनसे संबंधित कुछ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर के अंतर्गत रियायत की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए शेयरों को रोक रखने की अवधि 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दी गयी। आवासीय मकान की बिक्री कर उससे कोई नया मकान खरीदने पर प्राप्त होनेवाले पूंजीगत लाभ की छूट, जो अब तक अलग-अलग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थी, उसे हिंदू अविभक्त परिवारों पर भी लागू कर दिया गया।

164. दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अनुसार, बजट में यह संकेत किया गया कि अप्रैल 1987 में मूल्य-ह्रास के लिए उदार नियम लागू किये जायेंगे। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यह्रास के लिए अलग-अलग आस्तियों से जुड़ी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर आस्तियों के समूहों के संबंध में अनुमति दी जायेगी। मूल्यह्रास की दरों को भी युक्तिसंगत बनाया गया और उनकी संख्या घटाकर केवल तीन दरें, अर्थात् 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 33.1/3 प्रतिशत, निर्धारित की गयी हैं।

165. कंपनी कराधान में किये गये प्रमुख परिवर्तनों में शून्य-कर वाली कंपनियों के संबंध में 1983 में जोड़ी गयी धारा 80-फफ को वापस लेना शामिल है। उस प्रावधान के स्थान पर एक नया प्रावधान शामिल किया गया जिससे प्रत्येक कंपनी को अपने बही-लाभों की कम-से-कम 30 प्रतिशत राशि पर कंपनी कर देना होगा। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप किसी घरेलू कंपनी को बही-लाभों पर कम-से-कम 15 प्रतिशत कर देना होगा। अलबत्ता, इस प्रावधान को बाद में संशोधित कर दिया गया ताकि पिछली हानियों अथवा अनावशोषित मूल्यह्रास, जो भी कम हो, का लाभों से प्रतिसंतुलित किया जा सके। प्रशासन में सुधार करने और करवंचन को रोकने की दृष्टि से वित्त विधेयक में एक नई धारा 194-ड जोड़ दी गयी। इसके अन्तर्गत व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं का शुल्क, रायल्टी, किराया, कमीशन अथवा दलाली और सरकार को सप्लाई की गयी वस्तुओं के लिए भुगतान इत्यादि के एक निश्चित राशि से ऊपर किये गये भुगतानों के संबंध में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है। किन्तु यह प्रस्ताव बाद में इस अभिवेदन के आधार पर रोक दिया गया कि इससे बड़ी संख्या में कर-दाताओं को असुविधा हो जायेगी।

166. शुद्ध बचत सिद्धान्त के आधार पर, बजट में एक नई बचत योजना का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत 20,000 रुपये तक जमा करायी गयी राशि को 50 प्रतिशत राशि पर कर योग्य आय में छूट की अनुमति होगी। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के अन्तर्गत प्रदत्त 40,000 रुपये की सीमा के अतिरिक्त होगी। किन्तु आहरण के वर्ष में आहरित की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत उस वर्ष के दौरान की कर-योग्य आय में जुड़ जायेगा।

167. अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में संशोधित योजित मूल्य कर (मॉडवेट) योजना को जो, 1986-87 में कुछ पण्यों के लिए लागू की गयी थी, वस्त्र, तंबाकू और पेट्रोलियम क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर, सभी पण्यों पर लागू कर दी गयी है। बजट में अधिकांश मदों में अंतिम उत्पाद पर शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

168. विशेष तौर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। सामान्य परियोजना आयातों और सामान्य मशीनरी के आयातों पर शुल्कों की दरों में अंतर को समाप्त कर दिया गया और शुल्क की एक-समान दर लागू की गयी। देशी पूंजीगत वस्तु उद्योग के हितों को रक्षा करने की दृष्टि से उर्वरकों, 50 मे.वा. और उससे कम क्षमता वाले बिजली संयंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग जैसी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के आयातों के मामले में सीमा शुल्क में वृद्धि की गयी थी। इसके अलावा कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पॉवर, भारी उपस्कर तथा वस्त्र, मशीनरी इत्यादि में देशी निर्माताओं की लागत को कम करने की दृष्टि से इस्पात की विशेष किस्मों पर शुल्क में कमी की गयी।

169. भवन-निर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने के अलावा, बजट में सातवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए दस लाख मकानों का निर्माण करने के लिए इन्दिरा आवास योजना के वास्ते 125 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान रखा गया है। बजट में यह भी प्रावधान है कि भवन निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु एक नये वित्तीय ढांचे का निर्माण किया जाये। इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 100 करोड़ रुपये की ईक्विटी पूंजी के साथ एक शिखर स्तरीय नये आवास बैंक की स्थापना की जायेगी। यह बैंक स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों ही स्तरों पर भवन निर्माण संस्थाओं की स्थापना करेगा।

170. सितम्बर 1986 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ईक्विटी में निवेश हेतु एक पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड) की स्थापना की थी। भारतीय स्टेट बैंक भी इसी प्रकार की पारस्परिक निधि की स्थापना करेगा।

राज्यों के बजट : 1987-88

171. करों की 1986-87 की दरों पर, राज्यों की संयुक्त बजट स्थिति *वर्ष 1987-88 के लिए समग्र रूप से 1,545 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाती है जबकि 1986-87 (परिशोधित अनुमान) में 945 करोड़ रुपये का घाटा तथा 1985-86 (लेखा) में, 1,688 करोड़ रुपये का अधिशेष था। 1987-88 के दौरान बारह राज्यों ने 833 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व की आय के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय प्रस्तावित किये है। इसके अलावा राज्यों को केन्द्र के नये कर उपायों में से उनके अंश के रूप में 192 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। राज्यों के, स्वयं के अतिरिक्त संसाधन जुटाने और केन्द्र के नये कर उपायों में उनके अंश की राशि को हिसाब में लेने के बाद समग्र घाटा कम होकर 520 करोड़ रुपये रह जायेगा। 1987-88 में विकास-व्यय की राशि 1986-87 के 16.9 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत की कम दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष हुई 20.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1987-88 के दौरान 21.1 प्रतिशत की अधिक वृद्धि होगी।

*आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश और गोवा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

समेकित स्थिति : केन्द्र और राज्य : 1987-88

172. केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय स्थिति से संबंधित आंकड़े सारणी 25 में दिये गये है। केन्द्र और 23 राज्यों का संयुक्त बजट घाटा 1987-88 में 6,208 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो परिशोधित अनुमानों की तुलना में 3,022 करोड़ रुपये अथवा 32.7 प्रतिशत कम है, किन्तु 1986-87 के बजट अनुमानों की तुलना में 2,214 करोड़ रुपये अथवा 55.1 प्रतिशत अधिक है।

173. 1987-88 के दौरान केन्द्र और राज्यों की कुल प्राप्तियां 100,216 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो 87,185 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 14.9 प्रतिशत तथा 1986-87 के लिए 92,171 करोड़ रुपये के परिशोधित अनुमानों की तुलना में 8.7 प्रतिशत अधिक हैं। 1987-88 में उनकी राजस्व प्राप्तियों (69,282 करोड़ रुपये) और पूंजीगत प्राप्तियों (30,934 करोड़ रुपये) में पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में कर प्राप्तियों में पायी गयी तेजी 1987-88 में भी जारी रहने का अनुमान है। तदनुसार, कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 1986-87 में इनमें 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। 1987-88 में किये गये केन्द्रीय बजट कर प्रस्तावों से 514 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमें से 145 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से और 369 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से प्राप्त होंगे। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्रमुख अंश (302 करोड़ रुपये अथवा 81.8 प्रतिशत) उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होगा। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर निरंतर निर्भरता के कारण केन्द्रीय सरकार की कुल कर-वसूली में प्रत्यक्ष कर वसूली का अनुपात धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। कुल कर-प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर वसूली (शुद्ध) का अनुपात, जो 1985-86 के 17.8 प्रतिशत से घटकर 1986-87 (परिशोधित अनुमान) में 16.9 प्रतिशत रह गया था, आगे और घटकर 1987-88 में 15.8 प्रतिशत हो जायेगा।

174. 1987-88 में केन्द्र और राज्यों के कुल संवितरण 106,424 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 1986-87 के बजट अनुमानों से 16.7 प्रतिशत अधिक और परिशोधित अनुमानों से 5.0 प्रतिशत अधिक होंगे। विकास व्यय 1986-87 के बजट अनुमानों की तुलना में 7,338 करोड़ रुपये अथवा 12.7 प्रतिशत बढ़ जायेंगे और 64,789 करोड़ रुपये के परिशोधित अनुमानों की तुलना में यह राशि 133 करोड़ रुपये अथवा 0.2 प्रतिशत अधिक होगी। दूसरी ओर, गैर-विकास व्यय की 39,522 करोड़ रुपये की राशि बजट अनुमानों की तुलना में 7,941 करोड़ रुपये अथवा 25.1 प्रतिशत और 1986-87 के परिशोधित अनुमानों की तुलना में 5,406 करोड़ रुपये अथवा 15.8 प्रतिशत अधिक होगी। केन्द्र के योजना परिव्यय की राशि पिछले वर्ष के 23,625 करोड़ रुपये की तुलना में 24,622 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी हैं (परिशोधित अनुमान)। इस प्रकार उसमें 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का योजना परिव्यय 19,537 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक है। 1987-88 के दौरान योजना परिव्यय का केन्द्रीय बजट समर्थन 23,677 करोड़ रुपये होगा, जिसमें 14,923 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना के लिए और 8,754 करोड़ रुपये राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए होंगे।

बाजार उधार

175. 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल सात बार बाजार से उधार लिये। इनमें से एक बार 350 करोड़ रुपये की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में रखने के लिए ली गयी और कुल 6,350 करोड़ रुपये उधार लिये गये। वर्ष के दौरान अवधि पूर्णता वाले ऋणों के

सारणी 25—केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण
(1985-86 से 1987-88 तक के राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

मदें	1985-86 लेखा	1986-87 (बजट अनुमान)	1986-87 (संशोधित अनुमान)		1987-88 (बजट अनुमान)	
			राशि	पिछले वर्ष के लेखा से प्रतिशत घट-बढ़	राशि	पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	81221	87185	92171	+13.5	100216	+14.9
अ. राजस्व प्राप्तियां	54097	58217	63776	+17 9	69282	+19.0
जिसमें से कर प्राप्तियां (क+ख)	42991	46841	49469	+15 1	56457	+20.5
(क) प्रत्यक्ष कर	7047	7058	7989	+13.4	8563	+21.4
(ख) परोक्ष कर	35944	39783	41480	+15.4	47889	+20.4
आ. पूंजीगत प्राप्तियां	27124	28968	28395	+4.7	30934	+6.8
II. कुल वितरण (अ+आ+इ)	84470	91179	101401	+20.0	106424	+16.7
अ. विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	55032	57584	64789	+17.7	74922	+12.7
(क) राजस्व	32621	34832	38305	+17.4	39966	+14.7
(ख) पूंजी	12310	12530	14003	+13 8	13301	+6.2
(ग) ऋण और अग्रिम	10101@	10222	12481	+23.0	11655	+14.7
आ. गैर विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	27332	31581	3416	+24.9	33523	+25.1
(क) राजस्व	25984	29656	32020	+23.2	39744	+17.2
(ख) पूंजी	1116	1429	1564	+40 1	4280	+19.59
(ग) ऋण और अग्रिम	232	496	532	+129.3	498	+0.4
इ. अन्य	2106	2014	2496	+18.5	1980	--1.7
III. कुल अधिशेष (+) अथवा घाटा (—) (I-II)	—3249	—3994	—9230		—6208	

*इसमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं। बजट के बाद की कर रियायतों को नहीं लिया गया है।

@गैर विकासात्मक व्यय शामिल है।

टिप्पणियां (1) राज्यों के बजटों के संबंध में आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित हैं, अर्थात इनमें अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल नहीं हैं। इसके अलावा आंकड़ों में विधान सभा वाले संघशासित क्षेत्र शामिल नहीं है। नागालैण्ड तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 1985-86 के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबन्धित हैं।

(2) अन्य वितरणों में आन्तरिक और बाह्य ऋण चुकाना स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और दी गयी राशियां, आकस्मिक निधियों में विनियोजन और शुद्ध प्रेषण शामिल हैं और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबन्धित बजटों में दर्शाये गये केन्द्र सरकार के किये गये ऋण भुगतान के आंकड़ों के लिए उन्हें समायोजित किया गया है।

लिए 1,050 करोड़ रुपये की चुकौती की व्यवस्था करने के पश्चात् (3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946 सहित जिसकी 16 सितम्बर, 1936 को चुकौती की जानी थी) शुद्ध बाजार उधार की राशि 5,300 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 199 करोड़ रुपये अथवा 3.9 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 26)। 6,350 करोड़ रुपये के सकल बाजार उधारों में 5,883 करोड़ रुपये नकद अभिदान से और 467 करोड़ रुपये परिवर्तन से प्राप्त हुए।

176. 1986-87 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधारों की सकल राशि 1,446 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1,404 करोड़ रुपये नकद अभिदान से और शेष 42 करोड़ रुपये परिवर्तन से प्राप्त हुए थे। 283 करोड़ रुपये के अवधिपूर्णता वाले ऋणों की चुकौती को हिसाब में लेने के बाद राज्य सरकारों के शुद्ध बाजार उधारों की कुल राशि 1,163 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष में उधार ली गयी वास्तविक राशि की तुलना में 190 करोड़ रुपये अथवा 19.5 प्रतिशत अधिक थी।

177. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित स्थानीय प्राधिकरणों और संस्थाओं द्वारा लिये गये सकल उधारों की राशि 3,143 करोड़ रुपये थी। उसमें से अवधि-पूर्णता वाले ऋणों की चुकौती के लिए 782 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करने के बाद इन संस्थाओं की शुद्ध बाजार उधारों की राशि 2,366 करोड़ रुपये थी, जो 1985-86 की राशि की तुलना में 158 करोड़ रुपये अथवा 7.2 प्रतिशत अधिक थी।

178. 1987-88 के लिए केन्द्रीय बजट में 6,300 करोड़ रुपये के शुद्ध बाजार उधारों का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये (18.9 प्रतिशत) की वृद्धि के द्योतक हैं। इसके परिणामस्वरूप, शुद्ध बाजार उधार, जो 1986-87 में केन्द्र के चालू राजस्वों (राज्यों के अंश के शुद्ध) के 15.9 प्रतिशत थे, 1987-88 में बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो जायेंगे। केन्द्र के अपने बाजार उधारों के अतिरिक्त, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपनी विकास योजनाओं

सारणी 26—केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा बाजार से लिये गये ऋण—1985-86 और 1986-87 (राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	केन्द्र सरकार/निकाय	सकल बाजार ऋण		चुकौतियां (कुल ऋण जिनकी अवधि पूरी हुई)		शुद्ध बाजार ऋण	
		1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1		2	3	4	5	6	7
1.	केन्द्र सरकार	5,764	6,350	663	1,050	5101	5,300
2.	राज्य सरकारें	1,414	1,446	441	283	973	1,163
3.	सरकार के कुल ऋण (1+2)	7,178	7,796	1,104	1,333	6,074	6,463
4.	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	1,644	1,869	177	267	1,467	1,602
5.	राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं (स्थानीय निकायों सहित)	1,311	1,279	570	515	741	764
6.	संस्थाओं को कुल ऋण (4+5)	2,955	3,148	747	782	2,208	2,366
7.	कुल बाजार ऋण (3+6)	10,133	10,944	1,851	2,115	8,282	8,829

के वित्तपोषण के लिए देशी बाजारों में बांड जारी करने और विदेशों से वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गयी है।

179. 1987-88 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड जारी करके 1,500 करोड़ रुपये और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से 485 करोड़ रुपये जुटाये जाने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप योजना वित्त में उधार ली गयी निधियों का अंश धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त कुल उधारों से केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए 33.6 प्रतिशत वित्त प्राप्त होगा, जबकि 1986-87 में यह 33.0 प्रतिशत था। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में यह परिकल्पना की गयी थी कि केन्द्र के शुद्ध बाजार उधार 1985-86 के सकल देशी उत्पाद के 2.1 प्रतिशत से कम होकर 1986-87 में 1.6 प्रतिशत रह जायेंगे। 1986-87 के सांकेतिक सकल देशी उत्पाद में अनुमानित वृद्धि के आधार पर यह अनुपात 2 प्रतिशत के आसपास हो सकता है।

केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर ब्याज (कूपन) दरें

180. 1986-87 के दौरान दीर्घावधि प्रतिभूतियों पर 11.5 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर रखी गयी थी, किन्तु अवधि समाप्ति समय 30 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया था। 1986-87 के दौरान 5-वर्षीय और 10-वर्षीय ऋणों पर ब्याज (कूपन) दरों में 1.0 प्रतिशत अंक की वृद्धि करते हुए उन्हें क्रमशः 10.00 प्रतिशत और 10.50 प्रतिशत कर दिया गया था।

181. ऊपर वर्णित बाजार उधारों के अलावा, केन्द्र और राज्यों ने भविष्य निधियों और अल्प बचतों जैसे अन्य उधारों के माध्यम से भी संसाधन जुटाये थे। 1986-87 में केन्द्र और राज्यों के आंतरिक उधार और अन्य देयताओं में शुद्ध योग की राशि 27,020 करोड़ रुपये थी, जो सकल देशी उत्पाद की 9.9 प्रतिशत होगी, जबकि 1985-86 में वह 23,319 करोड़ रुपये अर्थात् 9.6 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंक का समर्थन

182. 11.5 प्रतिशत की उच्चतम कूपन दर और दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात के कड़ाई से प्रवर्तन के साथ 1985-86 में सांविधिक चलनिधि अनुपात में लागू की गयी वृद्धि ने बाजार से अधिक संसाधन जुटने में सहायता की। 1986-87 में जुटाये गये कुल ऋणों में से 11.5 प्रतिशत की कूपन दर पर जुटाये गये ऋण 82.8 प्रतिशत थे, जबकि 1985-86 में वे 72.4 प्रतिशत थे। परिणामस्वरूप, 1986-87 के दौरान ऋण जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समर्थन पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी हुई। 1986-87 में केन्द्रीय ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारंभिक नकद अभिदान की राशि 2,266.4 करोड़ रुपये अर्थात् कुल जुटाये गये ऋणों की 35.7 प्रतिशत थी। इसके विपरीत 1985-86 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,905.5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अभिदान दिया, जो कुल ऋणों का लगभग 50 प्रतिशत था। किन्तु, 1986-87 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुद्ध बिक्रियां की गयी थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड

183. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड (दूसरा निर्गम) 3 वर्ष की अवधि समाप्ति के साथ 7 जुलाई 1984 को जारी किये गये और उनकी ब्याज दर 7.5 प्रतिशत थी। जैसा कि 9 जुलाई 1979 से प्रारंभ किये जाने वाले सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों के मामले में था, उक्त बांड आस्तियों के अंतरण/बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निवेश सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से प्रारंभ किये गये थे। बांडों की बिक्री के प्रारंभ से 31 मार्च 1987 की स्थिति के अनुसार 3 वर्षीय बांडों की कुल बकाया राशि 55 करोड़ रुपये थी और 7 वर्षीय बांडों की 161 करोड़ रुपये थी।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र

184. 1 जून 1982 से जनता के उपयोग के लिए, विशेष रूप से छोटे बचतकर्ताओं की निजी बचत राशियों को जुटाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये। उनकी ब्याज दर (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर) 11.3 प्रतिशत थी। 31 मार्च 1987 की स्थिति के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों में किया गया कुल अभिदान 18.1 करोड़ रुपये था।

पूंजी निवेश बांड

185. पूंजी निवेश बांड 28 जून 1982 को 10 वर्ष की अवधि समाप्ति के साथ जारी किये गये थे। इन पर 7.0 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कर मुक्त ब्याज का प्रावधान है। 28 जून 1987 की स्थिति के अनुसार इन बांडों की बकाया राशियां 167.3 करोड़ रुपये थीं।

राष्ट्रीय जमा योजना

186. सार्वजनिक निवेश के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 30 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय जमा योजना प्रारंभ की गयी। मोटे तौर पर इसकी मुख्य बातें बैंकों की दीर्घावधि जमा योजनाओं जैसी ही हैं। इस योजना के अधीन चार वर्ष की अवधि के लिए जमाराशियां रखी जाती हैं, जिन पर प्रति वर्ष 10.50 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

प्रारंभ से लेकर इन जमाराशियों में अभिदान की राशि 31 मार्च 1987 को 68.3 करोड़ रुपये थी, जबकि निर्धारित लक्ष्य 500 करोड़ रुपये का था। यह योजना अब सरकार द्वारा पहली अप्रैल 1987 से बन्द कर दी गयी है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

187. छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-6 और 7 निर्गम पहली मई 1981 से प्रारंभ किये गये थे। ये प्रमाणपत्र उच्च प्रतिलाभ तथा आय कर अधिनियम और संपत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत उदार लाभ की वजह से निरन्तर लोकप्रिय और आकर्षक बनते गये हैं। 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान इन प्रमाणपत्रों की बिक्री से कुल प्राप्त राशि 1985-86 के 2,182 करोड़ रुपये की तुलना में 3,132 करोड़ रुपये थी। पहली अप्रैल 1987 से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की ब्याज दर 12.0 प्रतिशत से घटकर 11.0 प्रतिशत कर दी गयी है।

इन्दिरा विकास पत्र

188. ग्रामीण बचत को जुटाने की दृष्टि से भारत सरकार ने 19 नवम्बर 1986 को इन्दिरा विकास पत्र नामक एक नयी अल्प बचत लिखत प्रारंभ की। पांच वर्ष की अवधि समाप्ति वाले ये इंदिरा विकास पत्र 500 रुपये, 1,000 रुपये और 5,000 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किये गये थे। इनकी खरीद के समय निवेशकों को इंदिरा विकास पत्र के मूल्य-वर्ग की आधी कीमत चुकानी थी। इस प्रकार, प्रतिलाभ की अंतर्निहित ब्याज दर 14.87 प्रतिशत वार्षिक बैठती है। किन्तु इंदिरा विकास पत्रों पर किसी प्रकार की कर रियायत नहीं है। पहली अप्रैल 1987 से, इंदिरा विकास पत्र की समाप्ति-अवधि बढ़ाकर साढ़े पांच वर्ष कर दी गयी है ताकि इस पर होने वाले प्रतिलाभ को मार्च 1987 अंत में घोषित न्यूनतम ब्याज दर पद्धति के अनुकूल किया जा सके। मार्च 1987 अन्त में इंदिरा विकास पत्र योजना के संबंध में कुल बकाया राशियां 835 करोड़ रुपये थीं।

182-दिवसीय खजाना बिल

189. वर्ष के दौरान 182 दिवसीय खजाना बिलों की एक नयी विलीय लिखत प्रारंभ किये जाने के बारे में पहले उल्लेख किया जा चुका है। ये बिल कम से कम एक लाख रुपये की राशि और उसके गुणकों में बट्टागत आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। बट्टा दर और तदनुरूपी निर्गम मूल्य साप्ताहिक नीलामियों द्वारा निश्चित किया जाता है। ये बिल भारत के निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जिनमें व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, निगमित निकाय और संस्थाएं शामिल हैं। किन्तु, राज्य सरकारें और भविष्य निधियां इनमें निवेश करने के लिए पात्र नहीं है। रिजर्व बैंक इसके द्वारा निर्गम हेतु प्रस्तावित खजाना बिलों की राशि, निविदा की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक नीलामी पर निश्चित करता है और इसे बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। स्वीकृत निविदाओं के संबंध में, बोली लगाने वाले द्वारा संबंधित आवेदन पत्र में उल्लिखित मूल्य पर खजाना बिल जारी किये जाते हैं। यह बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए एक अनुमोदित निवेश है और यह रिजर्व बैंक की सहायक पुनर्वित्त सुविधा के अन्तर्गत उससे उधार प्राप्त करने के लिए एक पात्र जमानत है।

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम

190. रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी प्राप्तियों और व्यय की वजह से होने वाली नकदी प्राप्तियों में मौसमी असन्तुलनों पर काबू पाने के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराता है। अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं पिछली बार जुलाई 1982 में संशोधित की गयी थीं। राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों और 1982 के बाद से बजटीय लेन देनों में हुए उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक के पास खाते रखने वाले सभी राज्यों के मामले में सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की मौजूदा सीमाओं में पहली अक्तूबर 1986 से 20 प्रतिशत की मूल वृद्धि करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा, चूंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान राज्य सरकारों द्वारा महसूस की जा रही नकदी प्राप्ति की समस्या दूसरी छमाही की अपेक्षा अधिक तीव्र बनायी गयी है, अतः पहली छमाही की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की मंजूरी दी गयी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो रिजर्व बैंक के पास खाता रखने वाली 20 राज्य सरकारों को क्रमशः अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर मार्च की अवधि के लिए उस समय की मौजूदा कुल 520 करोड़ रुपयों की सामान्य सीमाओं पर 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि मंजूर की गयी थी। विशेष सीमाओं में अथवा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली न्यूनतम निधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बाद में, 3 नये बनाये गये राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम ने भी रिजर्व बैंक को अपना बैंकर नियुक्त किया। इस तरह रिजर्व बैंक के पास खाता रखने वाले राज्यों की कुल संख्या 23 हो गयी। अब अर्थोपाय अग्रिमों की कुल सीमाएं राजकोषीय वर्ष के अप्रैल-सितम्बर के दौरान 957.60 करोड़ रुपये तथा अक्तूबर-मार्च के दौरान 904.10 करोड़ रुपये हैं। इनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के लिए 226 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सीमाएं शामिल है।

191. वर्ष के दौरान सभी राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना का पालन किया। किसी भी राज्य ने ओवरड्राफ्ट के लिए निर्धारित 7 निरन्तर कार्य दिवसों का उल्लंघन नहीं किया।

पूंजीगत बाजार

192. 1986-87 (अप्रैल मार्च) में गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के 2,161.6 करोड़ रुपये के नये पूंजीगत निर्गम 1985-86 के 1646.6 करोड़ रुपये के निर्गमों की तुलना में 19.5 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 27)। ईक्विटी निर्गम 4.1 प्रतिशत अधिक रहे, अलबत्ता, यदि किसी एक कम्पनी द्वारा अपवाद के रूप में अधिक निर्गम के लिए गंजाइश रखी जाये तो ईक्विटी निर्गम 17.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 27.8 प्रतिशत कम रहे। दूसरी तरफ, परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम 1985-86 के 85.2 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 1986-87 में 1064.6 करोड़ रुपये हो गये। गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों से परिवर्तनीय डिबेंचरों की तरफ इस झुकाव के पीछे गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों से महसूस की जा रही प्रतिस्पर्धा तथा सक्रिय गौण बाजार की कमी जैसे कारण थे। इस संदर्भ में यह भी नोट किया जाना चाहिए कि 1986-87 में कुछ कंपनियों ने परिवर्तनीय डिबेंचरों के बहुत से निर्गम जारी किये जिनमें परिवर्तन की आकर्षक शर्तें दी गयी थीं।

सारणी-27 गैर-सरकारी पब्लिक लि. कंपनियों के पूंजीगत निर्गम

(करोड़ रुपये)

निर्गम के प्रकार	1985-86*	1986-87*
1	2	3
ईक्विटी शेयर	846.5	880.8
अधिमान शेयर	1.2	0.8
डिबेंचर	798.9	1,580.0
(1) परिवर्तनीय	85.2	1,064.6
(2) अपरिवर्तनीय	713.7	515.4
जोड़	1,646.6	2,461.6

*अनन्तिम

†बोनस शेयर शामिल नहीं।

टिप्पणी :

1. अधिक प्राप्त अभिदान की राशि, जो रख ली गयी है, के आंकड़े उन मामलों में शामिल है, जहां इस संबंध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी।
2. वित्तीय संस्थाओं आदि के पास निजी रूप में रखे गये निर्गम इन आंकड़ों में शामिल नहीं है।

193. 1986-87 के दौरान 14 प्रतिशत ब्याज दर और/अथवा कर मुक्त 10 प्रतिशत ब्याज दर वाले नये सार्वजनिक क्षेत्र के बांड जारी किये गये थे। 14 प्रतिशत बांड और 10 प्रतिशत बांड दोनों को ही संपत्ति कर से छूट मिली हुई है। इसके अलावा, 10 प्रतिशत बांडों से प्राप्त ब्याज की आय भी आयकर से मुक्त है। इससे प्राप्त कुल राशियां पिछले वर्ष के 353.7 करोड़ रुपये की तुलना में 4,516.1 करोड़ रुपये (रख लिये गये अधिक अभिदान सहित) थी। इन बांडों के लिए अभिदान का अधिकतर हिस्सा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुआ। हालांकि करमुक्त बांडों पर वास्तविक प्रतिफल काफी अधिक है, फिर भी अलग अलग निवेशकों की इसमें दिलचस्पी है। इस संबंध में निर्गम जारी करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चाहिए कि वे प्रचार और कारोबार की प्रगति के प्रयासों पर और अधिक ध्यान दें और वे निर्गमों को अब तक की तुलना में अधिक लंबी अवधियों तक के लिए खुला रखें। यदि इन बांडों के लिए एक गौण बाजार का विकास किया जाता है तो कारगर उपाय करने की जरूरत होगी।

194. अनंतिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1986-87 में गैर सरकारी कंपनियों द्वारा बोनस शेयरों में जुटायी गयी पूंजी को छोड़कर अन्य पूंजी (चुकता) की राशि 1,632 करोड़ रुपये थी जो 1985-86 की 1,071 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस तरह जुटायी गयी राशि पूंजीगत निर्गमों में अनेक कारणों से भिन्न है। पहले तो निर्गमों और वास्तविक अभिदानों के बीच समय का अन्तराल है। दूसरे जारी की गयी राशि का अभिदान एक से अधिक किस्तों में किया जा सकता है और तीसरे निश्चित राशि से कम अथवा अधिक अभिदान की संभावनाएं है।

195. जुटायी गयी पूंजी के संबंध में ये आंकड़े कुछ हद तक कम दर्शाये गये हैं। इसका कारण संबंधित कंपनियों द्वारा पूंजीगत निर्गमों के नियन्त्रण को सांख्यिकीय विवरणियां प्रस्तुत करने में देरी या चूक करना है। 1986-87 में सरकारी कंपनियों द्वारा अनुमोदनों के आधार पर जुटायी गयी पूंजी (अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी 14 प्रतिशत की ब्याज दर और/अथवा 10 प्रतिशत की करमुक्त ब्याज दर वाले बांडों के जरिये) 1978.6 करोड़ रुपये रही। पूंजीगत निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अन्तर्गत (जिसके अन्तर्गत एक करोड़ रुपये तक के निर्गम आमतौर पर पूंजी निर्गम नियंत्रण से मुक्त रहते हैं) गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा जुटायी गयी पूंजी 200 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। आंकड़ों की कम सूचना दी गयी है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकारी कंपनियों और गैर सरकारी कंपनियों द्वारा (पूंजीगत निर्गमों के लिए अनुमोदनों पर तथा छूट आदेश के अन्तर्गत) जुटायी गयी (चुकता) पूंजी 1,000 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

196. अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कंपनियों) द्वारा 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मंजूर और वितरित सहायता क्रमशः 7,486.0 करोड़ रुपये तथा 5,172.0 करोड़ रुपये रही। यह पिछले वर्ष की तुलना में मंजूरियों में 20.3 प्रतिशत की और वितरणों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1986-87 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मंजूरियां, निवेश करने की इच्छा के ऊंचे स्तर की द्योतक है। पूंजीगत निर्गमों के नियंत्रक द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों को 1986-87 में नये पूंजीगत निर्गमों के लिए मंजूर किये गये 5,489 करोड़ रुपयों के अनुमोदनों को देखते हुए, 1987-88 में औद्योगिक निवेश में उत्साह बने रहने की संभावना है (सारणी 28)।

87/1861 GI—11

सारणी 28—पूंजी जुटाने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों (सार्वजनिक और निजी) को पूंजी निर्गमों के नियंत्रक द्वारा मंजूर की गयी सहमतियां/स्वीकृतियां

(करोड़ रुपये)

क्र सं	निर्गम	1985-86	1986-87
1	2	3	4
1.	शेयर	1,082	1,512
	जिनमें से :		
	(1) प्रारम्भिक निर्गम	645	825
	(2) बाद के निर्गम	437	687
2.	डिबेंचर/बांड	2,377	3,977
	जिनमें से :		
	(1) परिवर्तनीय	372	1,962
	(2) गैर-परिवर्तनीय	2,005	2,015
		(354)	(1,107)
3.	उप जोड़ (1+2)	3,459	5,489
4.	बोनस शेयर	236	354
5.	विविध निर्गम (ऋण आदि)	221	228
6.	कुल जोड़ (3+4+5)	3,916	6,071

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के 14 प्रतिशत और दस प्रतिशत (कर मुक्त) बांडों के निर्गम के लिए दी गयी सहमतियां दर्शाते हैं।

स्रोत : पूंजी निर्गम नियंत्रक।

नीतिगत परिवर्तन

197. 1987-88 के लिए केन्द्रीय बजट में पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्ताव थे। मौजूदा प्रावधान को, जिसके अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 80 एम के अन्तर्गत नयी कंपनियों की कुछेक श्रेणियों के ईक्विटी शेयरों में निवेश के संबंध में कर योग्य आय से कर की कटौती की अनुमति को, जिसे 31 मार्च 1987 को समाप्त होना था, और 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इस तरह के शेयरों को रखने की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। बजट ने दीर्घकालिक पूंजी लाभों के लिए अनुमत रियायती कर ढांचे की श्रेणी में आने के प्रयोजनों के लिए शेयरों को रखने की अवधि को 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिया। इसके अलावा ईक्विटियों पर लाभांश के भुगतान और डिबेंचरों पर ब्याज के भुगतानों पर स्रोत पर कर को कटौती के लिए मौजूदा छूट सीमा को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया। इन उपायों से नियमित क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

198. पूंजी बाजार को मजबूत करने और निवेश के वातावरण को बेहतर बनाने की दृष्टि से सरकार ने 1986-87 में कई उपाय शुरू किये। भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पहले ही संगठित पारस्परिक निधि की तरह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक नयी निधि गठित करने का प्रस्ताव है। शेयर बाजारों तथा प्रतिभूति उद्योग के विनियमन तथा व्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए अलग से एक बोर्ड स्थापित किया जाना है। सरकार ने विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये और डिबेंचरों के जरिये निधियां जुटाने वाली कंपनियों के लिए डिबेंचर शोधन निधियां रखना अनिवार्य कर दिया। एक के बाद दूसरे बोनस निर्गम के बीच के न्यूनतम समय-अंतराल को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है।

199. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संगठनात्मक ढांचे और नीतिगत उपायों में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसने 20, मई 1986

को लघु उद्योग विकास निधि नाम की एक अलग निधि स्थापित की जो केवल लघु उद्योग क्षेत्र के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण, उसके नये क्षेत्र खोजने तथा पुनर्वास के लिए होगी। यह निधि लघु औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के लिए मध्यस्थ संस्था का कार्य करती है। लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना के साथ, विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उपाय किये हैं। राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को अपनी सहायता की सीमा में लाने के अलावा विकास बैंक ने लघु उद्योगों के लिए अपना पुनर्वित्त और बिल पुनर्भुनाई योजनाओं में कई रियायतें दी हैं।

200. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में समीक्षाधीन वर्षों के दौरान संशोधन किये गये। इन संशोधनों से अन्य बातों के साथ-साथ भा. औ. वि. नि. का कार्यक्षेत्र बढ़ा है और उसकी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि हुई है।

201. भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जुलाई 1986 में मेरिल लिंच इंटरनेशनल एण्ड कम्पनी के सहयोग से भारत निधि की स्थापना की ताकि अनिवासी भारतीय और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति तथा भारत से बाहर बसे व्यक्ति और संस्थाएं भारत के प्रतिभूति बाजारों में निवेश कर सकें। इस निधि का मूल उद्देश्य भारत में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश के जरिये दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि करना है। इस निधि के जरिये 139.5 करोड़ रुपये की निधि जुटाया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भी सितंबर 1986 में पारस्परिक निधि योजना शुरू की और इसके लिए 150 करोड़ रुपये जुटाये। इस योजना के अंतर्गत यूनिट, जो कि मास्टर शेयर कहलाते हैं, सभी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं।

202. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. नाम की एक कम्पनी स्थापित की है। यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रतिभूतियों के लेनदेनों से संबंधित कारोबार के बाद की कारगर सेवाएं उपलब्ध करायेगी। समय बीतने के साथ-साथ निगम द्वारा आम जनता को भी सेवाएं उपलब्ध कराने की आशा है।

ईक्विटी मूल्य

203. ईक्विटी मूल्यों में 1985-86 के दौरान असामान्य उछाल देखने में आया। यह उछाल मुख्य रूप से बाजार भाव बढ़ जाने की आशा तथा कुछ हद तक सट्टेबाजी बढ़ जाने के कारण आये। शेयरों के मूल्य फरवरी 1986 के मध्य में शिखर स्तर पर पहुंच गये किन्तु उसके बाद तेजी से घटने लग गये। बजट प्रस्तावों ने बाजार की आशाओं को पूरा नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने बाजार के रूख को प्रभावित किया, बजट प्रस्तावों से निवेश की अनुमति और अंतर-कारपोरेट लाभांश पर कर रियायत को वापस लेना तथा ब्याज के पूंजीकरण को अनुमति न देना शामिल है।

204. अप्रैल 1986 के पहले पखवाड़े में ईक्विटियों में कुछेक बजट प्रस्तावों में आशोधनों से आंशिक सुधार हुआ। इनमें अन्तर-कम्पनी लाभांशों पर कर से संबंधित प्रस्ताव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, अलबत्ता, अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में निरन्तर बिक्री दबावों के कारण और बाहरी समर्थन के अभाव में ईक्विटियां फिर से लुढ़की। यह प्रवृत्ति मई के तीसरे सप्ताह तक जारी रही, जब खास तौर पर हतोत्साहित करने वाले समाचारों की वजह से बाजार का रूख विपरीत रूप से प्रभावित हुआ।

205. बम्बई शेयर बाजार द्वारा 14 सक्रिय लिखतों को गैर-निर्दिष्ट सूची से निर्दिष्ट सूची में अंतरित करने के अनुकूल निर्णय और वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की चयनात्मक खरीद किये जाने से मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक स्थिति में फिर सुधार हुआ। बाद में निराशाजनक निगम रिपोर्टों से ईक्विटी मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। यह प्रवृत्ति जून, 1986 के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो कर अक्तूबर से थोड़ी सी संभलने के बाद, दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक जारी रही। उसके बाद, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये समर्थन से तथा शेयर बाजारों द्वारा अपनाये गये विनियामक उपायों से ईक्विटियों में जनवरी और फरवरी, 1987 में काफी सुधार हुआ।

206. फरवरी, 1987 से ईक्विटी मूल्यों में उतार-चढ़ाव भी बाजार की अत्यधिक बढ़ी हुई उम्मीदों से प्रेरित था जिन्हें 1987-88 के केन्द्रीय सरकार के बजट ने पूरा नहीं किया। जिन प्रस्तावों ने बाजार की भावना को विशेष रूप से धक्का पहुंचाया, उनमें बही लाभों पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर निगम कर लगाया जाना और कुछेक भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करना शामिल है। मार्च 1987 के पहले सप्ताह में भारी मात्रा में बिक्रियां हुईं और प्रमुख शेयर बाजारों ने मूल्यों में और गिरावट पर काबू पाने के लिए अल्पावधि बिक्रियों पर रोक लगा दी। उसके बाद मई में जब बही लाभों पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर कर से संबंधित बजट प्रस्ताव को आशोधित किये जाने और स्रोत पर कर की कटौती के प्रस्ताव को वापस लिये जाने के बाद बाजार की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ।

207. इन प्रवृत्तियों का द्योतक रिजर्व बैंक का सामान्य शेयर मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार 1980-81=100) जो 29 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 239.5 पर था, 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 248.6 पर जा पहुंचा। यह 24 मई को समाप्त सप्ताह में गिरकर 230.5 रह गया लेकिन 14 जून को समाप्त सप्ताह में फिर से बढ़कर 248.0 हो गया। उसके बाद सूचकांक में आमतौर पर गिरावट आयी और वह सितम्बर के अंत में 229.5 रह गया। अक्तूबर में कुछ सुधार के बाद वह कम होता हुआ 6 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 209.5 तक नीचे आ गया। उसके बाद सूचकांक 10 जनवरी तक 229.4 तक ऊपर उठा और उसके बाद सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होता हुआ 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में घटकर 219.3 पर रूक गया। अलबत्ता, 230.7 पर 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के लिए औसत सूचकांक 1985-86 के औसत की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष इसमें 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कई कंपनियों की सुधरी हुई लाभांश स्थिति से ईक्विटियों पर औसत सकल लाभ 1985-86 के 3.2 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर 1986-87 में 3.6 प्रतिशत हो गया।

208. ईक्विटी मूल्यों में अनियमित उतार-चढ़ावों ने प्राथमिक बाजार की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। हाल ही में देखा गया शेयर मूल्यों की प्रवृत्ति कुछ हद तक 1985-86 में पायी गयी असाधारण रूप से ऊंची वृद्धियों पर सुधारात्मक स्थिति मानी जा सकती है। आर्थिक मूलभूत बातों के काफी हद तक संतोषजनक होने के साथ बाजार के रूख में सुधार हो सकता है और पूंजी बाजार में पासा पलट सकता है।

विदेशी क्षेत्र विषयक गतिविधियां

भुगतान संतुलन

209. राजकोषीय वर्ष 1986-87 के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि चालू खाते में घाटा वर्ष के दौरान कुछ कम हो गया है, जबकि 1985-86 में इसमें तीव्र वृद्धि हुई थी। सकल देशी उत्पाद की तुलना में चालू खाते में घाटा (सरकारी अंतरणों सहित) जो 1985-86 के दौरान 2.4 प्रतिशत के ऊंचे स्तर तक जा पहुंचा था, व्यापार घाटे में कमी तथा परोक्ष खाते में कुछ सुधार की वजह से 1986-87 में घटकर 1.9 प्रतिशत के आस पास रह गया।

210. राजकोषीय वर्ष 1986-87 के दौरान, देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में, जिनमें रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां,

स्वर्णधारिताएं तथा विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं, मार्च 1987 के अंत में 331 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इनकी राशि 8,151 करोड़ रुपये हो गयी। जबकि 1985-86 के दौरान उनमें 577 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में ये निधियां £मार्च 1987 के अंत में 51,130 लाख विशेष आहरण अधिकारों के बराबर थी जो 1986-87 में 6,150 लाख विशेष आहरण अधिकार की गिरावट दर्शाती है। 1985-86 में इनमें 2,760 लाख विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट आयी थी। सारणी 29 में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आहरण और हाल ही के वर्षों में की गयी पुनर्खरीदें दर्शायी गयी हैं।

सारणी 29—भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

क्रम सं	निम्नलिखित माह के अंत में	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां					कोष से क्षतिपूर्ति निधि सुविधा तथा विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत संकल आहरण (दस लाख वि आ अ)	कोष से पुनः खरीद* (दस लाख वि आ अ)	शुद्ध आहरण (दस लाख वि आ अ) (8—9)
		वि आ अ (दस लाख)	वि आ अ** (लाख रु.)	स्वर्ण (लाख रु.)	विदेशी मुद्रा (लाख रु.)	जोड़ (लाख रु.) (स्तम्भ 4+5+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मार्च 1985	146.49	180,50	245,78	6816,79	7243,06	4166.00	199.50	3966.50
2.	जून 1985	303.67	376,89	246,67	6679,80	7303,36	4166.00	251.50	3914.50
3.	मार्च 1986	115.13	161,40	274,28	7384,35	7820,03	4166.00	397.25	3768.75
4	जून 1986	126.86	186,27	274,28	7084,91	7545,16	4166.00	466.00	3700.00
5.	मार्च 1987	139.44	231,76	274,28	7645,17	8151,21	4166.00	828.50	3337.50
6.	जून 1987 @	105.44	173,26	274,28	7276,44	7723,98	4166.00	953.50	3212.50

टिप्पणी : संकल आहरण और पुनः खरीद राशियां अगस्त 1980 से हैं, जब क्षतिपूर्ति निधि सुविधा का आहरण किया गया था।

*पुनः खरीद क्षतिपूर्ति निधि सुविधा और विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत है।

**संबन्धित महीनों के अंत में रुपया वि आ अ विनिमय दर पर।

@अनंतिम

£अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण का मूल्यन 35 विशेष आहरण अधिकार प्रति औंस दर पर किया गया है।

211. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि ऋण के संबंध में अदायगियों सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अदायगियां 1985-86 के 327 करोड़ रुपये की तुलना में 1986-87 में 840 करोड़ रुपये रहीं। मार्च 1987 के अंत में विस्तारित निधि सुविधा आहरणों तथा न्यास निधि ऋण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देयताएं 37,090 लाख विशेष आहरण अधिकारों के बराबर थीं। यह मौजूदा विनिमय दर पर 6,165 करोड़ रुपये के बराबर होती है।

पण्य कारोबार

212. 1986-87 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में, खास तौर पर निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 12,550 करोड़ रुपये के निर्यात 20.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि 1985-86 में इनमें 7.8 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। तेल से इतर निर्यातों में 1986-87 में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 1985-86 में यह वृद्धि 5.7 प्रतिशत की थी। अलबत्ता तेल के आयात बिल में काफी बचत करने के बावजूद कुल आयातों की वृद्धि मामूली-सी ही कम हुई। 1986-87 के दौरान 20,063 करोड़ रुपये के आयात पिछले वर्ष की 11.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। बाद में वर्ष के दौरान व्यापार घाटा 1985-86 के 7,951 करोड़ रुपये से 438 करोड़ रुपये घटकर 7,513 करोड़ रुपये रह गया।

213. निर्यातों में मात्रा की दृष्टि से वृद्धि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में तेल से इतर निर्यातों में 1986-87 के दौरान 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1985-86 में इनमें 2.4 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्यों तथा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ावों को ध्यान में रखने पर, हो सकता है कि 1986-87 में मात्रा की दृष्टि से भारत के निर्यात लगभग 7-8 प्रतिशत अधिक रहे हों। पिछले वर्ष इनमें मामूली-सी गिरावट आयी थी।

214. 1986-87 के लिए निर्यातों के पण्यवार उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि रत्नों और आभूषणों के निर्यातों में 37.5 प्रतिशत, चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यातों में 61.3 प्रतिशत और इंजीनियरी माल के निर्यातों में 27.5 प्रतिशत तथा काजू की गिरी के निर्यातों में 49.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यातों की बेहतर स्थिति का काफी श्रेय कपड़ों तथा तैयार, वस्त्रों, समुद्री उत्पादों, कॉफी तथा रसायनों और संबद्ध उत्पादों के अधिक निर्यातों को भी जाता है।

215. तेल निर्यातों को घटाकर, तेल के शुद्ध आयातों में 2,146 करोड़ रुपये की कमी आयी और वे 1986-87 के दौरान 2,656 करोड़ रुपये रह गये। इनसे स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट का पता चलता है। अलबत्ता, तेल से इतर आयात तेजी से बढ़ते रहे और 1986-87 में यह वृद्धि 29.6 प्रतिशत की रही, जबकि रुपये की दृष्टि से 1985-86 में यह वृद्धि 18.4 प्रतिशत की थी। विशेष आहरण अधिकार के रूप में इनमें पिछले वर्ष 9.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1986-87 में मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों, मोतियों तथा कीमती पत्थरों तथा कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के आयात काफी अधिक बढ़े। ये वृद्धियां पिछले वर्ष हुई वृद्धियों से अधिक थीं। मशीनरी आदि के आयातों में 1986-87 के दौरान 1985-86 के स्तर से 50.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोतियों, कीमती पत्थरों और कम कीमती

पत्थरों के निर्यातों में 35.2 प्रतिशत तथा कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के आयातों में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्यों में गिरावट से कुछ वस्तुओं जैसे कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और खाद्य तेलों के संबंध में भारत के आयात बिल में कुछ कमी आयी लेकिन गैर-तेल आयातों में कुल मिलाकर मात्रा की दृष्टि से वृद्धि काफी अधिक बनी रही ।

परोक्ष निर्यात

216. शुद्ध परोक्ष प्राप्तियों के संबंध में उपलब्ध आंकिक जानकारी से पता चलता है कि 1986-87 के दौरान परोक्ष प्राप्तियां, यात्रा प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। 1986-87 के दौरान भारत में आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 1985-86 के दौरान इनकी संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी सहायता के अंतर्गत तथा वाणिज्यिक शर्तों पर और अधिक ऋण लेने की वजह से निवेश आय से देश से बाहर जाने वाली राशियां निरंतर बढ़ती रहीं । परोक्ष निर्यातों की अन्य मदों के संबंध में आय पिछले वर्ष की तुलना से बहुत अधिक अलग प्रतीत नहीं होती।

विदेशी सहायता, द्विपक्षीय लेनदेन तथा कारोबारी ऋण

217. हाल ही के वर्षों में सकल विदेशी सहायता में घटी आ रही बढ़ोतरी की प्रवृत्ति 1986-87 के दौरान भी जारी रही। यह सहायता 3,532 करोड़ रुपये रही जो 1985-86 की तुलना में 645 करोड़ रुपये अधिक थी। विदेशी ऋणों पर परिशोधन भुगतानों की 1,166 करोड़ रुपये की राशि 1985-86 की 796 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता की शुद्ध प्राप्तियां 2,366 करोड़ रुपये रहीं जबकि 1985-86 के दौरान ये 2,091 करोड़ रुपये थीं। अमरीकी डालरों के रूप में 1986-87 के दौरान विदेशी सहायता की प्राप्तियां 18,520 लाख अमरीकी डालर थीं, इसकी तुलना में 1985-86 में यह राशि 17,090 लाख अमरीकी डालर थी। 1986-87 के दौरान द्विपक्षीय खाता रखनेवाले देशों के साथ लेनदेनों की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशियां देश से बाहर गयीं। 1985-86 में वाणिज्यिक उधारों का 1.5 अरब अमरीकी डालर की सीमा तक सहारा लिया गया और इस तरह के ऋणों की अदायगियों की शुद्ध राशि 1.0 अरब अमरीकी डालर रही। ऐसा प्रतीत होता है कि 1986-87 के दौरान वाणिज्यिक ऋणों का पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक योगदान रहा ।

अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि

218. 1986-87 के दौरान अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों के अंतर्गत आने वाली राशियां पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजनाओं के अंतर्गत मामूली सी अधिक थीं 1986-87 के दौरान अनिवासी (विदेशी) रुपया योजना के अंतर्गत वृद्धि (अनुमानित ब्याज अंश को छोड़कर), जिनके लिए अनंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं, 1985-86 के दौरान के 281 करोड़ रुपये की तुलना में 485 करोड़ रुपये रहीं । 1986-87 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत शुद्ध प्राप्तियां 1985-86 के 1,151 करोड़ रुपये की तुलना में 1,169 करोड़ रुपये थीं। इन अनिवासी खातों के अंतर्गत 1985-86 में 1,432 करोड़ रुपये और 1986-87 में 1,654 करोड़ रुपये की बड़ी मात्रा में प्राप्तियों से वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन को काफी सहारा मिलता रहा।

विदेशी मुद्रा आस्तियां

219. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के तीन घटकों में से, रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान वृद्धि । 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों में 192 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1985-86 की इसी अवधि के दौरान 405 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

विशेष आहरण अधिकार

220. 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान विशेष आहरण अधिकारों की धारिताओं में 214 लाख विशेष आहरण अधिकारों की कमी आई 1985-86 के दौरान 1,768 लाख वि. आ. अ. की कमी आयी थी 1986-87 के दौरान वि. आ. अ. धारिताओं के स्तर में यह कमी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4,875 लाख विशेष आ. अ. की पुनर्खरीद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 2,975 लाख वि. आ. अ. के बराबर प्रभारों ब्याज का भुगतान, 7,150 लाख वि. आ. अ. के बराबर वि. आ. अ. की प्राप्ति, अनुपूरक वित्तपोषण सुविधा प्रभारों के रूप में 254 लाख वि. आ. अ. की ब्याज सहायता तथा वि. आ. अ. धारिताओं पर ब्याज तथा 232 लाख वि. आ. अ. के बराबर प्राप्त पारिश्रमिक का शुद्ध परिणाम थी ।

स्वर्ण

221. रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं, जिनमें 1985-86 के दौरान 28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, वे 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान जून 1986 के अंत के स्तर पर अर्थात् 274 करोड़ रुपये रहीं ।*

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां

222. तेल मूल्यों में कमी और पण्य मूल्यों में लगातार गिरावट की वजह से औद्योगिक देशों को लगभग 100 अरब डालर के स्रोतों के विशाल अंतरण के बाद 1986 के दौरान उनकी आय वृद्धि में काफी अधिक सुधार की आशा की गयी थी, किंतु यह सुधार नहीं हुआ। वस्तुतः, औद्योगिक देशों ने पिछले वर्ष की 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 1986 में 2.4 प्रतिशत की कम वृद्धि दर दर्ज की। अलबत्ता, मात्रा की दृष्टि से विश्वव्यापी व्यापार में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि 1986 की 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। ईंधन से इतर वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों ने भी अपनी वृद्धि स्थिति को बेहतर बनाया और उसे 1985 के 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 1986 में 5.4 प्रतिशत पर ले आये और साथ ही मात्रा की दृष्टि से अपने निर्यातों को 5.2 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत कर दिया । ईंधन से इतर वस्तुओं का निर्यात करने वाले विकासशील देशों के चालू खाता घाटे और कम हो गये। अलबत्ता, उन्हें अंतरित की गयी शुद्ध राशियां (उनके द्वारा प्राप्त सकल ऋणों में से ऋण अदायगी घटाकर) 1986 में फिर बढ़ गयी परिणाम यह हुआ कि एक समूह के रूप में उनकी निवेश गतिविधि में रुकावट आयी और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में और गिरावट के बावजूद पूंजी आयात करने वाले विकासशील देशों का ऋण अदायगी अनुपात 1985 के 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 1986 में 24.7 प्रतिशत हो गया।

223. विश्व के अधिकतर देशों में मुद्रास्फीति की दरें निरंतर कम होती जा रही है। 1986 के दौरान औद्योगिक देशों में 2.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर पिछले 25 वर्षों में सबसे कम थी और इसके साथ ही 1986 में तेल मूल्यों में गिरावट तथा तेल से इतर पण्यों के मूल्यों में निरंतर कमी ने अपना योगदान दिया। विकासशील देशों के समूह में, जहां ईंधन से इतर निर्यातकों में मुद्रास्फीति की औसत दर 1985 के 55.9 प्रतिशत से कम होकर 1986 में 33.1 प्रतिशत रह गयी, वहीं ईंधन निर्यातक देशों में मूल्य वृद्धि 1985 के 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो गयी।

224. मुद्रास्फीति की दरों में काफी बड़ी असमानताओं की वजह से कई देशों में विनिमय दरों की गतिविधियों पर लगातार दबाव पड़ता जारी रहा, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों में अनिश्चितता बढ़ती रही। अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में स्वागत योग्य कमी जारी रही। हालांकि कुछ

*प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपये के सांकेतिक धारिता मूल्य के अनुसार निर्धारित मूल्य

समय से अमरीकी डालर की ब्याज दरों में कमी आयी है, जो सं. रा. अमरीका में बड़ी मात्रा में चालू खाता घाटे के वित्तपोषण की जरूरत को दर्शाता है। छमाही जमाराशियों के लिए यूरो डालर दर जून 1986 के अंत के 6.8 प्रतिशत से गिरकर अक्तूबर 1986 के अंत में 5.9 प्रतिशत रह गयी, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ते हुए जून 1987 के अंत में 7.3 प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर यूरो येन और यूरो ड्यूश मार्क की जमा दरें उसी अवधि में जून 1986 के अंत की 4.6 प्रतिशत से घटकर जून 1987 के अंत में 4.0 प्रतिशत के आसपास रह गयीं। यूरो अमरीकी दर के उतार चढ़ाव के अनुरूप अमरीका में प्रमुख दर जून 1986 को 8.5 प्रतिशत से कम होकर अक्तूबर 1986 में 7.5 प्रतिशत रह गयी, लेकिन उसके बाद बढ़कर जून 1987 में 8.25 प्रतिशत हो गयी।

225. अमरीकी डालर, येन तथा ड्यूशमार्क की विनिमय दरों में उल्लेखनीय एकरूपता आने के बावजूद इन देशों की चालू खाता शेष राशियों में 1986 के दौरान असंतुलन और बढ़ गये। इससे प्रशुल्कवाद दबावों को बढ़ावा मिला और व्यापारिक संबंधों में तनाव आया। अमरीका के चालू खाते का घाटा 1985 के 118 अरब डालर से बढ़कर 1986 में 141 अरब डालर हो गया, जबकि जापान तथा पश्चिम जर्मनी के अधिशेष 49 अरब डालर तथा 13 अरब डालर से बढ़कर क्रमश: 86 अरब डालर तथा 36 अरब डालर हो गये। इस बात को 2 वर्ष से अधिक हो चुके हैं कि इन मुद्राओं की विनिमय दरें सही दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी चालू खाता शेष राशियों में वांछित समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। अब यह सोचा गया है कि उनकी चालू खाता स्थिति में विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव को महसूस करने में अपेक्षाकृत काफी समय लगेगा।

226. अभी हाल ही में व्यापार में मात्रा की दृष्टि से कुछ परिवर्तनों के संकेत मिले हैं, जिनसे चालू मुद्रा दरों के पुनर्निर्धारण के प्रभाव का पता चल सकेगा। अलबत्ता, जापान और पश्चिम जर्मनी में घरेलू मांग इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि वह विदेशी मांग में कमी की भरपाई कर सके और इन सबका प्रभाव कुछ ही समय में विश्वव्यापी निवेश और वृद्धि पर पड़नेवाला है।

227. जिन विकासशील देशों का तेल से इतर निर्यातकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनकी 5.4 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हालांकि औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी जरूरतों की तुलना में पर्याप्त नहीं थी। औद्योगिक देशों में वृद्धि के लिए और मध्यावधि तक विश्वव्यापी व्यापार विस्तार के लिए वातावरण असंतोषजनक बना रहा। विकासशील देशों के समूह में भी उचित शर्तों पर बेहतर वित्तीय साधन जुटाने के आसार बहुत अच्छे नहीं हैं। परिणाम यह होगा कि इस समूह के देशों की चालू खाता स्थिति पर दबाव पड़ सकता है।

228. कुछ समय से विकासशील देश औद्योगिक देशों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने नीतिगत भेदभावों को दूर करें और अपने विकास में सुधार लायें, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है उनसे मुक्ति मिल सके। अब इस विचार को कई देशों का समर्थन मिल रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि विकसित देश शीघ्र ही उचित कार्रवाई करेंगे। सितंबर 1986 में उरुगुए में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार में हिस्सा लेनेवाले देशों द्वारा शुरु की गयी बहुपक्षीय व्यापार वार्ता को पूरा करने में कुछ वर्ष लगेंगे। तब तक खुले व्यापार की पद्धतियों को प्रशुल्कवाद के बढ़ते हुए दबावों से बचाने की जरूरत है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के अधिक हित के लिए यह उचित है कि विकासशील देशों के निर्यात, जो प्रतिस्पर्धा में ठहर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के औद्योगिक देशों के बाजारों में पहुंच सकें। पिछले कुछ वर्षों में विकासशील देश अपनी वृद्धि के साथ समायोजन करने के प्रयासों में जिस सबसे बड़ी अड़चन का सामना कर रहे हैं, वह है, आसान शर्तों पर पर्याप्त वित्त का मिलना। बहुपक्षीय संस्थाओं को, उनके सदस्यों द्वारा, इस बात के लिए प्रेरित किये जाने की जरूरत है कि वे अपने वित्त प्रदान करने के कार्य बढ़ायें, इसके लिए संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध कराये जाने चाहिये। विकासशील देशों को आधिकारिक विकास सहायता प्रदान कर रहे औद्योगिक और अन्य देशों को चाहिये कि वे अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करें, ताकि वे अपनी सहायता में काफी वृद्धि कर सकें। औचित्यपूर्ण मामलों में ऋणों की अवधि में फेरबदल करने की जरूरत है, ताकि वार्षिक ऋण चुकौती की राशियों में कमी लायी जा सके। कुछेक मुद्राओं में लिये जाने वाले ब्याज के संबंध में सांकेतिक और वास्तविक दरों को भी कुछ नीचे लाने की गुंजाइश है और नीतियों को इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है।

विनिमय दर संबंधी गतिविधियां

229. मई 1986 की टोकियो घोषणा के अनुसरण में ग्रुप 5/ग्रुप 7 के वित्त मंत्रियों ने वर्ष के दौरान प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों में सापेक्ष स्थिरता लाने के अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने समूह के बीच सापेक्ष ब्याज दरों में उचित संशोधन करते हुए तथा प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों की अपेक्षित श्रृंखला के समर्थन में सहमत दखल से नीतिगत समायोजनों पर एकमत होने के प्रयास किये। कई बार बातचीत सिर्फ ग्रुप-3 तक सीमित होकर रह गयी और द्विपक्षीय भागीदारी और सहमतियों की बात उभर कर ऊपर आने लगी। यह बात अक्तूबर 1986 में अमरीका और जापान के बीच हुई संधि से स्पष्ट हो जाती है। बाद में फरवरी 1987 में पेरिस तथा अप्रैल 1987 में वाशिंगटन में हुई बैठक से विनिमय में स्थिरता लाने के उपाय सुनिश्चित करने की दर को नया की पुष्टि कर दी और इसी की फिर से पुष्टि जून 1987 में वेनिस बैठक में हो गयी। अलबत्ता, विनिमय बाजारों में अस्थिरता अभी भी बरकरार है।

230. लगातार दूसरे वर्ष भी, अमरीकी डालर 1986-87 (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख मुद्राओं और वि. आ. अ. के मुकाबले कमजोर बना रहा। मासिक औसतों के आधार पर, डालर 1986-87 में वि. आ. अ. के मुकाबले नवम्बर 1986 और जून 1987 को छोड़कर हर महीने कमजोर बना रहा। इसी तरह ड्यूश मार्क की तुलना में, यह नवम्बर 1986, मार्च तथा जून 1987 को छोड़कर नीचे गिरा तथा येन के मुकाबले यह सितम्बर से नवम्बर 1986 और जून 1987 को छोड़कर सभी महीनों में कमजोर बना रहा। पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले डालर अगस्त से नवम्बर 1986 और जून 1987 में कमजोर बना रहा।

231. वर्ष 1986-87 के दौरान अमरीकी डालर में ड्यूशमार्क, येन तथा वि. आ. अ. की तुलना में मूल्यह्रास 1985-86 में हुए मूल्यह्रास की अपेक्षा अधिक था, लेकिन यह पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले कम रहा। अवधि के औसत (जुलाई-जून 1985-86 की तुलना में जुलाई-जून 1986-87 में) के रूप में, डालर येन के मुकाबले 22.7 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर हो गया, जबकि पिछले वर्ष उसके मूल्य में गिरावट 20.8 प्रतिशत रही थी। पिछले वर्ष के मुकाबले 1986-87 के दौरान अन्य मुद्राओं की तुलना में डालर के मूल्यों में गिरावट की तुलनात्मक दरें इस प्रकार रहीं, ड्यूशमार्क 22.4 प्रतिशत तथा 19.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग 5.6 प्रतिशत तथा 15.2 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकार 11.5 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत। येन में पौंड स्टर्लिंग, डालर तथा वि. आ. अ. की तुलना में पिछले वर्ष के मुकाबले और मजबूती आयी, लेकिन यह ड्यूश मार्क के मुकाबले कमजोर हुआ यही बात पौंड स्टर्लिंग, डालर तथा वि. आ. अ. की तुलना में ड्यूश मार्क के संबंध में भी रही। पौंड स्टर्लिंग डालर मुकाबले सुधरा, लेकिन ड्यूश मार्क, येन तथा वि. आ. अ. के मुकाबले कमजोर हो गया।

रुपये की विनिमय दर

232. रुपये की मूल्य भारत के प्रमुख कारोबारी भागीदारों के शामिल मुद्रा समूहों से तथा मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में पौंड स्टर्लिंग के

सन्दर्भ में निर्धारित होता रहा। कार-स्टर्लिंग दर में 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान समायोजनों की कुल संख्या 141 रही, जबकि 1985-86 में 149 बार समायोजन किये गये थे। अमरीकी डालर के मुकाबले रुपया मोटे तौर पर स्थिर बना रहा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, येन, ड्यूश मार्क, पाउंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक तथा फ्रेंच फ्रैंक के मुकाबले अमरीकी डालर मूल्य में गिरावट को देखते हुए रुपया इन मुद्राओं तथा वि. आ. अ. के मुकाबले नरम रहा।

रुपया-रूबल विनिमय दर

233. रुपया रूबल की विनिमय दर में 1986-87 (जुलाई-जून) में चार बार अर्थात् 17 जुलाई, 21 सितम्बर, 4 दिसम्बर, 1986 को तथा 23 जनवरी 1987 को परिवर्तन किया गया। परिणामस्वरूप रुपया-रूबल दर जो जून 1986 के अंत में 12.96 रुपये प्रति रूबल थी, जून 1987 के अंत में 14.79 रुपये प्रति रूबल हो गयी, इससे इस अवधि के दौरान रुपये में 12.4 प्रतिशत की नरमी का पता चलता है।

मूल्यांकन और संभावनाएं

234. 1986-87 के दौरान अर्थव्यवस्था की गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित वृद्धि की दर यथावत बनाये रखी गयी है। कृषि को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल मौसम के बावजूद 1986-87 में अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि दर, 1985-86 के मुकाबले थोड़ी-सी ही कम रहने की संभावना है, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रही थी। हालांकि कृषि की वृद्धि दर में स्थिरता और औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में अल्प वृद्धि दर चिन्ता का विषय हैं, लेकिन घरेलू क्षेत्र में बचत की दर में थोड़े से सुधार और सुधरी हुई निर्यात स्थिति को वर्ष 1986-87 में अर्थव्यवस्था की कुछ खास बातों के रूप में देखा जा सकता है। तेल के मूल्यों में काफी कमी और उनके परिणामस्वरूप तेल के आयात बिल में कमी के बावजूद व्यापार घाटा थोड़ा ही कम हो पाया। इस वजह से भुगतान संतुलन के क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है।

235. 1987 में अच्छे मानसून की आशा थी लेकिन उसने बहुत निराश किया। अगस्त के पहले सप्ताह के अंत तक देश के 35 मौसम वैज्ञानिक उप प्रभागों में से केवल 9 उप प्रभागों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप देश में भयानक सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है। 1987-88 में कृषि उत्पादन में भारी गिरावट के अलावा इतना बड़ा सूखा सरकार के वित्तीय साधनों पर भी असर डालेगा, क्योंकि राहत कार्यों पर व्यय बढ़ेगा। 1987-88 में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य भी उत्साहजनक नहीं होगा, क्योंकि बिजली की उपलब्धता अंशतः वर्षा पर निर्भर है। कृषि पैदावार अच्छी न होने का असर औद्योगिक क्षेत्र पर दो तरह से पड़ेगा—एक तो कच्चा माल कम उपलब्ध होगा, दूसरे मांग में गिरावट आयेगी। इस पृष्ठभूमि में मूल्य स्थिति पर सावधानी से नजर रखनी होगी। अनाज के उत्पादन में होनेवाली गिरावट को अनाज के भारी भंडारों में से निकालकर पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार 1987-88 के लिए अच्छी संभावनाएं नहीं हैं। हालांकि अगस्त के अंत और सितंबर की बरसात का सहायक असर, विशेषकर सर्दी की फसल पर होगा। भविष्य में पैदा होनेवाले अनेक तनावों के कारण, यदि विकास की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार की बाधा से बचाना है तो बड़ी निपुणता से आर्थिक व्यवस्था करनी होगी।

236. सातवीं पंचवर्षीय योजना का अब तीसरा वर्ष चल रहा है। हाल ही के वर्षों के वृद्धि के पैटर्न पर एक निगाह डालना उपयोगी रहेगा। हालांकि सकल देशी उत्पाद में संतोषजनक वृद्धि दर प्राप्त कर ली गयी है, ऊंची वृद्धि दर अंशतः कृषि और विनिर्माण जैसे पण्य उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि की तुलना में तृतीयक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि की स्थिति दर्शाती है। वार्षिक औसत आधार पर 1985-86 में समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि के दौरान कृषि में सकल मूल्य में वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रही, जबकि विनिर्माण में सकल मूल्य में वृद्धि दर इसी अवधि में 5.9 प्रतिशत रही। इसके विपरीत, तृतीयक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत तक ऊंची रही जो मुख्य रूप से लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा घटक में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। सकल देशी उत्पाद में इस घटक का हिस्सा 1980-81 के 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 9.6 प्रतिशत हो गया। अब कुल मिलाकर तृतीयक क्षेत्र का सकल देशी उत्पाद में योगदान 40 प्रतिशत का है। जहां तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई विविधता की द्योतक है, भारत जैसे विशाल देश में, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसके विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, पण्यों का उत्पादन करने वाले मजबूत और सक्रिय क्षेत्र की जरूरत है, जिससे निरन्तर आधार पर आर्थिक वृद्धि प्राप्त की जा सके।

237. कृषि क्षेत्र का कार्य अधिकांशतः अनाज की पैदावार पर निर्भर करता है जो कुल कृषि क्षेत्र के तीन-चौथाई से कुछ ही कम है। मानसून के विपरीत होने से अनाज के उत्पादन पर जो असर पड़ता उसे कुछ हद तक सिंचित क्षेत्र में लगातार और काफी वृद्धि करके तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसी निवेश-वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करके कम किया गया है। 1980-81 में 430 लाख हेक्टेयर में अधिक पैदावार वाले बीजों की किस्में बोयी जाती थीं जो बढ़कर 1985-86 में 550 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रमाणित बीजों का वितरण 1980-81 में 25 लाख क्विंटल था जो बढ़कर 1985-86 में 55 लाख क्विंटल हो गया है। उर्वरकों की खपत 1980-81 के 55 लाख टन से बढ़कर 1985-86 में 87 लाख टन हो गयी है। कृषि क्षेत्र के, हाल ही के कार्य में संस्थागत ऋण ने भी अहम भूमिका निभायी। किन्तु ऋण की उपलब्धता का सर्वोत्तम प्रभाव वहीं पड़ा है जहां सिंचाई सुविधाएं और अन्य निवेश सामग्री की व्यवस्था के लिए मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह विकसित हैं।

238. समग्र लचीलेपन के बावजूद उत्पादन और उपज में काफी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में औसत उपज 1981-82 और 1985-86 के बीच 27.4 प्रतिशत बढ़ी। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इन तीन राज्यों का हिस्सा भी 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 37.6 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान इन तीन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसने कुल खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि में 75.5 प्रतिशत का योगदान दिया। पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों और साथ ही मध्य प्रदेश ने भी उत्पादन का अच्छा स्तर दर्शाया। 1981-82 और 1985-86 के बीच असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में औसत उत्पादन 26.9 प्रतिशत बढ़ा है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में उनका हिस्सा 26.6 प्रतिशत से बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गया है। अलबत्ता, पश्चिम बंगाल को छोड़कर इन राज्यों में औसत उपज अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के समूह में, जिसका 1985-86 के खाद्यान्न उत्पादन में हिस्सा 41.0 प्रतिशत था, गतिहीनता या लगभग गतिहीनता की स्थिति बनी हुई है। भले ही उपजों में क्षेत्रीय अंतर से [illegible] प्राकृतिक विशेषताओं का पता चलता है, फिर भी, देश के कई हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन की उपज बढ़ाने की अभी भी बहुत गुंजाइश है।

239. इसके अलावा, कुछ वाणिज्यिक फसलों में मांग-पूर्ति के बीच असंतुलन बने हुए हैं। इनमें भी, शायद तिलहन के क्षेत्र में सबसे अधिक असंतुलन विद्यमान है, इसीलिए बड़ी मात्रा में आयात में किये जाने की जरूरत है।

240. तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में सफलता पाने की महत्ता का पता इसी बात से चलता है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कई व्यापक उपाय किये जा रहे हैं। मिशन की सफलता में इस बात का भी योगदान है कि तिलहन के मूल्यों में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। अलबत्ता, मूल्यों में इस वृद्धि का लाभ अक्सर किसान तक नहीं पहुंच

पाता। इसलिए बाजार की व्यवस्थाओं को मजबूत किये जाने की जरूरत है जिससे तिलहन उत्पादकों को वास्तव में मदद मिल सकेगी।

241. हाल ही के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के संकेत मिले हैं। औद्योगिक उत्पादन के 1980-81 के आधार वाले नये सूचकांक से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 1984-85 में 8.6 प्रतिशत तथा 1985-86 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सूचकांक ने 1986-87 के पहले 10 महीनों के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पूंजी की उत्पादकता में भी कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में पूंजी उत्पादन अनुपात में कुछ गिरावट आयी है, लेकिन कुछ घटकों की उत्पादकता वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस वृद्धि में आधारभूत उद्योगों के सुधरे हुए कार्य-निष्पादन ने भी अपना योगदान दिया है। कुछ भी हो, पूंजी के इस्तेमाल में तथा उत्पादन की इकाई लागत में कमी लाने में ज्यादा कुशलता लाने की एक निरन्तर जरूरत बनी हुई है, ताकि औद्योगिक माल के लिए मांग के क्षेत्र को और विस्तार दिया जा सके।

242. 1986-87 के दौरान कई उद्योगों ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास स्टॉक जमा हो गये हैं। इनमें उत्पादन और माल उठाये जाने के बीच के फर्क से बने माल भी शामिल हैं। इनमें अधिक उल्लेखनीय माल में उर्वरक, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात तथा जीपें शामिल हैं। इस तरह के माल जमा होने के पीछे हर उद्योग के लिए अलग-अलग कारण हैं, आयातों और उत्पादन के बीच समायोजन पर इस रूप में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि उपलब्धता और मांग साथ-साथ चल सकें। कुछ उद्योगों में मांग की कमी के लिए कृषि के क्षेत्र में कामकाज को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिन उद्योगों के पास स्टॉक जमा हो गये हैं, उनके मामले में अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें कुछ राहत दिलायी जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त माल के लिए अनिश्चित समय तक ऋण जारी रखने से माल की असहनीय सीमा तक कीमत बढ़ सकती है।

243. भारतीय उद्योग इस समय संरक्षित से अधिक प्रतियोगी माहौल की तरफ जाने के दौर से गुजर रहा है। लाइसेंस और आयात आदि को उदार बना देने से देशी और साथ ही अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। भारतीय उद्योग के ढांचे में कुछेक परिवर्तन किये जा रहे हैं। कुछ पुराने उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग अपनी महत्ता खो रहे हैं, जबकि रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की जड़ें गहरी हो रही हैं। संक्रमण काल की इन जरूरतों को बहुत ही सावधानीपूर्वक पूरा करना होगा, ताकि कम से कम विपरीत प्रभाव पड़े। लाइसेंस विनियमों आदि में ढील दिये जाने से निगम और गैर निगमित संस्थाओं के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वे भविष्य की बाजार जरूरतों के बारे में ठोस निर्णय कर सकें। यहां वित्तीय संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हालांकि क्षमता और मांग के बीच के कुछ असंतुलनों से बचा नहीं जा सकता और क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए हो सकता है, कुछ उपाय करने वांछनीय भी हों, परंतु समग्र रूप से पूंजी की कमी को देखते हुए किसी समय 'वरीय' समझे जाने वाले उद्योगों में ही पूंजी के केन्द्रीकरण से बचना होगा, क्योंकि इस प्रकार के केंद्रीकरण से औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न हो सकती है।

244. आयातों को उदार बनाये जाने से जरूरत की निवेश वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है और इससे औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए टेक्नालॉजी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिये। अलबत्ता, इस बात में सावधानी बरतनी होगी कि देशी उद्योगों को, खास तौर पर वहां, जहां वे पर्याप्त रूप से कुशल हैं, बड़े झटके न लगें। भुगतान संतुलन पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

245. पिछले तीन दशकों के दौरान भारत ने पूंजीगत माल की बहुत-सी किस्मों के उत्पादन के लिए एक बहुत ही शानदार आधार तैयार किया है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलम्बन का स्थान हासिल किया है। अलबत्ता, पूंजीगत माल के उद्योगों के कई घटकों में मौजूद टेक्नालॉजी पुरानी पड़ चुकी है। यह सीमित तथा रक्षित माहौल की वजह से हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि पूंजीगत माल के उद्योगों में स्तर और लागत की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए; अन्यथा उपभोक्ता क्षेत्रों तथा निर्यातों के लिए इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद, आयातों पर शुल्कों के जरिये मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने होंगे, ताकि इस क्षेत्र में कुशलता को बढ़ावा मिल सके। यह बदलाव की स्थिति धीरे-धीरे और चयनात्मक आधार पर हो और इसके लिए हर क्षेत्र की खास-खास बातों को ध्यान में रखा जाये।

246. पिछले वर्षों में पूंजी लगातार बढ़ रही है। इससे निजी निगमित क्षेत्र को और कुछ समय से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अपनी निवेश संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए वित्त जुटाने में काफी मदद मिलती है। इन्हीं प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए ईक्विटी मूल्य आमतौर पर ऊंचे बने रहे और 1985-86 में अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर जा पहुंचे। उस समय कुछ ईक्विटियां इतने ऊंचे मूल्यों पर बिक रही थीं कि वास्तव में संबंधित आधारभूत मूल्यों से काफी बाहर थीं।

247. 1986-87 के दौरान पूंजी बाजार ने मिली-जुली प्रवृत्तियां दर्शायीं। आम तौर पर अनुमोदन और नये पूंजी निर्गम, दोनों ही पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से काफी ऊंचे थे। परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम और ईक्विटी निर्गम ऊपर चढ़े लेकिन गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम नीचे आ गये। 1986-87 में ईक्विटी मूल्यों की प्रवृत्तियां अनियमित ही रहीं। प्राथमिक बाजार पर इसका 1986-87 की दूसरी छमाही में और विशेष रूप से अंतिम तिमाही में विपरीत प्रभाव पड़ा। कई नये निर्गमों को कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले।

248. हालांकि पूंजी बाजार में तीव्र और निरन्तर बनी रहने वाली ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति चिंता की बात है, फिर भी हाल ही की घटनाओं को उचित नजरिये से देखने की जरूरत है। तेजी से नीचे आने के बावजूद रिजर्व बैंक का साधारण शेयर मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार 1980-81=100) जून 1987 में 201.8 पर स्थित रहा जबकि 1984-85 में यह 136.0 के औसत पर था। यह 48.4 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। 1985-86 में मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बाद से बाजार कुछ हद तक अपरिहार्य सुधारात्मक दौर से गुजर रहा है।

249. बाजार में अच्छे, भरोसेमंद शेयरों की अपेक्षाकृत कमी है तथा कुछ कम्पनियों की निष्पादकता में हुए उतार-चढ़ावों ने बाजार के रुख को बुरी तरह प्रभावित किया है। अलबत्ता, इस खामी को समय के बीतने के साथ ही तभी दूर किया जा सकता है, जब अच्छी और बेहतर निष्पादकता वाली फर्में बाजार में अपनी जगह बनाती हैं। कुल मिलाकर, पूंजी बाजार की सारी मजबूती निगम क्षेत्र की निष्पादकता पर निर्भर करती है। जब निगमित क्षेत्र अच्छे परिणाम देने लगेगा तो निवेशकों का विश्वास लौट आयेगा।

250. इस बात में कोई शक नहीं है कि निगमित क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक जीवन्त और सक्रिय शेयर बाजार जरूरी है। अलबत्ता रुकावटें डालने वाले उतार-चढ़ावों से यदि बचना है तो बाजार की जरूरतों को अच्छी तरह से विकसित करना होगा। यदि ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते बाजार मूल्यों की तेज गति को रोकना है तो भीतरी लोगों और बाहरी ताकतों द्वारा बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को कड़ाई से हतोत्साहित करना होगा।

251. बाजार के ढांचे, उसकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा टेक्नालॉजी में सुधार की जरूरत है ताकि निवेशकों को तुरंत और कुशल सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इन मामलों पर सरकार पहले ध्यान दे रही है। इस संबंध में एक पर्यवेक्षी और नियामक बोर्ड की तत्काल स्थापना की जरूरत है।

252. बाजार स्थितियों में काफी विविधता देखने में आयी है। पूंजी बाजार में कई वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी भी बहुत बढ़ गयी है। वाणिज्य बैंक पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हुए हैं। अपने व्यापारिक बैंकिंग प्रभागों अथवा पट्टेदारी अथवा व्यापारिक बैंकिंग सहायक कम्पनियों के जरिए बैंक पूंजीगत निर्गमों की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं तथा अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। वे काफी बड़ी मात्रा में नये निर्गमों की हामीदारी कर रहे हैं। बैंक मजबूत और भरोसेमंद पार्टियों तथा सुनियोजित परियोजना प्रस्तावों को प्रायः नाम और समर्थन देकर तथा संदेहास्पद रिकार्ड और संभावनाओं वाले प्रस्तावों तथा पार्टियों की ओर ध्यान न देकर एक मजबूत बाजार के विकास में भी सहायता दे रहे हैं। हालांकि इन बांडों को जारी करनेवालों को भी आशा और से गहन विपणन प्रयास करने की भी जरूरत होती है। अलबत्ता, प्राथमिक निधियों की ऊंची अपेक्षाओं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की उनकी वचनबद्धताओं तथा कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने की उनकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए पूंजी बाजार में उनकी वित्तीय गतिविधियां निश्चित रूप से सीमित और सट्टेबाजी से परे होनी चाहिएं।

253. राजकोषीय स्थिति के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राजस्व खाते में बड़ी मात्रा में बजटीय घाटे, जिसका वित्तपोषण पूंजी बजट के अधिशेषों से किया गया था, के जारी रहने के बारे में बताया गया था। इसका परिणाम यह होता है कि विकास व्यय की कीमत पर वित्तीय चालू व्यय के ये स्त्रोत पहले ही खाली हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति 1987-88 के दौरान भी जारी रही। असंतुलन की यह स्थिति रातों-रात होनेवाली कोई घटना नहीं है। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दरों तथा राजस्व व्ययों के बीच एक लगातार खाई बनी रही है। इन दोनों के बीच गठनात्मक असंतुलन से मूलतः इसी तथ्य का पता चलता है कि चालू मूल्योंपर आय के संबंध में राजस्वों में वृद्धि (1974-75 से 1984-85 की अवधि में 1.022 से अधिक अनुमानित) राजस्व व्यय (इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि 1.232) से कम है। हालांकि सकल देशी उत्पाद में कर प्राप्तियों का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ रहा है, सकल देशी अनुपात में योजनेतर व्यय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। योजनेतर व्यय की ऊंची दर ने न केवल राजस्व में वृद्धि के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया है बल्कि साथ ही योजना के स्त्रोतों को भी खाली कर दिया है। सकल देशी उत्पाद में केन्द्र के कर का अनुपात (प्रतिशत रूप में) 1980-81 के 10.3 से बढ़कर 1984-85 में 10.9 तथा 1986-87 में और बढ़कर 12.0 हो गया; सकल देशी उत्पाद में योजनेतर व्यय का अनुपात 1980-81 के 10.2 से बढ़कर 1984-85 में 11.6 तथा 1986-87 में और बढ़कर 13.8 हो गया। योजनेतर व्यय के भीतर प्रतिरक्षा ब्याज के भुगतानों तथा सहायता राशि जैसी मदों में वृद्धि अधिक मुखर थी। सातवीं योजना में इन मदों में वृद्धि की मात्रा बहुत अधिक रही है। कुल योजनेतर व्यय में इन मदों का हिस्सा 1984-85 के 67.2 से तेजी से बढ़कर 1987-88 के बजट में 73.3 प्रतिशत हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चालू राजस्व की शेष राशियां अर्थात् योजनेतर राजस्व व्यय पर चालू राजस्वों का अधिशेष 1986-87 के (—)532 करोड़ रुपये से और कम होकर 1987-88 में (—)1,612 करोड़ रुपये हो गया।

254. राजस्व और व्यय के बीच स्त्रोतों के असंतुलन से अधिक मात्रा में ऋण लेने की प्रवृत्ति सामने आयी है। 1987-88 के दौरान केन्द्र के शुद्ध बाजार ऋणों से योजना व्यय की 26.6 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा जबकि 1986-87 में 23.1 प्रतिशत और 1984-85 में 24.4 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ था। सहकारी क्षेत्र के उद्यमों के देशी और बाहरी ऋणों को हिसाब में लेने के बाद उधार ली गयी निधियों से योजना परिव्यय के 33.6 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा जबकि 1986-87 में इन निधियों ने 33.0 प्रतिशत का वित्तपोषण किया था। बाजार ऋणों का बहुत अधिक सहारा लेने का प्रभाव निश्चित रूप से यह पड़ा है कि ऋण चुकाने का भार बढ़ गया है। 1987-88 के दौरान केवल ब्याज भुगतानों में ही कुल योजनेतर व्यय का 27.1 प्रतिशत हिस्सा निकल जाएगा, तीन वर्ष पहले यह अनुपात 23.8 प्रतिशत था। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों के ऋण भुगतानों को एक साथ मिलाया जाए तो ये 1987-88 में सकल देशी उत्पाद में 4.1 प्रतिशत होंगे जबकि 1984-85 में यह प्रतिशत 3.4 था।

255. हमारे सामने मुख्य कार्य यह है कि स्त्रोतों के असंतुलन पर काबू पाया जाए और योजना के लिए पर्याप्त राशियां जुटायी जाएं। अधिक उधार लेने से भविष्य के लिए समस्याएं जुड़ती चली जाएंगी, खासकर तब, जब इन निधियों से खड़ी की गयी आस्तियों पर प्रतिफल की दर अदा किये जाने वाले ब्याज की दर से भी कम पड़ जाए। सकल देशी उत्पाद में समग्र कर के अनुपात को 20 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाने की गुंजाइश का पता लगाने की जरूरत है।

256. 1986-87 में लगातार दूसरे वर्ष भुगतान संतुलन पर काफी दबाव बना रहा, हालांकि सकल देशी उत्पाद अनुपात में चालू खाता घाटे की तुलना में कुछ सुधार दिखाई दिया। यह घाटा वर्ष 1985-86 के 2.4 प्रतिशत से घटकर 1986-87 में लगभग 1.9 प्रतिशत रह गया था। मात्रा की दृष्टि से 1986-87 में निर्यात में वृद्धि मजबूत रही तथा सातवीं योजना में निर्धारित 6.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लगभग बराबर रही। निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों में सुधार लाने की दृष्टि से हाल ही में शुरू की गयी नीतियों के परिणाम दिखायी देने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी एक आकस्मिक घटना थी, जिससे 1986-87 में तेल आयात बिल में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। पर्यटकों के आगमन में वृद्धि से पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में एकदम तीव्र वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में गिरावट के कारण निवेश आय भुगतान की वृद्धि की गति कम हो गयी। अनिवासी भारतीयों से जमा खातों में नई पूंजी के आने से भुगतान संतुलन को काफी सहायता मिलती रही।

257. तथापि, सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में तेल से इतर वस्तुओं के आयात में तीव्र वृद्धि जारी रही। सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान ये आयात 55 प्रतिशत तक बढ़ गये। हालांकि इनमें से बहुत से आयातों के कारण मध्यावधि तथा दीर्घ अवधि में उत्पादकता, सक्षमता और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सुधार आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनसे व्यापार अंतराल बढ़ गया है और वित्तपोषण की आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं। काफी दिनों से निजी अंतरणों में जो बहुत अधिक वृद्धि हो रही थी, इन दिनों बन्द हो गयी तथा तेल मूल्यों में गिरावट के कारण हो सकता है, उसमें थोड़ी कमी भी हो गयी हो। रियायती विदेशी सहायता चाहे थोड़ी ही सही, वित्तीय आवश्यकताओं का एक हिस्सा होती है, जो विदेशी ऋणों तथा वाणिज्यिक या वाणिज्यिक जैसी शर्तों पर ऋण की निर्भरता को बढ़ाती है और इससे ऋण अदायगी देयताएं बढ़ जाती हैं।

258. सकल देशी उत्पाद की तुलना में चालू खाते में घाटे के अनुपात को और कम करना जरूरी हो गया है ताकि यह सातवीं योजना में बताये गये पूरी योजना अवधि के 1.6 प्रतिशत के बराबर हो जाए। तथापि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परेशान करने वाली कुछेक बातें मौजूद हैं जिनसे यह काम कठिन होगा। औद्योगिक देशों में वृद्धि दर कम बनी रही तथा विश्व व्यापार में सुधार की संभावना भी ज्यादा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में 1986 की कमी के बाद वृद्धि हुई जो भारत के तेल आयात बिल को बढ़ायेगी। रियायती सहायता की संभावनाएं असंतोषजनक बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में उतार चढ़ाव मिले जुले रहे। अमरीकी डालर की ब्याज दरें बढ़ी हैं, जबकि येन, ड्यूश मार्क तथा पौंड स्टर्लिंग की ब्याज दरें गिरी हैं। कुल मिलाकर विदेशी उधार की औसतन ब्याज दरों में वृद्धि होने की संभावना है।

259. यह महत्वपूर्ण होगा कि निर्यात वृद्धि की मात्रा में प्रति वर्ष कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि बरकरार रहे, जो कि सातवीं योजना में परिकल्पना की गयी है। हालांकि, विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा थोड़ा यानी लगभग 0.5 प्रतिशत है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बाजार में अपने हिस्से में सुधार लाना आसान होगा, क्योंकि बहुत से प्रतियोगी विकासशील देशों को मजबूरन अपने निर्यातों में सुधार लाना पड़ेगा। पिछले दो वर्षों में, विदेशों में भारतीय माल की प्रतियोगिता में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं और कुछ क्षेत्रों में इनके अच्छे परिणाम भी नजर आये हैं। इस सुधार को बनाये रखना जरूरी है। पण्यों के निर्यातों में स्थिरता बनाये रखनी चाहिए। नये निर्यात करने के लिए बड़ी और मझौली इकाइयों को आगे आने की जरूरत है। निर्यात स्थिति की सफलता के लिए उचित मूल्य स्थिरता बनी रहना भी महत्वपूर्ण है।

260. जहां तक आयातों का संबंध है, ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से तेल के कुशल उपयोग के लिए किये गये उपाय जारी रहने चाहिए ताकि तेल आयात बिल सीमित रहे इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा सातवीं योजना के बचे हुए वर्षों के दौरान देशी तेल उत्पादन में थोड़ी सी ही वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। देशी आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए 1987-88 के दौरान उर्वरकों तथा चीनी के आयात में काफी कटौती की संभावना नजर आती है, विशेष रूप में ऐसे क्षेत्रों में जहां देशी निर्माता उद्योग मांग की पूर्ति लगभग प्रतियोगी दरों पर पूरी कर सकते हैं, वहां पूंजीगत माल के आयात पर नजर रखनी होगी। आने वाले वर्षों में आयात आयोजना पर और अधिक ध्यान देना होगा।

261. वर्ष 1986-87 के दौरान पर्यटन उद्योग की बहुत अच्छी स्थिति से आने वाले वर्षों में परोक्ष लेखों में इसके योगदान की काफी आशाएं नजर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण निजी अंतरणों में कुछ सुधार की आशा की जा सकती है। जैसे जैसे हमारे विदेशी उधारों में वृद्धि होगी वैसे ही निवेश आय भुगतान में वृद्धि जारी रहेगी।

2. शुद्ध विदेशी सहायता प्राप्तियों में वृद्धि हो रही है। प्रतिबद्ध निधियों की प्राप्त होने वाली मात्राओं को देखते हुए यह जरूरी है कि सहायता प्राप्त परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाये और इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाये। सातवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (जिसमें न्यास निधि अग्रिम शामिल है) को लगभग 4,000 करोड़ रुपये लौटाने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खातों में आने वाली राशियों में काफी वृद्धि हुई है तथा यह महत्वपूर्ण होगा कि ऐसी नीतिगत ढांचा बनाये रखा जाये, जो उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन देता रहे।

263. वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में भारत ने सावधानी पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है तथा यह जारी रहना चाहिए, क्योंकि 1985-86 में ऋण भुगतान अनुपात 17 प्रतिशत तक पहले ही पहुंच चुका है। फिर भी जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण चुका दिये जाएंगे, उधार लेने की हमारी गुंजाइश और बढ़ जाएगी।

264. जून 1987 के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का स्तर, आयातों के चार महीनों से अधिक की अवधि के स्तर के बराबर था और इसे काफी संतोषजनक स्थिति माना जा सकता है। फिर भी, चालू खाता घाटे की पूर्ति करने के लिए इन प्रारक्षित निधियों में से राशियां निकालने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण की संभावनाओं तथा वाणिज्यिक उधारों पर स्व आरोपित विवेकपूर्ण सीमाओं को देखते हुए भुगतान संतुलन की क्षमता को बनाये रखना, निर्यात बढ़ाने के अधिक प्रयासों तथा आयातों के सावधानीपूर्वक आयोजना पर निर्भर करता है।

265. बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतियों ने अपनी प्रगति के समेकन पर बल देना जारी रखा, ताकि बैंकों की क्षमता, लेखा संबंधी आंतरिक कार्य, ग्राहक सेवा, ऋण प्रबंध और वित्तीय क्षमता में सुधार हो सके। बैंकों की पूंजी में वृद्धि की जा रही है। वर्तमान शाखा लाइसेंसीकरण नीति ग्रामीण क्षेत्रों में दो स्थानों की दूरी को भरने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में केवल बतायी गयी आवश्यकता तथा संभावित सक्षमता के आधार पर नयी शाखाएं खोलने की अनुमति देती है। घाटा दर्शाने वाली शाखाओं को लाभ कमाने वाली यूनिटों में बदलने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्टाफ की कार्य कुशलता बढ़ाने तथा लागत नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। ऋण संविभागों की स्थिति का मूल्यांकन और उनकी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं। बैंकों के कार्यकलापों का भी चयनात्मक रूप से मशीनीकरण किया जा रहा है।

266. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया है, बैंक अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए व्यापक समयबद्ध योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके लिए बैंकों ने अपने आंतरिक गठन का विशेष रूप से प्रधान कार्यालय, आंचलिक तथा क्षेत्रीय स्तरों पर औचित्यपूर्ण तथा मजबूत बना लिया है। उन्होंने अपनी प्रशिक्षण क्षमता तथा पाठ्यक्रमों की समीक्षा की है तथा उसमें सुधार किया है। लेखा संबंधी आंतरिक कार्यों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकों के लाभ भी बढ़ रहे हैं। बैंकर तथा ग्राहक के बीच अधिक निकटता, ग्राहकों की शिकायतों का तत्परता से निपटान, कूरियर सेवाओं में विस्तार के कारण बाहरी चैकों का त्वरित संग्रहण तथा बैंकिंग हाल में और तेजी से सेवाएं उपलब्ध होने के कारण ग्राहक सेवा में सुधार हो रहा है। फिर भी, हम इसी पर संतोष करके बैठे नहीं रह सकते।

267. हाल ही में हुए बैंक तथा स्टाफ यूनियन के समझौते से मशीनीकरण की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए, जिससे उच्चतर उत्पादकता तथा बेहतर ग्राहक सेवा मिल सकेगी। रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित प्रमुख समाशोधन गृहों में समायोजन कार्यों में कम्प्यूटरीकरण के अलावा रिजर्व बैंक द्वारा संचालित 8 प्रमुख समाशोधन गृहों में से बंबई, मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता में तेजी से काम करने वाले रीडर सार्टरों की स्थापना की गयी है, ताकि इन महानगरों में चेकों का समाशोधन तेजी से हो सके।

268. ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समय पर वसूली ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर बैंकों को अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण तथा औद्योगिक ऋणों के संबंध में अतिदेय राशियां अधिक बनी हुई हैं। जहां तक औद्योगिक ऋण का संबंध है, अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए स्वास्थ्य कूट की शुरूआत तथा अग्रिम सीमाओं की समय से समीक्षा करने पर जोर देने से बैंक अवरुद्ध तथा संभावित अवरुद्ध अग्रिमों के अधिक कारगर ढंग से पता लगाने और नियंत्रित करने का कार्य कर सकते हैं। सक्षम ऋण यूनिटों के पुनर्वास उपायों को अंतिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी क्रियाविधियों में तेजी लानी होगी। इस संबंध में मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं तथा संघ रूप में अग्रणी की भूमिका को मजबूत बनाते हुए बैंक संघ के के कामकाज को और बेहतर बनाया जा रहा है। ऋणों के संबंध में निर्णय तेजी से लिए जा सकें इसके लिए ऋण प्राधिकरण योजना को सरल बना दिया गया है। ऋण यूनिटों की समस्याओं के हल जल्दी ढूंढने में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से भी सहायता मिलनी चाहिए जिसका गठन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। पर साथ ही सक्षम न हो सकने वाले यूनिटों का अनावश्यक रूप से वित्तपोषण न होने पाये।

269. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बैंकों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। परन्तु इस क्षेत्र में देय राशि की वसूली का समग्र स्तर अपर्याप्त बना हुआ है। उदाहरण के

तौर पर कृषि संबंधी देय राशियों में वसूली का औसत पिछले वर्षों मांग का 50 से 55 प्रतिशत तक रहा। इसमें वैकिंग तंत्र की निधियों को फिर से इस्तेमाल करने तथा स्रोतों के इष्टतम उपयोग की क्षमता को हानि पहुंचती है, अतः क्षेत्रीय तथा अन्तर बैंकों में काफी घट बढ़ से यह पता चलता है कि वसूली कार्यों को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। वसूली कार्यों को कई बातें प्रभावित करती हैं। इनमें से दो का यहां विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। पहली, यह अवश्य देखा जाए कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए समय पर ऋण दिया जाता है तथा वस्तुतः उसी के अनुसार उसका उपयोग होता है। इस उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऋण देने के लिए निर्धारित सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली का पालन किया जाये, ऋण के उपयोग पर निगरानी रखी जाये तथा ऋण का दूसरे कामों में इस्तेमाल होने से रोका जाये। अभी हाल ही में यह निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण शाखाओं को सप्ताह में एक दिन गैर-कारोबारी कार्य-दिवस निश्चित करना चाहिए। शाखा प्रबंधक इस दिन को जमाराशि जुटाने के लिए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने, ऋण लेने वाले संभावित व्यक्तियों का पता लगाने, ऋणों के इस्तेमाल की निगरानी करने तथा बकाया राशियों की समय पर वसूली बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात यह है कि वित्तीय अनुशासन और बकाया राशियों की वसूली के अनुरूप एक माहौल बनाना और उसे बनाये रखना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों को इस संबंध में बहुत ही अहम भूमिका निभानी है। वे बैंकों को कारगर समर्थन दे सकते हैं, ताकि जानबूझकर की जाने वाली चूकें न हों। इसके अलावा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर विचार किये बिना ऋण लेने वालों को आमतौर पर माफ कर देने और बट्टे खाते डालने के मामलों पर निगरानी की भी जरूरत है, क्योंकि उनसे ग्रामीण ऋण प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है और किसानों, कारीगरों तथा अन्य उधारकर्ताओं के हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए वर्तमान उपबंध हैं। जब कभी जरूरत हो इनकी सहायता ली जाये। बैंकों के अलावा अन्य कोई भी प्राधिकरण इन ऋणों को बट्टे खाते नहीं डाल सकता। सामान्य छूटों के, जहां कहीं ऋणकर्ता के दायित्वों की चुकौती की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले लेती है, कभी गंभीर प्रभाव नजर आते हैं। ऐसे उपाय जहां सामान्य रूप से ऋणकर्ता को अपने ऋण चुकाने के लिए न केवल कमजोर बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा उनमें यह आशा भी जगाते हैं कि भविष्य में भी ऋणों में इस तरह की छूट मिलेगी, अतः समय पर चुकौती का वातावरण दूषित हो जाता है। छठे दशक के शुरू के वर्षों में संस्थागत ऋण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऋण का केवल 4 प्रतिशत था, अब बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत हो गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कृषि तथा अन्य ग्रामीण कार्यकलापों में काफी सहायता की है, तथा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित बजट स्रोतों का प्रमुख अनुपूरक बना गयी है, को कमजोर करने के लिए कुछ न किया जाये।

270. हाल ही के वर्षों में मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में समग्र चलनिधि को नियंत्रित करने की जरूरत तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच अधिक तालमेल पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। हालांकि उत्पादन, मुद्रा तथा मूल्यों के स्थूल अन्तर संबंधों को हमेशा ध्यान में रखा गया है, पर हाल ही की अवधि में मौद्रिक सकल राशियों में वृद्धि के अनुरूप प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। उत्पादन, मुद्रा तथा मूल्यों में अन्तर संबंध जटिल अन्तराल पर निर्भर करते हैं। इन अन्तरालों को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित करना हालांकि मुश्किल है, पर यह पाया गया है कि एक ग य के बाद निहित मूलभूत अन्तर संबंध अच्छे ही साबित होते हैं। इसी वजह से चक्रवर्ती समिति ने चलनिधि मौद्रिक लक्ष्यों की शुरुआत की सिफारिश की है, ताकि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन की वृद्धि से कम न हो। साथ ही समिति ने रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि पर भी एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में ध्यान केन्द्रीत किया है, क्योंकि यह प्रारक्षित मुद्रा सृजन के बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी होता है। 1987-88 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में संभावित वृद्धि के अनुमान का उल्लेख पहली बार किया गया है। इससे मुद्रागत तथा राजकोषीय नीतियों में बेहतर तालमेल का आधार उपलब्ध होना चाहिए।

271. 1986-87 में मौद्रिक नीति का उद्देश्य एम$_3$ की वृद्धि को पिछले तीन वर्षों के औसत स्तर से नीचे रखना था। अक्तूबर, 1986 के अंत तक मौद्रिक वृद्धि ठीक रही, लेकिन उसके बाद मुद्रागत विस्तार की गति में तेजी आयी, जो पिछले तीन वर्षों के औसत से स्पष्ट रूप से अधिक थी। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने जनवरी-मार्च 1987 की अवधि के दौरान मौद्रिक विस्तार की गति को कम करने के लिए कतिपय कदम उठाये। इस दौर में 1986-87 में मौद्रिक वृद्धि वांछित वृद्धि से अधिक थी। किन्तु यदि ये कदम न उठाये गये होते, तो यह वृद्धि और अधिक होती।

272. 1987 में कम कारोबार की अवधि की शुरुआत में घोषित ऋण नीति में कुछ विशिष्ट बातें हैं। पहली यह कि ब्याज दरों के विन्यास के मुताबिक इसमें काफी बदलाव हैं, जिनकी समीक्षा पिछली स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। 1979-81 की अवधि में ब्याज दरें उक्त अवधि में अत्यधिक मुद्रास्फीति की दरों के संदर्भ में तेजी से बढ़ायी गयीं। तथापि मुद्रास्फीति में कमी के साथ इन सांकेतिक दरों से ब्याज की वास्तविक ऊंची दरों का पता चलता है। हालांकि ब्याज दरों के संचालित विन्यास, मुद्रास्फीति की दरों में होने वाले अचानक परिवर्तनों सामने नहीं ठहर सकते, अतः यह आवश्यक है कि इन्हें कम-से-कम मध्यावधि, प्रवृत्तियों के अनुरूप बदला जाए। वर्ष 1979 तथा 1981 के बीच चल रही उच्च स्तरों से उतरती हुई मुद्रास्फीति की दरों के साथ, 1983 तथा 1985 के बीच, दो चरणों में उच्चतम उधार ब्याज दर को कम कर 19.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत पर लाया गया। मार्च 1987 में इसे और कम करके 16.5 प्रतिशत कर दिया गया। इसी वजह से जमाराशियों पर दी जाने वाली उच्चतम ब्याज दर को भी 11 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि यह दर 2 वर्षों और अधिक की अवधि समाप्ति वाले ऋणों पर लागू की गयी। जिन अवधियों के लिए उच्चतम ब्याज दर लागू है, उनकी संख्या में कटौती से बैंकिंग तंत्र में, जमाराशियों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कमी लायी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर ऋणों में भी लचीलापन लाया जा सकेगा। जब जमाराशियां लम्बी अवधि में परिपक्व होने वाले ऋणों में अटक जाती हैं तब उधार ब्याज दरों को जरूरत होने पर भी नीचे लाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्तमान जमाराशियों की अवधि पूरी होने में लम्बा समय लगता है तथा साथ ही काफी समय के लिए जमाराशियों की दर में कटौती का पूरा लाभ बैंकों को नहीं मिल पाता। बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों में कटौती के साथ अन्य बचत लिखतों आदि की दरों में भी एक साथ कटौती की गयी, ताकि विभिन्न बचत योजनाओं में आपस में प्रतियोगिता बनी रहे।

273. दूसरी बात, अप्रैल 1985 में शुरू हुई चयनात्मक ऋण नियंत्रण को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया और आगे बढ़ायी गयी। पिछले दो वर्षों से कई पण्यों जैसे कि गेहूं, धान और चावल, रुई और कपास तथा बिनौले और बिनौले के तेल के मामले में, जहां आपूर्ति-मांग का संतुलन पर्याप्त माना गया, वहां चयनात्मक ऋण नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। कतिपय अन्य पण्यों के मामले में शर्तों को सरल कर दिया गया। इससे नियंत्रण की प्रणाली और अधिक लचीली हो गयी तथा अधिक ऋण दिये जाने को रोकने के मूलभूत उद्देश्य से अलग न होते हुए कम जटिल हो गयी; अधिक ऋण से सट्टेबाजी के लिए स्टॉक रखने को बढ़ावा मिलता है।

274. तीसरे, विभिन्न उपायों द्वारा मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय सुधार लाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान साधनों को सुधारने तथा नये साधनों के विकास तथा मुद्रा बाजार साधनों को चलनिधि देने के लिए आवश्यक संस्थागत मूलभूत सुविधाओं के सृजन पर जोर दिया जा रहा

है। खजाना बिलों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है—नीलामी प्रणाली के अंतर्गत 182 दिन का एक नया खजाना बिल शुरू करना। बिल प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय घोषित किये गये। वित्त गृह की स्थापना की संभावना से दावों के निपटान में बिलों का इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अदायगी तंत्र में सुधार आना चाहिए।

275. वर्ष 1987-88 में मुद्रागत तथा ऋण नीति की मिसाल एक चेतावनी के रूप में, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबावों को पुनः उभरने से रोकने की आवश्यकता के संदर्भ में, बनी रहनी चाहिए। विभिन्न मुद्रागत तथा ऋण जमाराशियां जिनमें शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन शामिल हैं, का लगातार नियंत्रण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रागत तथा ऋण में वृद्धि मौसम के अनुसार बढ़ोतरी या गिरावट वास्तविक क्षेत्र के विकास के लगभग साथ हो है।

भाग II—बैंकिंग तथा अन्य गतिविधियां

276. इस रिपोर्ट के भाग I में 1986-87 के दौरान, समग्र आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठ भूमि में मौद्रिक और ऋण नीति विषयक उपायों की समीक्षा की गई है। इस भाग में रिजर्व बैंक के परिचालन-क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रस्तुत की जा रही हैं। रिजर्व बैंक के संगठनात्मक मामले और लेखे अंत में दिये गये हैं।

मुख्य बातें

277. वर्ष के दौरान गतिविधियों की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:

(i) शाखा लाइसेंस नीति में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक बैंक शाखा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, समेकन पर विशेष बल दिया गया।

(ii) शहरी निर्धन व्यक्तियों की गरीबी दूर करने के लिए नयी ऋण नीति प्रारम्भ करके सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। अल्प-संख्यकों को अधिकाधिक मात्रा में ऋण सुलभ कराने के उपाय भी किये गये।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी-आधार विस्तृत करके उन्हें सुदृढ़ बनाने की कार्रवाई की गयी।

(iv) जनवरी, 1988 से दिसम्बर 1990 के बीच की अवधि को व्याप्त करते हुए जिला ऋण योजनाओं के चौथे दौर की तैयारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।

(v) बैंकों द्वारा बिलों के वित्तपोषण को लोकप्रिय बनाने के बारे में उपाय किये गये।

(vi) बैंकों को और व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने और विलम्ब को कम करने की दृष्टि से ऋण प्राधिकरण योजना को और अधिक उदार बनाया गया।

(vii) रिजर्व बैंक ने पौंड स्टर्लिंग के अतिरिक्त, हाजिर आधार पर, प्राधिकृत व्यापारियों को अमरीकी डालर की बिक्री भी आरम्भ की।

(viii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अधीन न आनेवाली (गैर-फेरा) कम्पनियों के लाभांशों के प्रेषण, निर्यातों पर एजेंसी कमीशन के प्रेषण और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन नियमों को और उदार बनाया गया।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक और आयात व्यापार नियंत्रण (आई.टी.सी.) की पिछली निर्बंध परमिट योजनाओं (ब्लैंकेट परमिशन स्कीम्स) के स्थान पर निर्यात संवर्द्धन से सम्बद्ध सभी प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा विमुक्त करने की एक नयी विस्तृत आधार वाली [illegible] योजना आरम्भ की गयी।

वाणिज्यक बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

बैंकों के लिए कार्य योजना—नवम्बर 1985 से दिसम्बर 1987

278. बैंकों की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी बराबर जारी रही। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक की मार्च 1987 तक की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के विषय में, उनके अध्यक्षों से, 1986-87 के दौरान हर तिमाही के अन्त में चर्चाएं की जाती रहीं।

279. मोटे तौर पर बैंकों ने *प्रधान-कार्यालय* और *नियंत्रक-कार्यालय* स्तर पर अपने तंत्र को पुनर्गठित कर लिया है। समुचित शक्तियां का प्रत्यायोजन करते हुए विभिन्न स्तरों पर भूमिकाओं और दायित्वों की समीक्षा की गयी है।

280. कर्मचारीवर्ग की उत्पादकता में सुधार के लिये बैंकों ने विशेष प्रयास किये हैं। बैंकों ने प्रशिक्षण क्षमताओं की वृद्धि की दिशा में प्रगति की और 1986 के दौरान प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या 1985 की अपेक्षा बहुत अधिक रही। प्रशिक्षण के बाद की तैनातियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

281. बैंकों ने ऋण-प्रबंधन में परिवर्तन के लिए भी विभिन्न उपाय किये हैं। किन्तु यह देखा गया कि ऋण-सीमाओं की समीक्षा और नवीकरण से संबंधित स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। समस्या प्रणालीगत प्रतीत होती है और बैंकों से कहा गया है कि वे इस बारे में नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा, आवश्यक अनुशासन का परिपालन सुनिश्चित करें।

282. सभी बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये जानेवाले अग्रिमों विषयक निर्धारित लक्ष्यों और सामान्यतः उपक्षेत्रों विषयक लक्ष्यों को भी बराबर पूरा करते रहे। किन्तु सामान्यतः अतिदेय राशियों में वृद्धि हो रही है; दिसंबर 1986 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की बकाया राशियां, कुल बकाया ऋण की 20 प्रतिशत थीं जबकि गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों की बकाया राशियां 11.5 प्रतिशत थीं। प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में, वसूली के कार्य-निष्पादन की स्थिति असंतोषजनक हो गयी हुई है। बैंकों से जोर देकर कहा गया है कि वे [illegible] ([illegible]) प्रक्रिया पर निगरानी, रुग्ण इकाइयों के विषय में कार्रवाई, और समग्र वसूली विषयक कार्य निष्पादन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अपने तंत्र को सन्नद्ध करें।

283. यद्यपि शाखाओं द्वारा नियंत्रण विवरणियां भेजने, शाखाओं के निरीक्षण और लेखा-परीक्षा आदि में सुधार हुआ है, फिर भी इस दिशा में और सुधार की गुंजाइश है। शाखाओं में बहियों के तुलन और अन्तर शाखा खातों के समाधान में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

284. जहां तक लाभप्रदता (प्रोफिटेबिलिटी) का प्रश्न है, 1986 के दौरान बैंकों का कार्य निष्पादन सामान्यतः बहुत अच्छा रहा है। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किये कुछ निर्णयों से [illegible] लाभप्रदता में सहायता मिली है। इस प्रकार के कुछ निर्णय ये हैं: पूंजीगत आधार का संवर्धन, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर (कूपन रेट) में वृद्धि, खाद्य ऋणों पर उच्चतर ब्याज दर रिजर्व बैंक के पास रखे गये नकदी शेषों पर अधिक मात्रा में प्रतिलाभ और सेवा प्रभारों में वृद्धि। घाटा उठानेवाली शाखाओं की संख्या और उनके द्वारा उठाये घाटे की मात्रा में भी 1986 के दौरान कमी लायी गयी।

शाखा विस्तार नीति तथा प्रगति

285. गत वर्ष की रिपोर्ट में नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति के निर्धारण का उल्लेख किया गया था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त होगी। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने में काफी प्रगति करनेवाले बैंकों से आशा की जाती है कि वे अपनी स्थिति सुदृढ़ करेंगे और अपनी परिचालनगत कार्य कुशलता और सेवा गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नयी नीति का उद्देश्य यह है कि विकास खंड (डेवलपमेंट ब्लाक) को आधार मानते हुए, औसतन प्रति 17,000 व्यक्तियों (1981 की जनगणना के अनुसार) के लिए एक बैंक शाखा

का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोली जायें। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा की जाती है कि 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक बैंक शाखा उपलब्ध हो जाय जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को व्याप्त करेगी। पहाड़ी क्षेत्रों और कम आबादी वाले क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों पर जनसंख्या विषयक मानदंडों में ढील देकर विशेष रूप से विचार किया जाता है। बैंकों से यह भी कहा गया कि जिन क्षेत्रों में कारोबार की मात्रा और अन्य दृष्टियों से, नियमित शाखा स्थापित करना उपयुक्त न हो वहां अनुषंगी/चल शाखाएं खोलने पर विचार करें।

286. राज्य सरकारों से प्राप्त निर्धारित केन्द्रों की सूचियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने जून, 1987 तक 4,396 ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्र शाखाएं खोलने के लिये, बैंकों को आवंटित किये हैं। बैंकों से कहा गया है कि चालू कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित स्थानों पर शाखाएं खोलने के कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बांट लिया जाए।

287. ग्रामीण शाखाओं के कार्य की समीक्षा के बाद यह अनुभव किया गया कि यद्यपि बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं को देश के अंचलों तक पहुंचा दिया है, उनके कार्य-निष्पादन में सुधार की काफी गुंजाइश है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं में सप्ताह में एक दिन को बिना सार्वजनिक कारोबार कार्य-दिवस रखें, ताकि उन शाखाओं के प्रबंधक फील्ड में जाकर जमाराशियां जुटाने, ऋण-उपयोग पर निगरानी रखने, ऋणों की वसूली और ऋणकर्ताओं को समुचित मार्गदर्शन जैसे विकास और संवर्धन कार्यों के लिये उस दिन को पूरी तरह अपने वर्तमान और भावी ग्राहकों से संपर्क करने में बिता सकें।

288. भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. (बिना लाइसेंस वाले बैंक) के समामेलन की योजना को 18 दिसंबर, 1986 को स्वीकृति प्रदान की थी और उसके परिणामस्वरूप उस बैंक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 23 जनवरी, 1987 से हटा दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 79 बनी रही। वर्ष 1986-87 (अप्रैल 1986—मार्च 1987) के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों ने 417 कार्यालय खोले। मार्च 1987 अन्त की स्थिति के मुताबिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर, 53,565 हो गयी। नये खोले गये कार्यालयों में से 353 ग्रामीण स्थानों और 25 अर्ध शहरी स्थानों पर थे। यह संख्या नये खोले गये कार्यालयों की संख्या की 86.30 प्रतिशत बैठती है। इनमें से 40 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के 126 कार्यालय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के और 259 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के थे। मार्च 1987 में ग्रामीण कार्यालयों की संख्या कुल संख्या की 56 प्रतिशत हो गयी थी। इसकी तुलना में जून, 1969 में ग्रामीण कार्यालयों की संख्या 22 प्रतिशत थी।

विदेशों में भारतीय बैंक

289. इस वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में कोई शाखा नहीं खोली। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 4 शाखाएं बन्द कर दीं जिनमें से एक यूनाइटेड अरब अमीरात में, 2 ब्रिटेन में और एक गुयाना में थी। इसके अतिरिक्त भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के पुनर्गठन/पुनः संरचना के एक भाग के रूप में ब्रिटेन में कार्यरत पंजाब नेशनल बैंक की चार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तीन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक की एक-एक शाखा ने परिचालन कार्य बंद कर दिया। इन शाखाओं में बरमिंघम और ईस्थम में कार्यरत दो शाखाएं अंतरिती बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। जबकि अन्य शाखाएं बंद कर दी गयीं। इस प्रकार 30 जून 1987 की स्थिति के मुताबिक विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं की संख्या क्रमशः 9 और 123 हो गयी। इस वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने लेबनान में बेरूत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय बंद करने की सूचना दी और इस प्रकार चार भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 11 से घटकर 10 हो गयी। भारतीय बैंकों द्वारा स्थापित की गयी जमा राशियां स्वीकार करनेवाली कंपनियां (जो सभी हांगकांग में हैं) और पूर्ण स्वामित्ववाली बैंकिंग अनुषंगी कम्पनियों की कुल संख्या अपरिवर्तित रही और 6 बनी रही। साथ ही, 30 जून 1987 की स्थिति के मुताबिक भारतीय बैंकों के विदेशी-क्षेत्र में, बैंकिंग कारोबार में लगी हुई अधिकांश स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियां और चार संयुक्त उद्यम बैंक शामिल थे।

भारत में विदेशी बैंक

290. रिपोर्ट की अवधि के दौरान विदेशी बैंकों ने भारत में कोई नयी शाखा नहीं खोली। अलबत्ता, बैंक ऑफ कैलिफोर्निया (अमेरिका) बांका नेशनल डेल लावोरो (इटली), दाइ इचि कांग्यो बैंक लि. (जापान) और सानवा बैंक (जापान) ने देश में अपने प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किये। परिणामस्वरूप, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं और कार्यालयों की संख्या क्रमशः 136 (21 बैंकों की) और 18 (18 बैंकों की) हो गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

291. जुलाई 1986 से अप्रैल 1987 के बीच दो नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये और इस प्रकार इनकी कुल संख्या 196 हो गयी। जो 354 जिलों को व्याप्त करते हैं। सूचना देनेवाले 194 क्षे.ग्रा. बैंकों की जमाराशियां और मीयादी अग्रिमों की राशियां अप्रैल 1987 के अंत में क्रमशः 1,744 करोड़ रुपये और 1,841 करोड़ रुपये थीं। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे का अध्ययन करने और उनकी समग्र क्षमताओं में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। इस कार्यकारी दल की जो प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं वे ये हैं: (1) प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की चुकता पूंजी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए; (2) प्रायोजक बैंकों को अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले पुनर्वित्त पर उधार की दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर देनी चाहिए; (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी अतिरिक्त निधियां प्रायोजक बैंकों के चालू खातों में जमा न करके सरकारी और अन्य प्यासी प्रतिभूतियों में निवेश करनी चाहिए ताकि उनको लाभप्रदता बढ़े; और (4) प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निधि प्रबंधन, स्टाफ प्रशिक्षण और आंतरिक लेखा-परीक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

विशेष योजनाओं के अधीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों की सहायता

292. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विशेष योजनाओं के अधीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का अपना स्तर बराबर बनाये रखा। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की राशियां मार्च 1987 के अंत में 24,552 करोड़ रुपये थीं जो कि 44.0 प्रतिशत बैठती हैं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिम, बैंकों के शुद्ध ऋण के 11.0 प्रतिशत बैठते हैं। कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिम की बकाया राशियां 9,058 करोड़ रुपये थी जो कि कुल शुद्ध बैंक ऋण की 16.2 प्रतिशत बनती हैं, जबकि मार्च 1987 के लिए लक्ष्य 16 प्रतिशत रखा गया था। (अप्रैल, 1987 में शुरू किये गये संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम से पहले) 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन हिताधिकारियों को मिलनेवाली सहायता मार्च, 1987 के अंत में 162 लाख खातों में 8,458 करोड़ रुपये (अनंतिम) थी।

विभेदक ब्याज दर योजना

293. दिसंबर 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों की संख्या में 4.79 लाख की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 47.97 लाख हो गयी और ऋणों की बकाया राशियों में 98.13 करोड़ रुपए की वृद्धि होकर वह 560.83 करोड़ रुपए हो गयीं। मार्च 1987 के अंत की स्थिति के अनुसार ये अग्रिम और बढ़कर 48.79 लाख खातों में 575.34 करोड़ रुपए हो गए और कुल ऋणों के 1.1 प्रतिशत बैठते थे, जो कि 1 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधि थें। क

स्व-रोजगार तथा अन्य योजनाएं

294. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अधीन 1986-87 के दौरान सहायता पाने वाले हिताधिकारियों की संख्या पिछले दो वर्षों की तरह 2.50 लाख रखी गयी। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य में इस वर्ष के दौरान मंजूर किए गए औद्योगिक उद्यमियों का अनुपात कुल मंजूरियों के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था और व्यापार उद्यमियों के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ढील दी गयी। इन क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उद्यमियों का न्यूनतम अनुपात 50 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत रखा गया और व्यापार उद्यमियों के हिस्से की कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं की गयी। वर्ष 1985-86 के दौरान बैंकों ने 2.21 लाख हिताधिकारियों को 430 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए थे। जबकि हिताधिकारियों को 430 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए थे, और हिताधिकारियों का लक्ष्य संख्या 2.50 लाख था। रिपोर्ट भेजने वाले बैंकों के संबंध में उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष (1986-87) के दौरान मार्च 1987 तक 2.19 लाख हिताधिकारियों को कुल 455.12 करोड़ रुपए की समग्र राशि मंजूर की गयी है। यह सूचना मिलने पर कि वाणिज्य बैंकों ने उक्त योजना के अधीन ऋण आवेदनों में से बहुत बड़ी संख्या का रद्द कर दिया है, रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान इस प्रकार के रद्दकरण का अध्ययन किया। इस अध्ययन रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

295. सितम्बर 1986 में भारत सरकार ने शहरी निर्धन व्यक्तियों की गरीबी दूर करने के लिए एक नयी योजना आरंभ की। शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम नामक इस योजना में शहरी निर्धन व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है और यह 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले उन सभी नगरों/कस्बों पर लागू होती है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के अधीन नहीं आते हैं। यह कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुनी हुई शाखाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। चुने हुए हिताधिकारियों को प्रति परिवार 5,000 रुपए तक की सहायता मिलती है, जिसमें ऋण राशि के 25 प्रतिशत के बराबर भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। उधार की निर्धारित ब्याज दर 10 प्रतिशत है। यह सहायता पात्र केन्द्रों पर प्रति 300 की जनसंख्या पर एक हिताधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है। प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1987 तक 3.21 लाख हिताधिकारियों को कुल 109.18 करोड़ रुपए की समग्र राशि मंजूर की जा चुकी है।

296. भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार में मदद करने की भारत सरकार की योजना के अधीन वाणिज्य बैंक भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। यह योजना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के एक जिले में चालू थी और इसे अब तीन और राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, केरल और मणिपुर के 8 जिलों में लागू कर दिया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

297. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के अधीन मार्च, 1987 में समाप्त द्वितीय वर्ष में 37.41 लाख हिताधिकारियों को सहायता दी गयी और सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) ने 997.78 करोड़ रुपए के सावधिक ऋण मंजूर किए।

अल्प संख्यक समुदायों को ऋण

298. अल्प संख्यक समुदायों के कल्याण के विषय में प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप, बैंकों से जुलाई 1986 में कहा गया कि वे अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्राप्ति सुलभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय करें। इन उपायों में ये शामिल थे। अल्प संख्यकों के हितों की देखभाल के लिए विशेष कक्षों की स्थापना किए गए उपाय और प्रगति की सावधिक समीक्षा तथा जिन क्षेत्रों में अल्प संख्यक समुदायों की संख्या बहुत अधिक है वहां गरीबी निवारण के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित प्रचार।

अनु. जातियों/अनु. जनजातियों को ऋण

299. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशियां मार्च, 1986 के अंत के 1,394 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1987 के अंत तक 1,696 करोड़ रुपए हुई।

अग्रणी बैंक योजना

300. जिला ऋण योजनाओं के चौथे दौर के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिए जाने तक, अग्रणी, (लीड) बैंकों से कहा गया कि वे प्राप्त अनुभव के आधार पर आवश्यक समझे जाने वाले कुछ परिवर्तनों के साथ, सामान्य रूप रेखा के मुताबिक 1987 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करें। तदनुसार 1987 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गयी और उन्हें देश के सभी जिलों में कार्यान्वित के लिए प्रारंभ किया गया। इस बीच जनवरी 1988 से दिसम्बर 1990 तक की अवधि के लिए जिला ऋण कार्यक्रमों के चौथे दौर की तैयारी के विषय में मार्गदर्शी सिद्धांतों को सभी अग्रणी बैंकों को सूचित कर दिया गया है।

301. नए जिलों के निर्माण के परिणामस्वरूप तीन राज्यों के चार नए जिलों का अग्रणी दायित्व सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सौंपा गया। दिसम्बर 1986 के अंत की स्थिति के मुताबिक देश के 438 जिले अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत थे।

ऋण प्राधिकरण योजना

302. मुद्रा बाजार विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बिल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए। ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा (कट आफ प्वाईंट) से अधिक समग्र कार्यकारी पूंजीगत सुविधाओं का उपभोग करने वाले ऋणकर्ताओं के मामले में, 1 अप्रैल 1988 से वहीं ऋणों पर मंजूर की गयी ऋण सीमाएं अंतर्देशीय ऋण बिक्रियों का वित्तपोषण करने के लिए इस प्रकार के ऋण कर्ताओं को मंजूर की गयी कुल ऋण सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। शेष ऋण आवश्यकताओं का वित्तपोषण मांग/मीयादी बिलों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे मामलों, में जहां वहीं ऋणों पर नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त वित्तपोषण का अनुपात पहले ही 75 प्रतिशत से कम हो, वहां बैंकों को बिक्री के वित्तपोषण के मामलों के लिए अनुपात में वृद्धि की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 1 अप्रैल 1987 से बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे अन्तर्देशीय (इनलैंड) बिलों की सीमा में, 3 मास की अवधि के लिए, वर्तमान बिल सीमा के 10 प्रतिशत तक की तदर्थ वृद्धि उपलब्ध करा सकते हैं किन्तु शर्त यह है कि इस वृद्धि की उपरी सीमा एक करोड़ रुपए होगी यह सीमा 1 जुलाई 1987 से और बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गयी है। यह अनुमति बैंकों में पहले ही से निहित अन्य विवेक शक्तियों के अतिरिक्त है। ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आने वाले सभी ऋणकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 1988 तक, उधार खरीदों से बिल स्वीकरण के अपने अनुपात को 25 प्रतिशत तक पहुंचा दें। जिन मामलों में यह अनुपात उक्त स्तर से नीचे हों, वहां बैंकों को अपने ग्राहकों से कहना चाहिए कि वे क्रमशः इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर प्रगति करें।

303. जून, 1987 में की गयी ऋण प्राधिकरण योजना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि प्राधिकरण योजना से काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय अनुशासन आया है, फिर भी अनेक पार्टियों द्वारा इसका अनुपालन अपेक्षाओं से काफी कम है। ऋण सीमाओं की स्वीकृति और संवितरण में विलंबों

को कम करने के उद्देश्य से तथा विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने वालों को प्रोत्साहन देने तथा अन्य ऋणकर्ताओं को अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि जो पार्टियां मोटे तौर पर निर्धारित अनुशासन का पालन करती हैं उनके साथ अनुपालन न करनेवाली पार्टियों की तुलना में भिन्न व्यवहार किया जाये।

304. तदनुसार, 1 जुलाई 1987 से बैंक, रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना ही निम्नलिखित बड़े ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त स्वीकृत ऋण सीमाओं की संपूर्ण राशि प्रदान कर सकते हैं : (i) जो ऋण प्रदान करने की द्वितीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिसमें 1.33:1 का न्यूनतम चालू अनुपात अपेक्षित है; (ii) जो निर्धारित तिमाही विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं और (iii) जो वस्तु सूची प्राप्यों के स्तर को निर्धारित मानदंडों/पिछले स्तरों के भीतर या अनुरूप बनाए रखते हैं। दूसरे इस प्रकार के ऋणकर्ताओं के बारे में जो उपर्युक्त (i) और (ii) अनुशासनों का तो अनुपालन करते हैं मगर वस्तु सूची और प्राप्य के विषय में पूर्णतः अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों को यह विवेकाधिकार है कि मानदंडों में 20 प्रतिशत तक ढील दे। इस प्रकार के मामलों को भी परिवर्द्धित ऋण सीमाओं के संबंध में पूर्ण अनुमति के लिए रिजर्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि इन नियमों के कारण रिजर्व बैंकों को भेजे जाने वाले ऋण प्राधिकरण योजना के मामलों में लगभग 35 प्रतिशत की कमी आ जायेगी।

305. जिन मामलों को अभी भी रिजर्व बैंक के पास भेजना आवश्यक है, उनमें बैंकों द्वारा तीन महीने तक की वर्तमान अस्थायी निधि-सीमा को काफी बढ़ा दिया गया है और अब वे वर्तमान पैकिंग ऋण सीमा के 25 प्रतिशत और (पैकिंग ऋण से भिन्न) वर्तमान कार्यकारी पूंजी की सीमाओं के 10 प्रतिशत तक हो सकते हैं। इस विषयक समग्र सीमा अब तक के 2 करोड़ रुपये के बजाय 4 करोड़ रुपये होगी।

306. रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि वह पूर्व प्राधिकरण के लिए आये सभी प्रस्तावों पर अपने निर्णय उन प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर दे देगा। बैंकों से कहा गया कि वे बड़ी ऋण सीमाओं के विषय में कार्रवाई करने के अपने तंत्र को मजबूत बनायें ताकि उनके बारे में निर्णय अनावश्यक विलंब के बगैर किये जा सकें।

307. जिन पार्टियों के बारे में रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित था उनके मामलों में की संख्या मार्च, 1986 के अंत के 843 से घटकर जून, 1986 के अंत तक 598 हो गयी। इस संख्या में यह कमी अप्रैल 1986 में निर्दिष्ट-सीमा (कट-आफ-प्वाइंट) को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर देने के कारण हुई। जून 1987 के अंत तक ऋण प्राधिकरण योजना की पार्टियों की संख्या बढ़कर 644 हो गयी। इन पार्टियों से संबद्ध कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं, जून 1987 के अंत में 19,647 करोड़ रुपये थीं, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भाग 12,721 करोड़ रुपये अथवा 65 प्रतिशत था। जून 1987 के अंत में कुल ऋण सीमाओं का सुविधावार संवितरण इस प्रकार था : कार्यकारी पूंजीगत प्रयोजनों (पैकिंग ऋण सीमाओं और बिलों सहित) के लिए 93.3 प्रतिशत, सावधि बिल के लिए 5.6 प्रतिशत और आस्थगित अदायगी के आधार पर मशीनों की बिक्री के लिए 1.1 प्रतिशत।

बैंकों द्वारा संघीय व्यवस्था के अधीन ऋण प्रदान करना

308. संघीय व्यवस्था के अधीन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में देखी गयी कमियों के कारण इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जून 1987 में नये निर्देश जारी किये गये। इन निर्देशों में बहु वित्त-पोषण प्रबंधों के अधीन अग्रणी बैंक के चुनाव के बारे में स्वतः निर्णय (ऑटोमेटीसिटी) की व्यवस्था है और इस प्रकार के अग्रणी बैंक द्वारा केन्द्रीय भूमिका निभाये जाने की कल्पना है। इन निर्देशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : संघीय व्यवस्था में बैंकों की अधिकतम संख्या, जहां समग्र निधि के आधार पर किसी एक ऋणकर्ता को स्वीकृति किसी एक बैंक की ऋण सीमायें 100 करोड़ रुपये से अधिक होती हों, वहां संघ बनाने की आवश्यकता अग्रणी बैंकों द्वारा, अकेले स्वयं ही अथवा अगले नम्बर के बड़े वित्तपोषक बैंक के साथ मिलकर प्रस्ताओं का मूल्यांकन और, जहां आवश्यक हो, रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त करना और इसके लिए अन्य सदस्य बैंकों की मंजूरी की प्रतीक्षा न करना, बहुमत के आधार पर नये सदस्य/सदस्यों के प्रवेश निर्णय करने के बारे में बैंक अधिकारियों को अधिक विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान करना, एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर निर्णयों को लागू करना, प्रलेखों को सरल बनाना, शर्तों और उपबंधों की एकरूपता और कारोबार, आय और गैर-निधि पर आधारित सुविधाओं के संबंध में सान्धिक हिस्सेदारी। बैंकों से कहा गया कि वे विशेष रूप से संवितरण, प्रलेखन आदि के लिए एक स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य (सिंगल विंडो एप्रोच) प्राप्त करने का प्रयास करें और इस संकल्पना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के वास्ते एक समिति स्थापित की गयी है।

ऋणकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के उपाय

309. बैंकों से कहा गया कि वे ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि बिना किसी न्याय संगत कारण के सावधि ऋणों की वापसी अदायगी में निरंतर व्यतिक्रम करती रही हैं, उनकी (आस्थगित अदायगी गारंटियों सहित) नयी परियोजनाओं अथवा विस्तार के लिए नये सावधि वित्त मंजूर करने के आवेदनों पर विचार न करें। जहां तक कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं का संबंध है, जहां बैंकों के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि संबद्ध इकाइयों के प्रबंधक-वर्ग कदाचार (मालप्रैक्टिसेज) अपना रहे हैं और इसीलिए देय राशियों की वापसी अदायगी में बराबर व्यतिक्रम कर रहे हैं, वे नयी मंजूरियां देने अथवा निधियां विमुक्त करने को रोक रख सकते हैं और यदि प्रबंधक-वर्ग को अपेक्षित वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने के वास्ते आवश्यक हो तो उनके खातों के परिचालनों को अवरुद्ध कर सकते हैं या उन्हें बदलने के बारे में कार्रवाई कर सकते हैं।

310. ऋणकर्ताओं द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सांविधिक देय राशियों की अदायगी से संबद्ध बढ़ती हुई बकाया को ध्यान में रखते हुए बैंकों से अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि वे ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/नवीकरण/वृद्धि से संबद्ध आवेदन फार्मों में इस प्रकार से संशोधन करें कि यह सुनिश्चित हो सके कि सांविधिक देय राशियों के सम्बन्ध में सूचना उनमें स्पष्ट रूप से उभर कर आये।

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच समन्वय

311. वाणिज्य बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् राज्यों के वित्तीय, औद्योगिक विकास और निवेश निगमों) के बीच उपयुक्त समन्वयन स्थापित करने के उद्देश्य से बैंकों से यह कहा गया है कि वे कुछ अतिरिक्त उपाय करें। उद्देश्य यह है कि विलंब से बचा जाए और औद्योगिक इकाइयों के लिए बैंकों द्वारा कार्यकारी पूंजीगत सहायता उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाए। इन उपायों में ये शामिल हैं। संयुक्त अथवा साथ-साथ परियोजना मूल्यांकन, कार्यकारी पूंजीगत वित्त उपलब्ध कराने के संबंध में आरंभिक स्थिति में ही बैंकों द्वारा "सिद्धांत रूप से" वचनबद्धता और इकाइयों द्वारा उत्पादन आरंभ करने से कम से कम 3 महीने पहले बैंकों द्वारा कार्यकारी पूंजीगत ऋण सीमाओं की स्वीकृति। प्रभारों के धारणाधिकार के संबंध में पारस्परिक सहमति, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित करना और शाखा स्तर पर अधिक व्यापक स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित करना, आदि के मामले भी इनमें शामिल हैं।

विवादग्रस्त उत्पादन शुल्क और अन्य सांविधिक उपबंधों के बारे में कार्रवाई

312. कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के संबंध में विवादग्रस्त उत्पादन शुल्क और अन्य सांविधिक देयताओं से संबद्ध कार्रवाई के मामले की समीक्षा करके जून 1987 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये । इनमें यह कहा गया कि विवादग्रस्त उत्पादन शुल्क देयता को आकस्मिक देयता दिखाकर अथवा तुलन पत्र में इसके बारे में टिप्पणी देकर इस देयता को, बैंक-वित्त की गणना के लिए, अनुमत चालू देयता नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे वसूल न कर लिया गया हो अथवा ऋणकर्त्ता के खातों में उसके लिए व्यवस्था न कर दी गयी हो ।

चीनी उद्योग को अग्रिम

313. रिपोर्ट के भाग I में चीनी उद्योग को दिये जानेवाले अग्रिमों के विषय में नीतिगत परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है । ऋण खातों में वास्तविक आहरणों को मिलों के मासिक नकदी बजटों में प्रकट किये गये घाटे के आधार पर विनियमित किया जाना है । ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आनेवाली अलग-अलग इकाइयों के लिए 1985-86 के मौसम के दौरान उनके द्वारा उपभुक्त अधिकतम राशि के 115 प्रतिशत (पश्चिम उत्तर प्रदेश की इकाइयों के मामले में 125 प्रतिशत) की सीमा से अतिरिक्त ऋण सीमाओं के बारे में निर्णय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के अधीन होगा । ये मार्गदर्शी सिद्धांत सहकारी चीनी कारखानों के संबंध में गिरवी सीमाओं के बारे में राज्य सहकारी बैंकों को भी जारी किये गये ।

निर्यात ऋण

314 इस रिपोर्ट के भाग I में निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें घटाए जाने का उल्लेख किया गया है । संशोधित ब्याज दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :

	(1 अगस्त 1986 से लागू) प्रतिशत वार्षिक
पोतलदान पूर्व ऋण	
(i) 180 दिन तक	9.5
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	11.5
(iii) नकद प्रोत्साहन आदि पर, जिन्हें ईसीजीसी गारंटी के अन्तर्गत शामिल किया गया है (90 दिन तक)	9.5
पोतलदानोत्तर ऋण	
(i) मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथा निर्दिष्ट)	
(ii) मीयादी बिल—180 दिन तक	
(iii) नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि, जो ईसीजीसी की गारंटी के अन्तर्गत सरकार से प्राप्य है (90 दिन तक)	9.5
(iv) अग्राहरित शेष राशियां (90 दिन तक)	
(v) धारण राशि पर (केवल आपूर्ति अंश के लिए), जो पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के अंदर देय है (90 दिन तक)	
(vi) निर्यात ऋण जो अन्य प्रकार से निर्दिष्ट नहीं है (पहली अप्रैल 1987 से लागू)	14.0 से 15.5

315. वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि मांग बिलों पर दिये गये अग्रिमों के मामले में, यदि वे बिल "सामान्य मार्गस्थ अवधि" के समाप्त होने से पूर्व वसूल हो जाते हैं तो अग्रिम देने की तारीख से इस प्रकार के बिलों की वसूली की तारीख तक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाना चाहिए । यह दिसम्बर 1986 से प्रभावी होगा । बैंकों को ब्याज में सहायता केवल बिलों की वसूली तक की वास्तविक अवधि के लिए उपलब्ध होगी ।

316. बैंकों से जनवरी 1987 में यह भी कहा गया कि यदि पोतलदान पूर्व अग्रिम, उन अग्रिमों को मंजूर किये जाने के प्रारंभिक 180 दिन की अधिकतम अवधि के बाद भी 180 दिन तक निर्यात प्रलेख प्रस्तुत करके समंजित नहीं किये जाते हैं तो वे अग्रिम आरम्भ से ही निर्यातकर्त्ताओं के लिए रियायती दर पर ब्याज के पात्र नहीं रहेंगे । दूसरे शब्दों में, मूल अग्रिम की तारीख से यदि 360 दिन के भीतर निर्यात नहीं होता, तो बैंक अग्रिम के पहले दिन से ही निर्यात ऋण की उच्चतम सीमा तक ब्याज वसूल कर सकते हैं ।

आवास वित्त

317. 1986 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले आवास वित्त की मात्रा 150 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही । इसके अतिरिक्त बैंकों से कहा गया कि वे आवास विकास वित्त निगम (हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन--एच.डी.एफ.सी.) को (वार्षिक विनिधान में शामिल किये गये 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त) उसके आवास वित्त संबंधी कार्यों के वास्ते 10 करोड़ रुपये की और राशि उपलब्ध करायें । बैंकों को यह भी प्राधिकार दिया गया कि वे, संयोय आधार पर 150 करोड़ रुपये के समग्र विनिधान के भीतर, आवास और शहरी विकास निगम (हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन--एच.यू.डी.सी.ओ.) को 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायें, ताकि वह विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलायी जा रही अपनी आवास परियोजनाओं के निर्माण व्यय को आंशिक रूप से पूरा कर सके । एच.यू.डी.सी.ओ. और राज्य स्तरीय अन्य अभिकरणों को बैंकों द्वारा दी जानेवाली इस प्रकार की सीधी सहायता उस वित्त के अतिरिक्त होगी, जो उन्हें उनके गारंटीकृत बांडों और डिबेंचरों में अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था ।

318. जून 1986 में राष्ट्रीय आवास बैंक (नेशनल हाउसिंग बैंक) की स्थापना के प्रस्ताव की जांच के लिए भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल स्थापित किया था । इस दल से यह भी कहा गया था कि वह आवास के लिए निधियां एकत्र करने के तरीके पर भी विचार करे । इसमें आवास वित्त संस्था के निर्माण के प्रयोजन के लिए किये जाने वाले उपयोग का निर्धारण भी शामिल हैं । इस दल ने सिफारिश की है कि विशेषीकृत आवास वित्त संस्थाओं का एक जाल निर्मित किया जाए, जिसके शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय आवास बैंक हो और इसकी स्थापना 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेयर पूंजी से की जाए, जिसे पूरी तरह रिज़र्व बैंक उपलब्ध कराये । राष्ट्रीय आवास बैंक की, जो कि एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जा रहा है, प्राथमिक जिम्मेदारी यह होगी कि वह क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विशेषीकृत आवास वित्त संस्थाएं स्थापित करें । ये संस्थाएं अतिरिक्त बचत राशियां जुटायेंगी और आवास निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करायेंगी । उक्त बैंक आवास के लिए संसाधन और ऋण जुटाने के लिए निधियों का निर्माण, आवास वित्त संस्थाओं के कार्य का विनियमन और साथ ही उनकी और आवास क्षेत्र के अन्य अभिकरणों की गतिविधियों का समन्वयन करेगा । वह आवास वित्त विषयक मध्यवर्ती संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा । राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना से संबंधित वैधानिक ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

पट्टे पर देना

319. गत वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से वाणिज्य बैंकों को उपस्कर पट्टे पर देने (लीजिंग) के कारोबार के लिए सहयोगी बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के और निजी क्षेत्र के एक बैंक के (इसी प्रकार के दो और बैंकों के साथ मिलकर), उपस्कर पट्टे पर देने के कारोबार के लिए सहयोगी बैंक स्थापित करने की तीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है ।

शेयरों और डिबेंचरों तथा सरकारी बांडों में निवेश और उनकी हामीदारी

320. वाणिज्य बैंकों को हामीदारी अथवा वाणिज्यिक बैंकिंग वायदों के माध्यम से मिलनेवाली निजी कंपनी क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचरों को उनके अपने निवेश संविभाग में रखने की अनुमति दी गयी है । नवंबर 1986 में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि इस प्रकार के निवेश पिछले वित्तीय वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत की सीमा तक सीमित रहने चाहिए । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में लचीलेपन की भी अनुमति दी गयी है जिसके अनुसार कोई भी बैंक 1.5 प्रतिशत की सीमा पार करने पर इस प्रकार की अतिरिक्त राशि रखने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमोदन का अनुरोध कर सकता है; अलग-अलग बैंक, सभी बैंकों की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर इस प्रकार की अतिरिक्त राशियां रख सकते हैं ।

321. मई 1987 में बैंकों से कहा गया कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों की कुल राशि को उनके निवेशों की राशि के साथ मिलाने पर यह किसी भी राजकोषीय वर्ष में उनके पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो । किन्तु यदि कोई बैंक 1.5 प्रतिशत की इस सीमा का अतिक्रमण करे तो वह इसके कारणों को बताते हुए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है । यह सीमा राजकोषीय वर्ष 1987-88 से लागू होगी और निगमित क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचरों के संबंध में सीमा के अलावा होगी ।

322. बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे सरकारी क्षेत्र के बांडों अथवा निगमित क्षेत्र के शेयरों और डिबेंचरों की अपनी धारिताओं के संबंध में वापसी-खरीद (बाई-बैक) की व्यवस्था न करें । वापसी-खरीद के सौदे बैंकों द्वारा स्वयं अपने निवेश-संविभाग में वस्तुतः धारित सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूमियों तक ही पूरी तरह सीमित रहने चाहिये ।

रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान

323. इस रिपोर्ट के भाग I में रुग्ण इकाइयों की समस्या का उल्लेख किया गया है । जून 1986 के अंत में, उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा रुग्ण इकाइयों के रूप में निर्धारित इकाइयों की कुल संख्या 130,606 थी और उनकी कुल बकाया बैंक ऋण राशि 4,665 करोड़ रुपये थी । इनमें से 689 इकाइयां बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां थीं अर्थात् ऐसी इकाइयां जो अलग-अलग बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की ऋण-सीमाओं का उपभोग कर रही थीं और उनकी कुल बकाया बैंक ऋण राशि 3,239 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में जून, 1985 के अंत में ऐसी इकाइयों की संख्या 597 थी और उनकी बकाया राशि 2,655 करोड़ रुपये थी । उपर्युक्त 689 रुग्ण इकाइयों में से 598 इकाइयों के बारे में अर्थ-क्षमता अध्ययन पूरे कर लिये गये और इनमें से 374 इकाइयों की अर्थक्षमता की संभावना वाला माना गया तथा 230 इकाइयों को बैंकों के पोषण कार्यक्रम (नर्सिंग प्रोग्राम) के अधीन रख दिया गया । जून 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार, लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयां 128,687 थीं और इनमें 1,184 करोड़ रुपये की बैंक वित्त फंसा हुआ था । इसकी तुलना में एक वर्ष पूर्व, इस प्रकार की इकाइयों की संख्या 97,890 थी और उनमें 955 करोड़ रुपये का बैंक वित्त अन्तर्ग्रस्त था । उपर्युक्त 128,687 इकाइयों में से 13,028 इकाइयों को बैंकों ने अर्थक्षमता की संभावना से युक्त पाया और 2,656 इकाइयों को अपने पोषण कार्यक्रम के अधीन ले लिया ।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता

324. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1986-87 (जुलाई-जून) के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 330 करोड़ रुपये की एक ऋण-सीमा की मंजूरी दी । यह ऋण-सीमा 15 वर्ष की अवधि के लिए है और इस पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस ऋण-सीमा का पूरा उपयोग कर लिया है । इसने इस वर्ष के दौरान 44.58 करोड़ रुपये की राशि की वापसी अदायगी की है और जून 1987 के अंत में, उक्त निधि से इसके ऋण की बकाया राशि 2,875 करोड़ रुपये थी । अगस्त 1986 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 200 करोड़ रुपये की एक अल्पावधि ऋण-सीमा मंजूर की गयी थी (जो कि अक्टूबर 1986 के अंत तक वैध थी) किन्तु उसने इस ऋण-सीमा का उपयोग नहीं किया । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भुनाये गये पात्र मियादी बिलों (यूजेंस बिलों) की जमानत पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, 14 मई 1987 को, 300 करोड़ रुपये की एक नयी ऋण-सीमा मंजूर की गयी । यह ऋण-सीमा अगस्त 1987 के अंत तक वैध है ।

325. निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को, 1986-87 के लिये, "राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि" से 85 करोड़ रुपये की एक ऋण-सीमा मंजूर की गयी । एक्जिम बैंक ने इस ऋण सीमा का पूरा उपयोग किया और 30 जून 1987 को उक्त निधि से उसके ऋणों की बकाया राशि 315 करोड़ रुपये थी ।

326. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को "राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि" से 1986-87 के लिए 15 करोड़ रुपये की एक ऋण सीमा मंजूर की गयी। उक्त बैंक ने इस ऋण सीमा का पूरा उपयोग किया और जून, 1987 के अंत में उक्त निधि से ऋण की बकाया राशि 25 करोड़ रुपये थी ।

327. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 1987 के कैलेण्डर वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपये की एक तदर्थ उधार सीमा स्वीकृत की गयी थी। इस निगम ने 30 जून, 1987 के अंत तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया था ।

328. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) को 1986 के कैलेंडर वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपये की एक तदर्थ ऋण-सीमा मंजूर की गयी थी, इसे 31 मार्च 1987 तक की अवधि के लिए और बढ़ाया गया । उक्त तारीख को इस ऋण-सीमा के अधीन कोई राशि बकाया नहीं थी । आई. सी. आई. सी. आई. को, इस बीच 20 करोड़ रुपये की एक नयी ऋण-सीमा मंजूर की गयी है जो 31 मार्च 1988 तक वैध है। 30 जून 1987 को इस विषयक बकाया राशि 20 करोड़ रुपये थी ।

329 इस वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर, रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय निगमों को उन अधिदेशों के मुताबिक कुल 55.20 करोड़ की नयी तदर्थ ऋण सीमाएं मंजूर कीं। ये ऋण-सीमाएं 25 जून, 1987 तक वैध थीं । इन ऋण सीमाओं के विषय में कोई राशि बकाया नहीं थी ।

330. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को, वर्ष 1986-87 के लिए 1,400 करोड़ रुपये की ऋण-सीमाएं मंजूर की गयीं ताकि वह, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में अल्पावधि ऋण और अग्रिम उपलब्ध करा सके। इस ऋण सीमा के विषय में बकाया राशि की उच्चतम सीमा, 28 फरवरी, 1987 को 1,267 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी । जून, 1987 के अंत में इस ऋण व्यवस्था के अधीन 950 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

बैंकों का निरीक्षण

331. भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों के अधीन बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण किया जाता रहा है।

332. समीक्षाधीन अवधि में सरकारी क्षेत्र के 29 बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 12 स्थानीय प्रधान कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय की वार्षिक वित्तीय समीक्षा आरंभ/पूरी की गयी।

333. इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 4 बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय, निजी क्षेत्र के 17 बैंकों और 8 विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण या तो आरंभ किये गये अथवा पूरे किये गये। इन निरीक्षणों के अलावा उक्त विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी विभिन्न शिकायतों/धोखाधड़ी/बैंकों/उनके कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के अनेक मामलों की जांच की। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी क्षेत्र के ऐसे 7 बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों के सांविधिक निरीक्षण भी किये, जिनकी शाखाएं विदेशों में स्थित हैं।

देय राशियों की वसूली (सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं) विधेयक, 1985

334. सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देय राशियों की वसूलियों से संबंधित विधेयक का प्रारूप, जिसमें बैंक ऋणों की वसूली से संबंधित मुद्दों पर ही अधिनिर्णय के लिए विशेष न्यायाधिकरण (स्पेशल ट्रिब्यूनल) स्थापित करने का प्रावधान है, भारत सरकार के विचाराधीन है।

ग्राहक सेवा

335. मार्च 1986 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि वे ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों की सीमा, प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के बारे में सर्वेक्षण करें। यह बताया गया है कि बैंकों ने मोटे तौर पर इस कार्यकारी दल की अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया है कि वे 2,500 रुपये तक के बाहरी स्थान के चेकों और साथ ही सरकारी/अर्ध सरकारी निकायों द्वारा जारी किये गये वेतन के 2,500 रुपये के चेकों को तुरंत जमा दिखा दिया करें।

बैंकों में धोखाधड़ियां

336. जुलाई 1986 से अप्रैल 1987 तक की अवधि के दौरान 110 बैंक कार्यालयों में 21 धोखाधड़ियों/शिकायतों की जांच की गयी। इनके निष्कर्षों को सुधारात्मक कार्रवाई और कर्मचारियों के दृष्टिकोण से मामलों की जांच के लिए संबद्ध बैंकों को सूचित कर दिया गया। इन जांचों के निष्कर्षों को जहां कहीं आवश्यक था, सरकार के ध्यान में भी लाया गया।

337. सरकार और रिज़र्व बैंक देश में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, बैंक डकैतियों/लूट की बढ़ती हुई घटनाओं से बहुत चिंतित है। वर्ष 1986 में देश में बैंक डकैतियों/लूट की 110 घटनाएं हुईं जिनमें 395.34 लाख रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी। इसकी तुलना में 1985 के दौरान इस प्रकार के 79 मामले हुए थे जिनमें 171.14 लाख रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी। सुरक्षा उपायों के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये गये और बैंकों से कहा गया कि वे कार्य योजनाएं बनायें तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करें।

338. डकैतियों, लूटपाट की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि बैंकों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और उन्हें मजबूत बनाने के उपाय सुझाए जाएं। तदनुसार बैंकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 1987 में एक समिति स्थापित की जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

वाणिज्य बैंकों में सतर्कता तंत्र

339. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों का एक सम्मेलन अप्रैल 1986 में आयोजित किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सतर्कता व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए किये जाने वाले विभिन्न उपायों से अवगत कराया गया। उनसे यह भी कहा गया कि वे विचाराधीन पड़े हुए अनुशासनिक मामलों का शीघ्रता से निपटान करें और सतर्कता विषयक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के बारे में अपने कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें।

चेक समाशोधन का कंप्यूटरीकरण

340. एम आई सी आर फार्मेट में बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली पर आहरित अंतर-नगरीय चेकों का समाशोधन अब मध्यम गति के रीडर/सार्टर प्रणालियों और सेवा का उपयोग करके किया जाता है। इस नयी व्यवस्था के परिणामस्वरूप अब अंतर-नगरीय चेकों का एक सप्ताह के भीतर समाशोधन हो जाता है जबकि पहले इसमें चार सप्ताह तक लग जाते थे। 1987-88 के दौरान ग्राहकों द्वारा उपर्युक्त चार नगरों पर आहरित और अहमदाबाद, बंगलूर और हैदराबाद में जमा किये गये एम. आई. सी. आर. चेकों का समाशोधन भी उपर्युक्त योजना के अधीन किया जायेगा। स्थानीय समाशोधन चेकों की मशीनों द्वारा छंटाई और जांच के लिए बंबई और मद्रास में उच्च गति की रीडर/सार्टर मशीनें लगायी गयी हैं। उपर्युक्त दोनों केन्द्रों पर यह प्रणाली पूरी तरह परिचालन में आ गयी है। यह सुविधा 1987-88 में कलकत्ता और नई दिल्ली में लागू की जाएगी।

कार्यकारी दल/समितियां

341. राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद् द्वारा दिसंबर 1986 में दिये गये सुझावों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1987 में एक कार्यकारी दल स्थापित किया जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं की कार्यकारी सहित अथवा उसके बिना बैंकों द्वारा संघीय आधार पर रुग्ण और रुग्ण इकाइयों को दिये गये ऋणों की वर्तमान व्यवस्था की जांच करना, और उसके बारे में मानदंड निर्धारित करना है। इस कार्यकारी दल का निर्णय करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने और ऋणकर्ताओं को समय से और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से उचित सिफारिशें भी करनी हैं। इस दल ने अपनी पहली रिपोर्ट मार्च 1987 में प्रस्तुत की जिसमें मुख्य रूप से रुग्ण और कमजोर औद्योगिक इकाइयों के संबंध में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों के बीच समन्वयन की समस्याओं की जांच की गयी है।

342. इस दल की सिफारिशों के अनुसरण में जून 1987 में बैंकों को कारोबार निर्देश जारी किये गये जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संघीय व्यवस्था में अग्रणी बैंक और दूसरे नंबर पर सबसे बड़े बैंक (या बहुविध-वित्तपोषण व्यवस्थाओं में दो प्रमुख बैंकों) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने की कल्पना की गयी है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का संबंध अर्थक्षमता विषयक अध्ययन और पुनः स्थापना विषयक पैकेज उपायों के कार्यान्वयन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान, संयुक्त समीक्षा, अनियमों को बाधा मानने के संबंध में संयुक्त कार्रवाई, बैंक अधिकारियों को और अधिक विवेकाधीन शक्तियां देने और स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशिक्षण से है।

343. निर्यात वित्त संबंधी स्थायी समिति ने निर्यात ऋण के ब्याज दर ढांचे के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की थी। रिज़र्व बैंक द्वारा इस समिति की सिफारिशों की जांच की गयी और उनके बारे में अंतिम निर्णय किया जा रहा है।

344. रिज़र्व बैंक की 1985-86 की रिपोर्ट में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के निर्धारण और पुनः स्थापन विषयक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति का उल्लेख किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये जिनमें रुग्ण इकाइयों के लिए पुनः स्थापना के एक मुख्य उपायों के अधीन उपयुक्त और गहन राहत उपायों की आवश्यकता और उन्हें

शीघ्रता से लागू करने पर बल दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में प्रारंभिक रुग्णता के कार्य-मूलक संकेतों की उदाहरण सूची भी शामिल की गयी है और रुग्ण इकाइयों को दी जा सकने वाली राहतों/रियायतों की सूची भी दी गयी है।

345. लघु औद्योगिक क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता की समीक्षा विषयक स्थायी सलाहकार समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

346. राज्य सरकारों और लघु उद्योगों के विकास से संबद्ध संघों/संगठनों को औद्योगिक रुग्णता विषयक समस्याओं/कारणों के संबंध में लघु उद्योग इकाइयों के नमूना अध्ययन करने चाहिएं। ग्राहक सेवा केन्द्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय किये जाने चाहिएं ताकि ऋणों की उपलब्धता में विलंब को कम किया जा सके और समन्वयन की समस्याएं हल की जा सकें।

347. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में व्यापक चर्चा के बाद उक्त समिति ने यह महसूस किया कि मूलभूत ढांचे की सुविधाएं विस्तृत करके और उद्यम विकास, कच्चे माल और संबद्ध निविष्टियों की पर्याप्त आपूर्ति के सुनिश्चय, टेक्नोलॉजी के समुन्नयन और पर्याप्त बाजार सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र की ऋण उपयोग क्षमता को क्रमशः बढ़ाया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति

348. 30 जून, 1987 की स्थिति के मुताबिक देश में 1,359 प्राथमिक सहकारी बैंक थे, जिनमें से 1,262 शहरी सहकारी बैंक थे और 97 वेतनभोगियों की समितियां। जुलाई 1986 से जून 1987 के बीच की अवधि के दौरान 384 (नये और साथ ही पहले से मौजूद) बैंकों को बैंकिंग कारोबार शुरू करने और/अथवा चालू रखने के लाइसेंस जारी किये गये और इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 845 हो गयी। प्राथमिक सहकारी बैंकों को चार विस्तार काउंटर और 9 शाखा कार्यालय खोलने की भी अनुमति दी गयी। सहकारी प्राथमिक बैंकों के प्रधान कार्यालयों सहित उनके कुल कार्यालयों की संख्या मार्च 1986 के अंत तक 2,995 से बढ़कर 31 दिसंबर 1986 को 3,059 हो गयी। राज्य सहकारी बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और उनकी संख्या 8 बनी रही। लाइसेंसप्राप्त मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में एक की वृद्धि हुई और दिसंबर 1986 के अंत में उनकी संख्या 36 हो गयी। 1986-87 के दौरान चार राज्य सहकारी बैंकों को 11 नये कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी किये गये।

349. जुलाई 1986 से जून 1987 तक की अवधि के दौरान 386 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निरीक्षण किये गये। वर्तमान प्राथमिक सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के मानदंडों की समीक्षा की गयी और संशोधित मानदंड तैयार किये गये। इसके अतिरिक्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए 226 बैंकों की खाता बहियों की शीघ्रता से जांच और उनके परिचालनों के तरीकों का अध्ययन किया गया।

जमा और उधार दरें

350. रिपोर्ट के भाग I में वाणिज्य बैंकों की घरेलू, एफ. सी. एन. आर०और०एन० आर० ई० जमाराशियों पर लागू ब्याज दर ढांचे और उधार की ब्याज दरों में परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। ये परिवर्तन उसी तारीख से सहकारी बैंकों पर भी लागू किये गये।

ऋण प्राधिकरण योजना

351. महत्वपूर्ण पक्षों से संबंधित 5 करोड़ रुपये से अधिक के खातों के संबंध में रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन ऋण प्राधिकरण योजना को राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू करने विषयक कार्य नाबार्ड द्वारा किये जाते हैं। जुलाई 1986 से जून 1987 तक की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के इस प्रकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले 4 प्रस्ताव नाबार्ड से प्राप्त हुए, जिसमें कुल 283 करोड़ रुपये की कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण सीमा अंतर्ग्रस्त थी। जुलाई 1986 से जून 1987 तक की अवधि के दौरान 46.02 करोड़ रुपये की कुल राशि, ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन अग्रिम के रूप में मंजूर करने का प्राधिकरण मांगते हुए 12 शहरी बैंकों से 66 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 25.04 करोड़ रुपये की समग्र राशि के कुल 38 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

पुनर्वित्त सुविधाएं

352. अनुमोदित कुटीर और लघु उद्योगों के 22 व्यापक समूहों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यक राज्यों का वित्तपोषण करने के लिए शहरी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। 1986-87 के राजकोषीय वर्ष के दौरान कुटीर और लघु उद्योग इकाइयों का वित्तपोषण करने के लिए 53 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से 6 राज्य सहकारी बैंकों को 29.91 करोड़ रुपये की समग्र राशि के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकृत की गयीं। इसकी तुलना में पिछले वर्ष 24.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण

353. शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उनके ऋण, उनके कुल अग्रिमों के कम से कम 60 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाने चाहिएं, जिनमें से कम से कम 25 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के लिए होने चाहिएं। यद्यपि आरंभ में बैंकों से कहा गया था कि वे जून 1985 तक चरणबद्ध रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, किन्तु कुछ बैंक निर्धारित समय के भीतर यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें जून 1986 तक की समय वृद्धि दी गयी। यद्यपि छोटे शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, बड़े बैंकों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा।

स्थायी सलाहकार समिति

354. फरवरी 1987 में हुई शहरी सहकारी बैंकों विषयक स्थायी सलाहकार समिति की छठी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी सहकारी बैंकों के विकास में राज्य सहकारी बैंकों की भूमिका, शहरी बैंकों के सांकेतिक (नॉमीनल) सदस्यों को वित्त प्रदान करने पर प्रतिबंधों और शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबद्ध मामलों पर भी विचार किया गया। इस समिति ने वर्तमान शहरी बैंकों को लाइसेंस जारी करने और कमजोर बैंकों की पुनः स्थापना के कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

समितियां और कार्यकारी दल

355. शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसरण में, रिजर्व बैंक के एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य उक्त सम्मेलन में पारित संकल्पों की जांच करना और उनके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना था। रिजर्व बैंक के अतिरिक्त समिति में शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

356. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "नाबार्ड-I ऋण परियोजना" के एक भाग के रूप में देश में कृषि ऋण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा आरंभ करने के बारे में उल्लेख किया गया था। इस परियोजना में पहली जुलाई 1986 से 3 वर्ष की अवधि के वास्ते 3,750 लाख

ग्रमे. डालरों का कुल ऋण ग्रंतर्ग्रस्त है। यह सहायता कृषि में निवेश के लिए नाबार्ड के चालू ऋण पुनर्वित्त कार्यक्रम में सहभागिता के रूप में थी ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके और ऋण सुपुर्दगी व्यवस्था मजबूत हो सके। इस प्रयोजन के लिए गठित एक वरिष्ठ विशेषज्ञ दल, कृषि ऋण व्यवस्था को इस समय प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं और मुद्दों का मूल्यांकन करेगा और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम के बारे में सिफारिशें करेगा।

357. गत वर्ष की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता और संबद्ध विषयों की समीक्षा विषयक उच्च स्तरीय समिति का उल्लेख किया गया था। इस समिति ने मई 1987 में आयोजित अपनी चौथी बैठक में "उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग के विकास से संबंधित अध्ययन दल" की रिपोर्ट पर विशेष रूप से विचार किया। इस बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शीघ्र आर्थिक विकास पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इस प्रयोजन के लिये, इस क्षेत्र को हर राज्य के वास्ते एक अलग टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय किया गया। हर जिले में कम से कम एक ब्लॉक के विकास के लिये मार्गदर्शी (पायलट) आधार पर एक समन्वित योजना तैयार की जायेगी।

विदेशी मुद्रा और अन्य मामलों संबंधी गतिविधियां

रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डालरों की बिक्री

358. रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी 1987 से प्राधिकृत व्यापारियों को अमरीकी डालरों की बिक्री की योजना आरंभ की। इससे पहले रिजर्व बैंक केवल हाजिर आधार पर पौंड स्टर्लिंग का विक्रय कर रहा था, जबकि हाजिर और वायदा दोनों आधारों पर प्राधिकृत व्यापारियों से चार मुद्राओं, अर्थात् पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, ड्यूश मार्क और जापानी येन की खरीद करता था। रिजर्व बैंक द्वारा डालर बेचने के निर्णय से अब बैंकों के लिये यह आवश्यकता समाप्त हो गयी है कि वे अमरीकी डालरों की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये पहले अंतर-बैंक बाजार या रिजर्व बैंक से पौंड स्टर्लिंग खरीदें और फिर विदेशी बाजार से उन्हें डालरों में परिवर्तित करायें। रिजर्व बैंक जिन दरों पर डालर बेचता है वे सामान्यतः उन दरों से बेहतर होती हैं, जो रिजर्व बैंक से पौंड स्टर्लिंग खरीद कर उस मुद्रा को विदेशों में अमरीकी डालरों में परिवर्तित कराने पर प्राधिकृत व्यापारियों को प्राप्त होती। अभी बंबई तक सीमित इस योजना का उद्देश्य यह है कि स्थानीय विदेशी मुद्रा बाजार के स्वस्थ विकास में सहायता दी जाय और साथ ही आयातकों को प्राधिकृत व्यापारियों से बेहतर दरें प्राप्त करने में मदद मिले। डालरों की खरीद की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

भारतीय कंपनियों के अनिवासी शेयरधारकों को लाभांशों का प्रेषण

359. 31 जुलाई, 1986 से पहले यदि किसी गैर-फेरा (नान एफ. ई. आर. ए.) कंपनी में अनिवासी शेयरधारकों द्वारा धारित ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य में, कुल जारी ईक्विटी पूंजी के 25 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये से अधिक न हो, तभी प्राधिकृत व्यापारी, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर, उन अनिवासी शेयर धारकों के लाभांशों का प्रेषण कर सकते थे। अनिवासी शेयरधारकों को लाभांशों के शीघ्र प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 1986 से प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की सामान्य अनुमति प्रदान कर दी है कि वे सभी गैर-फेरा कंपनियों के अनिवासी शेयरधारकों के ईक्विटी शेयरों के लाभांशों का प्रेषण कर सकते हैं, चाहे अनिवासी शेयरधारकों द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य अथवा जारी पूंजी से प्रतिशतता कुछ भी क्यों न हो। अब केवल फेरा (एफ. ई. आर. ए.) के आवेदनों को पूर्व अनुमति के लिये रिजर्व बैंक को भेजना आवश्यक है।

नयी निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट योजना

360. भारतीय रिजर्व बैंक और आई. टी. सी. की अलग-अलग परमिट योजनाओं के स्थान पर रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिये एक ही व्यापक निर्बंध (ब्लैंकेट) विदेशी मुद्रा परमिट योजना की शुरुआत की। इस नयी योजना के मुख्य पहलू नीचे दिये गये हैं :

(1) अनुमोदित प्रयोजनों की सूची जिसके लिये निर्बंध परमिट धारक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं उसमें पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है ताकि निर्यातक रिजर्व बैंक में बार-बार आवेदन करने से बच सकें।

(2) अनुमोदित प्रयोजनों के लिये विदेशी मुद्रा व्यय की निर्धारित मद्वार सीमा को या तो हटा दिया गया है या पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है ताकि निर्यातकों को काफी आजादी मिल सके।

(3) विनिमय पात्रताओं की मात्रा, निर्यातित माल के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संदर्भ में वसूल किये गये विशिष्ट प्रतिशत से सम्बंधित रही है और उनका वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी उत्पाद सूचियों के अनुसार है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

361. अनिवासी भारतीयों को और अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित विदेशी निकायों को, भारतीय कंपनियों में पूंजी के प्रत्यावर्तन के लाभ और अन्य अर्जित आय का निवेश करने के वास्ते प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं। इनमें ये शामिल हैं : (1) नए औद्योगिक उपक्रमों में ईक्विटी पूंजी में शत प्रतिशत तक के बड़े पूंजी निवेश, (2) "40 प्रतिशत योजना" के अधीन भारतीय जहाजरानी कंपनियों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में लगी कम्पनियों या तेल समन्वेषण (एक्सप्लोरिंग) सेवाओं के जारी किये गये नये निर्गमों में निवेश, (3) "40 प्रतिशत और 74 प्रतिशत योजनाओं" के अधीन "चिकित्सा निदान केन्द्रों (मेडीकल डाइग्नोस्टिक सेंटर्स) में निवेश, और (4) "40 प्रतिशत योजना" के अधीन निजी लिमिटेड कंपनियों में निवेश।

निर्यातों से संबद्ध विदेशी मुद्रा नियंत्रण क्रियाविधियों में ढील

362. निर्यातकर्ताओं को और शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुछ विदेशी मुद्रा नियंत्रण क्षेत्रों में प्राधिकृत व्यापारियों की प्रत्यायोजित शक्तियां 23 अप्रैल 1987 से उपयुक्त रूप से बढ़ा दी गयीं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) गुणवत्ता, मात्रा आदि के दावों के कारण सभी नियमित निर्यात-कर्ता-ग्राहकों की ओर से निर्यात जहाजलदान के बीजक मूल्य में 10 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपए की जो भी कम हो, कमी करने की अनुमति। इससे पहले प्राधिकृत व्यापारी इस प्रकार के आवेदनों पर तभी विचार कर सकते थे जब वे निर्बंध (ब्लैंकेट) परमिटवाले निर्यातकों से प्राप्त हुए हों।

(2) निर्यात उत्पादनों की "चयन" सूची में शामिल वस्तुओं के संबंध में संबद्ध निर्यात पोतलदान के संबंध में एक लाख रुपए तक और अन्य निर्यात उत्पादनों के पोतलदान के संबंध में 50,000/- रुपए तक की राशि कमीशन के रूप में भेजने अथवा उस कमीशन राशि को बीजक मूल्य में से घटाने की अनुमति बशर्ते कि जिन दरों पर कमीशन अदा किया जाए वे दरों की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर हों :

(3) पोतलदानों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक अथवा 30,000 रुपए तक की राशि का, जो भी कम हो, निर्यात दावों के रूप में प्रेषण; और

(4) 5 करोड़ रुपए तक के मूल्यों वाली आस्थगित अदायगी की शर्तों पर इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात और विदेशों में टर्नकी/सिविल निर्माण ठेकों को पूरा करने के लिए बिड्स/आफर्स के बारे में प्रोबिड्स क्लियरेंस की मंजूरी। इस प्रकार के पोस्ट-बिड्स क्लियरेंस मंजूर करने के लिए एक्जिम बैंक को प्रत्यायोजित शक्तियां संबंधी मौद्रिक सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया।

विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति

363. खराबी/आपातकालीन स्थितियों, आदि से निपटने के लिए विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति की, तीन महीनों की अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जा सकती है। एक तकनीशियन को प्रति दिन देय पारिश्रमिक की सीमा, 18 जुलाई 1986 से, 300 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 500 अमेरिकी डालर कर दी गयी है। फर्मों/कंपनियों को भी रिजर्व बैंक ने 25 मार्च 1987 से इस बात की सामान्य अनुमति प्रदान की है कि वे आयातित संयंत्र/उपकरण/मशीनरी कार्य के निर्माण या उसे चालू करने के कार्य और साथ ही निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, सहयोगिता व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए वर्तमान संयंत्र/मशीनरी की खराबियों के लिए भी विदेशी विशेषज्ञों/तकनीशियनों की नियुक्ति के संबंध में रुपए में संबंधित खर्च उठा सकते हैं।

चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात के लिए योजनाएं

364. भारत सरकार ने विदेशी क्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गयी चांदी की अमानत पर चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात के लिए 8 दिसंबर 1986 से एक नयी योजना प्रारंभ की। उक्त योजना के अधीन विदेशी क्रेताओं को वस्तुओं/आभूषणों के निर्माण के लिए अपेक्षित चांदी की निःशुल्क आपूर्ति करनी होगी ताकि भारत से चांदी का शुद्ध निर्यात न हो। आभूषणों और वस्तुओं (जड़ाऊ वस्तुओं सहित) के निर्यात की अनुमति केवल तभी होगी जबकि निर्यात में कम से कम 20 प्रतिशत "मूल्य योजित" व्यवस्था हो।

365. उसी दिन आरंभ की गयी दूसरी योजना के अधीन, चांदी से निर्मित आभूषणों और वस्तुओं (सिक्कों को छोड़कर) के निर्यात, चांदी की प्रतिपूर्ति के लाभ के हकदार होंगे बशर्ते कि वे सरकार द्वारा निर्धारित "मूल्य योजित" और अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करें। उक्त योजना निर्यात के ऐसे आदेशों तक सीमित है जो अटल साख पत्र या सुपुर्दगी आधार पर नकद अदायगी या पूर्ण अग्रिम अदायगी द्वारा समर्थित हों।

परियोजना निर्यात

366. 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान परियोजना निर्यात से संबंधित कार्यकारी दल ने 3,702.81 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के 107 प्रस्तावों का अनुमोदित किया। इनमें सिविल निर्माण ठेकों (1,464.54 करोड़ रुपए) के 23 प्रस्ताव, टर्नकी ठेका (1,747.21 करोड़ रुपए) के 11 प्रस्ताव, इंजीनियरी माल की आपूर्ति के लिए आस्थगित अदायगी ठेकों (168.44 करोड़ रुपए) के 10 प्रस्ताव और परामर्शदाता ठेकों (322.62 करोड़ रुपए) के लिए 30 प्रस्ताव शामिल हैं।

भारत में दौरे पर आये अनिवासियों के संबंध में आतिथ्य

367. रिजर्व बैंक ने भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को 24 जुलाई 1986 से इस बात की सामान्य अनुमति प्रदान की है कि वह भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो भारत में दौरे पर हो, उसके दौरे की अवधि के दौरान, 2,000 रुपयों की अधिकतम सीमा तक आतिथ्य के तौर पर भारतीय रुपयों में अदायगी कर सकता है। इस सीमा को पुनः जून 1987 में 5,000 रुपयों तक बढ़ा दिया गया।

विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण और विदेशी ईक्विटी कम करना

368. जून 1987 के अन्त में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमा तक अपेक्षित भारतीयकरण/विदेशी ईक्विटी की कमी के संदर्भ में 389 कंपनियों का अंतिम आदेश जारी किए गए। इनमें से 14 कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने भारतीयकरण के बजाय अपनी गतिविधियों का समापन कर देने का विकल्प चुना। उक्त कंपनियों में से 368 कंपनियों ने उस तारीख तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) निदेशों का अनुपालन कर लिया है। शेष 21 कंपनियां अनुपालन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

विदेशों में संयुक्त उद्यम

369. दिसम्बर 1986 के अन्त में, विदेशों में, 187 भारतीय संयुक्त उपक्रम थे। इनमें से 150 कार्य कर रहे थे और 37 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। दिसम्बर 1986 के अन्त में विदेशों के संयुक्त उद्यमों में भारतीय उद्यमियों की शेयर पूंजी का मूल्य 92 करोड़ रुपए के आसपास और कार्यान्वित होने की प्रक्रिया के अधीन संयुक्त उद्यमों में 18 करोड़ रुपए के आसपास था। भारत को प्रत्यावर्तित लाभांश की कुल राशि लगभग 11.57 करोड़ रुपए थी और तकनीकी जानकारी शुल्क, रायल्टी आदि के कारण प्रत्यावर्तन की राशि प्रायः 34.79 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी। इन विदेशी परियोजनाओं के कारण भारत से कुल 161.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निर्यात संभव हुए हैं।

कार्यालयों का खोला जाना

370. 1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय कंपनियों/फर्मों को विदेशों में 16 व्यापारिक और 24 गैर व्यापारिक कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी। 18 भारतीय कंपनियों/फर्मों को भी अनुमति दी गयी कि वे विभिन्न विदेशी केन्द्रों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करें। उक्त अवधि के दौरान ही 63 विदेशी कंपनियों को भारत में नए संपर्क/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी। विशेष ठेकों को पूरा करने के लिए 21 परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति भी दी गयी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

371. वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा योजना और तीन ऋण गारंटी योजनाओं के परिचालन में खासी तरक्की की।

372. जुलाई 1986 से जून 1987 तक की अवधि के दौरान बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,887 हो गयी जिसमें 83 वाणिज्य बैंक, 194 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,610 सहकारी बैंक शामिल हैं। जमा बीमा योजना में अब हरियाणा सहित जहां 1 जनवरी 1987 से योजना लागू हुई थी, 15 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों की जमा राशियां शामिल हैं। इन वर्षों में निगम ने क्रमशः 1,500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की जमाराशियों के लिए बीमा रक्षा उपलब्ध करायी है जिसके अंतर्गत 2,320 लाख से अधिक खाते आते हैं जो कुल जमा खातों के 98 प्रतिशत हैं। बीमाकृत जमा राशियां बढ़कर 62,878 करोड़ रुपए हो गयीं जो कि जून 1986 के अन्त में कुल निर्धारणीय कर योग्य जमा राशियों का 72.9 प्रतिशत थीं।

373. जुलाई 1986 से जून 1987 तक के वर्ष के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में हिस्सा लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 251 से बढ़कर 263 हो गयी। इनमें 71 वाणिज्य बैंक और 192 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं की संख्या 173 से बढ़कर 175 हो गयी। इनमें 57 वाणिज्य बैंक, 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 37 सहकारी बैंक शामिल थे। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 में हिस्सा लेने वाले राज्य वित्तीय निगमों (राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित) की संख्या 20 पर अपरिवर्तित रही। जून 1987 के अन्त में लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 में भाग लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 44 से बढ़कर 66 हो गयी। दिसम्बर 1986 के अन्त में उपयुक्त चारों योजनाओं के अन्तर्गत छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये कुल गारंटीकृत अग्रिम 10,960 करोड़ रुपये हो गये जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

374. निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जुलाई 1986-जून 1987 के दौरान 462 से बढ़कर 486 हो गयी। इनमें 69 वाणिज्य बैंक, 152 क्षेत्रीय ग्रामीण

ग्रामीण बैंक, 14 राज्य वित्तीय निगम; 8 अन्य राज्य विकास ऐजेंसियां और 243 सहकारी बैंक शामिल थे। लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गए गारंटीकृत अग्रिम दिसम्बर 1986 के अन्त में 7,528 करोड़ रुपये हो गये जो कि वर्ष में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

375. जुलाई 1986-जून 1987 की अवधि के दौरान निगम को, छोटे उधारकर्ताओं सम्बंधी अपनी गारंटी योजनाओं के बारे में 199.52 करोड़ रुपये के लिये 8,52,227 दावे और लघु उद्योगों सम्बंधी योजना के बारे में 134.02 करोड़ रुपये के लिये 45,275 दावे प्राप्त हुए। इसी अवधि के दौरान कुल निपटान, छोटे उधारकर्ताओं के संदर्भ में 170.24 करोड़ रुपये के 6,93,865 दावे तथा लघु उद्योगों के संदर्भ में 94.99 करोड़ रुपये के 10,236 दावे रहा।

376. परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से और दावों की बढ़ती हुई संख्या के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से निगम निरन्तर क्रिया-विधियों का पुनरीक्षण करता रहा है और उन्हें सरल तथा कारगर बनाता रहा है। इस दिशा में निगम ने सभी गैर-औद्योगिक दावों का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है जिससे दावों की प्राप्ति और निपटान के बीच की समय सीमा घटकर 10-12 सप्ताहों तक रह गयी है। निगम द्वारा परिचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार से पुनरीक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी है ताकि वह निगम के कार्यकलापों में और सुधार लाने के लिये सिफारिशें कर सके।

गैर-बैंकिंग कंपनियां चिट फंड अधिनियम, 1982

377. आलोच्य वर्ष के दौरान, चिट फंड अधिनियम 1982 के उपबंध मध्य प्रदेश और पांडिचेरी में लागू किये गये। इससे यह अधिनियम 13 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में लागू हो गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, बिहार और दिल्ली के राज्यों ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और उनके द्वारा आगामी कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किया जाना

378. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निहित अध्याय III ङ के उपबंधों को, जोकि गैर-निगमित कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने से सम्बंधित हैं, लागू करने के लिए अब तक 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने आवश्यक कदम उठाये हैं। उक्त अध्याय III ङ के उपबंधों के अंतर्गत रिजर्व बैंक के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत-सी वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है इनमें से बहुत सी संस्थाओं द्वारा उक्त उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिकाओं पर अभी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई है।

गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियों की प्रवृत्ति

379. 31 मार्च 1986 की स्थिति के अनुसार, रिपोर्ट करने वाली 8,741 वित्तीय, गैर-वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा रखी गयी कुल जमाराशियां 18,072 करोड़ रुपये की थी, जबकि मार्च 1985 में रिपोर्ट करनेवाली 7,508 कंपनियों के पास 16,140 करोड़ रुपये की जमाराशियां थीं। इसी अवधि के दौरान जमा खातों की संख्या 124.1 लाख से बढ़कर 159 लाख हो गयी। विनियमित जमाराशियों में 451 करोड़ रुपये और छूटप्राप्त जमाराशियों में, 1,480 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। गैर-वित्तीय कंपनियों के पास रखी विनियमित जमा-राशियां उनके पास रखी हुई कुल शुद्ध स्वाधिकृत निधियों की 16.8 प्रतिशत थीं और इस प्रकार वे 35 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा से काफी कम थीं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित विनियमित जमाराशियां भी निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर ही रहीं। 31 मार्च 1986 को गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र में विनियमित जमाराशियां 3,266 करोड़ रुपये थी जो कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा धारित कुल जमाराशियों का 3.8 प्रतिशत थी, जबकि मार्च 1985 में यह प्रतिशत 3.9 था। 1985-86 के दौरान गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास रखी विनियमित जमाराशियों की वृद्धि दर 16 प्रतिशत थी जबकि अनु-सूचित वाणिज्य बैंक जमाराशियों के संदर्भ में यह वृद्धि दर 18.1 प्रतिशत थी। मार्च 1985 और 1986 के अन्त में विभिन्न श्रेणियों की कंपनियों के पास रखी जमाराशियों के ब्यौरे नीचे सारणी में दिये गये हैं।

करेंसी चेस्ट

380. मार्च 1987 के अन्त में करेंसी चेस्टों की कुल संख्या (489 रिपाजिटरियों को छोड़कर) 3,636 थी। इनमें से 17 करेंसी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास, 2,672 भारतीय स्टेट बैंक समूह के पास, 556 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास, 386 खजानों/उप खजानों के पास तथा 5 जम्मू और कश्मीर बैंक लि. के पास थे।

गैर-बैंकिंग निगम क्षेत्र के संबंध में जमा वृद्धि (करोड़ रुपये)

	1984-85		1985-86*	
	रिपोर्ट देने वाली कम्पनियां	राशि	रिपोर्ट देने वाली कम्पनियां	राशि
1	2	3	4	5
कुल जमाराशियां				
जिनमें से	7,508	16,140	8,741	10,072
(1) नियमित जमाराशियां	—	2,815	—	3,266
(2) छूटप्राप्त जमाराशियां	—	13,325	—	14,806
क. निम्नलिखित के पास जमाराशियां				
(1) सरकार/कम्पनियां	55	8,923	56	10,029
	(0.7)	(55.3)	(0.7)	(55.5)
(2) सार्वजनिक लि० कम्पनियां	2,516	5,617	2,823	6,756
	(33.5)	(34.8)	(32.3)	(37.4)
(3) निजी लि. कम्पनियां	4,937	1,600	5,861	1,287
	(65.8)	(9.9)	(67.0)	(7.1)

1	2	3	4	5
आ. निम्नलिखित के पास जमाराशियां				
(1) वित्तीय कम्पनियां	4,134 (55.1)	3,914 (21.3)	4,995 (57.1)	4,276 (23.6)
(2) गैर वित्तीय कम्पनियां	2,510 (33.4)	11,784 (73.0)	2,680 (30.7)	13,113 (72.6)
(3) विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां	861 (11.5)	442 (2.7)	066 (12.2)	689 (3.8)

कोष्ठकों में आंकड़े रिपोर्ट करने वाली कुल कम्पनियों और कुल जमाराशियों, जैसी भी स्थिति हो, के प्रतिशत दर्शाते हैं।

* अनन्तिम

381. आलोच्य वर्ष के दौरान, करेंसी चेस्टों की शेष राशियों को अधिक अच्छी सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बहुत से दूरगामी निर्णय किये गये। 26 फरवरी, 1987 से एक वर्ष की अवधि के लिये नये करेंसी चेस्ट/रिपॉजिटरी खोलने पर रोक लगा दी गयी ताकि करेंसी चेस्टों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को समेकित करने के लिये इस अन्तराल की अवधि का उपयोग किया जा सके। यह भी निर्णय किया गया कि पंजाब में 51 करेंसी चेस्ट/रिपॉजिटरी बंद कर दिये जाएं जिनमें से 43 को बंद किया जा चुका है।

संगठनात्मक मामले और रिज़र्व बैंक के लेखे

मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण

382. वर्ष के दौरान, कानपुर और कलकत्ता के समाशोधन गृहों के परिचालनों को व्याप्त करने के लिए वहां मिनी-कम्प्यूटर स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही, आठ समाशोधन-गृहों अर्थात अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास और नई दिल्ली में परिचालन कार्य, कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। 1987-88 के दौरान शेष छः केन्द्रों में अर्थात भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, पटना और तिरुवनन्तपुरम में भी, जहां समाशोधन गृहों का प्रबन्ध रिज़र्व बैंक के पास है, कम्प्यूटरीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

383. चार निर्गम कार्यालयों, अर्थात अहमदाबाद, भायखला, नागपुर और नयी दिल्ली में अब मिनी-कम्प्यूटर कार्यरत हैं; आगामी वर्ष में नौ और केन्द्रों के इसी प्रकार कम्प्यूटरीकृत होने की संभावना है। वर्ष के दौरान वित्तीय कम्पनी विभाग के बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक मिनी-कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित की गयी। रिज़र्व बैंक के लिए दो दूर संचार नेटवर्क विकसित करने में पर्याप्त प्रगति की गई है और आशा है कि टेलीप्रिंटर नेटवर्क 1987-88 में चालू हो जाएगा।

384. एडवान्स्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें प्रारम्भ में बम्बई में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। सरकारी लेखा विषयक कार्य-दल की सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक, सरकारों के परम्परागत लेखों और विभागीकृत मंत्रालयों के लेखों के अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से नागपुर में लेनदेनों के समेकन और निपटान के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहमत हो गया है।

रिज़र्व बैंक में प्रणालियों और क्रियाविधियों का अध्ययन

385. अक्तूबर, 1986 में रिज़र्व बैंक ने बैंक के भीतर प्रचलित पद्धतियों और क्रियाविधियों की गहराई से जांच का कार्य बाहर के परामर्शदाताओं अर्थात मेसर्स मेनेजमेन्ट स्ट्रक्चर्स एण्ड सिस्टम्स लिमिटेड को सौंपा। यह संगठन एक वर्ष की अवधि के भीतर सात प्रमुख विभागों का अध्ययन करेगा और ग्राहक सेवा में सुधार को सुविधाजनक बनाने, शीघ्र निर्णय लेने तथा कार्य के बेहतर अन्तर-विभागीय समन्वयन की दृष्टि से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। छः विभागों का अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभाग उनकी जांच कर रहे

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई

386. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम संचालित किये, जैसे- कम्प्यूटरीकरण (पद्धति विश्लेषण), वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, संकाय विकास (कम्प्यूटरों पर), विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सांविधिक ढांचा (फ्रेमवर्क), बाह्य वाणिज्यिक उधार, चयनित उद्योगों के लिए बैंक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पर आधार पाठ्यक्रम, ई०डी०पी० ऑडिट और कन्ट्रोल तथा विदेश स्थित कार्यालयों में भी तैनात किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम इत्यादि। वर्ष के दौरान, महाविद्यालय ने 95 कार्यक्रम सञ्चालित किये जिनमें 2,383 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 1954 में महाविद्यालय की शुरुआत से लेकर आलोच्य वर्ष के अन्त तक कुल 33,210 सहभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वाणिज्य बैंक महाविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र लेने के लिए अपने संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के निवेदन पर इस महाविद्यालय ने उन्हें संकाय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा। वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने सामान्य बैंकिंग पर दो कार्यक्रम और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्त पर एक कार्यक्रम हिन्दी माध्यम से संचालित किये।

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

387. विभिन्न विभागों के ग्रेड "ए" से लेकर ग्रेड "सी" के अधिकारियों की नियमित प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के अलावा, इस महाविद्यालय ने कार्यपालक स्वास्थ्य, वार्षिक वित्तीय समीक्षा, कम्प्यूटर मूल्यांकन, भारत में अनिवासी निवेश और वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थ लेन-देन संबंधी विश्लेषण पर कुछ विशेष कार्यक्रम संचालित किये। वर्ष के दौरान महाविद्यालय में शुरू किये गये नये कार्यक्रमों में निरीक्षण विभाग/क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्ष के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। नोट वापसी नियमावली पर कार्यशाला, निधियों और निवेश संविभाग का प्रबन्ध, कम्प्यूटर बेसिक्स और प्रबन्ध पर कार्यक्रम, ऋण और कार्य-निष्पादन बजटिंग, सरकारी लेन-देन और लेखा प्रणाली तथा सुरक्षा प्रबन्ध और प्रोटोकोल, शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में संशोधित फार्मेट लागू करने, रिकार्ड ऑफ फाइंडिंग्स, निरीक्षण रिपोर्टों इत्यादि पर कार्यशाला शामिल है। महाविद्यालय द्वारा संचालित कुछ कार्यक्रमों में भूटान, बोटसवाना, केन्या, मालावी, मलावी, सूडान और तंजानिया के केन्द्रीय बैंकों के सहभागियों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने 104 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया; जिनमें 2,277 सहभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। महाविद्यालय की स्थापना से लेकर आलोच्य वर्ष के अन्त तक 20,693 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

388. वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय ने 84 नियमित कार्यक्रम, एक बाहरी (आउटस्टेशन) कार्यक्रम और तीन सेमिनार/विशेष कार्यक्रम संचालित किये। नियमित कार्यक्रमों में विश्व बैंक की आर्थिक विकास संस्था, वाशिंगटन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित ग्रामीण वित्त पर एक कार्यक्रम और वर्ष के दौरान प्रारंभ किये गये नये कार्यक्रम, जैसे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) अधिकारियों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण पर कार्यक्रम, और बंजर भूमि विकास तथा सामाजिक और अन्य वन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण पर कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों का वित्तपोषण, शुष्क भूमि परियोजनाओं का वित्तपोषण और तिलहन एवं दलहन का उत्पादन और ग्रामीण ऋण प्रणाली पर सेमिनार शामिल हैं। वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा संचालित 88 कार्यक्रमों में 2,324 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना से लेकर आलोच्य वर्ष के अन्त तक सहभागियों की संख्या बढ़कर 28,637 हो गयी।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

389. बैंक के भायखला (बम्बई), कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने बैंक के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना जारी रखा। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने अधिकारियों के रूप में पदोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने वाले लिपिकों के लिए तैयारी पाठ्यक्रम संचालित किये। लिपिक के रूप में पदोन्नति की परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गये। सुरक्षा व्यवस्था पर समिति की सिफारिशों के अनुसार भायखला स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र ने सुरक्षा जानकारी के पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक पायलट कार्यक्रम का संचालन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन चार केन्द्रों पर, 1,873 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और 325 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे इन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर वर्ष के अन्त तक इनकी कुल संख्या बढ़कर क्रमशः 31,818 और 1,417 हो गयी।

वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण

390. पिछले वर्ष लागू की गयी वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण की तीन योजनाओं के अन्तर्गत, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा विभागों सहित प्रमुख विभागों के गहन परिचय के साथ, बैंकों के नियंत्रण/प्रधान कार्यालयों में, आलोच्य वर्ष के दौरान अपना प्रशिक्षण पूरा किया। 39 अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और शहरी शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

भारत और विदेश में प्रशिक्षण हेतु स्टाफ की प्रतिनियुक्ति

391. बैंक ने 263 अधिकारियों को भारत की प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया। बैंक के अन्य 29 अधिकारियों को विदेशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैण्ड, पश्चिम जर्मनी और जापान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अधिकारियों में आर्थिक सिद्धांत और भारतीय अर्थशास्त्र में समस्याओं के प्रति उनकी समझ के दायरे में वृद्धि करने, तथा व्यावहारिक अर्थशास्त्र में अनुसंधान के लिए पर्याप्त विश्लेषणात्मक कुशलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान दो अधिकारियों को व्यावहारिक अर्थशास्त्र में एम-फिल पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज़, त्रिवेन्द्रम में प्रतिनियुक्त किया।

392. रिज़र्व बैंक के स्वर्ण जयन्ती समारोह के एक भाग के रूप में बैंक के अधिकारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश में उच्चतर अध्ययन के वास्ते छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 के लिए चार अधिकारियों का चयन करके उन्हें उच्चतर अध्ययन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष 1987 के लिए चार और अधिकारी चुने गये हैं।

कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी में प्रशिक्षण

393. बैंक की कम्प्यूटरीकरण और मशीनीकरण योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के अभिप्रेरणा मूल्यांकन के लिए बैंक ने कम्प्यूटर के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करने के वास्ते एक प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और सभी अधिकारी किसी भी अनुमोदित संस्थाओं में कम्प्यूटर क्षेत्र में अल्पावधि डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ले सकते हैं। पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उन्हें उस पाठ्यक्रम के लिए अदा किये गये शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा 500 रुपये का मानदेय प्रदान किया जायेगा।

विदेशी बैंकों के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण सुविधाएं

394. विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर वहां के सहभागियों को प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 58 विदेशी प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया। इनमें 11 श्रीलंका से, 8 इथियोपिया से, 7-7 नेपाल, सूडान और तंजानिया से, 4 भूटान से, 2-2 केन्या सोमालिया, गाम्बिया और बोट्सवाना से और 1-1 मलावी, थाइलैण्ड मॉरिशस, मलेशिया, युगाण्डा और मिश्र से थे।

नियोक्ता कर्मचारी संबंध

395. बैंक में औद्योगिक संबंध-वातावरण कुल मिलाकर शान्तिपूर्ण रहा और सभी संघ/यूनियनों के साथ संबंध सामान्यतया सौहार्दपूर्ण रहे। वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संघों के साथ समाधान बैठकें रखी गयीं और कामगार कर्मचारियों से संबंधित कुछ मुद्दों के संतोषजनक हल निकाले गये।

396. बेहतर आपसी समझ को बढ़ावा देने की दृष्टि से गवर्नर और ऑल इण्डिया रिज़र्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों के बीच एक बैठक रखी गयी। कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे, रिज़र्व बैंक की भूमिका और दायित्व तथा इसमें कर्मचारियों की सहभागिता, बैंक की क्षमता और ग्राहक सेवा तथा बैंक में औद्योगिक संबंधों की स्थिति में सुधार पर इस बैठक में चर्चा की गयी। रिज़र्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इण्डिया रिज़र्व बैंक स्टाफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ नवम्बर 1986 में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान अधिकारियों के लिए सुविधाओं में कुछ सुधारों की घोषणा की गयी।

397. अप्रैल 1987 के दौरान आयोजित प्रबन्धकों और केन्द्रीय कार्यालय विभागों के अध्यक्षों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय से संबंधित मुद्दों जैसे औद्योगिक संबंधों की समीक्षा, अनुशासन और समय की पाबंदी सुरक्षा, प्रबन्ध और कम्प्यूटरीकरण/मशीनीकरण की प्रगति पर चर्चा की गयी।

398. वर्ष के दौरान बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान के संबंध में एक नई योजना लागू की और इसके लिए पहली जनवरी 1987 से प्रभावी "रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया मेडिकल असिस्टेन्स फंड" का गठन किया। इस योजना/निधि, जो कि अंशदायी योजना है, का उद्देश्य सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी और आश्रित बच्चे) तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी के भारत में इलाज हेतु ऑपरेशन/गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में किये गये चिकित्सा-व्यय के एक भाग की पूर्ति के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस निधि के अन्तर्गत,

सेवारत कर्मचारियों को उपलब्ध सहायता, बैंक की सामान्य चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिपूर्ति से अधिक होगी। इस निधि की सदस्यता ऐच्छिक है तथा बैंक का कोई भी पूर्णकालिक कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित दरों पर अंशदान चुकाकर इसका सदस्य बन सकता है। निधि के प्रारम्भिक संग्रह के लिए रिजर्व बैंक ने 15 लाख रुपये का अंशदान दिया है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व

399. 1 जनवरी 1987 की स्थिति के अनुसार बैंक में श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या क्रमशः 1,860 और 528, श्रेणी III में 1,881 और 872 और श्रेणी I में 355 तथा 76 थी। 1986 के दौरान बैंक में सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती के ब्यौरे और कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे के नीचे दिये गये हैं।

श्रेणी	भर्ती किये गये उम्मीदवारों की कुल सं.	जिनमें से		कुल में प्रतिशत	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रेणी I	72	12	8	16.7	11.1
श्रेणी III	708	121	48	17.1	6.8
श्रेणी IV					
(i) श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर	222	69	22	31.1	9.9
(ii) सफाई कर्मचारी	27	3	—	11.1	—

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

400. 1986 के दौरान, श्रेणी III में 730 रिक्तियों में से 106 और श्रेणी IV में 295 रिक्तियों में से 72 को, आरक्षण की निर्धारित दरों पर, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाना था, इनमें से क्रमशः 61 और 36 रिक्ति वास्तव में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयीं। दिसम्बर 1986 के अन्त में श्रेणी III और श्रेणी IV में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या क्रमशः 596 और 908 थी। हाल ही में बैंक ने, पदोन्नति की ऐसी योजना के लिए जहां न्यूनतम-पात्रता मानदण्ड के रूप में सेवा के कुछ वर्ष निर्धारित किये हैं, श्रेणी III और श्रेणी IV में भर्ती किये गये ऐसे भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों को, जिन्होंने बैंक में कम से कम तीन वर्ष की वास्तविक सेवा पूरी कर ली है, रक्षा सेवा के लिए वेटेज देने का निर्णय किया है। तदनुसार, श्रेणी III और श्रेणी IV में भर्ती किये गये ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पांच वर्ष तक रक्षा सेवा में रहे हों, उन्हें एक वर्ष की सेवा का लाभ मिलेगा और जो दस वर्ष अथवा अधिक रहे हों उन्हें, अखिल भारतीय मेरिट टेस्ट के अन्तर्गत स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" के पद पर पदोन्नति के लिए, और पदोन्नति के अवसरों की योजना के अन्तर्गत श्रेणी III में प्रमोशन के लिए अधिकतम दो वर्ष का लाभ मिलेगा। यह लाभ बैंक में सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान पदोन्नति की केवल एक योजना के लिए स्वीकार्य होगा।

हिन्दी का प्रयोग

401. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 1986-87 के लिए वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यान्वयन के वास्ते परिचालित किये गये थे। कार्यालयों/विभागों द्वारा परिपत्र, कार्यालय आदेश और अन्य सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी करने के लिए कार्यालयों/विभागों द्वारा प्रयत्न जारी रखे गये तथा बैंक के विभिन्न प्रकाशनों/रिपोर्टों को भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया गया। जनवरी 1986 से भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

402. कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से हिन्दी टिप्पण, प्रारूप-लेखन और पत्राचार का प्रशिक्षण दिया गया। अप्रैल 1987 में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी पहली बार एक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र 'ग' के कार्यालयों में उनके कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए 'राजभाषा शील्ड' प्रतियोगिताओं के अलावा विभागीय शील्ड योजना में भी उनको शामिल कर लिया गया। बैंक के कार्यालयों/विभागों द्वारा वर्ष के दौरान वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, कवि-सम्मेलन, दि निबन्ध प्रतियोगिताएं हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं और अन्य हिन्दी समारोह आयोजित किये गये।

कार्यालय परिसर और रिहायशी क्वार्टर

403. वर्ष के दौरान कार्यालय भवनों और रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण/अधिग्रहण मौजूदा परिसरों में परिवर्धनों/परिवर्तनों तथा जमीन की खरीद इत्यादि पर अनुमानित व्यय की राशि 43.11 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल व्यय 114.42 करोड़ रुपये बैठता है जबकि पंचवर्षीय योजना के अवधि में 161.13 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

404. वर्ष के दौरान बंगलूर में वर्तमान कार्यालय भवन का विस्तार तथा गोरेगांव, बम्बई में इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निर्माण का पूरा किया गया। चण्डीगढ़ बम्बई में बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स तथा कानपुर में कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है। भोपाल, कोचिन जम्मू तथा नई बम्बई में प्रस्तावित कार्यालय भवनों के संबंध में प्रोसेसिंग कार्य हाथ में लिया गया है/पूरा कर लिया गया है।

405. रिहायशी क्वार्टरों के संबंध में 1986-87 के दौरान कुल 1,317 फ्लैट और 27 एकल कमरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें 600 फ्लैट और 27 एकल कमरे अधिकारियों के लिए, 575 फ्लैट श्रेणी III के स्टाफ के लिए और 142 फ्लैट श्रेणी IV के लिए है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 3,877 फ्लैट और 63 एकल कमरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया जिनमें 1,189 फ्लैट्स और 63 स्वयंपूर्ण एकल कमरे अधिकारियों के लिए, 1,564 फ्लैट श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए 1,126 फ्लैट श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए बनवाए गये हैं। अन्य 893 फ्लैट अधिकारियों के लिए 1,248 फ्लैट श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए और 502 फ्लैट श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए 11 केन्द्रों में निर्माणाधीन हैं। बैंक कर्मचारियों के लिए हॉली-डे-होम के वास्ते मसूरी और लोनावला में संपत्तियों के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया है।

आवास ऋण

406. जुलाई 1986 से 30 जून 1987 की अवधि के दौरान हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटियों तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों क

मंजूर किये गये आवास ऋण की राशि 10.05 करोड़ रुपये है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	मंजूर राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
क. सहकारी आवास समितियां			
नये ऋण	14	218	159.35
अतिरिक्त ऋण	47	411	103.27
कुल	61	629	262.62
ख. वैयक्तिक ऋण			
नये ऋण		191	162.61
अतिरिक्त ऋण		191	20.27
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर ऋण			
नये ऋण		1,041	475.15@
अतिरिक्त ऋण		294	84.02@
कुल		1,717	742.06
कुल जोड़ (क+ख)		2,346	1004.67

@ 7 मार्च, 1987 तक

केन्द्रीय बोर्ड

407. श्री आर० के० कौल उप गवर्नर के रूप में अपनी अवधि पूरी होने पर 30 सितम्बर 1986 को पद-भार मुक्त हो गये। श्री कौल द्वारा की गयी सेवाओं के प्रति बोर्ड अपनी प्रशंसा अभिलेखित करता है। श्री अमिताभ घोष और डॉ० सी.रंगराजन क्रमशः 21 जनवरी 1987 और 12 फरवरी 1987 से 5-5 वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किये गये। श्री पी० आर० नायक पहली अप्रैल 1987 से 5 वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गये।

स्थानीय बोर्ड

408. उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य श्री गुलाम मोहम्मद मीर खासजन ने 25 मार्च 1987 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। उनके द्वारा की गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड अपनी प्रशंसा अभिलेखित करता है।

409. श्री ए० हुसैन कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी होने पर, 28 फरवरी 1987 को पद-भार मुक्त हो गये। श्री सत्यानन्द बगाई 2 फरवरी 1987 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

लेखे

410. 30 जून 1987 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रावधानों के लिए समायोजन करने के बाद बैंक की आय की राशि पिछले वर्ष के 1,331.40 करोड़ रुपये की तुलना में 1,461.37 करोड़ रुपये थी।

411. वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि में अंशदान क्रमशः 300 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 430 करोड़ रुपये था, जबकि 1985-86 के दौरान इनमें अंशदान की राशि क्रमशः 350 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये थी।

412. वर्ष के दौरान आय की 721.37 करोड़ रुपये की शेष राशि में से कुल व्यय के लिए 511.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लेने के बाद (1985-86 में आय की शेष राशि 621.40 करोड़ रुपये और व्यय की 411.40 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में) केन्द्रीय सरकार को भुगतान के लिए अलग रखी गयी अधिशेष लाभ की राशि 210.04 करोड़ रुपये थी (पिछले वर्ष यह 210.00 करोड़ रुपये थी)।

413. पिछले वर्ष के 1,381.40 करोड़ रुपये के स्तर के मुकाबले 1986-87 में बैंक की आय 79.97 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 1,461.37 करोड़ रुपये हो जाने के पीछे मुख्य योगदान रुपया खजाना बिलों पर अर्जित ऊंची दर पर बट्टा तथा बैंकों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज का रहा। इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर अर्जित ब्याज में कमी तथा बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी उनकी अतिरिक्त नकदी आरक्षित निधियों पर अदा किये गये ब्याज में वृद्धि के कारण प्रतिसंतुलित हो गया। व्यय में 99.93 करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिभूति मुद्रण की लागत में वृद्धि तथा सरकारी लेनदेन करने के लिए एजेंसी बैंकों को देय कुछ कमीशन में वृद्धि होना रहा।

414. बैंक लेखों की लेखा परीक्षा मेसर्स सी०डी० चोकसी एण्ड कं०, बम्बई, मेसर्स बेद एण्ड कं०, नयी दिल्ली, मेसर्स एस० आर० बाटलीबॉय एण्ड कं०, कलकत्ता, मेसर्स ब्रह्मय्या एण्ड कं०, मद्रास और मेसर्स हिंगोरानी एम० एण्ड कं०, नयी दिल्ली ने की है। मेसर्स हिंगोरानी एम० एण्ड कं०, नयी दिल्ली को छोड़कर और सभी लेखा परीक्षक भारत सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त किये गये थे। मेसर्स हिंगोरानी एम० एण्ड कं०, मेसर्स के० सी० खन्ना एण्ड कं०, नई दिल्ली के स्थान पर नियुक्त किये गये थे। मेसर्स के० सी० खन्ना एण्ड कं०, अपनी चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर निवृत्त हो गये हैं। इस वर्ष भी बैंक के सभी कार्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किये गये थे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंक के सभी कार्यालय छः क्षेत्रों में दिये गये थे। और प्रति क्षेत्र/प्रति लेखा परीक्षक 75,000 रुपये लेखा-परीक्षा शुल्क के रूप में अदा किये गये। शाखा लेखों के सत्यापन के लिए केन्द्रीय कार्यालय के लेखा-परीक्षकों को 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1987 की स्थिति का तुलन-पत्र

निर्गम विभाग

देयताएं	रु. पै.	रु. पै.	आस्तियां	रु. पै.	रु. पै.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	16,23,72,540.00		सोने का सिक्का और बुलियन		
संचलन में नोट	30917,42,86,343.50		(क) भारत में रखा हुआ	274,27,76,380.65	
			(ख) भारत से बाहर रखा हुआ विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50	
जारी किये गये कुल नोट		30933,66,57,883.50	जोड़		1838,33,51,634.15
			रुपये का सिक्का		56,19,85,449.35
			भारत सरकार की प्रतिभूतियां		29039,13,20,800.00
			देशी विनिमय बिलकु और दूसरे वाणिज्य पत्र		
कुल देयताएं		30933,66,57,883.50	कुल आस्तियां		30933,66,57,883.50

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रु. पै.	आस्तियां	रु. पै.
प्रदत्त पूंजी	5,00,00,000.00	नोट	16,23,72,540.00
आरक्षित निधि	150,00,00,000.00	रुपया सिक्के	10,63,920.00
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	3725,00,00,000.00	छोटे सिक्के	2,87,694.94
जमा राशियां :		खरीदे या भुनाये गये बिल	
(क) सरकार		(क) भारतीय	
(1) केन्द्र सरकार	52,03,91,736.93	(ख) बाहरी	
(2) राज्य सरकारें	14,98,99,027.19	(ग) सरकारी खजाना बिल	3951,67,02,333.14
(ख) बैंक		विदेशों में रखे गये बकाया शेष	3675,82,31,835.27
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	15853,38,34,875.88	निवेश (1)	20058,44,36,934.27
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	146,21,63,849.55	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम	
(3) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,38,38,937.03	(1) केन्द्र सरकार	—
(4) अन्य बैंक	27,01,46,455.41	(2) राज्य सरकारें (2)	79,98,00,000.00
(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जमाराशियां		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम	
(1) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि			
(2) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	134,87,20,915.61	(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	853,06,18,378.88
(घ) अन्य	4940,79,13,350.59	(2) राज्य सहकारी बैंक	30,77,59,000.00
देय बिल	126,50,59,489.06	(3) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	949,68,16,000.00
अन्य देयताएं	9612,14,26,908.55	(4) अन्य	107,50,00,000.00
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
		(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम	
		(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2875,29,60,500.00
		(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	345,00,00,000.00
		(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
		(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—
		(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—
		अन्य आस्तियां (3)	1852,71,76,409.30
कुल देयताएं	34796,31,95,545.80	कुल आस्तियां	34796,31,95,545.80

(1) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए 2036,55,83,302.37 रुपये शामिल हैं।

(2) अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

(3) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी या उन्हें अग्रिम के रूप में दी गयी राशियां शामिल हैं।

30 जून 1987 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

		रु. पै.
आय		
ब्याज, बट्टा विनिमय शुल्क, कमीशन आदि *		721,37,24,362.17
	जोड़	721,37,24,362.17
व्यय		
स्थापना व्यय		137,98,79,616.13
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की फीस और व्यय		2,72,211.22
लेखा परीक्षकों की फीस		9,28,056.24
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		7,38,51,598.34
विधि प्रभार		30,91,509.04
डाक और तार खर्च		2,25,95,794.17
कोष प्रेषण		7,87,31,709.85
लेखन सामग्री आदि		1,59,63,795.10
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म आदि)		173,04,97,738.50
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत		8,31,98,248.92
एजेन्सी प्रभार		163,64,17,443.29
स्टाफ उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान		2,65,00,000.00
विविध व्यय		5,84,82,308.00
	जोड़	511,33,20,028.80
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि		210,04,04,333.37
	जोड़	721,37,24,362.17
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष		210,04,04,333.37

*भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत सांविधिक अंशदान और नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

आरक्षित निधि लेखा

		रु. पै.
30 जून 1986 को शेष		150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अंतरित		
	जोड़	150,00,00,000.00

के. डी. पाटकर	रा. ना. मलहोत्रा	गवर्नर
मुख्य लेखाकार	ए. घोष	उप गवर्नर
	सी. रंगराजन	उप गवर्नर
तारीख 14 अगस्त, 1987	पी. डी. ओझा	उप गवर्नर
	पी. आर. नायक	उप गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा-परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1987 की स्थिति के रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।

हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों के साथ उपर्युक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, वह सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। यह तुलनपत्र, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरण और बैंकों की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि इससे बैंक कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

तारीख 14 अगस्त, 1987

मैसर्स बहुगुण्या एण्ड कं.
मेसर्स पी. सी. चोकसी एण्ड कं.
मेसर्स एस. आर. बाटलीबॉय एण्ड कं.
मेसर्स वासगुप्ता एण्ड कं.
मेसर्स मेघ एण्ड कं.
मेसर्स हिंगोरानी एम. एण्ड कं.

लेखा परीक्षक

भारतीय रिज़र्व बैंक

30 जून, 1985 और 30 जून 1986 के अंत में तुलन-पत्र का विवरण

विवरण	30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए		30 जून 1986 को समाप्त वर्ष के लिए	
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
निर्गम विभाग				
देयताएं				
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	39,68,97,530.00		15,38,14,668.00	
संचलन में नोट	24755,60,11,721.50		27376,84,16,312.50	
जारी किये गये कुल नोट		24795,29,09,251.50		27392,22,30,980.5
कुल देयताएं		24795,29,09,251.50		27392,22,30,980.5
आस्तियां				
सोने का सिक्का और बुलियन				
(क) भारत में रखा हुआ	246,66 66,362.28		274,27,76,380.65	
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ				
विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
रुपये का सिक्का	15,00,32,662.85		22,51 68,831.20	
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	22969,56,34,972.87		25531,37,10,515.15	
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र				
कुल आस्तियां			24,795,29,09,251.50	27,392,22,30,980.5
बैंकिंग विभाग				
देयताएं				
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
आरक्षित निधि	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	2895,00,00,000.00		3295,00,00,000.00	
जमा राशियां				
(क) सरकारी				
(1) केन्द्रीय सरकार	59,86,10,234.95		57,09,03,373.31	
(2) राज्य सरकारें	14,87,27,256.98		14,01,33,635.35	
(ख) बैंक				
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	108,86,01,46,502.08		12616,58,36,433.76	
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	142,83,62,962.37		171,70,80,711.49	
(3) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,57,75,099.57		5,93,85,498.77	
(4) अन्य बैंक	25,18,33,462.00		25,51,30,796.64	
(ग) नाबार्ड की जमाराशियां				
(1) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	117,56,65,242.03			
(2) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	261,28,55,673.58		266,87,20,915.61	
(घ) अन्य	64,61,81,25,057.68		5901,50,25,855.63	
देय बिल	22,28,24,900.36		129,16,08,519.88	
अन्य देयताएं	6074,47,42,058.44		9627,95,57,694.61	
कुल देयताएं		27140,78,68,450.04		31266,33,83,435.(

टिप्पणी :—30 जून 1985—आकस्मिक देयता अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर रु. 9,04,997रु. 42

तुलन-पत्र का विवरण (जारी)

विवरण	30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए		30 जून 1986 को समाप्त वर्ष के लिए	
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
बैंकिंग विभाग				
आस्तियां				
नोट	39,68,97,530.00		15,38,14,668.00	
रुपए का सिक्का	7,20,074.00		8,11,044.00	
छोटा सिक्का	2,19,447.75		2,45,831.52	
खरीदे और भुनाये गये बिल				
(क) देसी	—		—	
(ख) विदेशी	—		—	
(ग) सरकारी खजाना बिल	8394,06,37,831.32		15834,61,56,415.79	
विदेशों में रखी शेष राशियां	3732,00,89,774.67		3760,23,20,272.63	
निवेश	6952,77,49,528.59 (ख)		5554,25,29,142.84(ग)	
ऋण और अग्रिम	—		—	
(i) केन्द्रीय सरकार को	—		—	
(ii) राज्य सरकारों को (क)	315,58,00,000.00		18,06,00,000.00	
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	1863,00,79 190.68		474,54,19,484.23	
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को	21,66,25,000.00		19,73,42,000.00	
(v) नाबार्ड को	761,83,41,000.00		860,90,24,000.00	
(vi) दूसरों को	182,05,00,000.00		135,60,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश				
(क) ऋण और अग्रिम				
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को	2320,78,30,750.00		2589,87,90,500.00	
(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक को	180,00,00,000.00		260,00,60,000.00	
(ख) भा. औ. वि. बैंक/भा. नि. आ. बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—		—	
अन्य आस्तियां (घ)	2377,23,78,323.03		1743,03,30,376.03	
कुल आस्तियां		27140,78,68,450.04		31266,33,83,435.04

(क) अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

(ख) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु. 1383,73,85,508.44 शामिल हैं।

(ग) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु. 1760,62,12,768.79 शामिल हैं।

(घ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये गये अग्रिम या उनमें जमा की गयी राशियां शामिल हैं।

30 जून 1985 और 30 जून 1986 को समाप्त वर्षों का लाभ और हानि लेखा

	30 जून 1985 को समाप्त वर्ष	30 जून 1986 को समाप्त वर्ष
	रु. पै.	रु. पै.
आय		
ब्याज बट्टा विनियम कमीशन आदि	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38
जोड़	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38

व्ययः		
स्थापना	142,25 62-666-01	128,12,08,682.12
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	2,64 677.99	3,37,965.01
लेखा-परीक्षकों की फीस	6,68,795.90	7,08,633.50
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	4,77,58, 619.79	6,37,88,291.34
विधि प्रभार	8,56,772.09	34,53,597.76
डाक और तार खर्च	1,30,13,462.74	1,46,17,550.44
मुद्रण	2,27,86,300.80	4,08,34,355.50
लेखन-सामग्री आदि	1,50,83,724.29	147,79,459.38
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म आदि)	58,28,05,498.05	100,07,82,422.27
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत	6,63,11,894.66	6,64 16,997.37
एजेंसी प्रभार	132,84,76,907.52	150,01,19,357.24
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,70,00,000.00	2,15,00,000.00
विविध व्यय	10,21,97 196.67	10,54,64,541.40
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि,	210,00,00,824.47	210,00,01,000,05
जोड़	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	210,00,00,824.47	210,00,01,000.05

*भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अंतर्गत सांविधिक अंशदान और निर्धारित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

प्रारक्षित निधि लेखा		
30 जून को शेष	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
लाभ हानि लेखे से अंतरित	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोड़	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

[सं. एफ 19/29/ 87--बी. ओ.-1]
एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 6th November, 1987

S.O. 3568.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1987 :—

THE ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1986 to June 30, 1987

PART I—THE ECONOMIC SITUATION

During the year 1986-87, the second year of the Seventh Five Year Plan, the growth rate of real national income is expected to be between 4.5 and 5.0 per cent as compared to 5.1 per cent in 1985-86. Industrial growth rate, placed between 7 and 8 per cent, would be lower than that of 8.7 per cent achieved in the first year of the Plan. Agricultural output may show a marginal decline as against a moderate expansion of 1.9 per cent in the previous year. The target for the Seventh Plan as a whole is an average annual growth rate in national income of 5 per cent. This order of growth is expected to be sustained by an industrial growth of 8 per cent per annum and an agricultural growth of 4 per cent per annum. Taking the first two years together, the average rate of growth of real national income may be only fractionally lower than 5 per cent. While the growth in industrial sector has been close to the target, the agricultural sector has been performing well below the target. The contribution to the overall growth rate by the services sector, which has now a weight of over 40 per cent in gros, domestic product, has been substantial: it has been growing at around 7 per cent per annum.

2. The poor perfomance of agriculture during 1986-87 was due to decline in production of foodgrains and fibres. Only oilseeds and sugarcane have shown improvement. In industry, though the overall growth was lower, some of the infrastructural industries such as electricity, coal and cement, performed better than in the previous year.

3. The Wholesale Prices Index (WPI) on a point-to-point basis recorded an acceleration in the rate of increase from 3.8 per cent in 1985-86 to 5.3 per cent in 1986-87*. On a point-to-point basis, the rise in the Consumer Prices Index (CPI) was lower at 7.5 per cent in 1986-87 as against 8.9 per cent in 1985-86**. Thus, as in the preceding year, the inflation rate as measured by the CPI was much higher than that indicated by the WPI. The average price increase during the first two years of the Seventh Plan is 4.5 per cent on

*On average basis, However, the rise in WPI was marginally lower at 5.4 per cent in 1986-87 as against 5.7 per cent in 1985-86.
**On an average basis, However, the rise in the CPI was higher at 8.8 per cent as against 6.4 per cent in 1985-86.

a point-to-point basis and 5.5 per cent on an average basis in respect of wholesale prices, while the respective figures for consumer prices are 8.2 per cent and 7.6 per cent. A disquieting trend is a large increase, particularly in consumer prices for two years in succession.

4. Preliminary data indicate that net domestic saving as percentage of NNP was higher at 18.2 per cent in 1986 87 as against 16.8 per cent in 1985-86; aggregate net investment as percentage of NNP also shows a rise from 19.3 per cent in 1985-86 to 20.2 per cent in 1986-87.

5. On the external front, there was some narrowing down of trade deficit in 1986-87 due to improved performance of our exports and slower growth in the import bill largely because of a fall in oil price. The invisible receipts on account of travel and tourism were also higher in 1986-87.

6. The country's foreign exchange reserves, comprising foreign currency assets, gold holdings and SDRs, rose by Rs. 331 crores to Rs. 8,151 crores at end—March 1987, on top of a rise of Rs. 577 crores in 1985-86. In SDR terms, however, these reserves showed a decline of SDR 615 million in 1986-87 as compared to a fall of SDR 276 million in 1985-86.

7. Judged by the overall growth rate, the economy performed reasonably well in 1986-87, but the continued slackness in agricultural growth is a cause for concern. Even though there was a reduction in current account deficit, the balance of payment situation requires to be kept under watch.

AGRICULTURAL PRODUCTION

8. In 1986-87, agricultural production is estimated to show a marginal decline against a rise of 1.9 per cent in 1985-86 and a decline of 0.9 per cent in 1984-85. Although there has been relative stagnation over the last three years, the performance of agriculture during the quinquennium 1981-82 to 1985-86 showed an average rate of growth of 3.3 per cent.

9. The monsoon in 1986-87 continued to be indifferent for the third year in succession. Of the 35 Meteorological subdivisions, rainfall during the year was deficient or scanty in as many as 14 sub-divisions as against in only 9 subdivisions in the previous year and 8 sub-divisions in 1984-85.

10. The foodgrain production during 1986-87 is estimated to be between 149 and 150 million tonnes, as compared with 150.5 million tonnes in 1985-86. It is lower than the target for 1986-87 by 10.11 million tonnes. Kharif foodgrains production is estimated to be at about 83.84 million tonnes while rabi output is placed around 66 million tonnes. Rice production is placed lower at 60.0—60.5 million tonnes during 1986-87, as against 64 million tonnes in 1985-86.

11. On the other hand, wheat output reached a level of 48 million tonnes in 1986-87 which was higher than that of 46.9 million tonnes achieved in 1985-86. Coarse grains production which was severely affected by drought in 1985-86 showed signs of revival with the production reaching 28.0—28.5 million tonnes in 1986-87, which is, however, still short of the target of 32.0 million tonnes. The production of pulses at 13.0 million tonnes in 1986-87 was about the same as in 1985-86.

12. Among non-foodgrains crops, production of cotton and raw jute (including mesta) in 1986-87 is placed lower than that in 1985 86. The production of cotton during 1986-87 is estimated at 71.8 lakh bales as against 86.1 lakh bales in the previous season. Raw jute and mesta production is also placed lower at about 86.3 lakh bales as against the record production of 127.3 lakh bales in 1985-86. The lower raw jute and mesta production during 1986-87 season was mainly due to the reduction in the acreage under raw jute and mesta following the very large size of the crop in 1985-86. Despite lower production, total availability during the season for cotton and raw jute and mesta was comfortable due to large carry-over of socks from the previous season.

13. The oilseeds production is estimated to be higher at 12.0—12.3 million tonnes than 11.2 million tonnes in 1985-86, but lower than the target of 14.8 million tonnes for 1986-87. Sugarcane production at 175.5 million tonnes is placed slightly above the previous year's level of 171.7 million tonnes.

14. Total procurement of foodgrains in 1986-87 was 19.9 million tonnes as against 20.1 million tonnes in the preceding year. With the set-back in production of rice, procurement of rice was lower by 5.2 per cent at 9.1 million tonnes during October 1, 1986 to June 26, 1987 as against 9.6 million tonnes procured during the corresponding period of previous year. However, due to record production of wheat at 46.9 million tonnes in 1985-86, the procurement of wheat during 1986-87 was higher at 10.5 million tonnes than that of 10.3 million tonnes in 1985-86. The wheat procurement in the current rabi marketing season upto June 30, 1987 was 7.8 million tonnes which was lower than the procurement of 10.4 million tonnes in the corresponding period of the previous year.

15. Following increased allocation of foodgrains for poverty-alleviation programmes like the National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP), the offtake of foodgrains for these programmes during 1986-87 at 1.9 million tonnes was higher than the offtake of 1.1 million tonnes in the previous year. The total offtake by the public distribution system inclusive of these programmes for poverty-alleviation and open sale of wheat by the Food Corporation of India was 19.0 million tonnes (8.6 million tonnes of rice, 10.2 million tonnes of wheat and 0.2 million tonne of coarse grains) in the financial year 1986-87 as compared to the offtake of 19.3 million tonnes (7.4 million tonnes of rice, 11.7 million tonnes of wheat and 0.2 million tonne of coarse grains) in 1985-86. Reduced offtake of wheat reflects the Government policy of permitting the roller flour mills to purchase wheat from the open market.

16. As on July 1, 1987, the stock of foodgrains was 23.4 million tonnes which was lower than the stock of 28.3 million tonnes on July 1, 1986 and 28.6 million tonnes on July 1, 1985. As these stocks were considered to be higher than those reuired as per the norms of the Technical Group on Buffer Stock Policy, the Government have been trying to bring down the level of stocks by such measures as larger allocation through the public distribution system and open market sales. Reduction of stocks through distribution to the target groups under NREP, RLEGP, etc., has been continued during the year.

17. The procurement of raw jute and cotton was lower in 1986-87 as compared to 1985-86. Raw jute purchases by the Jute Corporation of India in 1986-87 season were 22.2 lakh bales as compared to 28.2 lakh bales in the preceding season. The decline in purchases was the result of lower crop output of about 86.3 lakh bales as compared to 127.3 lakh bales in the preious year. Similarly, cotton procurement too was lower. The purchases by the Cotton Corporation of India unto June 30, 1987 were 8.2 lakh bales, as against 15.2 lakh bales procured in the corresponding period of the previous year. The procurement by the Maharashtra State Co-operative Cotton Growers' Marketing Federation unto June 30, 1987 as 12.1 lakh bales was even less than half, as compared to 27.6 lakh bales in the corresponding period of previous year. This is attributed to lower crop this season at 71.8 lakh bales as against 86.1 lakh bales in the preceding year. To remove the element of uncertainty on cotton export front, the Government for the first time announced a three-year cotton export policy under which 6 lakh bales per year will be permitted for exports beginning with 1986-87. The exports will, of course, be subject to minimum export price fixed by the Government from time to time.

18. The marginal decline in agricultural production during 1986-87 was due to indifferent monsoon. The increased use of fertilisers and other inputs helped to prevent a larger fall in production. The consumption of fertilisers in 1986-87 is estimated to be around 92 lakh tonnes as compared to 87 lakh tonnes in 1985-86. This shows a growth rate of 5.7 per cent which is lower than the average rate of growth

of 6.5 per cent in the preceding two years. The increased supply of certified quality seeds has also helped the increase in production. The distribution of quality seeds went up from 55.0 lakh quintals in 1985-86 to 55.8 lakh quintals in 1986-87. The production of breeder seeds and certified seeds is estimated to have increased from 23.6 thousand quintals and 44.8 lakh quintals, respectively, in 1985-86 to 24.8 thousand quintals and 56.5 lakh quintals in 1986-87.

19. The performance of agricultural sector during the past three years has been characterised by supply-demand imbalances especially of a few commodities like oilseeds, sugarcane and pulses entailing imports of related consumer items and substantial drain on foreign exchange. Despite some improvement in production in 1986-87 (April-March), imports of edible oils amounted to 14.15 lakh tonnes involving a foreign exchange outgo of Rs. 612 crores as against 10.80 lakh tonnes valued at Rs. 769 crores in 1985-86. In 1986-87 sugar imports were appreciably lower at Rs. 205 crores as against Rs. 432 crores in the previous year. This is attributed to the improved sugar production in 1986-87 which is expected to be over 84 lakh tonnes as against 70 lakh tonnes in 1985-86.

20. In view of the inadequate output of oilseeds and large foreign exchange outgo involved in importing edible oil, increased efforts are being made for achieving self-reliance in the production of oilseeds by the end of the Seventh Plan. Under instructions from the Prime Minister, the Technology Mission on Oilseeds was set up and started functioning from May 1986. The Mission has drawn up a multi-pronged plan to achieve self-reliance in oilseeds by the end of the Seventh Plan. The targets fixed by the Mission are to achieve production of oilseeds of 18 million tonnes and recovery level of 5 million tonnes of edible oil by 1989-90, from the current level of 12.3 million tonnes of oilseeds (average of 3 preceding years) and 3.6 million tonnes of oil.

21 Higher production is proposed to be achieved by increasing irrigated area under oilseeds. This was 28 lakh hectares in 1985-86 and is to be increased to 52 lakh hectares by the end of the Seventh Plan. At present, 14.9 per cent of the total area under oilseeds is irrigated. By the end of the Seventh Plan, the percentage would be raised to 23.6 per cent.

22. As part of the strategy, the Mission has set-up four micro-missions of the programme. The first micro-mission relates to improving crop technology concentrating on five oilseeds which contirbute 80 per cent towards total oilseeds production, viz., groundnut, rapeseed/mustard, soyabean, sunflower and castorseed. In addition, technologies for improved production of coconut and oil palm are being developed in Kerala and Andaman and Nicobar. The second micro-mission relates to processing and post-harvest operations in which the focus is on the modernisation of plants which extract oil from oilseeds, as in the traditional technique, 7 to 10 per cent of the oil remains unextracted in the oil cake. The third micro-mission relates to farm support system, i.e., providing input services such as extension services and also supply of fertilizers to oilseeds growers who are generally small farmers and usually cultivate marginal lands, and ensuring adequate and timely availability of credit from financial agencies. Finally, the fourth micro-mission will focus on various aspects of price support, processing storage and marketing. The Technology Mission has decided to concentrate its activities in 180 districts spread over 17 States. The erstwhile programme of National Oilseeds Development has been brought under the Mission's ambit to enable it to take an integrated view of oilseeds production.

TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION

23. The rate of growth of industrial production in the first ten months (April-January) of 1986-87 is 7.7 per cent (under new series, 1980-81 = 100) as compared with 9.2 per cent during the corresponding period of the previous year (Table 1). The deceleration is mainly due to the lower growth recorded by the manufacturing sector; the growth rates in mining and quarrying and electricity sectors are higher in 1986-87 than those in the previous year.

Table 1— Trends in Industrial Production

(Base 1980-811=00)

Sl. No.	Item	Weight	April-March					April-January	
			1981-82	1982-83	1984-85	1984-85	1985-86	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mining and Quarrying	11.46	117.7 (+17.7)	132.3 (+12.4)	147.8 (11.7)	160.8 (+8.8)	167.5 (+4.2)	160.1 (+3.2)	171.0 (+6.8)
2.	Manufacturing	77.11	107.9 (+7.9)	109.0 (+1.4)	115.6 (+5.7)	12.8 (+8.0)	136.9 (+9.7)	130.7 (+10.6)	144.4 (+7.2)
3.	Electricity	11.43	110.2 (+10.2)	116.5 (+5.7)	125.4 (+7.6)	140.4 (+12.0)	152.4 (+8.5)	151.3 (8.2)	166.9 (+10.3)
	General Index	100.00	109.3 (+9.3)	112.8 (+3.2)	120.4 (+6.7)	130.7 (+8.6)	142.1 (+8.7)	19.4 (+9.2)	150.1 (+17.7)

Note : Figures in brackets represent percentage variation s over the corresponding period of the previous year.

New Index

24. The index of industrial production has been revised by shifting the base period from 1970 to 1980-81. In the process of revision of the index, classification of industries coverage of items and the assignment of weights based on gross value added originating in various industrial groups, have also been altered.

25. The weighting diagram and the number of items of the three sectors comprising the general index in the earlier series with 1970 as base year and the new series with 1980-81 as base year are compared in the table below:

Table 2—No. of Items and Weights in Old Series and New Series

Sl. No.	Industry/Sector	No. of items		Weight	
		Old Series (1970=100	New Series (1980-81=100	Old Series	New Series
1	2	3	4	5	6
1.	Mining & Quarrying	61	61	96.90	114.64
2.	Manufacturing	290	290	810.80	771.07
3.	Electricity	1	1	92.30	110.29
	Total	352	352	1000.00	1000.0

26. Though the total number of items included in each of the three sectors continues to be the same in both the series, the weight of the manufacturing sector has fallen and those of the other two sectors have risen. In respect of the manufacturing sector, though the total number of items has remained the same, their composition has undergone a change due to deletion/addition and consolidation/sub-division of items included in the old series.

27. Among the major groups under the manufacturing sector, maximum changes in composition of items have taken place in the case of 'chemicals and chemical products'; as many as 25 items have been dropped and 35 new items have been added. Consequently, the weight of this group has gone up to 12.5 per cent from 10.8 per cent. In the case of 'electrical machinery' group, as many as 16 new items have been added to give representation to the rapidly rising electronics an telecommunication industries like TVs, minicomputers, telephones and teleprinters, etc. On the other hand, many items have been excluded in the case of 'non-metallic mineral products', and 'manufacture of metal products and parts (except machinery and transport equipment)' Some of he items in the 'petrochemicals and allied products' which were not included in the earlier index have been included in this new index. With a view to measuring the growth in industrial production more accurately, production in the small-scale sector is also included in the new index.

Quarterly Trends

28. An analysis of the trends in industrial production on a quarterly basis reveals that the general rate of growth showed deceleration in two of the three quarters for which data are available for the year 1986-87 (Table 3). In the case of mining and quarrying, the rate of growth showed improvement in all the three quarters, while in the case of electricity there was a marginal deceleration during the second quarter. On the other hand, manufacturing sector showed a higher growth rate only during the second quarter, while the rate of growth decelerated substantially in the other two quarters.

Table 3—Trends in Index of Industrial Production on Quarterly Basis

(Base 1980-81 = 100)

Period		General Index		Mining and Quarrying		Manufacturing		Electricity	
Weight		100.00		11.46		77.11		11.43	
Sl. No.	Year	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	April—June	131.7 (+9.3)	139.7 (+6.1)	152.2 (+0.4)	162.3 (+6.6)	126.8 (+11.3)	133.5 (+5.3)	144.2 (+7.8)	159.2 (+10.4)
2.	July—Sept.	134.7 (+7.3)	146.1 (+8.5)	147.1 (+3.2)	159.0 (+8.1)	130.7 (+7.9)	141.2 (+8.0)	152.0 (+9.8)	166.0 (+9.2)
3.	Oct.—Dec.	147.3 (+11.8)	156.7 (+6.4)	169.7 (+4.9)	182.0 (+7.2)	143.1 (+14.0)	150.7 (+5.3)	154.1 (+7.0)	171.6 (+11.4)
4.	Jan.—March	154.6 (+6.5)	N.A.	201.0 (+7.6)	N.A.	147.0 (+5.8)	N.A.	159.0 (+9.4)	N.A.

Note : Figures in brackets represent percentage variations over the corresponding period of the previous year.

Sectoral Trends

29. During April-January 1986-87, the rate of growth decelerated in manufacturing sector to 7.2 per cent from 10.6 per cent achieved during the corresponding period of the preceding year. Within the manufacturing sector, the engineering group of industries for which data are available till October, reveal that the growth rate was halved to 6.7 per cent as compared with that of 13.2 per cent during the corresponding period of the previous year. The other two sectors, viz., mining and quarrying and electricity generation, recorded higher growth rates during April-January 1986-87, following the special emphasis laid on improving the performance of the infrastructural sectors.

Infrastructure

30. The composite index of six infrastructure industries (viz. electricity, coal excluding lignite, petroleum crude, petroleum refinery products, saleable steel and cement) with a weight of 28.77 per cent in the revised index of industrial production (24.55 per cent in the old series) recorded a lower growth of 7.4 per cent during the full financial year 1986-87 as compared with 7.9 per cent in the previous year. In addition the targeted growth for all infrastructure industries which was fixed at 9.5 per cent for the year could not be achieved. Among the six infrastructure industries, the growth rates were higher only in the case of electricity, coal and cement in 1986-87 than those attained during the corresponding period of previous year (Table 4).

Table 4—Trends in Infrastructure Industries

Sl. No.	Industry	Unit	Weight	Production (April-March)		
				1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
1.	Electricity	Mill. KWH	11.43	1,56,973	1,70,045 (+8.3)	1,87,568 (+10.3)
2.	Coal	Mill. Tonnes	6.61	147.41	150.24 (+4.6)	165.79 (+7.5)
3.	Saleable Steel	Thous. Tonnes	5.21	6,997.00	7,774.00 (+11.1)	8,219.00 (+5.7)
4.	Crude Petroleum	,,	2.41	28,990	30,168 (+4.1)	30,463 (+1.0)
5.	Petroleum Refinery Products	,,	1.52	33,236	39,881 (+20.0)	42,490 (+6.5)
6.	Cement	,,	1.60	30,174	33,130 (+9.8)	36,400 (+9.9)
Total Infrastructure Industries			28.77		(+7.9)	(+7.4)

Note : Figures in brackets represent percentage variations over the corresponding period of the previous year.

Trends based on Use-based and Input-based Classification:

31. Since the item-wise data on Index Numbers of Industrial Production based on the new series (1980-81 = 100) have not been released by the CSO, the analysis of trends under Use-based and Input-based classification is presented on the basis of the old index (1970=100). The index recorded a higher growth of 6.4 per cent during April-October 1986 as compared with that of 5.9 per cent in corresponding period of the previous year. The available data on item-wise indices upto October 1986 show that while the rate of growth decelarated in the case of capital goods industries and intermedilate goods industries during April-October, 1986, the basic industries which recorded lower growth rates in the group higher growth rates in April-October, 1986 as compared with the corresponding period of the previous year (Table 5).

Table 5—Growth in Industrial Production : Use -Based Classification

(In percentages)

Sl. No.	Industry Group	Weight	(April-March)	(April-October)	
			1985-86	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1.	Basic Industries	33.23	+7.2	+6.4	+8.5
2.	Capital Goods Industries	14.98	+3.4	+4.1	+3.2
3.	Intermediate Goods Industries	21.33	+10.1	+10.3	+3.4
4.	Consumer Goods Industries	30.46	+3.7	+3.2	+8.2
	(a) Durables	3.81	+14.3	+18.5	+22.3
	(b) Non-durables	26.65	+1.6	+0.1	+4.6
General Index (1970=100)		100.00	+6.3	+5.9	+6.4

The higher growth in the basic industries group at 8.5 per cent as against 6.4 per cent in the previous year was accounted for by mining and quarrying and electricity.

32. The lower rate of growth of 3.2 per cent in April-October, 1986-87 as against 4.1 per cent in the preceding year in the capital goods industries group mainly reflected the negative rates of growth in a number of industries, namely, commercial vehicles, ball and roller bearings, power transformers, power driven pumps, agricultural tractors, road rollers, jeeps, etc. However, there was a steep increase in the output of railway wagons 5(2.6 per cent) in April October 1986 as against a fall (26.2 per cent) during the codresponding period of the previous year. Provisional data for the full fiscal year 1986-87 in respect of commercial vehicles indicate that the decline in the rate of production during the year was moderated to 4.0 per cent due to a rise of 10.7 per cent in the second half as compared with a decline of 19.6 per cent occurred during the first half of the year. Their sales during 1986-87 were higher by 4.4 per cent as compared with an increase of only 0.3 per cent in 1985-86. In case of medium and heavy commercial vehicle sales, there was a positive growth rate of 2.0 per cent, compared with a decline of 5.1 per cent in the preceding year. Further, their stocks as at end-March 1987 declined by more than 50 per cent over the year.

33. The intermediate goods industries recorded a lower growth of 3.4 per cent in April-October, 1986-87 as against 10.3 per cent in the corresponding period of 1985-86. The industries which recorded lower growth rates in this group were mainly auto-tyres, cotton and blended yarn and petroleum refinery products, while industries such as grinding wheels, bolts, nuts and rivets and dry cells showed negative growth rates. Among the consumer goods industries, the consumer durables industry has shown a significant degree of dynamism since 1984-85 following the liberalisation of the licensing policies. The group recorded a higher growth rate of 22.3 per cent during April-October 1986 as against 18.5 per cent during the corresponding period of the previous year; the rise was mainly on account of passenger cars, bicycles, clocks and scooters. The non-durables recorded a growth of 4.6 per cent during April-October, 1986 in contrast to a decline of 0.1 per cent in the corresponding period of the previous year; higher growth rates were recorded by sugar (32.4 per cent), pencillin (28.1 per cent) and vanaspati industries (9.5 per cent) during the period.

34. According to input-based classification, production of agro-based and chemical-based industries groups rose at faster rates of 4.5 per cent and 9.5 per cent, respectively, during April-October, 1986 as compared with those of 1.7 per cent and 4.8 per cent in the corresponding period of the preceding year. However, the growth of metal-based industries group was sluggish at 3.6 per cent during 1986-87 as compared with 9.6 per cent in the corresponding period of the previous year.

Industrial Sickness:

35. Industrial sickness among the small medium and large-scale units continued to rise. This is causing concern due to its repercussions on the entire economy. According to a available data as at the end of June 1986 the total number of units identified by banks as sick rose to 1,30,606 with outstanding bank credit of Rs. 4,665 crores accounting for 8.4 per cent of total bank credit or 17.1 per cent of bank credit to industry (small, medium and large).

36. The importance of detection of sickness at the incipient stage, as also the need for proper coordination between the commercial banks and term-lending institutions in the formulation, implementation end rehabilitation packages, has been emphasised by the Reserve Bank from time to time. Banks have been advised to determine the viability of units identified as sick within a time limit as also to draw-up and activate the appropriate rehabilitation packages for viable units with utmost expedition.

37. In terms of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Government of India have set up the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in January 1987 (which has become operative since May 15, 1987) for determining the preventive ameliorative, remedial and other measures which are required to be taken in respect of sick industrial companies and for expeditious enforcement of measures so determined. The Board has been given wide-ranging powers in respect of approval of rehabilitation packages for sick industrial companies including their reconstruction and revival as well as change of management or amalgamation with any other company for sale or lease of a part or whole of the industrial undertaking, etc., or even winding up of the company. Detailed guidelines were issued on February 24, 1987, advising banks of the action required to be taken by them in respect of companies assisted by them and in whose cases the provisions of the Act would be attracted. Briefly, the guidelines relate to the reporting to the BIFR, with a copy endorsed to Reserve Bank the position in respect of accounts with banks on sick industrial units under the following heads: (i) cases where a programme of rehabilitation as approved by financial institutions and the Reserve Bank is being implemented, (ii) cases where biability studies have been completed and the preparation of rehabilitation programme is in progress, (iii) cases where viability studies are yet to be undertaken, and (iv) cases where efforts at revival have failed and the unit was considered non-viable.

38. The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) has initiated various steps for arresting the growth of industrial sickness and in helping their revival Out of the 333 units assisted by IRBI till the end of June 1986, 136 units were revived and 131 units are under nursing programme . The rest are either continuing to incur losses or have been denotified with measures initiated for legal proceedings and recall of advances.

39. In order to provide refinance assistance for the development, expenasion, modernisation and rehabilitation of small-scale industries, a Small Industries Development Fund (SIDF) was set up in the IDBI on May 20, 1986. Furthermore, for the purpose of financing modernisation of textiles and jute sectors, Government has set up two funds, viz., the Textile Modernisation Fund and the Jute Modernisation Found with effect from August 1, 1986 and from November 1, 1986, respectively.

NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT

40. On the basis of available broad indicators, the rate of growth in NNP in real terms is expected to be between 4.5 and .0 per cent in 1986-87 as compared with .1 per cent in 198-86; it was 16.9 per cent in 1984-85. The net saving provisionally placed higher at 18.2 per cent of NNP at current market prices in 1986-87 as against 16.8 per cent in 1985-86; it was 16.9 per cent in 1984-85.. The net saving of the household sector as percentage of NNP at current market prices which had remained constant at 15.6 per cent in 1985-86 is estimated to have risen sharply to 17.0 per cent in 1986-87. The public sector saving as percentage of NNP is expected to remain at 0.7 per cent in 1986-87, the same rate as in 1985-86. The net saving of domestic private corporate sector is estimated to remain at 0.5 per cent of NNP in 1986-87.

41. Aggregate net investment which went up from 18.4 per cent of NNP in 1984-85 to 19.3 per cent in 1985-86 is expected to register further improvement to 20.2 per cent in 1986-87; the improvement would have been larger but for a sharp fall in the inflow of foreign resources. The data relating to estimated net domestic saving and investment as percentage of NNP are provided in Table 6.

TABLE 6—Estimates of Domestic Saving and Investment (At Current Market Prices)

(In percentages)

Sl. No.	Sector/Item	Fiscal Years 1984-85	1985-86 (Provisional)	1986-87 (Quick Estimates)
1	2	3	4	5
1.	Net household sector's saving to NNP *of which:*	15.6	15.6	17.0*
	Saving in financial assets	9.3	8.7	10.1
2.	Net public sector's saving to NNP	0.8	0.7	0.7*
3.	Net domestic private corporate sector's saving to NNP	0.5	0.5	0.5
4.	Total net domestic saving to NNP (1+2+3)	16.9	16.8	18.2
5.	Inflow of foreign resources to NNP	1.5	2.5	2.0
6.	Aggregate net investment to NNP (4+5)	18.4	19.3	20.2

*In the absence of the CSO's estimate of investment in physical assets by the households and the estimate of saving of the public sector, the rate of the previous year is assumed for this year also, which would undergo a change when CSO releases its Quick Estimates in January 1988.

Note: The net ratios for 1984-85 and 1985-86 differ from those given in the previous year's Annual Report because of the substantial revition in the estimates of National Income and those of saving and investment consequent on the availability of further date.

42. The household sector's saving in the form of financial assets which had declined from 9.3 per cent of NNP in 1984-85 to 8.7 per cent in 1985-86 is estimated to have gone up substantially to 10.1 per cent of NNP in 1986-87 the saving in the form of physical assets which had increased from 6.3 per cent of NNP in 1984-85 to 6.9 per cent in 1985-86 is expected to remain at the same rate in 1986-87. The households' saving in financial assets (gross) is estimated to have gone up from 11.4 per cent of NNP in 1985-86 to 12.6 per cent in 1986-87. However, the financial liabilities of the households have declined from 2.7 per cent of NNP in 1985-86 to 2.5 per cent in 1986-87; it was 2.8 per cent of NNP in 1984-85. The saving in the form of currency which had decreased from 1.5 per cent of NNP in 1984-85 to 1.0 per lent in 1985-86 is estimated to have icreased to 1.3 per cent in 1986-87. The saving in the form of bank deposits, which had declined from 5.0 per cent of NNP in 1984-85 to 4.7 per cent of NNP in 1985-86, increased sharply to 5.4 per cent in 1986-87 mainly on account of larger accretion to commercial banks' deposits. In view of the above, the share of currency and deposits in financial assets (gross) of the household sector increased from 49.8 per cent in 1985-86 to 53.1 per cent in 1986-87. The housholds' claims on Government (mainly small savings) is estimated to have gone up from 1.5 per cent of NNP in 1985-86 to 1.7 per cent in 1986-87; the modest rise was mainly due to substantial outgo on account of repayment of compulsory deposits.

43. The net inflow of foreign resources which had increased substantially from 1.5 per cent of NNP in 1984-85 to 2.5 per cent in 1985-86 is expected to decline to 2.0 per cent in 1986-87. Thus, in spite of a sharp fall in the net inflow of foreign resources, the aggregate net investment as percentage of NNP is estimated to have gone up from 19.3 per cent in 1985-86 to 20.2 per cent in 1986-87.

DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY

Main Features:

44. In view of the large increase in the volume of reserve money and overall liquidity during the previous three years, it was considered essential to pursue a cautious credit policy to avoid a resurgence of inflationary pressures during 1986-87.

45. Reserve requirements continued to remain a major instrument of policy with special emphasis on effective maintenance of the SLR on a daily basis. The 4 per cent band of waiver (in relation to the amount required to be maintained under the statutory liqudity ratio) was gradually reduced and eventually extinguished. Since the growth of overall liquidity in 1986-87, particularly during the last quarter of the financial year, was in excess of what was necessary to support productive activity, various measures were taken to slow down the pace of monetary expansion. Reserve requirements, both SLR and CRR, were raised and the release of impounded cash balances, announced earlier, was partly rescinded. In the event, although the growth of M3 in 1986-87 was higher than in the previous year, these measures moderated the pace of monetary expansion.

46. A major development during the period under review related to the lowering of interest rates. With a view to reducing the cost of money and imparting flexibility to the interest rate policy, selective changes were made in the structure of lending rates and deposit rates and maturity structure of deposits. It was recognised that the inflation rate in recent years has been well below the high inflation rates of 1979-81 in response to which rates of interest had been raised sharply. The real rates of interest, particularly the maximum lending rate of banks, were high and accordingly, the process of a gradual reduction in the maximum lending rate which was undertaken in April 1983 and April 1985 was carried further in April 1987. For the first time, a co-ordinated across-the-board reduction in interest rates on savings instruments was implemented in April, 1987 covering bank deposits, post office deposits, National Savings Certificates, company deposits, debentures, public sector bonds and other schemes. In the case of bank deposits, there was a conscious effort to reduce the maturity applicable to the maximum deposit rate; this is expected to provide an element of flexibility to the banking system in making interest rate changes on deposits and loans in the context of changing economic situation in the country.

47. Other policy changes were in the nature of nationalisation and effective implementation of existing measures. The rationalisation of selective credit controls undertaken in 1985-86 was carried a step further during 1986-87. In the area of public debt management policy, the Reserve Bank introduced (i) a scheme of recycling of 91 days Treasury bills, (ii) an additional fee on early rediscounting of 91 days Treasury bills and (iii) a new instrument, namely, the 182 days Treasury bills.

48. The Working Group on the money Market had made certain recommendations for activiation and development of the money market. While some of the recommendations needed more detailed examination, the Reserve Bank has already taken specific action on a number of recommendations.

49. Details of credit policy measures announced as various points between July 1986 and June 1987 are set out below.

Policy Measures—August, 1986

50. Having regard to the imperatvie need to boost exports, the structure of interest rates on export credit was rationalised in March 1986; further reductions were effected in August 1986. The two revisions together resulted in a significant lowering of interest rates for a large part of export credit, the reductions ranging from 2.5 to 4.5 percentage points.

51. To ensure that the margin between the effective return to banks (after adjusting for interest subsidy) and refinance rate remained unimpaired, the interest rate on Reserve Bank's export credit refinance to scheduled commercial banks was also reduced from 10 per cent to 9 per cent effective from August 1, 1986.

Policy Measure—September, 1986

52. In the context of a continued decline in interest rates abroad, particularly in the United States, interest rates on term deposits under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNR) Scheme were once again revised downwards with effect from September 8, 1986. The interest rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts, were, however, kept unchanged. The structure of deposit rates is set in Table 7.

Table 7—Interest Rates on Non-Resident Deposits

(Per cent per annum)

Sl. No.	Maturity	FCNR Rates Effective from May 5, 1986	FCNR Rates Effective from Sept. 8, 1986	NRE Rates Effective from May 27, 1985
1	2	3	4	5
1.	15 days to 45 days	3.0	3.0	3.0
2.	46 days to 90 days	4.0	4.0	4.0
3.	91 days to less than 6 months	6.5	6.5	6.5
4.	6 months to less than 1 year	8.0	7.5	8.0
5.	1 year and above but below 2 years	8.5	8.0	10.5
6.	2 years and above but below 3 years	9.0	8.5	11.0
7.	3 years and above but below 5 years	10.0*	9.0*	12.0
8.	5 years and above			13.0

*FCMR deposits can be accepted at this rate only for 3 years' maturity.

Policy Measures—October 1986

53. Taking into account the developments in the economy during the first half of 1986-87 and the expected developments in the later half, the busy season credit policy was announced in October 1986 and contained the following measures.

Release of Impounded Cash Balances

54. Scheduled commercial banks were required to maintain an additional cash reserve ration of 10 per cent of the incremental net demand and time liabilities accruing between January 14, 1977 and October 31, 1980. Of the amount of Rs. 1,859 crores so impounded, one-fifth (Rs. 372 crores) was released in two instalments in October 1984 and December 1984; one-third of the remaining balances (Rs. 495 crores) was released in October, 1985. Thus, an amount of Rs. 992 crores had remained impounded with the Reserve Bank. With a view to supplementing banks resources to meet the anticipated increase in credit requirements during the busy season, it was decided to release one-half (Rs. 496 crores) of the remaining amount in two equal instalments on November 22, 1986 and on January 31, 1987. However, only one instalment was a fact released.

Access to the Discretionary Refinance Facility :

55. In order to provide banks with easier access to this facility, scheduled commercial banks (excluding RRBs) were permitted to draw discretionary refinance upto an amount equivalent to 0.5 per cent of the bank's average deposits in 1985-86 for a period not exceeding 14 days without prior sanction by the Reserve Bank of India. Drawing for a period beyond 14 days or in amounts in excess of the limit indicated above continued to require prior sanction of the Reserve Bank.

Export Refinance Limits

56. Deviating from the usual practice it was decided not to bring forward the base year for calculating the export refinance limits of banks, which meant in effect that the banks' access to export refinance facility would be higher by about Rs. 200 crores than what it would have been if the base had been brought forward.

Treasury Bills

57. Two measures bringing about changes in debt management policy relating to treasury bills were also announced.

(i) 182 Days Treasury Bills

58. Following the recommendations of the Committee to Review the Working of the Monetary System to develop treasury bills as a monetary instrument with flexible rates, a scheme for 182 days Treasury bills, initially on a monthly auction basis, without any rediscounting facilities with the Reserve Bank, was introduced and the first auction was held in November 1986. The new instrument was devised essentially to provide an alternative avenue for short term investments and it was expected that over time a wide array of maturities would emerge thereby facilitating the development of a secondary market.

(ii) Additional Early Rediscounting Fee on 91 Days Treasury Bills

59. In order to discourage volatile movements in the treasury bills portfolio of the Reserve Bank an additional fee on early rediscounting of 91 days Treasury bills was introduced in November 1986. The rate of fee per Rs. one lakh face value varied from Rs. 8.11 on the first day to Rs. 50 on the 7th day and remained at that rate till the 14th day. Beyond the 14th day there was no levy of additional early rediscounting fee. This resulted in the effective yield being zero on the first day and rising gradually upto the 14th day. From October 8, 1986, rediscounted treasury bills held with the Reserve Bank with an unexpired maturity period of over 10 days have been reissued to the investors with a rate of return identical to that on fresh bills. The additional early rediscounting fee has been levied both on fresh bills as well as the recycled bills issued by the Reserve Bank.

Advances to Sugar Industry for 1986-87 Crushing Season

60. The scheduled commercial banks were advised that they could sanction for the 1986-87 season (October-September) to sugar units need-based credit limits upto 115 per cent of the maximum amount availed of during the previous season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation.

Policy Measure — January 1987

61. As announced in October 1986, the first instalment of additional cash balances still impounded with the Reserve Bank under the incremental cash reserve ratio amounting to Rs. 248 crores was released on November 22, 1986. The release of the second instalment of Rs. 248 crores was, however, first postponed and subsequently rescinded in early March 1987 in view of the comfortable liquidity position of banks.

Policy Measure — February 1987

62. There was a large increase in the growth of overall liquidity towards the end of December 1986 and January 1987. With a view to immobilising a part of the liquidity of the banking system without hindering the seasonal flow of credit to the productive sectors, it was decided to raise the cash reserve ratio from 9.0 per cent to 9.5 per cent, effective from the fortnight beginning February 28, 1987.

Policy Measures — March 1987

63. The credit policy measures were reviewed in March 1987. It was observed that, as a result of the measures taken in 1985-86 and 1986-87, there was a marked improvement in compliance with the maintenance of SLR by banks. Again, the week-to-week volatility in the banks' holdings of treasury bills was sharply reduced. While the large increase in the reserve money during the past few years had been a cause for concern, the moderate growth of net domestic assets of the Reserve Bank @ indicated that domestically generated primary money creation was kept under control thereby preventing an unduly large secondary expansion. Net domestic assets of the Reserve Bank showed an expansion of Rs. 2,192 crores (9.5 per cent) in 1986-87 (April-March) as against an increase of Rs. 2,293 crores (11.0 per cent) in the previous year. In the light of the monetary and credit developments and expected developments in the real economy, credit policy measures for the first half of 1987-88 were announced on March 31, 1987.

64. In view of the price situation and the liquidity position in the economy, it was considered desirable to work towards containing the growth of overall liquidity in 1987-88 to a rate well below that in 1986-87. Consistent with the assumption of moderation in the growth of M-3, the working estimate for scheduled commercial banks' deposit growth in 1987-88 was put at Rs. 18,500 crores (18.0 per cent) as compared with an increase of Rs. 17,340 crores (20.3 per cent) in 1986-87. The deposit growth during the two halves of the year was expected to be approximately equal. With this growth, banks would not only be able to meet the credit requirements during the first half of 1987-88 but would also be able to build up their liquidity.

65. Since banks were expected to have a comfortable liquidity position in the first half of 1987-88, it was felt desirable that, given the overall objectives the policy adjustments should be put through during that half year itself. In this context the following package of credit policy measures was announced.

Lending and Deposit Rates of Scheduled Commercial Banks

66. As referred to earlier with a view to reducing the cost of money and to impart flexibility to the interest rate policy certain changes in lending and deposit rates were announced. The reduction in lending rates provides relief to many categories of borrowers for whom the interest rates had been raised

@ Reserve Money minus (net foreign exchange assets of RBI+Other Deposits with RBI).

sharply earlier. The lending rates for categories which already had a significant element of concessionality and which had experienced minimal increases in September 1979 and thereafter, remained unaltered. The simultaneous change in deposit rates would help protect the profitability of banks which would have been otherwise affected as a result of the lowering of lending rates.

(i) Lending Rates

67. All lending rates of scheduled commercial banks prescribed at levels above 15 per cent were reduced by one percentage point. While the system of interest rate bands was retained for various categories a fixed rate of 16.5 per cent was prescribed for the maximum slab of 16.5 — 17.5 per cent. The changes made effective from April 1, 1987 are as follows (Table 8) :

Table 8—Scheduled Commercial Banks' Lending Rates

(Per cent per annum)

Sl. No.	Effective upto March 31, 1987	Effective April 1, 1987
1	2	3
1.	Band of 16.50-17.50 and 17.50 (fixed)	16.50 (fixed)
2.	Bands with a ceiling of 16.50	Bands with a ceiling of 15.50
3	16.50 (fixed)	15.50 (fixed)

Themaximum effective interest rate on the discounting of bills of exchange was reduced to 15.5 per cent i.e. one percentage point below the new maximum lending rate. This measure would help to promote the bill culture and improve the payments system.

(ii) Deposit Rates

68. The maximum deposit rate was reduced from 11 per cent to 10 per cent with effect from April 1, 1987 and this maximum rate was made applicable to deposits with a maturity of two years and above. Existing deposits however, would continue to be governed till maturity by the rates effective upto March 31, 1987. The maturity structure of deposits had undergone a structural transformation over the past 15 years. In 1969, only 27 per cent of term deposits were at maturities of over 3 years while the comparable proportion in 1982 was 73 per cent. The sharp rise of deposits of longer maturities in the more recent period resulted in a rigidity in the interest structure in that banks found it difficult to adjust to a general downward movement in interest rates as they were committed to pay higher rates on the longer maturities. The shortening of the maturity structure, with the maximum deposit rate being paid on 2 years deposits instead of 5 years deposits hitherto, would enable easier adjustment of bank interest rates in response to changing circumstances. The revised structure of deposit rates (excluding FCNR and NRE accounts) is set out in Table 9.

Table 9—Scheduled Commercial Banks' Interest Rates on Deposits (Excluding FCNR/NRE)

(Per cent per annum)

Sl. No.	Range	Effective upto March 31, 1987	Effective April 1, 1987
1	2	3	4
1.	Current Accounts	Nil	Nil
2.	Savings Accounts	5.0	5.0
3.	Term Deposits		
	(a) 15 days to 45 days	3.0	3.0
	(b) 46 days to 90 days	4.0	4.0
	(c) 91 days and above but less 6 months	6.5	6.5
	(d) 6 months and above but less than 1 year	8.0	8.0
	(e) 1 year and above but less than 2 years	8.5	9.0
	(f) 2 years and above but less than 3 years	9.0	10.0*
	(g) 3 years and above but less than 5 years	10.0	
	(h) 5 years and above	11.0	

*Rate applicable to 2 years and above.

69. The existing deposit rate structure and maturity pattern of FCNR Accounts remained unchanged (these rates were already delinked from domestic deposit rates and a separate structure of rates was prescribed for FCNR deposits). In the case of NRE deposit rates of one year and over their link with the domestic deposit rates was severed and an independent structure of interest rates and maturities was specified effective April 1, 1987. The specified rates and maturities for NRE deposits were, however, not different from those obtaining prior to March, 31, 1987.

Statutory Liquidity Ratio (SLR)

70. From the fortnight beginning April 25, 1987, the SLR was raised from 37 per cent to 37.5 per cent of net demand and time liabilities. The Food Corporation of India had received Rs. 1,200 crores in 1986-87 as a soft loan from the Government of India, of which, Rs. 634 crores were released on March 31, 1987 which the banks received by way of return of food credit. The backlog of subsidies to the extent of Rs. 550 crores was paid to the FCI in the months of April and May 1987. Moreover a system of monthly "on account" payment of subsidy was introduced. As such, the increase in the SLR, effective from April 25, 1987, did not pose a problem to banks.

Cash Reserve Requirements on Foreign Currency (Non-Resident) Accounts

71. During the last two years the FCNR deposit rates were progressively brought down to levels somewhat lower than those on domestic bank deposits. As a measure of reducing overall liquidity in the banking system, the cash reseve in respect of FCNR deposit liabilities was raised from 3 per cent to 9.5 per cent effective from May 23, 1987. The FCNR deposit liabilities were however, exempt as before from the 10 per cent incremental cash reserve ratio introduced in November 1983.

Selective Credit Controls

72. During the last two years a major rationalisation of the selective credit controls was undertaken and where such controls were no longer needed these were abolished. Again in the case of items where the commodity balances and developments in prices showed favourable responses, the control were made less stringent. The following changes were made in the selective credit controls with effect from April 1, 1987.

(i) Level of Credit Ceilings

73. For commodities where there was a stipulation on the level of credit based on the three-year period 1981-82, 1982-83 and 1983-84 (November-October) the base was brought forward by one year to 1982-83, 1983-84 and 1984-85.

(ii) Margins

74. The minimum margins in respect of 'other foodgrains', pulses, released stocks of sugar, gur and khandsari were reduced across-the board by 15 percentage points. The minimum margins for oilseeds ,vegetable oils and unreleased stocks of sugar were kept unchanged. The new structure of minimum margins is set out in Table 10.

(iii) Credit to Millers/Traders

75. In the context of the large rabi 1987 wheat crop, banks were advised to consider freer flow of credit to wheat millers and traders than hitherto, subject, however, to the observance of normal credit discipline.

Access to Discretionary Refinance

76. In respect of banks which were not members of the food consortium and those with a large share in FCNR deposits, who might face problems of adjustment to the March 1987 measures, it was clarified by the Reserve Bank that requests for additional discretionary refinance for very short periods would be considered on merits.

Graduated Interest Rates on Cash Balances with the Reserve Bank

77. The scheme of graduated interest rates on eligible balances for shortfalls in the maintenance of cash reserve

ratio came into effect from January 1, 1982. To give some further relief to banks for small shortfalls in CRR, the schedule of graduated interest rates was revised. The earlier and the revised schedules are set out in Table 11.

Table 10—Minimum Margins on Bank Advances Against Stocks of Commodities Covered under Selective Credit Controls

(Effective April 1, 1987)

(Percentage)

Sl. No.	Commodities	Against stocks		Against warehouse receipts
		Processing units/mills	Others	
1	2	3	4	5
1.	"Other foodgrains"	30	45	30
2.	Pulses	30	45	30
3.	Oilseeds (groundnut, rapeseed/mustard, linseed, castorseed and all imported oilseeds)	30	45	30
4.	Vegetable oils (groundnut oil, rapeseed/mustard oil, linseed castor, oil, vanaspati and all imported oils)	30*	60	45
5.	Sugar			
	(a) Buffer	0	--	—
	(b) Unreleased stocks	17.5	—	-
	(c) Released	60	60	45
6.	Gur and Khandsari	30	60	45

*Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers

Table 11—Shortfall in Maintenance of Cash Reserve Ratio—Schedule of Graduated Interest Rates on Cash Balances

(Effective upto March 31, 1987)		(Effective April 1, 1987)	
Shortfall during a fortnight as percentage of the absolute amount of CRR required to be maintained (upto and inclusive of)	Rate of interest payable on the amount above the statutory minimum of 3 per cent actually maintained (per cent per annum)	Shortfall during a fortnight as percentage of the absolute amount of CRR required to be maintained (upto and inclusive of)	Rate of interest payable on the amount above the statutory minimum of 3 per cent actually maintained (per cent per annum)
0.0	10.50	0.0	10.50
0.5	10.00	0.5	10.25
1.0	8.75	1.0	10.00
1.5	5.25	1.5	9.50
2.0	2.50	2.0	8.75
		2.5	7.75
3.0	0.50	3.0	6.50
Over 3.0	0.00	3.5	5.00
		4.0	3.00
		4.5	1.25
		5.0	0.50
		Over 5.0	0.00

The Working Group onthe Money Market

78. The Working Group on the Money Market submitted its Report in January 1987. As indicated earlier, the Reserve Bank after wide ranging consultations announced the following decisions/measures :

Call Money Interest Rates and Participants

79. For the time being, the structure of the call money market in terms of the administered interest rates and the participants in the market would remain unchanged.

Lowering of the Bills Discount Rate

80. Interest rates prescribed for short-term advances which were uniform for various categories of borrowers on their cash credits, overdrafts and bills were altered. In the light of the reduction in the maximum lending rate from 17.5 per cent to 16.5 per cent, effective April 1, 1987, the interest rate on bills for such category of borrowers was prescribed at a rate, one percentage point below the new maximum lending rate. Thus, effective April 1 1987, banks were required to fix the bill discounting rate for such borrowers at a level equivalent to an effective interest rate of 15.5 per cent which was, in effect, a reduction of 2 percentage points over the then existing level.

The Working Group on the Money Market

81. With effect from April 1, 1987, the ceiling on the rediscount rate was raised from 11.5 per cent per annum to 12.5 per cent per annum. Even though the spread between the discount and rediscount rates for bills has been reduced to a little over 2.5 percentage points at their ceiling levels, this measure is expected to attract additional funds into the rediscount market and also to encourage the Life Insurance Corporation and the Unit Trust of India to progressively move away from the call market to the rediscount market.

Participants in the Rediscount Market

82. The Reserve Bank would, for the present, continue to control the entry to the rediscount market for institutions on a case-by-case basis although access to the rediscount market would be less restrictive than hitherto.

Measures to Promote Bill Financing

83. In addition to lowering the discount rate (to make the bills system attractive to borrowers) and increasing the rediscount rate (to augment the supply of funds in the rediscount market), the following measures were taken to promote bill financing :

(ii) Proportion of Receivables to be Financed Through Bills

84. In the case of all parties subject to the Credit Authorisation Scheme (both in the private sector and public sector), while determining the cash credit/overdraft facilities against receivables, effective April 1, 1988, only 75 per cent of the eligible receivables would be taken into account for financing

subject to the normal margins prescribed by banks. The remaining credit requirement could be financed through demand/usance bills. In the case of parties where the proportion of receivables financing was already less than 75 per cent the banks were advised not to permit an increase in the proportion of receivables financing under the cash credit/ overdraft facilities.

(ii) Discretion to Banks to Sanction Ad-hoc Bill Limits

85. In April 1986, the discretionary power of banks to sanction to all parties subject to the Credit Authorisation Scheme, additional limits temporarily for periods not exceeding 3 months upto 10 per cent of the existing working capital limit was enhanced from an overall ceiling of Rs. 75 lakhs to Rs. 2 crores. As an incentive to use the bill facility in the event of an increase in the scale of operations, in addition to the present powers to sanction additional limits temporarily, a separate additional inland bill limit is permitted to be provided by banks for a period not exceding 3 months upto an amount equivalent to 10 per cent of the existing bill limit subject to a ceiling of Rs. one crore.

(iii) Stipulation on Bill Acceptances to Credit Purchases

86. All parties subject to the Credit Authorisation Scheme (both in the private sector and public sector) would be required to attain a ratio of ill acceptances to credit purchases of 25 per cent by April 1, 1988. In cases where this ratio was below the stipulated level, banks would be required to advise their constituents to progressively move towards the attainment of the stipulated ratio. In the case parties that have already exceeded the stipulated ratio, slippages would not be permitted and in fact the endeavour would be to work towards an increase in the ratio of bill acceptances to credit purchases. Adherence to the stipulated ratio would be one of the key prerequisites in considering whether an account is being operated satisfactorily and after a run-in period, specific incentives/disincentives would be prescribed.

Introduction of a '182 days Treasury bill' Refinance Facility

87. A '182 days Treasury bill' refinance facility was introduced from April 1, 1987 under which scheduled commercial banks are provided refinance by the Reserve Bank of India equivalent to 50 per cent of a bank's holdings of 182 days Treasury bills, at an interest rate of 10 per cent per annum.

Setting up of a Finance House

88. The Reserve Bank has, in principle, decided to set up a Finance House to deal in short-term money market instruments with the primary object of imparting liquidity to these instruments. The Finance House would be se tup jointly with public sector banks and financial institutions.

89. Thus the credit policy measures announced on the eve of the slack season of 1987 covered a wide area and some of the measures were directed towards introducing certain basic structural changes.

Policy Measures—May 1987—Interest Rates on FCNR Deposits

90. In the wake of rise in interest rates in the international currency markets particularly in dollars, the Reserve Bank of India raised the interest rates on deposits held in FCNR accounts with banks with effect from May 25, 1987. The maximum rate payable on term deposits for 3 years was raised from 9 per cent to 10.5 per cent. The rate for deposits of 2 years and above but less than 3 years was raised from 8.5 per cent to 10 per cent, that for 1 year and above but less than 2 years from 8 per cent to 9.5 per cent and that for 6 months and above but less than 1 year from 7.5 per cent to 8 per cent.

TRENDS IN MONEY CREDIT AND PRICES

Money Supply

91. Monetary expansion in terms of broad money (M_3) was higher at 18.5 per cent during 1986-87 as against 16.1 per cent in 1985-86 (Rs. 21,918 crores as against Rs. 16,381 crores). The average growth rate during the last three years 1983-84 to 1985-86 was about 17.6 per cent which might be considered to be high in relation to the estimated growth of GNP at around 5 per cent per annum (Table 12). The growth in M_3 in 1986-87 at 17.4 per cent on the basis of average of last Fridays of months was marginally higher by 0.3 percentage point than that of the previous year.

92. Money supply with the public (M) recorded a sharper rise of Rs. 7,397 crores (17.0 per cent) on a point-to-point basis during 1986-87 as compared with that of Rs. 3,950 crores (10.0 per cent) in the previous year (Table 12). However, in terms of average of last Fridays of months, the expansion in M_1 at 14.5 per cent was higher by 0.6 percentage point.

93. Of the components of M_3, larger increases were recorded both in currency with the public and deposit money. The expansion in currency with the public at Rs. 3,371 crores or 13.4 per cent was larger by 2.4 percentage points than that in 1985-86. Aggregate deposits with banks rose by Rs. 18,446 crores (19.9 per cent) as against Rs. 14,229 crores (18.1 per cent) in the previous year. The increase in demand deposits with banks by Rs. 3,925 crores (21.6 per cent) was more than twice the rise of Rs. 1,798 crores (11.0 per cent) in the preceding year. Time deposits with banks also showed a larger rise of Rs. 14,521 crores than that of Rs. 12,431 crores in 1985-86; however the growth rate at 19.4 per cent was lower by 0.6 percentage point.

94. The incremental ratio of currency to M_3 at 0.15 did not show any variation over the previous year. However the year-end ratio of currency to M_3 continued to decline from 0.23 in 1983-84 to 0.20 in 1986-87 reflecting the spread of banking habit in the country. The incremental ratio of demand deposits to M_3 in 1986-87 showed a sharp increase from 0.11 to 0.18 (Table 13).

95. Of the factors which contributed to the expansion in M_3 during 1986-87, net bank credit to Government increased by Rs. 12,825 crores (21.9 per cent) which was larger than the rise of Rs. 9,572 crores (19.6 per cent) in the previous year. The increase was largely due to a spurt in other banks' credit to Government of Rs. 5,958 crores (30.4 per cent) as against only Rs. 445 crores (2.3 per cent) in 1985-86. Net RBI credit to Government recorded a lower rise of Rs. 6,867 crores (17.7 per cent) as compared with Rs. 9,127 crores (30.7 per cent) in the previous year. Apart from the fact that Government securities have been made more attractive through increase in coupon rates, stricter monitoring by RBI of SLR compliance on a daily basis by banks explains the sharp rise in banks' holdings of Government securities during 1986-87

96. Bank credit to commercial sector expanded by Rs. 10,878 crores (13.3 per cent) during 1986-87 as compared with a larger rise of Rs. 11,051 crores (15.6 per cent in the previous year. This was mainly due to a smaller expansion in other banks' credit to commercial sector by Rs. 10,515 crores (13.3 per cent) as against Rs. 10,750 crores (15.8 per cent) in 1985-86, following an absolute reduction in food credit as explained in a subsequent paragraph.

97. Net foreign exchange assets of the banking sector rose by Rs. 1,251 crores as compared with Rs. 195 crores in the preceding year.

98. During the first quarter of the fiscal year 1987-88, the growth rate in M_3 was lower both in absolute and percentage terms at Rs. 3,518 crores (4.7 per cent) as compared with Rs. 8,549 crores (7.2 per cent) in the same period of the previous year. The expansion in M_1 was also lower at

Table 12—Variations in Money Stock (M3)

(Rs. crores)

	Variations during*							
	1985-86		1986-87@		1986-87 (April-June)		1987-88@ (April-June)	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. M_3 (a+b+c)	+16381	+16.1	+21918	+18.5	+8549	+7.2	+6548	+4.7
(a) Currency with the public	+2504	+11.0	+3371	+13.4	+1490	+5.9	+1939	+6.8
(b) Aggregate deposits with banks (i+ii)	+14229	+18.1	+18446	+19.9	+7038	+7.6	+4695	+4.2
(i) Demand deposits	+1798	+11.0	+3925	+21.6	+1694	+9.3	+210	+1.0
(ii) Time deposits	+12431	+20.0	+14521	+19.4	+5344	+7.2	+4485	+5.0
(c) "Other" deposits with RBI	—352	—58.4	+101	+40.2	+21	+8.4	—86	—24.4
II. M1 (a+b)(i)+c)	+3950	+10.0	+7397	+17.0	+3205	+7.4	+2063	+4.0
III. Sources of change in Money Stock (M3) (1+2+3+4—5)								
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	+9572	+19.6	+12825	+21.9	+6773	+11.6	+6080	+8.5
A. RBI's net credit to Government (i—ii)	+9127	+30.7	+6867	+17.7	+4880	+12.5	+4874	+10.6
(i) Claims on Government	+3881	+11.0	+6757	+17.3	+4767	+12.2	+5875	+10.6
(ii) Government deposits with RBI	—5246	—96.7	—110	—61.5	—113	—63.1	+1	+1.4
B. Other banks' credit to Government	+445	+2.3	+5958	+30.4	+1893	+9.6	+1206	+4.7
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	+11051	+15.6	+10878	+13.3	+1814	+2.2	+803	+0.9
A. RBI's credit to commercial sector**	+301	+10.9	+363	+11.8	— 17	— 0.6	—59	—1.7
B. Other banks' credit to commercial sector	+10750	+15.8	+10515	+13.3	+1831	+2.3	+862	+1.0
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)	+195	+5.9	+1251	+36.0	+274	+7.9	— 223	—4.7
A. RBI's net foreign exchan ge assets	+299	+9.8	+1251	+37.4	+274	+8.2	—223	—4.9
B. Other banks' net foreign exchange assets	—104	—44.3	...	—	—	—	—	—
4. Government's Currency Liabilities to the Public	+163	+21.0	+201	+21.4	+74	+7.9	...	—
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	+4600	+21.1	+3237	+12.2	+386	+1.5	+112	+0.4
A. Net non-monetary liabilities of RBI	+2991	+38.9	+2183	+20.4	+557	+5.2	—253	—2.0
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)	+1609	+11.4	+1054	+6.7	—171	—1.1	+365	+2.2

*Based on last Friday of March/month data.

**Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

@Provisional.

Note : Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

Table 13—Monetary Ratios

Year	Year-End Ratios					Incrementa Ratios				
	C	C	AD	DD	TD	C	C	AD	DD	TD
	M_1	M_3	M_3	M_3	M_3	M_3	M_3	M_3	M_3	M^3
1982-83	0.58	0.23	0.77	0.16	0.61	0.57	0.21	0.79	0.15	0.64
1983-84	0.59	0.23	0.77	0.15	0.62	0.64	0.22	0.77	0.12	0.65
1984-85	0.57	0.22	0.77	0.16	0.61	0.47	0.19	0.79	0.20	0.59
1985-86	0.58	0.21	0.79	0.16	0.63	0.63	0.15	0.87	0.11	0.76
1986-87	0.56	0.20	0.79	0.15	0.64	0.46	0.15	0.84	0.18	0.66

C : Currency

AD : Aggregate Deposits

DD : Demand Deposits

TD : Time Deposits

Rs. 2,063 crores (4.0 per cent) than that of Rs. 3,205 crores (7.4 per cent). Of the components, while currency with the public recorded an acceleration in its growth rate, demand and time deposits with banks showed a deceleration with demand deposits facing a sharp fall in its rate of accrual. Source-wise, net bank credit to Government recorded a lower rise than that in the same period of the previous year. The increase in bank credit to commercial sector was also sizeably lower; net foreign exchange assets of the banking sector declined in contrast to arisen in the corresponding period of the previous year.

Reserve Money

99. Reserve money growth rate during 1986-87 was lower at 18.2 per cent (Rs. 6,904 crores) as compared with 20.3 per cent (Rs. 6,381 crores) in the previous year. Considered terms of average of months also, the growth rate of reserve money at 17.3 per cent was lower by 0.1 percentage point over that in 1985-86. Of the components, currency with the public showed a faster expansion of 13 4 per cent in 1986-87 as against 11.0 per cent in 1985-86 and accounted for a major share in the incremental reserve money (Table 14). Bankers' deposits with RBI recorded a lower rise as compared with the previous year. The slower growth in reserve money during the year was on account of a lower increase in net RBI credit to Government than in 1985-86. It is to be noted that the RBI credit to the Government and the reserve money have grown at a lower rate in 1986-87 than in 1985-86, although the Government's budgetary deficit in 1986-87 was larger than in 1985-86. RBI was able to effect net sales of securities during the year unlike in the earlier years (taking into account cash subscriptions to fresh loans).

100. During the first quarter of the fiscal year 1987-88, the reserve money growth was lower at 9.8 per cent (Rs. 4,395 crores) than that of 10.4 per cent (Rs. 3,919 crores) in the same period of 1986-87. The deceleration in reserve money growth during the quarter was due to a lower growth in net RBI credit to Government and a decline in its net foreign exchange assets.

Banking Variables

101. The trends in major banking variables relating to scheduled commercial banks during the financial year 1986-87 indicate substantial increases in deposits and investments accompanied by a slow down in credit expansion (Table 15). During the year, accretion to aggregate deposits in absolute

Table 14—Reserve Money Variations—Components and Sources

(Rs. crores)

	Variations during			
	1985-86	1986-87*	1986-87 (April-June)	1987-88* (April-June)
	1	2	3	4
RESERVE MONEY (1+2+3+4)	+6381	+6904	+3919	+4395
	(+20.3)	(+18.2)	(+10.4)	(+9.8)
1. Currency with the public	+2504	+3371	+1490	+1939
	(+11.0)	(+13.4)	(+5.9)	(—6.8)
2. "Other" deposits with RBI	—352	+101	+21	— 86
	(—58.4)	(+40.2)	(+8.4)	(—24.4)
3. Cash with banks	+89	+73	+438	+310
	(+7.4)	(+5.7)	(+33.9)	(+22.7)
4. Bankers' deposits with RBI	+4140	+3359	+1970	+2232
	(+59.1)	(+30.1)	(+17.7)	(+15.4)
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3+4+5—6)				
1. Net RBI Credit to Government	+9127	+6887	+4880	+4874
	(+30.7)	(+17.7)	(+12.5)	(+10.6)
2. RBI's claims on commercial and co-operative banks	—519	+405	—734	—449
	(— 18.5)	(+17.7)	(—32.1)	(—16.7)
3. RBI's credit to commercial sector	+301	+363	—17	+59
	(+10.9)	(+11.8)	(—0.6)	(—1.7)
4. Net foreign exchange assets of RBI	+299	+1251	+274	—223
	(+9.8)	(+37.4)	(+8.2)	(—4.9)
5. Government's currency liabilities to the public	+163	+201	+74	—
	(+21.0)	(+21.4)	(+7.9)	—
6. Net non-monetary liabilities of RBI	+2991	+2183	+557	—253
	(+38.9)	(+20.4)	(+5.2)	—(2.0)

*Provisional

@Including NABARD

Notes : 1. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

2. Figures within bracket represent percentage variations.

terms was Rs. 17,340 crores which substantially surpassed the previou year's level of Rs. 13,160 crores; the rate of growth of deposits was also higher at 20.3 per cent than that of 18.2 per cent in 1985-86.

Table 15—Variations in Important Banking Indicators
(Scheduled Commercial Banks)

(Rs. crores)

Sl. No.	Items	Amount outstanding as on			Variations during the financial year		Quarterly variations	
		March 28, 1986	March 27, 1987@	June 26, 1987@	1985-86	1986-87	1986 (April-June)	1987 (April-June)@
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Total Demand and Time liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI/NABARD)	97024	114914	120506	+15139	+17890	+6377	+5592
2.	Aggregate Deposits (a+b)	85404	102744	107345	+13160 (+18.2)	+17340 (+20.3)	+6424 (+7.5)	+4601 (+4.5)
	(a) Demand Deposits	15612	19234	19383	+1481 (+10.5)	+3622 (+23.2)	+1381 (+8.8)	+149 (+0.8)
	(b) Time Deposits	69792	83510	87962	+11679 (+20.1)	+13718 (+19.7)	+5043 (+7.2)	+4452 (+5.3)
3.	Borrowings from RBI	954	1293	1136	—604	+339	—410	—157
4.	Bank Credit (a+b)	56067	63236	63753	+7114 (+14.3)	+7169 (+12.8)	+1162 (+2.1)	+517 (+0.8)
	(a) Food Credit	5535	5131	4957	—130	—404	+876	—174
	(b) Non-food Credit	50532	58105	58796	+7254 (+16.7)	+7573 (+15.0)	+286 (+0.6)	+691 (+1.2)
5.	Investment (a+b)	30553	38634	40387	+2415 (+8.6)	+8081 (+26.4)	+2526 (+8.3)	+1753 (+4.5)
	(a) Government Securities	19044	24897	26093	+347 (+1.9)	+5853 (+30.7)	+1852 (+9.7)	+1196 (+4.8)
	(b) Other approved securities	11509	13737	14294	+2068 (+21.9)	+2228 (+19.4)	+674 (+5.9)	+557 (+4.1)
6.	Cash in hand	1127	1172	1481	+83	+45	+388	+309
7.	Balances with RBI	11053	14380	16572	+4169 (+60.6)	+3327 (+30.1)	+1887 (+17.1)	+2192 (+15.2)
8.	Credit Deposit Ratio (%)	65.6	61.5	59.4				
9.	Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	59.2	56.6	54.8				

@ Partially revised.

Note : Figures in brackets are percentage variations.

102. Component-wise, demand deposits registered a sharp increase of 23.2 per cent as compared with 10.5 per cent in 1985-86; rate of growth of time deposits, on the other hand, was lower at 19.7 per cent as compared with 20.1 per cent in the preceding year. Notably, the growth in demand deposits has been following a see-saw path with alternate high and low growth rates. However, these fluctuations narrow down considerably, if data on the basis fo average of monthly outstandings are considered (Table 16).

Table 16—Growth in Demand Deposits (in percentages)

Demand Deposits	Percentage growth rates during					
	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
On point to point bases	7.5	19.1	13.3	24.9	10.5	23.2
On twelve monthly average basis	19.3	11.6	14.1	17.0	18.9	17.7

103. The expansion in bank credit of Rs. 7,169 crores was higher in absolute terms as compared with that of Rs. 7,114 crores during 1985-86; the growth rate, however, at 12.8 per cent was lower by 1.5 percentage points. Food credit registered a larger decline of Rs. 404 crores in 1986-87 as compared with the decline of Rs. 130 crores in the previous year. This decline in food credit was due to the Centre's decision to make available soft loans to FCI to enable the latter to repay part of the outstanding food credit. Non-food credit, however, recorded a larger expansion of Rs. 7,573 crores as compared with that of Rs. 7,244 crores in 1985-86. Non-food non-petroleum bank credit also showed a larger rise of Rs. 7,827 cores in 1986-87 as against Rs. 6,943 crores in the previous year.

104. Banks' investments registered a sharp jump of Rs. 8,081 crores (26.4 per cent) in 1986-87 as compared with Rs. 2,415 crores (8.6 per cent) in 1985-86. The substantial build-up in investments, particularly in Government securities, reflects partly the change in yield rates of Government securities and partly better compliance of statutory requirements by banks consequent upon the imposition of penal provisions on SLR defaults.

105. Bank's cash in hand and their balances with the Reserve Bank recorded a lower order of increase of Rs. 3,372 crores as compared with that of Rs. 4,252 crores in 1985-86. Banks borrowing from the Reserve Bank increased by Rs. 339 crores in contrast to a decline of Rs. 604 crores in the preceding year.

106. During the first quarter of the financial year 1987-88 (i.e. March 27, 1987 to June 26, 1987), the operations of scheduled commercial banks were on a low key with a deceleration in the pace of growth of major banking variables like aggregate deposits, bank credit and banks' investment Deposits, growth at Rs. 4,601 crores (4.5 per cent) was lower both in absolute and percentage terms as compared with that in the corresponding quarter of 1986-87 (Rs. 6,424 crores or 7.5 per cent). The expansion in bank credit at Rs. 517 cror es (0.8 per cent) was also substantially lower than the expansion of Rs. 1,162 crores (2.1 per cent) in the first quarter of 1986-87, which was entirely attributable to the decline in food credit to the tune of Rs. 174 crores in contrast to a rise of Rs. 876 crores during April-June 1986. Non-food credit, on the other hand, increased by Rs. 691 crores as against Rs. 286 crores in the comparable quarter of the previous year. Additions to banks' investments were sizeably lower at Rs. 1,753 crores (4.5 per cent) as compared with Rs. 2,526 crores (8.3 per cent) during the first quarter of 1986-87.

@ Data relate to 0 scheduled commercial banks (see Table 17).

Credit-Deposit Ratio :

107. Credit-deposit ratio of scheduled commercial banks at the aggregate level has tended to decline over the recent years due to policy decisions governing reserve requirements. The credit deposit ratio has declined from 65.5 per cent at end-June 1981 to 62.3 per cent at end-June 1986 and further to 59.4 per cent at end-June 1987. The scheduled commercial banks were given a target of 60 per cent for credit-deposit ratio to be achieved by March 1979 in rural and semi-urban branches and the same has been achieved for rural branches though not for semi-urban branches.

108. Region-wise data show that there are significant inter-regional differences with respect to credit-deposit ratio of scheduled commercial banks (including RRBs). As per data for the end of June 1985, it ranged from 42.2 per cent for the north-eastern region to 81.5 per cent for the western region. Board on the utilisation of credit, the corresponding rations were 65.9 per cent and 80.3 per cent. If, however, besides credit utilised, investments in State-level securities and bonds were taken into account, the resultant ratio undergoes significant changes in relation to certain regions. Based on the credit sanction alone, the credit-deposit ratios for end June 1985 stood at 42.2 per cent for the north-eastern region, at 53.8 per cent for the eastern region and at 48.5 per cent for the central region. On the other hand, when credit utilized and investments are considered, the credit plus investment to deposit ratios for the same regions worked out to 89.8 per cent, 66.8 per cent, and 63.8 per cent respectively. In the other regions except in the south, the increase is not as pronounced. While credit-deposit ratio as a statistical indicator has its usese it needs to be used with care. In States with a large deposit base, even a low credit-deposit ratio can ensure a higher per capita credit availability while in States with small deposit base evern a high ratio may not result in high per capita credit. What is, therefore, important is to ensure that the credit needs of a State are adequately met for the assessment of which credit-deposit ratio is only one indicator.

Sectoral Deployment of Credit :

109. Data on sectoral deployment of credit@ indicate that during 1986-87 (April-March), the expansion in gross bank credit amounted to Rs. 7,330 crores (13.3 per cent) as compared with an increase of Rs. 7,257 crores (15.1 per cent) during the previous year. Bank credit extended for food procurement recorded a decline of Rs. 404 crores as compared with a smaller decline of Rs. 130 crores in the previous year. Non-food gross bank credit expansion amounted to Rs. 7,734 crores (15.6 per cent) as compared with Rs. 7,387 crores (17.5 per cent) during 1985-86 (Table 17).

Table 17—Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors @ (as on the last Friday)

(Rs. crores)

Sectors	Outstanding as on			Variations (Financial Year)	
	March 1985	March 1986	March 1987	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1. Gross Bank Credit (1+2)	47956	55213	62543	+7257	+7330
1. Public Food Procurement Credit	5665	5535	5131	—130	—404
2. Non-food Gross Bank Credit	42291	49678	57412	+7387	+7734
				(100.0)	(100.0)
A. Priority Sectors	18409	21566	25059	+3157	+3493
				(42.7)	(45.2)
(i) Agriculture	7660	9058	10588	+1398	+1530
				(18.9)	(19.7)
(ii) Small-Scale Industries	6612	7816	9103	+1204	+1287
				(16.3)	(16.6)
(iii) Other Priority Sectors	4137	4692	5368	+555	+676
				(7.5)	(8.7)

1	2	3	4	5	6
B. Industry (Medium & Large)	15939	19170	22187	+3231 (43.7)	+3017 (39.0)
C. Wholesale Trade (Other than food procurement)	2649	3066	3072	+417 (5.7)	+6 (0.1)
(i) Cotton Corporation of India	135	160	109	+25 (0.3)	—51 (0.7)
(ii) Food Corporation of India (fertiliser distribution)	166	141	149	—25 (+0.3)	+8 (0.1)
(iii) Jute Corporation of India	116	127	198	+11 (0.1)	+71 (0.9)
(iv) Other Trade	2232	2638	2616	+406 (5.5)	—22 (—0.3)
D. Other Sectors	5294	5876	7094	+582 (7.9)	+1218 (15.7)
II. Export Credit (included under item 2)	2335	2409	3143	+74	+734

Note: 1. Date relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further, these gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institutions and participation certificates.

2. Figures in brackets are proportions to incremental non-food credit.

110. Bank credit to priority sectors recorded a larger expansion of Rs. 3,493 crores during 1986-87 as against Rs. 3,157 crores in 1985-86. At the end of March 1987, priority sector advances constituted 42.3 per cent of net bank credit as against 40.8 per cent a year ago.

111. The share of agriculture and small-scale industries in total increase in advances to priority sectors amounted to Rs. 1,530 crores (43.8 per cent) and Rs. 1,287 crores (36.8 per cent), respectively, as compared with Rs. 1,398 crores (44.3 per cent) and Rs. 1,204 crores (38.1 per cent), respectively, in the previous year. As on the last Friday of March 1987, the amount of outstanding advances to agriculture stood at Rs. 10,588 crores as compared with Rs. 9,058 crores a year ago; its proportion to total priority sector advances increased fractionally to 42.3 per cent over the year. Advances to small-scale industries at Rs. 9,103 crores accounted for 36.3 per cent of the total advances to priority sectors, close to the 36.2 per cent ratio a year ago. Advances to other priority sectors which include small transport operators, self-employed persons, rural artisans, etc. rose to Rs. 5,368 crores and these advances formed 21.4 per cent of total priority sector advances in March 1987 as against Rs. 4,692 crores or 21.8 per cent in March 1986.

112. During 1986-87, advances to medium and large industry increased by Rs. 3,017 crores (15.7 per cent) to Rs. 22,187 crores as compared with an increase of Rs. 3,231 crores (20.3 per cent) to Rs. 19,170 crores during the previous year; excluding petroleum, the rise was Rs. 3,271 crores (17.4 per cent) and Rs. 2,930 crores (18.5 per cent), respectively.

113. The industry-wise (inclusive of small-scale industry) distribution of bank credit is presented in Table 18. Industries which accounted for a major part of the growth in credit during 1986-87 were the engineering group (Rs. 1,177 crores), chemicals group (Rs. 509 crores), iron and steel (Rs. 363 crores), cotton textiles (Rs. 290 crores), other textiles (Rs. 172 crores) and other industries (Rs. 1,267 crores). Substantial declines were reported in respect of petroleum (Rs. 254 crores) and SAFAUNS (Rs. 44 crores).

114. Advances to wholesale trade (other than food procurement) recorded a marginal rise of Rs. 6 crores during 1986-87; these had increased by Rs. 417 crores in 1985-86.

115. Credit to 'Other Sectors' which represent residual sectors and include advances to financial institutions, hire purchase agencies leasing companies, personal loans, etc. registered a larger increase of Rs. 1,218 crores as compared with a rise of Rs. 582 crores in the previous year.

116. The policy changes relating to the Reserve Bank accommodation to scheduled commercial banks have been discussed earlier while dealing with developments in credit policy.

117. The developments in the utilisation of various refinance facilities are set out below :

Food Credit Refinance

118. The outstanding level of food credit as at the end of March 1986, being below the threshold level of Rs. 5,800 crores, banks were not eligible for food refinance. As on the last reporting Friday of June 1986, banks' food credit refinance limits amounted to Rs. 736 crores of which the outstanding was Rs. 34 crores. The peak level of Rs. 866 crores of food credit refinance limits during the financial year 1986-87 was reached on July 18, 1986, whereas outstandings as on that date amounted to Rs. 281 crores (32.4 per cent utilisation ratio).

Export Credit Refinance

119. The banks' export credit refinance limits reached a peak of Rs. 894 crores on March 27, 1987 whereas the peak outstanding amount during the year was Rs. 778 crores on the same date when 87.0 per cent of limits was utilised. As on June 19, 1987 the limits under this facility amounted to Rs. 1,372 crores of which Rs. 343 crores or 25.0 per cent was utilised.

Stand-by Refinance Limits

120. The amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks as on the last reporting Friday of March 1986 was Rs. 50 crores of which Rs. 40 crores or 80.0 per cent was utilised. The maximum amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks during 1986-87 was Rs. 40 crores as on April 25, 1986 which remained entirely unutilised. As on March 27, 1987 the limits under this facility amouetnd to Rs. 14 crores which were fully utilised, whereas on June 19, 1987 the limits of Rs. 50 crores remained unutilised.

Discretionary Refinance Limits

121. With a view to providing easier access to the discretionary re-finance facility, effective from October 30, 1986, all licensed scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) were permitted to draw discretionary relinance without prior sanction by the Reserve Bank upto an amount equivalent to 0.5 per cent of a bank's average deposits in

Table 18—Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit @(As on the last Friday)

(Rs. crores)

Industry	Outstandings as on			Variations (Financial Year)	
	March 1985	March 1986	March 1987	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of small, medium and large scale)	22551	26986	31290	+4435	+4304
1. Coal	119	93	160	—26	+67
2. Iron and Steel	1430	1270	1633	—160	+363
3. Other Metals & Metal Products	801	958	1050	+157	+92
4. All Engineering	5560	6760	7937	+1200	+1177
5. Electricity	415	493	532	+78	+39
6. Cotton Textiles	1869	2169	2459	+300	+290
7. Jute Textiles	263	274	298	+11	+24
8. Other Textiles	1365	1639	1811	+274	+172
9. Sugar	428	536	550	+108	+14
10. Tea	295	320	387	+25	+67
11. Vegetable Oils (including vanaspati)	311	347	386	+36	+39
12. Tobacco & Tobacco Products	159	184	228	+25	+44
13. Paper & Paper Products	596	672	798	+76	+126
14. Rubber & Rubber Products	434	460	513	+26	+53
15. Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2325	3156	3665	+831	+509
Of which: Fertilizer	(361)	(700)	(852)	(+339)	(+152)
16. Cement	282	351	472	+69	+121
17. Leather & Leather Products	323	376	420	+53	+44
18. Construction	265	285	379	+20	+94
19. Petroleum	72	373	119	+301	—254
20. SAFAUNS*	376	326	282	—50	—44
21. Residual	4863	5944	7211	+1081	+1267

@Provisional.

*Ships acquired from abroad under the new scheme.

1985-86 (April-March) at a rate of interest of 14 per cent per annum for a period not exceeding 14 days followed by a "cooling off" period of 14 days. Banks seeking discretionary refinance for a block of more than 14 days or an amount in excess of the limit stipulated would, however, require the prior sanction of the Reserve Bank. The total discretionary refinance limits under this scheme amounted to Rs. 388 crores. The discretionary refinance limits as on March 28, 1986 aggregated to Rs. 398 crores of which Rs. 337 crores or 84.7 per cent was utilised. The level of discretionary refinance limits was Rs. 455 crores as on March 27, 1987 which was also the peak level during 1986-87. Of this Rs. 204 crore or 44.8 per cent were utilised. The overall utilisation of discretionary refinance limits by banks during 1986-87 was low. As on June 19, 1987 the discretionary refinance limits of Rs. 389 crores were totally unutilised.

Overall Position

122. The total of limits available under various Reserve Bank refinance facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans and duty draw backs) which stood at Rs. 787 crores as on March 28, 1986 came down to a relatively low level of Rs. 402 crores as on September 12, 1986. The utilisation of limits as on March 28, 1986 amounted to Rs. 629 crores or 79.9 per cent. As on March 27, 1987, the total refinance limits aggregated to Rs. 1,363 crores of which Rs. 995 crores or 73.0 per cent was utilised whereas as on June 19, 1987 total refinance limits amounted to Rs. 1,847 crores of which Rs. 343 crores or 18.6 per cent was utilised. (Table 19).

Credit Budgets

123. During the period under review, the credit budgets of 54 scheduled commercial banks were examined of which discussions with the Chief Executives of 21 public sector banks and 9 foreign banks were held during the period June-August 1986. During the discussions, it was stressed to banks that advance planning should be undertaken to ensure that there was a smooth adjustment to the phasing out of the 4 per cent band of waiver for SLR shortfalls. The banks' attention was drawn to the fact that with the greater emphasis being given to monetary targets, particularly net Reserve Bank credit to Government, violent fluctuations in banks' cash balances with the Reserve Bank should be avoided and in this context the need for improved cash management by banks was stressed. The banks were advised to plan their lending operations on the basis of their own resources and avoid large reliance on volatile money market funds. The banks were also advised that the credit budget formulation should closely reflect the actual outturn.

Price Situation.

124. The wholesale prices on a point-to-point basis rose by 5.3 per cent in 1986-87, as against 3.8 per cent in 1985-86 and 7.6 per cent in 1984-85. On a weekly average basis, however, the rise was marginally lower at 5.4 per cent as against 5.7 per cent in 1985-86.

125. The prices under CPI for industrial workers rose by 7.5 per cent in 1986-87 as against 8.9 per cent in 1985-86 on a point to point basis. However, on an average basis the rise in prices was higher at 8.8 per cent in 1986-87 as against 6.4 per cent in 1985-86.

Table 19—RBI Accomodation to Scheduled Commercial Banks
(Excluding special refinance against shipping loans and duty-draw-backs)

(Rs. crores)

As on the last reporting Friday	Food Credit Refinance		Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		Total Refinance	
	Limits	Out-standings	Limits	Out-standings	Limits	Out-standings	Limits	Out-standings	Limits	Out-standings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1986										
March	—	—	339.3	252.7	50.0	40.0	398.0	336.5	787.3	629.2
June	736.1	33.6	510.4	68.6	—	—	46.0	1.0	1292.5	103.2
September	—	—	463.3	89.1	—	—	—	—	463.3	89.1
December	—	—	634.7	111.3	—	—	388.3	—	1023.0	111.3
1987										
March	—	—	894.1	777.5	14 0	14.0	455.0	203.6	1363.1	995.1
June	—	—	1372.4	343.4	50.0	—	389.4	—	1846.8*	343.4

* Inclusive of 182 days Treasury bill refinance limit of Rs. 35.0 crores.

126. A group-wise analysis of the WPI on a point-to-point basis indicates that primary articles and manufactured products contributed to the bulk of the rise in 1986-87. Thus the Primary Articles Group recorded a rise of 4.9 per cent in 1986-87 as against 2.8 per cent in 1985-86. The Manufactured Products Group also showed a large rise of 6.3 per cent as against 3.1 per cent in 1985-86. On the other hand, the Group of Fuel, Power, etc. registered a smaller rise of 2.8 per cent as against 8.9 per cent in 1985-86 Table 20.

Table 20—Extent of Price Rise and Weighted Contributions of Major Commodity Groups to the Rise in Wholesale Price Index (1970-71=100)

Items	Wholesale Price Indices				Variations in per cent						Weighted contribution			
	Weight	End March			End June		Fiscal year		First Quarter		Fiscal year		First Quarter	
		1985	1986	1987	1986	1987	1985-86	1986-87	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10	11	12	13	14	15
All Commodities	1000.00	346.3	359.3	378.2	374.5	394.6	+3.8	+5.3	+4.2	+4.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Primary Articles	416.67	321.6	330.7	347.0	344.9	370.3	+2.8	+4.9	+4.3	+6.7	+29.1	+35.9	+39.0	+59.4
Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	559.2	609.2	626.2	618.1	626.2	+8.9	+2.8	+1.5	—	+32.4	+7.6	5.1	—
Manufactured Products	498.74	330.8	340.9	362.3	357.9	375.6	+3.1	+6.3	+5.0	+3.7	+38.5	+56.5	+55.7	+40.6

127. Table 21 presents the data on the weighted contribution of major commodity groups to the rise in wholesale price index.

128. The Manufactured Products Group with a weight of 50.0 per cent in the index contributed to the rise in prices to the extent of 56.5 per cent as against 38.5 per cent during 1985-86. The Primary Articles Group with a weight of 42.0 per cent in the index contributed 35.9 per cent to the price rise in 1986-87 as against 29.1 per cent in 1985-86. The smallest contribution to the rise in prices came from the group of Fuel, Power etc., which has a total weight of only 8 per cent in the index; it has contributed to the rise to the extent of 7.6 per cent in 1986-87 as against 32.4 per cent in 1985-86.

129. The seasonal trends in wholesale prices continued to persist as in the preceding year. There was a brisk rise in prices in WPI early in the year by 5.6 percentage points during April to July 1986 as compared with 5.4 percentage points in the corresponding period of 1985. In the next three months of August to October 1986, the growth slowed down to 1.4 percentage points as against a fall of 1.1 percentage points in the corresponding period of 1985. During the last five months of the financial year, i.e. November 1986 to March 1987, coinciding broadly with the major part of the busy season, there was a fall in prices by 1.7 percentage points as against 0.4 percentage point in 1985-86.

130. Table 22 presents these seasonal trends in WPI. The major Groups presented in the table show similar trends as in the case of all commodities. The seasonal trends are more marked in the case of Primary Articles Group. Thus, between end-March to end-July the rise in prices in 1986-87 was larger at 7.1 percentage points as compared with 6.6 percentage points in 1985-86. In the next period of end-July to end-October, this Group showed a rise of 1.8 percentage points in 1986-87 as against a fall of 3.3 percentage points

Table 21—Index Numbers of Wholesale Prices Trends in Weighted Contributions of Commodity Groups

Items	Weight	1985-86	1986-87
1	2	3	4
All Commodities	1000.00	100.00	100.00
I. Primary Articles	416.67	+29.1	+35.9
(1) Cereals	107.43	+24.0	+0.7
(2) Pulses	21.79	+2.8	+4.6
(3) Fruits and vegetables	61.32	+31.6	+14.7
(4) Milk and milk products	61.50	+3.0	+11.4
(5) Eggs, fish and meat	18.97	+7.1	+6.6
(6) Other food articles	16.04	—11.2	+4.0
(7) Oilseeds	42.01	—3.8	+15.3
(8) Fibres	31.73	—26.8	+8.5
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	+32.4	+7.6
(9) Coal mining	11.47	+7.2	—
(10) Mineral oils	49.12	+6.1	+0.1
(11) Electricity	24.00	+19.1	+7.5
III. Manufactured Products	498.74	+38.4	+56.5
(12) Dairy products	3.88	—	+0.3
(13) Grain mill products	4.64	+0.5	+0.7
(14) Bakery products	1.85	+0.2	+0.2
(15) Sugar, confectionary, etc.	0.53	+0.1	—
(16) Sugar, khandsari and gur	72.41	+18.8	—8.9
(17) Edible oils	37.16	—0.3	+21.3
(18) Tobacco manufactured	19.49	+12.5	+2.5
(19) Cotton textiles	81.02	—1.0	+5.4
(20) Jute, hemp and mesta textiles	12.14	—16.2	+1.8
(21) Footwear and leather products	0.90	+0.5	+0.3
(22) Transport equipments	16.73	+6.4	+1.3

Note: Weighted contributions are as percentages to All Commodities.

In the preceding year. During the last five months of the year (end October to end March) the decline in prices in 1986-87 was sharper at 3.7 percentage points as compared to 0.3 percentage point in the previous year. The Manufactured Products Group also moved more or less in a similar pattern.

Table 22—Three Pahses of Variations in Wholeasale Prices Index

(In prcentages)

Items	End- March to End-July		End- July to End-October		End- October to End-March	
	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
All Commodities	+5.4	+5.6	—1.1	+1.4	—0.4	—1.7
Primary Artices	+6.6	+7.1	—3.3	+1.8	—0.3	—3.7
Fuel, Power, Light and Lubricants	+1.7	+1.5	+1.4	+0.3	+5.6	+1.0
Manufactured Products	+5.4	+5.5	—0.1	+1.4	—2.2	—0.7

131. Commodity-wise analysis of price trends on a point-to-point basis given in Table 23 shows that among the Primary Articles Group the major commodities which showed a rise larger than the average increase were fruits and vegetables, milk and milk products, other food articles, fibres and oilseeds.

132. In the Manufactured Products Group the major items responsible for a larger price rise in 1986-87 were edible oils (36.4 per cent), textile (8.3 per cent) and chemicals and chemical products (5.4 per cent).

133. There was relative price stability in the sub-group of cereals. The decline in the prices of pulses by 8.9 per cent as against rise of 4.0 per cent in the previous year was due to the comfortable supply position supported by imports.

134. The sharp increases in prices of oilseeds and fibres were due to supply constraints following reduced imports of oilseeds and lower production of cotton. The increase in prices of fibres has, however, to be viewed in the background of a substantial fall in prices of jute and cotton in the previous year. The increase in prices of oilseeds and fibres may be expected to provide price incentive to farmers to increase production.

135. Among the Manufactured Products, the price increase of edible oils and textiles were in sympathy with the sharp rises in prices of oilseed and cotton, referred to earlier. On the other hand, sugar, khandsari and gur prices declined due to larger production.

136. In the Fuel, Power etc. Group, the rise in prices was substantially lower this year, mainly due to relatively stable prices of mineral oils.

137. The increase in the general price level during the first quarter of 1987-88 at 4.3 per cent on a point-to-point basis was roughly of the same order as that in the corresponding quarter of the previous year 4.2 per cent. The impetus to the recent price rise was provided by the Primary Articles Group, which rose sharply by 6.7 per cent during the first quarter of 1987-88 as compared with 4.3 per cent rise in the first quarter of 1986-87. While the Fuel, Power, Light and Lubricants Group did not register any price increase, that of the Manufactured Products Group recorded a smaller rise of 3.7 per cent as against an increase of 5.0 per cent. Important commodities which contributed to the price increase during the period were fibres, pulses, oil seeds and edible oils. While fibres and pulses recorded sharp increase of 13.4 per cent and 7.7 per cent in contract to declines of 4.5 per cent and 9.7 per cent respectively during the first quarter of 1986-87, oil seeds and edible oils recorded larger increases of 23.7 per cent and 17.2 per cent as compared with that of 16.0 per cent and 15.1 per cent, respectively. Sub-groups of fruits and vegetables and sugar, khandsari and gur, however, witnessed lower increases of 8.8 per cent and 10.8 per cent, respectively, as compared to 16.2 per cent and 14.7 per cent respectively, in the corresponding quarter of the previous year.

Changes in Administered Prices

138. The Government's price policy in respect of commodities subject to its control has multiple objectives, such as,

Table 23—Variations in Index Numbers of Wholesale Prices'

(1970-71=100)

Major groups/groups/ sub-groups/commodites	Weight	Percentage variations during financial years (point to point)			
		1985-86	1986-87	1986-87 (April-June)	1987-88 (April-June)
1	2	3	4	5	6
All Commodities	1000.00	+3.8	+5.3	+4.2	+4.3
I. Primary Articles	416.67	+2.8	+4.9	+4.3	+6.7
Food Articles	297.99	+7.8	+6.5	+4.8	+5.0
(a) Cereals	107.43	+11.9	+0.4	—1.5	+2.8
(i) Rice	51.31	+4.4	+6.7	+5.1	+4.4
(ii) Wheat	34.17	+16.8	—2.0	—8.6	—2.2
(b) Pulses	21.79	+4.0	—8.9	—9.7	+7.7
(c) Fruits and vegetables	61.32	+21.8	+12.2	+16.2	+8.8
(d) Milk and milk products	61.50	+2.4	+12.6	+3.5	+2.3
(e) Other food articles	16.04	—21.3	+14.1	+20.1	+8.9
Tea	11.49	—23.9	+19.2	+21.5	+7.4
Non-food articles	106.21	—9.7	+15.4	+4.5	+13.4
(a) Fibres	31.73	—36.9	+27.0	—4.5	+13.4
Raw Cotton	22.46	—25.2	+33.3	—7.8	+17.7
(b) Oil seeds	42.01	—4.1	+24.7	+16.0	+23.7
Minerals	12.47	+0.6	—30.9	+0.1	+0.1
Petroleum, crude and natural gas	6.02		—38.4	--	—
II. Fuel, Power, Light and					
Lubricants	84.59	+8.7	+2.8	+1.5	—
Coal	10.39	+13.8	--	---	—
Mineral oils	49.12	+2.7	+0.1	+0.3	—
Electricity	24.00	+24.2	+11.1	+5.3	—
III. Manufactured Products	498.74	+3.1	+6.3	—5.0	+3.7
Sugar, khandsari and gur	72.41	+9.9	—6.2	+14.7	+10.8
(i) Sugar	21.91	+23.2	—0.7	—4.2	+1.6
(ii) Gur	45.58	+4.8	—7.4	+23.2	+14.4
(iii) Khandsari	4.92	+21.9	—13.2	—1.0	+9.7
Edible oils	37.16	—0.3	+36.4	+15.1	+17.2
Textiles	110.26	—7.9	+8.3	+1.7	+1.1
Paper and paper products	8.51	+3.9	—0.3	—0.1	—
Cement	7.03	—6.0	—0.1	+0.1	+0.8
Chemicals and chemical products	55.48	+5.1	+5.4	+1.3	+1.1
Iron, steel and ferro alloys	34.73	+1.1	+0.7	+0.3	—

compensation for cost [illegible] while keeping a balance between the interests of producers and consumers and containing the magnitude of subsidies. There is usually a trade off between the increase in administered prices for covering up of costs and mobilisation of larger resources on the one hand and larger provisions from budgetary resources for bridging the gap between costs and prices of administered commodities, on the other.

139. The agricultural price policy continued to lay emphasis on increased production by providing remunerative prices. The Government raised the support prices of major agricultural commodities covering cereals, pulses, etc., during 1986-87 and 1987-88.

140. On December 16, 1986, the Government announced an increase of Rs. 4 per quintal in the procurement prices of wheat for the 1987-88 marketing season thereby raising it to Rs. 166 a quintal, following the rise in procurement prices for the 1987-88 marketing season, on April 9, 1987, the Government announced an increase in the Central issue price of wheat by Rs. 5 per quintal from May 1, 1987. Accordingly, for the public distribution system the Central Issue price would be Rs. 195 per quintal as against the existing Rs. 190 per quintal. For Integrated Tribal Development Project areas and tribal majority States, the Central issue 155 per quintal as against the existing prices of Rs. 125 and Rs. 150 a quintal, respectively.

141. On August 29, 1986, the procurement prices of paddy for all varieties—common, fine and superfine—were raised uniformly by Rs. 4 per quintal for the 1986-87 marketing season. Accordingly, the revised prices for common, fine and superfine varieties were fixed at Rs. 146, Rs. 150 and Rs. 154 per quintal, respectively. The issue price of rice sold through the public distribution system was also increased by Rs. 8 per quintal for all the three varieties, with effect from October 1, 1986. The revised rates were fixed at Rs. 239, Rs. 251 and Rs. 266 a quintal for common, fine and superfine varieties, respectively. The Central issue price of rice for distribution in the integrated tribal development programme areas and tribal States was kept unchanged at Rs. 160 per quintal for common variety, Rs. 170 a quintal for the fine and Rs. 185 per quintal for the superfine varieties.

142. The procurement price of coarse grains was raised in September, 1986 for the 1986-87 marketing season by Rs. 2 per quintal to Rs. 132 a quintal.

143. The minimum support prices for tur, moong and urad were raised uniformly by Rs. 20 a quintal to Rs. 320 a quintal for the 1986-87 marketing season. For the 1987-88

marketing season, the prices were uniformly raised further by Rs. 5 a quintal to Rs. 325 a quintal for all these pulses, mentioned above. In December 1986, the Government raised the minimum support price of gram by Rs. 20 a quintal to Rs. 280 per quintal for the 1987-88 marketing season.

144. The support prices for oilseeds were raised by a higher margin to give fillip to production. Thus, the minimum price for groundnut (in-shell) was raised on September 22, 1986 by Rs. 20 to Rs. 370 per quintal and for sunflower seed by Rs. 15 to Rs. 350 per quintal for the 1986-87 marketing season. The price for groundnut was further revised upward to Rs. 390 per quintal for the 1987-88 marketing season. The prices for soyabean (yellow and black varieties) were also increased by Rs. 15 and Rs. 5 respectively, to Rs. 290 and Rs. 255 per quintal for 1986-87 marketing season and further to Rs. 300 and Rs. 260 per quintal respectively, for 1987-88 marketing season.

145. Similarly, the minimum support price for F-414 and H-777 varieties of cotton was raised by Rs. 5 to Rs. 430 per quintal for 1986-87 marketing season and further to Rs. 440 per quintal for 1987-88 marketing season. The statutory minimum price for sugarcane linked to basic recovery of 8.5 per cent was raised from Rs. 17 per quintal in 1986-87 to Rs. 18 per quintal for 1987-88 marketing season. The issue price of levy sugar supplied through the public distribution system was raised by 5 paise per kg. to R. 4.85 per kg. from December 15, 1986. The statutory minimum price for jute (W-5 Ex Assam) was also increased by Rs. 15 to Rs. 240 per quintal for 1987-88 marketing season.

146. There were some increases in the electricity and railway tariffs. The electricity rates were revised upwards by some of the Electricity Boards resulting in a rise in the price index of electricity group in WPI by 11.1 per cent in 1986-87. As regards the railway tariff, the telescopic nature of the freight rates was modified in December 1986, in a way as to raise the freight charges on transport of goods.

147. Keeping in view the escalation in the cost of various inputs, the Government decided in December 1986 to increase the retention price of levy cement by Rs. 24.50 per tonne to Rs. 300.50 per tonne. As the increase in the retention price was to be met out of the savings of the Cement Regulation Account, there was no change in the price of levy cement for the consumers.

148. The Government revised upwards the prices of different grades of aluminium from March 1, 1987. The sale price, inclusive of excise duty, of commercial grade ingots was increased from Rs. 21,962 to Rs. 26,449 per tonne, electrical conductor grade ingots from Rs. 22,188 a tonne to Rs. 27,152 a tonne and electrical conductor grade wire rods from Rs. 22,894 a tonne to Rs. 27,858 a tonne. Following these changes, on March 2, 1987, the Government fixed the new retention prices for the aluminium producers.

149. As a sequel to the increase in the gas prices by the Oil and Natural Gas Commission, the Gujarat State Fertilisers Co., the monopoly suppliers of caprolactum, raised the prices of caprolactum by Rs. 1,400 a tonne to Rs. 30,400 a tonne (ex factory) from February 1, 1987.

150. The Joint Plant Committee raised the prices of steel items, specially for rounds, bars and rods by Rs. 100 per tonne with effect from April 23, 1987. This was in addition to an increase of Rs. 35 a tonne as 'packing extras' from April 1, 1987.

Trends in Consumer Price Indices

151. As in the preceding year, the inflationary pressures noticed in 1986-87 were more pronounced at the retail level than at the wholesale level. Thus, the rate of price increase on a point-to-point basis under CPI for industrial workers (base 1960 = 100) was higher at 7.5 per cent as compared to 5.3 per cent under WPI in 1986-87. On a point-to-point basis, the rise under CPI was by 7.5 per cent in 1986-87 as against 8.9 per cent in 1985-86. However, on an average basis, the rise was higher at 8.8 per cent in 1986-87 as against 6.4 per cent in 1985-86.

152. During the first quarter of 1987-88 (financial year) on a point-to-point basis, the CPI for industrial workers, increased by 4.2 per cent as against 3.1 per cent in the corresponding quarter of the previous financial year. However, during the same period, on an average basis, the rise at 8.0 per cent was marginally lower than that of 8.4 per cent in the corresponding period of the previous year.

153. The data on CPI for urban non-manual employees (base 1960 = 100) reveals that during 1986-87, while on an average basis the rise of 7.9 per cent was larger than that of 6.8 per cent in 1985-86, on a point-to-point basis, the increase of 7.0 per cent was lower than that of 8.1 per cent in the previous year.

154. The divergence in the rates of inflation under WPI and CPI for industrial workers can be explained in terms of the time-lag involved in transmitted of rise at wholesale level to retail level and due to differences in the product mix in the two baskets and weights given to the individual items. However, over a period of time the difference in the rates of increase as between these two series is not wide.

GOVERNMENT FINANCE

155. In the fiscal sphere, the budget for 1986-87 carried forward the fiscal reforms initiated in 1985-86. The highlights of 1986-87 budget were the introduction of MODVAT involving an overhaul of the excise tax structure, launching of a simpler and more growth-oriented scheme of excise duty concessions for small-scale units, rationalisation of taxation provisions relating to gift and capital gain, introduction of Investment Deposit Account Scheme in lieu of investment allowance, etc. The Central Government introduced new financial instruments like Public Sector Bonds, Indira Vikas Patras and '182 days Treasury Bills' to mobilise more resources for supporting Public Sector Plan Outlays. In view of the encouraging response under the voluntary disclosure of true income/wealth, the validity of the scheme was extended upto March 31, 1987. The Finance Minister also announced another scheme on August 1, 1986 for compounding of offences and settlement of Court cases relating to customs and excise duties.

156. The buoyancy in Central Government revenues continued in 1986-87. However, there was a sharp rise in expenditure, particularly on the non-Plan side, which outpaced the growth in revenues. According to revised estimates for 1986-87, Plan and non-Plan expenditure had increased by 9.2 per cent and 17.3 per cent, respectively, over the budget estimates for 1986-87. Consequently, the budgetary deficit for 1986-87 enlarged from Rs. 3,703 crores (BE) to Rs. 8,285 crores (RE). The deficit as percentage of GDP increased from 2.0 per cent in 1985-86 to 3.1 per cent in 1986-87. The States' finances also showed deterioration with the combined deficit of 23 States amounting to Rs. 945 crores in 1986-87 as against the budgeted anticipation of Rs. 291 crores.

Union Budget 1987-88

157. At 1986-87 rate of taxation, the budgetary deficit in 1987-88 is estimated at Rs. 6,010 crores. After taking into account the proposed tax measures and reliefs a net additional revenue of Rs. 322 crores is expected to accrue to the Centre leaving an uncovered budgetary deficit of Rs. 5,688 crores (Table 24). Despite an announcement of post-budget tax concessions amounting to Rs. 70 crores, the budgetary dificit would remain the same as the loss in revenue is expected to be made good by better collection during the course of the year. The Prime Minister gave a categroical assurance to the Parliament that the deficit for 1987-88 would not exceed the budgeted amount. A Cabinet Committee was accordingly set up to monitor Government expenditure for this purpose, reflecting the growing concern of the Government on the growth of, in particular, non-Plan expenditure. Although the increase in Plan outlay in 1987-88 has been only 3.2 per cent over 1986-87, total Plan outlay during the first three years of the Seventh Plan at 1984-85 prices amounted to 63 per cent of the total outlay envisaged. The sharp rise in non-Plan expenditure and shortfall in the expected contribution from public sector undertakings necessitated larger borrowings than those provided in the Plan in order to maintain this level of Plan expenditure.

Table 24—Budgetary Deficit, Market Loans and RBI's Support to Market Loans of the Central Government

(Fiscal Years 1985-86 to 1987-88)

(Rs. crores)

Sl. No.	Items	1985-86 (Accounts)	1986-87 (Budget Estimates)	1986-87 (Revised Estimates)	1987-88* (Budget Estimates)
1	2	3	4	5	6
1.	Revenue Account				
	(a) Receipts £	29,206	31,309	35,153	38,202
	(b) Expenditure £	34,771	38,464	42,386	44,944
	(c) Surplus (+)/Deficit (—)	—5,565	—7,155	—7,233	—6,742
2.	Capital Account				
	(a) Receipts	16,763	19,236	18,190	20,566
	. m ents	16,135**	15,784	19,242	19,512
	(c) Surplus (+)/Deficit (—)	+628**	+3,452	—1,052	+1,054
3.	Total Receipts 1(a) + 2(a)	45,969	50,545	53,343	58,768
4.	Overall Surplus (+)/Deficit (—)**	—4,937	+3,703	—8,285	—5,688
	4) as per cent of (3)	10.7	7.3	15.5	10.0
6.	Gross Market Loans	5,543	e6,350	6,350	7,121
7.	(6) as per cent of (3)	12.1	12.6	11.9	12.5
8.	Increase(+)/Decrease(—) of RBI holdings of Dated Securities$	+367.9	—1,51.21	—1,612.1	

* Include effects of budget proposals but exclude post-budget tax concessions.

£ Include commercial departments.

**Excludes Rs.1,628 crores of medium-term loans given to State Governments to clear their verdrafts as on January 28, 1985.

$ On book value basis, according to the records of RBI.

158. Under non-Plan expenditure, three major items, viz., interest payments, defence expenditure and major subsidies, have been steadily rising. Interest payments are expected to go up by Rs. 1,100 crores (11.5 per cent) over 1986-87. The share of interest payments in total non-Plan expenditure would go up from 25.5 per cent in 1986-87 to 27.1 per cent in 1987-88. The increasing burden of interest payments can be seen from the fact that during the first three years of the Seventh Plan, it has increased from Rs. 5,974 crores in 1984-85 to Rs. 10,650 crores in 1987-88 or by 78.3 per cent. This has pushed up the internal debt servicing ratio (ratio to total receipts of interest and repayment of loan) to 20.0 per cent in 1987-88 from 17.0 per cent in 1984-85. This ratio is likely to go up further in the coming years owing to increased borrowings. Another important non-Plan expenditure which has exerted pressure on budgetary resources is the defence expenditure, which is budgeted to show a further rise of Rs. 2,518 crores (22.7 per cent) over 1986-87 (RE), on top of an increase of 27.6 per cent in 1985-86. During the first three years of the Seventh Plan, defence expenditure has increased from Rs. 6,661 crores in 1984-85 to Rs. 12,512 crores in 1987-88 (BE) or by 87.8 per cent. The expenditure on major subsidies, i.e., subsidies on food, fertilizers and export promotion has gone up from Rs. 3,456 crore in 1984-85 to Rs. 4,780 crores in 1987-88 registering a rise of about 35 per cent over the last three years. As a result of sharp increase in interest payments, defence expenditure and subsidies, the share of these three items in total non-Plan expenditure has gone up from 67.7 per cent in 1986-87 to 73.3 per cent in 1987-88.

159. The tax proposals contained in the budget for 1987-88 are expected to yield additional revenue of Rs. 1,109 crores. The budget also gave concessions in excise and customs duties amounting to Rs. 595 crores that would provide relief to a number of industries and benefit the common man. After taking into account the loss of revenue on account of reliefs and States' share in new taxes, the net additional revenue to the Central Government would be Rs. 322 crores.

160. The present rate structure of income tax has been left unchanged in line with the Long-Term Fiscal Policy. However, in order to encourage investment in house construction, repayment of loans and interest payments made to the extent of Rs. 10,000 in a year towards the cost of any new residential property would qualify for deduction under Section 80-C within the existing annual limit of Rs. 40,000.

161. The budget proposes a new tax of 10 per cent on expenditure in expensive hotels. This tax would not, however, be imposed on tourists who pay their bills in foreign exchange so that tourism is not adversely affected.

162. The budget also proposes a tax of 15 per cent on foreign exchange released for foreign travel, excluding that for studies and medical treatment abroad.

163. While no changes were made in the rates of capital gains taxation, some provisions relating to these were rationalised. The lock-in period for shares for claiming the benefit of concessional treatment under long-term capital gains tax was reduced from 36 months to 12 months. The exemption of capital gains arising from the sale of a residential house if a new house is bought therewith, which hitherto available in the case of individuals was extended to Hindu undivided Families.

164. As envisages in the Long-Term Fiscal Policy, the budget indicated that a liberalised set of depreciation rules would be introduced from April 1987. Under the revised provision, depreciation would be allowed in respect of blocks of assets instead of the present system linked to individual assets. The rates of depreciation were also rationalied and reduced to only three rates, viz., 100 per cent, 50 per cent and 33-1/3 per cent.

165. Major changes in corporate taxation include withdrawal of Section 80-VVA inserted in 1983 in respect of zero-tax companies. In place of this provision, a new provision was incorporated whereby every company would be required to

pay a minimum corporate tax on at least 30 per cent of its book profits. As a result of this provision a domestic company would be required to pay a tax of at least 15 per cent of the book profits. However, the provision was later amended to provide for a set-off against profits of past losses or unabsorbed depreciation whichever is lower. With a view to improving the coverage and preventing tax evasion, a new Section 194E was inserted in the Finance Bill. It provided for tax deduction at source at prescribed rates in respect of payments beyond certain prescribed amount of fees for professional and technical services, royalty, rent, commission or brokerage and payments for goods supplied to Government, etc. This proposal was, however, dropped later on representation that it would entail inconvenience to a large number of tax payers.

166. The budget proposes a new savings scheme based on Net Savings Principle. Under the Scheme, 50 per cent of the amount deposited under the National Savings Scheme upto Rs. 20,000 would be allowed as a deduction from the taxable income in addition to the limit of Rs. 40,000 provided under Section 80-C of the Income Tax Act. However, in the year of withdrawal, 50 per cent of the amount withdrawn would be added to the taxable income during that year.

167. In the area of indirect taxes, the MODAVAT scheme which was introduced in 1986-87 for certain commodities has been extended to all commodities, except those relating to textiles, tobacco and petroleum sectors. The budget did not provide for any increase in duty on final products in majority of the items.

168. Customs duties were rationalised particularly on imports of capital goods. The differential in the rates of duties on general project imports and general machinery imports was removed and a uniform rate of duty was introduced. In order to safeguard the interests of domestic capital goods industry, customs duties in the case of specified project imports such as fertiliser, power plant of 50 M.W. and below and electronics industry were raised. Further, in order to reduce costs to domestic manufacturers in certain critical sectors such as power, hereby equipments and textile machinery etc., duty on special types of steel was reduced.

169. Besides giving a fiscal incentive for encouraging investment in housing sector, the budget provided an allocation of Rs. 125 crores for the Indira Awaas Yojana for construction of one million houses during the Seventh Plan period for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The budget also provided for creation of a new financial structure to provide funds for housing. Under the Scheme, a new housing bank at the apex level would be set up by the Reserve Bank with an equity capital of Rs. 100 crores. his bank would promote housing institutions at both local and regional levels.

170. In Spectember 1986, the UTI had set up a mutual fund for investment in equity to attract the small investors. The State Bank of India would also set up a similar mutual fund.

State Budgets for 1987-88

171. The combined budgetary position of States @ at 1986-87 rates of taxation reveals an overall deficit of Rs. 1,545 crores for 1987-88 as against a deficit of Rs. 945 crores for 1986-87 (RE) and a surplus of Rs. 1,688 crores in 1985-86 (Accounts). Twelve States have proposed measures to raise additional resources yielding a net revenue of Rs. 833 crores during 1987-88. In addition, the States would receive an estimated amount of Rs. 192 crores as their share in the Centre's fresh tax measures. After taking into account States' own additional resource mobilisation and their share in the Centre's new tax measures, the overall deficit would narrow down to Rs. 520 crores. Developmental expenditure in 1987-88 is projected to grow at a lower rate of 5.3 per cent as against 16.9 per cent in 1986-87 while non-developmental expenditure would show a larger rise of 21.1 per cent during 1987-88 as compared to 20.4 per cent last year.

@Date relate to 23 States. Date for Arunachal Pradesh and Goa are not available.

Consolidated Position : Centre and States : 1987-88

172. Data relating to the combined financial position of the Central and State Governments are presented in Table 25. The combined budgetary deficit of the Centre and the 23 States is expected to be Rs. 6,208 crores in 1987-88, showing a decline of Rs 3,022 crores or 32.7 per cent over the Revised Estimates but is higher by Rs. 2,214 crores or 55.4 per cent over the Budget Estimates of 1986-87.

Table 25—Combined Receipts and Disbursements of the Central and State Governments (Fiscal years 1985-86 to 1987-88)

(Rs. crores)

Items	1985-86 (Accounts)	1986-87 (Budget Estimates)	1986-87 (Revised Estimates)		1987-88* (Budget Estimates)	
			Amount	Percentage variation over the accounts of previous year	Amount	Percentage variation over Budget Estimates of previous year
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	81221	87185	92171	+13.5	100216	+14.9
A. Revenue Receipts	54097	58217	63776	+17.9	69282	+19.0
of which :Tax Receipts (a+b)	42991	46841	49469	+15.1	56457	+20.5
(a) Direct Taxes	7047	7058	7989	+13.4	8568	+21.4
(b) Indirect Taxes	35944	39783	41480	+15.4	47889	+20.4
B. Capital Receipts	27124	28968	28395	+4.7	30934	+6.8
II. Total Disbursements (A+B+C)	84470	91179	101401	+20.0	106424	+16.7
A. Development Expenditure (a+b+c)	55032	57584	64789	+17.7	64922	+12.7
(a) Revenue	32621	34832	38305	+17.4	39966	+14.7
(b) Capital	12310	12530	14003	+13.8	13301	+6.2
(c) Loans and Advances	10101@	10222	12481	+23.6	11655	+14.0

1	2	3	4	5	6			
B. Non-Developmental Expenditure								
(a+b+c)			27332	31581	34116	+24.8	39522	+25.1
(a) Revenue			25984	29656	32020	+23.2	34744	17.2
(b) Capital			1116	1429	1564	+40.1	4280	+199.5
(c) Loans and Advances			232	496	532	+129.3	498	+0.4
C. Others			2106	2014	2496	+18.5	1980	—1.7
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I-II)			-3249	—3994	—9230		—6208	

* Include effects of budget proposals and exclude post-budget tax concessions.

@ Includes non-developmental expenditure.

Note: 1. Data relate to 23 State Budgets i.e. excluding Arunachal Pradesh and Goa. Further, the data do not cover Union Territories with Legislatures. Figures for 1985-86 in respect of Jammu and Kashmir and Nagaland relate to Revised Estimates.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayat Raj Institutions, appropriation to contingency funds, net remittances and are adjusted for difference in the figures of repayment of loans by State Governments to the Central Government given in their espective budgets.

173. Aggregate receipts of the Centre and States are expected to reach a level of Rs. 1,00,216 crores in 1987-88, registering a rise of 14.9 per cent over the Budget Estimates of Rs. 87,185 crores and 8.7 per cent over the Revised Estimates of Rs. 92,171 crores for 1986-87. Their revenue receipts (Rs. 69,282 crores) and capital receipts (Rs. 30,934 crores) will increase in 1987-88 by 19.0 per cent and 6.8 per cent, respectively, over the Budget Estimates of the previous year. The buoyancy in tax receipts observed during the last two years is expected to continue in 1987-88. Accordingly, tax receipts are expected to rise by 20.5 per cent over the Budget Estimates of previous year on top of an increase of 15.1 per cent recorded in 1986-87. The tax proposals contained in the Central Budget in 1987-88 are likely to yield an additional revenue of Rs. 514 crores—Rs. 145 crores from direct tax proposals and Rs. 369 crores from indirect tax proposals. Under indirect taxes, a predominant share (Rs. 302 crores or 81.8 per cent) would come from excise duties. Owing to persistent reliance on indirect taxes for raising additional resources, the ratio of direct tax collection to total tax collection of the Central Government has been steadily going down. The ratio of direct tax collection (net) to total tax receipts which had declined from 17.8 per cent in 1985-86 to 16.9 per cent in 1986-87 (Revised Estimates) would further come down to 15.8 per cent in 1987-88.

174. Aggregate disbursements of the Centre and the States in 1987-88 are expected to be Rs. 1,06,424 crores, higher by 5.0 per cent over the Revised Estimates and higher by 16.7 per cent over the Budget Estimates of 1986-87. Developmental expenditure would rise by Rs. 7,338 crores or 12.7 per cent over Budget Estimates of 1986-87 and as compared with Revised Estimates of Rs. 64,789 crores, it would be higher by Rs. 133 crores or 0.2 per cent. On the other hand, non-developmental expenditure at Rs. 39,522 crores would be higher by Rs. 7,941 crores or 25.1 per cent over Budget Estimates and Rs. 5,406 crores or 15.8 per cent over Revised Estimates of 1986-87. Plan outlay of the Centre is fixed at Rs. 24,622 crores as against Rs. 23,625 crores in the previous year (Revised Estimates) showing a rise of 4.2 per cent. Plan outlay of States and Union Territories has been fixed at Rs. 19,537 crores representing an increase of 17.0 per cent over the previous year. The Central budgetary support of Plan outlay during 1987-88 would be Rs. 23,677 crores comprising Rs. 14,923 crores for the Central Plan and Rs. 8,754 crores for State and Union Territory Plans.

Market Borrowings

175. During 1986-87 the Central Government entered the market seven times—once for placing an amount of Rs. 350 crores in favour of the Reserve Bank of India—and borrowed a gross amount of Rs. 6,350 crores. After providing for a repayment of Rs. 1,050 crores of maturing loans during the year (including the 3 per cent conversion loan, 1946, which fell due for repayment on September 16, 1986) the net market borrowings amounted to Rs. 5,300 crores—higher by Rs. 199 crores or 3.9 per cent over the previous year (Table 26). Of the gross market borrowings of Rs. 6,350 crores, Rs. 5,883 crores was by cash subscription and Rs. 467 crores by way of conversion.

Table 26—Market Borrowings of Central and State Governments, Local Authorities and Institutions Sponsored by Central and State Governments 1985-86 and 1986-87 (Fiscal Years)

(Rs. crores)

Government/Authority	Gross Market Borrowings		Repayments (Total Maturities)		Net Market Borrowings	
	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
1. Central Government	5,764	6,350	663	1,050	5,101	5,300
2. State Governments	1,414	1,446	441	283	973	1,163
3. Total Government Borrowings (1+2)	7,178	7,796	1,104	1,333	6,074	6,463
4. Institutions sponsored by Central Government	1,644	1,869	177	267	1,467	1,602
5. Institutions sponsored by State Governments (Including Local Authorities)	1,311	1,279	570	515	741	764
6. Total Institutions Borrowings (4+5)	2,955	3,148	747	782	2,208	2,366
7. Aggregate Market Borrowings (3+6)	10,133	10,944	1,851	2,115	8,282	8,829

176. Gross market borrowings of the State Governments during 1986-87 were placed at Rs. 1,446 crores, of which Rs. 1,404 crores was through cash subscription and the balance of Rs. 42 crores was by way of conversion. After taking into account the repayment of maturing loans amounting to Rs. 283 crores, the net market borrowings of the State Govts. aggregated to Rs. 1,163 crores, larger by Rs. 190 crores or 19.5 per cent over the actual amount borrowed in the previous year.

177. The gross borrowings by local authorities and institutions sponsored by Central and State Governments stood at Rs. 3,148 crores. After providing for Rs. 782 crores for the repayment of maturing loans, net market borrowings of these institutions were placed at Rs. 2,366 crores recording a rise of Rs. 158 crores or 7.2 per cent over 1985-86.

178. The Central Budget for 1987-88 has assumed net market borrowings of Rs. 6,300 crores, a rise of Rs. 1,000 crores (18.9 per cent) over the previous year. As a result, net market borrowings which constituted 15.9 per cent of the Centre's current revenues (net of State's share) in 1986-87 would go up to 17.4 per cent in 1987-88. In addition to the Centre's own market borrowings, some public sector undertakings have also been permitted to raise resources through issue of bonds in domestic markets and commercial borrowings abroad for financing their developmental plans.

179. The public sector undertakings are expected to raise Rs. 1,500 crores through issue of bonds and Rs. 485 crores through external commercial borrowings in 1987-88. As a result, the share of borrowed funds in Plan finance has steadily been going-up. The total borrowings of the Central Government and Public Sector undertakings would finance 33.6 per cent of the Central Plan outlay as against 33.0 per cent in 1986-87. The Long-Term Fiscal Policy had envisaged that the Central's net market borrowings would come down from 2.1 per cent of GDP in 1985-86 to 1.6 per cent in 1986-87. Based on the estimated growth in norminal GDP in 1986-87 this ratio may be around 2 per cent.

Coupon Rates on Central Government Loans

190. During 1986-87 the highest coupon rate of 11.5 per cent on longdated securities was maintained but the maturity period was reduced from 30 years to 20 years. The Coupon rates on 5-year and 10-year loans were stepped up by 1.0 percentage point to 10.00 per cent and 10.50 per cent, respectively, during 1986-87.

181. Apart from market borrowings discussed above, the Centre and states also mobilised resources through other borrowings such as provident funds and small savings. The net additions to internal debt and other liabilities of the Centre and State in 1986-87 amounted to Rs. 27,020 crores as against Rs. 23,319 crores in 1985-86 and would account for 9.9 per cent of GDP as compared with 9.6 per cent in 1985-86.

Reserve Bank Support to Central Loans

182. The higher coupon rate of 11.5 per cent and the increase in SLR effected in 1985-86 alongwith stricter enforcement of SLR on a daily basis assisted in raising more resources from the market. Of the total loans raised in 1986-87 loans raised at a coupon rate of 11.5 per cent accounted for 82.8 per cent as against 72.4 per cent in 1985-86. As a result, the dependence on the Reserve Bank's support for raising loans came down considerably during 1986-87. The Reserve Bank's intial cash subscription to Central loans in 1986-87 amounted to Rs. 2,266.4 crores which accounted for 35.7 per cent of total loans raised. As against this,the Reserve Bank had provided initial subscription of Rs. 2,905.5 crores in 1985-86 accounting for about 50 per cent of total loans. However, during 1986-87, there were net sales by the Reserve Bank.

National Rural Development Bonds

183. National Rural Development Bonds (second issue) were put on tap from July 7, 1983 with a maturity period of 3 years and carrying an interest rate of 7.5 per cent. As in the case of 7-Year National Rural Development Bonds introduced on July 9, 1979, these bonds were intended to provide an investment facility to persons desirous of availing of exemption from captial gains tax on transfer/sale of assets. The total outstandings since inception from the sale of 3-year bonds amounted to Rs. 55 crores as on March 31, 1987 and from 7-year bonds, Rs. 161 crores.

Social Security Certificates

184. Social Security Certificates were introduced on June 1, 1982 to mobilise private savings for public use, especially from small savers. The rate of interest works out to 11.3 per cent per annum (compounded half yearly). The total subscriptions to Social Security Certificates as on March 31, 1987 amounted to Rs. 18.1 crores.

Capital Investment Bonds

185. Capital Investment Bonds were put on tap from June 28, 1982, with a maturity period of ten years and carrying tax-free interest at the rate of 7.0 per cent per annum. As on June 28, 1987 the outstanding amount of these bonds was placed at Rs. 167.3 crores.

National Deposit Scheme

186. With a view to mobilising additional resources for public investment, the National Deposit Scheme having broadly the same features of long-term deposits with banks was introduced on July 30, 1984. The deposits under the Scheme are for a period of four years and carry interest at 10.50 per cent per annum. The subscriptions to these deposits since inception were placed at Rs. 68.3 crores as on March 31, 1987 as against a target of Rs. 500 crores. The scheme has since been discontinued by Government with effect from April 1, 1987.

National Savings Certificates

187. The Six-Year National Savings Certificates—VI and VII issues—were put on tap from May 1, 1981. Due to high return and liberal benefits under the Income-tax Act and Wealth-tax Act, these certificates have become increasingly popular and attractive. The total collections from the sale of these certificates during 1986-87 (April-March) amounted to Rs. 3,132 crores as compared with Rs. 2,182 crores in 1985-86. With effect from April 1, 1987 the interest rate on National Savings Certificates has been reduced from 12.0 per cent to 11.0 per cent.

Indira Vikas Patra

188. The Government of India launched on November 19, 1986 a new Small Savings instrument known as Indira Vikas Patra (IVP) with a view to mobilising rural savings. The IVPs with a maturity period of five years were issued in the denominations of Rs. 500, Rs. 1,000 and Rs. 5,000. The investors at the time of purchase were required to pay only half of the denomination values of the IVPs. Thus, the implicit rate of return worked out to 14.87 per cent per annum. Howere, IVP is not eligible for any tax concessions. With effect from 1st April, 1987, the maturity period of IVP has been increased to five and a half years to bring the return in conformity with lower interest rate pattern announced at end-March 1987. The total amount outstanding under the IVP Scheme at the end of March 1987 was Rs. 835 crores.

182 days Treasury bills

189. The introduction of a new financial instrument of 182 days Treasury bills during the year has been referred to earlier. These bills are issued by the Reserve Bank for a minimum for a amount of Rs. 1 lakh and in multiples thereof on discounting basis, with the rate of discount and the corresponding issue price being determined through monthly auctions. The bills can be purchased by any person resident in India including individuals, firms, companies, corporate bodies and institutions. However, State Governments and provident funds are not eligible to invest in them. The Reserve Bank determines the amount of treasury bills it proposes to issue at each auction after receipt of tender and it has the full descretion to accept or reject any or all the bids without assiging any reason. In the case of accepted tenders, treasury bills are issued at the prices at which they are tendered by the bidder in the

relevant application. It is an approved investment for SLC purposes of banks and is an eligible collateral for borrowing from the Reserve Bank under its standby refinance facility.

Ways and Means Advances to State Governments

190. The Reserve Bank provides Ways and Means Advances to the States to tide over seasonal imbalances in cash flow on account of receipts and expenditures. The limits of Ways and Means Advances were earlier revised in July 1982. In response to representations, from States and taking into account the developments in budgetary, transactions since 1982 it was decided to effect a basic increase of 20 per cent in the existing limits of normal Ways and Means Advances in case of all States keeping accounts with the Bank with effect from October 1, 1986. Further, as the cash flow problem faced by the States is reported to be more severe in the first half of the year than in the second half, an additional 10 per cent rise was sanctioned for the former period. In other words, an increase of 30 per cent and of 20 per cent over the then existing aggregate to normal limits of Rs. 520 crores were sanctioned to the 20 State Governments banking with the Reserve Bank for the period April-September and October-March, respectively. There was no change in the Special Limits or in the minimum balances to be maintained with the Reserve Bank. Subsequently, three newly formed States, viz. Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram have also appointed the Reserve Bank as their bankers taking the total number of States banking with the Reserve Bank to 23. The aggregate limits for Ways and Means Advances now stand at Rs. 957.60 crores during April-September and Rs. 904.40 crores in October-March of the fiscal year including the aggregate limits of Rs. 226 crores for special Ways and Means Advances.

191. During the year all State Governments stayed within the overdraft regulation scheme. No State was in an overdraft position beyond the prescribed limit of 7 continuous working days.

CAPITAL MARKET

192. New capital issues by non-Government public limited companies at Rs. 2,461.6 crores in 1986-87 (April-March) were higher by 49.5 per cent than those of Rs. 1,646.6 crores in 1985-86 (Table 27). Equity issues were higher by 4.1 per cent. If however, allowance is made for an exceptionally large issue by one company, equity issues would show a decline of 17.0 per cent. Non-convertible debenture (NCD) issues were lower by 27.8 per cent during the year compared to those in the previous year. On the other hand, convertible debenture issues increased manifold from Rs. 85.2 crores in 1985-86 to Rs. 1,064.6 crores in 1986-87. The large shift from NCDs to convertible debentures is attributable to factors such as competition faced by NCDs from public sector bonds and absence of an active secondary market. It is also pertinent to note in this context that in 1986-87 a few companies made large issues of convertible debentures having attractive terms of conversion.

Table 27—Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies

(Rs. crores)

Types of Issues	1985-86*	1986-87*
1	2	3
Equity Shares†	846.5	880.8
Preference Shares	1.2	0.8
Debentures	798.9	1,580.0
(i) Convertible	85.2	1,064.6
(ii) Non-convertible	713.7	515.4
Total	1,646.6	2,461.6

*Provisional.

†Exclude bonus shares.

Note: 1. Data include amount of over-subscription retained in cases where specific information in this regard was available.

2. Data exclude issues privately placed with financial institutions etc.

193. During 1986-87, new issues of public sector bonds offering 14 per cent rate of of interest and/or 10 per cent tax-free rate of interest were issued. The 14 per cent bonds and 10 per cent bonds are both exempt from wealth tax; besides interest income from 10 per cent bonds is also exempt from income tax. The receipts from these bonds aggregated to Rs. 1,516.1 crores (including over-subscription retained) as compared with Rs. 353.7 crores in the previous year. Bulk of the subscription for these bonds was received from banks and other financial institutions. Though effective returns are quite high on tax-free bonds, the response from individual investors is not reported to be substantial. In this context, there appears to be greater need for publicity and concerted promotional efforts on the part of the issuing public sector entities and for keeping issues open for longer periods than has been the case so far. Effective measures will also be necessary if a secondary market is to be developed for these bonds.

194. Provisional data indicate that the amount of capital raised (paid-up) excluding bonus shares by non-Government companies in 1986-87 was higher at Rs. 1,632 crores as against Rs. 1,071 crores in 1985-86. The amounts raised differ from the capital issues for several reasons. One, there is a time lag between the floatation of issues and the actual subscription. Second, the amount issued may be subscribed in more than one instalment and third, there are possibilities of over subscription or under subscription.

195. The above data on capital raised also are to a certain extent, under-reported owing to delay or default in submission of statistical returns by the companies concerned to the Controller of Capital Issues. Capital raised against approvals by Government companies in 1986-87 (mostly through bonds offering 14 per cent rate of interest and/or 10 per cent tax free rate of interest issued by public sector undertakings) amounted to Rs. 1,978.6 crores. Capital raised by non-Government companies under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969 (under which issues upto Rs. 1 crore are generally exempt from capital issues control) was estimated at around Rs. 200 crores. Making allowance for under-reporting of data, capital raised (paid-up) by Government companies and non-Government companies (against approvals for capital issues and under the Exemption Order) was expected to be Rs. 4,000 crores.

Assistance by Financial Institutions

196. According to provisional data, assistance sanctioned and disbursed by all-India financial institutions (viz. IDBI, IFCI, ICICI, UTI, IRBI, LIC and GIC and its subsidiaries) during 1986-87 (April-March) aggregated to Rs. 7,486.0 crores and Rs. 5,172.0 crores, respectively. This shows a rise of 20.3 per cent in sanctions and 11.9 per cent in disbursements over the previous year. Such higher order of sanctions by the all-India financial institutions during 1986-87 as compared with those of the preceding year reflect a higher level of investment intentions. Considering the approvals of Rs. 5,489 crores granted by CCI for fresh Capital issues to Government and non-Government companies in 1986-87, the tempo of industrial investment is likely to be maintained in 1987-88 (Table 28).

Policy changes

197. The Union Budget for 1987-88 contained many proposals designed to strengthen the capital market. The existing provision, which follows deductions from income chargeable to tax in respect of investment in equity shares of certain categories of new companies under Section 80CC of the Income-Tax Act that was due to expire on March 31, 1987, was extended for three more years. Besides, the holding period of such shares was reduced from five years to three years. The Budget also reduced the holding period of shares for purposes of qualifying for the concessional tax treatment allowed for long-term capital gains from 36 months to 12 months. Further, the Budget raised the existing exemption limit for deduction of tax at source on dividend payments on equities and interest payments on debentures from Rs. 1,000 to Rs. 2,500. These measures would promote investment in shares and debentures of the corporate sector.

198. In order to strengthen the capital market and improve the investment environment, the Government have also initiated several measures during 1986-87. The creation of a new mutual fund by the State Bank of India on lines similar to the one already set up by the Unit Trust of India is proposed.

Table 28—Consents/Acknowledgements Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non-Government Companies for Raiting Capital.

(Rs. crores)

Sl.	Types of Issues	1985-86	1986-87
1	2	3	4
1.	Shares	1,082	1,512
	Of which:		
	(i) Initial Issues	645	825
	(ii) Further Issues	437	687
2.	Debentures/Bonds	2,377	3,977
	Of which:		
	(i) Convertible	372	1,962
	(ii) Non-Convertible	2,005	2,015
		(354)	(1,107)
3.	Sub-Total (1+2)	3,459	5,489
4.	Bonus shares	236	354
5.	Miscellaneous issues (loans etc.)	221	228
6.	Grand Total (3+4+5)	3,916	6,071

Note: Figures in brackets indicate consents granted for issue of 14 per cent and 10 per cent (tax free) public sector bond.

Source: The Controller of Capital Issues (CCI).

A separate board for the regulation and orderly functioning of stock exchanges and securities industry is to be set up. Specific guidelines were issued by Government, making it obligatory on all companies raising resources through debentures to create debenture redemption reserve. The minimum time-gap between successive bonus issues have been reduced to 24 months from 36 months.

199. An important development in the organisational structure and policy thrust of IDBI was the setting up of a separate fund called Small Industries Development Fund (SIDF) on May 20, 1986 exclusively to facilitate development, expansion, modernisation, diversification and rehabilitation of the small-scale sector. The SIDF serves as a focal point for financial and non-financial assistance extended to the small industrial sector. With the establishment of SIDF, IDBI has taken a series of measures for giving a boost to the small-scale sector. Besides bringing State Small Industries Development Corporations within the purview of its assistance, IDBI made certain relaxations for small-scale industries in its refinance and bills rediscounting schemes.

200. The Industrial Finance Corporation of India Act, 1948 was amended during the year under review. The amendment has inter alia enlarged the operations of IFCI and raised its authorised capital.

201. The Unit Trust of India launched the India Fund in July 1986 in collaboration with Merrill Lynch International & Co. to enable non-resident Indians and persons of Indian origin residing abroad and individuals and institutions resident outside India to invest in the securities markets of India. The principal objective of the Fund is long-term capital growth through investment in equity shares listed on stock exchanges in India. A sum of Rs. 139.5 crores was mobilised through this Fund. The UTI also launched a Mutual Fund Scheme in September 1986 and mobilised Rs. 150 crores for it. The units under this scheme, called 'Master Shares', are listed on all the stock exchanges in India.

202. All-India financial institutions have set up a company called Stock Holding Corporation of India Ltd. to secure effective post-trade services relating to transactions in securities carried out by them. In course of time, the Corporation is expected to render services to the general public also.

Equity Prices

203. Equity prices had experienced unusual buoyancy in 1985-86 which was mainly stimulated by high market expectations and, to an extent due to excessive speculative influences. The share prices reached peak levels in mid-February 1986, but reacted sharply thereafter. The budget proposals which fell short of market expectations and thus affected market sentiment included withdrawal of investment allowance and of tax concession on inter-corporate dividends and disallowance of capitalisation of interest.

204. In the first fortnight of April 1986, equities staged a partial recovery owing mainly to modification of certain budgetary proposals, particularly the one relating to taxation of inter-corporate dividends. In the second fortnight of April, however, equities again declined under sustained selling pressures and lack of buying support. The downward movement continued till the third week of May as sentiment remained adversely affected owing mainly to discouraging corporate news.

205. From the last week to middle of June equities gain recovered as a result of the favourable decision of the Bombay Stock Exchange to transfer 14 active scrips from non-specified to specify list and selective purchases of shares by financial institutions. Subsequently due to discouraging corporate reports a downward movement in equity prices gathered momentum since second fortnight of June 86 which, except for a modest recovery in October, continued till the second week of December. Thereafter, following the support extended by financial institutions and regulatory measures adopted by stock exchanges, equities recovered moderately in January and February 1987.

206. The behaviour of equity prices since February 1987 was again conditioned by the exaggerated market expectations which the Union Budget for 1987-88 could not meet. The proposals which particularly depressed market sentiment were imposition of corporate tax on minimum of 30 per cent of book profits and deduction of tax at source in respect of certain payments. The first week of March 1987 witnessed heavy selling and major stock exchanges banned short sales to arrest further fall in share prices. Thereafter, the market sentiment improved in May after the budget proposal regarding tax on minimum of 30 per cent of book profits was modified and the proposal for deduction of tax at source was withdrawn.

207 Reflecting these trends, the Reserve Bank's All India index number of ordinary share prices (base 1980-81=100), which stood at 239.5 for the week ended March 29, 1986, moved up to 248.6 by the week ended April 19, declined to 230.5 by the week ended May 24, but again rose to 248.0 by the week ended June 14. Thereafter, the index generally receded and reached 229.5 at end September, and after some recovery in October, moved downward touching a low of 209.5 in the week ended December 6. Later, the index rose to 229.4 by January 10, and after fluctuating within a narrow range upto the week ended February 28, declined to stand at 219.3 in the week ended March 28. The average index for 1986-87 (April-March) at 230.7 however, showed a rise of 4.1 per cent over the average for 1985-86, when the index had increased by 63 per cent. With improved dividend performance of a number of companies, the average gross yield on equities edged up from 3.2 per cent in 1985-86 to 3.6 per cent in 1986-87.

208. The erratic movements in equity prices had an adverse impact on the developments in the primary market. The trend in share prices witnessed recently has been, in part, a corrective to the disproportionately high buoyancy experienced earlier in 1985-86. With the economic fundamentals being fairly satisfactory, the market sentiment may improve and there could be a turn around in the capital market.

DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

Balance of Payments

209. Balance of payments data for the fiscal year 1986-87 are not yet available. Information that is available indicates that the current account deficit during the year narrowed down somewhat, after a sharp rise in 1985-86. The ratio of current account deficit (inclusive of official transfers) to GDP which reached a high of 2.4 per cent during 1985-86 seems to have declined to around 1.9 per cent during 1986-87, because of a reduction in trade deficit and some improvement on invisibles account.

210. During the fiscal year 1986-87, the country's foreign exchange reserves, comprising foreign currency assets of the

Reserve Bank, gold holdings and SDRs, rose by Rs. 331 crores to Rs. 8,151 crores at the end March 1987, as against an increase of Rs. 577 crores during 1985-86. In SDR terms, these reserves £ amounted to SDR 5.113 million at end March 1987 showing a decline of SDR 615 million in 1986-87 as against a fall of SDR 276 million in 1985-86. Table 29 presents India's foreign exchange reserves, and IMF drawings and repurchases in recent years.

Table 29 - India's Foreign Exchange Reserves

Sl. No.	End of the month	Foreign Exchange Reserves: SDRs (in millions)	SDM** (Ms. lakhs)	Gold (Rs. lakhs)	Foreign Exchange (Rs. lakhs)	Total (Rs. lakhs) (Col. 4+5+6)	Gross Drawings from the IMF under CFF and EFF (SDR millions)	Repurchases* from the RMF (SDR millions)	Net Drawings (SDR. millions) (8—9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	March 1985	146.48	180.50	245.78	6816.78	7243.06	4166.00	199.50	3966.50
2.	June 1985	303.67	376.89	246.67	6679.80	7303.36	4166.00	251.50	3914.50
3.	March 1986	115.13	161.40	274.28	7384.35	7820.03	4166.00	397.25	3768.75
4.	June 1986	126.86	186.27	274.28	7084.91	7545.46	4166.00	466.00	3700.00
5.	March 1987	139.44	231.76	274.28	7645.17	8151.21	4166.00	828.50	3337.50
6.	June 1987 @	105.44	173.26	274.28	7276.44	7723.98	4166.00	953.50	3212.50

*Repurchases under CFF and EFF.

**At Rupee-SDR exchange rate at the end of respective months.

@ Provisional.

Note: Gross drawings, repurchases and net drawings are from August 1980 when the CFF drawing was made.

£ Gold is valued at SDR 35 per ounce as in the International Financial Statistics of IMF.

211. Repayments to the IMF, inclusive of those in respect of the IMF Trust Fund loan, aggregated Rs. 840 crores during 1986-87 as against Rs. 327 crores in 1985-86. At the end of March 1987, liabilities repayable to the IMF in respect of the Extended Fund Facility drawings and the Trust Fund loan amounted to SDR 3,709 million equivalent of Rs. 6,165 crores at the prevailing exchange rate.

Merchandise Trade

212. There was a distinct improvement in India's foreign trade during 1986-87, particularly on the export front. According to provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), exports at Rs. 12,550 crores recorded a substantial rise of 20.4 per cent as against a decline of 7.8 pe. cent in 1985-86. The non-oil exports increased by 22.0 per cent during 1986-87 as against a rise of 5.7 per cent in 1985-86. Despite a substantial saving on oil import bill, growth in total imports, however slowed down only marginally. Imports at Rs. 20,063 crores expanded by 9.2 per cent during 1986-87 as against a rise of 11.4 per cent in the preceding year. Consequently, the trade deficit during the year narrowed down by Rs. 438 crores to Rs. 7,513 crores from Rs. 7,951 crores in 1985-86.

213.—Data on volume growth in exports are not yet available. Non-oil exports in SDR terms increased by 2.1 per cent during 1986-87 while these had declined by 2.4 per cent in 1985-86. Taking into account the developments in international commodity prices and prices of manufactures, India's exports in volume terms might have been higher by about 7-8 per cent in 1986-87, as against a marginal rise in the preceding year.

214. Available commodity-wise data on exports for 1986-87 indicate that exports of gems and jewellery were higher by 37.5 per cent, of leather and leather manufactures by 61.3 per cent, of engineering goods by 27.5 per cent and of cashew kernels by 49.3 per cent. The improved performance of exports also owes much to larger exports of textiles and apparels, marine products, coffee and chemicals and allied products.

215. Oil imports net of oil exports declined by Rs. 2,146 crores to Rs. 2,656 crores during 1986-87, reflecting essentially a drop in international oil prices. Non-oil imports, however, continued to expand rapidly by 29.6 per cent in 1986-87 as against 18.4 per cent in rupee terms in 1985-86; in SDR terms, these increased by 8.4 per cent, as against a rise of 9.3 per cent in the previous year. Imports of machinery and transport equipment, pearls and precious stones and of organic and inorganic chemicals increased substantially in 1986-87, on top of a significant rise therein in the preceding year. Imports of machinery, etc., rose by 50.4 per cent during 1986-87 over the level of 1985-86, those of pearls, precious stones and semi-precious stones were higher by 35.2 per cent and of organic and inorganic chemicals were larger by 17.9 per cent. While the decline in international commodity prices reduced India's import bill of some items such as crude oil and petroleum products, fertilizers and edible oils, the overall volume growth of non-oil imports seems to have remained substantial.

Invisibles

216. Partial information available indicates that net invisible receipts during 1986-87 might be somewhat higher than those in the preceding year due to a sharp rise in travel receipts. The number of foreign tourist arrivals during 1986-87 was higher by as much as 23 per cent than in 1985-86 when the arrivals had risen by 12 per cent. Outgo on account of investment income continued to rise as a result of further borrowings under 'external assistance' and on commercial terms. The outcome in respect of other items of invisibles might not have been significantly different from that in the preceding year.

External assistance, Bilateral transactions & Commercial borrowings

217. The rising trend in gross external assistance noticed in recent years continued in 1986-87. Such assistance amounted to Rs. 3,532 crores which was higher by Rs. 645 crores than that in 1985-86. The amortisation payments on external debt at Rs. 1,166 crore also significantly higher than those of Rs. 796 crores in 1985-86. Consequently, the net inflow of external assistance was Rs. 2,366 crores as against Rs. 2,091 crores in 1985-86. In terms of US dollars, the net inflow of foreign aid in 1986-87 was US $ 1,852 million as compared with US $ 1,709 million in 1985-86. Transactions with Bilateral Account countries during 1986-87 resulted in a larger net outflow than in the previous year. The resort to commercial borowings during 1985-86 was to the extent of US $ 1.5 billion and net of

repayments, such borrowings amounted to $ 1.0 billion. The reliance on commercial borrowings during 1986-87 seems to have been somewhat larger than in the preceding year.

Accretion under NR(E)RA and FCNRA Schemes

218. Inflows under Non-Resident (External) Rupee Accounts were substantially higher in 1986-87 than in the previous year, and marginally higher under the Foreign Currency Non-Resident Accounts (FCNRA) Scheme. The accretion under NR(E)RA Scheme (excluding the estimated interest element) during 1986-87 for which provisional data are available was Rs. 485 crores as compared with that of Rs. 281 crores during 1985-86. The net inflows under the FCNRA Scheme during 1986-87 were Rs. 1,169 crores as against Rs. 1,151 crores in 1985-86. The sustained large inflow of funds under these non-resident accounts of Rs. 1,432 crores in 1985-86 and Rs. 1,654 crores in 1986-87 has continued to be a source of strength to the balance of payments.

Foreign Currency Assets

219. Among the three components of foreign exchange reserves, foreign currency assets of the Reserve Bank have increased during 1986-87 (July-June). The foreign currency assets rose by Rs 192 crores during 1986-87 (July-June) as compared with an increase of Rs. 405 crores during the same period of 1985-86.

SDRs

220. Holdings of SDRs declined by SDR 21.4 million during 1986-87 (July-June) as compared with a fall of SDR 176.8 million during 1985-86. This decrease in the level of SDR holding during 1986-87 was the net result of repurchases of SDR 487.5 million from the IMF, payment of charges/interest amounting to SDR 297.5 million to the IMF, acquisition of SDRs worth SDR 715.0 million, interest subsidy of SDR 25.4 million towards Supplementary Financing Facility charges and interest on SDR holdings and remuneration received worth SDR 22.2 million.

Gold

221. Gold holding of the Reserve Bank which had risen by Rs. 28 crores during 1985-86, remained the same as at the end of June 1986, viz., Rs. 274 crores* during 1986-87 (July-June).

International Economic Developments

222. The much expected improvement in income growth of industrial countries during 1986, following the massive transfer of resources of about $ 100 billion to them as a result of a drop in oil prices and continued decline in commodity prices, failed to materialise. In fact, industrial countries recorded a lower growth rate of 2.4 per cent in 1986 as against 3.0 per cent in the preceding year. The expansion in world trade in volume terms at 4.9 per cent was, however, larger than that of 3.2 per cent in 1985. Non-fuel exporting developing countries also improved their growth performance from 4.6 per cent in 1985 to 5.4 per cent in 1986, along with a rise in their exports, in volume terms, from 5.2 per cent to 7.7 per cent. The current account deficits of non-fuel exporting developing countries narrowed down further. However, the net transfer of resources from them (debt servicing minus gross credit received by them) increased further during 1986. As a result, as a group, their investment activity was constrained and adjustment efforts were adversely affected. Notwithstanding further decline in international interest rates, the debt service ratio of capital importing developing countries rose 23.9 per cent in 1985 to 24.7 per cent in 1986.

223. Inflation rates have continued their downward course in most parts of the world. The inflation rate of 2.3 per cent in industrial countries during 1986 was the lowest in the last quarter century and was aided by the drop in oil prices and continued decline in non-oil commodity prices during 1986. In the group of developing countries, while the average rate of inflation of non-fuel exporters declined from 55.9 per cent in 1985 to 33.1 per cent in 1986, the price rise in fuel-exporting countries accelerated to 19.4 per cent from 13.4 per cent in 1985.

224. The wide disparities in inflation rates continued to exert pressures on relative exchange rate movements of many countries aggravating the uncertainties in international transactions. The welcome slide in international interest rates continued, though, of late, U.S. dollor interest rates have edged up, reflecting the persistence of the need to finance large current account deficit of the U.S.A. The Euro $ rate for six month deposits declined from 6.8 per cent at the end June 1986 to 5.9 per cent at end October 1986 but has risen thereafter to 7.3 per cent at end June 1987. On the other hand, Euro Yen and Euro DM deposit rates for the same period declined from around 4.6 per cent at end June 1986 to about 4.0 per cent at end June 1987. In line with the movement in Euro $ rate, the prime rate in the US declined from 8.5 per cent in June 1986 to 7.5 per cent in October 1986 before rising to 8.25 per cent in June 1987.

225. Despite, further significant realignment of exchange rates of the U.S. dollor, the Yen and the DM, the imbalances in the current account balances of these countries widened during 1986 leading to increased protectionist pressures and tensions in trade relations. The current account deficit of the U.S.A. increased from $ 118 billion in 1985 to $ 141 billion in 1986, while surpluses of Japan and West Germany rose from $ 49 billion and $ 13 billion to $ 86 billion and $ 36 billion, respectively. It is over two years that the exchange rates of these currencies have been moving in the right direction, but these have failed to produce a desirable adjustment in their current account balances. It is now thought that it would take considerably more time to have the effects of changes in exchange rates felt on their current account situation.

226. More recently, there is some indication of volume changes in trade which could reflect the impact of the current currency realignments. Domestic demand in Japan and West Germany, however, are not rising fast enough to compensate for the decline in external demand and all these have in short run tended to inhibit investment and growth world over.

227. The economic growth of 5.4 per cent in the group of developing countries classified as non-fuel exporters was much higher than in industrial countries but was inadequate as compared to their requirements. The outlook for growth in industrial countries and world trade expansion over the medium term remains unsatisfactory. Prospects for improved financial flows on appropriate terms to the group of developing countries are also no better. As a result, the current account position of this group of countries may come under pressure.

228. For some time, developing countries have been urging industrial countries to resolve their policy differences and to improve their growth performance so as to mitigate various economic problems encountering the international community. This stand is now being supported in many quarters and it is hoped that the advanced nations initiate appropriate actions soon. It would take a few years for the conclusion of the new round of multilateral trade negotiations which was launched by the GATT contracting parties in September 1986 in Uruguay. In the meantime, the open trading system needs to be protected from the protectionist pressures that have been growing. It is desirable, in the larger interest of the world economy, that developing countries' exports that are competitive find unrestricted access to markets in industrialisd countries. In recent years adequacy of finance on appropriate terms has been a serious constraint on efforts at adjustment with growth by the developing countries. Multilateral institutions need to be encouraged by its membership to step up their financing, for the purpose, the institutions should be provided with sufficient resources. Industrial and other countries, which have been providing ODA to developing countries, need to reassess their policies with a view to increasing substantially their assistance. Rescheduling of debts in appropriate cases is called for so as to reduce the

* Valued at the statutory holding price of Rs. 84.39 per 10 grams.

annual debt servicing amounts. There is also scope for some downward movement in nominal and real interest rates in respect of debt denominated in some currencies, and the policies need to be geared towards that end.

Exchange Rate Movements

229. In accordance with the Tokyo Declaration of May 1986, G-5/G-7 Finance Ministers continued their efforts during the year to bring about relative stability in exchange rates of major currencies. They attempted a consensus on policy adjustments among the group, with appropriate modifications in relative interest rates and concerted intervention in support of undisclosed-range of exchange rates of key currencies. At times the dialogue became restricted to G-3, with overtones of bilateral bargaining and understandings, as reflected by the October 1986 pact between the U.S.A. and Japan. Subsequently, the Paris meeting of February 1987 and the Washington meeting of April 1987 reaffirmed the intentions of the Group to ensure a measure of stability in exchange markets and this was reinforced in June 1987 by the Venice Summit. The instability in the exchange markets has, however, persisted.

230. For the second year in succession, the U. S. dollar weakened against all the major currencies and the SDR in 1986-87 (July-June). In terms of monthly averages, the dollar weakened against the SDR during 1986-87 in all months except November 1986 and June 1987. Similarly, in relation to DM it depreciated except in November 1986, March and June 1987, and against the Yen it fell in all the months except during September to November 1986 and June 1987. Against the pound sterling the dollar weakened except during August to November 1986 and June 1987.

231. During 1986-87, the rate of depreciation of the U. S. dollar was higher than in 1985-86, in relation to the DM, the Yen and the SDR but it was lower against the pound sterling. In terms of the period average (July-June 1986-87 over July-June 1985-86), the dollar weakened to the maximum against the Yen by 22.7 per cent as compared to its depreciation of 20.8 per cent in the preceding year. The comparable rates of depreciation of the dollar in relation to other currencies during 1986-87 as against last year were : DM 22.4 per cent and 19.2 per cent; pound sterling 5.6 per cent and 15.2 per cent and the SDR 11.5 per cent and 9.7 per cent. The Yen strengthened further, and more than in the preceding year against the pound sterling, the dollar and the SDR but less against the DM. This was true of the DM in relation to the pound sterling, the dollar and the SDR. The pound sterling appreciated against the dollar but weakened against the DM, the Yen and the SDR.

Exchange Rate of the Rupee

232. The value of the rupee continues to be determined in relation to a weighted basket of currencies of India's major trading partners, with the pound sterling as the intervention currency. The number of adjustments in the rupee-sterling rate aggregated to 141 during the year 1986-87 (July-June) as against 149 during 1985-86. The rupee was broadly stable against the U. S. dollar. In view of the weakening of the U. S. dollar, as mentioned earlier, against the Yen, the DM, the pound sterling, the Swiss franc and the French franc, the rupee softened against these currencies and the SDR.

Rupee-Rouble Exchange Rate

233. The rupee-rouble exchange rate was changed four times, i.e., on July 17, September 21, December 4, 1986 and January 23, 1987 during 1986-87 (July-June). As a result, the rupee-rouble exchange rate which was Rs. 12.96 per rouble at end-June 1986 became Rs. 14.79 per cent rouble at end-June 1987, reflecting softening of the rupee by 12.4 per cent over the period.

ASSESSMENT AND PROSPECTS

234. The developments in the economy during 1986-87 suggest that the growth path envisaged in the Seventh Five Year Plan is being more or less maintained. Despite unfavourable weather affecting agriculture, the real growth rate of the economy in 1986-87 is expected to be not much lower than in 1985-86 when the growth rate of GNP was 5.1 per cent. While a continued stagnation in agricultural output and a growth rate in industrial production lower than that in the pre 1985 year are matters of concern, a modest rise in the savings rate of the household sector and an improved export performance are favourable features seen in the economy during 1986-87. Despite a substantial fall in the price of oil and therefore in the oil import bill, the decline in trade deficit was only small. This calls for continued vigilance on the balance of payments front.

235. Contrary to expectations, the monsoon in 1987 has turned out to be extremely disappointing. Upto the end of the first week of August, of the 35 meteorological sub-divisions in the country, only 9 sub-divisions have had normal or excess rainfall leading to a drought of very severe magnitude covering a greater part of the country. Apart from causing a sharp decline in agricultural output in 1987-88, a drought of this dimension will also strain the finances of Government as relief expenditures increase. The performance of the industrial sector in 1987-88 may not also be encouraging as the availability of power is dependent partly on rainfall. Poor agricultural performance will have its impact on the industrial sector through both reduced availability of raw materials and decline in demand. Against this background, the price situation will need careful watching with a view to taking effective and timely measures to contain price increases. The effects of a fall in foodgrains production can be partly offset through a drawdown of the large stocks of foodgrains. The prospects for growth in 1987-88 are thus not good though rains in late August and September would have beneficial effects, especially for the winter crop. The various strains that will develop will call for skillful management of the economy if a serious disruption of the growth process is to be avoided.

236. The Seventh Five Year Plan is now in its third year and it may be useful to take a look at the pattern of growth in recent years. While a satisfactory growth rate in gross domestic product has been achieved, the higher growth rate reflects in part the strong growth in the tertiary sector as compared with the growth of the commodity producing sectors like agriculture and manufacturing. On an average annual basis, the gross value added in agriculture registered a growth rate of 2.7 per cent during the 5 years ending 1985-86, while gross value added in manufacturing has grown at the rate of 5.9 per cent per annum during the same period. In contrast, the average annual growth rate of tertiary sector has been as high as 7.4 per cent reflecting mainly a growth of 12.2 per cent in the component 'Public Administration and Defence' which increased its share in GDP from 6.9 per cent in 1980-81 to 9.6 per cent in 1985-86. The tertiary sector taken as a whole now contributes 40 per cent of the GDP. While growth in the tertiary sector is a sign of growing diversification of the economy, for a large country like India with a growing population and at its present stage of development, a strong and vibrant commodity producing sector is essential for achieving economic growth on a sustained basis.

237. The performance of the agricultural sector depends largely on the performance of the food crops which account for a little less than three fourths of the area under cultivation. Some degree of insulation of food-grains output from the vagaries of monsoon has been achieved by a continuous and substantial expansion of the area under irrigation and increased use of inputs like high-yielding seed varieties, fertilisers and pesticides. The area under high-yielding seed varieties has increased from 43 million hectares in 1980-81 to 55 million hectares in 1985-86. Distribution of certified seeds has increased from 2.5 million quintals in 1980-81 to about 5.5 million quintals in 1985-86. Consumption of fertilisers has increased from 5.5 million tonnes in 1980-81 to 8.7 million tonnes in 1985-86. Institutional credit has also played a role in the recent performance of the agricultural sector. Availability of credit has had however, the maximum impact where irrigation facilities and the infrastructure for provision of other material inputs are well developed.

238. Despite the overall resilience, the trends in production and yields show considerable regional disparities. Average yield in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh rose by 27.4 per cent between 1981-82 and 1985-86. The share of these three States in total foodgrain production of the country

has also increased from 32.7 per cent to 37.6 per cent. Foodgrain output in these States rose by 29.7 per cent over this period and contributed as much as 75.5 per cent of the total increase in the foodgrain output. Some of the States in the eastern region as well as Madhya Pradesh have also done well. The average yield in Assam, Bihar, West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh has increased by 26.9 per cent between 1981-82 and 1985-86 and their share in total foodgrains output has also risen from 26.6 per cent to 30.1 per cent. However, the average yields in these States except for West Bengal still remains below the National average. Stagnancy or near-stagnancy in yields is seen in a group of States, comprising Himachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala accounting for 41.0 per cent of area under foodgrains production in 1985-86. While regional disparities in yields reflect differing natural endowments, nevertheless there exists large scope for increasing the yield in foodgrains production in many parts of the country.

239. Besides, supply-demand imbalances persist in some commercial crops. Among these, the oilseeds sector perhaps has the most severe imbalance necessitating substantial imports.

240. The importance of achieving a breakthrough in oilseeds production is reflected in the comprehensive package of measures being implemented under the Oilseeds Technology Mission. The success of the Mission should be helped by the fact that prices of oilseeds have risen considerably over recent years. The advantage of this price buoyancy has, however, often not accrued to the farmer. Special efforts are, therefore, needed to strengthen marketing arrangements which would provide real support to oilseed growers.

241. There are signs of accelerated growth in the industrial sector in recent years. The new index of industrial production with its base as 1980-81 indicates a growth of 8.6 per cent in 1984-85 and 8.7 per cent in 1985-86. The index has registered a rise of 7.7 percent during the first 10 months of 1986-87. There are also indications of some improvement in the productivity of capital. The capital-output ratio in manufacturing has shown some decline and the total factor productivity an increase. This has been helped by improved functioning of infrastructural industries. Nevertheless, there is continuing need to bring about greater efficiency in the use of capital and reduction in the unit cost of production in order to widen the demand base for industrial goods.

242. During 1986-87, several industries have reported accumulation of stocks, indicating a mismatch between Production and off take. Most notable among them are fertilizers, coal, saleable steel, and jeeps. The causes for such accumulation vary from industry to industry. More attention needs to be paid to adjusting imports and production such that availability is in step with demand. The weakening of demand in some industries can be traced to the slackness on the agricultural front. In the case of industries with stock accumulation, while additional credit availability may provide temporary relief, indefinite continuance of credit for large inventories can entail unbearable carrying costs.

243. The Indian industry is passing through a stage of transition from a protected to a more competitive environment. Liberalisation with respect to licensing and imports has intensified domestic as well as external competition. Certain structural changes are also underway in Indian industry. Some of the older industries like textiles are losing in importance while chemical and electronics industries are gaining ground. These transitions need to be managed with care to minimise their adverse impact. Relaxation of licensing regulations casts a responsibility on corporate and non-corporate entities to make informed judgements about future market demand. Here, the role of the financial institutions could be crucial. While some imbalance between capacity and demand is unavoidable and a modest measure of over-capacity may even be desirable, crowding into what may at particular time be regarded as the preferred' industries needs to be avoided considering the overall scarcity of capital and the potential of such concentration for causing industrial sickness.

244. Liberalisation of imports has improved availability of needed inputs and should promote modernisation of technology for improving productivity and competitiveness of the industrial sector. In this context undue strains on the balance of payments need watching. It is also necessary to avoid severe shocks to domestic industries especially where these are reasonably efficient. Recent changes in the customs duty on capital goods have this objective in view.

245. During the last three decades, India has built up an impressive base for manufacturing a wide variety of capital goods and has attained a degree of self-reliance in this important area. However, in several segments of the capital goods industries, existing technology is dated. This has happened partly because of a restrictive and protective environment. There is no doubt that capital goods industries must remain competitive in terms of quality and cost; otherwise, this can have adverse implications for the user sectors and for export. Accordingly, time-bound programmes to modernise some of the important segments of the capital goods industries are already under way.

246. In recent years, the capital market has been growing steadily. This has enabled the private corporate sector and, lately some public sector entities, to raise considerable resources for financing rising investment needs. Reflecting these trends, equity prices had been generally buoyant and touched unprecedented heights in 1985-86 when many scrips were quoting at levels which were substantially out of line with the relevant fundamentals.

247. The capital market in 1986-87 exhibited mixed trends. Both approvals and new capital issues were higher by a large percentage over the previous year. While convertible debentures and equity issues rose non convertble debenture issues showed a decline. Equity prices be have derratically in 1986-87 This had an adverse impact during the second half and more particularly in the last quarter of 1986-87 on theprimary market. Several new issues did not evoke encouraging response.

248. While a sharp and persistent downturn, in the capital market is a matter of concern recent developments need to be looked at in the proper perspective. Despite a shar fall in recent months, the Reserve Bank of India's All-India index number of ordinary share prices (base:1980-81-100) stood at 201.8 in June 1987 as compared with an average of 136.0 in 1984-85 showing an increase of 48.4 per cent. To some extent, the market is passing through an inevitable corrective phase following the steep rise in prices during 1985-86.

249. There is a relative scarcity of blue chips and the ups and downs in the performance of a few companies have had disproportionate effects on the market sentiments. This deficiency can, however, be corrected only over a period of time as more and more good performers gain a place in the market. Ultimately, the strength of the capital market rests on the performance of the corporate sector. Investors confidence will revive as the corporate sector turns out better results.

250. There is no doubt that a vibrant and active stock market is necessary for the growth corporate sector. However, the market needs to develop along healthy lines if disfunctional functions are to be avoided. Excessive speculation by insiders and other operators needs to be firmly discouraged if overshooting in both rising and falling markets is to be avoided.

251. The market structure as well as the systems, procedures and technology need improvement to render prompt and efficient services to investors. Those issues are already receiving attention of the Government. In this connection, the early establishment of a supervisory and regulatory board is called for.

252. There has been considerable diversification of market instruments. Participation of various financial institutions in the capital market has also intensified. Commercial banks have been encouraged to play a useful role in the development of the capital market. Through their merchant banking divisions or leasing or merchant banking subsidiaries, banks are managing and supporting capital issues and rendering other financial services. They have been underwriting a reasonable proportion of new issues. Banks can also help in the development of a healthy market by lending their name and support to sound and reliable parties and well-conceived project proposals and avoiding proposals and parties with doubtful antecedents or prospects. They are also lending support to the floatations of public sector bonds, though the issuers of these bonds also need to make intensive marketing efforts on their own. However, considering their high reserve requirements, commitment to the priority sectors and major function of providing working capital, the banks financial involvement in the capital market has of necessity to be limited and non-speculative.

253. On the fiscal side, mention was made in last year's Report about the continuance of large budgetary deficits on revenue account which were financed by the surpluses of the capital budget. This results in pre-emption of resources for financing current expenditure at the expense of development expenditure. This trend has continued during 1987-88. This imbalance is not a sudden development. There has been a persistent divergence between the rates of growth of revenue-receipts and revenue expenditures. The structural imbalance between the two reflects primarily the fact that the buoyancy of revenues with respect to income at current prices (estimated at 1.022 over the period 1974-75 to 1984-85) is lower than that of revenue expenditure (1.232 during the same period). While the ratio of tax receipts to GDP has been gradually rising, that of non-Plan expenditure to GDP has been increasing at a much faster pace. The higher growth rate in non-Plan expenditure has not only neutralised the effect of the rise in revenue but has also preempted resources away from the Plan. The Centre's tax to GDP ratio (in per cent) rose from 10.3 in 1980-81 to 10.9 in 1984-85 and further to 12.0 in 1986-87; the ratio of non-Plan expenditure to GDP increased from 10.2 in 1980-81 to 11.6 in 1984-85 and further to 13.8 in 1986-87. Within non-Plan expenditures, the rise was more prominent in items like defence, interest payments and subsidies. The magnitude of increase in these items has been much higher in the Seventh Plan. The share of these items in total non-Plan expenditure has risen sharply to 73.3 per cent in 1987-88 budget from 67.2 per cent in 1984-85. As a result, the balance from current revenues, i.e. surplus of current revenues over non-Plan revenue expenditure has further deteriorated from (+) Rs. 582 crores in 1986-87 to (—) Rs. 1,612 crores in 1987-88.

254. The resource imbalance between revenue and expenditure has led to increased borrowing. During 1987-88, the Centre's net market borrowings would finance 26.6 per cent of Plan expenditure as compared with 23.1 per cent in 1986-87 and 24.4 per cent in 1984-85. Taking into account the domestic and external borrowings of Public Sector Undertakings, the borrowed funds would finance 33.6 per cent of Plan outlay as compared with 33.0 per cent in 1986-87. The impact of increased reliance on market borrowings has naturally increased the burden of debt servicing. During 1987-88 interest payments alone would account for 27.1 per cent of total non-Plan expenditure; three years earlier, this ratio was 32.8 per cent. The debt servcing of the Centre and States taken together would account for 4.1 per cent of GDP in 1987-88 as compared with 3.4 per cent in 1984-85.

255. The main task ahead is to overcome the resource imbalance and generate adequate resources for the Plan. Excessive borrwing stores up problems for the future, especially when the rate of return on the assets created out of these funds falls short of the rate of interest to be paid. The scope for raising the overall tax to GDP ratio from its existing level of 20 per cent needs to be explored. More importantly, there is need to contain the growth of non-Plan revenue expenditure. In this effort, serious thought has has to be given to restricting the growth in the various forms of subsidies.

256. In 1986-87, for the second year in succession, the balance of payments remained under pressure, though there was some improvement in the current account deficit to GDP ratio which declined from 2.4 per cent in 1985-86 to around 1.9 per cent in 1986-87. Export growth in 1986-87, in volume terms, was strong and at least equal to the annual growth of 6.8 per cent postulated under the Seventh Plan. Policy initiatives introduced recently over wide areas to improve the export performance seem to have started bearing fruits. A fortuitous development was the drop in international oil-prices which provided a saving of over Rs. 2,100 crores in oil import bill in 1986-87. A sharp increase in tourist arrivals boosted exchange earnings from travel. The decline in international interest rates slowed down the rise in investment income payments. Net capital inflows to deposit accounts from non-resident Indians continued to provide a substanital support to the balance of payments.

257. The rapid rise in non-oil imports however continued over the first two years of the Seventh Plan, these have increased by as much as 55 per cent. While most of these imports may go to improve productivity, efficiency and competitiveness of the economy over the medium term, immediately they have widened the trade gap and increased the financing needs. The buoyahcy in private transfers which prevailed over a long period has of late tapered off and may even have slightly declined following the drop in oil prices. The concessional external assistance constitutes but a small portion of financing needs, necessitating increased reliance on external loans and credits on commercial or near-commercial terms and there by raising debt servicing obligations.

258. It is imperative to reduce the ratio of current account deficit to GDP further so as to bring it in line with the Seventh Plan projection of 1.6 per cent for the Plan period as a whole. There are, however, certain disquieting features in the international scene which need to be taken into account. The growth rate in the industrial countries remains subdued and the prospects for improvement in world trade are not bright. The international oil prices have risen from the low of 1986 and will add to India's oil import bill. The prospects for concessional assistance remain unsatisfactory. Developments in international interest rates have been mixed, with U. S. dollar interest rates rising and those of yen, DM and pound-sterling falling. On balance,

the average interest rates on external borrowings are likely to rise.

259. It is important that volume growth in exports is maintained at about 7 per cent a year, if not higher, as envisaged under the Seventh Plan. Though India's share in world exports is small at around 0.5 per cent it does not mean that it would be easy to improve market share, as many competing developing countries are under compulsion to improve their export performance as well. A number of measures have been taken over the last two years to improve the competitiveness of Indian goods abroad with good results in some areas. It is necessary to build on this performance. Stability of commodity exports should be maintained. Large and medium units need to give a lead in the new export drive. Reasonable price stability is also important for the success of export performance.

260. As for imports, measures directed towards efficient use of energy resources, particularly oil, need to be continued in order to contain the oil import bill, as international oil prices have risen and only modest increases are envisaged in domestic oil production during the remaining years of the Seventh Plan. Substantial reduction in imports of fertilisers and sugar is visualised during 1987-88, in view of better prospects of domestic supplies. Imports of capital goods need to be watched, especially in areas where domestic manufacturing industry can meet the demands on near competitive terms. Import planning may have to receive still greater attention in the coming years.

261. The remarkably strong performance of the tourism industry during 1986-87 has raised high expectations about its contribution to the invisible account in the coming years. With the rise in international oil prices, some improvement in private transfers may be expected. The investment income payments will continue to rise as our external borrowings increase.

262. The net inflow of external assistance has been growing. The large pipeline of committed funds call for speedy implementation of assisted projects which should have a high priority. Repayments to the IMF (including Trust Fund Loans) are estimated at about Rs. 4,000 crores during the last three years of the Seventh Plan. There have been large net inflows into FCNR deposit accounts during the last two years and it is important to maintain a policy framework which would continue to encourage their growth.

263. India has followed a cautious approach regarding commercial borrowings and this should continue as the debt servicing ratio has already reached 17 per cent in 1985-86. However, as the IMF loans get repaid there may be scope for some increase in our borrowings.

264. The level of foreign exchange reserves at end June 1987 was equivalent to about four months of imports and could be considered as reasonably comfortable. There is, however, not much room for drawdown of these reserves for financing the current account deficits. Given the prospects for various types of financing and self-imposed prudent limits on commercial borrowings, maintenance of the viability of balance of payments depends on a vigorous export drive and careful planning of imports.

265. Policies relating to the banking sector continue to emphasise consolidation of its progress with a view to improving efficiency, house-keeping, customer service, credit management and financial strength of banks. The capital of banks is being augmented. The current branch licensing policy while stressing the need to cover spatial gaps in rural areas, permits opening of new branches in urban and metropolitan areas only on the basis of demonstrated need and potential viability. Attention is also being paid to coverting loss-making branches into profitable units. There is a stress on raising productivity of staff and restraining costs. Efforts are underway for assessing and upgrading the health of loan portfolios. Banks' operations are also being selectively mechanised.

266. As indicated in last year's Report, banks are implementing comprehensive time-bound plans for improving their performance. To this end, banks have rationalised and strengthened their internal structures, particularly at the Head Office, zonal and regional levels. They have reviewed and improved their training capacities and curricular. There has been a distinct improvement in house-keeping. Bank profits are also looking up. Customer service is improving due to greater interface between bankers and clients, speedier disposal of customer complaints, quicker collection of outstation cheques due to expansion of courier services and more expeditious services in the baking hall. There is, however, no room for complacency.

267. With the recent conclusion of agreements with bank staff unions, the process of mechanisation should accelerate leading to higher productivity and better customer service. Besides computerisation of settlement operations in 8 major clearing houses managed by the Reserve Bank, high speed readers-sorters are being set up in Bombay, Madras, Delhi and Calcutta to speed up the clearing of cheques in these metropolitan cities.

268. Improving the quality of loan assets and timely recovery of dues are two areas which deserve the maximum attention of banks. Overdues in respect of rural and industrial loans have remained high. In the case of industrial loans, the introduction of a health code for classifying advances and the emphasis on timely review of loan limits should enable banks to identify and monitor sticky and potentially sticky advances more effectively. Banks and other financial institutions have to speed up their procedures for finalising and implementing rehabilitation packages for viable sick units. In this connection, steps have been taken to improve co-ordination between term-lending institutions and banks and to tone up the functioning of bank consortia by strengthening the role of consortia leaders. The credit authorisation scheme has been liberalised to expedite credit decisions. The constitution of the Board of Industrial and Financial Reconstruction should also help in arriving at speedy solutions to the problems of sick units. At the same time, infructuous financing of non-viable units needs to be avoided.

269. Banks have done commendable work in achieving the prescribed target for lending to the priority sectors. However, the overall level of recovery of dues in this area remains inadequate. For instance, the average revovery of agricultural dues has ranged between 50 and 55 per cent of demand in recent years. This impairs the banking system's ability to recycle funds and make optimum use of resources. The wide inter-regional and inter-bank variations indicate the scope for improved recovery performance. Recovery performance is affected by several factors, two of which may be highlighted here. First, it must be ensured that timely credit is provided for productive purposes and is in fact used accordingly. For this purpose, it is important that the prescribed lending norms and methodology are adhered to, utilisation of loans is monitored and misdirection credit avoided. More recently, it has been directed that rural branches should observe one day in a week as a 'non-business' working day which branch managers would devote to developing contacts with clients, mobilising deposits, indentifying potential loanees, monitoring credit use and promoting timely recovery of dues. Secondly, it is important to create and maintain an environment conducive to financial discipline and recovery of dues. The role of

State Government in this context is crucial. They can provide effective support to banks so that wilful default is discouraged. Besides, generalised waivers or write offs of loan obligations, irrespective of the merits of each case, need to be eschewed as these can harm the rural credit system and thereby adversely affect the interest of farmers, artisans and other borrowers. There are existing provisions for providing relief to borrowers in case of natural calamities and other adverse circumstances and these should be invoked whenever need arises. Also, no authority other than the banks themselves can write off their loans. Generalised waiver, even where the borrowers' obligations to repay are taken over by a State Government, has serious demonstration effects. Such measures, besides weakening the inclination of borrowers in general to repay their loans, also build up expectations that even future loans would be similarly waived. Thus the environment for timely repayment gets vitiated. Institutional credit in the early 1950s which formed only 4 per cent total credit in the rural sector has now increased to around 65 per cent. It, is therefore, important that nothing is done to weaken the health of the rural credit system which has over the years greatly helped agricultural and other rural activities and has become a major supplement to the budgetary resources allocated for rural development.

270. Monetary policy in recent years has been paying increasing attention to the need for controlling overall liquidity in the economy and for greater co-ordination between monetary and fiscal policies. While the broad inter-relationships of output, money and prices have always been kept in view, in the more recent period, there has been a clear recognition of the need to control the growth of the monetary aggregates and in particular the growth of reserve money, in line with the increase in real output and an acceptable degree of increase in prices. The inter-relationships among output, money and prices are subject to complex lags. While it is difficult to set out the precise operation of these lags, it is found that the basic underlying inter-relationships nevertheless hold good over a period of time. It is for this reason that the Chakravarty Committee recommended the introduction of flexible monetary targets which would ensure that increases in money supply are not too far out of alignment with growth in output. Furthermore, the Committee had focussed attention on growth of net Reserve Bank credit to Government as a vital indicator as it accounted for the bulk of reserve money creation. The Central Budget for 1987-88 has, for the first time, referred to an estimate of the likely increase in net Reserve Bank credit to the Central Government. This should provide a basis for better co-ordination between monetary and fiscal policies.

271. In 1986-87, the objective of monetary policy was to keep the growth of M_3 below the average level of the previous three years. Upto the end of October 1986, the monetary growth appeared to be on course but thereafter there was a pick up in the pace of monetary expansion to a level clearly above the average of the previous three years. It was in this context that the Reserve Bank took certain measures during the period January-March 1987 to curtail the pace of monetary expansion. In the event, the monetary growth in 1986-87 was in excess of the desired growth but, in the absence of these measures, it would have been even larger.

272. The credit policy announced on the eve of the slack season of 1987 has some notable features. First, there have been a number of changes in relation to the structure of interest rates and these need to be viewed in the perspective of past developments. Interest rates had been raised sharply in the period 1979-81 in the context of high inflation rates of that period. However, with the reduction in inflation, these nominal rates implied high real rates of interest. While the administered structure of interest rates cannot respond to volatile changes in inflation rates, it is necessary to alter them at least in response to medium-term trends. With the slowing down of the inflation rates from the peak levels that ruled between 1979 and 1981, the maximum lending rate had been brought down from 19.5 per cent to 17.5 per cent in two phases between 1983 and 1985. This was further reduced to 16.5 per cent in March 1987. For the same reason, the maximum rate on deposits was also brought down from 11 per cent to 10 per cent. However, this rate was made applicable to maturities of two years and above. The reduction if the maturities for which the maximum rate of interest is applicable will provide the banking system the flexibility to adjust upward or downward the interest rates on deposits and therefore on lending as conditions change. When deposits are locked up in longer maturities, it becomes difficult to bring about any downward adjustment in lending rates even when warranted because it takes a long time for the existing deposits to mature and as such banks do not get the full benefit of the reduction in deposit rate for quite some time. Along with the reduction in the interest rates on bank deposit there was a simultaneous reduction in interest rates on other savings instruments also in order to maintain the *inter se* competitiveness of various saving instruments.

273. Second, the process of rationalisation of selective credit controls which began in April 1985 has been carried further. Over the past two years, in the case of several commodities where supply-demand balances were considered to be adequate such as wheat, paddy and rice, cotton and kapas, and cotton seed and cotton seed oil, selective credit controls were abolished. In the case of certain other commodities stipulations have been simplified. This has made the system of controls more flexible and less complex without departing from the basic objective of preventing the flow of excess credit which might facilitate a speculative build-up in stocks.

274. Third, a significant of the money market has been attempted through several measures. The emphasis is on improving existing instruments as well as developing new instruments and the creation of the necessary institutional infrastructure for providing liquidity to money market instruments. In the area of treasury bills, a significant change has been the introduction of a new bill 182 days under an auction system. The various measures announced to foster the bill system and the prospects of setting up of a Finance House should encourage the use of bills in the settlement of claims and thus improve the payment system in the economy.

275. The stance of monetary and credit policy in 1987-88 must continue to be one of caution particularly in the context of the need to prevent resurgence of inflationary pressures in the economy. Continuous monitoring of the various monetary and credit aggregates including changes in net foreign exchange assets is necessary to ensure that monetary and credit growth while meeting seasonal upswings and downswings is broadly in line with the development in the real sector.

PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

276. In part I of the Report, monetary and credit policy measures have been reviewed against the backdrop of overall economic scenario in 1986-87. In this part, important developments relating to the Reserve Bank's area of operations are presented. The organisational matters and accounts of the Bank are set out at the end.

The Highlights

277. The highlights of the developments during the year are :

(i) The branch licensing policy laid special emphasis on consolidation while ensuring the availability of a bank branch within a distance of 10 Kms. in rural and semi-urban areas.

(ii) Areas of social banking were further widended by introducing a new lending scheme for poverty-alleviation for the urban poor. Also measures weret aken to increase the flow of credit to the minority communities.

(iii) Action was proposed to strengthen Regional Rural Banks (RRBs) by increasing their capital base.

(iv) Guidelines were issued for the preparation of the fourth round of District Credit Plans covering the period January 1988 December 1990.

(v) Measures were initiated for popularising bill financing by banks.

(vi) Credit Authorisation Scheme was substantially liberalised further to give larger discretionary powers to banks and to reduce the time-lag involved.

(vii) In addition to Pound Sterling, the Reserve Bank initiated the sale of US Dollars on a spot basis to authorised dealers.

(viii) The exchange control rules were further liberalised in respect of remittance of dividend by non-FERA companies, remittance of agency commission on exports and investment by non-resident Indians.

(ix) A new broad-based Blanket Exchange Permit Scheme (providing for release of exchange for all purposes connected with export promotion) was introduced to replace the earlier RBI and ITC blanket permit schemes.

DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKING

Action Plans for Banks—November 1985 to December 1987

278. Progress in implementation of Action Plans of banks continued to be monitored by the Reserve Bank. During 1986-87, discussions at the end of each quarter were held with the Chairmen of 20 nationalised banks and State Bank of India to review the progress made by banks in the implementation of their Action Plans upto March 1987.

279. By and large banks have re-organised their set up at head offices and controlling offices. Roles and responsibilities at various levels have been reviewed, with adequate powers delegated.

280. Special efforts have been made by banks to improve staff productivity. Progress was made by banks in increasing training capacities and the number of staff trained in 1986 was much higher than in 1985. Post-training placements have also received greater attention.

281. Banks have taken various steps to revamp credit management. It was, however, observed that the position relating to review and renewal of credit limits left scope for improvement. The problem appears to be a systemic one and banks have been advised to ensure that the controlling offices and the branches observe necessary discipline in this behalf.

282. All the banks continued to fulfil the targets fixed for priority sector advances and generally those for the sub-sectors also. However, overdues in general are on the increase; those under priority sectors accounted for 20 per cent of the outstanding credit at end-December 1986 as against 11.5 per cent under non-priority sectors. Recovery performance in the case of direct agricultural advances continues to be unsatisfactory. Banks have been exhorted to gear up their machinery at various levels for monitoring sticky advances, handling of sick units and improving the overall recovery performance.

283. Although there is an improvement in regard to submission of control returns by branches, inspection and audit of branches, etc., there is scope to improve tham further. There has been a substantial improvement with regard to the balancing of books at branches and reconciliation of inter-branch accounts.

284. As for profitability, banks have generally performed well during 1986. Certain decisions taken by Government and the Reserve Bank like augmenting capital base, increase in coupon rates on Government securities, higher interest rate on food credit, increased return on cash balances kept with the Reserve Bank, coupled with the increase in the service charges, have contributed to comparatively higher profitability. The number of loss-making branches and amount of losses incurred by them were also reduced during 1986.

Branch Expansion Policy and Progress

285. Mention was made in the previous year's Report about the formulation of the new branch licensing policy to be co-terminus with the Seventh Five Year Plan. Banks, having already achieved considerable progress in extending offices in rural and semi-urban areas, are expected to consolidate their position and concentrate on improving their operational efficiency and quality of service. The new policy envisages opening of additional bank branches so as to achieve average population per bank office of 17,000 (as per 1981 census) in rural and semi-urban areas with the Development Block as the basis. Besides, a rural branch is expected to be available within a distance of 10 kms. and cover an area of about 200 sq. kms. Hilly tracts and regions which are sparsely populated and tribal areas are given special consideration by relaxing the population norms. Banks were also advised to consider setting up of satellite/mobile branches in areas where the volume of business and other considerations did not warrant the setting up of a regular branch.

286. On the basis of the lists of identified centres received from the State Governments, the Reserve Bank has allotted 4,396 rural/semiurban centres to banks upto June, 1987. Banks were advised that opening of branches at the centres allotted to them under the current programme should be spread over the remaining period of the Seventh Plan.

287. On a review of the functioning of rural branches it was felt that while banks had taken banking services into the country side, there was considerable scope for improving their performance. Banks were advised to observe one day in a week as non-public business working day at the rural branches, so that managers could spend that day exclusivley in the field for contacting their present and potential clientele for development and promotional work like mobilisation of deposits, monitoring of credit utilisation, recovery of loans and providing appropriate guidance to borrowers.

288. The scheme of amalgamation of the Hindustan Commercial Bank Ltd., (unlicensed bank) with Punjab National Bank was sanctioned by the Government of India, on December 18, 1986 and consequently the name of the bank was excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 from January 23, 1987. The number of scheduled commercial banks, excluding RRBs, stood at 79. During the year 1986-87 (April 1986-March 1987) commercial banks, including RRBs opened 417 offices. The total number of bank offices stood at 53,565 as at the end of March 1987. Of the new offices opened, the number at rural centres was 353 and at semi-urban centres 25. These constitute 86.3 per cent of the new offices. Of these, 40 belonged to State Bank of India and its associates, 126 to the 20 nationalised banks and 259 to RRBs. Rural offices at the end of March 1987, constituted 56 per cent of the total number as compared with 22 per cent in June 1969.

Indian Banks Abroad

289. During the year no new branches were opened abroad by Indian banks. Bank of Baroda closed four of its branches—one in United Arab Emirates, two in the U.K. and one in Guyana. Besides, as part of the reorganisation/restructuring of overseas operations of Indian banks, four branches of Punjab National Bank, three of Central Bank of India and one each of Union Bank of India and Punjab & Sind Bank — all in the United Kingdom — ceased operations. Two of these branches at Birmingham and at Eastham are being operated by the transferee banks while the others were closed down. Consequently, the number of Indian banks operating abroad and their overseas branches stood at 9 and 123, respectively, as on June 30, 1987. During the year, State Bank of India reported closure of its representative office at Beirut in Lebanon, thereby bringing down the number of representative offices of four Indian banks from 11 to 10. The number of deposit-taking companies set up by the Indian banks (all in Hongkong) and the wholly-owned banking subsidiaries remained unchanged at 6. Besides, two majority-owned subsidiaries engaged in banking business and four joint venture banks also formed part of the overseas sector of Indian banks as on June 30, 1987.

Foreign Banks in India

290. During the period under Report, no new branches were opened in India by foreign banks. However, Bank of California (USA), Banca Nationale Del Lavoro (Italy), Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (Japan) and Sanwa Bank (Japan) opened their representative offices in the country. Consequently, the number of branches and representative offices of foreign banks operating in India stood at 136 (of 21 banks) and 18 (of 18 banks), respectively.

Regional Rural Banks

291. During July 1986 to April 1987 two Regional Rural Banks (RRBs) were set up, taking the total number of RRBs to 196 covering 354 districts. The deposits and advances outstanding of 194 reporting RRBs as at the end of April 1987 were Rs. 1,744 crores and Rs. 1,841 crores, respectively. The Government of India had set up a working group to examine the existing structure of RRBs and to suggest appropriate measures for improving their overall capabilities. The important recommendations made by the working group, which have been accepted, are : (i) the paid-up capital of each RRB should be increased from Rs. 25 lakhs to Rs. 100 lakhs; (ii) the sponsor banks should reduce their lending rate for refinance provided to RRBs from 8.5 per cent to 7 percent; (iii) RRBs may invest their surplus funds in Government and other trustee securities instead of keeping them in current accounts with the sponsor banks in order to improve their profitability and (iv) the sponsor banks should play more active role in funds management, staff training and internal audit of the RRBs.

Banks' Assistance to Priority Sectors and under Special Schemes

292. Public sector banks continued to maintain the tempo of credit flow to the priority sectors and under special schemes. The priority sector advances of 28 public sector banks as at the end of March 1987 at Rs. 24,552 crores formed 44.0 per cent, and advances to weaker sections within the priority sector formed 11.0 per cent of total net bank credit Direct advances to agriculture outstanding at Rs. 9,058. ores constituted 16.2 per cent of total net bank credit as against the target of 16 per cent set for March 1987. Assistance to the beneficiaries under the 20-Point Programme (prior to the modified 20-Point Programme introduced in April 1987), amounted to Rs. 8,458 crores in 162 lakh accounts as at the end of March 1987 (Provisional).

DRI Scheme

293. During the year ended December 1986, the number of loan accounts of public sector banks under the Differential Rate of Interest scheme rose by 4.79 lakhs to 47.97 lakhs and the amount of loans outstanding by Rs. 98.13 crores to Rs. 560.83 crores. These advances further rose to Rs. 575.34 crores in 48.79 lakh accounts as at the end of March 1987 and formed 1.1 per cent of total advances, which exceeded the prescribed minimum level of 1 per cent.

Self-Employment and Other Schemes

294. Under the self-employment scheme for the educated unemployed youth, the number of beneficiaries to be assisted during 1986-87 was fixed at 2.50 lakhs, the same as in the previous two years. The proportion of industrial ventures to be sanctioned during the year out of the total target set for each State was to be not less than 50 per cent and that of business ventures not more than 30 per cent of the cases sanctioned. However, a relaxation was made in respect of hilly areas of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. In these areas, the minimum proportion of industrial ventures was 30 per cent instead of 50 per cent and there was no upper ceiling on the share of business ventures. During 1985-86 banks sanctioned loans amounting to Rs. 430 crores to 2.21 lakh beneficiaries against the target of 2.50 lakh beneficiaries. During the current year (1986-87), as per provisional data available in respect of reporting banks, an aggregate amount of Rs. 455.12 crores has been sanctioned to 2.19 lakhs beneficiaries upto March 1987. Following reports that commercial banks had rejected a large number of loan applications under the scheme, the Reserve Bank conducted, during the year, a study of the reasons for such rejection.

The study report is under scrutiny.

295. In September 1986 the Government of India introduced a new poverty—alleviation scheme for the urban poor. The scheme, called the self-employment programme for the urban poor, envisages provision of self-employment opportunities to urban poor and covers all cities/towns with a population exceeding 10,000 and not covered under IRDP. The programme is being implemented through selected branches of public sector banks. Assistance not exceeding Rs. 5,000 per family is available to the selected beneficiaries with a subsidy of 25 per cent of the loan amount provided by the Government of India. The lending rate prescribed is 10 per cent. The assistance is provided at the rate of one beneficiary for every 300 population in the eligible centres. As per information received, an aggregate amount of Rs. 109.48 crores has been sanctioned to 3.21 lakh beneficiaries upto March 1987.

296. Commercial banks have been rendering financial assistance to ex-servicemen under the 'Government of India scheme of assisting ex-servicemen for self-employment. The scheme, which has been in operation in one district each in Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil-Nadu and Uttar Pradesh was extended to another 8 districts in the three States of Andhra Pradesh, Kerala and Manipur.

IRDP

297. Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP), during the financial year ended March 1987, 37.41 lakh beneficiaries were assisted and term credit of Rs. 997.78 crores was granted by the banks (including RRBs and co-operative banks).

Credit to Minority Communities

298. In tune with the Prime Minister's 15-Point Programme on the welfare of minority communities, banks were advised in July 1986 to take certain steps for facilitating flow of adequate credit to minority communities. These included the setting up of special cells for looking after minorities' interests, periodical reviews of steps taken and progress made and due publicity of various anti-poverty programmes in areas having large concentration of minority communities.

Credit to SCs/STs

299. Outstanding advances of public sector banks to scheduled castes/scheduled tribes b eneficiaries increased from Rs 1,394 crores as at the end of March 1986 to Rs. 1,696 crores at the end of March 1987.

Lead Bank Scheme

300. Pending finalisation of the guidelines for the fourth round of District Credit Plans (DCPs), the lead banks were advised to prepare Annual Action Plans (AAPs) for 1987 on the usual lines subject to a few changes which were considered necessary in the light of the experience gained. Accordingly, AAPs for 1987 were prepared and launched for implementation in all the districts of the country. Guidelines for the preparation of the fourth round of DCPs covering the period January 1988 to December 1990 have since been communicated to all the lead banks.

301. Consequent on the creation of new districts, the lead responsibility in four new districts in 3 States was entrusted to public sector banks. As at the end of December 1986, the Lead Bank Scheme covered 438 districts in the country.

Credit Authorisation Scheme

302. Based on the recommendations made by the Working Group on the Money Market a few measures to promote bill financing were initiated. In the case of borrowers who enjoy aggregate working capital facilities exceeding the cut-off point under the Credit Authorisation Scheme (CAS), with effect from April 1, 1988, the limit sanctioned against book debts is not to exceed 75 per cent of the aggregate limits sanctioned to such borrowers for financing inland credit sales. The remaining credit requirements are to be financed through demand/usance bills. In cases where the proportion of receivables financing by way of *cash credit/overdraft* facilities against book debts is already less than 75 per cent, banks should not permit an increase in this proportion for financing sales. Effective April 1, 1987 banks were permitted to provide *ad-hoc* increase in inland bills limit up to 10 per cent of the existing bills limit for a period of 3 months subject to a ceiling of Rs. 1 crore; this has been further raised to Rs. 2 crores effective July 1, 1987. This is in addition to other

discretionary powers already vested with Banks. All CAS borrowers are required to attain a ratio of bill acceptances to credit purchases of 25 per cent by April 1, 1988. In cases where the ratio is below this level, banks should advise their constituents to progressively move towards attaining it.

303. A review of the Credit Authorisation Scheme made in June 1987 showed that while the CAS has brought about a large measure of financial discipline, compliance by many parties was still below expectations. With the objective of reducing delays in the sanction and disbursement of credit limits and in order to provide suitable incentives to those who comply with the various requirements as well as to encourage other borrowers to move towards such compliance, it was decided that parties which broadly comply with the prescribed discipline should be treated differently from those who do not.

304. Accordingly, effective from July 1, 1987, in respect of such large borrowers who (i) comply with the second method of lending requiring a minimum current ratio of 1.33 : 1, (ii) submit regularly the prescribed quarterly statements and (iii) maintain levels of inventory/receivables within or at the prescribed norms/past levels, banks can release the entire amount of additional sanctioned limits without the Reserve Bank's prior authorisation. Secondly, in the case of borrowers who comply with the disciplines at (i) and (ii) but are not fully complying with inventory and receivables norms, banks will have the discretion of relaxing the norms up to 20 per cent. Such cases also need not be referred to the Reserve Bank for prior approval of enhanced credit limits. These decisions are expected to reduce the number of CAS cases to be referred to the Reserve Bank by about 35 per cent.

305. Where cases have still to be referred to the Reserve Bank, the existing limit for temporary accommodation by banks upto three months has been raised substantially up to not exceeding 25 per cent of the existing packing credit limits and 10 per cent of the existing working capital (other than packing credit) limits, subject to an overall ceiling of Rs. 4 crores, as against Rs. 2 crores hitherto.

306. The Reserve Bank has decided that it would give its decision on all proposals received for its prior authorisation within one month from the date of receipt of such proposals. Banks were advised to gear up their machinery for handling proposals for larger credit limits so that decisions relating to them are taken without undue delay.

307. The number of parties in whose cases prior authorisation from the Reserve Bank under CAS was required, declined from 843 at the end of March 1986 to 598 by the end of June 1986 on account of the raising of the cut-off point from Rs.4 crores to Rs. 6 crores in April 1986. By the end of June 1987 the number of CAS parties increased to 644. Total working capital limits in force relating to these parties were Rs. 19,647 crores as at the end of June 1987, the share of public sector undertakings being Rs. 12,721 crores or 65 per cent. The facility-wise distribution of total limits at the end of June 1987 was 93.3 per cent for working capital purposes (including packing credits and bills), 5.6 per cent for term finance and 1.1 per cent for sale of machinery on deferred payment basis.

Lending under Consortium Arrangements by Banks

308. Taking into account the deviations noticed in adhering to the guidelines issued by the Reserve Bank regarding lending by banks under consortium arrangements, fresh instructions to strengthen the arrangements were issued in June 1987. They provide for automaticity about the choice of the lead bank under multiple financing arrangements and envisage a pivotal role to be played by the lead bank. These instructions cover: maximum number of banks in a consortium the need to form a consortium where the aggregate fund-based limits granted to a borrower by any single bank exceeds Rs. 100 crores, appraisal of proposals by the lead bank itself exclusively or alongwith the next major financing bank, seeking the Reserve Bank authorisation, where necessary, on approval by the Board of Directors of the lead bank without waiting for sanction by the other member banks admision of new members based on majority opinion, vesting bank officials with larger discretionary powers in taking decision, honouring of decisions within a specified time frame, simplified documentation, uniformity in terms and conditions and equitable sharing of business, income and risk relating to non-fund based facilities. Banks were advised to endeavour to move towards the single window approach particularly indisbursement, documentation etc., and a committee has been set up to frame operational guidelines for effective implementation of the concept.

Measures to Enforce Financial Discipline on Borrowers

309. Banks were advised not to conside. applications for sanction of fresh term finance (including deferred payment guarantees) for new projects, of expansion by companies which were persisten defaulters in payment of term credit without any ustifiable reasons. Regardig working capital advances, where banks had reasons to believe that the managements of the units were indulging in malpractices and hence were persiitent defaulters in the repayment of dues, they could withhold fresh sanctions and release of funds and even consider freezing of operations on the accounts, if such action was necessary for bringing round the management to comply with the required financial discipline, or to change management wherever found necessary.

310. In view of the mounting arrears relating to payment of statutory dues such as Provident Fund and Employees State Insurance dues by borrowers banks were advised *inter alia*, to modify the application forms for grant/renewal/enhancement of credit facilities so as to ensure that the position regarding the statutory dues is disclosed therein.

Co-ordination Between Banks and State Level Financial Institutions

311. In order to ensure proper co-ordination between commercial banks and State-level financial institutions (viz., State financial, industrial development and investment corporations banks were advised to take certain additiona measures. The object is to avoid delay and to make adequate provision for working capital assistance by banks to the industrial units. These measures include joint or simultaneous project appraisal, "in principle commitment bc banks at an early stage to provide working capital finance and sanction of working capital limits by banks at least three months before the units are due to commence production They also cover such matters as mutual understanding regarding holding of charges establishment of necessary rapport between the financial institutions and banks, and delegation of larger sanctioning powers to the branch levels.

Treatment of Disputed Excise Duty and other Statutory Provisions

312. On a review of the matter relating to treatment of disputed excise duty and other statutory liabilities in connection with the assessment of working capital requirements, fresh guidelines were issued to scheduled commercial banks in June 1987 stating that the disputed excise liability shown as a contingent liability or by way of notes to the balance sheet will not be treated as a current liability for calculating the permissible bank finance unless it has been collected or provided for in the account s of the borrower.

Advances to Sugar Industry

313. Reference has been made in Part I to the policy changes in respect of advances to sugar industry. They actual drawings in the borrowal accounts were to be regulated on the basis of the deficit disclosed in the monthly cash budgets of mills. Additonial credit limits beyond 115 per cent of the maximum amount availed of during the 1985-86 seson to individual units covered by the CAS (125 per cent in the case of units in western Uttar Pradesh) would be subject to the Reserve Bank's prior authorisation. These guidelines were

also issued to State-co-operative banks in respect of pledge limits to co-operative sugar factories.

Export Credit

314. Reference has been made in Part I of the Report to the reduction in the interest rates on export credit. The revised interest rates are given below

	(Effective August 1, 1986) Per cent per annum
Pre-shipment credit	
(i) Upto 180 days	9.5
(ii) Beyond 180 days and upto 270 days	11.5
(iii) Against cash incentive, etc. covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	9.5
Post-shipment credit	
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	9.5
(ii) Usance bills—upto 180 days	
(iii) Cash incentives, duty drawback etc. receivable from Government covered by guarantee of ECGC (upto 90 days)	
(iv) Undrawn balances (upto 90 days)	
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	
(vi) Export Credit not otherwise specified (w.e.f. April, 1, 1987)	14.0 to 15.5

315. Commercial banks were advised that in the case of advances against demand bills if the bills were realised before the expiry of the "normal transit period," interest at concessional rate should be charged from the date of advance till the date of realisation of such bills effective December 1, 1986. The banks would be eligible for interest subsidy only for the actual period until the realisation of such bills.

316. Banks were also advised in January, 1987 that if preshifment advances were not adjusted by submission of export documents within 180 days after the initial maximum period of 180 days for which the advances were granted, the advances would cease to qualify for concessional rate of interest to the exporters *ab initio*. In other words where exports do not take place within 360 days from the date of the original advance banks may charge interest not exceeding the ceiling rate on export credit from the very first day of the advance.

Housing Finance

317. In 1986, the quantum of housing finance earmarked to be provided by the banking system remained unchanged at Rs. 150 crores. Besides banks were asked to provide further Rs. 10 crores (in addition to Rs. 10 crores included in the annual allocation) to the Housing Development Finance Corporation (HDFC) for its housing finance operations. Banks were also authorised to extend, in consortium ,Rs. 50 crores to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) with the overall allocatoin of Rs. 150 crores to enable it to meet a part of the cost of construction of housinig projects for SCs/STs and economically weaker sections in different States. Such direct assistance by banks to HUDCO and State-level agencies would be in addition to finance provided to them in the form of subscription to their guaranteed bonds and debentures.

318. In June 1986, the Government of India had set up a high level group under the charimanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank to examine the proposal for establishing a National Housing Bank. The Group was also asked to look into the manner in which funds could be raised for housing, including identification of measures needed for that purpose and creation of housing finance institutions. The Group recommended the creation of a network of specialised housing finance institutions with a National Housing Bank at the apex level to be set up with an initial share capital of Rs. 100 crores fully contributed by the Reserve Bank. The primary responsibility of the National Housing Bank., which is being set up as a statutory corporation, will be to promote and develop specialised housing finance institutions ot regional and local levels which will mobilise additional savings and provide finance for housing construction. It will also formulate policies relating to mobilisation of resources and credit for housing regulate the working of housing finance institutions, co-ordinate their activities as also those of other agencies in the housing field and extend financial support to housing finance intermediaries. The legislative framework for the establishment of the National Housing Bank is being finalised.

Leasing

319. Mention was made in last year's Report regarding commercial banks being allowed to set up subsidiaries with the prior permission of the Reserve Bank to take up the business of equipment leasing, consequent on the amendment to the Banking Regulation Act. During the year, the Reserve Bank approved three proposals, two of public sector banks and one of a private sector bank jointly with two other such banks, to set up subsidiaries for undertaking equipiment leasing business.

Investments in and Underwriting of Shares and Debentures and Government Bonds

320. Scheduled commercial banks have been permitted to hold in their own investment portfolio shares and debentures of the private corporate sector devolving on them through their underwriting or merchant banking commitments. In November 1986, it was specified that such investment should be limited to the extent of 1.5 per cent of incremental deposits of the previous financial year. In administering these guidelines, an element of flexibility has been allowed, in that, any bank that may exceed the limit of 1.5 per cent may seek the approval of the Reserve Bank for holding such excess; individual banks may be allowed such excess holdings within the overall linit of 1.5 per cent of incremental deposits of all banks.

321. Banks were advised in May 1987, that the aggergate amount of the bonds of public sector undertakings, added to their own investment portfolio in any fiscal year, does not exceed 1.5 per cent of their incremental deposits of the previous year. If however, any bank exceeds the limit of 1.5 per cent, it can seek the approval of the Reserve Bank for holding such excess stating reasons there for. This limit, effective from the fiscal year 1987-88, would be in addition to the limit in respect of shares and debentures of the corporate sector.

322. Banks were further advised not to enter into buy-back arrangements in respect of their holdings of public sector bonds or corporate shares and debentures. The buy-back deals should be exclusively confined to Government and other approved securities actually held by banks on their own investment portfolio.

Sick Industrial Undertakings

323. Reference has been made to the problem of sick industrial units in Part I of the Report. According to the latest data available as at the end of June 1986, the total number of units identified by banks as sick stood at 1,30,606 with outstanding bank credit of Rs. 4,665 crores. These included 689 large sick industrial units (i.e., units individually enjoying credit limits of Rs. 1 crore and above from the banking system with aggregate outstanding bank credit of Rs. 3,239 crores as compared to 597 units with outstanding amount of Rs. 2,655 crores at the end of June 1985. Of the 689 sick units, viability studies in respect of 598 units were completed, of which 374 units were considered as potentially viable and 230 units were put under nursing programme by the banks. As at the end of June 1986, there were 1,28,687 sick small-Scale industrial units involving bank finance of Rs. 1,184 crores, as compared to 97,890 units involving bank finance of Rs. 955 crores a year ago. Out of 1,28,687 sick units 13,028 units were considered by banks as potentially viable and 2,656 units were brought under their nursing programme.

RBI Assistance to Financial Institutions

324. The Reserve Bank sanctioned a credit limit of Rs. 330 crores to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund for 1986-87 (July-June). The credit limit is for a period of 15 years and carries an interest rate of 8 per cent per annum. The IDBI has fully availed of the limit. It has also repaid an amount of Rs. 44.58 crores during the year and its outstanding borrowing from the Fund stood at Rs. 2,875 crores at the end June, 1987. A short-term-credit limit of Rs. 200 crores was sanctioned to IDBI in August 1986 (valid upto end-October 1986), but was not utilised by it. The IDBI was sanctioned a fresh limit of Rs. 300 crores on May 14, 1987 against the security of eligible usance bills rediscounted by it. This limit is valid upto end-August 1987.

325. The Export-Import Bank of India was sanctioned a credit limit of Rs. 85 crores out of the NIC (LTO) Fund for 1986-87. The Exim Bank fully availed of the limit and its outstanding loans from the fund stood at Rs. 345 crores as on June 30, 1987.

326. The Industrial Reconstruction Bank of India was sanctioned a credit limit of Rs. 15 crores out of NIC (LTO) Fund for 1986-87. The limit was fully availed of by the Bank and its outstanding borrowings from the Fund amounted to Rs. 25 crores as at end-June 1987.

327. An *ad-hoc* borrowing limit of Rs. 15 crores was sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India for the calendar year 1987. The Corporation did not avail of the facility till June 30, 1987.

328. An *ad-hoc* borrowing limit of Rs. 15 crores which was sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) for the calendar year 1986, was extended for a further period upto March 31, 1987. No amount was outstanding against this limit on that date. A fresh borrowing limit of Rs. 20 crores has since been sanctioned to ICICI valid up to March 31, 1988. The outstanding against it as on June 30, 1987 was Rs. 20 crores.

329. During the year, the Bank sanctioned fresh *ad-hoc* borrowing limits aggregating Rs. 55.20 crores to 15 State Financial Corporations as applied for, against *ad-hoc* bonds guaranteed by the respective State Governments. These limit were valid upto June 25, 1987. No amount was outstanding against the limits.

330. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was sanctioned a credit limit of Rs. 1,400 crores for the year 1986-87 to enable it to provide short-term loans and advances by way of refinance to State co-operative banks and RRBs. The maximum level of out standing reached against the credit limit was Rs. 1,267 crores on February 28, 1987. As at end June 1987, the outstanding balance under this line of credit was Rs. 950 crores.

Inspection of banks

331. In terms of the powers vested in the Reserve Bank inspections of commercial banks continued to be carried out by the Department of Banking Operations and Development.

332. During the period under review the annual financial review of 27 public sector banks and 12 local head offices and the Central Office of State Bank of India was taken up/completed.

333. Financial inspections of 4 public sector banks, 13 local head offices and the Central Office of State Bank of India, 17 private sector banks and 8 foreign banks were either taken up or completed during the period. In addition to these inspections, the regional offices of the Department also carried out a number of scrutinies into various complaints/frauds/allegations against banks/their employees. Regional offices had also undertaken portfolio inspections of international banking divisions of 7 public sector banks having overseas branches.

Recovery of Dues (Public Sector Banks and Financial Institutions) Bill, 1985

334. The draft bill on recovery of dues of public sector banks and financial institutions providing for the setting up of Special Tribunals to exclusively adjudicate issues relating to bank loan recoveries is under consideration of the Government of India.

Customer Service

335. Public sector banks were advised in March 1986 to conduct surveys on the extent, efficacy and implementation of the recommendations of the Working Group on Customer Service. It is reported that banks have by and large implemented most of the recommendations of the Working Group. Public sector banks were advised to afford immediate credit of outstation cheques upto Rs. 2,500 as also salary cheques upto Rs. 2,500 issued by Government/quasi-Government bodies.

336. During the period July 1986 to April 1987, investigations into 21 frauds/complaints at 110 bank offices were carried out. The findings were communicated to the concerned banks for corrective action and for examination of

the cases from the staff angle. The out come of the scrutinies was also brought to the notice of the Government wherever necessary.

337. The Government and the Reserve Bank are seriously concerned with the increasing incidence of bank dacoities/robberies in the country, particularly in Punjab and Haryana. There were 110 cases of robberies/dacoities in the country involving an amount of Rs. 395.34 lakhs during 1986 as against 79 cases involving an amount of Rs. 171.14 lakhs during 1985. Several important decisions on security arrangements were taken and banks were advised to evolve action plans and furnish quarterly progress reports of their implementations.

338. In view of the increasing number of dacoities/robberies, it was considered necessary to review the security arrangements in banks and suggest measures to strengthen them. Accordingly, Reserve Bank of India set up a committee in March 1987 comprising members from public sector banks, Reserve Bank of India and Government to review the security arrangements in banks. The report of the Committee is under examination.

Vigilance Machinery in Commercial Banks

339. A conference of the chief vigilance officers of all public sector banks was held in April 1986. The public sector banks were advised of the various steps to be taken to strengthen the vigilance arrangements. They were also advised to expedite disposal of pending disciplinary cases and impart necessary training to the staff to optimise the effectiveness of vigilance procedures.

Computerisation of Cheque Clearance

340. Clearance of inter-city cheques in MICR format drawn on Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi is now done by using medium speed reader/sorter systems and the courier service. The new system has resulted in the inter-city cheques being cleared within a week as against the previous time lag of up to 4 weeks. During 1987-88 MICR cheques drawn on the above four centres and deposited by customers with banks in Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad will also be cleared under the above scheme. High speed reader/sorter machines have installed at Bombay and Madras for mechanised processing of local clearing cheques. The ststem has become fully operational at both these centres. The facility will be extended to Calcutta and New Delhi during 1987-88.

Working Groups/Committees

341. In accordance with the suggestion made by the National Finance and Credit Council in December 1986, a Working Group was set up by the Bank in January 1987 to examine the present system and formulate norms relating to advances made both to healthy and sick units by banks in consortium with or without participation of financial institutions. The Working Group was also to make appropriate recommendations from the point of view of speeding up the decision-making process and providing timely and adequate credit to borrowers. The Group submitted its first report in March 1987 covering mainly problems of co-ordination amongst the all-India financial institutions and commercial banks in regard to sick and weak industrial units.

342. Following the recommendations of the Group, detailed instructions were issued to banks in June 1987 which inter-alia, envisage a major role to be played by the lead bank and the second largest financing bank (or two major banks under multiple financing arrangements). The other important instructions relate to carrying out the viability studies and formulation and implementation of rehabilitation packages, exchange of information between banks and financial institutions, carrying out joint reviews, adoption of a unified stand on recall of advances, vesting of bank officials with larger discretionary powers and upgradation of skills and training of staff.

343. The Standing Committee on Export Finance had set up commitee to study the structure of interest rates on export credit. The recommendations of the Committee were examined by the Bank and a final decision is being taken.

344. Mention was made in the Bank's Report for 1985-86 about the appointment of a Committee to consider problems of identification and rehabilitation of sick small-scale industrial units. On the basis of the Committee's recommendations, guidelines were issued to banks stressing the need for adequate and intensive relief measures under rehabilitation package for sick units and their speedy application. The guidelines also included an illustrative list of working signals of incipient sickness and a list of reliefs/concessions that could be extended to sick units.

345. The Standing Advisory Committee to review the flow of institutional credit to small-scale industries sector made, among others, the following recommendations:

346. The State Government and federations/associations concerned with the development of small-scale industries may take up sample studies of SSI units to identify problems /causes leading to industrial sickness. Measures should be taken to popularise customer service centres so as to reduce delays in flow of credit and sort out problems of co-ordination.

347. After detailed deliberations on financing of SSI sector in the North-Eastern region, the Committee felt that the credit absorption capacity of the region should be gradually increased by expanding in frastructural facilities, and through entreprencurial development, assured supply of adequate raw materials and related inputs, upgradation of technology and adequate market support.

DEVELOPMENTS RELATING TO CO-OPERATIVE BANKING

Progress of Primary Co-operative Banks

348. As on June 30, 1987 there were 1,359 primary co-operative banks in the country, of which 1,262 were urban co-operative banks and 97 were salary earners' societies. During the period July 1986 to June 1987, 384 banks (new as well as existing) were issued licences to commence and/or carry on banking business, taking the total number of licensed primary co-operative banks to 845. Permission was also granted to primary co-operative banks for opening of 4 extension countres and 9 branch offices. The number of offices including head ofilces of primary co-operative banks increased from 2,995 at the end of March 1986 to 3,059 as on December 31, 1986. There was no addition to the number of licensed State co-operative banks which remained at 8; the number of licensed Central co-operative banks increased by one to 36 as at end December 1986. During 1986-87, licences were issued to 4 State co-operative banks for opening 13 new offices.

349. During the period July 1986 to June 1987, Inspections of 386 primary co-operative banks were conducted. The

norms for licensing of existing primary co-operative banks were reviewed and revised norms evolved. Besides, quick scrutiny of books of accounts and methods of operations of 226 banks was undertaken for expediting the issue of licences to the banks.

Deposit and Lending rates

350. The changes in the interest rate structure applicable to domestic, FCNR and NRE deposits as also in the lending rates of commercial banks referred to in Part I, were also made applicable to co-operative banks with effect from the same dates.

Credit Authorisation Scheme

351. The work relating to the Credit Authorisation Scheme in respect of State and Central co-operative banks is handled by NABARD, subject to the Reserve Bank's approval in respect of sensitive commodities involving accounts exceeding Rs. 5 crores. During the period July 1986 to June 1987, 4 proposals requiring such approval of the Reserve Bank were received from NABARD and approved involving total working capital limit of Rs. 283 crores. During the period July 1986 to June 1987, 66 proposals from 12 urban banks seeking authorisation for grant of advances under CAS for an aggregate amount of Rs. 46.02 crores were received; in all 38 proposals for an aggregate amount of Rs. 25.04 crores were approved.

Refinance Facilities

352. Refinance facilities are made available to urban co-operative banks for financing working capital requirements of 22 broad groups of approved cottage and small scale industries. Short-term credit limits aggregating Rs. 2991 crores were sanctioned to 6 State co-operative banks on behalf of 53 primary co-operative banks for financing cottage and small-scale industrial units during the fiscal year 1986-87 as against Rs. 24.61 crores sanctioned in the previous year.

Lending to Priority Sectors

353. Urban co-operative banks were advised to ensure that their lendings to priority sectors should reach a level of at least 60 per cent of their total advances, of which at least 25 per cent should be for weaker sections of society. Although, banks were advised to achieve this target in a phased manner by the end of june 1985 intially, some of the badks could not attain the target within the prescribed time and were given extension of time upto June 1986. While smaller urban co-operative banks have made significant strides in lending to priority sectors, the performance of bigger banks was not satisfactory.

Standing Advisory Committee

354. The sixth meeting of the Standing Advisory Committee for urban co-operative banks held in February 1987 discussed, among others, matters relating to the role of State co-operative banks in the growth and development of urban co-operative banks, restrictions on provision of finance to nominal members of urban banks, and appointment of chief executives and other key personnel in urban co-operative banks. The Committee reviewed the progress in issuing licences to existing urban banks and in the rehabilitation of weak banks.

Committees & Working Groups

355. In pursuance of the announcement made by the Reserve Bank at the Conference of urban co-operative banks and credit societies at Delhi, a Committee under the chairmanship of an Executive Director of the Reserve Bank was set up to examine and make suitable recommendations on the resolutions passed at the Conference. Apart from the Reserve Bank, the Committee comprised representatives of the National Federation of urban co-operative banks and credit societies, Registrars of co-operative societies and State Bank of India. The Committee has finalised its recommendations and submitted its report.

356. Mention was made in the previous year's Report of comprehensive review of the agricultural credit system in the country to be undertaken as part of the World Bank aided NABARD-I Credit Project. The Project involves a total credit of US $ 375 million for a three-year period from July 1, 1986. The assistance was to be by way of participation in NABARD's on-going loan refinance programme for investment in agriculture with a view to increasing agricultural production and strengthening the credit delivery system. A senior expert group constituted for the purpose is to evaluate the major problems and issues currently affecting the agricultural credit system and to make recommendations for a programme to strenghten the sector.

357. The High Level Standing Committee to review the flow of institutional credit for rural sector and other related matters referred to in last year's Report, at its fourth meeting (May 1987), considered specifically the Report of the Study Group on Banking Development in North-Eastern Region. Emphasis was laid at the meeting for bringing about rapid economic development in North-Eastern region. For this purpose, it was decided to set up a separate Task Force in each State in the region. An integrated plan for development of at least one block in each district would be drawn up on a pilot basis.

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL AND OTHER MATTERS

US Dollar Sale by RBI

358. The Reserve Bank introduced a scheme for sale of US dollar to the authorised dealers effective February 2, 1987. Earlier, the Bank was selling only spot Pound sterling while it bought, both on spot and forward basis, four currencies, viz., Pound sterling, US dollar, Deutsche Mark and Japanese yen from authorised dealers. The decision to sell dollars has obviated the need for banks to first buy the Pound sterling in the inter-bank market or from the Reserve Bank and convert it into dollars in the overseas market to meet their dollar requirements. The Reserve Bank sells dollars at rates which are generally better than what the authorised dealers would obtain if they were to buy Pound sterling from the Reserve Bank and convert the currency into US dollars overseas. The scheme, which is presently confined to Bombay, is intended to assist the healthy growth of local exchange market as also to help importers to get finer rates from authorised dealers. There is no ceiling on the amount of dollar purchases.

Remittance of Dividend to Non-resident Shareholders of Indian Companies

359. Prior to July 31, 1986, authorised dealers could effect remittance of dividend to non-resident shareholders without the prior approval of the Reserve Bank, if equity shares held by non-resident shareholders in a non-FERA company, did not exceed 25 per cent of the total issued equity capital or Rs.5 lakhs in face value. In order to facilitate prompt remittance of dividend to non-resident shareholders, the Reserve Bank has granted general permission to authorised dealers with effect from July 31, 1986 to make remittances towards equity

dividends to non-resident shareholders of all non-FERA companies, irrespective of the face value of equity shares or percentage of the issued capital held by the non-resident shareholders Only applications of FERA companies are now required to be submitted to the Reserve Bank for prior approval.

New Blanket Exchange Permit Scheme

360. The Reserve Bank has introduced a single broad-based Blanket Exchange Permit Scheme for exporters in place of the separate RBI and ITC Blanket Permit Schemes. The main features of the new Scheme are given below :

(i) The list of approved purposes for which foreign exchange can be availed of by holders of blanket permits has been expanded considerably to obviate frequent applications from exporters to the Reserve Bank.

(ii) Monetary ceilings prescribed for foreign exchange expenditure for the approved purposes have been either removed or considerably enhanced to afford greater freedom to exporters.

(iii) Quantum of exchange entitlements has been related to specific percentages of realised f.o.b. value of goods exported and their classification in accordance with product lists prepared by the Government of India.

Investment by NRIs

361. With a view to providing further incentives to non-resident Indians (NRIs) and overseas bodies owned directly or indirectly to the extent of at least 60 per cent by NRIs, to make investments in Indian companies with the benefit of repatriation of capital and income earned, certain additional facilities were offered to them. These cover: (i) bulk investments upto 100 per cent of equity capital in sick industrial units, (ii) investments in new issues of Indian shipping companies and companies engaged in development of computer software or oil exploration services under the '40 per cent Scheme', (iii) investments in 'medical diagnostic centres' under the '40 per cent and 74 per cent schemes', and (iv) investments in private limited companies under the '40 per cent scheme'.

Relaxations in Exchange Control Procedures Relating to Exports

362. In order to render more prompt service to exporters, the powers delegated to authorised dealers in certain exchange control areas were suitably enhanced with effect from April 23, 1987. These include:

(i) permission to allow reduction upto 10 per cent of the invoice value of an export shipment or Rs.10,000 whichever is less, on account of disputes about quality quantity, etc., on behalf of all regular exporter-clients. Earlier, authorised dealers could consider such applications only from exporters who held blanket permits;

(ii) permission to remit commission or agree for deduction of commission amount from the invoice of the relative exportshipment upto Rs. 1 lakh in respect of shipments of goods included in the 'select' list of export products and upto Rs. 50,000 in respect of shipments of other export products provided the rates at which commission is paid are within the prescribed ceiling rates;

(iii) to effect remittances towards export claims upto 10 per cent of f.o.b. value of the shipment or Rs.30,000 whichever is less; and

(iv) grant of pre-bid clearance for bids/offers for export of engineering goods on deferred payment terms and execution of turnkey /civil construction contracts abroad up to the value of Rs.5 crores. The monetary ceiling on the powers delegated to the Exim Bank to grant such pre-bid clearances was raised from Rs. 5 crores to Rs.20 crores.

Engagement of Foreign Technicians

363. Engagement of foreign technicians can be permitted by Reserve Bank for a period of three months for attending to breakdowns/emergencies, etc. The limit of *per diem* remuneration payable to a technician in foreign currency was enhanced from US $ 300 to US $ 500 with effect from July 18,1986. The Bank also granted general permission to firms/companies with effect from March 25, 1987 to incur rupee expenses towards engagement of foreign experts/technicians for attending to he work of erection or commissioning of imported plant/equipment/machinery as also breah-downs of existing plant/machinery supplied under collaboration arrangements, subject to compliance with prescribed conditions.

Schemes for Export of Silver Jewellery and Articles

364. The Government of India introduced from December 8, 1986 a new scheme for export of silver jewellery and articles against silver supplied by foreign buyers. Under the scheme the silver required for the manufacture of articles/jewellery has to be supplied free of charge by the foreign buyers so that there is no net export of silver from India. Export of jewellery and articles (including studded ones) would be permitted only if the "value added" in the export is at least 20 per cent.

365. Under a second scheme introduced from the same day exports of jewellery and articles (other than coins) made of silver would be entitled to the benefit of replenishment of silver, provided they satisfy the 'value added' and other requirements laid down by the Government. The scheme is restricted to exports effected against orders which are backed by irrevocable letters of credit or payment on cash-on-delivery basis or full advance payment. Imports of silver under the scheme are to be handled by State Bank of India.

Project Exports

366. During 1986-87 (July-June), the Working Group on Project Exports accorded approvals for 107 proposals involving an aggregate value of Rs.3,702.81 crores. These comprised 23 proposals for civil construction contracts (Rs.1,464.54 crores), 44 proposals for turnkey contracts (Rs.1,747.21 crores), 10 proposals for deferred payment contracts for supply of engineering goods (Rs.168.44 crores) and 30 proposals for consultancy contracts (Rs.322.62 crores).

Hospitality to Non-residents on Visits to India

367. The Reserve Bank granted from July 24, 1986 general permission to any person resident in India to make payments in Indian rupees towards hospitality extended to any person resident outside India who is on a visit to India, upto a maximum of Rs.2,000 during the course of such visit. This was further raised to Rs.5,000 in June 1987.

Indianisation of Foreign Companies and Dilution Foreign Equity

368. As at the end of June 1987, final orders under Section 29(2) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 requiring Indianisation/dilution of foreign equity to a specified level were issued to 389 companies including 14 companies which opted for winding up of their activities in India instead of

Indianisation. Of these, 368 had complied with the FERA directives by that date. The remaining 21 companies are at various stages of compliance.

Joint Ventures Abroad

369. As at the end of December 1986, there were 187 Indian joint ventures, of which 150 were in operation and 37 were at different stages of implementation. The value of share capital contributed by Indian entrepreneurs in overseas joint ventures was around Rs. 92 crores and that of joint ventures under implementation around Rs.18 crores at the end of December 1986. The total amount of dividend repatriated to India was approximately Rs.11.57 crores and repatriation on account of technical know how fees, royalty, etc., amounted to about Rs.34.79 crores. These projects have generated aggregate exports from India to the tune of Rs. 161.63 crores.

Opening of Offices

370. During 1986-87 (July-June) permission was granted to Indian companies/firms for opening 16 trading and 24 non-trading offices abroad. Permission was also granted to 18 Indian companies/firms for posting their representatives at various foreign centres. During the same period 63 overseas companies were granted permission to open new liaison/representative offices in India. Permission was also granted for opening 21 Project Offices for execution of specific contracts.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

371. Good progress was recorded during the year by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in the operation of the deposit insurance scheme and the five credit gurarantee schemes.

372. During the period July 1986 to June 1987 the number of insured banks rose to 1,887 comprising 83 commercial banks, 194 RRBs and 1,610 co-operative banks. The Deposit Insurance Scheme now covers deposits of co-operative banks in 15 States, including Haryana to which the scheme was extended from January 1, 1987 and 3 Union territories. Over the years, the Corporation has progressively increased the insurance coverage for deposits from Rs. 1,500 to Rs. 30,000 covering over 2,320 lakh accounts constituting 98 per cent of the total deposit accounts. The insured deposits increased to Rs. 62,878 crores, representing 72.9 per cent of to total assessable deposits at the end of June 1986.

373. The number of credit institutions participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 increased from 251 to 263 during the year July 1986 to June 1987, comprising 71 commercial banks and 192 RRBs, while those participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme 1971, increased from 173 to 175, comprising 57 commercial banks, 81 RRBs and 37 co-operative banks. The number of State Financial Corporations (including State Industrial Development Corporations) participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 20. The number of primary urban Co-operative banks participating in the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 rose from 44 to 66 by the end of June 1987. The total guaranteed advances to small borrowers under the above four schemes aggregated Rs. 10,960 crores at the end of December 1986, indicating a rise of 16.3 per cent over the previous year.

374. The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 rose from 462 to 486 during July 1986—June 1987, comprising 69 commercial banks, 152 RRBs, 14 State Financial Corporations, 8 other, State development agencies and 243 co-operative banks. The guaranteed advances to the small-scale industrial sector increased by 15.4 pr cent over the year to Rs. 7,528 crores at the end of December 1986.

375. During the period July 1986-June 1987, the Corporation received 8,52,227 claims for Rs. 199.52 crores in respect of its guarantee schemes relating to small borrowers and 45,275 claims for Rs. 134.02 crores in respect of the scheme for small-scale industries. The total disposals during the same period aggregated 693,865 claims for Rs. 170.24 crores in respect of small borrowers and 40,236 claims for Rs. 94.99 crores in respect of the SSI scheme.

376. With a view to increasing the operational efficiency and speeding up the settlement of the increasing inflow of claims, the Corporation has been constantly reviewing, streamlining and simplifying procedures. Towards this end, it has computerised all non-industrial claims thus bringing down the time-lag between receipt and disposal of claims to 10-12 weeks. An Expert Committee has been constituted to review in detail the various schemes operated by the Corporation and to make recommendations for further improvements in the working of the Corporation.

Non-Banking Companies : Chit Funds Act, 1982

377. During the year, the provisions of the Chit Funds Act, 1982 were brought into force in Madhya Pradesh and Pondichery. With this, the Act became operative in 13 States/Union territories. The States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Haryana, Manipur, Meghalaya, Punjab, Rajasthan Bihar and Delhi finalised the rules and further action by them was awaited.

Acceptance of Deposits by Non-Banking Companies

378. So far 11 States/Union territories have taken the necessary steps to enforce the provisions of Chapter III C incorporated in the Reserve Bank of India Act, 1934 which relate to prohibition of acceptance of deposits by unincorporated bodies. The Reserve Bank initiated action against several private financial concerns under the provisions of Chapter III C in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. The writ petitions filed by many of these concerns challenging the Constitutional validity of the provisions are awaiting hearing in the Supreme Court.

Trend in Deposits with Non-Banking Corporate Sector

379. Aggregate deposits held by 8,741 reporting financial, non-financial and miscellaneous non-banking companies stood at Rs. 18,072 crores as on March 31, 1986 as compared with Rs. 16,140 crores held by 7,508 reporting companies in March 1985. The number of deposit accounts rose from 124.1 lakhs to 159 lakhs during the same priod. Regulated deposits rose by Rs. 451 crores and exempted deposits by Rs. 1,480 crores. Regulated deposits held by non-financial companies, constituting 16.8 per cent of their aggregate net owned funds, were well below the statutory ceiling of 35 per cent. Regulated deposits held by non-banking financial companies also remained within the prescribed ceilings. Regulated deposits of Rs. 3,266 crores in the non-banking corporate sector as on March 31, 1986 constituted 3.8 per cent

of total deposits held by all scheduled commercial banks as compared with 3.9 per cent in March 1985. Regulated deposits with non-banking companies recorded a growth rate of 16 per cent during 1985-86 as against 18.1 per cent in respect of scheduled commercial bank deposits. Details of deposits held by different categories of companies as at the end of March 1985 and 1986 are given in the Table overleaf.

Currency chests

380. The total number of occurrency chests at the end of March 1987 was 3,636 (excluding 489 repositories). Of these, 17 currency chests are with the Reserve Bank, 2,672 with the State Bank of India group, 556 with nationalised banks, 386 with treasuries and sub-treasuries and 5 with Jammu and Kashmir Bank Ltd.

381. During the year, a number of far-reaching decisions were taken in the interest of providing greater security to the currency chest balances. An embargo was placed on the opening of new currency chest/repository for a period of one year from February 26, 1987 so as to utilise the intervening period to consolidate the security arrangements at currency chests. It was also decided to close down 51 currency chests/ repositories in Punjab of which 43 have already been closed.

Deposit Growth with the Non-Banking Corporate Sector
(End March)

(Rupees Crores)

	1984-85		1985-86*	
	No. of reporting companies	Amount	No. of reporting companies	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aggregate deposits (i + ii)	7,508	16,140	8,741	18,072
(i) Regulated deposits		2,815		3,266
(ii) Exempted deposits		13,325		14,806
A. eposits held by :				
(i) Government Companies	55 (0.7)	8,923 (55.3)	57 (0.7)	10,029 (55.5)
(ii) Public Limited Companies	2,516 (33.5)	5,617 (34.8)	2,823 (32.3)	6,756 (37.4)
(iii) Private Limited Companies	4,937 (65.8)	1,600 (9.9)	5,861 (67.0)	2,187 (7.1)
B. eposits held by :				
(i) Financial Companies	4,134 (55.1)	3,914 (24.3)	4,995 (57.1)	4,270 (23.6)
(ii) Non-Financial Companies	2,510 (33.4)	11,784 (73.0)	2,680 (30.7)	13,113 (72.6)
(iii) Miscellaneous Non-banking Companies	864 (11.5)	442 (2.7)	1,066 (12.2)	689 (3.8)

Figures in brackets are percentages to total numer of reporting companies and aggregate deposits as the case may be.
*Provisional.

ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

Mechanisation/Computerisation

382. During the year, installation of mini-computers to cover clearing house operations at Kanpur and Calcutta was completed. With this, the operations in eight clearing houses, viz., Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, and New Delhi, have been computerised. Computerisation will be extended during 1987-88 to the remaining six centres, viz., Bhubaneswar, Gauhati, Jaipur, Nagpur, Patna, and Trivandrum, where the clearing houses are managed by the Reserve Bank.

383. Mini-computers are now operational in four Issue Officers, viz., Ahmedabad, Byculla, Nagpur and New Delhi: nine more centres in the coming year are expected to be similarly computerised. Amini-computer system was nstalled at the Bombay regional office of the Department of Financial Companies during the year. Considerable progress was made in the development of two Telecommunication networks for the Bank and it is expected that the tele, printer network would be commissioned in 1987-88.

384. Advanced Ledger Posting Machines are proposed to be introduced initially at Bombay. On the recommendations of the Working Group on Government Accounts, the Bank has agreed to computerise, besides the traditional accounts of Governments and Departmentalised Ministries Accounts, the consolidation and settlement of transactions at Nagpur on behalf of the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs.

Study of Systems and Procedures in the Bank

385. In October 1936, the Bank entrusted the work of indepth examination of the systems and procedures obtaining in the Bank to outside consultants M/s. Management Structures and Systems Ltd. The organisation would study seven major departments within a time frame of one year and come out with recommendations to facilitate improved customer service, faster decision-making and better inter-departmental co-ordination of work. Study of six departments has already been completed and the recommendations are being examined by the concerned departments for implementation.

Bankers Training College, Bombay

386. The Bankers Training College conducted a number of new programmes during the year such as, computerisa-

tion (Systems Analysis), computer appreciation for senior officers of commercial banks, computerisation programme for the Reserve Bank officers, Faculty Development (of a computers), statutory framework for foreign exchange business, external commercial borrowings, bank finance for selected industries, foundation course on international banking, programme on EDP Audit & Control, programme for officers of public sector banks to be posted at offices abroad etc. During the year, the College conducted 95 programmes and trained 2,283 officers. In all 33,210 participants attended the various programmes since the inception of the College in 1954. The College continued to provide faculty assistance to commercial bank colleges, in response to their request by deputing its faculty for taking sessions in the courses conducted by them. During the year, the College conducted owh programmes on general banking and one on finance priority sectors through the Hindi medium.

Reserve Bank Staff College, Madras

387. Apart from catering to the regular training needs officers in Gr.A to Gr.C in different departments, the College conducted some special programmes on executive health annual financial review, computer appreciation, non-resident investment in India and transactional analysis for the beenifit of senior officers. The new programmes introduced in the College during the year included a programme for officers of the Inspection Department/regional audit cell, workshop on note refund rules, seminar on funds and portfolio manages ment, programme on computer basics and management credit and performance budgeting, Government transactions and accounting system and security management and protocol, workshop on introduction of revised formats, record of findings, inspection reports, etc., in respect of Urban Coperative Banks. Participants from the Central Banks bf Bhutan, Botswana, Kenya, Macau, Malawi, Sudan and Tanzania attended some of the programmes conducted by the College. During the year, the College conducted 104 training programmes, imparting training to 2,277 participants. The total number of officers trained since inception of the College stood at 20,698.

College of Agricultural Banking, Pune

388. During the year, the College conducted 84 regular programmes, one outstation programme and three seminars' special programmes. The regular programmes include one on rural finance sponsored jointly by the Economic Development Institute of the World Bank Washington and the Reserve Bank, and new programmes introduced during the year cover programme on credit to priority sectors for IAS officers, programme on financing of waste land development and social and other forestry projects, financing of non-farm activities in rural areas, financing of dry land projects and production of oilseeds and pulses and seminar on rural credit system. During the year, 2,324 officers attended 88 programmes conducted by the College, thus raising the total number of participants trained since the inception of the College to 28,637.

Zonal Training Centres

389. The Zonal Training Centres (ZTCs) of the Bank at Buculla (Bombay), Calcutta, Madras and New Delhi continued to cater to the training needs of the Banks Class III and IV staff. Apart from the regular programmes, the ZTCs conducted preparatory course for the clerks appearing at the test for promotion as officers. Training programmes were also held for the class IV staff preparing for the test for promotion as clerks. In line with the recommendation of the Committee on Security Arrangements, the Zonal Training centre at Byculla conducted a pilot programme for class IV staff on security awareness. During the period under review 1,878 class III staff and 325 members of class IV staff received raining at the four centres, raising the total number of staff trained to 31,818 and 1,417, respectively, since the inception of these training centres.

Training in Commercial Banks

390. Under the three schemes of training in commercial banks introduced in the previous year, 3 senior officers completed their training during the year in the Controlling He and Offices of banks for an indepth exposure in key departments including internal inspection/audit departments; 39 officers are under training in rural and urban branches of public sector banks.

Deputation of Staff for Traning in India and Abroad

391. The Bank deputed 263 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management institutes of repute in India. Another 29 officers of the Bank were deputed for training and study visits to banking and financial institutions abroad including the USA, the UK, Switzerland, West Germany and Japan. In addition, with a view to providing an opportunity to the officers in the Department of Economic Analysis and Policy to broad-base their understanding of economic theory and Indian economic problems as well as adequate analytical skills for research in applied economics, the Bank deputed two officers during the year to attend the M. Phil course in applied economics at the Centre for Development Studies, Trivandrum.

392. A scheme of awarding scholarships to Bank's officers for higher study abroad for a period of one year was formulated as part of the Golden Jubilee celebrations of the Bank. Under the scheme 4 officers were selected for the yaar 1986 and were deputed abroad for higher studies in different universities. Four more officers have been selected for 1987.

Traning in Computer Technology

393. For the successful implemenation of the Bank s computerisation and mechanisation plan, as also for motivating apperciation of the fast advancing field of computer technology, the Bank introduced a scheme of incentives for acquiring qualification in the field of computers. Under the scheme, members of staff in class III and all officers may take up short-term diploma/certificate courses in computer area at the approved institutions. On successful completion of the course, they would be paid an honorarium of Rs. 500 in addition to reimbursement of the tuition fee paid for the course.

Training Facilties to Officers of Foreign Banks

394. Under the scheme of extending training and study facilities to participants from foreign Central and commercial banks in response to specific requests, 58 foreign delegates availed of tranining facilities during the year : 11 from Sri-Lanka, 8 from Ethiopia, 7 each from Nepal, Sudan and Tanzania, 4 from Bhutan, 2 each from Kenya, Somalia, Gambia and Bostswana and one each from Malawi, Thailand, Mauritius, Macau, Uganda and Egypt.

Employer-Employee Relations

395. The industrial relations climate within the Bank was by and large peaceful and the relations with all the associationss/unions were generally cordial. During the year, conciliation meetings were held with the recognised Class III and Class V unions and satisfactory solutions to certain issues concering the workmen employees were arrived at.

396. With a view to promoting a better mutual understanding, a meeting was held between the Governor and the General Secretary and other office bearers of the All-India Reserve Bank Employees' Association (AIRBEA). Certain important issues such as the role and responsibilities of the Reserve Bank and the employees' involvement in it, improving the Bank's efficiency and customer service and the state of industrial relations in the Bank, were discussed during the meeting. A joint consultation committee meeting each with the Reserve Bank Officers' Association and the All-India Reserve Bank Staff Officers' Association was held November 1986 Certain improvements in facilities for the officers were announced during the meetings.

397. During the annual conference of Managers and head of the Central Office Departments held in April 1987, several issues relating to branch/regional offices and Central Office such as, review of industrial relations, discipline and punctuality, security arrangements and progress of computerisation/mechanisation were discussed.

398. During the year, the Bank introduced a new scheme relating to provision of medical assistance for the serving as well as retired employees and for this purpose constituted the 'Reserve Bank of India Medical Assistance Fund' effective January 1, 1987. The object of the Scheme /Fund, which, a contributory one, is to provde financial assistance for meeting a part of the medical expenditure incurred by serving employees and their families (spouse and dependent children) and by the retired employees and their spouses for treatment in India towards hospitalisation for operations/serious ailments. The asistance available to the serving employees under the Fund will be over and above reimbursements admissible under the Bank's normal medical facilities scheme. Membership of the Fund is optional and is open to all full-time employees of the Bank and retired employees on payment of contribution at prescrived rates . The Bank has initially contributed Rs.15 lakhs towards the corpus of the Fund.

Representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes

399. The total strenght of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in the Bank as on January 1, 1987 was 1,860 and 528 in Class IV, 1,881 and 872 in Class III and 355 and 76 in Class I respectively. Particulars of direct recruitment in various classes of service in the Bank during 1986 and the representation of scheduled castes/scheduled tribes in the total recruitment are given below:

Category	Total No. of candidates recruited	of which		Percentage to total	
		SCs	STs	SCs	STs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Class I	72	12	8	16.7	11.1
Class III	708	121	48	17.1	6.8
Class IV					
(i) ther than sweepors	222	69	22	31.1	9.9
(ii) Sweepers	27	3	—	11.1	—

Inspection of rosters was carried out at our Chandigarh, Jammu Calcutta, Patna, Bangalore and Hyderabad offices by the Liaison officer and found them to be in order.

Employment of Ex-Servicemen

400. During 1986, 106 out of 730 vacancies in Class III and 72 out of 295 vacancies in Class IV were required to be reserved for ex-servicemen at the prescribed rates of reservation; as against this, 61 and 36 vacancies, respectively, were actually filled in by ex-servicemen. The total strenght of ex-servicemen was 596 in Class III and 908 in class IV at the end of December 1986. The Bank has recently decided to give weightage for defence service of ex-servicemen employees recruited to Class III and Class IV who have completed at least 3 years' actual service in the Bank for schemes of promotion where certain number of years of service is prescribed as a minimum eligibility criteria. Accordingly, ex-servicemen recruited in Class III and Class IV, who have put in 5 years' defence service, will get the benefit of one year's service and those who have put in 10 years or more will get the benefit of a maximum of 2 yeats, for the purpose of promotion to the post of Staff Officer Gr. A under the All-India merit test and to Class III under the scheme of avenues of promotion, respectively. This benefit is admissible only for one scheme of promotion during the entire period of service in the Bank.

Promotion of Hindi

401. For the purpose of promoting the use of Hindi, annual time-bound programmes for 1986-87 were circulated to various offices/departments for implementation. Efforts were continued to be made by offices/departments for the issuing of circulars, office orders and other general orders bilingually and Bank's various publications/reports also continued to be brought out both in Hindi and English. Since January 1986 the Reserve Bank of India Bulletin is being published in bilingual form.

402. Employees were imparted training in Hindi noting, drafting and correspondence through Hindi workshops. A five-day Hindi workshop for senior officers of the Bank was also organised for the first in April 1987. Apart from the 'Rajbhasha Shield' competitions, departmental shield scheme was extended to offices in Region 'C' also to encourage them to progressively use Hindi in their working. Elocution competitions, poets' gatherings, essay competitions, competitions in noting and drafting in Hindi and other Hindi *samarohas* were organised during the year by the Bank's offices/departments.

Office Premises and Residential Quarters

403. During the year, the expected expenditure on construction/acquisition of office buildings and residential quarters, additions/alterations to the existing premises, purchase of land, etc., was a sum of Rs. 43.11 crores. The total expenditure during the first four years of the five-year plan would thus work out to Rs.114.42 crores against a total outlay of Rs.161.13 crores over the 5-year plan period.

404. The expansion of the existing office building at Bangalore and the construction of the Indira Gandhi Institute of Development Research at Goregaon, Bombay were completed during the year. Work is in progress in respect of construction of office building at Chandigarh, Bandra-Kurla complex, Bombay and Kanpur. Processing work relating to the proposed office buildings at Bhopal, Cochin, Jammu and New Bombay has been taken up/completed.

405. As regards residential quarters, a total of 1,317 flats and 27 single rooms were completed during 1986-87 comprising 600 flats and 27 single rooms for Officers, 575 flats for Class III staff and 142 flats for Class IV staff. Thus, in the first four years of the five-year plan, a total of 3,877 flats and 63 single rooms were completed for various categories of staff — 1,189 flats and 63 self-contained single rooms for officers,

1,564 flats for Class III staff and 1,126 flats for the Class IV staff. Another 893 flats for officers, 1,248 flats for Class III staff and 502 flats for Class IV staff are under construction at 11 centres. The selection of properties for holiday homes for Bank's employees at Mussoorie and Lonavla was also finalised.

Housing Loans

406. During the period July 1986 to June 30, 1987 housing loans sanctioned to the housing co-operative societies as well as individual employees amounted to Rs.10.05 crores as detailed overleaf.

Central Board

407. Shri R.K. Kaul relinquished office as Deputy Governor on the expiry of his term on September 30, 1986. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri Kaul. Shri A. Ghosh and Dr. C. Rangarajan were reappointed as Deputy Governors for a term of 5 years each, with effect from January 21, 1987 and February 12, 1987, respectively. Shri P.R. Nayak was appointed as Deputy Governor for a term of 5 years effective April 1, 1987.

Local Board

408. Shri Gulam Mohamed Mir Lasjan, a member of the Local Board of the northern area, resigned from the Board on March 25, 1987. The Board places on record its appreciation of the valuable services rendered by him.

409. Shri A. Hasib relinquished charge as Exective Director on expiry of his term on February 28, 1987. Shri S.V. Bagai was appointed as Executive Director, effective February 2, 1987.

	No. of societies	No. of Employees	Amount sanctioned (Rs. lakhs)
1	2	3	4
A. **Co-operative Housing Societies**			
Fresh loans	14	218	159.35
Additional loans	47	411	103.27
TOTAL	61	629	262.62
B. **Individual loans**			
Fresh loans		191	162.61
Additional loans		191	20.27
Sanctioned by Regional Offices			
Fresh loans		1,041	475.15@
Additional loans		294	84.02@
Total		1,717	742.05
GRAND TOTAL (A—B)		**2,346**	**1004.67**

@Upto March 1987.

Accounts

410. During the accounting year ended June 30, 1987 the Bank's income after making adjustments for various provisions, amounted to Rs.1,461.37 crores as against Rs.1,381.40 crores for the previous year.

411. The contributions to the National Rural Credit (Long Term Operations) Fund, National Rural Credit (Stabilisation) Fund and National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund during the year 1986-87 were Rs.300 crores, Rs.10 crores and Rs.430 crores as against Rs.350 crores Rs.10 crores and Rs. 400 crores, respectively, during 1985-86.

412. Out of the balance of income amounting to Rs.721.37 crores, after allowing for total expenditure of Rs.511.33 crores during the year (as against the balance of income of Rs.621.40 crores and expenditure of Rs.411.40 crores in 1985-86), the surplus profit set aside for payment to the Central Government was Rs. 210.04 crores (as against Rs.210.00 crores in the previous year).

413. The rise of Rs.79.97 crores in the income of the Bank from the previous year's level of Rs.1,381.40 crores to Rs. 1,461.37 crores in 1986-87, was mainly due to higher discount earned on Rupee treasury bills and higher interest earned on loans and advances to banks, partly offset by a decline in the interest earned on ways and means advances to State Governments and increased amount of interest paid to scheduled commercial banks on their additional cash reserves kept with the Bank. The rise of Rs. 99.93 crores in expenditure was mainly due to an increase in the cost of security printing and larger turnover commission payable to the agency banks for handing Government transactions.

Auditors

414. The accounts of the Bank have audited by Messrs. C.C. Chokshi & Co., Bombay, Messrs. Ved & Co. Ghaziabad, Messrs. Dass Gupta & Co., New Delhi, Messrs. Ved & Co. Messrs. S.R. Batliboi &Co., Calcutta, Messrs. Brahmayya & Co.,Madras and M/s Hingorani M. & Co., New Delhi. All the auditors except M/s. Hingorani M. & Co. New Delhi, were re-appointed by the Government of India M/s. Hingorani M. & Co., were appointed in place of M/s. K.C. Khanna & Co., New Delhi, who have retired on completion of their four-year term. This year also, all the offices of the Bank were audited by the statutory auditors. For the purpose of audit, all the offices of the Bank were divided into six zones and the audit fees paid per zone/per auditor were Rs.75,000. An additional fee of Rs.5,000 was paid to the Central Office Auditors for consolidation of branch accounts.

RESERVE BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1987

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department	16,23,72,540.00		Gold Coin and Bullion:		
Notes in circulation	30917,42,85,343.50		(a) Held in India	274,27,76,380.65	
			(b) Held outside India	—	
			Foreign Securities	1564,05,75,253.50	
			Total		1838,33,51,634.15
Total Notes issued		30933,66,57,883.50	Rupee Coin		56,19,85,449.35
			Government of India Rupee Securities		29039,13,20,800.00
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper		—
Total Liabilities		30933,66,57,883.50	Total Assets		30933,66,57,883.50

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.
Capital Paid Up	5,00,00,000.00	Notes	16,23,72,540.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin	10,13,920.00
National Industrial Credit (LTO) Fund	3725,00,00,000.00	Small Coin	2,87,694.94
Deposits :		Bills Purchased and Discounted :	
(a) Government		(a) Internal	—
(i) Central Government	52,03,91,723.93	(b) External	—
(ii) State Governments	14,98,99,027.19	(c) Government Treasury Bills	3951,67,02,333.14
(b) Banks		Balances held abroad	3675,82,31,835.27
(i) Scheduled Commercial Banks	1585 3,38,34,875.88	Investments (1)	20056,44,36,934.27
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	146,21,63,849.55	Loans and Advances to :	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	8,38,38,937.03	(i) Central Government	—
(iv) Other Banks	27,01,46,455.41	(ii) State Govrnment(2)	79,98,00,000.00
(c) NABARD Deposit		Loans and Advances to :	
(i) NRC (Long-Term Operations) Fund	—	(i) Scheduled Commercial Banks	853,06,18,378.88
(ii) NRC (Stabilisation) Fund	134,87,20,915.61	(ii) State Co-operative Banks	30,77,69,000.00
(d) Others	4940,79,13,350.59	(iii) NABARD	949,68,16,000.00
Bills Payable	126,50,59,489.06	(iv) Others	107,50,00,000.00
Other Liabilities	9612,12,26,908.55	Loans, Advances & Investments from National Industrial Credit (LTO) Fund :	
		(a) Loans & Advances to :	
		(i) Industrial Development Bank of India	2875,29,80,500.00
		(ii) Export Import Bank of India	345,00,00,000.00
		(b) Investment in bonds/debentures issued by :	
		(i) Industrial Development Bank of India	—
		(ii) Export Import Bank of India	—
		Other Assets(3)	1852,71,76,409.30
Total Liabilities	34796,31,95,545.90	Total Assets	34796,31,95,545.80

(1) Include Rs. 2036,55,83,302.37 held abroad in foreign currencies.
(2) Includes Ways & Means Advances.
(3) Includes amounts advanced to or diposited with scheduled commercial banks and special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1987

INCOME		Rs. P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.*		721,37,24,362.17
	Total	721,37,24,362.17
EXPENDITURE		
Establishment		137,98,79,616.13
Directors & Local Board Members Fees & Expenses		2,72,211.22
Auditors Fees		9,28,056.24
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		7,38,51,598.34
Law Charges		30,91,509.04
Postage and Telegraph Charges		2,25,05,794.17
Remittance of Treasure		7,87,31,709.85
Stationery, etc.		1,89,63,795.10
Security Printing (Cheque, Note Forms etc)		173,04,97,738.50
Depreciation, and Repairs to Bank Property		8,31,98,248.92
Agency Charges		163,64,17,443.29
Contributions go Staff Gratuity and Superannuation Funds		2,65,00,000.00
Miscellaneous Expenses		5,84,82,308.00
	Total	511,33,20,028.80
Not available balance		210,04,04,333.37
	Total	721,37,24,362.17
Surplus payable to the Central Government		210,04,04,333.37

*After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of Reserve Bank of India, Act, 1934.

RESERVE FUND ACCOUNT

	Rs. P.
Balance on 30th June, 1986	150,00,00 000.00
Transfer from Profit and Loss Account	
Total	150,00,00,000.00

K.G. PATKAR
Chief Accountant

Dated the 14th August, 1987.

R.N. MALHOTRA — Governor
A. GHOSH — Deputy Governor
C. RANGARAJAN — Deputy Governor
P.D. OJHA — Deputy Governor
P.R. NAYAK — Deputy Governor

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1987.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of all Officers of the bank and report that where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank

Dated the 14th August, 1987.

M/s. BRAHMAYYA & CO.
M/s. C.C. CHOKSHI & CO.
M/s. S.R. BATLIBOI & CO. Auditors
M/s. DAS GUPTA & CO.
M/s VED & CO.
M/s. HINGORANI M. & CO.

RESERVE BANK OF INDIA

STATEMENT ON BALANCE SHEET AS AT THE END OF 30TH JUNE 1985 AND 30TH JUNE 1986

Particulars / For the year ended	June 30, 1985		June 30, 1986	
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	P.
ISSUE DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Notes held in the Banking Department	39,68,97,530.00		15,38,14,668.00	
Notes in circulation	24755,60,11,721.50		27376,84,16,312.50	
Total notes issued		24795,29,09,251.50		27392,22,30,980.50
Total Liabilities		24795,29,09,251.50		27392,22,30,980.50
ASSETS				
Gold Coin and Bullion				
(a) Held in India	246,66,66,362.28		274,27,76,380.65	
(b) Held outside India	—		—	
Foreign Securities	1564,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
Rupee Coin	15,00,32,662.85		22,51,68,831.20	
Government of India Rupee Securities	22969,56,34,972.87		25531,37,10,515.15	
Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—		—	
Total Assets		24795,29,09,251.50		27392,22,30,980.50
BANKING DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
National Industrial Credit (LTO) Fund	2895,00,00,000.00		3295,00,00,000.00	
Deposits				
(a) Government				
(i) Central	59,86,10,234.95		57,09,03,373.31	
(ii) States	14,87,27,256.98		14,01,33,635 35	

STATEMENT ON BALANCE SHEET (Contd.)

Particulars / For the year ended	June 30, 1985		June 30,1986	
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
(b) Banks				
(i) Scheduled Commercial Banks	10886,01,46,520.08		12616,58,36,433.76	
(ii) Scheduled State Co-op. Banks	142,83,62,962.37		171,70,80,711.49	
(iii) Non-Scheduled State Co-op. Banks	4,57,75,099.57		5,93,85,498.77	
(iv) Other Banks	25,18,33,462.00		25,51,30,796.64	
(c) NABARD Deposit				
(i) NRC (LTO) Fund	117,58,65,242.03		—	
(ii) NRC (Stabilisotion) Fund	281,28,55,673.58		266,87,20,915.61	
(d) Others	6461,81,25,057.68		5901,50,25,855.62	
Bills Payable	22,28,24,900.36		129,16,08,519.88	
Other Liabilities	6074,47,42,058.44		8627,95,57,694.61	
Total Liabilities		27140,78,68,450.04		31266,33,83,435.04

Note : June 30, 1935 -Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,04,997.42 equivalent of £50,000.

BANKING DEPARTMENT

ASSETS

Notes	39,68,97,530.00		15,38,14,668.00	
Rupee Coin	7,20,074.00		8,11,044.00	
Small Coin	2,19,447.75		2,45,531.52	
Bills purchased and discounted				
(a) Internal	—		—	
(b) External	—		—	
(c) Government Treasury Bills	8394,06,37,831.32		15834,61,56,415.79	
Balance held abroad	3732,00,89,774.67		3760,23,20,272.63	
Investments	6952,77,49,528.59(b)		5554,25,29,142.84(c)	
Loans and Advances to				
(i) Central Government	—		—	
(ii) State Governments (a)	315,58,00 000.00		18,06,00,000.00	
(iii) Scheduled Commercial Banks	1863,00,79,190.68		474,54,19,484.23	
(iv) State Co-operative Banks	21,66,25,000.00		19,73,42,000.00	
(v) NARBARD	761,83,41,000.00		860,90,24,000.00	
(vi) Others	182,05,00,000.00		135,00,00,000.00	
Loans, Advances and Investments from				
NIC (LTO) Fund :				
(a) Loans and Advances to				
(i) Industrial Development Bank of India	2320,78,30,750.00		2589,87,90,500.00	
(ii) Export Import Bank of India	180,00,00,000.00		260,00,00,000.00	
(b) Investment in Bonds/Debentures issued by :				
IDBI/EXIM Bank	—		—	
Other Assets (d)	2377,23,78,323.03		1743.03,30,376.03	
Total Assets		27140,78,68,450.04		31266.33,83,435.04

(a) Includes Ways & Means Advances.

(b) Includes Rs. 1383,73,65,508.44 held abroad in foreign currencies.

(c) Includes Rs. 1760,62,12,768.79 held abroad in foreign currencies.

(d) Includes amounts advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1985 AND 30TH JUNE 1986

For the year ended——	June 30,1985 Rs. P.	June 30,1986 Rs. P.
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.*	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38
TOTAL	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38
EXPENDITURE		
Establishment	142,25,62,666.01	128,12,08,682.1
Directors' and Local Board Members Fees and Expenses	2,64,677.99	3,37,965.01
Auditors' Fees	6,68,795.90	7,08,633.50
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	4,77,58,619.79	6,37,88,291.34
Law Charges	8,56,772.09	34,53,597.76
Postage and Telegraph Charges	1,30,13,462.74	1,46,17,550.44
Remittance of Treasure	2,27,80,309.80	4,08,34,355·50
Stationery, etc.	1,50,83,724.29	1,47,79,459.38
Security Printing (Cheque, Note Forms etc.)	58,28,05,498.05	100,07,82,422.27
Depreciation and Repairs to Bank Property	6,63,11,894.66	6,64,16,997.37
Agency Charges	132,84,76,907.52	150,01,19,357.24
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	1,70,00,000.00	2,15,00,000.00
Miscellaneous Expenses	10,21,97,196.67	10,54,64,541.40
Net Available Balance	210,00,00,824.47	210,00,01,000.05
TOTAL	571,97,87,340.98	621,40,12,853.38
Surplus payable to Central Government	210,00,00,824.47	210,00,01,000.05

*After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil	Nil
TOTAL	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

[No. F.19/29/87-BO. I]

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.